

राष्ट्रभारत

डा० राम विलास शर्मा



अक्षर प्रकाशन प्रा० लिमिटेड

२/३६, अगसारी रोड, दरियागंज, दिल्ली-६

प्रकाशक अक्षर प्रकाशन प्रा० लि०

२१३६, अन्मारी रोड, दरियागञ्ज, दिल्ली-६

●

मूल्य बारह रुपये

प्रथम संस्करण दिसम्बर, १९६४

●

आवरण

नरेंद्र श्रीवास्तव

●

मुद्रक

हिंदी प्रिंटिंग प्रेस

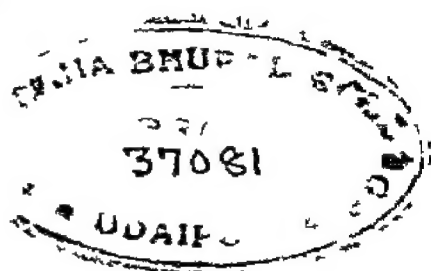
मिनाथम, कबीर रोड,

दिल्ली

●

पुस्तक-व्यय

विजय बुक बाइंडिंग हाउस, दिल्ली



## भूमिका

भाषा की समस्या मूलतः जातीय समस्या का ही एक अंग है। इस देश में अनेक भाषाएँ बोलनेवाली जातियाँ रहती हैं। इनसे मिलकर भारत राष्ट्र बना है। इस राष्ट्र में जातियों की सम्पर्क भाषा क्या हो, एक ही सम्पर्क भाषा हो या अनेक हों—यह समस्या का एक पक्ष है। कुछ लोग इस देश को उपमहाद्वीप कहते हैं; उनका मत है कि राष्ट्रीयता का भाव अंग्रेजों का विरोध करने से पैदा हुआ; वास्तव में यह देश राष्ट्र नहीं है क्योंकि यहाँ एक भाषा के बदले अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं। इस तरह राष्ट्रभाषा की समस्या का विवेचन करते हुए राष्ट्र की व्याख्या करना आवश्यक हो जाता है, विशेषकर भारतीय राष्ट्रीयता के ऐतिहासिक विकास पर कुछ कहना आवश्यक हो जाता है। राष्ट्रभाषा की समस्या विशुद्ध भाषा-विज्ञान की समस्या न होकर बहुजातीय राष्ट्र के गठन और विकास की ऐतिहासिक-राजनीतिक समस्या बन जाती है।

भारत की जातियों में हिन्दी-भाषी जाति सख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी है। कुछ लोग इन जाति के अस्तित्व से ही इन्कार करते हैं। वे कहते हैं कि उत्तर भारत के पुराने जनपदों में रहनेवाले लोग स्वतन्त्र जातियाँ हैं; बुन्देलखण्डी, अवधी, ब्रजभाषा आदि हिन्दी की बोलियाँ नहीं हैं, वे हिन्दी से स्वतन्त्र भाषाएँ हैं। हिन्दी क्षेत्र में भाषा और बोलियों की यह समस्या हिन्दीभाषी जाति के विकास की समस्या बन जाती है। इस विकास को समझे बिना भाषा और बोली के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता। भाषा-समस्या का यह दूसरा पक्ष है।

इसी हिन्दी प्रदेश में बोलचाल की भाषा के आधार पर साहित्यिक भाषा के दो रूप—हिन्दी और उर्दू—विकसित हुए। उर्दू मुसलमानों की भाषा है या हिन्दुओं और मुसलमानों के मिलने से बनी, भारत में जो मुसलमान आये वे एक क़ौम के थे या कई क़ौमों के, उनकी एक भाषा थी या वे कई भाषाएँ बोलते थे, क्या हिन्दी का विकास हिन्दू राष्ट्रवाद के अभ्युत्थान के कारण हुआ, क्या मुसलमानों की अलग क़ौम है, उर्दू को क्षेत्रीय भाषा बनाया जाय या नहीं—ये सभी प्रश्न हिन्दी-भाषी जाति के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ जुड़े हुए हैं। भाषा-समस्या का यह तीसरा पक्ष हुआ।

भारतीय जनता के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने बहुजातीय राष्ट्र की विशेषताएँ पहचानें, इस राष्ट्र में हिन्दी-भाषी जाति की भूमिका पहचानें। इस दृष्टि से भारत की भाषा-समस्या का व्यापक महत्त्व है, इसमें



प्रकाशक अणार प्रकाशन प्रा० लि०

२, १६, अन्तारी गट, दरियागट, दिल्ली-६

●

सूच्य बारह छत्रे

प्रथम संस्करण दिसम्बर, १९६५

●

आवरण

नरन्ध श्रीरामनव

●

मुद्रक

हिन्दी प्रिंटिंग प्रेस

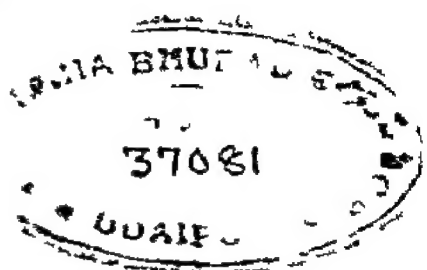
मिनाम, नवीन रोड,

दिल्ली

●

पुस्तक-वध

विजय बुक बाइडिंग हाउस, दिल्ली



## भूमिका

भाषा की समस्या मूलतः जातीय समस्या का ही एक अंग है। इस देश में अनेक भाषाएँ बोलनेवाली जातियाँ रहती हैं। इनसे मिलकर भारत राष्ट्र बना है। इस राष्ट्र में जातियों की सम्पर्क भाषा क्या हो, एक ही सम्पर्क भाषा हो या अनेक हों—यह समस्या का एक पक्ष है। कुछ लोग इस देश को उपमहाद्वीप कहते हैं; उनका मत है कि राष्ट्रीयता का भाव अंग्रेजों का विरोध करने से पैदा हुआ; वास्तव में यह देश राष्ट्र नहीं है क्योंकि यहाँ एक भाषा के बदले अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं। इस तरह राष्ट्रभाषा की समस्या का विवेचन करते हुए राष्ट्र की व्याख्या करना आवश्यक हो जाता है, विशेषकर भारतीय राष्ट्रीयता के ऐतिहासिक विकास पर कुछ कहना आवश्यक हो जाता है। राष्ट्रभाषा की समस्या विशुद्ध भाषा-विज्ञान की समस्या न होकर बहुजातीय राष्ट्र के गठन और विकास की ऐतिहासिक-राजनीतिक समस्या बन जाती है।

भारत की जातियों में हिन्दी-भाषी जाति संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी है। कुछ लोग इस जाति के अस्तित्व से ही इन्कार करते हैं। वे कहते हैं कि उत्तर भारत के पुराने जनपदों में रहनेवाले लोग स्वतन्त्र जातियाँ हैं; बुन्देलखण्डी, अवधी, ब्रजभाषा आदि हिन्दी की बोलियाँ नहीं हैं, वे हिन्दी से स्वतन्त्र भाषाएँ हैं। हिन्दी क्षेत्र में भाषा और बोलियों की यह समस्या हिन्दीभाषी जाति के विकास की समस्या बन जाती है। इस विकास को समझे बिना भाषा और बोली के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता। भाषा-समस्या का यह दूसरा पक्ष है।

इसी हिन्दी प्रदेश में बोलचाल की भाषा के आधार पर साहित्यिक भाषा के दो रूप—हिन्दी और उर्दू—विकसित हुए। उर्दू मुसलमानों की भाषा है या हिन्दुओं और मुसलमानों के मिलने से बनी, भारत में जो मुसलमान आये वे एक क़ौम के थे या कई क़ौमों के, उनकी एक भाषा थी या वे कई भाषाएँ बोलते थे, क्या हिन्दी का विकास हिन्दू राष्ट्रवाद के अभ्युत्थान के कारण हुआ, क्या मुसलमानों की अलग क़ौम है, उर्दू को क्षेत्रीय भाषा बनाया जाय या नहीं—ये सभी प्रश्न हिन्दी-भाषी जाति के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ जुड़े हुए हैं। भाषा-समस्या का यह तीसरा पक्ष हुआ।

भारतीय जनता के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने बहुजातीय राष्ट्र की विशेषताएँ पहचानें, इस राष्ट्र में हिन्दी-भाषी जाति की भूमिका पहचानें। इस दृष्टि से भारत की भाषा-समस्या का व्यापक महत्त्व है, इसमें

निर्भी को सदेह न होना चाहिए।

इस पुस्तक में निम्नलिखित तीनों वर्गों में भाषा-समस्या पर विवेकपूर्ण और मेरे अधिकृत निवेदनों का संग्रह है। इनमें पाठक इस नक़्क़े कि इन अवधि में भाषा-समस्या के तीन स पक्ष, किम समय एक हिन्दी लेखक के मन को आन्तर्निहित करने रहे। इन वर्गों में मेरे विचार बढ़ते हैं। लघु में समस्या के विभिन्न पक्षों पर अलग-अलग समझ पर काम-रचना जा दिया गया है किन्तु भगीश्वर बुनियादी मायनाओं में कार्य अन्तर्गत नहीं आया। पहली यह कि अग्रणी भाषाओं सभी भाषाओं पर साक्षात्कारादिया द्वारा सादी हुई भाषा है जोर उमका प्रमुख ज़रूरी म-जन्दी खत्म करना चाहिए। दूसरी यह कि हिन्दी और उर्दू मूलतः एक ही भाषा हैं जोर प्राग-जनक दाना पुनः निवृत्त एक ही भाषा के आधार पर एक ही साहित्यिक भाषा का विकास होगा। तीसरी यह कि बुन्देल-मण्डी, ब्रज अवध जादि हिन्दी की दायिनी हैं स्वतन्त्र भाषाएँ नहीं हैं।

भारत की बहुजातीय राष्ट्रीयता के बारे में हिन्दी भाषी जाति के विकास के बारे में हिन्दी-उर्दू की बुनियादी एकता और हिन्दी और जनपदीय बोली के साम्य सम्बन्ध के बारे में भगी मायनाओं में काट परिवर्तन नहीं हुआ।

भारतीय संविधान के अनुसार सन् '६७ में केन्द्र के राजकीय काम-काज में अंग्रेज़ी का व्यवहार समान हो जाना चाहिए था। स्वभावतः इस वर्ष मैं जो लेख लिखे हैं उनका सम्बन्ध अंग्रेज़ी हिन्दी अथवा अंग्रेज़ी बोलाम भारतीय भाषाओं के विवाद में अधिक है। मेरे कुछ मित्रों ने मुझे याद दिलाया है कि सन् '४६ में मैं अनिवार्य राजभाषा का विरोधी था, अब हिन्दी की राष्ट्रभाषा बनवाने के लिए अन्य राष्ट्रवादियों की तरह दूसरों पर जोर-जबर्दस्ती हिन्दी लादन का आदोलन कर रहा हूँ।

इन मित्रों की सलाह में निवेदन है कि जिस मैं अनिवार्य राजभाषा का विरोधी सन् '४६ में था, वैसे ही आज भी हूँ। मैं किसी भी भाषा पर हिन्दी लादन का विरोध करता हूँ। मैं हिन्दी का सम्पन्न-भाषा बनाने के पक्ष हूँ दूसरी भाषाओं के क्षेत्र में राजकीय और शिक्षा-सम्बन्धी कार्यों में हिन्दी का व्यवहार के पक्ष में नहीं हूँ। सम्पन्न-भाषा की भी कुछ लाग हिन्दी का सादा जाना समझते हैं। मैं किसी भी प्रदेश की इच्छा के विरुद्ध उसके लिए हिन्दी को सम्पन्न भाषा बनाने का भी समर्थन नहीं करता। लेकिन मैं यह भी कहना हूँ, अंग्रेज़ी प्रेमियों का हिन्दीभाषी प्रदेशों पर अंग्रेज़ी लादने का कोई अधिकार नहीं है। अहिन्दी भाषी प्रदेशों के नेता नहीं चाहते कि केन्द्र में अंग्रेज़ी की जगह हिन्दी का चलन हो, उनकी इच्छा। वे केन्द्र में हिन्दी के अलावा अन्य भाषाओं का चलन कर सकते हैं। इसमें उन्हें अराजकता दिनायी देनी हो तो अंग्रेज़ी ही चलाने में किन वे हिन्दीभाषियों को बाध्य नहीं कर सकें कि लोकसभा राज्यसभा तथा केन्द्रीय राजकाज में वे भी अंग्रेज़ी का व्यवहार करें।

हिन्दी भाषी जाति भारत की सबसे बड़ी जाति है। वह केन्द्र में अपने प्रतिनिधियों का हिन्दी लिखने-बोलने के लिए बाध्य करके अंग्रेज़ी का प्रमुख खत्म कर सकती है।

१४ मार्च, सन् '६५ के 'धर्मयुग' में इस आशय का सुझाव देखकर कम्युनिस्ट नेता श्री योगीन्द्र शर्मा ने लिखा था कि यह गृहयुद्ध की ललकार है ।

मई, सन् '५८ के 'समालोचक' में मैंने लिखा था, "यदि हिन्दी-भाषी जनता संगठित हो, यदि वह अपने प्रदेश में हिन्दी को पूर्ण रूप से राजकाज की भाषा बनाये तो यह असम्भव है कि यह विशाल प्रदेश और उसकी बहुसंख्यक जनता सारे देश को अपने साथ खींचकर न ले चल सके ।"

६ जनवरी, सन् '६३ के 'धर्मयुग' में मैंने लिखा था, "यदि समस्त हिन्दी-भाषी प्रदेश में शिक्षा-संस्थाओं, न्यायालयों, राजकीय कार्यों में हर स्तर पर हिन्दी का व्यवहार होने लगे, यदि विधान-परिपदों के सदस्य प्रतिज्ञा करें कि वे अपना सार्वजनिक कार्य हिन्दी में ही करेंगे, यदि लोकसभा के सदस्य तय कर लें कि वे राजभाषा के रूप में हिन्दी का ही व्यवहार करेंगे, तो क्या इसमें किसी को सन्देह हो सकता है कि समूचे राष्ट्र का वातावरण बदल जायेगा और हिन्दी की राष्ट्रभाषा बनाते ज़रा भी देर न लगेगी ।"

योगीन्द्र शर्माजी नोट कर ले, जिसे वह गृहयुद्ध की ललकार कहते हैं, वह बात काफ़ी पुरानी है ।

इस संग्रह में काफ़ी लेख ऐसे हैं जो कम्युनिस्ट पार्टियों के सदस्यों और मार्क्सवादी लेखकों में आपसी बहस के लिए लिखे गये थे । सन् '४९ में जो लेख 'कम्युनिस्ट' पत्रिका में छपा था, उसके ऊपर लिखा था, 'बहस के लिए लेख' । सितम्बर, सन् '६४ के 'न्यूएज' (भासिक) में हिन्दी और राष्ट्रीय एकता पर मेरा जो लेख छपा था, उस पर भी लिखा था, 'बहस के लिए लेख' । यह बताना इसलिए आवश्यक है कि पाठकों को यह भ्रम न हो कि मैंने अपने लेखों में जो बातें कही हैं, वे कम्युनिस्ट पार्टियों की स्वीकृत मान्यताएँ हैं ।

यद्यपि मैंने हिन्दी-उर्दू समस्या तथा हिन्दी क्षेत्र में भाषा और बोलियों के प्रश्न पर अनेक बार और काफ़ी विस्तार से लिखा है, किन्तु मेरी स्थापनाओं का विरोध करने-वालों ने कभी भी मेरे तर्कों का खण्डन नहीं किया । इसके बदले वे मुँहजवानी मेरे बारे में अफ़वाहें फैलाते रहे हैं । इधर जब से अंग्रेज़ी को लेकर संघर्ष तेज़ हुआ है, वे उन अफ़वाहों को छापे के हल्कों में प्रकाशित भी करने लगे हैं । इन मित्रों से निवेदन है कि क्रतवे देने से भाषा-समस्या का समाधान नहीं हो सकता । तर्क का उत्तर तर्क से ही दीजिए ।

भाषा-समस्या का घनिष्ठ सम्बन्ध राष्ट्रीय एकता से है, यह बात किसी से छिपी नहीं है । जिस राष्ट्र में जितनी ही आन्तरिक दृढ़ता होगी उतना ही वह हर तरह के तनाव और बोझ सह लेने की स्थिति में होगा । जिस देश की फ़ौज और जनता में दृढ़ भाईचारा होता है ; जिस फ़ौज में नायकों और सैनिकों के बीच दृढ़ भाईचारा होता है, जिस देश की राज्यसत्ता के पीछे संगठित जनता की शक्ति होती है वह देश अपराजेय होता है । भाषा-समस्या का सही समाधान राष्ट्रीय एकता को दृढ़ करके उसे अजेय बना सकता है ; भाषा-समस्या का ग़लत समाधान लोगों में असन्तोष पैदा करके राष्ट्रीय एकता को कमजोर कर सकता है । इस तरह का असन्तोष हर अवस्था में विघटनकारी

होता है। दीधनार्थीन युद्ध की परिस्थितियों में वह विशेष रूप से खतरनाक साबित हो सकता है। हमारी राष्ट्रीय एकता हर परिस्थिति में हर तरह का तात्कालिक बर्दान्त करने अट्ट धनी रहे हम यही प्रयत्न करना चाहिए।

इन सभ्य व कुछ नम अंग्रेजी में प्रकाशित हुए थे, उनका यहाँ अनुवाद दिया गया है। भाषा और साहित्य में वाकिस्मान' लखनऊ की एक पेंगला पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। उसका भी अनुवाद दिया गया है। अधिकांश लेख हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं और यहाँ पहली बार गवर्नित किए गये हैं। कुछ लेख मरे अप निम्न-महारा में आ चुके हैं। अन्तिम तीन भाग इस सभ्य में पहली बार प्रकाशित हो रहे हैं। कुछ लेखों के अनावश्यक अंग काट दिये गये हैं किन्तु उनकी कोई मुद्रा स्थापना में बदले भी दृष्टि में आज बह गयी हो या चलन, इसका मैं ध्यान रखा है। मनु '६६' वाले निबंध में मैंने अनिवार्य केन्द्रीय राजभाषा का विरोध किया था और कहा था कि हिन्दी का केन्द्रीय राजभाषा प्रस्ताव में बड़े पूँजीपतियों को लाभ होगा। यह स्थापना उक्त निबंध में गहन दी है यद्यपि बड़े पूँजीपतियों की भूमिका और केन्द्रीय राजभाषा के बारे में मैंने विचार बही नहीं है। मैं केन्द्रीय राजभाषा का अनिवार्य बना देने वाली द्वाग की दृष्टि के निम्न उन पर 'आदने का विरागी हूँ किन्तु इस बात का आवश्यक हो- वाटनीय समझता हूँ कि भारत के विभिन्न दर हिन्दी को केन्द्रीय राजभाषा प्रदान के लिए प्रयत्न करें। इन दलों के नेता ही जनमज के प्रतिनिधि बनते हैं, वे अपनी पार्टियों के केन्द्रीय दायरों में अंग्रेजी निवाले तो उन्हें अन्तिम भारतीय सम्भव के लिए पाने अपनी पार्टियों में, फिर ग्रासन व्यवस्था में हिन्दी के व्यवहार की उपयोगिता दिखायी देने लगे।

भारत की राजनीतिक पार्टियों में मेरा सम्बन्ध कम्युनिस्ट पार्टियों में रहा है। मैंने यह आवश्यक समझा कि मनु कम्युनिस्ट पार्टियों के अन्दर अंग्रेजी का व्यवहार खत्म करने के लिए आन्दोलन किया जाय। इस आगम से कुछ बानें मैंने मितम्बर, मनु '६४ की 'पू-एज पत्रिका में लिखी थी। यह पत्रिका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टियों का मुखपत्र है। 'भाषा की समस्या—अति आवश्यक' और 'भाषा की समस्या और राष्ट्रीय विघटन' लेख 'जनशक्ति' में प्रकाशित हुए। जनशक्ति भारतीय कम्युनिस्ट पार्टियों की बिहार शाखा का मुखपत्र है। इसमें श्री धीमीन्द्र शर्मा ने मेरी मान्यताओं का खण्डन करते हुए दो लेख लिखे। 'भाषा की समस्या और मजदूर वर्ग' तथा 'भारत की राजभाषा अंग्रेजी और राष्ट्रीय जनताधिकार मोर्चा' उनके लेखों के प्रत्युत्तर हैं। ये भी 'जनशक्ति' में प्रकाशित हुए थे।

मैं 'जनशक्ति' के सम्पादक का कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टियों के एक अन्ध्र भारतीय नेता के विरुद्ध मेरे तीव्र खण्डनात्मक लेख छापे।

मेरे अनेक भाषा-सम्बन्धी लेख धर्मयुग में प्रकाशित हुए हैं जिससे मेरी बात

हजारों ऐसे पाठकों तक पहुँची है जो मेरी पुस्तकों और लेखों से एकदम अपरिचित थे। इसके लिए मैं 'धर्मयुग' के सम्पादकों का कृतज्ञ हूँ। 'धर्मयुग' ने अंग्रेजी-विरोधी आन्दोलन में सक्रिय भाग लेकर सराहनीय कार्य किया है। उसका वीटनिक-प्रेम थोड़ा कम हो जाय तो वह हिन्दी भाषा और साहित्य की और भी सेवा करे।

५ अक्टूबर, '६५

—रामविलास शर्मा

## अनुक्रम

१. स्वदेशी भाषा और अहिंसावादी साहित्य	१७
२. राजनीतिक नेता और हिन्दी	२०
X ३. <u>भाषा और राष्ट्रीयता</u>	२२
४. भाषा और साहित्य में पाकिस्तान	२३
५. हिन्दी गद्य-शैली पर कुछ विचार	२७
६. राष्ट्रभाषा हिन्दी और हिन्दू राष्ट्रवाद	३३
७. हिन्दी का 'संस्कृतीकरण'	३६
८. उर्दू-साहित्य की सांस्कृतिक परम्परा	४५
✓ ९. <u>भारत की भाषा-समस्या</u>	६०
१०. जातीय भाषा के रूप में हिन्दी का प्रसार	७७
११. हिन्दी-उर्दू समस्या	८५
१२. भाषा और प्रान्तीयता	६२
१३. अनिवार्य राजभाषा का सवाल	६५
१४. अंग्रेजी के हिमायती	१००
१५. सोवियत क्रान्ति और भाषा-समस्या	१०४
१६. अंग्रेजी-प्रेमी भारतवासी	१०६
✓ १७. <u>बहुजातीय राष्ट्रीयता और राष्ट्रभाषा हिन्दी</u>	१११
१८. हिन्दी की व्याकरण-सम्बन्धी कठिनाइयाँ	११६

१६ उद्‌ की समस्या	१०१
२० ज्ञानीय प्रतिष्ठा इला और हिन्दी	१२८
२१ राष्ट्रभाषा अग्रणी	१३६
२२ मौलिक मय म भाषा समस्या समाधान	१४०
२३ हिन्दी-उद्‌ की मुनियानी गणना	१४३
२४ राष्ट्रीय गणना और अग्रणी	१४७
२५ राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय प्रभुगणना	१५०
२६ हिन्दी भाषा प्रभु म हिन्दी प्रकार की भाषागणना	१५६
२७ सरकारी भाषागणना और राष्ट्रभाषा	१६४
२८ सामयिकी कम्पुनिस्त्र भाषा व कायमम का मगोदा	१७१
२९ राष्ट्र, ज्ञान और सामयकार	१७४
३० अंतरराष्ट्रीय वैधानिक गणनागणनी	१८१
३१ मम्पुति और भाषा	१८३
३२ भाषा की समस्या—धनि ज्ञानमय	१८६
३३ अग्रणी की मुगुधा व निग मयम	१८८
३४ भाषा का समस्या और राष्ट्रीय विमटन	१९३
३५ भाषा की समस्या और मजदूर मय	१९६
३६ भारत की राजभाषा अग्रणी और राष्ट्रीय	
जननात्रिक मोर्चा	२१२
३७ वेग का विमटन और अग्रणी	२२६
३८ प्रगतिशील साहित्यकार और भाषा समस्या	
व जननात्रिक समाधान	२३७

## परिशिष्ट—१

१ भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और उन्नीसवीं सदी मे

आदोलन २६५



परिशिष्ट— २

१. प्रेमचन्द और भाषा-समस्या	३०५
२. उत्तरप्रदेश की सरकार और हिन्दी	३१२
३. भारत का भाषा-संकट	३१५

१६ उर्दू की समस्या	१२१
२० ज्ञानीय प्रतिबद्धता और हिन्दी	१२८
२१ राष्ट्रभाषा अंग्रेजी	१३६
२२ सोवियत संघ में भाषा समस्या समाधान	१४०
२३ हिन्दी-उर्दू की बुनियादी एकता	१४३
२४ राष्ट्रीय एकता और अंग्रेजी	१४७
२५ राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय प्रभुत्व	१५२
२६ हिन्दी भाषा प्रयोग में हिन्दी-प्रचार की आवश्यकता	१५६
२७ सरकार की कार्यवाही और राष्ट्रभाषा	१६६
२८ वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यक्रम का समाधान	१७१
२९ राष्ट्र ज्ञान और भावभाव	१७५
३० 'अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन'	१८१
३१ सम्मेलन और भाषा	१८३
३२ भाषा की समस्या—जानि आवश्यक	१८६
३३ अंग्रेजी की मुद्दा के लिए समय	१८८
३४ भाषा की समस्या और राष्ट्रीय विघटन	१९३
३५ भाषा की समस्या और सज्जन वर्ग	१९६
३६ भारत की राजभाषा अंग्रेजी और राष्ट्रीय	
जनजातिक मोर्चा	२१२
३७ देश का विघटन और अंग्रेजी	२२६
३८ प्रगतिशील माहि प्रचार और भाषा समस्या	
के जनजातिक समाधान	२३७

### परिशिष्ट—१

१ भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और अन्तीमवी सदी में

आन्दोलन २६५

२. गांधीजी और भाषा-समस्या

२७८

**परिशिष्ट— २**

१. प्रेमचन्द और भाषा-समस्या

३०५

२. उत्तरप्रदेश की सरकार और हिन्दी

३१२

३. भारत का भाषा-संकट

३१५

राष्ट्रभाषा की समस्या

## स्वदेशी भाषा और अहिंसावादी साहित्य

हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के अनेक पदाधिकारी इस बार अपनी असाहित्यिकता के कारण एक विरोधता लिये हैं। साहित्य में जितने भी जन अधिक संख्या में दिलचस्पी लें, हमें उससे प्रसन्न होना चाहिए। परन्तु ये मेधावी हिन्दी-साहित्य के पास विद्यार्थी के रूप में नहीं आए। उसे जानने-पहचानने की उन्होंने चेष्टा नहीं की। राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करनेवाली अपनी प्रकृति के अनुसार उन्होंने हिन्दी-साहित्यिकों को तरह-तरह के उपदेश दिए हैं। यदि वे हमारे साहित्य का सहृदयतापूर्वक अनुशीलन कर उसकी त्रुटियाँ साहित्यिकों को बताते तो उनके कार्य पर सबको हर्ष होता। पर उनकी असाहित्यिकता और साहित्य के अज्ञान का घोप उनके उपदेश की मयूर वाणी से मेल नहीं खाता।

सम्मेलन के सभापति ने, शायद अपने पूर्व राष्ट्रपति होने का स्मरण कर कहा है—“सुविधा के विचार से हिन्दी को राष्ट्रभाषा हमने माना है।” फिर इस सुविधा के मार्ग में जो अड़चन आएँ, उन्हें क्यों न हटाया जाए? आप कहते हैं—“हिन्दुस्तान में हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, सिख वसते हैं और तो भी वह हिन्दुस्तान है। उसी प्रकार हिन्दी में सभी भाषाओं से उत्तम शब्द हम लेंगे और तो भी वह हिन्दी ही रहेगी।” जैसे कांग्रेस, राष्ट्र की एकता का प्रतीक, अपने भीतर सभी प्रान्तों के प्रतिनिधि रखती है, वैसे हिन्दी तब तक राष्ट्रभाषा न होगी, जब तक उसमें सभी भाषाओं के प्रतिनिधि शब्द न होंगे। सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष श्री ब्रजलाल वियाणी ने इस बात को भली-भाँति समझा है और उसे सबसे अधिक स्पष्ट रूप में कहा है—“हिन्दी-भाषा के प्रचार तथा सर्वप्रियता के लिए आवश्यक है कि उसका शब्द-भण्डार सब भाषाओं से लिए हुए शब्दों से भरा हो। हरेक प्रान्तवासी में हिन्दी के लिए मनत्व पैदा होने के लिए हिन्दी के शब्द-कोश में उसका भी हिस्सा होना आवश्यक है।” जब तक यह शब्दकोश न बने, तब तक इस भाषा की कल्पना करना कठिन है। अभी अन्य प्रान्तों के भिन्न भाषा-भाषी हिन्दी ही सीखते थे, अब वे उसके साथ थोड़ी-थोड़ी सभी प्रान्तीय भाषाएँ सीखेंगे। हिन्दी बोलनेवाले, जिन्हें तमिल, कन्नड़, बँगला, मराठी, गुजराती आदि का ज्ञान नहीं—कोश देखकर शुद्ध हिन्दी बोलेंगे। यह भाषा हिन्दी होगी या और कुछ, इसे काका साहब श्री कालेलकर ने अच्छी तरह समझा है। इस भाषा का अपना नामकरण करते हुए उन्होंने

चाहता था कि उसीके अनुकूल आचरण करने के भाव पाठक या श्रोता के मन में उत्पन्न हों। आधुनिक साहित्य में कलात्मक आनन्द की ओर अधिक ध्यान है। किसी खूनी का चित्रण कर कवि हमें खूनी बनने के लिए नहीं कहता। संसार के बड़े-से-बड़े साहित्यिकों ने पाप को अपना विषय बनाकर अद्भुत कृतियों को जन्म दिया है। अस्तु, यदि स्त्री-पुरुष के पारस्परिक मनोभावों और आकर्षण-प्रत्याकर्षण का स्वस्थ वर्णन हो तो वह साहित्य भी समाज को उठानेवाला होगा।

काका कालेलकर को साहित्य-नियन्त्रण के सम्बन्ध में और किसी से कम चिन्ता नहीं। आज साहित्य पर न राजसत्ता का नियन्त्रण है, न धर्माचार्यों का। “जो लोग साहित्य का रस जानते हैं और समाज का हित चाहते हैं, इतिहास और आदर्श, दोनों की दृष्टि रखकर जो लोग समाज की प्रगति में मदद कर सकते हैं, ऐसे पुरुषों का ही नियन्त्रण साहित्य पर रहना चाहिए। दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे साहित्याचार्यों ने अपना यह कर्तव्य छोड़-सा दिया है और साहित्य-जगत् में मनमानी मचाने की ठान ली है।” हमें काका साहब से सहानुभूति प्रकट करने की आवश्यकता नहीं, हमारे यहाँ आचार्य लोग अब भी अधिकांश प्यूरिटन प्रवृत्ति के हैं। यह सभी जानते हैं कि अश्लीलता का कही आभास पाते ही वे धरती सिर पर उठा लेते हैं। परन्तु काका साहब को इन पर विश्वास नहीं। उन्हें आशा है, एक दिन साहित्यिक शासन की बागडोर उनके हाथों में आएगी; तब वह इन उच्छृङ्खल व्यक्तियों को गिन-गिनकर फाँसी पर लटकाएँगे।— “भारतीय साहित्य परिपद् जब पूर्ण रूप से विकसित होगी, तब साहित्य-शुद्धि संभालने की जिम्मेवारी कानून या धर्मतन्त्र के हाथों में नहीं रहेगी, साहित्य ही अपने क्षेत्र को संभाल लेगा।”

आदर्श साहित्य-निर्माण के लिए गांधीजी, बाबू राजेन्द्रप्रसाद, काका साहब आदि सभी ने उपदेश दिए हैं। इन्हें देखकर कोई अपरिचित यही समझेगा कि हिन्दी में एकदम पतित और समाज का अहित करनेवाला साहित्य रचा जा रहा है। इसका उत्तर एकलेख में देना सम्भव नहीं। साहित्यिकों के नाम गिनाने की अपेक्षा उनकी कृतियों का सुचारु विवेचन अधिक श्रेयस्कर होगा। तब तक अपने नेताओं की शुभ-कामनाओं के लिए अनुगृहीत होते हुए हम यही आशा करते हैं कि यदि उनका हमारे साहित्य से कुछ दिन और सम्पर्क रहा तो वे उसमें अपने अनेक सिद्धान्तों को कार्य-रूप में परिणत पाएँगे।

बना है—“स्वदेशी भाषा में हम बोलेंगे।”

भाषा मस्कार के साथ इन हिंदी के शुभेच्छुओं को हमारे साहित्य की उन्नति का भी ध्यान है। राजनीतिक सुविधाओं के लिए हिंदी की आवश्यकता नहीं। वाक्य गजेन्द्रप्रसाद के अनुसार 'राष्ट्र का प्राण साहित्य होता है और उम साहित्य का निर्माण वर्तमान समाज का बहुत बड़ा भेदक होता है।' तब हिन्दी-साहित्य की भुटियाँ दूर होनी ही चाहियें। काकाकालकर के अनुसार आधुनिक साहित्य का पूर्व भाग दूसरा की नकल का फल है। “उम अमाने का हमारा प्रारम्भिक साहित्य अनुकरणरूप ही था और अनुकरण तो निष्प्राण ही हो सकता है।” ‘हमारे साहित्य’ में किन किन साहित्यों की गणना है, नहीं मानूँ यदि हिन्दी की है तो उसके साथ जयाय है। ‘उम अमाने का हमारा प्रारम्भिक साहित्य एक ऐसा गोन वाक्य है कि समय ठीक से निर्धारित नहीं हो सकता। फिर भी भारतेन्दु से लेकर आज तक जो नय युग का जीवन है, उसमें उन्नत किसी भाग का साहित्य पर ऊपर का आशेष लागू नहीं होता। अन्य साहित्यिक जागृतिओं की भाँति हमारे यहाँ बाहरी साहित्यों के सम्पर्क से विचारा में नवीनता आई है, पुरानी रूढ़ियों का ध्वंस और नई धाराओं का निर्माण हुआ है। यदि यह अनुकरण है तो कोई भी जीवित साहित्य उससे नहीं बचा।

“पिछले थोड़े वर्षों में हिन्दी ने बँगला, मराठी, गुजराती और प्रांतीय साहित्यों से अपना साहित्य कम समृद्ध नहीं किया है। आदात-प्रदान में हिन्दी सिद्ध हो चुकी है। हम हिन्दी को जो कुछ देते हैं, वह उसे मशोषित कर देश के काने-कोन में पहुँचा देती है।” किसी नव-जाग्रत भाषा का साहित्य की उँचाई जल्दी आकाना आसान नहीं। जो कृतियाँ मोघ प्रसिद्धि पाती हैं, वे बहुधा पाठकों की पूर्व-निश्चित धारणाओं के बहुत-कुछ अनुकूल तथा कुछ-कुछ पुरानी रूढ़ियों का अवलम्ब लिये होती हैं। हिन्दी में अब भी इतने रूढ़िवादी हैं कि पत्रके कान्तिकारियों को उचित श्रेय या विज्ञापन नहीं मिला। जो हमारे यहाँ का वास्तविक मौलिक साहित्य है, उसकी समुचित ध्यानवीन धीरे-धीरे ही सम्भव है। परन्तु वैसा करना उसकी ओर से आँख मूंदकर राय देने में सम्भव नहीं, उसके लिए अध्ययन करना पड़ेगा।

हिन्दी भाषा में अरबी फारसी के प्रचलित शब्दों के अहिंकार के समान हमारे नेताओं ने हिन्दी साहित्य में अस्वीकृति का दुःस्थान भी देखा है। गांधीजी का बड़ा चले ता वह साहित्य-सम्मेलन में उस रस का त्याग ही मानवा दें। बड़ा चले तो गांधीजी ब्रह्मचर्य द्वारा सबसे सन्तति निग्रह करवा दें। परन्तु बड़ा चले ता भी यह हानिकार होगा। सम्मानानुकूल प्रवृत्ति की पुकारों का न मानने से बुरा फल मिलता है। असाधारणता का नियम मात्र पर लागू नहीं हो सकता। यदि साहित्य का सम्पर्क जीवन में रहता तो उसमें शृंगारी वर्णन अवश्य आएँगे। क्या हिन्दी, क्या मस्कन, बड़े-बड़े सत्तो ने अपने साहित्य में जीवन का पूरा चित्र उजागरे के लिए शृंगार का बहिष्कार नहीं किया। देखना केवल यह होता है कि यह शृंगार पतित मनोभावों का परिचायक तो नहीं है। हिन्दी के गुञ्जर साहित्य के लिए यह आक्षेप सही हो सकता है। तब वह जिस रस का वर्णन करता था,

सिर झुका देते तो आज का रूसी-साहित्य कहाँ होता ? हमारे देश में भी अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करके लोग अपनी शिक्षा का परिचय देना आवश्यक समझते हैं। जा वावूवर्ग इंग्लिस्तानी में बातचीत करता है, वह इसलिए कि अपनी भाषा में विचार करने की उसमें अक्षमता है। उसकी भाषा तीन कौड़ी की होती है और भाव दो कौड़ी के। हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए कुछ लोगों ने अंग्रेजी, अरबी, फारसी—सभी से शब्द भर लेने की सलाह दी है। जहाँ नये-नये अर्थों के शब्द खोजने पड़ें, वहाँ संस्कृत से न लेकर उन्होंने अंग्रेजी से लेने को कहा है। मानो अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्द खुद उसके घर के हों, उसने उन्हें लैटिन और ग्रीक से उधार न लिया हो। ग्रीक और लैटिन के शब्द अंग्रेजी की चलनी में छनते हुए हिन्दी में आएँ, उन्हें स्वीकार है; संस्कृत से हम शब्द लें, उन्हें स्वीकार नहीं।

जो भारत की जलवायु में पला है, उसे भारत की भाषा और संस्कृति अपनाती होगी, उसे भारत की ही महत्ता का स्वप्न देखना पड़ेगा। भारतीय भाषाओं को अभा-तीय ढाँचे में ढालने की चेष्टा पुरानी साम्राज्यवादी मनोवृत्ति का एक अवशिष्ट चिह्न है, हम उससे किसी प्रकार समझौता नहीं कर सकते। जिस तरह हम भारत की भूमि से अन्न-जल ग्रहण करते हैं, उसी तरह उसकी भाषा भी। जब हम देश से प्रेम करना सीखेंगे, तब उसकी भाषा से भी प्रेम करेंगे। न हम देश-प्रेम में किसी से समझौता करना चाहते हैं, न भाषा-प्रेम में। देश-प्रेम और भाषा-प्रेम दो अलग वस्तुएँ नहीं, एक हैं। (१९३६)



## राजनीतिक नेता और हिन्दी

राजनीतिक नेता लोग साहित्य पढ़ेंगे, इसकी आशा करना व्यर्थ जान पड़ता है। फिर भी साहित्य राजनीति में अज्ञान नहीं किया जा सकता। नेताओं की राजनीति गंदली होने पर उसका प्रभाव साहित्य पर भी पड़ सकता है, विशेषकर जब थोड़ा-बहुत शासनाधिकार हाथ में होना से वे बालका और नवयुवकों की शिक्षा के लिए उत्तरदायी भी हों। लंगी दंगा में शिक्षा और भाषा में हस्तक्षेप करने के पहले उन्हें साहित्य के विकास और उनकी भूतपाश का ज्ञान होना आवश्यक है। आज की भारतीय राजनीति समझौते पर निर्भर है। यह समझौता कभी 'इंडिया एक्ट' के लिए अंग्रेज सरकार से कुछ शर्तें, मनवाकर जाना है नहीं केन्द्रिय तथा प्रांतीय शासन में बँटवारा करने के लिए श्री जिन्ना से महाभाषाधी और श्री जनाहरान नेहरू की वानचीन के रूप में प्रकट होता है। हमने हिन्दी साहित्य में समझौता करना नहीं सोचा। हम समझौता नहीं, एका करार में विश्वास रखते हैं और यह एक एक स्वतंत्र अविभाजित राष्ट्र की भूमि पर ही हो सकता है। जो प्रांतीयता और साम्प्रदायिकता लेकर आगे बढ़ता है, वह राष्ट्रीयता का द्रोही है, उससे एक राष्ट्र-प्रेमी समझौता कैसे कर सकता है? इस उग्र राष्ट्रीयता की भावना में राजनीति में हिन्दी-साहित्य में निधाने सकते हैं। हमारे साहित्य का उद्भव ही एक विदेशी साम्राज्यवाद के प्रति विरोध से हुआ था और सदियों तक देश की भाषा और सस्कृति की रक्षा के लिए हमारे साहित्यिकों ने इस विदेशी साम्राज्यवाद से मोर्चा लिया है। यह मोर्चा नए ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भी जारी रहा है। इस दायता में भी हमने अंग्रेजी को क्यों नहीं अपनाया? इसलिए कि हमारी भाषा हमारी राष्ट्रीय चेतना की प्रतीक है। अरबी और फारसी के विरुद्ध इसी तरह तुलसीदास और भूपण ने हिन्दी की पनाह ऊँची रखी, इसलिए कि समाज के जीवित रहने का अर्थ हिन्दी का जीवित रहना भी था। यद्यपि हिन्दी का रूप बदलता रहा है लेकिन उसकी एकता नष्ट नहीं हुई। गुरुनानक की यह मनोवृत्ति रही है कि वे विदेशी सस्कृति और भाषा को जल्दी अपना लेते हैं क्योंकि उनका अपना सामाजिक जीवन नहीं वे बराबर होता है। फ़ार्सि के पूर्व के रूप में वहाँ के शिक्षित और धनी वर्गों में इसी प्रकार फ़ैल भाषा का बोलबाला था। रूसी भाषा को लोग गैदार्क और अर्थ-शास्त्रीय से हीन समझते थे। यदि वहाँ के साहित्यिक इस कुत्सित मनोवृत्ति के सामने

सिर झुका देते तो आज का रूसी-साहित्य कहाँ होता ? हमारे देश में भी अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करके लोग अपनी शिक्षा का परिचय देना आवश्यक समझते हैं। जा बाबूवर्ग इंग्लिस्तानी में बातचीत करता है, वह इसलिए कि अपनी भाषा में विचार करने की उसमें अक्षमता है। उसकी भाषा तीन कौड़ी की होती है और भाव दो कौड़ी के। हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए कुछ लोगो ने अंग्रेजी, अरबी, फारसी—सभी से शब्द भर लेने की सलाह दी है। जहाँ नये-नये अर्थों के शब्द खोजने पड़ें, वहाँ संस्कृत से न लेकर उन्होंने अंग्रेजी से लेने को कहा है। मानो अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्द खुद उसके घर के हों, उसने उन्हें लैटिन और ग्रीक से उधार न लिया हो। ग्रीक और लैटिन के शब्द अंग्रेजी की चलनी में छनते हुए हिन्दी में आएँ, उन्हें स्वीकार है; संस्कृत से हम शब्द ले, उन्हें स्वीकार नहीं।

‘‘जो भारत की जलवायु में पला है, उसे भारत की भाषा और संस्कृति अपनाती होगी, उसे भारत की ही महत्ता का स्वप्न देखना पड़ेगा। भारतीय भाषाओं को अभारतीय ढाँचे में ढालने की चेष्टा पुरानी साम्राज्यवादी मनोवृत्ति का एक अवशिष्ट चिह्न है, हम उससे किसी प्रकार समझौता नहीं कर सकते। जिस तरह हम भारत की भूमि से अन्न-जल ग्रहण करते हैं, उसी तरह उसकी भाषा भी। जब हम देश से प्रेम करना सीखेंगे, तब उसकी भाषा से भी प्रेम करेंगे। न हम देश-प्रेम में किसी से समझौता करना चाहते हैं, न भाषा-प्रेम में। देश-प्रेम और भाषा-प्रेम दो अलग वस्तुएँ नहीं, एक हैं।’’ (१९३६)

## भाषा और राष्ट्रीयता

इसी साल अभी ब्राम्ह के यहीने म थी रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कलकत्ता में महा-  
 त्वाति भवन का गितागम करने हुए बताया है कि बंगाल में भारतवर्ष के नये अस्तित्वान  
 में निम्न प्रकार योग दिया है। बंगाली भाषा, साहित्य, कला और संगीत—सभी का  
 उन्हें उल्लेख किया। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर भी अभिमान प्रकट किया कि  
 विदेशी सभ्यता का स्वागत करने में बंगाल सबसे प्रथम था। अंग्रेजी समाचारपत्रों में उनका  
 वक्तव्य इन प्रकार छपा था— *Bengal led India in welcoming European culture  
 to her heart.* यूरोप की सभ्यता अपनाते में बंगाल भारत का अग्रणी था। विदेशी  
 सभ्यता विदेशी शासन के ही साथ हमारे देश में आई है। स्वाभाविक था कि राष्ट्र-प्रेमी  
 व्यक्ति ने विदेशी शासन के समान उस सभ्यता में भी अपने-आपको दूर रखा। परन्तु  
 बंगाल में उसे स्वागतार्थ व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने उद्योग के लिए अंग्रेजी गिषा की  
 आवश्यक समझा। उस शिक्षा के प्रसारके साथ बंगाल के नये साहित्य का उद्भव भी हुआ।  
 इसीलिए अनेक बंगाली अपने साहित्य पर गर्व करते हुए उस शिक्षा पर भी गर्व करते हैं।  
 कि भी गुप्तानी गुप्तानी है उस पर अभिमान करना किसी को शोभा नहीं देता।

बंगाली विद्वानों के हृदय में विदेशी शिक्षा और सभ्यता के प्रति यह भावना  
 किन्हीं दृढ़ता से धर कर गई है, इसका एक ओर प्रमाण देखिए। बंग-साहित्य-सम्मेलन  
 के सभापति सुप्रसिद्ध विद्वान् डा० मुनीनिकुमार चटर्जी ने इसी बात का उल्लेख कर कहा  
 था— *उन्होंने उनके इन्वेन्टोर अनुगामी बंगाली इंग्रेजी शिक्षाएँ भारतेर गुरुत्वाधीन  
 हैं। और नहीं कि केवल घटनाक्रम में पड़कर अंग्रेजों के अनुगामी बंगाली को  
 अंग्रेजी शिक्षा से जोड़ो हो, बंगाल के अन्ततम भाषा-स्वविद् डा० चटर्जी ने उसी शिक्षा  
 की आवश्यकता बतलाते हुए कहा है— 'इंग्रेजी के बाद दिया अन्य कोन भाषा के ताहार  
 स्थाने बसादने गेने आमादेर मानसिक मति घटिबे।' दुनिया बड़ा बड़ा अंग्रेजी के प्रति  
 उनका प्रेम है कि उसके स्थान पर अगर किसी भाषा को खूने से मानसिक शक्ति को  
 मजबूतना है। ऐसे शब्द उसी व्यक्ति के मुह से निकल सकते हैं जिसकी परमुखापेक्षित  
 चरम माना को पहुँच चुकी हो।*

(१९३६)

## भाषा और साहित्य में पाकिस्तान

राष्ट्रभाषा को लेकर बहुत दिनों से विवाद चल रहा है। हिन्दीभाषी कहते हैं कि हिन्दी राष्ट्रभाषा होगी। बंगाली लोग बंगला को राष्ट्रभाषा बनाने में लगे हुए हैं। उर्दू-भाषी लोग उर्दू को भारत की 'आमफहम' और 'मुश्तक़ा ज़वान' मानते हैं। कांग्रेस के नेता कहते हैं, देश की 'कॉमन लैंग्वेज' हिन्दुस्तानी है। हिन्दुस्तानी नाम की कोई भाषा है या उस भाषा को अभी जन्म लेना है, यह स्पष्ट नहीं है।

राष्ट्रभाषा के बारे में इतनी बातें सुनकर लगता है कि हमारा भी एक राष्ट्र है। राष्ट्र के गठन के रास्ते में कोई अड़चन नहीं है, इसीलिए राष्ट्रभाषा की समस्या इतनी महत्वपूर्ण हो गई है। किन्तु कुछ दिन से देश में एक 'पाकिस्तान' की चर्चा होने लगी है। अखबारों को देखने से लगता है कि 'पाकिस्तान' हास-परिहास का विषय बना हुआ है। आश्चर्य की बात यह है कि जिन्होंने देश के अन्दर एक नये पाकिस्तान की कल्पना की है, वे उर्दू को भी राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं।

मुस्लिम लीग के नेता यह आन्दोलन करते हैं कि कांग्रेसी नेता उर्दू के शत्रु हैं और उनका उद्देश्य केवल हिन्दी-प्रचार करना है। इससे पहले मुस्लिम लीग के यही नेता कहते थे कि देश की राष्ट्रभाषा उर्दू है। अब उर्दू-प्रचार में अड़चनें देखकर या अड़चनों की कल्पना करके उन्होंने तय कर लिया है कि उनकी भाषा राष्ट्रभाषा न होगी, इसलिए राष्ट्र भी कायम न रहेगा! तब यह पाकिस्तान की चर्चा कोरा राजनीतिक आन्दोलन है या उसका और भी कोई आन्तरिक महत्त्व है? पाकिस्तान का 'गुल' खिलते देखकर अनेक मुसलमानों का चित्त चंचल हो उठा है। इस भारत-उद्यान में यह 'गुल' क्या अत्यन्त तुच्छ और निम्नस्तर पाकर ही नहीं खिला है? साहित्य और भाषा में मुसलमानों ने जो आन्दोलन छेड़ दिया है, उसे देखकर लगता है कि इस विप्लव की जड़ें धरती में बहुत गहरी चली गई हैं।

मध्य भारत में बहुत दिनों से हिन्दी और उर्दू का विवाद चलता रहा है। लखनऊ और दिल्ली को मुस्लिम संस्कृति का केन्द्र कहा जाता है। इस कारण देश के इस भाग में दरवारी संस्कृति के साथ भारत की एक अन्य व्यापक और अधिक प्राचीन संस्कृति का संघर्ष स्वाभाविक हो गया। किन्तु हिन्दीभाषी समझते हैं कि इस तरह का संघर्ष उन्हीं के साहित्य

म पाया जाता है, अन्य प्रांतों में भाषा-सम्बन्धी कोई समस्या है, ऐसा उन्हें नहीं मालूम होता। किन्तु वनमान कान में अन्य प्रांतों में भी भाषा की लेकर सघर्ष चल रहा है, वह मध्य चाहे तेलुगु, चाहे भीमा हो, उसके अस्तित्व में इन्कार नहीं किया जा सकता। बंगाल के हास्य रत्नामक पत्र में भाषा की उर्दू का नया विकास पहचानने की बात लेकर अनक ध्वज प्रकाशित हुए हैं। किन्तु मौलवी फजलुलहक का मद्रिमण्डन वापस होने के बाद बना भाषा की विवृत करने की चेष्टा और जोरा से होने लगी है। अब वह चर्चा हाम-परिहाम का विषय नहीं रह गई। देश में आन्दोलन द्वारा उसका प्रतिकार आवश्यक हो गया है।

वर्गीय-साहित्य-सम्मेलन में डॉ० मुनीनिकुमार चट्टोपाध्याय ने इस बारे में कई बातें कहा हैं। उन सब पर विचार करने से भाषा समस्या की गम्भीरता समझ में आ जाती है। आजकल के अरबी-फारसी प्रेमी अनेक मुस्लिम नेताओं की तुलना में भारत के आदि-मुस्लिम आक्रमणकारी भी इतने साम्प्रदायिक नहीं थे। डा० चट्टोपाध्याय ने कहा है, "वे बुद्धिमान या धूर्तिध्वसी थे, किन्तु उद्बान-सिक्कन या भाषा-ध्वसी वे नहीं थे।" उन्होंने वनमा मूल भाषा में प्रकाशित न करके उसका अनुवाद देशी भाषाओं में प्रकाशित किया था। किन्तु आज साम्प्रदायिकता इतनी प्रबल हो गई है कि कलमा तो दरकिनार, साहित्य का कलम की भाषा में लिखने का प्रयत्न हो रहा है।

तुर्कों से अरबी-फारसी शब्दा का बहिष्कार हुआ, फारसी से अरबी शब्दा का बहिष्कार हुआ, यह सब साम्प्रदायिक मुस्लिम नेताओं को दिखाई नहीं देता। वे 'पैन इस्लामिज्म' की बातें करते हैं। किन्तु अन्य मुस्लिम देशों की राह छोड़कर उन्होंने अपनी नई राह पकड़ी है, यह बात व भूल जाने हैं। भाषा के अलावा भावों में भी साम्य होता है। भारत के साम्प्रदायिक नेता भाव और भाषा दोनों ही क्षेत्रों में, अन्य स्वाधीन मुस्लिम राष्ट्रों से एकदम अपरिचित हैं। डा० चट्टोपाध्याय ने बंगाल में यह भाषा ध्वसी कुचैष्टा देखकर सख्त कहा है, "पश्चिम के मुसलमान लेखकों में अधाधुन भाषा में अरबी-फारसी शब्द भरने की प्रवृत्ति को रोकने की बात चली है। क्या केवल बंगाल भाषा में उस रीति को नया रूप देकर ग्रहण किया जायगा और पाच करोड़ में ऊपर जनता की दुर्लभ सहायण एकता को स्वेच्छा से विलुप्त कर दिया जायगा?"

मध्य भारत में उर्दू को सहज और सरल बनाने के लिए, उसे अरबी-फारसी के शब्द-जाल से मुक्त करने के लिए आन्दोलन हो रहा है। इस आन्दोलन के सूत्रधारों में अनेक प्रगतिशील लेखक हैं। वे कोशिश कर रहे हैं कि साहित्य यथाम्भव जन साधारण के लिए बोधगम्य हो। लोकप्रिय मुबोध साहित्य रचने के लिए उसे अरबी-फारसी के कठिन शब्द-जाल से मुक्त करना ही होगा। सभी लोग प्रयत्न करते हैं कि उनकी भाषा का प्रचार और प्रसार हो। किन्तु अध साम्प्रदायिकता का जाल अरबी-फारसी के शब्द समेटकर बहुसङ्ख्यक जनता के लिए भाषा का दुर्बोध बना देता है। इस तरह का प्रयत्न मुस्लिम साम्राज्य के वैभव के दिना में न हुआ था। आज यह प्रत्यन्त इतना समर्थ क्यों

हो गया है ?

मुस्लिम साम्राज्य में पुराने हिन्दी-साहित्य का चरम विकास हुआ था। तुलसीदास, सूरदास आदि कवि उसी युग में हुए थे। और उस युग के साहित्यिक थे रहीम, रसखान जैसे मुसलमान कवि। वे हमारे देश के, हमारी भाषा के कवि हैं। क्या उनकी ख्याति किसी भी मुसलमान लेखक के चाहने योग्य नहीं है ? सर इकबाल का हम नाम सुनते हैं। रहीम के दोहे और रसखान के छन्द गाँवों के हिन्दू और मुसलमान दोनों के ही कंठ में बसे हुए हैं। क्या वह लोकप्रियता पाकिस्तान के जन्मदाता के लिए दुष्प्राप्य नहीं है ? मुस्लिम साम्राज्यकाल में मुस्लिम साहित्यकार अपनी भाषा में अपना कोई स्मृति-चिह्न न चाहते थे। साम्राज्य का नाश होने पर अनेक लोगों के हृदय में यह इच्छा हुई कि वीते वैभव का एक सांस्कृतिक चिह्न सुरक्षित कर लिया जाय। उर्दू भाषा का विकास तभी सम्भव हुआ जब मुस्लिम साम्राज्य का अधःपतन आरम्भ हो गया। उस युग के साहित्य में सामाजिक और राजनीतिक पतन के अनेक लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं। जन-साधारण की भाषा छोड़कर दरवारी साहित्यकारों ने एक नई दरवारी भाषा का आविष्कार किया। उसे खूब मार्जित करके उन्होंने उसे अपना सांस्कृतिक चिह्न मान लिया। भाषा में ऊपरी चमक-दमक थी। किन्तु उस भाषा में देश के प्राणों की गूँज नहीं थी। कविता का प्रधान गुण हो गया चमत्कार-प्रदर्शन। उस चमत्कार-प्रदर्शन की भाषा हुई उर्दू। इस चमत्कार-प्रियता ने ही सर्वनाश की राह दिखाई। इस सर्वनाश से कोई भी 'चमत्कार' उनका उद्धार न करेगा, यह बात उनके दिमाग में नहीं आई। ईरान की पतन-कालीन साहित्यिक परम्परा को अपनाकर मुसलमान दरवारी कवियों ने अपने साहित्य का विकास किया। आज अरबी-फारसी शब्दों का मोह त्यागने की बात आने पर उन्हें लगता है कि उनके गौरव का इतिहास नष्ट हो जायगा। मुस्लिम साम्राज्य के वैभवकाल में मुसलमान साहित्यकारों ने लोकभाषा का व्यवहार करके कितनी शक्ति प्राप्त की, यह बात इनके दिमाग में पैठती ही नहीं।

देश में जो लोग पाकिस्तान चाहते हैं, वे पाकिस्तान लेकर भी सन्तुष्ट न होंगे। वे अब भी विगत साम्राज्य की मधुर स्मृति में निमग्न हैं। उनकी समझ में उस स्मृति के साथ अरबी-फारसी शब्दों से लदी हुई भाषा का कोई आध्यात्मिक सम्बन्ध है। इसलिए राजनीति में जो पाकिस्तान के समर्थक हैं वे भाषा का भी विभाजन करने को तैयार हैं। वे सोचते हैं कि उनकी नई भाषा समय बीतने पर देश की अन्य भाषाओं पर अपना आविपत्य कायम कर लेगी। इसीलिए अरबी-फारसी संस्कृति को आधार बनाकर उन्होंने भारत की अनेक भाषाओं में विध्वंस-कार्य आरम्भ कर दिया है।

हमने अरबी, फारसी या अन्य विदेशी शब्दों का वहिष्कार किया हो, ऐसा नहीं है। हिन्दी-साहित्य की लोकप्रिय और धर्मग्रन्थ के समान पूजनीय पुस्तक रामायण में अनेक विदेशी शब्द हैं। हिन्दी के किसी भी उत्तरदायी साहित्यकार ने कभी भी यह नहीं कहा कि हमारी भाषा केवल संस्कृत शब्द लेकर समर्थ बनेगी। लेकिन अस्वाभाविक रूप से

हिन्दी में अपरिचित शब्द भरने से विकासक्रम भग होगा, यह बात भूलना न चाहिए। भारत की अधिकांश भाषाओं का एक सामान्य सांस्कृतिक आधार है। थोड़े परिश्रम से लोग हिन्दी, बंगला, मराठी आदि भाषाएँ समझ सेते हैं, कारण यह कि इन भाषाओं में बहुत से शब्द सामान्य हैं। देश की एकता के सूत्र में बाँधने के लिए भाषा की यह एकता प्रधान साधन है। अपनी कुचेष्टा से अनेक जन इस एकता पर आघात कर रहे हैं किन्तु जितना आघात करेंगे, उतना ही देश की भाषाओं का परस्पर साम्य-बोध और भी दृढ़ होगा। तभी देशवासी हम राष्ट्रघातक प्रयत्न को समूल नष्ट कर देंगे। (१९४१)

## हिन्दी गद्य-शैली पर कुछ विचार

अज से लगभग सत्तर वर्ष पहले भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने नये हिन्दी गद्य की नींव डाली थी। वैसे ब्रजभाषा से भिन्न नई हिन्दी लिखने का प्रयास और भी पहले आरम्भ हो गया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि अब तक नये हिन्दी गद्य के सौ वर्ष बीत चुके हैं और अब इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि साधारण गद्य के लिए हम एक साफ-सुथरी शैली बना सके हैं या नहीं। हिन्दी गद्य के विकास में जो दो-तीन मार्ग-चिह्न स्पष्ट दिखाई देते हैं, उनमें सबसे पहले तो आधुनिक हिन्दी के जन्मदाता भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र और उनके सहयोगियों ने ही हिन्दी गद्य-शैली पर एक अमिट छाप डाली है। इस शैली पर विचार करते हुए दो बातें सभी आलोचक मानते हैं। पहली तो यह कि इसमें एक ऐसी जिन्दादिली है जो वाद के गद्य में प्रायः नहीं मिलती। दूसरी यह कि इस भाषा में परिष्कार की जरूरत है और अपने तात्कालिक रूप में वह शैली आज ग्रहण नहीं की जा सकती।

इतदोनों बातों पर कुछ ठहरकर विचार करना आवश्यक है। भारतेन्दु-युग के लेखकों की शैली में जिन्दादिली क्यों है और वाद के गद्य से वह लोप क्यों हो गई? इसका कारण कुछ लोग यह बतलाते हैं कि भारतेन्दु और उनके सहयोगी बहुत गम्भीर चीजें नहीं लिखते थे। इसलिए उनकी शैली में हँसी-मजाक की गुंजाइश ज्यादा रहती थी। आगे चलकर हमारी शैली में भाव-गाम्भीर्य आया और इसलिए यह जरूरी हो गया कि इस गहराई में जिन्दादिली डूब जाय। एक बात ध्यान देने की यह है कि भारतेन्दु-युग के लेखक इस पीढ़ी के लेखकों की तुलना में संस्कृत के अधिक निकट थे। उनके सामने हिन्दी गद्य की कोई विकसित परम्परा न थी और इसलिए होना तो यह चाहिए था कि संस्कृत के शब्दों की भरमार से उनकी शैली बोझिल बन जाती, लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। इसके सिवाय यह बात भी सही नहीं है कि उस युग में गम्भीर आलोचना नहीं लिखी गई। उस युग के मासिक पत्रों की जिल्दों में सैकड़ों सुन्दर आलोचनात्मक निबन्ध आज भी सुरक्षित हैं। (यात्री जहाँ उन्हें रद्दी में बेच नहीं डाला गया या जिल्दों में दीमक नहीं लग गया।) उनका संकलन करके अब तक किसी ने उन्हें प्रकाशित नहीं किया, इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारे प्रकाशकों को है। उन निबन्धों से आज के बहुत ही मामूली आलोचनात्मक निबन्धों की



विद्वान् क आचार्य हिन्दी के चाहे त्रिम रूप की कल्पना करें, भारत के इतिहास में उसके हमारे ही रूप का रचना और संवारना शुरू कर दिया है। अभी तक हम हिन्दी की जनता की भाषा कहते आये थे। लेकिन जनता का ६० फीसदी भाष हमारी इस हिन्दी में उपरिविस्तृत था। अब समय आ गया है कि ६० फीसदी जनता गिनित हाथर अपनी भाषा को पहचान और उसका रूप संवारन में हाथ बढ़ाए। गिना का प्रसार एक एसी बाढ़ होगी जो हमारी भाषा और साहित्य के उद्योग पर एक बार छा जाएगी और यहाँ की तमाम त्रिनासकरी प्राप्त प्राप्त को बहा ल जायेगी। व दक्षिणाराधण त्रिनारा नाम लेकर हम हिन्दी का राष्ट्रभाषा मानने जाते हैं, हिन्दी बानेंगे और निर्योगे भी। भाषा विद्वान् के आचार्यों ने चौका लाकर, छूत-याक का बड़ा विचार करते हुए, जो तन्मम लिखड़ी पकाई थी उसमें अब दक्षिणाराधण भी हिम्मा बटायेगे। यह मानी हुई बात है कि ऐसा होने पर आचार्य लोग यह विवाद करेंगे कि इन असम्भूत और अशिक्षित व्यक्तियों ने हमारा गुड साहित्य और गुड मसृति के बीके को छूत कर डाला। दक्षिणाराधण को बहुत दिन तक भुला रखा गया है। साम्राज्यवाद ने उनके पट को ही नहीं मारा, मसृति के साम पर भी उह यनाशक्ति भुला मारने की कोशिश की है। गिगित और जाग्रत होने पर जनता मकीर छीवकर चीत ने बाहर नहीं रगो जा सकेगी। वास्तव में वही मसृति की निर्माता है, वही तद्रूप और तन्मम रूपों का, ससृति और प्राकृत रूप का मानुभाषा और राष्ट्र-भाषा के प्रयत्न का समाधान करनेवाली है। उस समय देखना होगा कि हिन्दी की गद्य-गनी आज की-सी ही रहनी है या उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन होगा है।

उपर जा कुछ कहा गया है, उसका यह अर्थ नहीं है कि हिन्दी के बड़े लेखका ने बोलचाल की भाषा को आधार मानकर अपनी गैली को रचा ही नहीं है। प्रेमचन्द के उपन्यास इस बात की जीती-जागती प्रमाण है कि बोलचाल की भाषा को आधार मानते थे कितनी लोकप्रिय रचनाएँ की जा सकती हैं। कविता के क्षेत्र में श्री मैथिलीशरण गुप्त, दिनकर, नरेंद्र, मुमन, गिरिजाकुमार, नेदारनाथ, नेरानी आदि न सरन और सुबोधशीली अपनापन की चेष्टा की है। मुद्र-काल में और उसके बाद कुछ लेखका ने मंचेत होकर इस तरफ ध्यान दिया है और उन्होंने छायावाद के उत्तरकाल की शैली को बदला है। कोई नहीं कह सकता कि इस प्रयत्न में उनकी व्यक्तनाशक्ति कम हो गई है। वास्तव में यह शक्ति कम होने के बदेने और बढ़ गई है।

पुगनी मौनी की जड़ता सबसे बड़ा नाटक में अवरनी है। नाटक की संरचना सबसे अधिक बालबाल की स्वाभाविकता पर निर्भर है। हिन्दी में त्रिन लोगो ने नाटक लिखने का रिवाज तोड़ा है, उन्होंने भी इस स्वाभाविकता को बार-बार ठुकराया है। यदि नाटक की व्यावस्तु ऐतिहासिक या पौराणिक हुई, तब ता लेखक अपने लिए छूट मानता है कि वह अधिक-से-अधिक अस्वाभाविक गैली अरना सकता है। बात ससृति पात्रों की नहीं है, तन्मम रूप नाटकों में भी स्थाप्य जा सकते हैं। अस्वाभाविकता की जड़ सम्प्र-गम्य उलझे हुए वाक्या की रचना है। त्रिम लेखक को रामक का थोड़ा भी ज्ञान होगा,

यह तुरन्त परस लेगा कि जिस नाटक के वाक्य धोलने में अभिनेता हाँफ जाय और दर्शक उसके आदि-अन्त का ही पता लगाता रह जाय, वह नाटक कभी सफल नहीं हो सकता। दुर्भाग्य से अस्वाभाविक वाक्य-रचना को कठिन समझकर उससे पाठ्य-क्रम की गोभा भी बढ़ाई जाती है। एक नाटक इण्टरमीडिएट के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। इसको अनानक बीच से खोलने पर विक्रममित्र नाम का पात्र यह कहते देखा जाता है—

“यवनों के आक्रमण से जब मालव और सिन्धुगण मूल स्थान के निकट नहीं ठहर सके और मगध की केन्द्रीय शीर्षशक्ति ने भी अपने कर्तव्य का पालन जब नहीं किया तब उन्हें सिन्धु के दक्षिण मध्यनिका और कर्कोटक में शरण लेनी पड़ी। मेघवाहन क्षारवलि और पितामह वसुमित्र ने सेना-साधन में उनकी सहायता कर उन्हें उन्हीं स्थानों में स्थिर किया और आगे बढ़कर यवनों के उस पार शाकल तक पहुँचा दिया।”

इन वाक्यों में ‘उन्हें, उन्हीं’ और ‘स्थान, स्थिर’ के जोड़े दर्शनीय हैं। यदि नाटककार आँख खोलकर लिखने के साथ कान खोलकर अपने वाक्य सुनते भी जायें तो विक्रममित्र से ऐसे अतृप्त वाक्य न कहलाएँ। उसी पृष्ठ पर विक्रममित्र महाशय पुनः कहते सुने जाते हैं—

“इन मालवों की सनातन वैदिक विधान में जो आस्था थी, उसने पितामह वसुमित्र को तो प्रभावित किया ही, जैन क्षारवलि तो उससे इतना प्रभावित हुआ कि उसने मालव नहेन्द्रादित्य के साथ अपनी पुत्री सौम्य दर्शना का विवाह कर दिया।” इस वाक्य में ‘आस्था’ शब्द पर ध्यान दीजिये। यह ‘आस्था’ कर्ता है, उसने वसुमित्र को प्रभावित किया। लेकिन आगे कर्ता से बदलकर करण बन गई और जैन क्षारवलि उससे प्रभावित हो गया। कर्ता, करण के उलभाव में वाक्य अशुद्ध और अस्वाभाविक बन गया। छपने पर उसने चार पंक्तियाँ घेरी हैं, यह अलग से।

एक सामाजिक नाटक लीजिए। इसमें नीतिराज ‘एक समाजवादी युवक; उम्र चौबीस वर्ष’ और विमला ‘एक युवती, उम्र बाईस वर्ष’ आधुनिक विज्ञान पर बहम कर रहे हैं। नीतिराज कहता है—

“आखिर आप रमणी है न ? जिस दिन आप कमल-कुसुम के समान वर्तमान सामाजिक पानी की तह से ऊपर उठ आएँगी, उस दिन यह कह देंगी कि त्यागवाद महान् नहीं हो सकता। जिस त्याग का ढिंडोरा पीटा जा रहा है वह या तो समाज में इस समय जो धर्म प्रचलित है उस धर्म के भय से किया जा रहा है या वह समाज में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सारे दान-पुण्य, सत्कर्म कहे जानेवाले कार्य इन्हीं दो कारणों के परिणाम हैं। सारा सामाजिक संगठन अवैज्ञानिक नहीं है। जो चीज वैज्ञानिक नहीं है, वह महान् हो ही नहीं सकती। मिस विमला, इस युग के दो सबसे बड़े तत्त्ववेत्ता हैं—डार्विन और कार्ल मार्क्स। दोनों ग्रहणवादी हैं।”

बाईस साल की लड़की के धीरे की प्रशंसा करनी होगी। लगभग पूरा पृष्ठ सुन जाती है और एक बार भी उस चौबीस साल के युवक को नहीं टोकती। नीतिराज ने भी, मालूम होता है, कॉलेज में हिन्दी के नाटक ही पढ़े हैं। इसलिए विमला से कहता है—

'बाहिर जाय समझी है न।' क्या हा अर्थात् जो कि बौद्ध के लिये मरना हिन्दू विद्यापियों के लिए ऐसे ही सुन्दर मरणों का प्रयास किया करें। 'सामाजिक पानी की तह' से ऊपर उठाना भी कमान है। एक वाक्य में नीतिराज भवनानों का प्रयोग हुआ है 'जाति' का धर्म प्रवर्गित है उस धर्म के अर्थ में, '—बार-बार धर्म की दुहाई देना समझा है। 'समाज के प्रतिष्ठित न्याय प्राप्त करना' आदि ऐसे दुहाई हैं जो नाटकों को वाक्य रचना में ठट्ठेन मारते हैं। नीतिराज ने डाकिन और बाग मार्ग को ही अपना नहीं दिया, वाचवाच की हिंसा पर भी पानी फेर दिया है।

नाटका में इस तरह की चीन्ही प्रयोग दित नहीं बन सकती। वाङ्मय-रचना में पानित करने पर भी इस तरह के नाटक सिद्धी के समर्थ का उद्धार नहीं कर सकते।

आलोचनात्मक सम्मीर चिन्तन का नाम पर हूर तरह की वाक्य रचना धर्म बन जाता है। एक उदाहरण देना ही काफी है। सामाजिक वाक्य के समझ में परतन विराधी ध्वनियों का मरण पाना है। मान्य उद्योग मज्जीव चिन्तन कर यह स्मरण कर देना है कि उनमें वह सप्रिय रूप में भाग ल रहा है और यह कि वह सामाजिक समर्थ एक स्थिर बन्तु नहीं है बल्कि 'निम्नान और परिवर्तनीय है।' इस बात का और भी मरण का मे कहा जा सकता था और इस तरह का वाक्य रचने के लिए सम्मीर चिन्तन का दुहाई नहीं दी जा सकती। वाक्य के बेइतपन का कारण सम्मीर चिन्तन नहीं, अपर्याप्त 'that' का अर्थ अनुवाद है, यह कि यह।

मार्ग में सिद्धी की मध्य चीन्ही को संभारने के लिए वाक्य-रचना पर ध्यान देने समझे ज्यादा जरूरी है। निम्नतम समय हम वाक्य को सुनने भी आएँ या पितृत्व का उन्हें डार से पढ़कर सुने-सुनाएँ जिन्हे कि उसका अध्यात्मिक प्रकाश प्राप्त मान्यता जान और हम उनमें आत्मन्य सुनार कर लें। इसके अलावा समाज की हर भाषा के पुष्ट गद्य का आधार आम जनता की वाचवाच की भाषा रही है। हमें अपनी गद्य-शैली को स्वयं और समय बनाने के लिए फिर यही आधार ज्ञापन करना है। ऐसा करने से हिन्दी भारत की दूसरी भाषाओं से दूर न जा पड़ेगी। यह भय इसलिए पैदा होता है कि हम भारतीय भाषाओं के विकास को ही प्रगत समझ बैठे हैं। यह विवादास्पद बातों को नहीं लौट रहा है बल्कि तद्भव रूप को अपनाता हुआ भाषा के प्राकृत रूप को बर्बर कर रहा है—प्राकृत, अपने मौखिक और व्यापक अर्थ में। भारतेन्दु और प्रेमचन्द की इस शैली विकास की ओर खिंच करती है। हिन्दुस्तान की अधिकांश जनता हिन्दी बोलती है या उसे समझती है। लेकिन हम अपनी गद्य-शैली को उस जनता के बोलने-समझने के लिए पर यह गद्य-शैली बदलती। नई पीढ़ी के लेखकों पर विशेष रूप से यह भार है कि वे अपनी चीन्ही को इस तरह लें कि निम्न प्रसार में हमने सहायता मिले और हमें कोटि-कोटि जनता के सम्पर्क से बचने भी अपनी भाषा और साहित्य को समृद्ध करे।

(१९४५)

## राष्ट्रभाषा हिन्दी और हिन्दू राष्ट्रवाद

हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने की माँग कुछ नई नहीं है। भारतेन्दु से लेकर अब तक इस माँग का आधार यही रहा है कि हिन्दी जनता की भाषा है; बोलने, लिखने और समझने में वह सरल है; हिन्दुस्तान की अधिकांश जनता अभी भी उसे बोलती और समझती है। अपनी माँग को पुष्ट करने के लिए हिन्दी-भाषियों ने जनता को अपनी कासौटी बनाया था। उन्होंने राष्ट्रभाषा की समस्या को जनतांत्रिक ढंग से ही सुलझाने का प्रयत्न किया था। लेकिन इधर कुछ वर्षों से यह परिस्थिति बदल रही है। साहित्य-सम्मेलन के मंच से हिन्दी-हिन्दुस्तान का नारा लगाकर अपनी भाषा के प्रसार को संकुचित करने और उसके सहज विकास को रोकने का प्रयास किया गया है। एक तरफ तो हम गर्व के साथ कहते रहे हैं कि हिन्दी आम जनता की भाषा है जिसके बोलनेवाले सभी जातियों और धर्मों के लोग हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रीयता के नाम पर साम्प्रदायिकता का जहर फैलानेवाला यह नया हिन्दू राष्ट्रवादी दल भाषा की धर्म के साथ जोड़कर हिन्दी को जनता की भाषा के पद से हटा देना चाहता है। ऊपर से देखने में मालूम होता है कि ये हिन्दू राष्ट्रवादी हिन्दी के समर्थक हैं, जो उसका प्रसार और विकास चाहते हैं, वास्तव में इनसे बड़ा शत्रु हिन्दी का कोई दूसरा नहीं हो सकता। राष्ट्रों की तरह भाषा का विकास भी जनतांत्रिक आधार पर होता है, जनता की उपेक्षा करके फासिज्म को आधार बनाने पर राष्ट्र की तरह भाषा का भी सत्यानाश होना अनिवार्य है। हिन्दी का सत्यानाश करना तो विघाता के लिए भी कठिन होगा। विघाता की इच्छाओं के एकमात्र टीकाकार ये हिन्दू-राष्ट्रवादी उसके विकास में कुछ देर के लिए बाधा जरूर डाल सकते हैं।

राष्ट्रभाषा के साथ हिन्दू-राष्ट्रवाद के गठबन्धन को सबसे ताज़ी मिसाल श्री रविशंकर शुक्ल की लिखी हुई एक पुस्तक है जिसका नाम है—‘हिन्दीवालो, सावधान !’ ‘इस्लाम खतरे में है’ की तरह लेखक ने हिन्दू-धर्म खतरे में है, कहकर हिन्दीवालों को सावधान करने की चेष्टा की है। जहाँ-जहाँ ‘इस्लाम खतरे में है’ का नारा लगाया गया है, वहाँ-वहाँ साबित हो चुका है कि इस्लाम के बदले किसी की ज़मीन-जायदाद ही खतरे में थी जिसे बचाने के लिए यह खतरे की घंटी बजाई गई थी। इस बहाने जायदाद की

हियाजन हो नहीं पाती और जनता इस दंग बिया का पहला नंबर जायदाद का जमाना करती ही दम लेती है। लेखक ने इतिहास का साक्षी न मानकर खुलेआम धर्मों का आदर्श मानकर उसके पीछे चलने की गिफारिंग की है। प्रत्यक्ष हिन्दू-मुसलमानों के आर में जिनका का विरोधी होते हुए भी हृदय से उनकी को अपना आदर्श मानता है। काप्रेम जो देश के स्वाधीनता सपना के सार में वह तीव्र व प्रतिक्रियावादी सनाओ के समान ही झूठा प्रचार करना है। रविशंकर शुक्ल का अभियोग है कि काग्रम न हिन्दुओं के साथ 'योग विश्वास' धान किया है।' (हिन्दीवाचो पाठधान परिशिष्ट, पृ० ६३)। हिन्दुओं का विश्वास-धान तो कोई हिन्दू विना हो हा सकता था क्योंकि उसके दुभाष से हिन्दुओं का ऐसा कोई नेता नहीं है जामि० बिन्ना में दखल में सक। (उ०३०) हिन्दुओं में ऐसा नेता पैदा करना व लिए जरूरी है कि हर हिन्दू के हृदय में राष्ट्रियता की परम्परा को निर्मल कर दिया जाए। इसलिए काप्रेमी नयाओ व लिए सबसे न यह दावा किया है कि उन्होंने 'कम-अर मनमा वाचा और कमणा यह निष्ठ करने की चाटा की है, और अब भी कर रहे हैं, कि व हिन्दू नहीं हैं।' (उ०५०) काप्रेम पर अहिन्दू हान का अभियोग लगाने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि काग्रम की प्रेरणा से जा अनवादी परम्परा कायम हुई है, उसमें निहित स्वार्थों की रक्षा की जाए। इस हिन्दू प्रेम के पीछे पूजोवाद और जमींदारी प्रथा का प्रेम छिपा हुआ है जो उसके में इस तरह की दर्जाने पया कराना है—'५० मेहू की हिन्दुस्तान का नाम में चिह्न है क्योंकि उसमें हिन्दू नाम जुड़ा हुआ है। इसलिए वह चाहते हैं कि देश का 'इशिया' ही बना जाए और उस मामल में गांधीजी 'इनकी दोष धनधया रहे हैं' (परिशिष्ट, पृ० ६८)। ५० मेहू के भाषणा का उतना भी मुनसी है और वह अच्छी तरह जानती है कि व इशिया गद्द का प्रयोग करते हैं या हिन्दुस्तान का। लेकिन फामिस्म का आधार मूठ हाता है और हिन्दू राष्ट्रवाद एक फामिस्ट विचारधारा है।

हिन्दू और मुस्लिम प्रतिक्रियावादी एक-दूसरे व कितने निकट हैं, इसकी एक मिथान देखिए। दोनों ही बहुसं-संस्कार की एक हिन्दू सम्प्रदायवादी सरकार के रूप में चलता करते हैं। एक इतना ही है कि मुस्लिम प्रतिक्रियावादी उसे हिन्दू सरकार पहले से ही मानते हैं और उनके हिन्दू भाई उसे ऐसी बनाना चाहते हैं। शुक्लजी कहते हैं कि 'हमारा मसाल मेहू सरकार का हिन्दू सरकार बताता और समझता है—जबकि वास्तव में अथवा असल में वह हिन्दू सरकार नहीं है। ऐसी भ्रांति का कारण यही रहने या अविश्वस्य में उत्पन्न हान दिया जा सकता। (उ०५०) सारे सभार में चर्चित और उनके पिछू ही ऐसा प्रचार करत हैं और बी० बी० सी० दुनिया भर में विज्ञापित करती है कि ५० मेहू की हिन्दू सरकार मुसलमानों का नाग कर देना चाहती है। लेकिन सभार में सब चर्चित, पीछा खा नून या उनके हिन्दू कर्तव्य (रविशंकर शुक्ल जैसे) ही नहीं हैं। दुनिया का हर जननवादी न तो मेहू सरकार को एक हिन्दू सम्प्रदायवादी सरकार मानता है और न उसे हान देना चाहता है।

हिन्दू राष्ट्रवाद की खुनी घोषणा इस प्रकार है—

“हिन्दुस्तान एक हिन्दू राष्ट्र हो जिसका राज-धर्म हिन्दू धर्म हो और जिसमें नव प्रमुख पदों पर हिन्दुओं और अमुस्लिमों की नियुक्ति हो ! ऐसा कोई व्यक्ति जो स्पष्ट रूप से हिन्दू धर्म न मानता हो, हिन्दुस्तान सरकार का प्रधान नहीं हो सकता ।” (उप०) स्पष्ट रूप से हिन्दू धर्म मानने का मतलब क्या है ? यह कि जो मुसलमानों को हिन्दुस्तान में रहने दे, वह पूरा हिन्दू नहीं है । “इस्लाम धर्म के किसी अनुयायी को हिन्दुस्तान में नागरिकता के अधिकार नहीं मिल सकते” और “अल्पसंख्यक के किसी झूठे नाम पर पाकिस्तान के फिथ कॉलम को स्वच्छन्द नहीं छोड़ा जा सकता” (पृ० ६६) । यह है सच्चे हिन्दूपन की कसौटी ! अगर लीगी नीति धर्मान्वित है तो क्या हम नहीं हो सकते ? अगर वे एक बार कुएँ में गिरे हैं तो हम सौ बार गिरेंगे ! हिन्दू राष्ट्रवाद की वीरता इसी प्रकार की है ।

इस हिन्दू राष्ट्रवाद को भाषा के क्षेत्र में लागू करना मुश्किल नहीं है । जैसे हिन्दुस्तान का हर मुसलमान पाकिस्तान का फिथ कॉलम है, वैसे ही हिन्दी में आया हुआ अरबी-फारसी का हर शब्द फिथ कॉलम है, जिसे निकाल बाहर करना चाहिए । बात कुछ बहुत मौलिक नहीं है क्योंकि मराठी में वीर सावरकर भी यह काम कर चुके हैं । उन्हें सफलता कितनी मिली है, यह मराठी का कोई अखबार उठाकर देख लीजिए ।

कठिनाई तब पैदा होती है जब जनता के व्यवहार का प्रश्न सामने आ जाता है । हिन्दू राष्ट्रवादियों के दुर्भाग्य से इस देश की जनता हिन्दू-मुसलमान शब्दों की पहचान नहीं कर पाती । फल यह होता है कि इस जनता से प्रेरणा पाने वाले कवि और लेखक भी हिन्दू-मुस्लिम शब्दों का भेदभाव भूल जाते हैं । इसलिए हिन्दू राष्ट्रवाद के इन आचार्य ने जनता का झगड़ा ही खत्म कर दिया है । आपने लिखा है—“जनता तो भेड़ों के झुण्ड के समान है, उसे नेताओं ने जिवर हाँक दिया उधर चल दी... जनता को पेटभर खाने और तनभर कपड़े के सिवाय किसी और चीज की चिन्ता नहीं होती ।” (मूल पुस्तक, पृ० ८५) ।

यह तर्क भी अधिक मौलिक नहीं है । जब हिन्दुस्तान में आजादी का आन्दोलन चला, तब अंग्रेज साम्राज्यवादियों ने भी यही दलील पेश की थी कि हिन्दुस्तान की आम जनता को तो खाने-पहनने से मतलब है; कुछ थोड़े से असन्तुष्ट लोगों ने उसे आजादी का नाम लेना सिखा दिया है । अगर उन्हें पकड़कर जेल में बन्द कर दिया जाय तो वह आजादी का हल्ला भी एक दिन में खत्म हो जाएगा, इस विचार के अनुसार जनता को भेड़ और अपने को भेड़िया समझनेवालों ने काम भी किया लेकिन उसका फल क्या हुआ, इसे सारी दुनिया जानती है । श्रीमान् रविशंकर शुक्ल जनता को ‘लैंग्वेज कान्वास’ करने के फेर में स्वयं जनता की शक्ति से ‘अनकान्वास’ हो गये हैं ! लेकिन अंग्रेज बहादुर की शक्ति पर आपका विश्वास अड़िग है ! भारतीय जनता तो अपनी भाषा के प्रति कभी जागरूक नहीं रही लेकिन ‘भला हो अंग्रेज बहादुर का जिसने फारसी को हटाकर प्रान्तीय भाषाओं को प्रतिष्ठित किया’ (पृ० ५८) । गोया लार्ड मैकाले ने हिन्दी का सर्वनाश करने

हिफाजत हो नहीं पाती और जनता इस ठग विद्या की पहचानकर आषाढ़ाद को जन्म करके ही दम लेती है। लेखक न इतिहास का साक्षी न मानकर खुले-आम धमकियाँ का आदस मानकर उसके पीछे चलने की सिफारिश की है। प्रत्येक हिन्दू-राष्ट्रवादी ऊपर में जिन्ना का विरोधी हाते हुए भी हृदय में उही की अपना आदस मानता है। कांग्रेस और देश के स्वाधीनता संग्राम के बारे में वह राग के प्रतिक्रियावादी नवाजी के समान ही भूटा प्रचार करता है। खिन्नकर गुप्त का अभिप्राय है कि कांग्रेस न हिन्दुओं के साथ 'घोर विश्वासघात किया है।' ('हिन्दीवालो मावयान' परिशिष्ट, पृ० ६७)। हिन्दुओं का विश्वासपात्र तो कोई हिन्दू जिन्ना ही हो सकता था लेकिन लखनू क दुर्भाग्य से 'हिन्दुजा का ऐसा कोई नेता नहीं है जामि० जिन्ना में टक्कर ले सके।' (उ०) हिन्दुजा न ऐसा नेता पैदा करन के लिए जरूरी है कि हर हिन्दू के हृदय में 'गण्टीयता की परम्परा को निमल कर दिया जाए। इसलिए कांग्रेसी नेताओं के लिए लेखक ने यह दावा किया है कि उन्होंने 'कम भर मनमा, वाचा और कम्पा यह मिद्ध करने की चपटा की है और अब भी कर रहे हैं कि वह हिन्दू नहीं है।' (उ०) कांग्रेस पर अहिन्दू होने का अभिप्राय लगाने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि कांग्रेस की प्रेरणा से जा जनवादी परम्परा कायम हुई है, उससे निहित स्वार्थों की रक्षा की जाए। इस हिन्दू प्रेम के पीछे पूँजीवाद और जमींदारी प्रथा का प्रेम छिपा हुआ है जो लेखक से इस तरह की दलीलें पैदा कराना है—प० नेहरू को हिन्दुस्तान का नाम से चिढ़ है क्योंकि उसमें हिन्दू नाम जुड़ा हुआ है। इसलिए वह चाहते हैं कि देश को 'इंडिया ही कहा जाए और इन मामलों में गांधीजी 'उनकी पीठ बगलपा रहे हैं' (परिशिष्ट, पृ० ६८)। प० नेहरू के भाषणा का जनता भी सुनती है और वह जकड़ी तरह जानती है कि वह इंडिया शब्द का प्रयोग करने हैं या हिन्दुस्तान का। लेकिन फासिज्म का आधार मूठ होता है और हिन्दू राष्ट्रवाद एक फासिस्ट विचारधारा है।

हिन्दू और मुस्लिम प्रतिक्रियावादी एक-दूसरे के कितने निकट हैं, इसकी एक भिगाल दलील। दोनों ही नेहरू-सरकार की एक हिन्दू सम्प्रदायवादी सरकार के रूप में कल्पना करते हैं। परन्तु इतना ही है कि मुस्लिम प्रतिक्रियावादी उसे हिन्दू सरकार पहले से ही मानते हैं और उनके हिन्दू भाई उसे ऐसी बनाता चाहते हैं। मुकलजी कहते हैं कि 'हमारा समार नेहरू सरकार को हिन्दू सरकार बनाता और समझता है—जबकि वास्तव में अर्थात् असल में वह हिन्दू सरकार नहीं है। ऐसी भावि का कारण नहीं रहने या भविष्य में उत्पन्न होन दिया जा सकता।' (उ०) मानें समार में चर्चित आर उनके पिछ्छू ही ऐसा प्रकार करते हैं और बी० बी० गी० दुनिया भर में विनाशिन करती है कि प० नेहरू की हिन्दू सरकार मुगलधारा का नाश कर देना चाहती है। लेकिन समार में सब चर्चित, फीराज साँ नून या उत्तर हिन्दू नगराल (गविाकर गुप्त जैसे) ही नहीं हैं। दुनिया का हर जनतवादी न तो नेहरू-सरकार का एक हिन्दू सम्प्रदायवादी सरकार मानता है और न उस होने दना चाहता है।

हिन्दू राष्ट्रवाद की खुली घोषणा इस प्रकार है—

“हिन्दुस्तान एक हिन्दू राष्ट्र हो जिनका राज-धर्म हिन्दू धर्म हो और जिनमें सब प्रमुख पदों पर हिन्दुओं और अभुम्बिनों की नियुक्ति हो। ऐसा कोई व्यक्ति जो राष्ट्र रूप से हिन्दू धर्म न मानता हो, हिन्दुस्तान सरकार का प्रधान नहीं हो सकता।” (पृ०) राष्ट्र रूप से हिन्दू धर्म मानने का मतलब क्या है? यह कि जो मुसलमानों को हिन्दुस्तान में रहने दें, यह पूरा हिन्दू नहीं है। “इस्लाम धर्म के किमी अनुयायी को हिन्दुस्तान में नागरिकता के अधिकार नहीं मिल सकते” और “अलमगार के किमी कूटे नाम पर पाकिस्तान के फ़ायर कालम को स्वच्छन्द नहीं छोड़ा जा सकता” (पृ० ६६)। यह है सच्चे हिन्दूपन की कसौटी! अगर लींगी नीति धर्मान्य है तो क्या हम नहीं हो सकते? अगर वे एक बार कुएं में गिरे हैं तो हम भी चार गिरेंगे! हिन्दू राष्ट्रवाद की बीरता इसी प्रकार की है।

इस हिन्दू राष्ट्रवाद की भाषा के क्षेत्र में लागू करना मुश्किल नहीं है। जैसे हिन्दुस्तान का हर मुसलमान पाकिस्तान का फ़ायर कालम है, वैसे ही हिन्दी में आया हुआ अरबी-फारसी का हर शब्द फ़ायर कालम है, जिसे निकाल बाहर करना चाहिए। बात कुछ बहुत मौलिक नहीं है क्योंकि मराठी में बीर मावंगकर भी यह काम कर चुके हैं। उन्हें सफलता कितनी मिली है, यह मराठी का कोई अगरार उठाकर देख लीजिए।

कठिनाई तब पैदा होती है जब जनता के व्यवहार का प्रश्न सामने आ जाता है। हिन्दू राष्ट्रवादियों के दुर्भाग्य से इस देश की जनता हिन्दू-मुसलमान शब्दों की पहचान नहीं कर पाती। फल यह होता है कि इस जनता में प्रेरणा पाने वाले कवि और लेखक भी हिन्दू-मुस्लिम शब्दों का भेदभाव भूल जाते हैं। इसलिए हिन्दू राष्ट्रवाद के इन आचार्य ने जनता का झगड़ा ही गलत कर दिया है। आपने लिखा है—“जनता तो भेदों के भुण्ड के समान है, उसे नेताओं ने जिवर हाँक दिया उधर चल दी... जनता को पेटभर खाने और तनभर कपड़े के सिवाय किमी और चीज की चिन्ता नहीं होती।” (मूल पुस्तक, पृ० ८५)।

यह तर्क भी अधिक मौलिक नहीं है। जब हिन्दुस्तान में आजादी का आन्दोलन चला, तब अंग्रेज साम्राज्यवादियों ने भी यही दलील पेश की थी कि हिन्दुस्तान की आम जनता को तो खाने-पहनने से मतलब है; कुछ थोड़े से असन्तुष्ट लोगो ने उसे आजादी का नाम लेना मिला दिया है। अगर उन्हें पकड़कर जेल में बन्द कर दिया जाय तो वह आजादी का हल्ला भी एक दिन में खत्म हो जाएगा, इस विचार के अनुसार जनता को भेट और अपने को भेड़िया समझनेवालों ने काम भी किया लेकिन उसका फल क्या हुआ, इसे सारी दुनिया जानती है। श्रीमान् रविशंकर शुक्ल जनता को ‘लैंग्वेज कान्फ़स’ करने के फेर में स्वयं जनता की शक्ति से ‘अनकान्फ़स’ हो गये हैं! लेकिन अंग्रेज बहादुर की शक्ति पर आपका विश्वास अडिग है! भारतीय जनता तो अपनी भाषा के प्रति कभी जागरूक नहीं रही लेकिन ‘भला हो अंग्रेज बहादुर का जिसने फारसी को हटाकर प्रान्तीय भाषाओं को प्रतिष्ठित किया’ (पृ० ५८)। गोया लार्ड मैकाले ने हिन्दी का सर्वनाश करने



न किए कुछ उठा रखा था और उनकी चलाई हुई शिक्षा-प्रणाली के लिए हिन्दुस्तानियों का उनका कृतन हाना चाहिए। अपनी जनता को गाली कि वह भेड़ है और अंग्रेज के लिए गावासी कि वह इन्साफमन्द है—यह है हिन्दू राष्ट्रवाद का मज्जा रूप।

हिन्दी भाषी जनता को भेड़ियाघसान बनाकर इस लेखक ने हिन्दी के बड़े-से-बड़े साहित्यिकों का भी उसमें शामिल कर लिया है। यह हिन्दी के लिए भय की बात है कि उसके बड़े-बड़े साहित्यकारों ने बोलचाल की भाषा को अपना आधार बनाया है। रविशंकर गुप्त की मर्मभूमे इस बोलचाल की भाषा को अपनाने का मतलब है उर्दू कोष की जननात। निम्ना है—“उर्दू कोष केवल हिन्दी शब्द-सागर में ही नहीं समायो हुआ है, वह व्यंग्य में भी बहुत दूर तक हिन्दी पत्र और पुस्तकों के पन्नों पर विद्यमान है, और हिन्दी के बड़े-से-बड़े साहित्यिकों की बोलचाल में भी विद्यमान है, बल्कि या कहिये, बोलचाल में ही भी अधिक प्रबल रूप से विद्यमान है” (पृ० ३)। इस बोलचाल के खतरे में बचन के लिए आपने यह वाक्य प्रमाण रूप में रखा है—“कण्ठगतऽपि प्राणे यावन्ती न वनेन। आर टीका की है—‘संस्कृत की इस अखण्ड पीढ़ी में आज हिन्दी है। आज हिन्दी का बहो काम करना है जो संस्कृत ने पानी में और अपभ्रंश न किया है’ (पृ० ६)। संस्कृत की अखण्डता से अपभ्रंश कैसे पदा हो गई, अपने अद्भुत भाषा-विज्ञान का प्रकाश इस प्रश्न पर भी डाल देने तो हिन्दीवाले और गावधान हो जाने।

लेखक को हर जगह हिन्दी हारती हुई और उर्दू जीतती हुई दिखाई देती है। उर्दू की जीत का कारण उसका विगुडतावाद यानी हिन्दी शब्दों के बहिष्कार की प्रवृत्ति बताई गई है। जब उस विगुडतावाद को हिन्दी में लागू करने का हठ किया गया है। वास्तव में हार न हिन्दी रही है, न उर्दू, हार रहे हैं दोनों तरफ के विगुडतावादी जो दोनों को बोलचाल के जस्मो फीसदी शब्दों के आधार पर नजदीक आने देखकर हाय-हाय करके छाती पीट रह हैं। उनका यह काम उचित भी है क्योंकि दोनों के पास आने की वे बिलकुल नहीं राह पाते। लेखक ने कई जगह ऐसे शब्दों की सूची बनाई है जिन्हें वह हिन्दी से निकाल देना चाहता है। पृ० २२-२३ पर ऐसे शब्दों की सूची देखने लायक है। इसमें तलाग, मूगल, वनग, गोगुल, पंदावार, दाग, दद, रोशनी, हजम करना, सल्ल, मज्जीक, महमान, कभरबन्द, बीबी, दिल, किताब, अन्दर, तरफ, इन्कार, खरीदना, आवाज देना, खून जमे शब्द हैं जिन्हें हिन्दू संस्कृति के लिए धातक बनाया गया है। पाठक स्वयं साचें कि हिन्दी भाषा का इन शब्दों से खतरा है या रविशंकर गुप्त जैसे उसके समर्थकों से।

इन शब्दों के हिन्दी पर्यायवाची तो और भी मनाहर हैं। किताब के लिए केवल ‘पाथी’ निमना चाहिए और बीबी के लिए ‘बहू’।

हिन्दीवालों की भावधान करनेवाले इन मज्जन में अगर कोई पूछे कि क्या आपन यह ‘पाथी’ अफीम खाकर निम्नी भी तो कोई बेजा सवाल न होगा। ऐसे एक-दो नहीं पचीसो शब्द हैं जिन्हें आपने हिन्दी से निकालने की सलाह दी है लेकिन जो दूसरी जगह आरके ‘संवेक बाराग’ दिमाग पर भी मवार हो गए हैं। मिगाल के लिए पृ० ३३

पर आप 'किना' शब्द निकाल देने की सलाह देते हैं लेकिन पृ० १५६ पर हिन्दी शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए 'किले' की ही शरण ले बैठे हैं।

इसी सूची में आपने 'वच्चा' शब्द भी रखा है जिसे हिन्दी से आप विदेशी समझकर निकलना चाहते हैं ! पाठकों को ऐसी अपार भूर्खता पर विश्वास न हो तो इस पुस्तक के पृष्ठ ३४ की दूसरी लाइन देख लें। लेकिन बाहू रे वच्चो, शावाण ! पृ० १७६ पर जब लेखक महाशय हिन्दी रक्षा संघ स्थापित करने में लगे थे, तभी आठवीं पंक्ति में तुम भी आकूदे ('हिन्दी जनता में प्रबल आन्दोलन किया जाय कि वह अपने वच्चों को.....' इत्यादि)। इसी तरह 'आवादी' का आप विरोध करते हैं लेकिन पृ० २५ पर अवध को 'आवाद' करते हैं। आदत आपको पसन्द नहीं लेकिन पृष्ठ २७ पर आप खुद उसके 'आदी' दिखाई देते हैं। जादू वह जो सिर पर चढकर बोले और वह आपके ही नहीं, हिन्दी-उर्दू दोनों के विशुद्धतावादियों के सिर पर चढकर बोलता है। जितना ही बोलचाल के शब्दों से पर भाड़ते हैं, उतना ही वे चिपकते जाते हैं !

पृ० ४०-४१ पर एक दूसरी सूची है, उन शब्दों की जो बोलचाल में प्रचलित नहीं हैं। इनमें बगावत, कुर्बानी, गद्दार, हिमायत, उस्ताद, हमदर्दी, नाराज, नाखुश, नर्दी जैसे शब्द भी हैं। पूछना चाहिए कि आप किस देश के रहनेवाले हैं जो इन शब्दों को बोलचाल का नहीं समझते। आपका दुराग्रह कितना बढा हुआ है, यह इस बात से जाहिर है कि आपने 'देशदूत' जैसे पत्र और वेडव बनारसी जैसे लेखक को भी—जिन पर हिन्दी-उर्दू के मामले में उदार होने का कलंक कभी नहीं लगाया जा सकता—उर्दू-परस्तों की पाँत में बिठा दिया है !

आप पर प्रतिक्रियावादी होने का आरोप लगाया जायगा, यह आप पहले से ही जानते हैं। इसलिए पृ० ८३ पर आपने गर्व से घोषणा की है—'हमें एक बार नहीं सौ बार प्रतिक्रियावादी कहलाना स्वीकार है।' उसके बाद यह भी मुक्तकठ से स्वीकार किया है कि 'ये सब बातें पुनरुत्थान की भावना से प्रेरित हैं।' (उप०) बोलचाल के शब्दों के आने से आप भाषा को कृत्रिम मानते हैं; अधिक संस्कृतनिष्ठ होने से हिन्दी स्वाभाविक हो जायगी ! (पृ० ८८-८९)

एक सुभाव मार्को का है। अगले प्रान्तीय चुनाव के लिए हिन्दी जनता को अभी से तैयार करना चाहिए ! (पृ० १७६)। राष्ट्रीय मुसलमानों और कांग्रेस के नेताओं पर यह विपक्षमन उस चुनाव की तैयारी का ही एक अंग है। ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो देश को जनतन्त्र की तरफ बढ़ने से रोककर साम्राज्यवाद की पाली-पोसी हुई व्यवस्था कायम रखना चाहते हैं। इनके प्रचार में एक ऐसी हिन्दी को स्थान दिया गया है जिसका भारत की जनता से यथासम्भव कम सम्बन्ध है ! जितना सम्बन्ध हिन्दू राष्ट्रवाद का हिन्दू जनता से है, उतना ही हिन्दी के इनसमर्थकों का हिन्दी से। कलम पकड़ते चार दिन नहीं हुए कि तुलसीदास, भारतेन्दु और प्रेमचन्द—सभी की परम्पराएँ उलटने को तैयार हैं। मानो ईश्वर के यहाँ से हिन्दी की जायदाद का वनामा कराके लीटे हैं ! हिन्दी के

उस भूत बड़े लेखक का नाम बताएँ जिसने इन भिदातों को मानकर रचना की हो। भाषा के निर्माता कुछ अच्छे प्रतिप्रियावादी नहीं हो सकते। उसके निर्माता हिन्दुस्तान के व गेड़ी किसान, मजदूर और साधारण लोग हैं जिनकी बोसचाल की भाषा से आपको अमलों बनना दिखाई देता है। हिन्दी बोलनेवालों ने जिन शब्दों को अपना लिया है, उन्हें तमाम सुमनसाला की कल्पना करके भी हिन्दी में नहीं निवाला जा सकता। यह मस्तिष्क की 'गपटुता' जनता के अर्थ से उत्पन्न हुई है क्योंकि एक बार अंग्रेजों से टकराते-ते-ते के बाद यह जनता उनक दमो नकवाला स डरकर चुप रहनेवाली नहीं है। जिस समय हिन्दी के व वधित हिमायती एक दूगर की कोमते रह हैं, उस समय यही जनता मना, 'वदिलता' बार कारखाना में एक मिली जुली भाषा गटती रही है जिसकी उमेक्षा काना डाला में ने किसी के लिए भी सम्भव नहीं है। हिन्दी जपर है, इसलिए कि वह अपनी स्वाधीनता के लिए लटनेवाली जनता की मजीब भाषा है। (१९४८)

## हिन्दी का 'संस्कृतीकरण'

बहुत से लोगो का विचार है कि संस्कृत ने मृत भाषा का रूप इसलिए ले लिया कि पंडितों ने उसे व्याकरण के नियमों से जकड़ दिया था। परन्तु व्याकरण और भाषा की सजीवता में कोई ऐसा अन्तर्विरोध नहीं दिखाई देता कि संस्कृत की मृत्यु के लिए व्याकरण को दोषी ठहराया जाय। अगर आज की जीवित भाषाओं को लें तो देखेंगे कि वे व्याकरण से कम अनुशासित नहीं हैं और किसी हद तक तो उनके व्याकरण में ऐसी विशेषताएँ मौजूद हैं जो तर्कबुद्धि को स्वीकार ही नहीं होती। कौन नहीं जानता कि अंग्रेजी-व्याकरण बारह साल पढ़ने के बाद भी भाषा में अशुद्धियाँ रह जाना एक साधारण बात है। फिर भी अंग्रेजी संसार की सबसे सजीव भाषाओं में है। संस्कृत की अपेक्षा उसमें स्वच्छन्दता कहीं कम है। संस्कृत वाक्य-रचना में आप शब्दों का हेर-फेर कर सकते हैं—'एतद् मम पुस्तकम्' को मम, पुस्तकम्, एतद् किसी भी शब्द से प्रारम्भ करके लिख सकते हैं। लेकिन अंग्रेजी में 'दिस इज माई बुक' को 'इज दिस माई बुक' लिखकर देखिये, कितना अन्तर हो जाता है ! और कहीं 'बुक माई इज दिस' लिख दीजिये, तब तो वाक्य का कचूमर ही निकल जायगा ! छोटे बच्चे अंग्रेजी सीखते हुए अक्सर इस तरह की वाक्य-रचना करते हैं। और बच्चे ही क्या, बालिग भी हिन्दी से अंग्रेजी शुरू करते हैं, तो आरम्भ में यही गलती करते हैं। अगर कोई समझे कि 'रामः रामो रामाः' की रटन्त से अंग्रेजी ही अच्छी तो उसे हिन्दी के 'राम से, राम में, राम पर' आदि रूप याद रखने चाहिएँ और बिहारी भाइयों की 'ने' सम्बन्धी कठिनाई को न भूल जाना चाहिए।

इसका यह मतलब नहीं है कि संस्कृत, हिन्दी और अंग्रेजी दोनों से सरल है और इसलिए उसे राष्ट्र-भाषा बना देना चाहिए। ऊपर की बातें कहने का उद्देश्य यह है कि संस्कृत के मृत भाषा बनने का कारण व्याकरण नहीं कुछ और है। दरअसल संस्कृत कुछ गिने-चुने शिक्षितों की भाषा रह गई थी और लोक-प्रचलित भाषा से इतनी दूर चली गई थी कि आम जनता के लिए वह दुरूह हो गई थी। उसका व्याकरण कितना भी सरल किया जाता, वह 'जीवित' भाषा का पद न पा सकती थी। अक्सर अनेक ग्राम-भाषाओं का व्याकरण संस्कृत से कम कठिन नहीं होता, वल्कि उससे भी अधिक गहन और विस्तृत होता है, फिर भी ग्रामीण बच्चे बिना सूत्र धोखे हुए ही व्याकरण के अनुसार नित्य वाक्य-

रचना करते रहते हैं। फ्रांस और स्पेन के कुछ भागों में 'वास्क' नाम की ऐसी ही बोली आज भी प्रचलित है। उसका व्याकरण लैटिन से भी दुरुह बताया जाता है लेकिन लैटिन सम्बन्ध के पद को प्राप्त हुई और वास्क अब भी जीवित है। वास्क के लिए एक कहानी प्रसिद्ध है कि खुदा ने शैतान पर गुस्सा होकर उसे वास्क-व्याकरण याद करने के लिए भेजा। सात साल तक परिश्रम करने के बाद भी शैतान कोरा-का-कोरा ही वापस लौटा।

व्याकरण की कठिनाई नई भाषा सीखनेवालों को महसूस होती है। जो उसे नियम-प्रति बोधन है उनके लिए व्याकरण 'सीखने' का प्रश्न नहीं उठता।

इसी प्रकार काग दखकर भी कोई हिन्दी, उर्दू या हिन्दुस्तानी में बोलें नहीं करता। काफी दिन तक काश-निर्माण में परिश्रम करने के बाद अधिकांश लोग यह समझ गए हैं कि हिन्दी, उर्दू, हिन्दुस्तानी की समस्या का चाहे जो हल हो, वह कम-से-कम कोश-निर्माण में हल नहीं हो सकती।

लेकिन कोशकार भला यह कब माननेवाले हैं। उनके लिए अमर-कोश पहले है, कालिदास बाद की। उनके लिये भाषा के बोलनेवाले बाद की हैं, उनकी कोश रचना पहले है। जनता क्या बोलेगी, वैज्ञानिक, डॉक्टर, वकील, राजनीतिक नेता, आदि-आदि किन शब्दों का प्रयोग करेंगे इस अदृश से दुबले कोशकार मोटे मोटे कोशों का निर्माण करने में लगे हैं। काग रचना में ऐसी राह नहीं रख जाते जो व्यवहार में आते हैं बल्कि ऐसे गन्दे गन्दे रास्ते आते हैं जो व्यवहार में लाये जायेंगे। अगर 'जनता' की समझ और व्यवहार का ठिक कीजिये तो जनता का मूख और अशिक्षित बहकर भाषा के क्षेत्र से उन्हे निकाल बाहर किया जाता है और कोशकार दत्तचित्त होकर फिर अपने गन्दे-निर्माण में लग जाते हैं।

छोटे से बड़े तक अनेक पंडित-महापंडित कई वर्षों से इस काय में लगे हैं। हिन्दी में लग हैं और उर्दू में लगे हैं और इनके माथ बेंगना जैसी अथ भाषाओं में भी लग हैं। इस हिसाब से हम इस 'भारतीय साहित्य का कोश-युग' कह सकते हैं।

काशकार अपन निर्दोष काय में लग रहते और उनके एकान्त चिंतन में बाधा देने की कोई जरूरत नहीं अगर उनकी कोश रचना आम जनता पर लागू करने की न होनी। जब उनके इस काय का सरकारी या अर्द्ध-सरकारी सम्बन्ध मिल जाता है, तब यह खतरा पैदा हो जाता है कि कचहरी डाकघरों में हमें ऐसे कागज-पत्र पढ़ने को मिलेंगे जिन्हें सम्बन्ध के लिए भारी श्रम का काम साथ लेकर चलना पड़ेगा।

✓ कल्पना कीजिये, एक 'अपमजित' व्यक्ति अपने अपमान पर अभिभोग लगाता है और 'अपमजक' का मित्र 'अपमज' करता है। आप अशक्त में 'प्रत्यास्थान' करते हैं। बकौल 'अयय' की अभ्युक्ति करता है। इन ही में एक 'अपमज' का मुकुटमा और पग होता है लेकिन मुकुटमा का 'लम्बन' हो जाता है या 'विकृष्ट' हो जाता है। वादका 'अभिज्ञा' 'राज्य-पक्ष' देता है जिससे फिर 'व्यवन' विकल्प होता है। इसके बाद 'पुनर्वाद' के 'अयय' की नौबत आती है और तब 'अपचारक' में कहा जाता है कि 'इस

वाद का व्यय वाद के परिणाम का अनुसरण करेगा ।'

यदि आप हिन्दी-प्रेमी हैं, तो इन शब्दों पर कुछ देर तक विचार कीजिए । यदि अंग्रेजी और हिन्दी पर्यायवाची शब्दों के बिना आप इनका मतलब समझ लेंगे तो 'वीर सराही तोहि' हमें कहना पड़ेगा । ऊपर के शब्द उस कोश से लिये गये हैं जिसे उत्तर प्रदेश की सरकार और टिहरी राज्य की सहायता से नागरी-प्रचारिणी सभा तैयार कर रही है । वानगी के तौर पर कुछ शब्द २ जून, १९४८ की 'अमृत वाज्जार पत्रिका' में छपे हैं । यदि नागरी-प्रचारिणी सभा ऐसी ही हिन्दी का प्रचार करना चाहती है तो उसे लोगों को धोखे में न डालकर अपना नाम बदल डालना चाहिए ।

इसमें संशय है कि ये शब्द संस्कृत में भी उसी अर्थ में प्रयुक्त होते हैं जो कोशकारों को अंग्रेजी के आधार पर अभीष्ट हैं । यह संस्कृत और हिन्दी दोनों के साथ अन्याय है । इस तरह की भाषा को यू० पी० सरकार, टिहरी राज्य और नागरी-प्रचारिणी सभा तीनों मिलकर और उन-जैसे दस-पाँच नहीं चला सकते; क्योंकि ये शब्द जनता के गले से उतरेंगे नहीं । कोशकार भले ही आज जनता को अग्निहित कहकर उसकी बोलचाल की भाषा की उपेक्षा करें, लेकिन यह कोश-भाषा आखिर बुलवाना तो उसी जनता से है !

हिन्दी के इस 'संस्कृतीकरण' से हिन्दी का राष्ट्रभाषा बनना तो दूर, उसका प्रांतीय भाषा के रूप में भी लोकप्रिय रहना कठिन हो जाएगा । यह हिन्दी की सेवा करना नहीं, उसका गला घोटना है । हर हिन्दी-प्रेमी को इनका विरोध करना चाहिए ।

यह बात नहीं है कि संस्कृत से शब्द लेना एकदम बन्द कर देना चाहिए । लेकिन शब्द लेना एक बात है, भाषा को संस्कृतमय बना देना दूसरी बात । इन कोशकारों की नजर में हिन्दी का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है । उसमें जो कुछ है और होना चाहिए, वह केवल संस्कृत का ! इनके लिए मध्यकाल से लेकर अब तक केवल सांस्कृतिक पतन ही होता आया है और जितनी जल्दी सतयुग की ओर लौट चलें, उतना ही अच्छा । यह हठधर्म कुछ नया नहीं है । जब गोस्वामी तुलसीदास ने 'रामचरितमानस' रचा था और पंडितगण उनकी रचना को 'भदेस' कहकर हँसते थे, तब से यह क्रम चला आ रहा है । यूरोप में इस प्रकार लैटिन के आगे 'वल्गर टंग' का मज़ाक उड़ाया जाता था, लेकिन वही 'भदेस' भाषाएँ संसार की सबसे समृद्ध भाषाएँ बन गईं । वह पद हिन्दी भी प्राप्त करेगी, लेकिन कोश-रचना और संस्कृतीकरण के रास्ते पर चलकर नहीं ।

ऊपर की कोश-निर्मित शब्दावली सरल शब्दों में भी लिखी जा सकती है । लेकिन कोश-प्रेमियों का कहना है कि सरल शब्दावली पारिभाषिक कहाँ हुई ! इस तरह हिन्दी को इतना पारिभाषिक बनाया जाएगा कि वह 'भाषा' न रहकर केवल 'परिभाषा' रह जाएगी !

हैदराबाद के स्वनामधन्य निज़ाम साहब उर्दू के लिए ऐसे ही कोश बनवा चुके हैं । उनसे उर्दू कितनी लोकप्रिय हुई है, इस बात पर हिन्दी-प्रेमियों को विचार करना चाहिए ।

‘मारे देश मे ममभी जाण’—इस बहाने हर भाषा के कठमुन्ने अपनी भाषा की जान लेने पर तुने हुए हैं।

पश्चिमी प्रगति की अत्यन्त प्रगतिशील सरकार के ‘स्वराष्ट्र विभाग’ न सरकारी कामों के लिए ‘व्यवहार्य परिभाषा’ का पटना भाग प्रकाशित किया है। सरकार की तरफ से छापी हुई चीज है इसलिए उनमें नुकताचीनी की गुंजाइश भी कम है। आज ‘परिभाषा’ का ज़ा मतलब लगाने हा, कम सरकार न उसका अर्थ ‘महदावली’ किया है, यह याद रखें।

उसके स्वयंसेवाओं में डा० सुनीतिकुमार चटर्जी का प्रसिद्ध नाम भी है। भूमिका में बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश प्रचलित होने हुए भी उसकी जगह ‘जान’ और ‘गुण’ में गणनित्य और ‘महागणनिक’ गढ़ रहे गए हैं। रवीन्द्रनाथ के बंगाल में यह नवित्व पदावली रखी जा रही है। इसी प्रकार ‘अदानत’ गढ़ बोली सम्मानपूर्ण नहीं, ‘Not dignified enough’ समझा गया है। इसलिए उसकी जगह धर्माधिकरण सजाया गया है, जिसका नाम सुने ही अपराधियों के छक्के छूट जायें।

भूमिका में भाषा-विज्ञान की यह अप्रुव बात भी कही गई है—‘Bengali Hindi Marathi and the rest now depend upon Sanskrit—they are not free to utilise their own basic elements’ यानी बँगला, हिन्दी, मराठी वगैरह को खुद अपने भीतर से गढ़ निर्माण करने की छूट नहीं है। उह संस्कृत का ही मूढ़ जोहना पड़ेगा।

हिन्दुस्तान में भाषा-विज्ञान ने कितनी प्रगति की है, यह ऊपर के इस एक वाक्य में प्रकट है, जिस पर डा० सुनीतिकुमार चटर्जी के हस्ताक्षर हैं।

भाषा की प्रचारिणी व कोणकाश की मेवा में हम इस बर्गीय ‘परिभाषा’ से कुछ गढ़ पग करने हैं। भाषा लोग अलग अलग न जान क्यों परिश्रम कर रहे हैं, हिन्दी-बँगला जब दोनों संस्कृत में लनी है तब उनमें भेद कहा रहा? आप्ते के शब्द-कोष पर हिन्दी बँगला लिपिकर क्यों नहीं चालू कर देने? बातचीत देविए—

‘भाषापाठ, महा व्यावहारिक (नया है विशेषण न समझ लीजिएगा।), स्वयंजि, नाविन्यकार, कुरी यावक (यह वातव धोनेवाला है।), आत्ययिक, चक्रचर नियामक, दाहवचन आधिकारिक (डैरी में सम्बंध है), दुष्टति विमर्श विभाग, उप-आयुक्तक उप प्राणिक पवित्रण महाध्यक्ष, उप आराम्याध्यक्ष, एध-अधिकर्ता, नाहिन-उपदेष्टा, प्रमोत्साह पन्द्रिक, नाधिक रक्षक, लेख-प्रापक, राजस्व-करणिक, विश्वयिक, विनिष्ट-मुद्रितक-उपदेष्टा परिमाण करणिक अवसर, अन्त शुक्ल कृत्यक, शिल्प व सम्पन्न मन्त्र, राष्ट्र-प्रमानिकोपाधिकार, कन्या प्रणयि, पूर्ण पत्र (एकमप्रेस चिट्ठी) इत्यादि।

यह महदावली के निर्माण ज्ञान है कि उस बंगाल में कोई न समझेगा। इसलिए नोत्रवानों को आग दिया गया है कि जितना समय अंग्रेजी सीखने में लगाते हों, उसका चौथाई भी मातृभाषा (यानी संस्कृत) सीखने में लगाओ तो वे अपरिचित शब्द उतने अपरिचित न रह जायेंगे।

इन कोशकारों के लिए सबसे अच्छी सजा यही है कि इनसे इन्हीं के बनाये हुए कोश याद कराये जाएँ। जहाँ भूले वहाँ फिर याद करने की ताकीद कर दी जाय। जब हिन्दी, बँगला आदि के कोशकार अपने-अपने कोश या सम्मिलित महाकोश याद कर डालें तभी वह कोश जनता तक पहुँचे, उसके पहले नहीं।

हिन्दी का संस्कृतीकरण पारिभाषिक शब्दों को लेकर ही नहीं है। साधारण साहित्य में, दैनिक और मासिक पत्रों आदि में भी तत्सम शब्दों को इसलिए भरा जाता है कि इससे हिन्दी सुबोध हो जाएगी—खुद हिन्दी बोलनेवालों के लिए नहीं बल्कि दूसरी भाषाओं के बोलनेवालों के लिए। मिसाल के लिए, शायद बंगाल के लोग संस्कृत-बहुल हिन्दी को बोलचाल की खिचड़ी भाषा से ज्यादा अच्छी तरह समझ सकेंगे। देखना चाहिए कि बोलचाल की बँगला में तत्सम शब्दों का अनुपात कैसा रहता है। इस पर डा० मुनीतिकुमार चटर्जी ने ज्यादा कौन अधिकारी विद्वान राय दे सकता है? बँगला भाषा की उत्पत्ति और विकास पर लिखे हुए अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ के पहले भाग में उन्होंने यह मत प्रकट किया है—

‘In Modern Bengali, the Colloquial has a surprisingly small ‘percentage of Sanskrit words.’ (‘The Origin and Development of the Bengali Language’, Vol. 1, p. 221) यानी बोलचाल की बँगला में संस्कृत शब्दों की तादाद असाधारण रूप से कम है !

हिन्दी पाठक इस वाक्य पर कुछ देर तक विचार करें। जिन अन्य भाषा-भाषियों की दुहाई देकर हिन्दीपन को बिगाड़कर उसे संस्कृतमयी बनाया जा रहा है, वे स्वयं बँगाल जैसे प्रान्त में भी संस्कृत शब्दों का कम-से-कम प्रयोग करते हैं।

पारिभाषिक शब्दों की समस्या बोलचाल की भाषा के नियमों को तोड़कर हल नहीं की जा सकती। बोलचाल की भाषा में अंग्रेजी और फारसी के शब्द भी आते हैं और संस्कृत से भी आते हैं। लेकिन आर्य संस्कृति के जोग में शुद्धतावादी केवल संस्कृत के तत्सम शब्दों को लेने पर तुले हुए हैं। वे यह भूल जाते हैं कि स्वयं संस्कृत दूसरी भाषाओं से शब्द लेकर समृद्ध होती रही थी। इस बात को मुनीति बाबू भी मानते हैं। उपर्युक्त पुस्तक में लिखा है—“The Aryan speech has been borrowing words from the Dravidian ever since the former came to India”—Ib., p. 178. अर्थात् “आर्यों की भाषा हिन्दुस्तान में आने के बाद से ही द्रविड़ भाषाओं से बराबर शब्द उधार लेती रही है।” लेकिन ‘देववाणी’ भले शब्द लेती रही हो, देशवाणी के कलजुगी समर्थक जोरों से हृदय-कपाट बन्द किये हैं कि कहीं विदेशी हवा लगने से उनका देवत्व खंडित न हो जाय !

अगर कोई कहे कि ‘इनकम टैक्स इन्स्पेक्टर, वारंट, करेंसी, गार्जियन, रिपोर्ट, रिसेवर, समन, सब-जज’ आदि अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों को ग्रहण कर लेना चाहिए और उनकी जगह नये शब्द न गढ़ने चाहिएँ तो यह राष्ट्रभाषा के प्रति द्रोह कहा जाएगा। लेकिन इन्ही शब्दों की सुनीति बाबू ने अपनी पुस्तक में ‘Typical Naturalised English



Words (पृ० ६४४ ४८) कहा है। ये शब्द बंगला के आने शब्द मान लिये गए हैं और यही नहीं इनके साथ एंग्लिशिज्म, ब्रिटिश-रूम, कॉमिन, मिरीमेंट (एमीनेट), नोटिस, वज्ज्राइन (बुलूजा), मरगिज, रजिस्ट्री, निषर, हाक माइड आदि शब्द भी बंगला की स्वीकृत गणानि माने गये हैं। यकिन बंगला की 'अवस्थापरिभाषा' उठाकर देखिए तो इही शब्दा या इन जैसा क बदल जाँगे। सुनीति कुमार और उनके मध्योगी मने-नये भाषी-भरकम शब्द रखने दिखाई देंगे और गुरु बगानियों की समझ मन आने पर उनमें कहेंगे कि अपनी मानभाषा सीखने में कुछ समय लगाओ।

इसी तरह अपनी पुस्तक के पृ० २१३ (पृष्ठ १) पर उन्होंने बेंनेट, मैन्टरी, प्रिटर, गड्डट, टाइममेबल, रोमांस, रामाटिक, कनामिज, डैजिक, बॉमिज, आर्ट, पयूवरिज्म, माइम, प्राटोप्लाज्म, प्लीस्टोमीन ला प्लाट, कैमिस्ट्री, रिडिक्ल आदि शब्दों के लिए लिखा है कि वे 'are being bodily adopted at the present day,' यानी वे जैसे-जैसे बंगला में अवतार ल रहें हैं। लेकिन यहाँ क्या कि वही सुनीति बाबू अब इनके लिए मरुत की किसी धानु म नमा शब्द न पड़ लें।

अपनी पुस्तक के पृ० २१२ (पृष्ठ १) पर उन्होंने यह भी लिखा था कि बंगला के समकालीन लेखक उदादा मरुता में आया आ रहा है, इसलिये फारसी, अरबी के शब्दों का बंगला में आना बिनाकुल स्वाभाविक होगा ('will be in the nature of things') लेकिन अवस्थापरिभाषा में इन स्वाभाविक रूप में आया हुए शब्दों की रूढ़ि के लिए ज़रूर आकर ख़ुदबोली की उन्नत पड़ती।

जिस तरह पूँजीवादी नया चुनाव ल रिये हुए शब्दों को मन्त्री बनन पर भूल जाते हैं, वैसे ही 'रिवाजनिज्म' के जोग में (आये मरुति के मोह में) सुनीति बाबू जय भाषा बैनानिक खुद अपने बनाये हुए मिश्रानों को भूल गए हैं। यह पूँजीवादी मरुति के हान का चिह्न है, उसके उतारान का नहीं। यह रास्ता बंगला और हिंदी की उन्नति का नहीं, उनकी अवनति का है।

(१६४८)

## उर्दू-साहित्य की सांस्कृतिक परम्परा

हिन्दी-उर्दू की समस्या का एक पहलू उनके साहित्य की परम्परा का भी है। हिन्दी और उर्दू एक भाषा है; या एक भाषा की दो शैलियाँ हैं, वे आगे चलकर मिलेंगी या उनमें से एक ही रह जाएगी आदि मसलों को पेश करते हुए और उनका हल खोजते हुए इन दोनों की सांस्कृतिक परम्परा का सवाल भी उठाया जाता है।

उर्दू की साहित्यिक और सांस्कृतिक परम्परा क्या है? यह परम्परा हिन्दी की साहित्यिक और सांस्कृतिक परम्परा से कहाँ तक अलग है? क्या दोनों की कोई सामान्य परम्परा भी है जिसे आगे विकसित किया जा सकता है?

इन प्रश्नों का जवाब देने से हिन्दी-उर्दू की समस्या को सही तौर से पेश करने और उसे हल करने में सहायता मिलेगी।

१

उर्दू की सांस्कृतिक परम्परा के बारे में एक मत यह है कि वह विदेशी है; उसी की वजह से देश के बँटवारे की नींवत आई (या वह परम्परा भी बँटवारे का एक कारण है); इस परम्परा से हिन्दी का कोई समझौता नहीं हो सकता और दरअसल उस परम्परा को, चूँकि वह राष्ट्रद्रोही है, जल्दी-से-जल्दी खत्म कर देना चाहिए।

इस मत को हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के नये सभापति सेठ गोविन्ददास ने बड़ी धूम-धाम से पेश किया है। इसी मत को श्री राहुल सांकृत्यायन, श्री सम्पूर्णनन्द, श्री पुरुषोत्तम-दास टंडन आदि सज्जन भी पेश कर चुके हैं। सेठ गोविन्ददास ने उसे पेश करने में धूम-धाम के अलावा किसी मौलिकता का परिचय नहीं दिया, इसलिए यहाँ पर श्री पुरुषोत्तम-दास टंडन के शब्दों को उद्धृत करना ज्यादा अच्छा होगा। टंडनजी सम्मेलन के प्राण हैं। सम्मेलन के सालाना सभापति जो मत प्रकट करते हैं, उनमें इन प्राणों की ध्वनि ही गूँजती रहती है।

सम्मेलन के पैंतीसवें अधिवेशन में टंडनजी ने उर्दू की सांस्कृतिक परम्परा पर ये विचार प्रकट किये थे :

“ उर्दू कवियों की जो कविताएँ हुई, वे अरब और ईरान के तहजीब की प्रतीक थी। उर्दू कविताएँ हमें अपने नगर, अपने देश, अपने गली-कचो की ओर ले जाने के बजाय,

दगन और अरब के नगर तथा गरीब-बूचा की ओर ले जाती हैं। उसकी सांस्कृतिक परम्परा हमारे देश की हमारी मिट्टी न निकली हुई आत्मरति है, उसके विपरीत है।

उर्दू कविता के स्वरूप में उर्दू कविता का सांस्कृतिक प्रयत्न स्पष्ट दिखाई पड़ता है। उनकी कविताओं में यदि बीर की उपमा दी जाती है तो रक्तम, साहराब, अर्धांगनाद को ध्यान किया जाता है। कहीं पर आपकी भीम, अबुल आदिल की उपमा नहीं मिलेगी। नारी की उपमा जब जाती है तो उर्दू अरब की, मेसापोटामिया की और ईरान की नदियों का दान होती है। पवन की माद होती है तो उन्हें ईरान के पञ्जाब की माद आती है। हिमालय पवन की माद नहीं आती। फना में उनको 'नगिन' की माद आती है। पक्षियों में उनको बुलबुल दिखाई पड़ता है, अपने देश के या मुन्दर और अब्दुल पानी हैं, उनकी चर्चा नहीं करते। उनका यह प्रयत्न था कि सन्तुष्ट की गिनियाँ 'अरबी' बन जाएँ। 'अरबी' ईरान का एक भाग है। सन्तुष्ट की लज्जा का कवि या उसका एक शेर 'फमाना अजायब' में यह है—'बुलबुले सीराज को है रक्त नागिन का धूल'। अरबी इमने किए हैं, लज्जा के कूचे और गिनियाँ। कहने का तात्पर्य यह है कि उर्दू का सांस्कृतिक क्रम पृथक्वाद है और उनका परिणाम यह हुआ है कि जन्म-जन्म उर्दू का विकास हुआ, जैसे जैसे सांस्कृतिक पृथक्ता बढ़ती गई। जहाँ-जहाँ उर्दू का साम्राज्य था, वहाँ-वहाँ पृथक्वाद का विरोध बन था जैसे उलर प्रदेश और पञ्जाब में।"

(हिन्दी साहित्य सम्मेलन, पैंतीसवें अधिवेशन का विवरण, प्रयाग, पृ० ७६-७७)

यह सब कहने का मोक्ष मतलब यह है कि उर्दू की सांस्कृतिक परम्परा अन्तर्गत पैदा करती रही है, इसलिए उसे कम कर देना चाहिए। आज जब टडनकी कहते हैं कि "मुझे उर्दू कविता अच्छी लगती है," तब हमने पूछा जा सकता है कि इस राष्ट्र-विरोधी कविता के अच्छा लगने का पाप आप जैसे विगुड़ भारतीयता प्रेमी से कैसे हो गया? अगर उर्दू की सांस्कृतिक परम्परा हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डगलती है तो इस बारे में दा मत नहीं हो सकते कि ऐसी परम्परा को खत्म कर देना चाहिए। ऐसी परम्परा तो फटपरस्तों की ही अच्छी लग सकती है।

## २

उर्दू साहित्य के इतिहास पर दृष्टि डालने से पहली चीज यह दिखाई देती है कि उर्दू की सांस्कृतिक परम्परा परिवर्तनशील रही है। जो परम्परा जोक या दाग की थी, वही परम्परा ग़ाल-क़ासिआ आग या क़ान-ख़न्दर की नहीं है। हमें देखना चाहिए कि यह परम्परा पत्तन क्या थी और उसमें कौन-कौन-सी खास तब्दीलियाँ हुई हैं।

जिस तरह हम भारते-हु के पहले की हिन्दी कविता को मोटे तौर पर रीति-कालीन कविता कहते हैं, उसी तरह हाली के पहले की उर्दू कविता को मोटे तौर पर हम रीति-कालीन कविता कह सकते हैं।

इस जमाने की उर्दू कविता पर दरबारी सृष्टि की अवस्था छाप है। उसके भावों

और भाषा पर सामन्ती संस्कृति की छाप है। यह नामन्ती संस्कृति साहित्य में ईरानी साहित्य की परम्परा को अपनाती थी। उसने ईरानी साहित्य में प्रचलित उपमाओं, रूपकों वगैरह को अपने साहित्य में सजाने की कोशिश की।

हर देश के रीतिकालीन साहित्य में—उस समय के साहित्य में जब उद्योग-धन्धों के विकास से सामन्ती ढाँचा मृत नहीं हुआ—वात कहने के ढंग पर ज्यादा जोर दिया जाता है, भावों और विचारों की मौलिकता पर कम जोर दिया जाता है। हिन्दी की रीतिकालीन कविता, विहारी और देव की रचनाओं में यह तैली हम देख सकते हैं। यही बात उर्दू की रीतिकालीन कविता पर भी लागू होती है।

आगे चलकर रीतिकालीन परम्परा ज्यादा नाथ नहीं देती। उसमें चाहे भीम और अर्जुन का गुणगान हो, चाहे सोहराब और अफ़सियाब का, उस परम्परा से नाता तोड़ना ही पड़ता है। हिन्दी की रीतिकालीन परम्परा में रामायण और महाभारत के वीरों की कमी नहीं थी, फिर भी खड़ी बोली के कवियों ने उन परम्परा का जोरों से विरोध किया और छायावादी कवियों ने उससे नाता तोड़कर एक नई परम्परा को जन्म दिया। उर्दू-साहित्य में भी उसकी रीतिकालीन परम्परा एक निर्जीव परम्परा हो गई है। उर्दू-साहित्य उससे बहुत आगे बढ़ चुका है। रीतिकालीन परम्परा का विरोध करने और उससे नाता तोड़ने पर खुद उर्दू के लेखकों और कवियों ने जोर दिया है।

जैसे हिन्दी में भारतेन्दु से पहले की सभी रीतिकालीन कविता ऐसी नहीं है, जिसे उठाकर रद्वी की टोकरी में फेंक दिया जाय; उसी तरह उर्दू की रीतिकालीन कविता में बहुत-सा हिस्सा सांस्कृतिक परम्परा का एक अंग बनकर सुरक्षित रहेगा। उर्दू के बहुत-से पुराने कवियों की ऐसी सैकड़ों पंक्तियाँ हैं जो अपनी उक्ति-चातुरी की वजह से बार-बार उद्धृत की जाती हैं और अब उन्होंने बोलचाल में कहावतों की जगह ले ली है। मसलन—

बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का  
जो चोरा तो इक क्रतरण खूँ न निकला।

○ ○ ○

जमीने चमन गुल खिलाती है क्या-क्या,  
बदलता है रंग आस्माँ कैसे-कैसे।

○ ○ ○

न जोरे सिकन्दर न है क़त्त्रे दारा,  
मिटे नामियों के निशों कैसे-कैसे।

○ ○ ○

अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे,  
मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे।

○ ○ ○

हजरत दाग जहाँ बैठ गया बैठ गये  
और होंगे तेरी महानि से उभरनेवाले ।

इस तरह की पत्तियाँ खानचात में इस तरह आती हैं कि उन्हें हिन्दुस्तानी (मंडी बोली) खानावाली जनता की मासुनिष्ठ परम्परा का एक अंग कहा जा सकता है ।

हामी में पहले की उन्नीसवीं शताब्दी की देन इतनी ही नहीं है । हाली में पहले भी बहुत-से कवियों ने रीतिवादी परम्परा में बंधे न रहकर अपना नया रास्ता बनाया था । इन कवियों में गालिब का नाम सबसे पहले आता है जिनके व्यक्तित्व की छाप उनकी रचनाओं पर इस तरह पड़ी है जिन तरह अपन व्यक्तित्व की छाप डालना किसी भी रीतिवादी कवि के लिए मुमकिन नहीं है । गालिब ने अपने जीवन के बारे में बड़े दर्दे से लिखा है । इस तरह का दद दूसरों की रचनाओं की नकल करने में नहीं पैदा होता । इटली के महान् कवि दात ने जिन तरह अपन जीवन की अपार बेदना अपने महाकाव्य में उँडेल दी थी, उन्नी तरह गालिब के दोर उम्र अमान के बानावरण के प्रति दोष, भ्रान्ति और बेदना में डूब हुए हैं ।

गालिब के अमान में बहुत-से लोग दुःख की छायाँ करने थे । वे फारसी साहित्य की उन्माएँ और रूपक लेकर अपनी रचनाओं को सँवारने की कोशिश करते थे । इन सब में फारसी साहित्य से प्रभावित होते हुए भी गालिब एक महान् प्रतिभाशाली कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं ।

गालिब की पचीसा पत्तियाँ साधारण बोलचान में बराबर उद्भूत की जाती हैं ।  
ममाल के लिए—

हमका मालूम है जन्म की हकीकत लेकिन,  
दिल के खुद करने को गालिब में तयाल अच्छा है ।

उनको देखे में जो आ जाती है मुह पर रीनक,  
वो समझत है कि बीमार का हाल अच्छा है ।

कर्म की पीते थे मय लेकिन समझते थे कि हाँ,  
रा लायेगी हमारी फाजामस्ती एक दिन ।

गंगा में दीडो फिरने के हम नहीं जायल,  
जो आँख ही से न टपका तो फिर सहु क्या है ।

न था कुछ तो खुदा था कुछ न होता तो खुदा हाता,  
डबोया मुझको उहो न होता मैं तो क्या होता ।

मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसों हो गईं ।

दर्द का हृद से गुजरना है दवा हो जाना ।

है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ,  
घरना क्या बात करनी नहीं आती ।

अनेक हिन्दी लेखकों की रचनाओं में गालिव के शेर उद्धृत किये जाते हैं । उग्रजी की शायद ही कोई पुस्तक, शायद ही कोई लेख हो जिसमें गालिव के शेर उद्धृत न किये गये हों । निरालाजी ने जहाँ-तहाँ गालिव के शेर उद्धृत ही नहीं किये, उन पर 'प्रबन्ध पद्य' में लिखा भी है । गालिव की रचनाएँ किस तरह हिन्दी लेखकों की सांस्कृतिक परम्परा बन गई हैं, इसकी एक मिसाल निरालाजी के जीवन में मिलती है । निरालाजी को अपने जीवन में जो मुसीबतें उठानी पड़ी हैं, जो अपमान सहने पड़े हैं और जिस तरह विरोधियों के मुकाबले में अपने आत्मविश्वास को अडिग रखना पड़ा है, उससे गालिव की रचनाओं से उन्हें एक आन्तरिक सहानुभूति पैदा हो गई थी । मने उन्हें पचीसों वार इन पंक्तियों को गाते सुना है और आखिरी वार अभी पिछले साल बनारस में जब वह काफ़ी अस्वस्थ थे, उन्हें फिर गालिव के शेर गुनगुनाते सुनकर काफ़ी ताज्जुब भी हुआ कि इनके मन की दुनिया में और बहुत-से उलटफेर हुए, लेकिन गालिव, रवीन्द्रनाथ और तुलसीदास—ये तीन महाकवि अपनी जगह अब भी कायम हैं ।

रहिये अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई न हो,  
हमसखुन कोई न हो और हमजवाँ कोई न हो ।  
वे दरो दीवार-सा इक घर बनाना चाहिए,  
कोई हमसाया न हो और पासवाँ कोई न हो ।  
पड़िये गर बीमार तो कोई न हो तीमारदार  
और अगर मर जाइये तो नौहाख्वाँ कोई न हो ।

जब श्रीपुरुषोत्तमदास टंडन उर्दू की सांस्कृतिक परम्परा को विदेशी और राष्ट्र-विरोधी कहकर उस पर हमला करते हैं, तब हम यह मोचने पर मजबूर होते हैं कि हिन्दी की सांस्कृतिक परम्परा को 'निराला' की देन महान् है या श्रीटंडन की देन महान् है । निराला की देन महान् है और इसीलिए महान् है कि उनके हृदय में वह संकीर्ण साम्प्रदायिकता नहीं थी जिसका परिचय श्रीटंडन ने बार-बार दिया है । संकीर्ण हृदय से महान् सांस्कृतिक परम्परा का कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता ।

गालिव के बाद पुरानी उर्दू कविता के दूसरे महान् रचनाकार मीर हैं । मीर की बहुत-सी रचनाओं में रीतिकालीन परम्परा से साफ़ नाता टूटा हुआ दिखाई देता है । कौन-सा रीतिकालीन कवि अपने घर का इस यथार्थ ढंग से वर्णन करेगा !—

लोनी लग लग के भड़ती है माती,  
 आह क्या उग्र धेमड़ा काटो ।  
 भाइ बाँगा है मेह ने दिन-रात,  
 घर की दीवारें हँगी जैसे पान ।  
 बाउ मे कापते हैं जो घरघर,  
 उन पे रहा रमे कोई क्याकर ।

मीर की भी अनेक पंक्तियाँ कटावता का दर्जा पा चुकी हैं, जैसे ये—

भाम म कुछ बुझा-या रहता है,  
 दिल हुआ है चिराग मुफलिस पा ।

हाली से पहले जिन लोगों ने रीतिवासीन परम्परा में नाता तोड़ा, उनमें नजीर का नाम महत्वपूर्ण है। नजीर क काव्य में मोह-भोला, कटावता और लोह-मस्दूति को जगह दिया गया है, उससे आज भी हम बहुत-कुछ सीख सकते हैं। नजीर जनता के कवि थे। इन्होंने आम जनता की जिन्दगी के बारे में बड़ी मजीब रचनाएँ की हैं। इनकी भाषा के बारे में श्री बजरत्नदाम ने लिखा है

‘इनकी भाषा देगी थी और उसे विनायनी ब्रह्मण का कभी इन्होंने प्रयत्न नहीं किया। इनका चयनी भाषा पर पूरा अधिकार था और फारसी तथा अरबी के कालों से चुन चुनकर अपनी भाषा का लद्दू बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जैसा विषय चूना, वैसी ही भाषा ली और वैसे ही वास्तविकता से उसका चित्रण भी कर डाला।

(उद्द साहित्य का इतिहास, बनारस, म० १९६१, पृ० १८२)

नजीर की बहुत-सी रचनाओं पर मुफ्तिपन का रंग है। दरअसल उनकी कविता की जड़ें उस जमाने के समाज में दूर तक खनी गई थीं। वह आदमवादी कवियों की तरह गरीबी का गुणगान नहीं करने बल्कि इल्मान की वे मुसीबतें बयान करते हैं जो गरीबी के सबब से उग पा जाती हैं। लिखा है—

जब आदमी के हाल पे जाती है मुफ्लिसी,  
 किस किस तरह से उसकी सतानी है मुफ्लिसी  
 प्यासा तमाम रोज बिठाती है मुफ्लिसी  
 भूखा तमाम राउ मुलाती है मुफ्लिसी,  
 यदु खवा जाने जिसपै कि आती है मुफ्लिसी ।

उनीयवी मंडी के उत्तरार्द्ध में देश के जदरगद् राष्ट्रीय चेतना विकसित होने लगी। हिन्दी-साहित्य में भारत-बुद्ध हरिचन्द्र ने किस तरह देश-भक्तिपूर्ण कविताओं की परम्परा चलाई इसे सभी लोग जानते हैं। उस समय की राष्ट्रीय चेतना पर धुनल्लयानवाद का भी रंग चढ़ा हुआ था। भारत-बुद्ध ने आर्य जाति के प्राचीन गौरव के गीत गाये। हाँ तो ने मुनतमाना ने बीने बैसय के स्वप्न देखे। फिर भी हाली और भारत-बुद्ध—दोना ने ही यह अनुभव कर लिया था कि देश की उन्नति हिन्दू मुसलमाना के मेल से ही

उनकी मिली-जुली राष्ट्रीय चेतना से ही हो सकती है। हाली ने देश पर लिखा था—

ऐ वतन ऐ मेरे वहिश्ते वरीं  
क्या हुए तेरे आसमाँ और जमी  
रात और दिन का वो समाँ न रहा  
वो जमीं और वो आसमाँ न रहा ।

हिन्दू-मुस्लिम-एकता पर लिखा था—

तुम अगर चाहते हो मुल्क की खैर,  
न किसी हमवतन को समझो ग़ैर ।  
हों मुसल्माँ इसमें या हिन्दू  
बौद्ध मज्जहव हो कि या ब्राह्मो,  
सबको मीठी निगाह से देखो ।  
समझो आँखों की पुतलियाँ सबको ।  
हिन्द में इत्तफाक होता अगर  
खाते ग़ैरों की ठोकरें क्योंकर ?

आधुनिक हिन्दी साहित्य के आरम्भ-काल में जैसे सामाजिक कुरीतियों पर बहुत-सी रचनाएँ की गईं, उसी तरह उर्दू-साहित्य में भी समाज-सुधार पर बहुत-सी चीज़ें लिखी गईं। बीसवीं सदी में आकर साहित्य का मतलब मुख्य रूप से कविता नहीं रहता; उसके दूसरे रूप कहानी, उपन्यास, आलोचना वगैरह भी फलने-फूलने लगते हैं। इस नए ज़माने का हिन्दी-उर्दू साहित्य और भी नजदीकी सांस्कृतिक परम्पराएँ बनाता हुआ चलता है।

हिन्दी उपन्यासों में देवकीनन्दन खत्री के ऐयारी उपन्यासों के बाद हम प्रेमचन्द के सामाजिक समस्याओं वाले उपन्यासों तक पहुँचते हैं। उर्दू में पं० रतननाथ सरशार के 'फिसान-ए-आज़ाद' से आगे बढ़ते हुए हम फिर प्रेमचन्द तक पहुँचते हैं। प्रेमचन्द ने उर्दू और हिन्दी में सामाजिक समस्याओं वाले उपन्यासों की नींव डाली। प्रेमचन्द में हिन्दी-उर्दू की सांस्कृतिक परम्पराओं का मिलकर एक होना साहित्य की बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। उससे जाहिर होता है कि सांस्कृतिक परम्परा की जड़ें सामन्ती साहित्य के ज्यादा भीजूदा सामाजिक जिन्दगी में धँसी होती हैं। प्रेमचन्द के ज़माने में एक नई परम्परा गढ़ी जा रही थी जिसके तत्त्व इस्लाम या हिन्दू-धर्म से न लिये जाकर देश के सामाजिक और राजनीतिक आन्दोलनों से, समाज की नई प्रगति से, वर्गों के नए सम्बन्ध से लिये जा रहे थे। प्रेमचन्द ने हिन्दी और उर्दू में जो नई परम्परा डाली, वह गुणात्मक रूप से साहित्य की पुरानी परम्परा से भिन्न थी। वह दाग, जौक, बिहारी, पद्माकर की परम्परा से ही भिन्न न थी, वह हाली और भारतेन्दु की परम्परा से भी काफ़ी अलग थी। प्रेमचन्द साहित्य के विकास की वह मंजिल थी जो अपने में सुधारवादी राष्ट्रीयता खत्म करके नये प्रगतिशील साहित्य की तरफ इशारा करती है।



प्रेमचन्द एक नई परम्परा का इस्तिलाफ़ दे सके कि हमारे समान मेनने परिवर्तन हो रहे थे, उसमें नई आशाएँ, नये उद्देश्य लेकर नये आन्दोलन चल रहे थे।

हिन्दी-उद साहित्य में प्रेमचन्द की परम्परा हम वान का सबसे बड़ा सबूत है कि सभ्यता रचने का काम मनुष्य का सामाजिक जीवन करता है। यह सामाजिक जीवन बदलना पड़ता है, इसलिए सभ्यता की धारा भी बदलती रहती है। सामाजिक जीवन के मुकाबले में धर्म-सम्प्रदाय, मन मतान्तरी के स्वरूप बहुत ही कमजोर साबित होते हैं, और सभ्यता पर उनका असर कम-से-कम होता जाता है।

प्रेमचन्द खुद हम वान को बहुत अच्छी तरह जानते थे कि सामान्य-काल की सांस्कृतिक परम्परा खत्म हो रही है और नये जमाने की एक नई परम्परा कायम हो रही है। वह जानते थे कि दोनों के उद्देश्य, दोनों के साहित्यिक रूप, दोनों के मौल्य-सम्बन्धी मानदण्ड अलग-अलग हैं।

पुरानी साहित्यिक परम्परा के द्वारे में उठोने लगा था—

‘हमारे साहित्यकार कल्पना की एक सृष्टि खड़ी करके उसमें मनमाने तिलिस्म बारा करते थे। वही फिमान-ए-अजायब की दास्तां थी, वही बोस्ताने गुयान की और वही चंद्रकांता सभ्यता का। इन साह्यानों का उद्देश्य केवल मनोरंजन था और हमारे अद्भुत रस-प्रेम की क्षति

‘क्या हिन्दी और क्या उर्दू—कविता में दोनों की एक ही हानि थी ऐसे पतन के काज में लोग या तो आत्मिकी करते हैं या अध्यात्म और वैराग्य में मन रमाते हैं।

“कला का नाम था और ज़र भी है, सज्जित रूप-भूषण का, शब्द-भोजन का, नायक-विषय का। उसमें लिए कोई आदश नहीं है, जीवन का कोई ऊँचा उद्देश्य नहीं है—भक्ति वैराग्य अध्यात्म और दुनिया से किताराकशी उसकी सबसे ऊँची कल्पनाएँ हैं। हमारे उस कलाकार के विचार में जीवन का चरम लक्ष्य वही है। उसकी दृष्टि अभी इतनी व्यापक नहीं कि जीवन-संग्राम में वह सौ-दर्प का परमोत्कर्ष देखे।”

(सल्लनऊ, प्रगतिशील लेखक सम्मेलन में सभापति पद से दिये गये भाषण से)

इस परम्परा को प्रेमचन्द खत्म कर रहे थे। उन्होंने साफ़ माँग की थी कि साहित्य के पुराने मानदण्डों को बदला जाय। उन्होंने कहा था—

“हमें सुंदरता की नसोटी बदलनी होगी। अभी तक यह कसोटी अमीरी और विलासिता के दग की थी। हमारा कलाकार अमीरों का पल्ला पकड़े रहना चाहता था। उसकी निगाह अन्नपुर और बँगला की ओर उठती थी। भौंपड़े और खडहर उसके ध्यान के अधिकारी न थे। उन्हें यह मनुष्यता की परिधि के बाहर समझता था। अभी उनकी खर्चा करता भी था तो उनका मन्त्रांक उड़ाने के लिए।” (उप०)

प्रेमचन्द का दूर धर्म उनके सच्चे जनवादी हृदय से निकला है, जो समाज के नये विराग्य के लिए, साहित्य की परम्परा बदलने के लिए और से समकारता है।

“यदि साहित्य में अमीरों के याचक बनने को जीवन का पहला धना दिया है,

और उन आन्दोलनों, हलचलों और क्रांतियों से देखवर हो जो समाज में हो रही हैं—अपनी ही दुनिया बनाकर उसमें रोता और हँसता हो तो इस दुनिया में उसके लिए जगह न होने में कोई अन्याय नहीं है।” ( उप० )

प्रेमचन्द के ये प्रभावशाली शब्द—उनके हृदय के ये सच्चे उद्गार बतलाते हैं कि साहित्य की जो परम्परा धार्मिक अन्धविश्वासों, साम्प्रदायिक विद्वेष और भेदभाव, सामन्ती रुढ़ियों और प्राचीनतावाद को अपना आधार बनाती है, वह खत्म हो जाती है। साहित्य की वह परम्परा जो समाज के गतिशील जीवन को, उसके क्रान्तिकारी वर्ग को, जनता के संघर्ष को अपना आधार बनाती है, वह जीवित रहती है और वही परम्परा जीवन रह सकती है। प्रेमचन्द ने हिन्दी-उर्दू में इसी परम्परा को जन्म दिया था।

कुछ लोगों के मन में शका पैदा हो सकती है कि प्रेमचन्द ने तो यह सब काम हिन्दी में किया था, उसका जिक्र उर्दू साहित्य के सिलसिले में क्यों किया जा रहा है ? ऐसे पाठकों की सेवा में प्रेमचन्द के ये शब्द अर्पित हैं—

“मेरा सारा जीवन उर्दू की सेवकाई करते गुजरा है और आज भी मैं जितनी उर्दू लिखता हूँ, उतनी हिन्दी नहीं लिखता।”

(प्रेमचन्द : कुछ विचार; पृ० १६१)

हिन्दी-उर्दू के लिखनेवालों का सामाजिक वातावरण आम तौर से एक-सा रहा है, इसलिए उनकी साहित्यिक परम्परा के उतार-चढ़ाव, उसके मोड़ और नई दिशा में प्रवाह भी मिलते-जुलते रहे हैं। हिन्दी में रीतिकालीन परम्परा का विरोध किया गया। उर्दू में भी उस परम्परा का विरोध किया गया। हिन्दी में राष्ट्रीय कविता का युग आया, चक्रवर्त और इकबाल यह युग उर्दू कविता में भी लाये।

हिन्दी-कविता में छायावाद के नाम से नई रोमांटिक कविता का युग आया। इस तरह की रोमांटिक कविता का युग उर्दू में भी आया।

गुलज़ार में कोयल की सदा गूँज रही है,  
कोहसार में पुरखोर हवा गूँज रही है,  
कुलकुल से जुनूँखेज फज़ा गूँज रही है,  
मैदान में घनघोर घटा गूँज रही है;  
बरसात है, बरसात है, बरसात है,  
बरसात !

छायावादी कविता के उत्तरकाल में जैसे हिन्दी के कुछ कवियों ने निराशा, ऊब और अकेलेपन के गीत गाये, वैसे ही उर्दू में—

शहर की रात और मैं नाशाद ओ नाकारा फिहँ,  
जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिहँ,  
शहर की बस्ती है कब तक दरबदर मारा फिहँ,  
ऐ गमे दिल क्या कहँ, ऐ वहशते दिल क्या कहँ,

यह सपत्नी छवि यह आकाश पर लाने का जाल,  
जैसे गुफा का समुद्र, जैसे आगि का खयाल,  
आह लेकिन बौन जान बौन समझ जो का हान,  
ए गमे दिन क्या कष्ट, ए बहूशते दिन क्या कष्ट ।

हिन्दी में जमे कुछ कविता ने प्राचीनतावाद को ऐसा साधन बनाया है कि साहित्य का पापी उत्तर जाय, उसी तरह उर्दू में भी अजगज और फूट पैदा करनेवाले, इस्लाम में उर्दू का नाता जाइनेवाले, मुगलमाना को अलग जानि और उस को अरब और ईरान की सस्टुति में मित्रानवाने साधर भी हुए हैं। लेकिन उनकी बजह से उर्दू-साहित्य को साम्प्रदायिक समझना उतनी ही बड़ी जखनमन्दी होगी, जितनी विप्लिंग की बजह से अंग्रेजी साहित्य को साम्प्रदायवादी समझना ।

श्री पुरुषोत्तमदान टंडन का कहना है कि उर्दूवान राम, कृष्ण, भीम, अजुन बर्गहं न। नाम तेना अपनी सस्टुति के खिलाफ समझने हैं। अगर ऐसा है तो नजीर ने 'बगहेया का बालपन' क्या लिखा? और लिखा तो ऐसा की जानि-बाहर क्यों नहीं कर दिया गया? नजीर न लिखा है—

बारा मुनो ये दधि के मुटुया का बालपन,  
औ मधुपुरी नगर के अनीया का बालपन,  
मोहन-स्वरूप नुग्य करैया का बालपन,  
बा बन के खाल गीर्छे खरैया का बालपन,  
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण बगहेया का बालपन ।

नजीर ने दीवानो पर लिखा था—

हर एक मकान में जला फिर दिया दिवाली का,  
हर एक तरफ को उजाला हुआ दिवाली का,  
मभी के दिल में समा आ गया दिवाली का,  
किसी के दिल को मज्जा खुश लगा दिवाली का,  
अजब बहार का है दिल बना दिवाली का ।

हो-नी पर दूसरे गुरु-ताल में लिखा था—

अब फागुन रंग भ्रमकते हो तब देख बहारें होली की,  
और रुफ ने धोर लटकने हो तब देख बहारें होली की ।

नये युग के कवियों में सागर निजामी ने कृष्ण में बामुरी बजाने इत्यादि पर लिखा है—

अब गोपाल भूमकर बसरी बजाओ फिर ।  
बसरी के रफ से दिल को मुदगुदाओ फिर,  
प्रेम और प्रीति की, रीति को जगाओ फिर

खुद ही तुम कमल बनो, खुद ही मुसकराओ फिर,  
बूयेगुल के रूप में, सबके पास जाओ फिर,  
बंसरी बजाओ फिर दो जहाँ पै छाओ फिर,  
अब गोपाल भूमकर बंसरी बजाओ फिर।

यहाँ पर अकबर दलाहावादी का जिक्र करना उचित होगा, जिनके ढेरों शेर अनेक हिन्दी लेखकों की रचनाओं में उद्धृत किये हुए मिलेंगे। उनके बहुत से शेर कहावतों का दर्जा पा गये हैं—

खीचो न कमानों को न तलवार निकालो,  
जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।

कोम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ,  
रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ।

अकबर की नजर अक्सर धार्मिक आस्था और पुरानी तहजीब पर रहती है। वह अंग्रेजियत के खिलाफ है लेकिन उसके बदले एक नई जनवादी संस्कृति का नक्शा उनके सामने नहीं है। उनके जमाने की सीमाएँ भी थीं। फिर भी प्राचीनतावादियों पर कैसा व्यंग्य किया है !—

पेट मसरूफ है किलकीं में  
दिल है ईरान और टर्की में।

प्राचीनतावाद और कट्टरतावाद के खिलाफ बहुत-से उर्दू कवियों ने लिखा है। यही सबब है कि वह अपने यहाँ एक जनवादी और प्रगतिशील परम्परा कायम कर सके हैं।

मुस्लिम प्राचीनतावादियों पर व्यंग्य करते हुए जोश ने लिखा है—

आ ही नहीं सकता मेरे मुँह लालाए बुजदिल (यानी बुजदिल लाला मेरी बराबरी नहीं कर सकता)।

मैं पाक, वो नापाक, मैं गोरा हूँ, वो काला,  
बया उसका मेरा जिक्र, वो देशी मैं विदेशी,  
मैं मस्जिद की मस्जिद, वो बनारस का शिवाला,  
गंगा की हर इक लहर में गलतीदा है पस्ती,  
दजले की हर एक मौज में रक्साँ है हिमाला।

(प्राचीनतावादी मौलाना फर्माते हैं कि गंगा की लहरों में पस्ती है और दजला की मौजों में हिमालय का नज्जारा है !)

जोश ने लिखा है कि शैतान मौलवी को यों फँसा लेता है—

यही कह-कह के राह करता है गुम  
कि खुदा के हो खानदान से तुम।

प्राचीनतावाद के विरोध के पनम्बल्य हिन्दू-मुस्लिम-एकता पर उर्दू कवियों ने बहुत सुन्दर रचनाएँ की हैं।

इकबाल ने लिखा था—

आ गेरियत के पर्दे इक बार फिर उठा दें  
विछड़ो को फिर मिला दें, नवने हुई मिटा दें।  
मूनी पढी हुई है मुहत्त से दिल की बस्ती  
आ एक नया गिवाला, इस देस में बसा दें।  
दुनिया के तीरसा मे ऊँचा हो अपना तीरय,  
दामाने आममाँ मे उसका कलस मिला दें।  
हर सुबह उठके गाये मत्तर को मोठे मोठे,  
सारे पुजारियों को भय पीठ की पिला दें।  
मस्ती भी शाली भी भक्तों के गीत मे है  
घरती के बामियों की मुक्ती पिरौत मे है।

यह याद रखना चाहिए कि हिन्दू-मुस्लिम-एकता की अड़िग और पक्की नींव जनतंत्र ही है, भावुकता के आधार पर कायम की हुई एकता, मित्र ईश्वर-अल्ला का नाम लेकर कायम की हुई एकता टिकाऊ नहीं हो सकती। बहुत कायेमी नेता एकता का दम भरते थे, आज व प्राचीनतावाद और हिन्दू सम्प्रदायवाद के भ्रम नष्ट हो जाते हैं। कारण यह है कि किसान मजदूरों ने आन्दोलन का विरोध करके, उनके मघप को अपने लिए बाल समझकर कोई भी एकता का हिमायती नहीं हो सकना। उमे एकता अपने लिए एक खतरा मानूँ हीने लगती है। इकबाल भी इस एकता को छोड़कर सम्प्रदायवाद की तरफ मुक गये थे।

उर्दू में अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ बहुत काफी और बहुत जोरदार कविताएँ लिखी गई हैं। इन पर एक नजर डालने से ही जाहिर हो जाता है कि यह आरोप कितना भूठा है कि उर्दू के कवियों को अपने देश से प्रेम नहीं है। जोश ने खास तौर से साम्राज्य-विरोधी आन्दोलन पर बहुत सुन्दर पक्तियाँ लिखी हैं।

सत्यन मे बादशाह सलामत के राजगद्दी पाने पर जाग ने हिन्दुस्तान के बारे मे लिखा था—

‘ईश्वरे हिन्दोस्ताँ मे रात का हंगामे साव,  
करवटे रह-रह के लेता है फुडा मे इनकनाव,  
गम है मोझे बग़ावत से जवानो का दिमाग,  
आधियाँ आने की हैं ऐ बादशाही के चिराग

आपके ऐवाम में रखत हैं लपटें उद की,  
हिन्दियों की साग से आता है बुबाद की।

साम्राज्यविरोधी आन्दोलन पर जोश ने लिखा था—

क्या हिन्द का जिन्दा काँप रहा है गूँज रही हैं तकवीरें  
उकताए है शायद कुछ कंदी और तोड़ रहे हैं जंजीरें

क्या उनको खबर थी, ओठों पर जो कुपल लगाया करते थे,  
एक रोज इसी खामोशी से टपकेंगी दहकती तकरीरें,  
सँभलो कि वो जिन्दा गूँज उठा, झपटो कि वो कंदी छूट गये,  
उठो कि वो बैठी दीवारें, दौड़ो कि वो टूटी जंजीरें।  
ईस्ट इंडिया कम्पनी के फ़र्जन्दों से कहा था—

इक कहानी वक्त लिखेगा नये मजमून की  
जिसकी सुर्खी को जरूरत है तुम्हारे खून की।

जोश का साम्राज्य-विरोध १५ अगस्त, सन् '४७ के बाद गुमराह हो गया है।  
आजकल वह 'आजकल' के संपादक हैं। वह उन लोगों में हैं जो अपनी जनता का साथ  
छोड़कर उस दल के साथ जा मिले हैं जो हिन्दुस्तान को साम्राज्यवादी खेमे के साथ बाँधे  
हुए हैं।

३

उर्दू पर यह दोष लगाया जाता है कि उसमें फारसी की दस-पाँच बहरें ही काम  
में लाई जाती हैं और हिन्दी के हजारों छन्दों के भण्डार को अछूता छोड़ दिया गया है।

यहाँ पर पहले तो यह याद रखना चाहिए कि उर्दू की बहरें अब सिर्फ उर्दू तक  
सीमित नहीं रही। हिन्दी में बहुत से कवियों ने उन्हें अपना लिया है और उनमें बेरोक  
रचनाएँ करते हैं। इस तरह की रचनाएँ वे कवि भी करते हैं, जो प्राचीनतावाद के  
उपासक हैं, जैसे दिनकर।

धुँधली हुई दिशाएँ, छाने लगा कुहासा,  
कुचली हुई शिखा से, आने लगा धुआँ-सा,  
कोई मुझे बता दे, क्या आज हो रहा है,  
मुँह को छिपा तिमिर में, क्यों तेज रो रहा है।

इसके अलावा फारसी की बहरों और हिन्दी के छन्दों में उतना फर्क नहीं है जितना  
कुछ लोग समझते हैं। श्री हरिश्चंद्र शर्मा ने अपने 'उर्दू-साहित्य के इतिहास' (पृ० १६) में  
लिखा है—“उर्दू में इस्तेमाल होनेवाले कुछ छन्दों के नाम ये हैं—सुमेरु, विधाता,  
विहारी, शास्त्र, पीयूषवर्षा, भुजंगप्रयात, खरारी, हरिगीतिका, आनन्दवर्द्धक, दिग्पाल,  
भुजंगी, चीपाई आदि।” इससे यह तो जाहिर ही होता है कि छन्दों के लिहाज से हिन्दी-  
उर्दू की सांस्कृतिक परम्पराओं के बीच कोई गहरी न पट सकने वाली खाई नहीं है।

छायावादी कवियों ने—खासकर निरालाजी ने—जिस तरह मुक्तछन्द लिखने  
की प्रथा डाली थी, उसी तरह उर्दू में बहुत-से कवियों ने भी मुक्तछन्द में रचनाएँ की।

तबिन जो चीज हिन्दी-उर्दू कविता को सबसे ज्यादा नज़दीक लाती है, वह उनके गीत हैं। उर्दू कवि एक अरसे में गीत लिखने आये हैं। प्रगतिशील कवियों ने जो गीत लिखे हैं, वे रोमांटिक गीतों के लग दायरे से निकलकर आम जनता के गाने में रम चुके हैं। ऐसे गीत एक दो नहीं, भरपूर हैं। उर्दू-साहित्य का यह पहलू उमका सबसे लोकप्रिय और जनशायी रूप हमारे सामने लाता है। इन गीतों की सांस्कृतिक परम्परा एक ऐसी शक्ति-शाली और प्रातिनीतिक परम्परा है जो हिन्दी-उर्दू के बाकी भेदभाव को दूर करने में बहुत बड़ी मदद करेगी। इन गीतों को देखने से पता चलता है कि जब हम जनता के साथ, उनकी मुनोज़्जा, आगाआ और आदमी की लेकर साक्ष्य रखते हैं, तब प्राचीनवाद के तमाम अन्तर्गत पैदा करनेवाले रूप आप से आप खत्म हो जाते हैं। हमारी जनता की सम्झति एक है। हमारा साहित्य जितना ही जनता के नज़दीक आता है, उतना ही उसकी सांस्कृतिक परम्परा प्राचीनता से मुंह मोड़कर अपने लिये मौजूदा जमाने से तत्त्व चुनती है। जनता की यह सबल सांस्कृतिक परम्परा पुराने जमाने की सभ्यता से निकल के चोखे लेती है जो उभय धार्मिक अंधविश्वास और भेदभाव पैदा करने के बदेन उसे एकता, आजादी और जनतन्त्र के नज़दीक ले जाती हैं और जनवादी भावनाओं को मजबूत करती हैं।

उर्दू के कवियों ने हमारे जन-आन्दोलन को जो गीत दिये हैं, उनमें मख़दूम मुज़िबुद्दीन का गीत—'यह जग है जगो आजादी आजादी के परचम के तल' मजदूर वर्ग का अपना गीत है। बग़ाल के अकाल पर कामिक का यह गीत लोकप्रिय हो चुका है—

पूरब देस में डुग्गी बाज़ी फला दुग का जाल,  
दुग की अगनी कौन बुभाये सूख गये सब ताल,  
जिन हाथों ने मोती रोले आज वही बग़ाल,  
र सायी आज वही बग़ाल ।

भूखा है बग़ाल ।

भूखा है बग़ाल रे भायी, भूखा है बग़ाल ।

दूसी तरह मजाज़ का गीत 'बाल अरी ओ घरनी, बोल, राजसिंहामन डाँवाडोल,' अली सरदार जाफरी के कई गीत, प्रेम धवन का 'अरे अब भागो, लन्दन जाओ' उर्दू में एक ऐसी परम्परा की नींव डाल चुके हैं जिसे हम हिन्दी-उर्दू की मिली-जुली परम्परा कह सकते हैं।

आधुनिक उर्दू-कविता उन तमाम कवियों और कल्पनाओं से पीछा छुड़ा चुकी है जिन्होंने रघुपतिनहाय फ़िख्रि ने 'मदरा बहार और सदा साहान' कहा था। उन्होंने भारतन्तु में लेकन निगाहा तक हिन्दी-साहित्य के तमाम विकास पर जो झुहारी फेर दी थी, उन्हें हिन्दी को उर्दू के नज़दीक लाने में मदद नहीं मिल सकती थी। इसके अलावा हिन्दी के तमाम विकास पर कीबड़ उछालने के बाद उन्होंने आस्था रूप से जो धारणा निरूपित की और पुराने रूपों के शाश्वत मौल्य की ओर व्याख्या की थी, वह एक प्रतिक्रिया-

वादी काम था, जिसका विरोध करना जरूरी था। पुराने रूपकों और प्राचीनतावाद का विरोध जिस तरह उर्दू के नये कवियों ने—खास तौर से प्रगतिशील कवियों ने किया है, उसके लिए उनकी जितनी तारीफ की जाय, थोड़ी है। इस सिलसिले में मित्र हमन का लेख विशेष ध्यान देने योग्य है जिसमें उन्होंने इकबाल की जनतंत्र-विरोधी धारणाओं की आलोचना की थी। यह लेख 'नया अदब' में छपा था (जब 'नया अदब' लखनऊ से निकलता था)। जिस तरह हिन्दी की प्रगतिशील कविता पर यह तोहमत लगाई जाती है कि उसने प्राचीन सस्कृति से नाता तोड़ लिया है, वह छिछली राजनीतिक और प्रचारात्मक हो गई है वगैरह, उसी तरह उर्दू की प्रगतिशील कविता पर भी आरोप लगाए जाते रहे हैं। इनका जवाब देते हुए एहतेयाम हुसेन ने बहुत-कुछ लिखा है और उन्होंने उर्दू में नई तरह की आलोचना को आगे बढ़ाया है। उर्दू की आलोचना, उसके नाटक, कहानियाँ, उपन्यास आज उसी तरह नये रास्ते पर चल रहे हैं जिस तरह हिन्दी-साहित्य के ये रूप। उपन्यासों और कहानियों का सम्बन्ध अवाम की जिन्दगी से होता है, इसलिए इनमें प्राचीन रूपको, अलंकारों वगैरह का असर नहीं के बराबर होता है। हिन्दी के बहुत से पाठक 'हंस' में कृशनचन्दर की कहानियाँ, स्केच पढ चुके होंगे। खास तौर से रुद्रदत्त भारद्वाज पर उनका स्केच, 'तीन गुंडे' नाम की कहानी यह जाहिर करती है कि उर्दू-साहित्य मौजूदा जिन्दगी से अपनी विषयवस्तु चुनकर एक मिली-जुली जनवादी परम्परा गढ़ रहा है।

उर्दू की नई कविता में पुरानी व्यवस्था का विरोध और जनतन्त्र की तरफ बढ़ने की खाहिश पग-पग पर मिलती है। उर्दू कविता में देश-विदेश की महत्वपूर्ण घटनाओं, जन-आन्दोलनों की गहरी छाप है। रूस पर हिटलरी हमला, लाल फौज का वीरतापूर्ण संग्राम, वर्लिन की जीत, हिन्दुस्तान में क्रिप्स-मिशन का आना, देश का बँटवारा, साम्प्रदायिक दंगे, गांधीजी की हत्या, आज़ाद हिन्दुस्तान में जनता के आन्दोलनों पर दमन, नये जन-संघर्ष, इन सभी की तसवीरें उर्दू कविता में मिलेगी। इनसे स्पष्ट हो जाता है कि उर्दू की सांस्कृतिक परम्परा को आज वही घटना-क्रम, वही सामाजिक परिस्थितियाँ, वही जन-संघर्ष रच रहे हैं जो हिन्दी की सांस्कृतिक परम्परा रच रहे हैं। (१९४६)



## भारत की भाषा-समस्या

### भाषा-समस्या का सामान्य महत्त्व

भाषा-समस्या मजदूर वर्ग, उसकी पार्टी, सामान्य श्रमिक जनता और प्रगतिशील बुद्धिजीवियों के लिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि लेनिन के शब्दों में, "भाषा मानवीय सम्पर्क का सबसे महत्त्वपूर्ण साधन है" (जातियाँ के आमनियम का अधिकार) ।

भाषा समस्या का महत्त्व सामाजिक विकास की मंडिला में अलग-अलग होता है ।

पूँजीवाद से घटने सामन्ती और कबीलाई सामाजिक सम्बन्ध विभिन्न जनसमूहों का एक ही जाति (नेशन) में संगठित होने से रोकता है, इसलिए वे आधुनिक के विकास में भी बाधा डालते हैं । वस्तुगत रूप से पूँजीवाद किसी जाति के घटने में श्रमनिरीक्ष्य भूमिका पूरी करता है, इस तरह वह आधुनिक भाषाओं के विकास में भी प्रगतिशील भूमिका पूरी करता है ।

इसमें स्पष्ट हो जाता है कि जातीय समस्या और भाषा समस्या में बड़ा गहरा सम्बन्ध है, किसी जाति के सामाजिक विकास तथा उस विकास के सांस्कृतिक प्रतिबिम्ब में गहरा सम्बन्ध है । यह सांस्कृतिक प्रतिबिम्ब सामाजिक विकास को भी प्रभावित करता है ।

लेनिन के अनुसार "नमस्त मसार में सामन्तवाद पर पूँजीवाद की अन्तिम विजय का युग जातीय आन्दोलनों का साथ जुड़ा रहा है । इस आन्दोलन का आधिक्य आधार यह है कि बिनाक्रमान की पैदावार को पूरा विजयी बनाने के लिए पूँजीपतियों के हाथ में घरेलू बाजार आ जाना चाहिए, उनके अधिकार में राजनीतिक रूप में एकताबद्ध प्रदेश होने चाहिए जहाँ के लोग एक ही भाषा बोलने लगे, इस भाषा के विकास में और साहित्य में उनके व्यवहार को सुनिश्चित करने में आ भी जड़चने आती है, उन्हें दूर करना होगा है ।"

पूँजीवादी सामाजिक विकास की आवश्यकताएँ, उन्हे पैमाने पर जातियों के आत्म-निर्णय का अधिकार, व्यापार-सम्बन्ध कायम करने की आवश्यकताएँ, घरेलू बाजार को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकताएँ सभी में यह कि जातीय पैमाने पर पूँजीवादी

सामाजिक सम्बन्धों के गठन की आवश्यकताएँ भाषा की एकसूत्रता और उसके विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती हैं। भाषा की एकता और विकास के बिना आधुनिक जातियों का विकास असम्भव है।

‘मार्क्सवाद तथा जातीय और औपनिवेशिक समस्या’ नाम की पुस्तक में स्टालिन ने बताया है कि जो जातियाँ पूँजीवादी विकास में पिछड़ गईं; जिन्हें बहुजातीय पूँजीवादी राष्ट्र में राज्य बनाने का अधिकार नहीं मिला, उनका उत्पीड़न उन बड़ी जातियों के पूँजीपतियों ने किया जो पूँजीवादी विकास में आगे रही थीं। जारगाही रूस में गैर-रूसी जातियों की भाषाओं का दमन किया गया। अपनी भाषा का व्यवहार करने के लिए संघर्ष जातीय आन्दोलन का मुख्य अंग बन गया। उत्पीड़ित जाति के पूँजीपति सभी वर्गों को अपने हितों के लिए एकजुट करने का प्रयत्न करते हैं। भाषा-समस्या को लेकर भी उनकी यही नीति रहती है। किन्तु भाषा की समस्या उत्पीड़ित जाति के मजदूर वर्ग के लिए भी महत्वपूर्ण है। स्टालिन के अनुसार “तानार या यहूदी मजदूर को सभी भाषाओं में अपनी भाषा का व्यवहार करने की सुविधा न दी जाय, यदि उसके स्कूल बन्द कर दिए जाएँ तो उनके बौद्धिक विकास की कोई सम्भावना न रहेगी,” (मार्क्सवाद तथा जातीय और औपनिवेशिक समस्या)। मजदूर वर्ग के हित में है कि वह स्कूलों, भाषणों, अखबारों आदि में अपनी भाषा के व्यवहार के लिए लड़े।

स्टालिन ने यह भी बताया है कि उत्पीड़न से पूँजीपतियों के लिए यह आसान हो जाता है कि मजदूर वर्ग को यह भुलावा दें कि उसके और पूँजीपतियों के हित एक हैं। जातीय समस्या मुख्य सामाजिक प्रश्नों में लोगों का ध्यान हटा देती है। भाषा-समस्या से भी पूँजीपति इस प्रकार लाभ उठाते हैं और लोगों को क्रान्ति के रास्ते से हटा देते हैं।

समाजवादी क्रान्ति के बाद जातियों का नया स्वाधीन विकास आरम्भ हुआ। सोवियत संघ में जातियाँ स्वायत्त सत्ता के अधिकार को व्यवहार में ला सकें, इसके लिए अपनी भाषा के विकास और व्यवहार का प्रश्न फिर सामने आया। स्कूलों, अदालतों, सरकारी संस्थाओं आदि में अपनी भाषा के व्यवहार के बिना कोई भी जाति सोवियत स्वायत्त शासक को अमली रूप नहीं दे सकती।

समाजवादी क्रान्ति के बाद भी सोवियत संघ में पूँजीवाद के अवशेष बने रहे। ये अवशेष इस बात से जाहिर हुए कि जातीय समस्या को लेकर छोटी और बड़ी दोनों ही तरह की जातियों में अव-राष्ट्रवाद के रुझान दिखाई दिये। एक तरफ तो सोवियत संघ में ऐसे लोग थे जो कहते थे कि उनकी जाति ही नहीं है; इन लोगों का विचार था कि बोल्शेविक पार्टी कृत्रिम रूप से इस जाति को गड़कर खड़ा कर रही है। दूसरी तरफ ऐसे लोग थे जो कहते थे कि समाजवाद की जीत के बाद सब जातियाँ मिलकर एक हो जाएँगी, उनकी भाषाएँ आपस में घुल-मिल जाएँगी और सबकी एक ही सामान्य भाषा होगी। गैर-रूसी जातियों में कुछ लोग ऐसे थे जो यह माँग करते थे कि उनकी जाति के मजदूरों की संस्कृति को रूसी मजदूर वर्ग की संस्कृति के प्रभाव से मुक्त रखा जाय। इन

प्रचार समाजवादी शक्ति के बाद भी विभिन्न रूपों में अध राष्ट्रवाद की छतरा बना रहा।

मजदूरवर्ग को भाषा-समस्या का दोहरा महत्व समझना चाहिए। मजदूरवर्ग के अपने राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास के लिए भाषा-समस्या का महत्व है, साथ ही शक्ति के विरुद्ध पञ्चायति वर्ग उसका उपयोग मजदूरों को भटकाने के लिए भी करता है।

पूँजीवादी सपहल के समाज में मुख्य वस्तु यह होता है कि सामन्ती विघटन के विनाश भाषा की एकता के लिए सघन किया जाय। जागे बड़ी हुई जातियाँ के सवहारा वर्ग का बन-य है कि वह पिछड़े लोगों की जातिरूप में सुगठित होने में मदद दे।

जहाँ जातियाँ औद्योगिक विकास की मजिलें पार कर चुकी हैं लेकिन जिन्हें अपनी भाषा का व्यवहार करने की आजादी नहीं है, वहाँ उत्पीड़क और उत्पीड़ित दोनों ही तरफ की जातियाँ के मजदूर वर्ग का कर्तव्य यह है कि जनशक्ती शक्ति की छाकस्यताओं का ध्यान में रखन हुए जातीय भाषा के व्यवहार के अधिकार के लिए सघन करें। पूँजीवाद पर मजदूर वर्ग का विजय के पहले और बाद की—दोना ही स्थितियों में—दम बान का ध्यान रगना चाहिए कि भाषा-समस्या को लेकर छाटी और बड़ी—दोनों ही तरफ की—जातियों में अध राष्ट्रवादी रुमान पदा न ह।

यह हुआ भाषा-समस्या का सामान्य महत्व।

### भारत में भाषा समस्या का विशेष महत्व

ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विनाश भारत की शमाम जनता सघन करती रही है—सबसे पहले भाषा-समस्या का महत्व दम सघन के स-दम में है।

ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने अंग्रेजी को अनिवार्य राजभाषा के रूप में भारत पर इस-दिए सादा कि वह जनता का शोषण कर सके। इस प्रकार उसने भारत की एक जातियों की भाषाओं की प्रगति मबाधा डाली। स्वाधीनता संग्राम के दौरान भारतीय जनता ने यह भाग बराबर पेश की कि सिंधा-समस्याओं, अदालतों, शासनत्र आदि में अंग्रेजी की जगह उसकी भाषा का चनन ह। जातीय प्रदेशों में अंग्रेजी की जगह वहाँ की भाषाओं का व्यवहार हो, जनता के लिए यह अब भी ज्वलन्त प्रश्न बना हुआ है और अगस्त, सन् १९४७ के राजनीतिक परिवर्तन के बाद यह समस्या अभी वहाँ हल हानी नहीं दिखाई देनी।

हिन्दुस्तानी श्रेय तथा समस्त भारत की राजभाषा हिन्दी, उर्दू अथवा हिन्दुस्तानी हो—इस स-दर्भ में भारत की भाषा-समस्या विशेष महत्वपूर्ण हो गई है। सबसे बड़े प्रचार समस्या के इसी पक्ष का लेकर हुए हैं। प्रमुख सामाजिक समस्याओं में जनता का ध्यान हटाने में उच्च वर्गों के पाम हिन्दी उर्दू समस्या सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक साधन रही है। साम्प्रदायिक विद्वेष पैदा करने के लिए इस समस्या का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है। भारत और पाकिस्तान में चरम प्रतिक्रियावाद अपने हिन्द साधने के लिए इस समस्या का उपयोग करते हैं।

भारत-जैसे बहुजातीय देश में अनिवार्य राजभाषा का प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुजातीय पूँजीवादी राज्यों से देखा जाता है कि इस तरह की अनिवार्य राजभाषा राजनीतिक-सांस्कृतिक क्षेत्रों में दूसरी भाषाओं के व्यवहार पर रोक लगाती है और कभी-कभी उनके इस अधिकार को एकदम अस्वीकार करती है। भारत के बड़े पूँजीपतियों से अन्य जातियों और जनसमूहों का जो सम्बन्ध है, उसे देखते हुए राष्ट्रभाषा का प्रश्न अपना बर्ग महत्व रखता है।

कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ लोग मिली-जुली बोलियाँ बोलते हैं। वहाँ सामन्ती सम्बन्ध अब भी कायम हैं। वहाँ के जातीय प्रदेश में टकसाली जातीय भाषा का विकास अभी तक नहीं हो पाया। राजस्थान, हिमाचल में जहाँ पहाड़ी बोलियाँ बोली जाती हैं, ऐसे ही इलाके हैं।

भाषा-समस्या कबीलों और पिछड़े हुए जातीय गुटों के लिए महत्वपूर्ण है। विभिन्न पूँजीवादी गुट इनका शोषण करते हैं। उन्हें अपनी भाषाओं के व्यवहार करने का अधिकार नहीं है। उनकी भाषाओं का अस्तित्व ही अस्वीकृत कर दिया जाता है।

इतनी बातों से ही स्पष्ट हो जाता है कि मजदूर वर्ग और उसकी पार्टी को भाषा-समस्या पर क्यों ध्यान देना चाहिए।

## ब्रिटिश साम्राज्यवाद और राजभाषा के रूप में अंग्रेजी की भूमिका

शिक्षा और संस्कृति के मामलों में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नीति यह रही है कि आम जनता को अज्ञान और पिछड़ेपन की दशा में रखा जाय। शासन-व्यवस्था के लिए क्लर्कों की फौज तैयार करने के लिए साम्राज्यवाद ने अंग्रेजी की पढ़ाई अनिवार्य कर दी और उसे शिक्षा का अनिवार्य माध्यम बनाया। पाश्चात्य विचारधारा के सम्पर्क से भारतीय भाषाओं और साहित्य को जो भी लाभ हुआ, वह अप्रत्यक्ष रूप से हुआ; वह लाभ साम्राज्यवादियों की आशाओं के विपरीत था। इस बात का प्रचार वे बराबर करते रहे कि भारत भाषाओं का अजायबघर है और उसमें जो भी एकता है वह इसलिए कि अंग्रेजी ने 'लिंगुआ फ्राङ्का' की भूमिका पूरी की है। यूरोप के अनेक प्रसिद्ध भाषाशास्त्रियों ने ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की यह स्थापना मान ली, इसलिए भी कि अपने उपनिवेशों में वे भी यही खेल खेल रहे थे।

भारतीय जनता ने माँग की कि शिक्षा, अदालत, कचहरी, शासन इत्यादि में अंग्रेजी की जगह उसकी अपनी भाषा चले। यह विलकुल न्यायपूर्ण माँग थी। राष्ट्रीय नेताओं से आशा की जाती थी कि सन् १९४७ में आजादी पाने के बाद इस माँग को वे पूरा करेंगे। लेकिन विभिन्न कारणों से वे उसे पूरा नहीं कर सके। सबसे पहला कारण तो यह है कि अक्सर ये नेता स्वयं अंग्रेजी में डूबे होते हैं। उन्होंने भारतीय भाषाओं के विकास के लिए प्रायः कुछ भी नहीं किया। दूसरा कारण यह है कि वे विभिन्न जातीय भाषाओं में संस्कृत के शब्द ठूँनने की नीति पर चल रहे हैं, जिससे कि आम जनता देश के राज-

जीवन और साम्प्रतिक जीवन में भाग न ले सके। जब इस सम्बन्ध-गर्भित भाषा पर लाठी हँसने हैं और उनकी हँसी उचित ही है, तब वे एक सदे आह भरकर अंग्रेजी की गरण में लोट आते हैं और कहते हैं कि अंग्रेजी अभी पाँच या दस साल और चलन ही ज़ायम। दो साल तक उदात्त उच्चारण का राष्ट्रीयकरण न होगा, वैसे ही पाँच या दस साल तक ज़ायम ज़तना की उच्च गिना राजनीतिक और सांस्कृतिक कायवाही उसही अपनी भाषा में न होगी।

बुद्ध विद्वान् ज़िन्दी के ही मस्तीकरण की माँग नहीं कर रहे हैं। बंगला जैसी भाषा में बावही विद्वान् उसी मस्तीकरण की माँग कर रहे हैं और उनका उद्देश्य भी वही है। कुछ समय पहले पश्चिम बंगाल की सरकार ने उच्चकोटि के विद्वानों की एक समिति बनाई जिसमें प्रसिद्ध भाषाविद् डा० सुनीतिकुमार चटर्जी भी थे। इस समिति का यह काम भीषण गया था कि वह शासन में व्यवहार के लिए बंगला में पारिभाषिक शब्दावली बनाए। इस शब्दावली की भूमिका में उन उच्चकोटि के विद्वानों ने कुछ प्रचलित शब्दों को अस्वीकृत कर दिया क्योंकि उनकी समझ में वे शब्द काफी गरिमायुक्त नहीं हैं। उनके बदले उन्होंने ऐसे शब्द रखे हैं जो जन-साधारण की समझ में नहीं आते, जो कभी-कभी असाधारण जनों की समझ में नहीं आते। इसलिए पारिभाषिकी-निर्माताओं न बंगाली जनता के देश प्रेम को लनकारा है कि जैसा वे अंग्रेजी का अध्ययन करते रहें हैं, वैसे ही मातृभाषा के अध्ययन की भी अधिक समझ दें।

केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारें जनता की इस माँग को पूरा नहीं कर पा रही हैं शिक्षा-संस्थाएँ, कचहरी, अदालत, सरकारी दफ्तरो आदि में जनता की भाषाओं का व्यवहार हो। शिक्षा और मस्ति के क्षेत्र में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की विरासत कायम है।

पूँजीवादी सामन्ती औपनिवेशिक व्यवस्था भारतीय भाषाओं के पूर्ण विनाश को रोकती है। शासक-वर्ग जनता को या तो अंग्रेजी की गरण लेने को कहते हैं या भारतीय भाषाओं का ऐसा मस्तीकरण करते हैं कि वे लोगों को दुबोरा हो जाएँ।

### अनिवार्य राजभाषा का सवाल

विभिन्न प्रदेशों में अंग्रेजी की जगह भारतीय भाषाओं का व्यवहार हो, यह सही माँग है और मजबूर वगैरे इसका समर्थन करना चाहिए। लेकिन अंग्रेजी की जगह सारे देश में एक ही भाषा का चलन हो, यह माँग उस जनताधिक माँग में भिन्न है। अंग्रेजी ने सारे भारत पर अंग्रेजी लादी—यह साम्राज्यवादी काय था। उसका स्थान एक भारतीय भाषा ले ले, यह बात जनताधिक और न्यायपूर्ण न होगी। फिर भी पूँजीवादी नेता हिन्दी उर्दू या हिन्दुस्तानी और अंग्रेजी को भी अनिवार्य राजभाषा बनाने का कार्य करते रहे हैं।

भारत की नव्युनिष्ट पार्टों के राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया है कि बड़े पूँजी-

पति महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु आदि प्रदेशों के आत्मनिर्णय के अधिकार को नहीं मान रहे। 'हिन्दुस्तान टाइम्स' ने ६ दिसम्बर, १९४८ के अंक में लिखा है कि ब्रिटिश 'सम्पर्क' की कुछ विरासत सुरक्षित रहनी चाहिए जैसे कि हाईकोर्टों में केन्द्रीय भाषा का ही चलन होना चाहिए और विभिन्न प्रान्तों में एक ही केन्द्रीय भाषा का चलन न होने से उच्च शिक्षा की प्रगति में बाधा पड़ेगी। इस प्रकार विभिन्न प्रदेशों के हाईकोर्टों और उच्च शिक्षा-संस्थाओं में एक ही केन्द्रीय भाषा के चलन की माँग करके बड़े पूँजीपति जातियों के पूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास में बाधा डालते हैं।

भारत के बड़े पूँजीपति चाहते हैं कि अंग्रेजों की जगह देश के शोषक बन जाएँ; यह सम्भव न हो तो विदेशी मालिकों के साथ मिलकर शोषण में हिस्सा बँटाएँ। जब तक साम्राज्यवाद से समझौता नहीं हुआ था, तब तक वे भाषायी इलाकों—अर्थात् वहाँ के पूँजीपतियों के आत्मनिर्णय का अधिकार मानते थे। विदेशी मालिकों की छत्रछाया में जहाँ एक बार उनका अधिकार राज्यसत्ता पर हो गया, वहाँ उन्होंने राष्ट्रवाद, एकता, केन्द्र आदि के नाम पर अपने बायदे तोड़ना आरम्भ कर दिया। भारत के बड़े व्यापारी सारे भारत के लिए एक राष्ट्रभाषा या राजभाषा की चर्चा बराबर करते रहे हैं क्योंकि इसके द्वारा वे अपने हित में बाजार को मुदृढ कर सकेंगे और दूसरी जातियों के पूँजीपतियों को निकाल सकेंगे।

जो लोग हिन्दी, उर्दू या हिन्दुस्तानी बोलते या लिखते हैं, उन्हें बड़े पूँजीपतियों की महत्वाकांक्षाओं से दिलचस्पी नहीं हो सकती। वे बिल्कुल न चाहेंगे कि किसी भारतीय भाषा के पूर्ण और स्वतन्त्र विकास में बाधा डाली जाय। बड़े पूँजीपति उनकी साम्राज्य-विरोधी भावना से लाभ उठाना चाहते हैं। वे पूछते हैं: अंग्रेजी जाय; उसकी जगह कौन-सी भाषा ले?

वाम जनता अवश्य चाहती है कि अंग्रेजी उन पर न लदी रहे जैसे वह अब तक लदी रही है। बड़े पूँजीपति इस बात को जानते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि अंग्रेजी जाय। लेकिन वे लोगों को यह सोचने का मौका नहीं देते कि उसकी जगह कौन लेगा? बजाय यह कहने के कि जब अंग्रेजी जायगी तब प्रत्येक भारतीय भाषा को अपने स्वत्व प्राप्त होगा, वे पूछते हैं, कौन-सी एक भाषा अंग्रेजी की जगह लेगी। इस तरह सवाल को पेश करके वे जनता को गुमराह करते हैं।

जो लोग चाहते हैं कि इस तरह के सवाल जनतान्त्रिक ढँग से हल किये जाएँ, वे सबसे पहले हर जाति का यह हक मानेंगे कि हर स्तर पर वह अपने राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यों में अपनी भाषा का व्यवहार कर सकें और इस अधिकार पर कोई भी रोक न लगनी चाहिए।

इस के पूँजीवादी-सामन्ती राज्य में बोल्शेविक पार्टी ने माँग की थी कि अनिवार्य राजभाषा का चलन बन्द किया जाय। उसने हर जाति को राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अपनी भाषा के व्यवहार की पूरी छूट दी। बोल्शेविक पार्टी पर यह आरोप लगाया

मरा कि 'उमकी नीति अध्यावहारिक है।' 'नेतिन मे हम आरोप का उत्तर न देना' लिया, 'हम जाति के राष्ट्रवादी पूँजीपति' की दृष्टि में सबहारा का भाषा काम जातीय समस्या का मदभ म हवाई जाता है। सबहारा जन हर तरह का राष्ट्रवाद का विरोध करता है, इसलिए ये 'हवाई समानता की माँग करते हैं। वे माँग करते हैं कि मिट्टा नउ किनी का घाटे-मो बिना अधिकार न मिले।'

एवोनति भाषा-समस्या का व्यावहारिक समाधान पना करते हैं। वे कहते हैं कि नवी भाषाया म पाठ्य पुस्तकें छपवाने में व्यय का लक्ष्य होता है। तभीत उक्त सामान्यता जो विविधताओं म एक ही के द्वीय भाषा का चलन होता चाहिए। मरदुम कम दम तरह का व्यावहारिकता का स्वीकार नहीं कर सकते।

मोक्षियन मय में सभी अनिवार्य राजभाषा नहीं है। प्रधान मन्त्रिण में होने की अपनी भाषा में बातचीत का अधिकार है और सदस्य मर-मर भाषाया में चिह्न भाषा। व लतवाद की माँग कर सकते हैं। मोक्षियन मय के प्रजापन्ना म सभी की पढ़ाई स्कूला और बनिना म अनिवार्य है। इसम कोई थुराई नहीं है। जानिया की मनों के विचार कनों की पढ़ाई अनिवार्य नहीं की गई। भारत में यदि सभी जानिया म बराबर मर्या में चल-बानी दग में चुन हुए प्रतिनिधि पिठाक्रम में किसी स्तर पर किसी एक जातीय भाषा का अध्ययन अनिवार्य करना चाहें और किसी जानि के प्रतिनिधि इसका विरोध न करें तो 'म न'ह की प्रतिवाप पिठा में कोई दोष नहीं है। मुख्य बात यह है कि कोई 'भाषा किसी जानि पर उनकी दृष्टि के विरुद्ध लादी न जानी चाहिए।

बहुजातीय पूँजीवादी राष्ट्र में जानिया का उत्पीडन होता है। उमम अनिवार्य राजभाषा बड़े पूँजीपतियों के हित-साधन का कारण बनती है। उमने विभिन्न जानिया की भूमि जनता म एकता नहीं पैदा होती वरन् परस्पर विग्रह उत्पन्न होता है। हम नहीं चाहते कि कोई एक भाषा अपेक्षी की जगह ले। विदेशी साम्राज्यवाद ने हमारे ऊपर अपेक्षी लादी थी। हम नहीं चाहते कि किसी भारतीय भाषा के पूर्ण विनाश पर कोई देशी साम्राज्यवादी राक संगार्य। बड़े पूँजीपति उन जानियों के अधिकार नियमित करन हैं जो कमजोर आर्थिक विभाग कर चुकी हैं। जो जानिया पिछड़ी हुए हैं, - नई राजनीतिक और सामूहिक विज्ञान को ये बड़े पूँजीपति अवरोध कर देने हैं। वे उत्तम कहते हैं मुम्हारी अपनी कोई भाषा नहीं है जो भाषा हम मुम पर लादे, वही मुम्हारी भाषा होगी। इस नीति का हम विरोध करेंगे।

बहुजातीय दम में समाजवादी सत्ता स्थापित होने पर उत्पीडित जानियों की भाषाया को नया जीवन प्राप्त होता है। उनकी भाषाएँ और मरहटियाँ नई शक्ति पाकर लहलहा उठती हैं। समाजवाद जान पर विभिन्न जानियों की भाषाएँ मुरभाकर खम न हा जालेंगी और बड़ी जानि की भाषा उनकी जाहू न ले लेगी। इसलिए बहुजातीय समाजवादी राज्य में भी मरमात्र अनिवार्य राजभाषा का चलन न होगा।

मोक्षियन मय में सभी भाषा सबमें ब्यापक बोली और समझी जाती है। नह मर-

इसी जातियों की मातृभाषा तभी बन सकती है, जब उनका रूसीकरण हो जाय। स्तालिन ने बताया है कि तमाम दुनिया में समाजवादी क्रान्ति की विजय हो जाने के बाद भी भाषा और संस्कृति के भेद रहेंगे। इससे स्पष्ट है कि भविष्य में जनता का राज कायम होने पर भी सारे देश में केवल एक ही भाषा बोली जाय, ऐसा न होगा। देश में जनता का राज कायम नहीं हुआ। इसलिए खतरा यह है कि जातियों की समानता का सिद्धान्त ऊपर से मान लिया जाय और अमल में उसका उल्लंघन किया जाय। इसलिए भारत में अनिवार्य राजभाषा के रूप में या सारे देश की एकमात्र सामान्य भाषा के रूप में हिन्दी स्वीकार न की जाएगी।

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के राजनीतिक प्रस्ताव में दूसरी पर हावी होनेवाले बड़े पूँजीपतियों का उल्लेख है जो केरल, महाराष्ट्र, आन्ध्र आदि के आत्मनिर्णय के अधिकार का विरोध करते हैं। ये बड़े पूँजीपति मुख्यतः मारवाड़ी हैं। बिड़ला, डालमिया, सिंघानिया, गोयन्का आदि जिन्होंने भारत में अपना जाल बिछा रखा है, इसी जाति के हैं। इनमें अन्य पूँजीपति भी शामिल हैं जो मारवाड़ी नहीं हैं। बिड़ला, गोयन्का आदि की मातृभाषा हिन्दी नहीं राजस्थानी है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने सामन्तवाद को सुरक्षित रखा। ये सज्जन अपने घरेलू बाजार को सुगठित करके पूँजीपति नहीं बने; आरम्भ से ही अपने व्यापार और उद्योग-धन्धों का प्रसार वे अन्य प्रदेशों में करते रहे, यही कारण है कि इन्होंने राजस्थानी के लिए कुछ नहीं किया लेकिन हिन्दी पत्र निकालने में वे पूँजी लगाते हैं। उनकी नीति से दक्षिण तथा अन्यत्र लोग हिन्दी को अपने ऊपर हावी होनेवाली जाति की भाषा समझने लगे हैं। अंग्रेज और उनके हाली-मवाली भाषा-समस्या को लेकर विभिन्न जातियों में द्वेष फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। जातीय विद्वेष की जो अग्नि बंधका रहे हैं, उससे इन भाषाओं में परस्पर आदान-प्रदान का क्रम भंग होता है और बहुत से अन्य हिन्दी राष्ट्रवादी यह समझने लगे हैं कि और सब उनकी भाषा सीखेंगे, वे किसी की भाषा न सीखेंगे।

बड़े पूँजीपतियों की नीति हिन्दी को अनिवार्य राजभाषा बनाने की है। इसके विपरीत प्रान्तीय पूँजीपति कहते हैं कि उनके विरोधी भाषायी साम्राज्यवाद कायम करना चाहते हैं। और वे अपनी जाति को आत्मनिर्णय का पूरा अधिकार देने की बात कहते हैं, वशतः कि इस प्रश्न पर मजदूर वर्ग उनके झंडे के नीचे आ जाय। प्रान्तीय पूँजीपति जब इस तरह के दावे करते हैं, तब उनका पर्दाफाश करना चाहिए।

प्रान्तीय पूँजीपतियों की नज़र पड़ोसी इलाकों पर है। बिहार के आदिवासी इलाकों के लिए बंगाल और बिहार के पूँजीपतियों में झगड़ा है। बम्बई और मद्रास किसके हिस्से में होंगे, इसको लेकर झगड़े हैं। श्री पट्टाभि सीतारमैया श्री क० मा० मुंशी के भाषायी-साम्राज्यवाद का विरोध कर रहे हैं। लेकिन हैं दोनों एक ही थैली के चट्टे-बट्टे।

सभी जातियों की श्रमिक जनता मजदूर वर्ग के नेतृत्व में केन्द्रीय और प्रान्तीय दोनों तरह के पूँजीपतियों तथा जमींदारों के खिलाफ संघर्ष करके हर जाति के लिए



मदनमोहनमालवीय राजनीतिक और सामाजिक विकास का अधिकार सुनिश्चित कर सकती है। यही नीति है कि बड़े पत्रोपनि दूसरे पर अनिवार्य राजभाषा न पाद भर्त्सने और सभी जातियाँ की भाषाओं को विकसित होने का पूरा अवसर मिलेगा।

## हिन्दी-उर्दू-हिन्दुस्तानी समस्या

समस्या यह है कि हिन्दुस्तानी प्रदेश की भाषा हिन्दी, उर्दू या हिन्दुस्तानी में कौन-सी है या नीति है या इनमें कोई दो हैं।

हिन्दी केवल हिन्दुजा की भाषा नहीं है, मुस्लिम जनता भी हिन्दी बोलती है। उन्नीसवीं शताब्दी में मुसलमानों की भाषा नहीं है। बुनियादी तौर पर हिन्दी-उर्दू एक ही भाषा है। नेता का आधार जनमाधुर्य की बोचाल की भाषा है। दल बोचाल की भाषा के मतलब के प्रित न तो हिन्दी का एक वाक्य लिखा जा सकता है, न उर्दू का। उर्दूवाले कहते हैं, उनकी भाषा आम जनता की जवान है। वे ठीक कहते हैं, इस अर्थ में कि जनता की भाषा के बिना उर्दू का एक वाक्य नहीं लिखा जा सकता। हिन्दी-उर्दू में भेद उनके बोचाल के रूप में नहीं है, भेद है उनकी उच्च स्तरीय शब्दावली में। बोचाल की एक ही भाषा की दो शैलियाँ हैं। उनके भेद का कारण यह है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के जन्मन हमारे देश की जातियों का विकास विपरीत रूप में हुआ है।

विदेशी पूँजी ने भारतीय सामन्तवाद को अपना दास्त बनाया। उसने भारतीय उद्योग-धंधों का विकास रोककर, आम जनता का बुरी तरह शोषण किया और उसे अक्षिगति दिया, जमींदारों का बग बनाकर अपने लिए सहायक तैयार किया, यहाँ की भाषाओं के विकास को भरोसा रखा और जनता पर विदेशी भाषा लादी और बड़े पूँजीपतियों से मौदा पक्का किया कि मिलकर देश का शोषण करें।

इस कारण आम जनता सस्कृति के क्षेत्र में अपनी एकता का प्रभाव पूरी तरह न डाल सकी। पश्चात्य शिक्षा, भाषा और साहित्य ने बुद्धिजीवियों को जो भी प्रेरणा मिली हो, आम जनता अपनी साम्राज्य-विरोधी, सामन्त विरोधी पूँजीवाद विरोधी दृष्टिकोण का प्रभाव सस्कृति पर नहीं डाल पाई। ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने रायसाहबों, राय बहादुरों, नाननहादुरों आदि की सेना तैयार कर ली और ये हिन्दी-उर्दू के नेता बन गए। इनके साम्राज्य-परस्त दृष्टिकोण का प्रभाव भाषा के विकास पर भी पड़ा। ब्रिटिश साम्राज्यवाद प्रत्यक्ष रूप से तथा अपने सहायकों के जरिये अप्रत्यक्ष रूप से भाषा और सस्कृति के मामलों में दखल देना रहा। भाषा और साहित्य में वह धार्मिक विद्वेष भड़काता रहा। प्रियसन का मत था कि इस्लाम के साथ उर्दू दूर-दूर तक फैली, उन्हें इस बात का ध्यान न रहा कि भारत में इस्लाम के प्रवेश के बहुत दिनों बाद उर्दू का विकास आरम्भ हुआ। प्रियसन ने यह नहीं बताया कि इस्लाम के साथ उर्दू भारत में ही क्यों आई, मिन्न, अलजीरिया, तुर्की या इस्लाम के घर अरब में क्यों नहीं पहुँची?

ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने सामन्तवाद का शोषण किया। सामन्ती बग की विशेष

विचारधारा है पुनस्तथानवाद । इसके प्रभाव से धार्मिक और साम्प्रदायिक रुझान मजबूत हुए हैं । ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने भारत की हर जाति को ब्रिटिश सूबों और देशी राज्यों में बाँट दिया । इस कारण जातियों की सांस्कृतिक और राजनीतिक एकता दृढ़ करने में रुकावट हुई ।

भारत के नेता जब दुनमुल तरीके से साम्राज्यवाद का विरोध कर रहे थे, तब वे भाषा और संस्कृति को धर्म से परे मानते थे । वे कहते थे कि नागरी और फारसी लिपि में लिखी जानेवाली हिन्दुस्तानी राष्ट्रभाषा होगी । वे साम्राज्यवाद से समझौता करने और जनवादी क्रान्ति के विरोध के रास्ते पर चले । साम्राज्यवाद के खिलाफ जनता में जहाँ क्रान्तिकारी उभार आया, उन्होंने उसे दबाया । उन्हें भय था कि विदेश साम्राज्य के खात्मे के साथ कहीं उनकी शोषण-व्यवस्था भी खत्म न हो जाय । कांग्रेस के भीतर और बाहर उन्होंने किसानों और मजदूरों के वर्ग-संगठन बनाने का विरोध किया । किसानों और मजदूरों की एकता ही राष्ट्र की एकता को मजबूत कर सकती है, देश की हर जाति की भाषा और संस्कृति की एकता को मजबूत कर सकती है ।

इस नीति के कारण राष्ट्रीय नेता राष्ट्र के साम्राज्यवादी विभाजन में ही साझीदार नहीं हुए, वे अपने अन्दर भी अन्ध राष्ट्रवादी रुझान पालते रहे हैं । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी फासिस्ट संस्थाओं से संघर्ष करने का दिखावा करते हुए वे उस तरह की प्रवृत्तियों को कांग्रेस के अन्दर ही पुष्ट करते रहे हैं । वे सामान्य संस्कृति और सामान्य भाषा की मीठी-मीठी बातें भूल गए और चरम साम्प्रदायिक रुझानों का समर्थन करने लगे हैं । वे भाषा-विवाद जैसी चीजों का उपयोग इसलिए कर रहे हैं कि जनता जनतन्त्र और समाज-वाद के लिए संघर्ष करना बन्द कर दे । भाषा-विवाद और प्रान्तों के विभाजन से सम्बन्धित झगड़े उनके हाथ में ऐसे अस्त्र हैं जिनसे जनता का ध्यान मुख्य सामाजिक समस्याओं से हटा दिया जाय । सामन्ती-पूँजीवादी शोषणकायम रखने के लिए वे जनता में फूट डालनेवाले साम्राज्यवाद के तमाम दाँव-पेंच इस्तेमाल कर रहे हैं । इसलिए यह आशा करना व्यर्थ है कि वे इन समस्याओं को हल करने में रतीभर सहायता करेंगे । भारत में मजदूर वर्ग और उसके साथी किसान और मध्य वर्ग के लोग हरजाति की सामान्य संस्कृति और सामान्य भाषा का निर्माण करेंगे ।

कानपुर या आगरा की एक ही मिल में काम करनेवाले हिन्दू और मुसलमान मजदूर क्या दो भाषाएँ बोलते हैं ? उनकी भाषा एक है । उत्तर प्रदेश के किसान भी एक ही भाषा बोलते हैं और एक-दूसरे की बात समझते हैं । अपने दफ्तरों और मुहल्लों में मध्यम-वर्गीय कामकाजी लोग आपस में एक ही भाषा बोलते हैं । हर प्रदेश में हिन्दू और मुसलमान मजदूरों की भाषा एक है, हिन्दू और मुसलमान किसानों की भाषा एक है, मध्य वर्ग के कामकाजी हिन्दुओं और मुसलमानों की भाषा एक है । इस भाषा में स्थानीय भेद होते हैं किन्तु धर्म के आधार पर भेद नहीं पैदा होता । जब बोलचाल की भाषा साहित्य और उच्च सांस्कृतिक कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है, तब उसकी शब्दावली में भेद पैदा हो जाता है ।

हिन्दी-उर्दू बुनियादी तौर से एक है किन्तु अपन साहित्यिक रूपों में भिन्न है, यह अन्तर्विरोध सामाजिक अन्तर्विरोध का ही परिणाम है। साम्राज्यवाद ने सामन्तवाद कायम रखा और पूँजीवादी वर्ग में हिन्दू मुस्लिम आधार पर भेद डाला। पूँजीवादी नेताओं की समझौतापद्धति के कारण साम्राज्यवादी नीति सफल हुई। यह कहना कि बोलचाल की भाषा में उच्च शिक्षा और सस्कृति के सभी कार्य सम्पन्न किए जा सकते हैं, सामाजिक विकास के वास्तविक अन्तर्विरोध में औरें मूढ़ लेना है।

हिन्दी और उर्दू का हिन्दू धर्म और इस्लाम में सम्बन्ध नहीं बिधा जा सकता। उद्दम इरान और ज़रब की साहित्यिक परम्परा का अनुसरण है, उसी साहित्यिक शास्त्रावली ज़रबी और फारसी के आधार पर रखी गई है। हिन्दी की साहित्यिक शास्त्रावली का आधार मन्त्रत है और वह भारत की साहित्यिक परम्परा का अनुसरण करती है। दोनों की ही साहित्यिक परम्परा में सामान्य जनवादी तत्त्व विद्यमान हैं और इन्हीं के आधार पर भविष्य में सामान्य साहित्यिक भाषा का विकास होगा। जो विमुक्त धार्मिक तत्त्व हैं वे विहीन हो जाएंगे, पुरानी गाथाएँ, देव-कथाएँ आदि सामान्य सांस्कृतिक परम्परा का अंग बन जाएंगी। हिन्दी और उर्दू में धाज जो परस्पर-भिन्न साहित्यिक परम्पराएँ दिखाई देती हैं, वे एक ही साहित्यिक भाषा और सामान्य साहित्यिक परम्परा के विकास में दुर्लभ बाधा नहीं हैं। जनसाधारण की उच्च सांस्कृतिक आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए (अर्थात् उर्दू दशन, राजनीति, अर्थशास्त्र आदि की शिक्षा देने के लिए) जनवादी आन्दोलन की बढ़ती के साथ दोनों के बीच का फास दूर होगा।

बोलचाल की भाषा में केवल सस्कृत के या केवल अरबी-फारसी के शब्द नहीं होते। साहित्यिक शास्त्रावली में शुद्धता की रक्षा न की जा सकेगी। राष्ट्रमन्त्री ने सविधान का 'मर्मोदा' लिखा है जबकि डॉ० रघुवीर न मसौदा के लिए 'प्राख्य' लिखा है। कुछ लोग कहते हैं कि साहित्य की भाषा और जनता की भाषा में सदा अन्तर रहेगा। यह भेद उच्च वर्गों और जनसाधारण की सस्कृतिका भेद प्रकट करता है। जनतन्त्र और समाजवाद की आर प्रगति के साथ यह भेद भी मिट जाएगा। प्रगतिशील लेखक जब जन-संघर्षों को आगे बढ़ाते हैं लिए साहित्य रचते हैं, तब यह भेद खत्म हो जाता है या कम हो जाता है।

दारापूरी पूँजीवादी नेता हिन्दी-उर्दू को मिलाते में असफल हुए। वे यह न जानते थे कि दोनों में भेद क्यों है। उन्होंने इस समस्या का सम्बन्ध आभ जनता की सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रगति में नहीं आड़ा, उन्होंने यह नहीं देखा कि इस समस्या का सम्बन्ध जनता की निरक्षरता दूर करने से है, जनसाधारण के लिए साहित्य और सस्कृति मुलभ करने से है, ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के सहयोगियों ने बुद्धजीवियों में जो पुनरुत्थानवादी दमन पैदा किए हैं, उनमें संघर्ष करने से है।

मान्यप्रदायिक अनुपात लागू करने से (अर्थात् अनुमानित आदि के कितने एम० एल० ए० होंगे, यह निर्दिष्ट करने से) हिन्दू-मुस्लिम समस्या हल न हो सकती थी। इसी तरह फारसी और संस्कृत के बोझ से किसी निर्दिष्ट अनुपात के अनुसार धाद लेकर

मिलाने से सामान्य साहित्यिक भाषा का विकास न हो सकता था।

दो लिपियों में लिखी जानेवाली हिन्दुस्तानी भाषा समस्या का कोई हल प्रस्तुत नहीं करती। दोनों लिपियों में यदि शब्दावली भिन्न है, तो हिन्दुस्तानी नाम देने से बेहिसाब भगड़े बढ़ते हैं। हिन्दी और उर्दू में आज वास्तविक भेद है। यह भेद खत्म करके तुरन्त हिन्दुस्तानी नहीं गढ़ी जा सकती। इसलिए अभी कुछ समय तक हिन्दी और उर्दू दोनों का चलन स्वीकार करना चाहिए जिससे कि स्वाभाविक रीति से दोनों मिलकर एक हो जाएँ।

## पारिभाषिक शब्दावली की समस्या

लोग कहते हैं कि भारतीय भाषाएँ संस्कृत से उत्पन्न हुई हैं। इसलिए हिन्दी का जितना ही संस्कृतीकरण होगा, वह सारे भारत में उतनी ही सुबोध और लोकप्रिय होगी। पिछले पाँच सौ वर्षों का इतिहास बतलाता है कि भारतीय भाषाओं में असंस्कृत रूप निरन्तर विकसित होते गये हैं। ये रूप लोकप्रिय हैं, इसमें जरा भी सन्देह नहीं। कहा जाता है कि बँगला में संस्कृत शब्द सबसे ज्यादा हैं। 'बँगला भाषा का उद्भव और विकास' नामक ग्रन्थ में डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी ने लिखा था, "आधुनिक बँगला के बोलचाल वाले रूप में संस्कृत शब्दों का अनुपात आश्चर्यजनक रूप से कम है" (खण्ड १, पृ० २२१)। कारण यह है कि 'तद्भव शब्दों का सम्बन्ध आये दिन के जीवन से है और भाषा में, कहना चाहिए, सबसे ज्यादा ध्रम इन्हीं को करना पड़ता है।' (उप०, पृ० १६७-६८)

संस्कृत के शब्द अपने तद्भव रूप में सुरक्षित रहते हैं। शुद्धतावादी के लिए ये शब्द अशुद्ध हो जाते हैं। न केवल बँगला में वरन् उन तमाम भारतीय भाषाओं में, जो संस्कृत से सम्बद्ध हैं, तत्सम शब्दों की संख्या आश्चर्यजनक रूप से कम है। संस्कृतीकरण द्वारा हिन्दी को लोकप्रिय बनाने की माँग ग़लत है और लोगों को उसका विरोध करना चाहिए। उर्दू को फारसी-गर्भित करना उर्दू के लिए हानिकारक है और उर्दू-प्रेमियों को उसका विरोध करना चाहिए।

इसका यह अर्थ नहीं है कि हिन्दी-उर्दू, संस्कृत-फारसी से शब्द न लें। यह कार्य विवेक से, बोलचाल की भाषा की प्रकृति पहचानते हुए करना चाहिए। इससे भाषा समृद्ध होगी और उसका लोकप्रिय रूप नष्ट न होगा। नये शब्द गढ़ने और उधार लेने के अलावा, बोलचाल की भाषा की रचनात्मक क्षमता को भूल न जाना चाहिए। हिन्दी-उर्दू की उच्च शब्दावली में अंग्रेज़ी शब्दों का प्रवेश भी विलकुल वन्दन न करना चाहिए।

कई लोग पारिभाषिक शब्दों के छोटे-बड़े कोश बना रहे हैं। वे कहते हैं कि जो शब्द प्रचलित हैं, वह पारिभाषिक नहीं हो सकता। संविधान के अनुवादक श्री घनश्याम सिंह गुप्त ने लिखा है, "सभी भाषाओं में लोक-प्रचलित शब्द अर्थ की दृष्टि से शिथिल और अनिश्चित होते हैं... हर विशेष विषय की अपनी विशेष शब्दावली होती है और लोक-प्रचलित भाषा से यह उद्देश्य सिद्ध नहीं होता।" (भारतीय संविधान का प्रावरण,

१९६८)

अपानी हिन्दी पाठक की सहायता के लिए डॉ० रघुवीर ने श्रुतिधान के मसौदे के अन्त में गन्द-सूची दे दी है। इस सूची से बहुत अच्छी तरह पता चल जाता है कि पारिभाषिक तथा लोक-प्रचलित शब्दावली में किस तरह का सम्बन्ध है। शब्द-सूची के पहले तीन पृष्ठों में इस तरह के अंग्रेजी शब्द दिये हुए हैं—

ओपन, पायर-आर्म, आडिट, अनाउंस, ऐक्ट, बारट, एडवोकेट, मीटिंग, मीट, क्लेम जाईनिंग आर्टीकल, साइमन, डाट, प्रविटस, प्री, सेपरी, एजेंट, इजीनियरिंग, रेलवे, माइनर इत्यादि। ये शब्द अंग्रेजी में ही लोक-प्रचलित नहीं, उनमें से बहुतों को हमें देना पड़ेगा कि अतिशय कम ही सम्भव है। अधिपत्र, अधिष्ठान, अयोध्या क्या हैं? बारट, मीट और रेलवे।

यदि अंग्रेजी के लोक-प्रचलित शब्द उस भाषा में पारिभाषिक माने जा सकते हैं तो कोई कारण नहीं कि उस नियम का पालन हिन्दी में न किया जाय। कठिन शब्दावली का पता यह होगा कि जनताधारण शिक्षा और मस्कृति में दूर रहेंगे। दुःख की बात यह है कि डॉ० रघुवीर के बनाये हुए बहुत से शब्दों को उच्च शिक्षा पाये हुए लोग भी नहीं समझते। इस जड़ता को भारत के प्राचीन गौरव और राष्ट्रीय एकता के नाम पर स्थापपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। अपनी गन्द-सूची की भूमिका में डॉ० रघुवीर ने लिखा था, “हमन भौतिक ही नहीं, ऐतिहासिक दृष्टि में भी भारत की एकता का ध्यान रखा है। भारत के दीर्घकालीन गौरवमय अतीत में जो कुछ उपयोग्य था, उस हमने आत्ममान् कर लिया है।”

वास्तव में उन्होंने जो कुछ किया है, वह इसका ठीक उलटा है। उन्होंने बेसुनाम शब्द छोड़ दिये हैं, जो न केवल हिन्दी-भाषी प्रांती मकरन् दक्षिण भारत तथा अन्य समझे जाते हैं। ये शब्द उनके लिए पारिभाषिक नहीं हो सकते क्योंकि इनमें लोकप्रियता का दावा ला गया है। उन्होंने वे समस्त शब्द छोड़ दिये हैं जो अतीत में जनता के परस्पर सम्पर्क के कारण प्रचलित हो गये हैं। महापंडित राहुल साहूत्यायन ने डॉ० रघुवीर की आलोचना की है और उनके अनुवाद के बदले अपना अनुवाद प्रस्तुत किया है।

हम कोई मन्देह नहीं कि नये शब्द आवश्यक हैं और वे या तो दूसरी भाषाओं से लिए जायेंगे या प्राचीन भाषाओं के शब्दों, धातुओं के आधार पर गढ़े जायेंगे। जो लोग इन शब्दों का व्यवहार करेंगे, उनकी आवश्यकताएँ ध्यान में रखी जायें तो यह कार्य ज़्यादा सन्तुष्टजनक हो से सम्पन्न होगा। सबसे पहले उन शब्दों का संग्रह करना चाहिए जिनका व्यवहार विभिन्न पेशों के लोग पढ़ने से ही कर रहे हैं। इसके बाद सम्स्कृत, फारसी या अंग्रेजी से आँख मूँदकर शब्द न लेने चाहिए बल्कि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे बोलीबाल की भाषा की प्रवृत्ति के अनुकूल हैं या नहीं। ग्रीक और लैटिन के आधार पर बनाये हुए जो अंग्रेजी के शब्द यूरोप की अन्य भाषाओं में प्रचलित हैं उन्हें विदेशी होने के कारण ही न छोड़ देना चाहिए। आवश्यकतानुसार उनकी जगह लोकप्रिय

हिन्दुस्तानी शब्दों को दी जा सकती है।

हिन्दी-उर्दू की उच्च स्तरीय सांस्कृतिक शब्दावली देर में धुल-मिलकर एक होगी, लेकिन सामान्य बोलचाल की भाषा की तरह हिन्दी-उर्दू की पारिभाषिक शब्दावली भी एक दिन मिलकर एक होगी, इसमें जरा भी सन्देह नहीं है।

## लिपि का प्रश्न

लिपि भाषा का अभिन्न अंग नहीं है। यूरोप की अनेक भाषाएँ लैटिन वर्णमाला का व्यवहार करती हैं। किन्तु इससे वे मिलकर एक नहीं हो जाती। भारत में हिन्दी और मराठी की लिपि प्रायः एक-सी है, फिर भी दोनों भाषाओं में बहुत अन्तर है। इस दृष्टि से लिपि का प्रश्न गौण है। फिर भी लिपि-भेद होने से हिन्दी-उर्दू के बीच का फासला बढ़ा है। यदि हिन्दी के पाठक उर्दू से और उर्दू के पाठक हिन्दी से परिचित होते तो यह फासला इतना बड़ा न होता। एक लिपि होने से उन्हें निकट लाने और मिलाने में सुविधा होगी।

एक लिपि की स्वीकृति स्वेच्छा से ही हो सकती है। फिर भी मजदूर वर्ग को आन्दोलन करना चाहिए कि एक ही लिपि का चलन हो जिससे हिन्दी-उर्दू जल्दी-से-जल्दी धुल-मिलकर एक हो सकें। यह लिपि कुछ सगोथनों के साथ देवनागरी ही हो सकती है।

## पिछड़ी हुई जातियों की भाषाओं का प्रश्न

भारत में मराठी, बँगला, तमिल, तेलुगु आदि सुविकसित भाषाओं के अलावा बोलियों के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ किसी बोली ने विकसित होकर अभी भाषा का रूप नहीं लिया। इस तरह के क्षेत्रों में राजस्थान है। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जिनके लिए पड़ोसी प्रान्तों के पूँजीपतियों में आपस में झगड़ा है। बिहार के आदिवासी इलाकों के लिए बंगाली और बिहारी पूँजीपतियों में झगड़ा है। कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ लोग अभी आदिम समाज-व्यवस्था में ही रह रहे हैं। मध्यप्रदेश और राजस्थान के आदिवासी न अपना, न अपनी भाषाओं का विकास कर पा रहे हैं। इनकी भाषाओं के विकास की बात कोई हवाई सैद्धान्तिक प्रश्न नहीं है। यह उनके सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का प्रश्न है। जनवादी आन्दोलन और मजदूर वर्ग को उनके राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए।

## हर बोली या भाषा के लिए एक प्रजातन्त्र का सवाल

महार्पडित राहुल सांकृत्यायन कुछ समय पहले तक यह माँग करते रहे हैं कि उन प्रदेशों में प्रजातन्त्र कायम किया जाय जहाँ अवधी, ब्रजभाषा, बुन्देलखण्डी आदि का चलन है। उनके चरणचिह्नों पर श्री शिवदानसिंह चले (देखिए उनकी पुस्तक 'प्रगति-

वाद' में जनपद जादातन नाथ (निवृत्त), श्री व्योमराज राजेन्द्रमिश्र श्री बनारसीदास चतुर्वेदी आदि जन-जादातनो में लोग दत्त रह हैं। प्रश्न यह है कि अवधी, ब्रजभाषा, बुन्देलखण्डी आदि बालियाँ हैं या भाषाएँ, उनके योजनवाले हिन्दुस्तानी जाति के अन्तर्गत हैं या भिन्न भिन्न स्वतन्त्र जातियों के रूप में विकसित होंगे। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या इनमें एक ही कृत्रिम प्रजापञ्च या प्रान्त बनना चाहिये।

गाँवा में किसान अवधी ब्रज आदि का व्यवहार करते हैं। गहरों के मजदूर, सामानों में मिठा और कारखाना के श्रमिक आपस में खड़ी बोली का व्यवहार करते हैं। कापुर में उन्नाव रायचरेनी, पीतापुर, गाँवा और छपरा तक में मजदूर आते हैं। लखनऊ जंगल और भीमों के साथ बकवास कारखानों आदि में इसी तरह विभिन्न क्षेत्रों के मजदूर काम करते हैं। जो किसान सीधा गाँव में आकर मजदूर बना है, वह अपना गाँव की बोली बोलता है और उसके साथी उसकी बात समझ लेते हैं। कुछ समय बाद वह गहर की बोली—खड़ी बोली—सीख लेता है और अपने साथियों से इसी में बात करता है। यद्यपि घर पर वह अपनी गाँव की बोली का ही व्यवहार करता है।

हिन्दुस्तानी प्रदेश के मजदूर का में अवधी, ब्रज आदि बोलनवाले लोग हैं। इनका सामान्य परिवेश और सामान्य आर्थिक सम्बन्ध उन्हें एक सामान्य भाषा बोलने पर मजबूर करत हैं। यह भाषा खड़ी बोली या हिन्दुस्तानी होती है। अलबारी में अर्द्धो नियम के लिए, इनकारों के लिए नर्मो जंगल जानपुर और लखनऊ के मजदूर बुन्देलखण्डी, ब्रजभाषा या अवधी का व्यवहार नहीं करते। ये मजदूर हिन्दी उर्दू का ही व्यवहार करते हैं और उनकी बोलीचान में कोई भेद नहीं होता। शहरों के मध्यवर्गों का भी यही हाल है।

खड़ी बोली और पारसी के मध्य में खड़ी बोली (उर्दू) की विजय हुई। कविता में ब्रजभाषा का व्यवहार हो या खड़ी बोली का, इस संपर्क में खड़ी बोली (हिन्दी) की विजय हुई। भारत-दुःखापुरी क्षेत्र के थे प्रजापनारायण मिश्र अवध के, राधाचरण मास्वामी ब्रज के इन सबने एक के लिए खड़ी बोली का अपनाता। यह विकास उन्नीसवीं सदी में हुआ किन्तु उसका आरम्भ पहले ही हुआ था। इस विकास का कारण था पूँजीवाद का विकास। भारत में पूँजीवाद उन्नीसवीं सदी से आरम्भ नहीं हुआ। व्यापारी पूँजीवाद उन सौदागरों के साथ शुरू हुआ जो अपने साथ खड़ी बोली मुद्रा हैदराबाद ले गये। ब्रिटिश पूँजीवाद में टकराव होने पर भारतीय पूँजीवाद के सहज विकास में बाधा पड़ी लेकिन वह रुक नहीं गया। पूँजीवाद के विकास के साथ हम मिलों और कारखानों में मजदूरों की खड़ी बोली बोलन देखते हैं। देशान्त में जहाँ सामन्ती सम्बन्ध अब भी दृढ़ हैं, वहाँ भाषायों एकीकरण का यह काम पूरा नहीं हुआ। मध्यवर्ग पूँजीवादी विकास का ही परिणाम है और किसानों की अपेक्षा यह वय खड़ी बोली का अधिक अपनाता है। इसी कारण हिन्दी-उर्दू लेखकों में ऐसे लोग हैं जो घर में खड़ी बोली से अलग अन्य कोई बोली नहीं बोलते हैं। श्री मैथिलीकरण गुप्त घर में बुन्देलखण्डी, श्री राहुल

सांस्कृत्यायन भोजपुरी, श्री शिवमंगलसिंह 'मुमन' और अली सरदार जाफरी अवधी बोलते हैं, या पहले बोलते थे ।

इसका अर्थ यह है कि उपर्युक्त बोलियों के बोलनेवाले पूँजीवाद के विकास के साथ एक ही जाति में संगठित हुए हैं, एक ऐसे स्थायी जन-समुदाय के रूप में गठित हुए हैं जिनकी सामान्य भाषा है और सामान्य आर्थिक जीवन है । यह विकास पूरा नहीं हुआ । सामन्ती सम्बन्ध अभी बने हुए हैं । इसीलिए हिन्दुस्तानी प्रदेश में भाषा और बोली का प्रश्न भी हमारे सामने आता है । खड़ी बोली 'भाषा' बनी; ब्रज, अवधी आदि 'बोलियाँ' रही । यह प्रक्रिया अनोखी नहीं है । जिन देशों में भी सामन्ती सम्बन्धों की जगह पूँजीवादी सम्बन्ध विकसित हुए हैं, वहाँ इससे मिलनी-जुलती प्रक्रिया देखने को मिली है । लन्दन के आस-पास की अंग्रेजी, पेरिस के आस-पास की फ्रांसीसी, मास्को के आस-पास की रूसी सामाजिक सम्पर्क और साहित्य की भाषा बनी । ब्रिटेन में वेलश जैसी भाषा अंग्रेजी के मुकाबले और फ्रांस में प्रोवांसाल जैसी समृद्ध साहित्यिक भाषा फ्रांसीसी के मुकाबले बोली की हैसियत ही पा सकी ।

समाज में किसान या मजदूर वर्ग के कुछ हिस्से अपनी बोली छोड़ते नहीं हैं या टकसाली भाषा के साथ उसका भी व्यवहार करते हैं, तो यह भारत में होनेवाली कोई अद्भुत क्रिया नहीं है । फ्रांस जैसे विकसित पूँजीवादी देश में भी बोलियों का अस्तित्व है । भाषाविद वान्द्राई ने ब्रेतों बोली के बारे में लिखा है, "मछुओं में, तराई के नमक बनाने वालों में स्लेट-मजदूरों और घुमन्त सौदागरों में ब्रेतों का व्यवहार अब भी होता है और कोई नहीं कह सकता कि कब तक होता रहेगा" (वान्द्राई, भाषा, लन्दन, १९३१, पृ० २८६) । मेइये के अनुसार इसी प्रकार फ्रांस और स्पेन में बास्क का व्यवहार होता है । इसलिए इसमें आश्चर्य न होना चाहिए कि हिन्दुस्तानी प्रदेश में टकसाली भाषा के अलावा भी अनेक बोलियों का चलन बना हुआ है ।

भाषा और बोली का भेद केवल भाषागत भेद नहीं है; वह सामाजिक भेद भी है । किन्ती समय हमारे यहाँ ब्रजभाषा और फ्रांस में प्रोवांसाल समृद्ध साहित्यिक भाषाएँ थी । पूँजीवाद के विकास के साथ दिल्ली, मेरठ तथा पेरिस के आस-पास की बोलियों को व्यापारी दूर-दूर तक ले गये । बोलियों ने भाषा का रूप लिया । जिन क्षेत्रों में अवधी, ब्रज आदि बोलियाँ अभी बोली जाती हैं, उनकी टकसाली भाषा खड़ी बोली है । इस टकसाली भाषा के कारण—साम्राज्यवाद और पूँजीवाद के बावजूद—यहाँ की जनता सीमित विकास कर सकी है । इन क्षेत्रों के मजदूर टकसाली भाषा यानी खड़ी बोली के जरिये एक-दूसरे के निकट आते हैं । इस तरह इस टकसाली भाषा का विकास जनवादी क्रान्ति की विजय के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 'जनयुग' और 'नया जमाना' अवधी, ब्रजभाषा आदि में निकाले जाएँ तो इससे मजदूरों की एकता दृढ़ न होगी । मैंने 'जनयुग' के लेख अवधी में उलथा करके उन्नाव और रायबरेली के किसानों को सुनाये हैं, यह देखने के लिए कि उनकी शब्दावली में कितना परिवर्तन करना पड़ता है । व्याकरण-रूपों को छोड़कर ६८



फीमरी शब्दावली बढ़ी रहती है। य बालियाँ एक-दूसरे के इतना निकट हैं कि यदि एक ही लेख—साम तीर से अखबारी पत्र—का उन्हा उनमे करें ता ६८ फीमरी इवारउ एक-सी होगी। य बालियाँ मुहावरो, मुन्दर अथ-अजक शब्दावली और अनहत बचनो स समृद्ध हैं। टकमाली भाषा के उन्वक इनमे बहुत कुछ सीख सकत हैं। इनमे अष्टना सजाना है जिन अपना मे टकमाली भाषा की व्यञ्जना-गति बहुत ज़ादा बढ़ेगी। लेकिन इनका यह जय बिनकुल नहीं है कि इनका व्यवहार करनेवाला कोइम स्वतन्त्र जानियो मान लें।

श्री राहुल साह्यायन तथा अन्य लोगों की यह माँग कि अवधी, बज्ज, बुंदेलखण्डी आदि की विभिन्न जानियाँ की टकमाली भाषा माना जाय, प्रात्रिय्यावादी माँग है। यह माँग केवल सामन्ती वर्गों के हित में है जो इन तरह एक पतनशील व्यवस्था की रक्षा करना चाहत हैं। इन माँग में हिन्दुस्तानी पदों के मजदूरों की एकता में बाधा पड़ती है।

हर बोली के लिए एक प्रजातन्त्र या प्रान्त बनान का मतान नहीं है। सीवियत संघ में ६० से ऊपर भाषाएँ हैं प्रजातन्त्र इनमे बहुत कम हैं। अवधी, बज्ज आदि विभिन्न जातियों की भाषाएँ होती, ता भी उनके लिए हर जगह प्रजातन्त्र कायम न किये जाते। वे बोलियाँ हैं, इसलिए उनमें स हक के लिए प्रजातन्त्र बनान की माँग विशेष रूप से हास्यास्पद है। आरक्षा के महाराज जनपद आन्दोलन में त्याग दिलवती लेते रहे हैं, यह बात आकस्मिक नहीं है।

भारत में भाषा-समस्या के ये कुछ मुख्य पहलू हैं।

(१९४६)

## जातीय भाषा के रूप में हिन्दी का प्रसार

जातीय भाषा बनने से पहले हिन्दी या खड़ी बोली एक जनपद की भाषा थी। ब्रज, अवध, बुन्देलखण्ड आदि जनपदों में ब्रज, अवधी, बुन्देलखण्डी आदि भाषाएँ बोली जाती थी। इन जनपदों में रहनेवाले छोटी-बड़ी रियासतों में बँटे हुए थे। वे सब किसी जाति में संगठित न हुए थे और इसीलिए एक जातीय भाषा के रूप में उनके पास आपसी व्यवहार की कोई भाषा न थी। कुछ पढ़े-लिखे लोग संस्कृत से काम चलाते थे लेकिन उसे आम जनता न तो समझती थी, न बोलती थी।

तब के समाज की दो विशेषताएँ ध्यान देने योग्य हैं। एक तो यह कि समाज चार वर्णों में बँटा हुआ था जिनके अन्तर्गत सैकड़ों जात-विरादरियाँ थीं। दूसरी यह कि गाँव बहुत-कुछ खुदमुख्तार थे; ऊपर से आँवी-तूफान निकलते रहें, ये छोटे-छोटे पंचायती राज अपनी जगह बदस्तूर कायम रहते थे।

तेरहवीं-चौदहवीं सदी में सामन्ती समाज का यह ढाँचा ढीला पड़ने लगा था, वर्ण-व्यवस्था शिथिल हो रही थी और लोग अपने खानदानी पेशे छोड़कर नये पेशे अपनाने लगे थे। तुर्कों के हमलों से यह ढाँचा और कमजोर पड़ा हालाँकि उसे तोड़नेवाली ताकतें उसके भीतर ही पैदा हो रही थी। तिलक जो हिन्दी और फारसी दोनों जानता था और अबुलहसन और महमूद गजनवी की सेवा में रहा था, एक नाई का लड़का था। रूहप नाम का एक बनिया परिवार राजा से क़िला छीनकर इल्तमश से लड़ा था (कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ़ इंडिया, खण्ड ३, पृ० ५३)। गुजरात में तगी चमार ने दिल्ली के बादशाह के खिलाफ विद्रोह की अगुआई की। हेमू, जिसने अकबर का मुक़ाबला किया था, बनिया था। अकबर का चित्रकार दसवन्त कहार था। रामानन्द के शिष्यों में कबीर जुलाहा, रैदास चमार और सेना नाई थे। कबीर के उत्तराधिकारी घरमदास बनिया थे। दाढ़ के लिए कहा जाता है कि वह मोची थे। उनके शिष्य मुन्दरदास बनिया थे और मलूकदास खत्री थे। इस तरह की और भी मिसालें दी जा सकती हैं। इससे नतीजा यही निकलता है कि संस्कृति पर अब ब्राह्मण-पुरोहितों का इजारा टूट रहा था; राज्य और घरती पर अत्रियो का अधिकार ढीला पड़ रहा था।

तुर्क बादशाहों ने बाज़ार, तोलने के बाँट, सिक्कों आदि के बारे में जो सुधार

जिसे, उसमें मोदागरा का फायदा पहुँचा। इस उमान में मई-नई मछियाँ और नये-नये मछर जायाद हुए। फीरोज मुगलक के लिए कहा जाता है कि उसने फीरोजाबाद, जनहाबाद, फीरोजपुर, बदायूँ, बीनपुर आदि शहर बनाये। गेरगाह के उमान में पटना गहर किए व्यापार का मन्द प्रता। उसके समय में जो मड़कें और नहरें नैपार हुई, उनसे व्यापार बढ़ा। गेरगाह १ सगाण बनवाई धार्मिक उदारता की नीति बरती, और साम बात यह कि राज्य और किसान के बीच सीधा सम्बन्ध कायम किया। पठने गांव का मुनिवा मानगुजारी तय करता था, उसका वह हक दित गया। इन गहर एक तरह से मोदागरी और व्यापार के केन्द्र के नीर पर गहर बडती पर ५, दूमरी तरफ गाँवा की खुदमुल्कारी पर पाइन्दी गयी। अकबर ने बाग़द का महत्व समझा। राज्य में गाँव कायम रखने के लिए उसने साम नीर में बाग़द का भरोसा किया। सामनी युग के तीर-नमान और तलवार पुरानी चीजें बनने लगे थे। अकबर ने मारे राज्य में एक-सी मुद्रा-व्यवस्था बताकर व्यापार की बडती में मदद की। तनवाह के लिए जाग्री दी लेकिन मालगुजारी बाराह तय करने का हक जागीरदारों को नहीं दिया। कभी-कभी उन्हें जागीर में दूर भी सेनात कर दिया जाता था। इस तरह सामनी और जागीरदारों की ताकत कम हुई। धार्मिक मामला में अकबर ने उदार नीति बरती।

मुगल बादशाहों का खुद भी व्यापार में दिलचस्पी थी। अकबर खुद व्यापार करना था। लखनऊ मुनिमिटी के डा० पत के अनुसार गुजरात आगरा और बदायूँ के बडिया उद्याना का इजारा उसने हाथ में था। शाहजहाँ ने नील का व्यापार अपने हाथ में रखा था और मनाङ्गम का राज्य में उधार रख कर व्यापार करने की आज्ञा दी थी और मुनाफे में हिस्सा लेता था। नरजहाँ भी नील और जरी के बन्नों के व्यापार में दिलचस्पी लेती थी। बादशाहों के भाई-भतीजे मोदागरी में घन कमाने थे। मुगल राज्यसत्ता की आमदनी का जरिया मिला जमीन न थी, बल्कि व्यापार भी था।

व्यापार की उन्नति से पुराने जनपदों का जलगाव दूर हुआ। पटना, बनारस, इलाहाबाद, आगरा और दिल्ली एने केन्द्र बन गये जिनके चारों तरफ एक कौमी बाजार कायम हुआ। यात्री मानगोके के अनुसार सन १६४० में आगरा की आबादी छ लाख थी। माकम ने बागरीय इतिहास पर अपनी पुस्तक में लिखा है कि अकबर के उमान में दिल्ली दुनिया का सबसे बड़ा शहर था। जो नया बाजार कायम हुआ, उसके सबसे बड़े केन्द्र आगरा और दिल्ली ही थे।

ब्रिटेन में हिन्दुस्तानी कपड़े की माँग बढ़ने से यहाँ का राजगार और चमका। सप्तर्ही नदी के पहले हिस्सा में जागम में विलासत कपड़ा मेजा जाता था और यह कपड़ा अबध में बिकर आता था। इस तरह अबध और अबध एक बाजार में संगठित हुए। खुद अबध में दरिदाबाद और खराबाद अपने उद्योगों के लिए प्रसिद्ध हुए। इसी तरह पटना, बनारस, लखनऊ वर्ग रहने में आम-धाम के दहात को अपनी तरफ समेटा और उनका पुराना अलाव बढ़ने कुछ दूर किया। शम्सी यात्री बनिबर ने जिन मुगल बाराणसी का जिक

किया है, मुमकिन है कि वे पूँजीवादी पैदावार की पहली मंजिल रहे हों। बहरहाल जुलाहों को सौदागर पेनागी रुपया देते थे और उनसे तैयार माल लेते थे। पेनागी लेने पर जुलाहा अपने माल पर अधिकार खो देता था। पेनागी के जरिये सौदागर उसकी श्रम-शक्ति खरीद लेता था। यह पैदावार का पूँजीवादी तरीका था। सन् १८४४ में एंगेल्स ने अपनी पुस्तक 'इंग्लैंड के मजदूर वर्ग की दशा' में लिखा था, "मशीनें चालू होने से पहले कच्चे मान को कातने और बुनने का काम मजदूर के घर पर होता था।" सत्रहवीं सदी में यह सिनमिला यहाँ भी कायम था। लैनिन ने मिखाइलोव्स्की को जवाब देते हुए बतलाया था कि सत्रहवीं सदी में आपसी विनिमय की वजह से, बिकाऊ माल के चलन के धीरे-धीरे तेज होने से, और छोटे-छोटे बाजारों के एक बड़े बाजार में सिमटने से रूसी जाति का निर्माण हुआ। सत्रहवीं सदी में इसी तरह हमारे यहाँ भी हिन्दुस्तानी जाति का निर्माण शुरू हुआ था।

भाषा और साहित्य के क्षेत्र में हम जनपदों का एक-दूसरे के नजदीक आना और उनका अलगाव दूर होना देखते हैं। 'रामचरितमानस' अवधी में लिखा गया है, लेकिन ब्रज, भोजपुरी आदि के इलाकों में भी वह अपनाया जाता है। यही नहीं, गोस्वामीजी ब्रज और अवधी दोनों में कविता करते हैं और उनकी भाषा में एक से अधिक बोलियों के शब्द और प्रयोग देखे जा सकते हैं। उधर ब्रजभाषा की कविताएँ—मीरा, सूर, रसखान और रहीम की रचनाएँ—दूर देहात तक पहुँच रही थी। खड़ी बोली में भी खुसरो, कबीर आदि रचनाएँ करने लगे थे। रहीम ने किसी को खड़ी बोली में ही गाते सुनकर लिखा था—भुक-भुक मतवाला गावता रेखता था।

दक्खिन में खड़ी बोली का अलग विकास हुआ, गद्य और पद्य दोनों में यह प्रदेश मुख्यतः तेलुगुभाषी था और खड़ी बोली वहाँ कम तादाद के लोगों की भाषा थी। उत्तर की भाषा पर उसका असर कुछ देर से पड़ा।

साहरों में व्यापार और विनिमय के लिए जिस भाषा का उपयोग होता था, वह भाषा खड़ी बोली या हिन्दी थी। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि देश-विदेश के जो लोग काम-काज के लिए दिल्ली या आगरा आते थे, वे यही भाषा सीखते थे। ग्रियर्सन ने लिखा है कि "उन दिनों के कुछ अंग्रेज सौदागर निःसन्देह घड़ल्ले से हिन्दुस्तानी बोल सकते थे..." (लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ़ इंडिया, खण्ड १, पृ० २)। और इतिहासकार सरदेसाई ने लिखा है कि इतालवी यात्री मनुच्ची ने शिवाजी से, बिना किसी दुभाषिये की मदद के उर्दू में बातचीत की। फारसी के दबाव की वजह से यह भाषा पहले-पहल दक्खिन में फूली-फली।

हिन्दुस्तान में जो तुर्क, पठान, ईरानी, उजबक आदि जातियों के लोग आये, वे यहाँ किसी नई भाषा को जन्म न दे सके। उनके बहुत से शब्द यहाँ वालों ने ले लिए, उनके प्रत्यय लगाकर कुछ नए शब्द भी गढ़े—जैसे पागलखाना, अफीमची (और पिछले दोनों जगवाज) वगैरह। लेकिन हमारी भाषा की व्याकरण-व्यवस्था, उसके मूल शब्द भण्डार

में कोई भारी तबदीली नहीं हुई। तुर्कों, पठानों, ईरानियों, उजबकों आदि के आने से पहले भी हिन्दी भाषा थी, उनके हिन्दुस्तानी बन जाने के बाद भी रही। इमतिाघादवाहों के लखवारा म नई उबाने गड़न की कल्पना भ्रामक है।

बाहर ने जानवाने लोग के शब्दों में हमारी भाषा और भुगुद हुई लेकिन उनमें अपन जातीय रूप की रक्षा की। भाषा के बार में गैरशाह और अकबर की नीति अंग्रेजों की तरह अनुशासनी थी। गैरशाह न तो फारसी के साथ हिन्दी में काम-बाज करने की हिदायत दे रखा थी।

वज्रभाषा, जवही नहीं बोली जादि सभी ने हिन्दुस्तानी जाति के निर्माण में मदद दी। हमारी जाति का चरित्र सघर्षों द्वारा जोर पक्का हुआ। इन सघर्षों के दो पहलू थे, एक तो जातीय धूनरा जनवादी। यानी एक तरफ तो यहाँ के लोग विदेशी आततायियों के खिलाफ लड़, दूसरी तरफ वे मामूली उपोहन के विनाश वण-व्यवस्था और पुरोहितों-सामन्ता के विरोध अधिकारों के विनाश भी लड़े। भक्ति-आन्दोलन में ये दोनों पहलू मौजूद हैं। जुलाहे और किसान इन आन्दोलन को शक्ति देनेवाले हैं। सौदागर उनके सहायक हैं, हिन्दू और मुसलमान सूफी और सत दानो उनमें शामिल हैं। भक्ति-आन्दोलन एक जातीय जाग जनवादी आन्दोलन है। क्या उस समय हिन्दुओं और मुसलमानों की दो मस्कृतियाँ थीं? कुछ धार्मिक भेदभाव खरूर था लेकिन दो मस्कृतियाँ नहीं थीं। जायसी, रमराम रहीम जायस दोष, पजनम वगैरह की वहाँ मस्कृति थी ओ मूर, मीरा, तुलसी नन्ददास, दादू रैदास आदि की थी। यह मस्कृति जातीय और जनवादी थी, दमीनिए कबीर को हिन्दू और मुसलमान दोनों अपनाते के लिए तैयार थे। दरबारों की मस्कृति अलग थी। मुगल राज्यसत्ता इस जनवादी मस्कृति को बाधय देनेवाली न थी।

हिन्दुस्तान के लोग सामन्ती टाँबा खत्म करके अपनी जातीय राज्यसत्ता कायम कर देने लेकिन तभी अंग्रेजों की दखलन्दाजी से उनकी ऐतिहासिक प्रगति में बाधा पड़ी।

उन्नीसवीं सदी में अंग्रेजों ने हिन्द प्रदेन का अपन अधिकार में किया। हिन्दुस्तान में ऐसी परिस्थितियाँ थीं जिनसे फायदा उठाकर उन्होंने भाषा और मस्कृति के भ्रामलों में दखल देना और यहाँ के लोगों में फूट डालना शुरू किया।

महाराष्ट्र, आंध्र, बंगाल, पंजाब आदि में वे परिस्थितियाँ न थीं जो हिन्दी-भाषी इलाके में थीं। महाराष्ट्र में गिवाओ एक जातीय रियासत कायम कर चुके थे। बंसी कोई कोशिस यहाँ न हुई थी। शिक्षा का कोई भिला-जुला जातीय जन निश्चिन न था, मुन्ना-मडिता के हाथ में अब भी शिक्षा की जिम्मेवारी थी। इस धार्मिक शिक्षा की वजह से दो लिपियों का प्रयोग होना था और भाषा की एकता के हिमाव से सब जगह एक ही लिपि का चलन न था। मुगल साम्राज्य के उखलने के बाद नवाबों के अहु वयादातर हमारे इलाके में रहे। बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र वगैरह इनमें अपभासित मुक्त रहे। हैदराबाद में उर्दू के अमर से तेलुगु भाषा में कुछ तबदीली हुई, लेकिन उस हद तक नहीं कि तेलुगु में हिन्दी उर्दू की तरह दो धाराएँ चल पड़े।

अंग्रेजों ने जिस अलगाव से फायदा उठाया और उसे गहरा बनाया, वह यहाँ की धार्मिक शिक्षा और सामन्ती पिछड़ेपन की वजह से था। बहुत से राज-दरबारों में ब्रज भाषा के आगे नयी जातीय भाषा हिन्दी की पूछ न थी; नवाबों के यहाँ खड़ी बोली के लोकप्रिय रूप और जनवादी कविता की कद्र न थी। इस तरह खड़ी बोली में दो धाराएँ चल निकली—एक तो लोकप्रिय धारा, दूसरी सामन्तों के आश्रयवाली धारा। कुछ कवियों ने साधारण भाषा के शब्दों के वहिष्कार की नीति अपनायी जिससे उनकी खड़ी बोली-धारा की भाषा से अलग मालूम होने लगी।

अंग्रेजों ने इस भेद को और गहरा किया। गिलक्राइस्ट ने हिन्दुओं और मुसलमानों की अलग भाषाओं के सिद्धान्त की रचना की। रिजले ने धर्म के आधार पर दो क़ाँमें गढ़ों और ग्रियर्सन ने भाषा और संस्कृति के क्षेत्र में फूट के उसूल को धार्मिक रूप दिया। सर सैयद ने लश्करों में नयी भाषा बनने की तजवीज़ पेश की। इक़्बाल ने मुस्लिम क़ाँम और मुस्लिम संस्कृति का नारा लगाया। ये सब साम्राज्यवादी विपक्ष के फल थे।

अंग्रेजों के राज में गाँवों की पुरानी व्यवस्था तो टूटी लेकिन उन्होंने सामन्तवाद और सामन्ती संस्कृति को मजबूत भी किया। इसी जर्जर सामन्ती संस्कृति पर उन्होंने अपनी तहजीब का ताज रखा। हिन्दीभाषी इलाके को उन्होंने कई सूबों में बाँटा, यहाँ ताल्लुकदारों और नवाबों को पाला-पोसा, और भाषा के मामले में जातीय उत्पीड़न का एक नया तरीका निकाला। कभी हिन्दुओं को दबाया, मुसलमानों को उभारा, कभी हिन्दुओं को उभारा और मुसलमानों को दबाया। कचहरी, अदालत और पुलिस में वह जवान चलाई कि किसान कभी समझ ही न सके और उसे ठगने और लूटने में उन्हें आसानी हो। इस तरह एक तरफ उर्दू की धारा वहीं, दूसरी तरफ हिन्दी की। फिर भी भाषा के बुनियादी शब्दों और मूल व्याकरण-व्यवस्था के बिना कोई भी धारा आगे न बढ़ सकती थी।

हिन्दी-उर्दू का भेद उन्नीसवीं सदी से पहले नागण्य है। उन्नीसवीं सदी में अंग्रेजी राज कायम होता है और तभी यह भेद गहरा होता है। इसलिए उस भेद के लिए सबसे ज़्यादा अंग्रेज ही जिम्मेदार हैं। अगर सूफियों और सन्तों की परम्परा जिम्मेदार होती तो इस तरह की दो धाराएँ बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह में भी बहती दिखाई देतीं। वहाँ नहीं दिखाई देतीं, यह इस बात का प्रमाण है कि हिन्दी-उर्दू का भेद अस्थायी है, जो जनता के स्वाधीनता आन्दोलन की बढ़ती के साथ कम होते-होते मिट जायगा। आखिर अभी सौ साल भी तो इस खाई को नहीं हुए।

हिन्दीभाषी इलाके में सामन्ती अवशेष कायम रखकर, हिन्दी-उर्दू के सवाल से साम्प्रदायिकता उभारकर, एक ही भाषा की दो धाराएँ बहाकर और दोनों पर अंग्रेजी लादकर, आम जनता को अशिक्षित रखकर अंग्रेजों ने हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को भारी नुक़सान पहुँचाया है।

फिर भी हर जगह उनकी मनचीती नहीं हुई। हिन्दुस्तानी जनता ने आसानी से

उनका जुआ स्वीकार नहीं किया। १८५७ में दिल्ली, मेरठ, कानपुर, भोली आदि शहरों के अवध, भोजपुरी, बुन्देलखण्ड आदि जनपदों के वीरों ने अंग्रेजों के दान सट्टे कर दिए। अगर अंग्रेजों को हिन्दुस्तानियों से ही मदद न मिलती तो देश का इतिहास ही दूसरा होता। हमारे साहित्यकारों ने जनवादी संस्कृति की परम्परा को निवाहा। हिन्दी-उर्दू के लेखकों का महायुग अंग्रेज स्वतन्त्र नहीं कर पाए। भारतेन्दु, प्रतापनारायण मिश्र, बालमुकुन्द गुप्त, जो आधुनिक हिन्दी के निर्माता हैं, उर्दू के भी लेखक थे। प्रेमचन्द ने उस परम्परा को जोर आगे बढ़ाया।

कांग्रेस और लीग के नेताओं ने प्रांतिकारी जन-आन्दोलन का ता विरोध किया, लेकिन साम्राज्यवादियों की स्वाधीनता-योजना स्वीकार की। भारतीय जनता में भय बाकर अंग्रेजों ने अपना भडा और अपनी फीज तो हटा ली लेकिन अपने पूँजीवादी पंजे दश में और भी गंदा दिए।

अंग्रेजों पूँजी का हिन इस बात में है कि बँटवारे के बाद कायम की हुई दोना गियासतों आपस में लड़ें या उनमें तनावनी रहे जिससे कि लोगों का ध्यान छिपे हुए चुटोरों की तरफ न जाय। इसके लिए उन्होंने दंगे कराए, कश्मीर की लड़ाई कराई और साम्प्रदायिक दला के ज़रिए तनावनी कायम रखी।

साम्प्रदायिकता में फायदा उठाकर पाकिस्तान के शासकों ने वहाँ की भाषाओं का दबाया और उन पर उर्दू लादी। हिन्दुस्तान के साम्प्रदायिकों ने कहा कि अब तो उर्दू पाकिस्तान गई और उसकी यहाँ बात करना भी राष्ट्रद्रोह है। राजपि टंडन और महापंडित राहुल ने इस विषय में प्रचार का नेतृत्व किया। उत्तर भारत के सूबा में हिन्दी ठीक ही राजभाषा घोषित की गई लेकिन उर्दू के व्यवहार और शिक्षा आदि में तरह-तरह के अड़ने लगाये गए।

हिन्दी के कुछ लेखक इस परिस्थिति को मन्तोपजनक समझते हैं। लेकिन उर्दू का दबाने में हमारी जातीय भाषा के विकास में बाधा पड़ती है इसलिए इस परिस्थिति को सन्तोपजनक कैसे कहा जा सकता है? उर्दू में लोकप्रिय साहित्य का बहुत बड़ा हिस्सा मौजूद है। उसमें बौद्धधर्म के मुहावरों का निखरा हुआ रूप ही नहीं है, हमारी भाषा और साहित्य का इतिहास उसके बिना अधूरा रहेगा। इसलिए अपनी जाति के साम्प्रदायिक इतिहास के लिए अपनी जातीय भाषा के विकास के लिए मैं उर्दू के दबाने का विरोध करता हूँ।

कांग्रेसी नीति के विनाश उर्दू के कुछ लेखकों ने विधान की सहायता लेते हुए बनाई जवान का मवाल उठाया है। हिन्दी से अलग उर्दू का कोई अलग इलाका नहीं है हालाँकि उर्दू या हिन्दी की अपनी एकमात्र साहित्यिक भाषा समझनेवाले लोग हैं। इसलिए उर्दू के पढ़ने-पढ़ाने और उसे व्यवहार में लाने में जो भी बाधाएँ आती हैं, उन्हें दूर करने के लिए आवाज बुलन्द करना सभी जनवादियों का कर्तव्य है। उसे अलग इलाकाई ख़ान मानना गलत है।

हिन्दीभाषी इलाके की जनता के लिए किसानों में शिक्षा का सवाल भाषा की

समस्या के साथ जुड़ा है। किसानों को आम शिक्षा किस लिपि में दी जाय ? अगर किसानों को एकजुट करना है, उनकी राजनीतिक चेतना को विकसित करना है, उनके आन्दोलन को राष्ट्रीय आन्दोलन की धुरी बना देना है तो आम शिक्षा के लिए दो लिपियाँ रखना हानिकारक होगा। इसलिए मेरी राय है कि देवनागरी लिपि के जरिये आम जनता में शिक्षा के प्रचार पर जोर देना चाहिए।

अंग्रेजों ने १८५७ से सबक लेकर हमारे इलाके को सबसे ज्यादा टुकड़ों में बाँटा है। सदियों से एक साथ रहनेवाले आगरा और दिल्ली भी अलग हो गए। हिन्दीभाषी इलाका एक होना चाहिए। इसके बारे में यह बहाना भी नहीं चल सकता कि बड़े सूबे को छोटे सूबों में हम बाँटना चाहते हैं। यहाँ सवाल छोटे टुकड़ों को मिलाकर बड़ा सूबा बनाने का है। अलग-अलग प्रान्तीय सभाएँ और हुकूमतें चलाने का खर्च बचेगा, व्यापार और उद्योग-धन्वों की तरक्की में मदद मिलेगी। हमारा सांस्कृतिक आन्दोलन पूरे प्रदेश में जातीय पैमाने पर चलेगा और भाषा भी अपना जातीय रूप निखार सकेगी।

किसान-आन्दोलन की बढ़ती के लिए यह आवश्यक है कि बोलियों में साहित्य रचा जाय। अभी भी वह रचा जा रहा है। लेकिन हर जनपद के लिए, अलग सूबा या प्रजातन्त्र बनाने की माँग करना जातीय प्रदेश के बँटवारे को दूसरे रूप से कायम रखना है। इससे सावधान रहना चाहिए।

हिन्दीभाषी लेखकों का हित इस बात में है कि वे भाषावार प्रान्त-निर्माण के आन्दोलन का समर्थन करें, दूसरों की मर्जी के खिलाफ उन पर हिन्दी भाषा लादने का विरोध करें। इससे दूसरी भाषाओं के लोग उनकी जातीय एकता के आन्दोलन का समर्थन करेंगे। उन्हें इस भ्रम में कि संस्कृत-गर्भित होने से हिन्दी दक्षिण में ज्यादा समझी जाएगी, अपनी भाषा को बिगड़ने न देना चाहिए। संस्कृत-गर्भित हिन्दी के पक्षपाती साहित्य-सम्मेलन ने दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार का काफ़ी अहित किया है। वहाँ पर हिन्दी का प्रचार किया है, 'दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा' ने जिसकी नीति सम्मेलन से भिन्न है।

हिन्दीभाषी इलाका भारत का सबसे बड़ा इलाका है। संख्या के विचार से हिन्दु-स्तानी जाति दुनिया की तीन-चार सबसे बड़ी जातियों में गिनी जाएगी। ऋग्वेद और महाभारत की रचना इसी प्रदेश में हुई है। यही की नदियों के किनारे वाल्मीकि और तुलसी ने अपने अनूष्टुप और चौपाड्यों गाई हैं। तानसेन और फय़ाज़ खाँ, हाली, मीर, अकबर, ग़ालिब, भारतेन्दु, प्रेमचन्द, निराला यहीं के रत्न हैं। ताजमहल और विश्वनाथ के मन्दिर यहीं के हाथों ने गढ़े हैं। आल्हा और कजली ने सैकड़ों साल तक यहीं का आकाश गुंजाया है। अठारह सौ सत्तावन में यहीं की धरती हिन्दुओं और मुसलमानों के खून से सींची गई है। जिस दिन यह विशाल हिन्द प्रदेश एक होकर नये स्वाधीन जन-जीवन का निर्माण करेगा, उस दिन इसकी संस्कृति एशिया का मुख उज्ज्वल करेगी।



जिनाता और मजदूरों की एकता या जनता की एकता की धुरी है, वह दिन निकट लाएगी। हिन्दी और उर्दू के लोगों का इस जनता के हितों का ध्यान में रखाकर अपनी जातीय परम्परा के अनुसार लोकप्रिय भाषा और जनवादी साहित्य के विकास में आगे बढ़ना चाहिए।

(१९५३)

## हिन्दी-उर्दू समस्या

अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति का तनाव दूर करने के लिए शान्ति-प्रेमी जनता जोर-जबर्दस्ती के बदले समझौते की बातचीत का रास्ता पसन्द करती है। भारतीय शान्ति-आन्दोलन के नेताओं ने भी तीमरे महायुद्ध की तैयारियाँ रोकने के लिए समझौते की बातचीत चलाने पर जोर दिया है।

मेरा विचार है, हिन्दी-उर्दू समस्या को लेकर जो तनाव पैदा किया गया है, उसे दूर करने के लिए भी समझौते की बातचीत चलाना और छुरेबाजी को प्रोत्साहन न देना श्रेयस्कर हो सकता है।

पिछले दिनों उर्दू-प्रेमियों की तरफ से उर्दू को क्षेत्रीय भाषा के रूप में मानने और उसके लिए क्षेत्रीय भाषा के अधिकार माँगने के बारे में आन्दोलन हुआ था। उस आन्दोलन के जवाब में कुछ हिन्दी-प्रेमियों की तरफ से भी आन्दोलन हुआ और लखनऊ में उर्दू-प्रेमियों के सम्मेलन के अवसर पर एक उर्दू-प्रेमी को एक हिन्दी-प्रेमी ने छुरा मारकर उसे अस्पताल भेज दिया।

आप मानेंगे कि टेक और ऐटम बम का खतरा न होने पर भी लखनऊ जैसे शान्ति-प्रेमी नगर में यह कांड होना जाहिर करता है कि जैसे अन्तर्राष्ट्रीय तनाव दूर करने के लिए बमबाजी का रास्ता बुरा बताया जाता है, वैसे ही भाषा की समस्या हल करने के लिए छुरेबाजी का रास्ता भी बुरा समझा जाना चाहिए।

उकसावा पैदा करनेवाले आन्दोलन अक्सर अर्द्ध-सत्यो को लेकर चलते हैं। इसमें शक नहीं कि बहुत से उर्दू-प्रेमियों में सम्प्रदायवादी भी है, और पहले भी रहे हैं। लेकिन इस बात को लेकर अर्द्ध-सत्य प्रेमी सज्जन यह नतीजा निकालते हैं कि सभी उर्दूवाले सम्प्रदायवादी हैं, उर्दू का जन्म ही सम्प्रदायवाद से हुआ है, पाकिस्तान का जन्म भी उर्दू के कारण हुआ है (भले ही पूर्वी पाकिस्तान के लोग उर्दू को राजभाषा बनाने के खिलाफ लड़े हों) और इसलिए जितना ही जल्दी उर्दू को मिटाया जाय, उतना ही अच्छा !

इसमें भी शक नहीं है कि हिन्दी-प्रेमियों में बहुत से सम्प्रदायवादी हैं और पहले भी रहे हैं। लेकिन इस बात से उर्दू-खेमे के अर्द्ध-सत्यप्रेमी यह नतीजा निकालते हैं कि सभी हिन्दी-प्रेमी सम्प्रदायवादी हैं, हिन्दी का जन्म ही सम्प्रदायवाद से उर्दू के मोठे सरल शब्दों को निकालकर उनकी जगह संस्कृत के कंकड़-पत्थर भरकर हुआ है। हिन्दी को

बिहार या उत्तर प्रदेश की राजभाषा बना दिया गया है, यह हिन्दी-प्रेमियों की साम्प्रदायिकता का सबसे बड़ा प्रमाण है ।

इसी तरह हिन्दी सेम के अनेक समर्थक उर्दू विरोध को राष्ट्रीयता की पहली शर्त मानते हैं । यह उर्दू विरोध उल्टे ही मुस्लिम विरोध का रूप ले लेता है और उन्नावी पैदा करनेवाली दलीलें दी जाती हैं कि उन्हें मुनवर मालूम होने लगता है कि जनता की भुनमरी, अगिधा अकाल और महामारी का एकमात्र कारण उर्दू है ।

उधर उर्दू सेम के अनेक समर्थक उर्दू को हिन्दी से और दूर पीछे कर, हिन्दुस्तानी जनता के सांस्कृतिक इतिहास से और दूर ले जाकर, दुश्मनाप से उर्दू का सम्बन्ध अपनी मसल में और पक्का करने, जसगाव की भावना का और मजबूत करने हैं । समूची हिन्दुस्तानी जनता के साथ होकर अपनी मिस्री-जुनी सङ्कति, अपना मिला-जुला लिखित साहित्य त्याग बढाएंगी, अवधी, उर्दू, बुन्देलखण्डी, भोजपुरी आदि से हम अपनी भाषा के लिए क्या लेंगे, कैसे उसे मोलह कराइ के लिए मुलभ बनाएंगे, ये समस्याएँ उनके लिए हैं ही नहीं । उल्टा ये किसी महा अस्तीत पत्रिका की बिक्री का हवाला देकर पूछेंगे, 'कहिए, आपके यहाँ कोई पत्रिका इतनी बिकती है ? या अपन बहपन की डोग हकिंगे, 'हमने जितना कमाल हासिल किया है उतना किसी ने किया ही नहीं है ।'

उर्दू-सेम के ये जट्ट-समर्थक आशा और निराशा के बीच मकोले खाने हैं । कभी तो वे उर्दू के अजर-मजर होने की बात साचकर गद्गद हो उठते हैं और कभी उसका विनाश निश्चिन समझकर बेसे हो उदास और परेशान हो जाते हैं ।

किसी दिन या मूक को ध्यान में रखकर हिन्दी-उर्दू की समस्या स्थायी रूप से हल नहीं हो सकती । यह समस्या तभी हल होगी जब हम हिन्दी प्रेमी और उर्दू प्रेमी दोनों—समूची हिन्दुस्तानी जाति के राजनीतिक और सांस्कृतिक पुनर्गठन की समस्या के सन्दर्भ में उन पर विचार करेंगे । मवाल यह है कि जैसे तेलुगु, मराठी, तमिल या कन्नड भाषाएँ घातकताले अपने-अपने प्रदेश में अपना राजनीतिक और सांस्कृतिक पुनर्गठन करने के लिए उठ खड़े हुए हैं या उठ खड़े हो रहे हैं, वैसे ही क्या हिन्दुस्तानी लोग भी मुघल और ब्रिटिश राज के अपने अत्याचारी छत्र-चरके एक जातीय प्रदेश में अपने राजनीतिक और सांस्कृतिक पुनर्गठन के लिए उठेंगे ? या वे अपनी सामान्य समस्याएँ अलग-अलग अपने जिलों और मन्तों में ही उलझाते-मुनमाने रहेंगे ?

कभी पिछले दिना भाषावार प्रान्त बनाने के सिलसिले में जो सम्मेलन हुआ, उसमें और भाषाओं के प्रतिनिधियों ने तो अपने जातीय इलाकों के पुनर्गठन की बात उठाई लेकिन हिन्दुस्तानी प्रदेश का मवाल वहाँ उठा ही नहीं । इसका सबब यह है कि हिन्दुस्तानी जनता का प्रदेश और जातियों के प्रदेश से कहीं बड़ा बड़ा है । उनसे बड़ा बड़ा हुआ है, यहाँ की जातीय चेतना को कभी हिन्दी-उर्दू विवाद से, कभी भोजपुरी या मैथिली प्रान्त के आन्दोलन से, कभी बिहारी-बंगाली फसाद से सही रूप में बिकसित होने नहीं दिया गया ।

हिन्दी-उर्दू समस्या को लेकर जो लोग साम्प्रदायिक प्रचार करते हैं, वे हिन्दुस्तानी जनता की जातीय चेतना पर सबसे पहले प्रहार करते हैं।

हिन्दी-उर्दू के अर्द्ध-सत्यप्रेमी हिन्दुस्तानी जाति के प्रदेश का सवाल, उसके राजनीतिक और सांस्कृतिक पुनर्गठन का सवाल नहीं उठाते, यह बात आकस्मिक नहीं है। वे सारे हिन्दुस्तान में हिन्दी फैलाने के लिए कटिबद्ध हैं, लेकिन जब दक्षिण के लोग उनसे पूछते हैं—हिन्दी किस प्रदेश की भाषा है, तो वे बगलें भाँकने लगते हैं।

यह बात आकस्मिक नहीं है कि हिन्दी-खेमे के कुछ अर्द्ध-सत्यप्रेमी हिन्दुस्तानी जाति के इलाके को 'बोलियों' के आधार पर ग्यारह हिस्सों में बाँट देने का प्रचार करते हैं। 'भाषा' के आधार पर वे प्रान्त-निर्माण की बात नहीं करते वरन् 'बोली' के आधार पर एक जातीय प्रदेश के बहुत से टुकड़े करने की बात करते हैं।

समूचे हिन्दुस्तानी प्रदेश को ध्यान में रखते हुए हिन्दी-उर्दू समस्या पर विचार किया जाय, तो ये परिणाम निकलते हैं—

१. जहाँ तक साधारण जनता की बोलचाल का सम्बन्ध है, हिन्दू-उर्दू का कोई भेद नहीं है।

२. हिन्दी-उर्दू का भेद लिखित भाषा के सिलसिले में उठता है।

३. उर्दू को लिखित भाषा के रूप में काम में लानेवाले लोग आम तौर से सम्प्रदायवादी नहीं हैं। वास्तव में कुछ हिन्दू सम्प्रदायवादी भी लिखित भाषा के रूप में उर्दू का प्रयोग करते हैं। उर्दू का प्रयोग करनेवाले सब मुसलमान ही नहीं, शैर-मुसलमान भी हैं।

४. लिखित भाषा के लिए जो लोग हिन्दी का प्रयोग करते हैं, उनकी संख्या उर्दू का प्रयोग करनेवालों से ज्यादा है। इससे नतीजा यह निकलता है कि हिन्दुस्तानी प्रदेश में एक 'सांस्कृतिक अल्पमत' लिखित उर्दू का प्रयोग करता है।

५. व्यवहार में इस सांस्कृतिक अल्पमत की जरूरतों का ध्यान रखा जाता रहा है, जैसे फिल्मों में हिन्दी लिपि के साथ उर्दू का प्रयोग, अनेक शैर-साम्प्रदायिक संगठनों का उर्दू पत्र निकालना (जिनमें कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल है)।

हिन्दी-खेमे के अर्द्ध-सत्यप्रेमी यह मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि उर्दू एक सांस्कृतिक अल्पमत के काम में आनेवाली लिखित भाषा है। वे इस सत्य को दोहराकर कि जनता की भाषा यानी 'बोलचाल की भाषा' एक है, इस बात से इन्कार करते हैं कि लिखित भाषा में आज भेद है और उर्दू एक सांस्कृतिक अल्पमत की जरूरतें पूरी करती है।

इसलिए वे हिन्दी को राजभाषा बनाकर उर्दू के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहते हैं जिससे लिखित भाषा के एकीकरण का सवाल एक-दूसरे से सीखकर, कुछ आपस में आदान-प्रदान करके हल न हो, बल्कि एक लिखित रूप को दबाकर हो।

उर्दू-खेमे के अर्द्ध-सत्यप्रेमी यह मानने से इन्कार करते हैं कि समूचे हिन्दुस्तानी

प्रदेश में उर्दू का व्यवहार एक निश्चित भाषा के रूप में एक सांस्कृतिक अन्तर्गत करता है। वे यह मानने से इन्कार करते हैं कि मयाल सांस्कृतिक अन्तर्गत की निश्चित भाषा की रखा करने, उसके उपयोग की सुविधाएं देने का है। वे कभी राजकाज के लिए शीतो लिपियों के चलन की बात बहते हैं, कभी उसे शीतो भाषा मानकर उसके लिए लिपि, भाषा और लक्षण का 'क्षेत्र' बूझने लगते हैं।

उर्दू-खेमे के दोस्त हकीकत परधानन में गलती करने हैं, जिससे हिन्दी-खेमे के सम्प्रदायवादी ही मचकून होते हैं, उर्दू की रखा और उसके व्यवहार की सुविधा देने का असली प्रश्न टल जाता है।

निश्चित भाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग हमारे प्रदेश के बहुसंख्यक लोग करते हैं। इसलिए उनकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है कि एक ही निश्चित भाषा के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ तैयार करने में मदद दें। इन काम में एक बाधा यह प्रचार है कि निश्चित भाषा के रूप में उर्दू को दवान से हमारी भाषा-समस्या सुलभ जाणगी। जो लोग इस तरह का प्रचार करते हैं, वे बड़-सूय का महारा लेकर निश्चित उर्दू के सामन्ती साहित्य, उसकी दीगती परम्पराओं का हवाला तो दते हैं लेकिन निश्चित उर्दू के जनवादी और लोकप्रिय साहित्य के बारे में खामोश रहते हैं या सरासर झूठा प्रचार करते हैं।

सन् ४७ के बाद हिन्दी-खेम के सम्प्रदायवादियों ने नए सिरे से और मारा है। राजनीतिक जीवन से उगड़ होने पर कुछ सज्जन भाषा को लेकर सम्प्रदायवाद का प्रचार करने लगे। कुछ मित्रों को यह भ्रम है कि ऐसे लोग कबल भाषा के मामले में सम्प्रदायवादी हैं, बाकी मामलों में आत्मप्रदायिक और जनवादी हैं।

इस तरह की धारणा बनाते हुए बहुत सनक रहता खट्टरी है।

सन् '८७ में—भारत-विभाजन के बाद—राहुलजी ने हिन्दी-उर्दू समस्या के सिलसिले में ही कहा था—

“इस्लाम को भारतीय बनना चाहिए—उनका भारतीयता के प्रति यह विद्वेष सदियों से चला आया है मही किन्तु महीन भारत में कोई भी धर्म भारतीयता को पूर्णतया स्वीकार किये बिना फल-फूल नहीं मकना।”

बात थी उर्दू की, महीका निक्ता कि “उनका भारतीयता के प्रति यह विद्वेष सदियों से चला आया है,” मानी मुसलमान मूलतः राष्ट्र-विरोधी हैं।

और ‘आज की राजनीति’ (१९५०) में राहुलजी ने हिन्दी-उर्दू समस्या के सिलसिले में ही लिखा था—

“इस्लाम ने जो भी कहा हो, किन्तु मुसलमानों ने अपने को देश की धारा का अंग मानने से मदा इन्कार किया।”

बात थी उर्दू की, महीका निक्ता कि मुसलमानों ने अपने को इस देश की धारा का अंग ही न समझा।

और भी, उसी पुस्तक में राहुलजी कहते हैं—

“इस्लाम का भारतीयकरण करना ही हितकर होगा। मौलाना आज़ाद की यह मनोवृत्ति यदि भारतीय मुसलमानों में रही, तो उनकी भक्ति तथा सहानुभूति हमेशा भारत की अपेक्षा पाकिस्तान के साथ रहेगी। यह भावना भारतीय मुसलमानों को छिपा पंचमांगी बनाकर छोड़ेगी।”

यदि मुसलमान पंचमांगी बन रहे हैं, तो उनके साथ व्यवहार भी वही होगा जो देशद्रोहियों के साथ होता है ! हिन्दू-मुस्लिम दंगे कराने के लिए इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है ? आप कहेंगे, यह तो भापा-सम्बन्धी मनोवृत्ति को लेकर लिखा गया है।

मान लिया, भापा-सम्बन्धी मनोवृत्ति को लेकर लिखा गया है, लेकिन इस किताब में युधिष्ठिर नाम का पात्र—जो राहुल उवाच की जगह सूत्रधार का काम करता है—कहता है, “आप कुरान को उठाकर किसी धर्म के प्रमुख ग्रन्थ से मिलाकर देख लीजिए, वह हर तरह से निम्नकोटि का जैवेगा।”

अब आप पता लगाइए, कि दुनिया के तमाम मुसलमानों के धर्मग्रन्थ से हिन्दी-उर्दू समस्या का क्या सम्बन्ध है !

देखिए, राहुलजी का केवल भापा के सवाल पर सम्प्रदायवादी होना अकल ठीक करने के कैसे सुन्दर नतीजे तक पहुँचता है !

हमारे अनेक शुभ विचार रखनेवाले भाइयों ने राहुलजी का विरोध करना तो दूर, उनकी पीठ थपथपाई कि आप वास्तव में प्रगतिशील विचारक हैं ! उनका खयाल था कि राहुलजी का पर्दाफाश करने से ‘संयुक्त मोर्चा’ टूट जाएगा (राहुलजी की नीति से उन्हें संयुक्त मोर्चे के लिए कोई भय न था !), इसलिए कभी तो वे उनके ‘भापा-सम्बन्धी’ प्रचार को ‘आदर्श’ कहते रहे, कभी चुप रहे और कभी घेरे जाने पर बोले कि राहुलजी को सम्प्रदायवादी कहने से क्या होता है, सभी हिन्दी लेखक वैसा ही सोचते हैं ! ! !

इस अवसरवादी नीति को, साम्प्रदायिकता को, तरह देने का नतीजा यह हुआ कि राहुलजी के चरणचिह्नों पर चलनेवाले और ‘प्रगतिशील’ लेखक भी आगे आ रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में उर्दू को क्षेत्रीय भाषा बनाने के आन्दोलन के सिलसिले में ‘उत्तर प्रदेश भाषा समिति, लखनऊ’ ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के नाम एक आवेदन-पत्र छपवाया था। इसमें कहा गया था—

“हम इस प्रदेश की भाषा के वोटवारे और भाषा को वोटकर जनता में फूट डालने की विपरीत साम्प्रदायिक नीति का घोर विरोध करते हैं। यह प्रवृत्ति जन-विरोधी, राष्ट्रीयता-विरोधी और देशद्रोही है।”

जब कोई प्रवृत्ति ‘देशद्रोही’ करार दी जाएगी, तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा ? आवेदन-पत्र ने ऐसा वातावरण तैयार करने की कोशिश न की जिसमें

हिन्दी उर्दू लेखक बैठकर समस्या पर विचार करते और उसे सुलझाने की कोशिश करते। उर्दू-प्रेमियों के क्षेत्रीय भाषा के लिए जैसे हिन्दी लेखकों में सनातन मतविरा विषे बिना जांचोचन छेड़ दिया या और उर्दू की रक्षा की मझी मौन का क्षेत्रीय भाषा की सुलझ मोर में सुलझा दिया या, बसे ही और उसमें पंचम चरम आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश भाषा समिति ने इन उर्दू-प्रेमियों की कोशिश का दमदाह करार दे दिया।

इसमें खुल सम्प्रदायवादियों ने फायदा उठाया और दुर्गुशाही के लिए वातावरण पैदा कर लिया।

अब यह स्पष्ट हो गया होगा कि जनराष्ट्रीय भाषा की तरह भाषा-सम्बन्धी भाषाभाषा भी उच्चाव की नीति के बदल मुनह-समझने की बानधीन चलाना बुरी जरूरी है।

आवेदन-पत्र पर भाषा समिति के मंत्री की हेमियन में गुप्तसिद्ध प्रगतिशील कर्ताकार बंगाल के दम्नान है।

बंगालजी यह अहमत्व मानकर कि हिन्दुस्तानी जनता की एक भाषा है, उसने दा लिखित रूपों का आत्र की आवश्यकता का निरूपण एक लिखित रूप रखकर सुरक्षित रख कर देना चाहते हैं। उनके विचार से हिन्दी-उर्दू के आश्रान प्रदान का सवाल नहीं है। मध्यभा-बुझाकर एक लिपि बनाने का सवाल नहीं है। सवाल है दो में से एक ही रूप रखकर समस्या को हल करने का। हिन्दा उर्दू की समस्या को जोर-झड़वस्ती में हल करने का समर्थन करते हुए बंगालजी कहते हैं—

‘दमन और जत्र बड़ अभियान है। हम इन शब्दों की मदद ही अपने निरोधियों के गन मड़ते हैं। तस्तिन किमो भी नियम या अनुशासन को दमन और जत्र कह दिया जा सकता है। अनिवार्य शिक्षा भी एक प्रकार का दमन और जत्र है और पैदावार के साधना का राष्ट्रीयकरण तो बहुत बड़ा दमन और जत्र बताया जाएगा।’

(नया पय — मित्रम्बर, १९२३)

कहाँ राष्ट्रीयकरण वहाँ हिन्दी-उर्दू समस्या। गहन तो भाग्य में पैदावार के साधना का राष्ट्रीयकरण का सवाल ही नहीं उठता और जहाँ उठता है या उठा है, वहाँ कामचोर वर्गों की मिलिबदन सम करने का उठा है। क्या जो सांग लिखित भाषा के लिए उर्दू काम में मान है, कामचार वर्गों के लोग हैं? यशपालजी की उपमा ही आहिर करती है कि उठाने कामचार वर्गों की वास्तविक समस्या भुलाकर (जो य वर्ग लिखित भाषा के लिए हिन्दी उर्दू दाना का प्रयोग करते हैं) समझ उर्दू प्रेमियों को—या लिखित भाषा के लिए उर्दू-प्रयोग की सुविधा चाहनेवाला का—कामचार-वर्ग बना दिया है और उन्हें अधिभारहीन करने का फैसला कर लिया है।

अनिवार्य शिक्षा का चयन करने पर दमन और जत्र जनता पर नहीं होता बल्कि उन कामचोर वर्गों पर होता है जो जनता को निरक्षर रखते हैं। राष्ट्रीयकरण में जो व्यवहार कामचार वर्गों के साथ होता है, उसकी तुलना जनता को अनिवार्य शिक्षा देने

से करके यशपालजी ने जनता और गोपक वर्गों का भेद भुला दिया है।

जब तक हमारे कुछ लेखक यह प्रचार करते रहेगे कि जोर-जवर्दस्ती से हल करने पर लिखित भाषा की एकता कायम हो जाएगी, तब तक वह एकता उतनी ही दूर चली जाएगी, जनता में फूट डालनेवाले भाषा के सवाल को प्रेम से इस्तेमाल करेंगे और इस सबसे हिन्दुस्तानी जनता के राजनीतिक और सांस्कृतिक पुनर्गठन का सवाल—हिन्दी प्रदेश के एकीकरण का सवाल—खटाई में पड़ा रहेगा।

यह समझना भूल होगी कि सभी हिन्दी-लेखक राहुलजी या यशपालजी की तरह सोचते हैं।

अगस्त, १९५३ की 'अवन्तिका' ने मम्पादकीय नोट में इस बारे में लिखा है।

'अवन्तिका' उर्दू को किसी क्षेत्र की अलग भाषा नहीं मानती। लेकिन वह उसे स्वदेशी भाषा मानती है, राहुलजी की तरह अरब जेहादियों का कीर्ति-स्तम्भ नहीं। वह उसके विकास में बाधा देने का विरोध करती है, जोर-जवर्दस्ती से राष्ट्रीयकरण या इस्लाम के भारतीयकरण का सवाल नहीं उठाती।

इससे यह परिणाम निकलता है कि उकसावा पैदा करनेवाला वातावरण खत्म करके अगर हिन्दी-उर्दू के जनवादी लेखक इस समस्या को सुलझाने बैठें तो ऐसा हल निकल सकता है, जिसमें किसी के साथ जबर भी न हो और क्रमशः हमारे हिन्दुस्तानी प्रदेश में एक लिखित भाषा के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ भी तैयार हो जाएँ।

(१९५३)



## भाषा और प्रान्तीयता

इस बार गर्मियों में जब कलकत्ता गया तो लगा, शहर कुछ बदला-सा है। बंगला-भाषी मित्र बंगला छोड़कर आम तौर से दूसरी भाषा में बात न करते थे। कुछ लोगों ने यह दिखावन भी की कि इस या ट्रान में किसी बंगाली कइक्टर से हिन्दी में टिकट माँगी तो वह टिकट न देगा या उपरा दिखनाएगा, दफ्तर में हिन्दी वालकर काम करने जाओ ता वीस बिमुवे काम हागा नहीं। एकाध साहित्य प्रेमी ने कहा, "आप ओ कुछ हिन्दी भाषण में कहते हैं, उसे अप्रेओ में नी कह, हय उनमें बंगला साहित्यकारो और प्राफेसरो का भी बुनाएगे, उन्ह नी मानूम होना चाहिए कि हिन्दी में क्या है।"

एक बंगलाभाषी हिन्दी-प्रचारक मित्र ने कहा, "आपने यहाँ से कुछ सोना आकर हमारा काम चौपट कर जान हैं। यहाँ आकर कहते हैं, 'बंगला में है क्या ? रवीन्द्रनाथ ने जो कुछ लिखा है कबीर में।' अरे बाबा, आप लोग हिन्दी हिन्दी क्या चिन्ताने हा ? है क्या आपकी हिन्दी में ? और हिन्दी-प्रचार तो हम राधा राममोहन राय के समय से कर रह हैं जब आपके यहाँ लोग हिन्दी-प्रचार का नाम भी न जानते थे।"

एक चौहतर वष के क्रान्तिकारी, विचारक और लेखक ने पूछा, "हिन्दुस्तान के त्रिविष्य के बारे में क्या सोचने हो ?" मैंने कहा, "इस प्रश्न का उत्तर तो मुझमें अच्छा आप दे सकते हैं। मेरी समझ में हमारा त्रिविष्य उज्ज्वल है।" उन्होंने कहा, "गृह-युद्ध होनेवाला है।" पूछा, "किसमें ?" मेरे मन में आया, शायद मजदूर प्रजापतियों की लड़ाई की बात सोचते होंगे। लेकिन वह बोले, "हिन्दुस्तानिया और बंगालिया में युद्ध होगा।" सुना था, कुछ दिन पहले बंगाली और हिन्दुस्तानी ट्राम-जखदूरा में भगडा हो चुका था। खखबारों ने अममियों और बंगालियों के दंग की बात भी पढ़ चुका था। इसलिए गृह-युद्धवारी बात में हँसकर टाट न सका।

कलकत्ता की लगभग भाषी जनता हिन्दुस्तानी है। यहाँ के भारवाडी व्यापारी आपन में राजस्थानी बोलते हैं लेकिन गिरा, भाषण, प्रकाशन आदि के लिए हिन्दी ही काम में लाते हैं। एक ओर तो ये बड़े-बड़े व्यापारी हैं, दूसरी ओर अवधी, भोजपुरी, मैथिली जादि बोलनेवाले पूर्वी हिन्दी भाषी प्रदेश के लोग हैं जो ज्यादातर सेहतन-मजदूरी के सहारे चिन्दगी बसर करते हैं। नाम की अपने डेरा पर दोल-मंजीरा या खनटी या हड्डक

लेकर ये अपने लोकगीत गाते हैं। बंगला और हिन्दीभाषी भद्रजन समान रूप से इन्हें असम्पन्न और असंस्कृत समझकर इनसे प्रायः घृणा करते हैं। इनके अलावा बहुत-से अध्यापक और लेखक हैं, जिनमें से अधिकांश का उद्देश्य कलकत्ता आकर पैसा कमाना है, साहित्य-सेवा करना नहीं।

ऐसी स्थिति में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, यह भाव लोगों के मन में बड़ी जल्दी पैदा होता है। इसका नतीजा यह होता है कि देश की विभिन्न जातियाँ आपस में मित्रता बरतने के बदले एक-दूसरे से वैर मानने लगती है, एक-दूसरे से सीखने के बदले अपने बड़-प्पन की डींग हाँकने में सारा समय लगा देती है। जहाँ तक साहित्य का सम्बन्ध है, यहाँ की जातियाँ एक-दूसरे से सहयोग करके ही उसे सँवारती रही हैं और आगे भी उसे सँवार सकती हैं। मूर और तुलसी के युग में यहाँ के सांस्कृतिक आन्दोलन बराबर एक प्रदेश के बाहर के लोगों को भी प्रभावित करते रहे हैं। यदि ये व्यापक आन्दोलन न होते तो न मूर के पद रचे जाते, न चण्डीदास के। इसी तरह आधुनिक काल में देशभक्ति की जो लहर सारे देश में फैल गई, उसमें अनेक जातियों के लेखकों का हाथ था। इसलिए किसी भी भाषा के साहित्य पर गर्व करते हुए उसके प्रेमियों को यह भूल जाना चाहिए कि उसका विकास दूसरों के सहयोग से ही सम्भव हुआ है और उससे मिलती-जुलती विशेषताएँ दूसरों के साहित्य में भी हैं।

जहाँ तक भाषा का सम्बन्ध है, वास्तविक स्थिति यह है कि बंगाल आदि राज्यों में बंगला-जैसी समृद्ध भाषाएँ भी वहाँ के राजकाज की भाषाएँ नहीं बनीं। अंग्रेजी का बोलवाला अब भी है और तनाव अंग्रेजी और देशी भाषाओं के बीच नहीं, हिन्दी और यहीं की दूसरी भाषाओं के बीच है। हिन्दी-प्रेमियों का हित इस बात में है कि बंगला आदि भाषाएँ राजकाज के लिए अपने देश में पूरी तरह काम में लाई जाएँ। जब तक अहिन्दी-भाषी प्रदेशों में वहाँ की भाषाएँ अपने पूर्ण अधिकार नहीं पातीं, तब तक उनके बीच हिन्दी भी पूरी तरह परस्पर व्यवहार का माध्यम नहीं बन सकती। इसके विपरीत उन्हें डर रहेगा कि हिन्दी हमारी जगह छीनना चाहती है।

इधर शिक्षा के माध्यम को लेकर जो विवाद चल पड़े हैं, उनसे परिस्थिति और विगड़ गई है। कई जगह यह प्रचार किया गया है कि किसी भाषा-विशेष के बदले हिन्दी ही शिक्षा का माध्यम बनेगी। तर्क यह होता है, हर जगह हिन्दी शिक्षा का माध्यम न होगी तो विश्वविद्यालय आपस में ज्ञान-विनिमय न कर सकेंगे, विज्ञान की उन्नति न हो सकेगी, देश की सांस्कृतिक एकता टूट जायगी, इत्यादि। इस स्थिति से लाभ उठाकर अंग्रेजी-भक्त कहते हैं—“यह सब वहस बेकार है, सबसे भली अंग्रेजी; इससे नया ज्ञान भी मिलेगा, पारिभाषिक शब्द गढ़ने की समस्या भी न रहेगी और भारत की एकता भी बनी रहेगी।” इधर कुछ विश्वविद्यालय इस ओर काफ़ी सरगرمी दिखा रहे हैं। विभिन्न भाषा-क्षेत्रों में जितना ही वहाँ की भाषाओं के हक मारे जाएँगे, उतना ही अंग्रेजी उनके सिर पर सवार रहेगी, यह बात असंदिग्ध है। आवश्यकता इस बात की है कि देश की

भाषाएँ समान अधिकार पाकर विकसित हो और इनके बोलनेवाले अन्तर्जातीय व्यवहार के लिए हिंदी अपनाएँ। साहित्य के क्षेत्र में बहष्पन की होड़ लगाने के बड़े भारतीय साहित्य की सामान्य विशेषताओं का भी पहचानें और एक-दूसरे से सीखने की बात सोचें। यद्यपि कुछ पढ़े लिखे लोगों और धनी जना में जातीय द्वेषभाव काफी बड़ा हुआ है, तथापि जनसाधारण में परस्पर प्रेम और दंगभक्ति के भाव कितने दृढ़ हैं, इसका एक प्रमाण गोंगा का सत्याग्रह है। इस छाट-मे प्रदेग का मुक्त कराने के लिए बंगाली, मराठी, पंजाबी, हिन्दी आदि अनेक भाषाएँ बोलनेवाले नौजवानों ने अपने प्राणा की बाजी लगा दी। किसी ने यह नाचकर जागा-पीछा नहीं किया कि गोंगा के लोगों की भाषा तो कोकणी या मराठी है हम उनके लिए क्यों जान द। पन्द्रह अक्षय के बाद देश में जो व्यापक प्रदर्शन हुए, वे भी इसी जातीय सहयोग और दस प्रेम का सूचक हैं। जनसाधारण में यह भाईचारे का भाव दस की बहुत बड़ी सामूहिक निधि है। यही वह शक्ति है जो देश की जातीय द्वेष के भाग से हटाकर प्रेम, समानता और सहयोग के भाग पर ले आयगी। इसके बिना न तो समूचे देश का विकास सम्भव है, न किसी जाति-विरोध का। (१९५५)

## अनिवार्य राजभाषा का सवाल

भारत के संविधान में राजभाषा से सम्बन्धित धाराओं को स्वीकृत हुए चार वर्ष से ऊपर हो गए। जो कमीशन हिन्दी के व्यवहार के बारे में राष्ट्रपति के सामने अपने सुझाव रखेगा, वह भविष्य में बनेगा। किन्तु कुछ विद्वान् राजनीतिज्ञ को उस भाषायी क्रान्ति की सम्भावना से घबरा उठे हैं जिसके जनक वे स्वयं थे। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने पटना में भारतीय हिन्दी परिषद् के अधिवेशन में कहा था, “अगर अंग्रेजी हटाने पर बहुत जोर दिया जायगा तो इससे हिन्दी को लाभ नहीं हानि होगी, राष्ट्रीयता लुप्त हो जायगी, प्रादेशिक भावनाएँ प्रबल होंगी, भारत के टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे।” ऐसा लगता है कि अंग्रेजी की स्थिति को ज़रा-सा भी धक्का लगने पर देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। एक अन्य राज्यपाल, मद्रास में श्री श्रीप्रकाश ने संस्कृत को भारत की राजभाषा बनाने की बात कही है।

स्पष्ट है कि संविधान की भाषा-सम्बन्धी धाराएँ स्वीकृत करने के बाद भी कांग्रेसी नेता भाषा-समस्या का अन्तिम समाधान पेश नहीं कर चुके।

सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में जनता की भाषाओं के व्यवहार के लिए संघर्ष स्वाधीनता और जनतन्त्र के लिए होनेवाले संघर्ष का ही एक अंग है। रवीन्द्रनाथ और भारती जैसे कवियों ने बँगला और तमिल के गौरव-गीत गाये। जनता ने मैकाले की भाषा-नीति का विरोध किया, जिसका उद्देश्य विदेशी साम्राज्यवादियों की चाकरी करने-वाले बुद्धिजीवी तैयार करना था। ब्रिटिश शासकों ने कोशिश की कि जनता की भाषाएँ दबाई जाएँ, उन पर अंग्रेजी लादी जाय, और जनता की एकता नष्ट कर दी जाय। साम्राज्यवादियों का स्वप्न रिजले की पुस्तक ‘द पीपुल ऑफ़ इंडिया’ में इस तरह प्रकट हुआ है, “यह सम्भव है—यद्यपि सम्भावना दूर भविष्य की है—कि शायद अंग्रेजी ही भारत की राष्ट्रभाषा बनेगी।”

प्रारम्भिक दिनों में कांग्रेस के नेताओं की भाषा अंग्रेजी थी। किन्तु १९२० के बाद राष्ट्रीय स्वाधीनता-आन्दोलन की प्रगति के बाद भारतीय भाषाएँ राजनीतिक मंच पर अग्रसर होने लगीं। लेकिन भारतीय भाषाओं की यह प्रगति नेताओं को हमेशा अच्छी नहीं लगी। उनमें से कुछ चक्रवर्ती सम्राटों के गौरवमय इतिहास का स्वप्न देखते हैं

जब पुरोहितों की सहायता में वण-व्यवस्था वाले समाज में संस्कृत का बोलचाल था। कुछ अन्य नेता 'डूबने की तिनके का सहारा' की मसल चरिताथ करते हुए अंग्रेजी का दामन धामे हुए हैं।

कांग्रेसी नेताओं ने जब हिन्दी को राजभाषा के लिए मान्य किया, तब तब सत्ता प्राप्त किए उधर चार वर्ष हो गए थे। लेकिन इस फैसले के साथ उन्होंने यह भी मुनिदिचन कर दिया कि सभी सरकारी कामों के लिए अगले पन्द्रह साल तक अंग्रेजी का व्यवहार होगा। इस प्रकार अंग्रेजी का चलन उन्होंने बीस साल के लिए पक्का कर लिया। संविधान को लागू हुए पाँच साल भी नहीं बीते कि हमें उपदेश सुनने की मिलने लगे हैं कि अंग्रेजी को हटाना खतरनाक है। पन्द्रह साल के बाद पार्लियामेंट कानून बनाकर अंग्रेजी का चलन बनाय रह सकते हैं। कांग्रेसी नेताओं की यह भाँसा नहीं थी कि अंग्रेजी हटाने के लिए जमकर कोशिश करें। उन्होंने स्पष्ट ही अपने सामने यह सम्भावना रखी थी कि पन्द्रह साल के बाद भी अंग्रेजी जारी रहेगी। शायद उसके अगले पन्द्रह साल तक भी जारी रहेगी, हाँ सकता है कि इसके आगे भी जारी रहे। संविधान-सभा में बहस की तमाम सरगमियों के पीछे यह निमग्न निश्चय साफ दिखाई देता है कि समस्त भारतीय भाषाओं की हानि करत हुए अंग्रेजी का अनिवार्य राजभाषा के रूप में चालू रखा जाय। श्री नेहरू ने बड़ी स्पष्टता से कहा है कि "आप इस बात को प्रस्ताव में चाहे लिखें, चाहे न लिखें, अंग्रेजी भाषा की तौर से भारत में बहुत महत्वपूर्ण भाषा बनकर रहती जिसे बहुत लोग सीखेंगे और शायद उन्हें उसे बचराना भी पड़ेगा होगा।" लागू इन तमाम वर्षों में अंग्रेजी जरूरत सीखते आये हैं। अब उनके सामने एकमात्र यह सम्भावना पेश की गई है कि अंग्रेजी के बिना हमारी कला और विज्ञान का पतन हो जायगा और देश का विघटन होगा, उसका नाश हो जायगा।

अंग्रेजी की विशेषाधिकार वाली स्थिति इस बात से और दृढ़ हो गई है कि उसका व्यवहार सुप्रीम कोर्ट और प्रत्येक हाईकोर्ट की कार्यवाही में, पार्लियामेंट या विधान-सभाओं में पेश हानेवाले हर बिल के लिए होगा और बिल का अंग्रेजी रूप ही अधिकारी रूप माना जायगा। यदि राज्यपाल या राज्यप्रमुख की आना से किसी बिल, ऐक्ट या आर्डीनेंस के लिए हिन्दी का व्यवहार किया जायगा तो अंग्रेजी रूप ही अधिकारी रूप माना जायगा। भारतीय जनता के लिए इससे अधिक अपमानजनक दूसरी बात हो नहीं सकती। अंग्रेजी के मुकाबले में तमाम भारतीय भाषाओं को नीचा दर्जा संविधान ने ही दे रखा है।

संविधान में यह लिख दिया गया है कि पन्द्रह वर्ष तक भारत की भाषा नीति में कोई भी परिवर्तन न होगा। संविधान ने राज्यों को इसके लिए भी बाध्य किया है कि वे एक-दूसरे से केवल हिन्दी या अंग्रेजी में ही पत्र-व्यवहार करें। अपनी सरकारी कार्यवाही में विशेष कानून बनाये बिना कोई राज्य अंग्रेजी की जगह अपनी भाषा का व्यवहार नहीं कर सकता। वतीजा यह है कि लगभग सभी राज्यों में सारा सरकारी काम अंग्रेजी में

होता है। इस प्रकार यह विदेशी भाषा न केवल अखिल भारतीय स्तर पर अनिवार्य राजभाषा बनी हुई है वरन् विभिन्न राज्यों में भी अनिवार्य राजभाषा बनी हुई है।

भारत के कुछ बुद्धिजीवी अनिवार्य राजभाषा के रूप में हिन्दी का तो विरोध करते हैं लेकिन अंग्रेजी जो सब पर हावी है और जिसे खास अधिकार मिले हुए हैं, उसके बारे में चुप रहते हैं। ये लोग समझते हैं कि आम जनता पिछड़ी हुई है, इसलिए अंग्रेजी पढ़े लोगों का काम है उस पर शासन करना और जनता का काम है शासित होना। कहा जाता है कि अंग्रेजी के बिना देश की आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति बन्द हो जायगी। लेकिन आम जनता के सहयोग के बिना किसी तरह की प्रगति नहीं हो सकती, न आर्थिक, न सांस्कृतिक।

भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध करने से अंग्रेजी का प्रभुत्व कायम रखने में मदद मिलती है। एक ही राज्य में अनेक जातियों के रहने से उनमें से कोई भी अपना राजकाज अपनी भाषा में नहीं कर सकती। अपनी जातीयता के आधार पर जब तक लोग अपने राज्यों में पुनर्गठित न होंगे, तब तक अंग्रेजी का प्रभुत्व समाप्त न होगा।

ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के मुखपत्र लन्दन के 'इकॉनोमिस्ट' ने लिखा था, "भारत की संविधान सभा ने गरम वहस के बाद तय किया है कि हिन्दी के राजभाषा बनने से पहले अभी पन्द्रह साल तक अंग्रेजी राजभाषा और बनी रहेगी। इससे पता चलता है कि भारत के राजनीतिज्ञ यथार्थ का सामना करने को तैयार हैं और समझौता स्वीकार करते हैं। उनके इस रवैये की बहुत-सी मिसालें आजादी के बाद मिल चुकी हैं।"

इस साम्राज्यवादी पत्र और राज्यपाल श्री मुशी के यथार्थ-दर्शन में काफी समानता मालूम होती है।

जहाँ तक अंग्रेजी के प्रभुत्व का सवाल है, हम वही हैं, जहाँ सन् '४७ में थे। यह प्रभुत्व और दृढ़ ही हुआ है। असली यथार्थ यही है जिसका दर्शन आम जनता आये दिन करती है, इस यथार्थ को बदलना है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, सुब्रह्मण्य भारती, बीरेशलिंगम, बल्लत्तोल आदि महान् साहित्यकारों ने जो संघर्ष आरम्भ किया था, उसे तब तक जारी रखना चाहिए जब तक अंग्रेजी को हटाकर भारतीय भाषाओं को उनके उचित अधिकार न दिला दिये जाएँ। यह संघर्ष हमारे राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय गौरव और आत्मसम्मान की मुरावा के लिए संघर्ष है; वह समानता और परस्पर सहयोग के आधार पर भारतीय जनता की एकता को दृढ़ करने के लिए संघर्ष है।

भारत में पूँजीवादी राष्ट्रवाद की लपटें उठ रही हैं। उत्तर दक्षिण के लोग भीम और दुर्योधन के समान एक-दूसरे पर प्रहार करने को उद्यत दिखाई देते हैं। संविधान-सभा की वहस में श्री एल० के० मेत्र, श्री गाडगिल, श्री रामलिंगम चेट्टियार, श्री श्यामाप्रसाद मुखर्जी, श्री शंकरराव देव आदि ने हिन्दी के प्रभुत्व से भय की बात की। श्री श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने कहा था, "भारतीय संविधान में एक धारा बना देने से आप

सब लोगो को बाध्य नहीं कर सकते कि वे एक ही भाषा को स्वीकार कर लें।" उन्होंने यह भी कहा था, "दुर्भाग्य से लोगो में यह भय है और कई जगह उस भय का असली रूप भी दिखाई देना है। इन जगहों में लोगो को अपनी भाषाओं के व्यवहार की अपनी मुद्रिधा भी नहीं दी गई जिनकी धूनि विदेशी राज्य में भी उन्हें प्राप्त थी।"

संविधान में हिन्दी को राजभाषा का पद दिया गया है, किन्तु इस राजभाषा का वास्तविक क्या है? अंग्रेजी ने राजभाषा बनकर प्रादेशिक भाषाओं के बहुत-से अधिकार छीन लिये थे। विभिन्न राज्यों की स्वायत्त शासन के काफी अधिकार दिये बिना अंग्रेजी की जगह हिन्दी को देने का मतलब है, दूसरी भाषाओं के अधिकार निषिद्ध करना। संविधान में हिन्दी के विकास की बात कही गई है अन्य भाषाओं का उल्लेख नहीं है। इस तरह की मनोवृत्ति से भारत की विभिन्न जातियों में मैत्री और भाईचारा न बढेगा।

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम में कहा गया है, 'देश की एकता के नाम पर एक प्रदेश की भाषा 'हिन्दी' को सभी जातियाँ और राज्यों के लिए उनकी भाषाओं का अहित करने हुए, अनिवार्य राजभाषा बना दिया गया है।' इसलिए अहिन्दी जातियाँ अनिवार्य राजभाषा के रूप में हिन्दी का विरोध करती हैं और माँग करती हैं कि उनकी भाषाओं को सभी सरकारी कामों में इस्तेमाल किये जाने की सुविधा दी जाय।

भाषावार राज्य निर्माण का आन्दोलन जारी पकड़ रहा है। यह स्पष्ट है कि जातीयता के आधार पर जो नये राज्य गठित होंगे, उनमें राजकाज की भाषाएँ प्रादेशिक भाषाएँ होंगी। जो साग दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार करते रहें हैं, वे इस बात को समझते हैं। उन्होंने कहा है कि अपने-अपने प्रान्तों में प्रादेशिक भाषाएँ ज्ञान विज्ञान और राजकाज की भाषाएँ बन जाएँगी, तभी हिन्दी सचमुच राष्ट्रभाषा बनेगी।

(‘इतिहास’, दिल्ली, जुलाई-सितम्बर, १९५३)

माकमवाद दूसरों की दृष्टि के विरुद्ध किसी भाषा को अनिवार्य राजभाषा बनाने का विरोध हमेशा करता रहा है। लेकिन वह एक या अधिक भाषाओं के माध्यम द्वारा विभिन्न जातियों के परस्पर सम्पर्क कायम करने का समर्थक भी रहा है। लेकिन ने इस बात की जोर ध्यान दिलाया था कि स्विट्जरलैंड की पार्लियामेंट में इटालियन-भाषी प्रतिनिधि फ्रेंच बोलते हैं और कहा था, 'ऐसा वे किसी बर्बर पुलिस कानून के कारण डरे के भय से नहीं करत (स्विट्जरलैंड में ऐसा कोई कानून नहीं है) बल्कि केवल इसलिए कि किसी भी जनजात के सम्म नागरिक उस भाषा का व्यवहार करता उचित समझते हैं जिसे बहुमूल्यक जनता समझती हो।'।

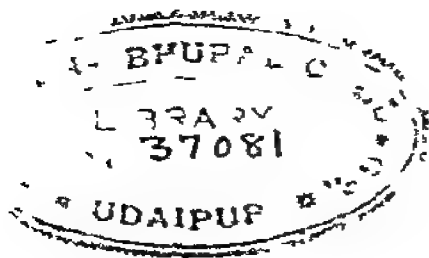
सावियन सभ के राष्ट्रपति कालानिन ने गैर रूसी जातियों में राजनीतिक प्रचारको से कहा था, "यह बहुत जरूरी है कि गैर-रूसी जातियों के सैनिक रूसी भाषा सीखें। रूसी भाषा सीखे बिना फौज में काम नहीं चल सकता। हमारे फौजी कानून-कानून रूसी में होते हैं। इसी भाषा में फौजी हुक्मनामे जारी किये जाते हैं और रूसी में ही सिपाहियों की कमान होती है। सोवियन सभ में रूसी सभी जनो की सम्पर्क-भाषा है।"

लेनिन ने जातीय समस्या पर लिखते हुए कहा था, “आर्थिक सम्पर्क की आवश्यकताएँ स्वयं बता देंगी कि किसी देश में बहु-संख्यक लोगों को किस भाषा के सीखने से व्यापार आदि में सुविधा होगी।” अंग्रेजों के आने से पहले भारत में व्यापार का अभाव न था। अनुभव से साबित हो गया है कि कौन-सी भाषा सीखने से बहु-संख्यक जनता को लाभ होता है। यह हिन्दुस्तानी जाति की भाषा है। सोलहवीं-सत्रहवीं सदियों में ही व्यापार की उन्नति होने पर यह भाषा देश के विभिन्न और नुदूर प्रदेशों तक पहुँच रही थी। न केवल भारत के व्यापारी यह भाषा सीखते थे बल्कि विदेशी सौदागर भी, अंग्रेजों की श्रेष्ठता पर ध्यान न देकर, यही भाषा सीखते थे। यही कारण है कि इटली के यात्री मनुच्ची ने शिवाजी से हिन्दुस्तानी में बातचीत की थी। महाराष्ट्र और तजौर में हिन्दी में कविता रचनेवालों का अस्तित्व इस भाषा की लोकप्रियता का प्रमाण है। इसलिए यह समझना गलत है कि अंग्रेजों के बिना न राष्ट्रीय आन्दोलन होता, न राष्ट्रीय एकता होती। अंग्रेजों ने देश के एकीकरण में बाधा डाली; इस एकीकरण में हिन्दुस्तानी जाति की भाषा महत्त्वपूर्ण भूमिका पूरी कर रही थी। वैष्णव कवियों ने सांस्कृतिक स्तर पर जनता की एकता को दृढ़ किया। उन्नीसवीं सदी के समाज-सुधारकों और धर्म-प्रचारकों ने अपने कार्य के लिए इस भाषा को अपनाया। यह स्वाभाविक था; क्योंकि संख्या की दृष्टि से सम्भवतः चीनी जाति को छोड़कर हिन्दुस्तानी जाति संसार की सबसे बड़ी जाति है। इस कारण भारत की विभिन्न जातियों में आर्थिक और सांस्कृतिक सम्पर्क के लिए उसका व्यापक व्यवहार हुआ।

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी अनिवार्य राजभाषा का विरोध करती है। इसका यह अर्थ नहीं है कि वह राष्ट्रीय एकता का मूल्य नहीं समझती, या उस एकता को दृढ़ नहीं करना चाहती। कम्युनिस्ट पार्टी पूरी तरह अनुभव करती है कि राष्ट्रीय स्वाधीनता की सुरक्षा और देश की आर्थिक प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न राज्यों और प्रदेशों की जनता की एकता और परस्पर भाईचारा दृढ़ किया जाय। स्वभावतः प्रग्त उठता है कि जिन लोगों की मातृ-भाषाएँ अलग-अलग हैं, वे किस भाषा में परस्पर बातचीत करें। भारत की ठोस परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कहा जाएगा कि यह भाषा हिन्दी ही हो सकती है। यह प्रक्रिया अभी भी चालू है। इसलिए अपनी मदुरा कांग्रेस में कम्युनिस्ट पार्टी ने यह स्पष्ट कहा है कि अनिवार्य राजभाषा को लागू करने का विरोध करते हुए भी पार्टी चाहती है कि हिन्दी विभिन्न राज्यों की जनता तथा उनकी सरकारों के बीच परस्पर सम्पर्क का साधन अविकाधिक बने।

(१९५४-५५)





१४

## अंग्रेजी के हिमायती

अंग्रेजी अन्तराष्ट्रीय भाषा है और उसे इस पद पर बगए रखने में भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य ने काजी बोग दिया है। उपवास, कविता, राजनीति, विमान—किस पर वे नहीं निम्ने ? किस पर वे नहीं बोलने ? अभी तक साहित्य और महत्ति का अन्तराष्ट्रीय नियम नहीं लिखा गया, लिख गया है विश्व, महाद्वीपों, राष्ट्रों या जातियों के इतिहास। यदि कभी अंग्रेजी ने अपनी भाषा का महत्त्व पहचाना और उसका अन्तराष्ट्रीय सांस्कृतिक इतिहास लिखा तो उन्हें इस भारत के अंग्रेज अदीबों को महत्त्वपूर्ण स्थान देना होगा।

मिर्ज़े जियाँ एक अंग्रेजी पत्र के 'कॉन्सलिट'—'अदीब'—में भारतीय भाषाओं के बारे में गंभीर विचार प्रकट किए हैं। उनका कहना है कि अंग्रेजी की भी व्यञ्जन शक्ति किसी नागरीय भाषा में नहीं है। इनलिए भावुकता छाटकर अंग्रेजी की छरण जाना ही उचित है। यह बात किन्हीं नहीं है, इसे 'अदीब' के साथ इन पत्रियों का लेखक भी अनुभव कर रहा है। 'कॉन्सलिट' का पर्यायवाची हिन्दी में मिलता नहीं है, उपर अंग्रेजी शब्द की अंग्रेजी-वाक्यों लिखन में खतरा यह है कि जपड़ हिन्दीभाषी उसे अपभ्रंश बनाकर 'कलमनष्ट' में कर दें। हिन्दी के पाठक ऐसे जाहिल हैं कि उनमें से कुछ 'अदीब' का अर्थ अदब लगा लें, ता भी आश्चर्य नहीं। लेकिन इतना तो उह मायूम ही होता चाहिए कि अदीब अंग्रेजी का शब्द नहीं है। हिन्दुस्तान का न सही, एशिया का तो है। अंग्रेजी के लेखक हाल हुए भी अदीब ने अपने लिए एशियाई उपनाम चुना, इस पर दो महीने बाद दिल्ली में होतवाल एशियाई लेखक-सम्मेलन को उह बगार्दे देनी चाहिए।

हिन्दी की व्यञ्जन-शक्ति कितनी सीमित है इसके उदाहरणस्वरूप 'अदीब' ने इतिहास की दो पत्रियों का अनुवाद दिया है—

हम जोउले हैं।

हमारे अंदर सूना भरा हुआ है।

महाकवि इण्डियन की नावेल पुरस्कार मिला चुका है। अब हिन्दी के पाठक उनकी रचनाओं में ऐसे महान् विचार प्रकट होने देखकर आधुनिक अंग्रेजी कविता के बारे में क्या सोचेंगे, जो लखेंगे, उससे भारत विज्ञ-संज्ञी कैसे दृढ़ होगी और भारत में अंग्रेजी साहित्य-

रचना का भविष्य क्या होगा, इस तरह की समस्याएँ सभी चिन्तकों को चिन्तित कर सकती हैं। इलियट की महान् कल्पना—हम खोखले हैं; हमारे अन्दर भूसा भरा हुआ है !—‘अदीव’ के अनुसार हिन्दी के अनुवाद में, सत्य बात कहते हुए भी हास्यास्पद हो जाती है। वास्तव में सत्य कभी-कभी हास्यास्पद हो ही जाता है, यद्यपि हिन्दी में हास्य-रस को उतना ही उच्च स्थान दिया गया है जितना अन्य रसों को। सहृदयों को तो साधारणीकरण द्वारा यहाँ भी रस-निष्पत्ति में आपत्ति न होगी !

इलियट—जैसे कवियों का उल्लेख करते हुए ‘अदीव’ ने पूछा है कि इनसे हिन्दी, बँगला या तमिल कैसे बुलवाएँ ? बहुत ही अदब से कहना चाहता हूँ कि बँगला या तमिल में बुलवाने की जरूरत क्या है ? राष्ट्रभाषा हिन्दी ही उन सब की बोलियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए काफी है। फिर आपने हमारे प्रयोगवादियों की बोली नहीं सुनी ? इतने दिन इलियट के भूसे में हिस्सा बँटाकर जो वत्स आनन्दमय स्वर में रँभाते रहे हैं, उनकी रागिनी पर आपने कान नहीं दिया ? माना कि ‘हम खोखले हैं’ और अंग्रेजी की मूल पंक्तियों का अनुवाद करना कठिन है, लेकिन उसी काव्य-परम्परा की इस एक पंक्ति का आप ही अंग्रेजी में अनुवाद कर डालिए—“मैं ही मरघट का वह रिरियाता कुत्ता।”

‘अदीव’ ने क्या ही मुन्दर विचार प्रकट किया है—

A language is not a donkey ! भाषा गधा नहीं है। गधे तो भाषा के बोलने और लिखनेवालों में होते हैं। भाषा को ठोकर मारो, चाहे पुचकारो, कोई लाभ न होगा। लेकिन यह क्रिया भाषा के बोलने या लिखनेवालों के साथ करो, अवश्य फल देगी। मेरी समझ में भारत में अंग्रेजी के लेखकों के प्रति हमारी राष्ट्रीय नीति पुचकारने की है और भारतीय भाषाओं के लेखकों को ठोकर मारने की। मैं इस नीति की सफलता चाहता हूँ।

और इस नीति में बुरा क्या है ? भारत के लोगो ने अपनी भाषाएँ छोड़कर अभी तक अंग्रेजी नहीं अपना ली—जैसे कि जारशाही रूस के अभिजात वर्ग ने फ्रांसीसी भाषा अपना ली थी—इस सकीर्णता को क्या कभी क्षमा किया जा सकता है ? रूसी लेखक गोगल ने एक नगर की सम्भ्रान्त महिलाओं के बारे में लिखा था—“रूसी भाषा का संस्कार करने और उसे ऊँचा उठाने के लिए उन्होंने अपने शब्द-भण्डार के आधे शब्द बहिष्कृत करके उनकी जगह फ्रांसीसी शब्द रख लिये थे।”

आप स्वीकार करेंगे कि दिल्ली और वन्वर्ड—जैसे नगरों के सज्जन—अर्थात् वास्तव में शिक्षित सज्जन—उन रूसी महिलाओं ने बाजी मार ले गए हैं।

सम्भ्रान्त रूसी समाज के पाठकों के लिए गोगल ने लिखा था—“इनके मुँह से कभी कोई सभ्य रूसी शब्द मुनने को नहीं मिलता। फ्रांसीसी, जर्मन और अंग्रेजी शब्दावली का प्रवाह उनके मुँह से फूट पड़ता है। उनका उच्चारण भी तरह-तरह का होता है। वे फ्रांसीसी बोलते हैं तो नाक से, और थोड़ा तुतलाते हुए। अंग्रेजी बोलते हैं तो चिड़ियों की तरह, दुस्त चहचहाते हुए। और जब बोलते हैं तब चिड़ियों—जैसे दिखाई भी देते हैं।

व उन पर हँसत हैं जो बिड़िया-जैसा मूत्र नहीं बना पान। वे हमी में कुछ नहीं लिखते। उनकी दण्डमयन इसमें प्रकट होती है कि वे ग्रीष्म-निवास के लिए रूसी नीली में भोपड़ी बनवा लें।

परन्तु जब शिमला, मसूरी, तैनीताल आदि में अंग्रेजी शैली के 'कॉटेज' होने के कारण भारत के अन्तर्राष्ट्रीयतावादियों के लिए हिन्दुस्तानी ढंग की भोपड़ी बनाना भी आवश्यक नहीं। यहाँ भी व स्त्रियों से जाते हैं।

गोपन की शिकायत है कि उन समय के सम्मानित विद्वान् हमी भाषा के लिए स्वयं तो कुछ न करते थे लेकिन यह गौण अवश्य करत थे कि हमी भाषा परिष्कृत और समझ हा जाय, वह अपने परिष्कृत और समृद्ध रूप में आम्रमान में उतरे और उनका नाम इनका ही हा कि जो भी निवास कर उमे गय कर लें।

परन्तु 'अदीव' की यह माँग नहीं है कि हिन्दी या अन्य भारतीय भाषाओं को समृद्ध किया जाय। उनकी माँग यह है कि भारतीय भाषाओं के बदले अंग्रेजी में ही सारा काम चलाय रह। यहाँ भी भारत के सम्मानित विद्वानों ने डारणाही रूस के सम्मानित विद्वानों को पीछे छोड़ दिया है।

अदीव ने चेनावनी दी है कि अंग्रेजी का महारा न लिया तो पुन टूटने लगेंगे और हमारी-नीमरी चौकी पचवर्षीय योजनाएँ असफल हो जाएँगी। यह चेनावनी एकदम नास्तिक है। अभी हिन्दी को केन्द्रीय राजकाज की भाषा बनाने की बात ही चली है कि हेनरादाद राज्य में दो बार पुन टूट चुके हैं और अनन्तता की भारी क्षति हुई है। जब चर्चा का ही यह पत्र है तब व्यवहार में आने पर हिन्दी से कोन-सी क्षति न होगी, आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। हमी तरह योजनाओं के सम्बन्ध में भी। घूम और रिदवत का वाजान गन है। योजना पूरी हा नहीं पायी कि घूम-गवन की जाँच के लिए समिति बैठाया आवश्यक हो जाता है। जब तक हिन्दी का पूर्ण बहिष्कार नहीं हो जाता, तब तक हर योजना को व्यवहार में लाने के साथ-साथ घूम और रिदवत की जाँच के लिए पहले से ही एक समिति बना देनी चाहिए। इसने निश्चय हा जाणगा कि योजनाओं द्वारा पैसा खाने-बाने का सिद्धी स कितना गहरा सम्बन्ध है।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का सम्मान बढ़ रहा है। राष्ट्रीय जीवन में भी अंग्रेजी का वैसा ही प्रभुत्व रह तो जश्न घेकारी, वाड, नुखमरी आदि की समस्याएँ तुल्य हल हो जाएँ और प० नरेश की गृहनीति में भी चार चाँद लग जाएँ। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में पचशील का शब्द अस्तर चल पडा है। यह 'पचशील' या और किसी तरह का चीन उन अंग्रेजी-अमरीकियों को पसन्द नहीं है, जिनको अपनी भाषा अंग्रेजी है। इस राज्य को त्याग देना चाहिए। इसके सिवाय आपने ध्यान दिया होगा कि रूस के प्रधानमंत्री आप थे तो अपने साथ हिन्दी बोलनेवाला दुमापिया लाए थे। स्पष्ट है कि साम्यवादी देशों के राजनीतिज्ञ अंग्रेजी के बदले हिन्दी को प्रश्रय देते हैं। इसलिए जो लोग राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत द्वारा अंग्रेजी के बदले हिन्दी के व्यवहार पर जोर देते हैं, वे

ज्ञान में या अनज्ञान में इसी पड़्यन्त्र के सहायक बन जाते हैं।

‘अदीब’ की घ्राण-शक्ति सराहनीय है कि उन्हे हिन्दी में मध्यकालीनता की गन्ध मिल गई। जिनकी घ्राण-शक्ति क्षीण हो गई है, वे हिन्दी को आधुनिक भाषा समझने लगे हैं। यद्यपि विज्ञान-सम्बन्धी पुस्तकें हिन्दी में काफ़ी निकली हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने उसमें मौलिक पुस्तकें तो नहीं ही लिखी। इसलिए हिन्दी और उसी की तरह अन्य भारतीय भाषाओं में भी मध्यकालीनता मिले, तो आश्चर्य क्या? अब अंग्रेजी को देखिए। उसके द्वारा अणु बम बनाए जाते हैं जिनसे विश्वशान्ति कायम है और भंग भी होगी तो जन-संख्या की समस्या हल हो जाएगी। हमारा विचार है कि प्राचीन भारत में गणित ने जो प्रगति की थी, वह भी अंग्रेजी के कारण। आर्य भट्ट ने अवश्य नेसफील्ड ग्रामर पढ़ी होगी। दशमलव-ज्ञान का श्रेय भारत को दिया जाता है, लेकिन उस श्रेय में नेसफील्ड का भी हाथ है, यह बहुतों को नहीं मालूम। पाणिनि ने अपना व्याकरण लिखा और आधुनिक भाषा-विज्ञान के विकास में उस व्याकरण की महत्त्वपूर्ण भूमिका स्वीकार की जाती है। दुर्भाग्य से पाणिनि पर नेसफील्ड के प्रभाव की खोज किसी भी डॉक्टर के उम्मीदवार ने अभी तक नहीं की। जर्मनी, इटली, फ्रांस, रूस आदि देशों में जो वैज्ञानिक प्रगति हुई है, उसका कारण यह है कि वहाँ की भाषाएँ अंग्रेजी से उत्पन्न हुई हैं। न उत्पन्न हुई होगी, तो वहाँ का सारा वैज्ञानिक कार्य अंग्रेजी के माध्यम से होता होगा। न होता होगा, तो वह विशुद्ध वैज्ञानिक कार्य भी न होगा। जिस तरह भी विचार करें, आप यह स्वीकार किए बिना न रहेंगे कि संसार में वैज्ञानिक प्रगति अंग्रेजी द्वारा ही हुई है। सुना है कि मंगल नक्षत्र में जो प्राणी रहते हैं, वे भी अंग्रेजी बोलते हैं। अमरीकी खगोल-विशारदों ने रेडियो पर उनसे बातचीत की है। इस प्रकार अंग्रेजी का महत्त्व विश्वव्यापी ही नहीं, सृष्टिव्यापी है।

अस्तु! ‘अदीब’ के इस निष्कर्ष से सहमत होना ही होगा कि किसी राष्ट्र के जीवन में दस, सौ या हजार वर्ष भी क्या हैं, सोचने-विचारने और आगा-पीछा देखने के लिए समय की कमी नहीं है। तब तक आइए, हम इस मन्त्र का जप करें—

हम खोखले हैं!

हम में भूसा भरा हुआ है!

(१९५६)

## सोवियत क्रान्ति और भाषा-समस्या

आज से चात्सीस साल पहले समार की महान् समाजवादी क्रान्ति की विजय ने पिछड़े हुए बहुजातीय देशों के सामान सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का एक नया आदेश रखा। यह विकास पिछड़ी हुई जातियों की भाषाओं के माध्यम से ही सम्भव था। इसलिए सामाजिक विकास की समस्याओं के साथ समाजवादी क्रान्ति ने भाषा-समस्या हल करने का भी एक नया माग हमें दिखलाया।

अभी सौ साल न बीते थे जब रूस का अभिजान वग रुसी की पिछड़ी हुई भाषा मानता था। वह अपने सांस्कृतिक जीवन में अधिकतर फ्रांसीसी भाषा का व्यवहार करता था। हमारे देश में भी अनेक विद्वान् हिन्दी ही नहीं, भारत की सभी भाषाओं की पिछड़ी हुई मानते हैं। इसलिए केन्द्रीय राजकाज के लिए वे बहुत दिना तक अंग्रेजी का व्यवहार उचित समझते हैं। रूस के नेताओं ने अपने राजनीतिक पत्र फ्रांसीसी के बदले रुसी में ही प्रकाशित किये थे। रूसी उनके राजनीतिक जीवन की भाषा थी। गैर-रूसी इलाकों के नेता वहा की भाषाओं का व्यवहार करते थे। इसलिए रूसी की पिछड़ी हुई भाषा मानकर संक्रमण काल के लिए अनेक वर्षों तक फ्रांसीसी भाषा के व्यवहार का प्रस्ताव उन्होंने नहीं रखा। रूसी जनता के लिए उन्होंने तुरन्त रूसी भाषा को राजकाज की भाषा घोषित कर दिया। आज तो लोग मानते हैं कि रूसी समार की समृद्ध भाषाओं में से है लेकिन यह स्थिति १९१७ में न थी। तोन्स्तोय, बेखव, गोर्की आदि कुछ उपन्यासकार अवश्य हा गए थे, जैसे भारत में रबीन्द्रनाथ, भारती, प्रेमचन्द, शरत्चन्द्र, इत्यादि आदि कवि और कथाकार हो गए हैं। लेकिन फ्रांस जर्मनी और ब्रिटेन की तुलना में वैज्ञानिक शिक्षा की पुस्तकें उसमें कहीं थी ? यह तर्क दिया जा सकता था कि किसी भी विषय की समुचित शिक्षा के लिए रूसी भाषा पर्याप्त नहीं है, इसलिए जब तक वह समृद्ध न हो जाय तब तक केन्द्रीय राजकाज फ्रांसीसी में होना चाहिए। लेकिन के नेतृत्व में स्वाभिमानी रूसी जनता ने अपनी पिछड़ी कहारनेवाली, अभिजान वर्ग द्वारा उन्मिन्न भाषा में ही अपना मारा राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्य आरम्भ किया। भारत में जहाँ भाषा और शिक्षा की हजार वर्ष पुरानी परम्परा है (मिथु घाटी के जन भी लिखना-पढ़ना जानते थे) वहाँ आज यह दयनीय स्थिति है कि देश की सभी भाषाओं की पिछड़ा हुआ मानकर अनेक वर्षों के लिए अंग्रेजी के व्यवहार का समर्थन किया जाता है।

खैर, रूसी में तो रवीन्द्रनाथ, प्रेमचन्द की तरह तोल्स्तोय और गोर्की जैसे विश्व-विख्यात लेखक थे। वैज्ञानिक शब्दावली में फ्रेंच के मुकाबले में रूसी भले ही पिछड़ी रही हो, कथा-साहित्य में हिन्दी और बँगला की तरह रूसी समृद्ध थी। किन्तु वेलोह्सी, उक्रेनी, जाज़ियाई आदि भाषाओं में तो इतने बड़े नाम न थे। सोवियत राज्यसत्ता ने उन्हें भी अपने-अपने क्षेत्र में राजकाज की भाषा बनाया। इनसे भी गई-गुजरी अज़रबैजनी, ताजिक, कज़ाक आदि भाषाएँ थीं जिनमें मौखिक साहित्य ही अधिक प्रचुर था। ये भी राजकाज की भाषा बननीं। इनसे भी 'पिछड़ी हुई' चुकची, वुर्यात, मंगोल, चेरकास, समोयेद आदि भाषाएँ थी जिनकी स्थिति भारत के अनेक आदिवासी जनों की भाषाओं से भी गर्द-ब्रीती थी। इनको भी विकसित होने का मौका मिला। आज उनमें व्याकरण, कोण, विज्ञान, कथा-साहित्य, काव्य—सभी-कुछ है। हमारे देश में भाषा-समस्या के विवेचन में आदिवासियों की भाषाओं की चर्चा करने का अभी चलन नहीं है।

सोवियत संघ में कहीं भी यह दलील नहीं दी गई कि भाषाएँ पिछड़ी हुई हैं, इसलिए चालीस साल तक, उनके व्याकरण और शब्दकोश तैयार होने तक, उनकी जगह रूसी भाषा का व्यवहार होगा। भाषा जनता के लिए है, जनता भाषा के लिए नहीं है। हमारे देश में जनता की आवश्यकताओं को देखकर भाषा-समस्या हल नहीं की जाती; अंग्रेजी से हमारे जो काम हो जाते हैं, वे भारतीय भाषाओं से होंगे या नहीं, यह समस्या पहले आती है। पारिभाषिक शब्दावली इस तरह गड़ी जाती है मानो वह जनता के काम आने के लिए नहीं, उसकी जीभ और तालू का व्यायाम कराने के लिए है! पूँजीवादी और समाजवादी दृष्टिकोणों में यही अन्तर है। यदि भारत में साधारण जनता शासन के कामों में भाग ले, यदि उसके अपने जन-संगठन राज्यसत्ता का वास्तविक आधार हों, अर्थात् यदि इस जनवादी देश में जनता का राज सचमुच हो तो क्या यह कल्पना की जा सकती है कि एक दिन भी यहाँ अंग्रेजी से काम चलेगा ?

नवम्बर क्रान्ति ने मानवता के उद्धार और विकास का नया मार्ग दिखलाया; उस मार्ग पर चलकर नवनिर्माण का आदर्श हमारे सामने रखा। इस निर्माण में एक वर्ग दूसरे का शोषण और उत्पीड़न नहीं करता; उसमें एक जाति 'फ्री वर्ल्ड' के लुटेरों की तरह दूसरी जाति को दबाकर उसकी भाषा और संस्कृति को पैरों तले नहीं रौंदती। मानव-समाज जाति और वर्गों के रूप में ही संगठित हुआ है। वर्ग मिट जाने पर भी जाति बनी रहती है; इसलिए वर्ग-शोषण मिट जाने पर किसी सीमा तक जातीय उत्पीड़न की सम्भावना रहती है। सोवियत संघ ने सभी जातियों में परस्पर समानता, दूसरे की स्वाधीनता की रक्षा, उसके घरेलू मामलों में दखल न देने और एक-दूसरे की सहायता करने का आदर्श हमारे सामने रखा है। समाजवादी देशों की भाषा-सम्बन्धी नीति इसी मानववादी दृष्टिकोण का परिणाम है। भारत में इस दृष्टिकोण को अपनाकर हम अपनी भाषा-समस्या हल कर सकते हैं और अंग्रेजी की गुलामी से छुटकारा पा सकते हैं।

## अंग्रेजी-प्रेमी भारतवासी

अंग्रेजी भाषा के आदि कवि चौमर की प्रसिद्ध पुस्तक 'कॉण्टरबरी टेल्स' के 'प्रोलोग' (भूमिका) में एक पशुकार ('समनर') है जिसे लैटिन से बहुत प्रेम है। अदालत की कायवाही के मिनसिने में वह लैटिन के शब्द सुना करता है। इसलिए कुछ लैटिन शब्द उसे भी याद हो गए हैं। वैसे तो वह लोगों से अंग्रेजी में बातें करता है लेकिन जब शराब के नशे में होता है तब लैटिन छोड़कर बात नहीं करता।

अंग्रेजी राज की कृपा में कुछ लोगों ने अंग्रेजी भाषा सीखी है। वैसे तो वे अपनी भाषा में भी बात कर सके हैं लेकिन जब हिन्दी को केन्द्रीय राजभाषा बनाने का सवाल उठता है, तब वे अंग्रेजी छोड़कर बात नहीं करते।

ये अंग्रेजी-प्रेमी भारतवासी अंग्रेजी में, विनोदकर अंग्रेजी साहित्य से, यह सीख सकते थे कि अपने देश और अपनी भाषा में कैसे प्रेम करना चाहिए। इनका मुख्य तर्क है कि अंग्रेजी समृद्ध है विश्वभाषा है, हिन्दी दरिद्र है, चालीस फीसदी या उससे भी कम की भाषा है। घाड़ी दर के लिए हम यह तर्क स्वीकार कर लेते हैं। यदि इस मनोवृत्ति के लोग इंग्लैंड में होने लगे तो शायद ज्ञान वहाँ अंग्रेजी को भी राजभाषा का पद न मिला होता, लोग 'समनर' की तरह लैटिन में ही राजकाज करने होते।

एक युग ऐसा भी था जब अंग्रेजी ज्ञान की हिन्दी ने कहीं अधिक दरिद्र थी और अंग्रेजी जितना हिन्दी में बढ़कर आज है, उससे कहीं ज्यादा अंग्रेजी के मुकाबले में लैटिन बढ़कर थी। लैटिन यूरोप की अन्तर्राष्ट्रीय भाषा थी, वह ईसाइयों के संगठित धर्म-संघ की भाषा थी। सत्रहवीं सदी तक यूरोप और इंग्लैंड के लोगों में लैटिन द्वारा परस्पर कूटनीतिक सम्पर्क कायम रहना था और अन्तर्राष्ट्रीय वादविवाद लैटिन में होता था। इंग्लैंड में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो अंग्रेजी को मध्यमगुरु और लैटिन को स्थायी भाषा मानकर उसी में, अथवा उमम में अपने शास्त्रत मूल्यों वाले ग्रन्थ रचते थे। लैटिन ही नहीं, चौदहवीं-पंद्रहवीं सदी में फ्रांसीसी भाषा अंग्रेजी से अधिक विकसित और समृद्ध थी। इंग्लैंड में ऐसे साहित्यकार भी थे जो फ्रांसीसी में रचना करके अमर होना चाहते थे। किन्तु इतिहास ने लैटिन और फ्रांसीसी में लिखे हुए इनके ग्रन्थों को कूड़े के ढेर में फेंक दिया जहाँ वे अब केवल अनुसंधानकर्ताओं के काम आते हैं।

अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान पर शासन किया; अंग्रेजों के देश पर भी रोमनों और फ्रांसीसियों ने शासन किया था। किसी समय इंग्लैंड के अभिजात वर्ग पर फ्रांसीसी भाषा का वैसा ही रौब गालिब था जैसा आज के समनर-गोत्रीय भारतवासियों पर अंग्रेजी का है। किन्तु लैटिन या फ्रांसीसी को अधिक समृद्ध मानकर अंग्रेज जनता ने उसे राष्ट्रभाषा न मान लिया। उसके साहित्यकारों ने अपनी भाषा को समृद्ध किया और उसे यूरोप की नवीन और प्राचीन भाषाओं की पाँति में सम्मानप्रद आसन दिलाया। अंग्रेजी समृद्ध होने के बाद राजभाषा नहीं बनी; राजभाषा होने के बाद वह समृद्ध हुई। वह लैटिन और फ्रांसीसी भाषाओं की तुलना में समृद्ध हुई जिनके हिमायती उसके उचित आसन से उसे हटाना चाहते थे।

अंग्रेज शासकों ने यहाँ की जनता के आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास को रोका। उन्होंने यहाँ की भाषा के ऊपर साम्राज्य की तरह अंग्रेजी को प्रतिष्ठित किया। अंग्रेजी भाषा को अंग्रेज-प्रेमी भारतवासियों के पूर्वजों ने विधान-सभा में प्रस्ताव पास करके स्वीकार न किया था। वह अंग्रेज आततायियों द्वारा लादी हुई भाषा थी। संसार में अंग्रेजी का बोलवाला मिल्टन और शेले के कारण नहीं हुआ, उसका प्रसार करनेवाले क्लाइव और डलहौजी की विरादरी के थे। उत्तरी अमरीका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों में अंग्रेजी का प्रसार करनेवाले वे आक्रमणकारी थे जिन्होंने वहाँ के आदिवासियों के नरमेव रचाये थे, जिनका मिल्टन और शेले से इतना ही सम्बन्ध था कि दोनों ही अंग्रेजी बोलते थे (कैसी अंग्रेजी बोलते थे, यह प्रश्न छोड़ दीजिए)। यदि समृद्धि के बल पर कोई भाषा अंग्रेजी की तरह 'विश्वभाषा' बनती तो पाणिनि और कालिदास की भाषा मृत भाषा न कहलाती; दान्ते, गेटे, तोल्स्टोय की भाषाएँ भी विश्वभाषा बन जातीं। अंग्रेजी के समर्थक उसके प्रसार के लिए मिल्टन और शेले का नाम लेते हैं; उस ब्रिटिश साम्राज्य की कहानी भूल जाते हैं जिसमें कभी सूर्यास्त न होता था और अर्नेस्ट जोन्स के शब्दों में जिसकी धरती पर कभी रक्त न सूखता था।

अंग्रेजी-प्रेमी भारतवासी अपनी प्रिय विश्वभाषा के पक्ष में जितनी दलीलें देते हैं उनमें एक भी ऐसी नहीं है जिसे पहले 'लिवरल' राजनीति-विशारदों ने न दी हो। ये 'लिवरल' भद्रजन अंग्रेजी राज और अंग्रेजी भाषा के मामले में अत्यन्त उदार थे, हिन्दुस्तानी जनता के राज और हिन्दी भाषा के बारे में अत्यन्त अनुदार थे। वे अंग्रेजी राज को प्रगतिशील मानते थे, अंग्रेजों को भारतीय अराजकता दूर करके यहाँ न्याय और शान्ति की व्यवस्था कायम करनेवाला मानते थे। कभी इतनी ही थी कि अंग्रेज उच्च पदों पर इन्हें नियुक्त न करते थे। भारतीय जनता के क्रान्तिकारी आन्दोलन से त्रस्त ये उदारपन्थी महानुभाव नौकरियों में रियायतें पाने के लिए परम प्रगतिशील अंग्रेज शासकों के सामने प्रार्थना-पत्र पेश करने में महान् गौरव अनुभव करते थे। उन्हीं की परम्परा निवाहनेवाले ये वर्तमान 'लिवरल' हैं जिनके लिए अंग्रेजी के राजभाषा न रहने से राष्ट्र छिन्न-भिन्न हो जायगा, देश में गृहयुद्ध छिड़ जायगा, हिन्दीवाले सब नौकरियाँ



हथिया लेंगे, विश्व-सत्कृति से आदान-प्रदान के द्वार बन्द हो जाएँगे, इत्यादि। अंग्रेजों के चले जाने से बहुसंख्यक हिन्दू जल्पमस्यक मुसलमानों और अछूता को प्या डालेंगे—राउड टबुल कार्फेसो में जैसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री यह दलील पेश करते थे, वैसे ही स्वाधीन भारत के ये 'लिबरल' अंग्रेजों के बारे में कहते हैं, अंग्रेजों गई नहीं कि हिंदीवाने सारी नोकरिया हथिया लेंगे, उत्तरवाले दक्षिण पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लेंगे, अहिंदी भाषाओं का नाम निसान मिट जायगा। यह बान नहीं है कि राउड टबुल कार्फेसो के दिना में सम्प्रदायवादी रुढ़िवादी हिन्दू नहीं थे जो अछूता को गुलाम बनाकर रखना चाहते, जो मुसलमानों को अपना शत्रु समझते थे। किन्तु इनमें अछूता और मुसलमानों की रक्षा करने के लिए यह आवश्यक न था कि हिन्दू अहिन्दू सभी अंग्रेजों की शरण जाते। आज भी ऐसे हिन्दी प्रेमी हैं जो अहिंदी भाषाओं का दबाकर हिन्दी को वही स्थान देना चाहते हैं जो अंग्रेजी को प्राप्त था। इनमें अहिंदी भाषाओं की रक्षा करने का मांग यह नहीं है कि हम अंग्रेजों की शरण में जाएँ।

अंग्रेजी को राजभाषा बनाने रखने के पक्ष में उदारपक्षियों की दलीलों का खंडन प्रेसभक्त भारतवासियों ने ही न किया था, वरन् उनका खंडन भारत प्रेमी अंग्रेजों ने भी किया था। उदाहरण के लिए, उदार-हृदय सी० एफ० ऐण्ड्रूज ने 'द डू इंडिया' नाम की अपनी पुस्तक में लिखा था—“अभी तक अंग्रेजी भाषा को समझनेवाले मुड़ी-भर बुद्धिजीवी ही हैं किन्तु यह उभरती हुई माधारण भाषा, जो 'हिन्दुस्तानी' कहलाती है, उत्तर और मध्यभारत में पचीस करोड़ जनता द्वारा आमानी में समझी जाती है, दक्षिण में भी जहाँ द्रविड भाषाएँ बोली जाती हैं उत्तर की इस भाषा से नाग थोड़ा-थोड़ा परिचित हो गए हैं। यहाँ मद्रास प्रेसीडेन्सी के इन निरूपण जाश्रम में जब मैं लोगों की बातचीत सुनता हूँ तो उत्तर के उन संस्कृत शब्दों का पहचान लेता हूँ जो तमिष में घुल मिल गए हैं। कल एक व्यक्ति मुझसे मिलने आया था उससे जब मैंने अंग्रेजी में बातचीत करने की कोशिश की तो उसने कहा, 'कृपा करके हिन्दुस्तानी में बात कीजिए'। और जब मैं उस भाषा में बोला तो वह मेरी बात आमानी से समझ गया।”

सी० एफ० ऐण्ड्रूज की यह पुस्तक १९३६ में प्रकाशित हुई थी, तब में दक्षिण में हिन्दी पढ़नेवाला और हिन्दी समझनेवालों की संख्या बहुत बढ़ गई है। अंग्रेजी पढ़ने-बालों और अंग्रेजी समझनेवालों की संख्या उसी अनुपात में नहीं बढ़ी। अंग्रेजी के समर्थक अब भी मुड़ी-भर बुद्धिजीवी ही हैं।

भारत-प्रेमी ब्रिटिश महिला ऐनी बेसेंट ने 'इंडिया वाउण्ड और फ्री में राजभाषा अंग्रेजी के विरुद्ध अपनी अथ विभी रचना से यह कथन उद्धृत किया था—“जब मैंवाने ने अंग्रेजी सिंगा पर जोर दिया था, तब वह भारत के महान् साहित्य का धूणा की दृष्टि में देख रहा था। उसने यह न अनुभव किया था कि अंग्रेजी सिंगा पर जोर देकर वह विशाल जनता को अज्ञान के हवाले कर रहा था। रोटी के बदले वह पत्थर द रहा था। सबके सिंगा पाने से और अपने देश की श्रेष्ठ कृतिया में अपरिचित रहते थे। वे अंग्रेजी में

व्यवस्था झाड़ सकते थे, अपनी मातृभाषा में नहीं। किसी देश में राष्ट्रीयता के भाव नष्ट करने का इसमें अधिक कुशल उपाय नहीं है कि एक विदेशी भाषा को उच्च वर्गों की भाषा, कानून और अदालतों की, कॉलेजों की भाषा बना दिया जाय और सरकारी नौकरियों के लिए उस विदेशी भाषा की जानकारी आवश्यक कर दी जाय।”

ऐनी बेसेंट का कथन जितना युक्तिपूर्ण तब था, उतना ही आज भी है। अंग्रेजों के जाने के बाद साम्राज्यवाद से भारतीय जनता का अन्तर्विरोध समाप्त नहीं हो गया। इन्दोनेशिया, पाकिस्तान, मिस्र, सीरिया आदि एशिया के देशों में साम्राज्यवाद अपने मित्रों की तलाश में है जिनकी सहायता से वह इन देशों के आन्तरिक जीवन में हस्तक्षेप करे। इसलिए भारतीय जनता की राष्ट्रीय एकता को दृढ़ करने की ओर हमें सचेत रहना चाहिए।

ऐनी बेसेंट ने ‘इंडिया: वाउण्ड और फ्री’ में उपर्युक्त कथन उद्धृत करने के बाद लिखा था, “मैं यही कहना चाहूंगी कि इंग्लैंड ने बहुत कुछ, यद्यपि पूरी तरह नहीं, उसी शिक्षा-नीति का अनुसरण किया था जिसे पोलैंड में रूस ने लागू किया था। स्कूलों में पोलिश भाषा में शिक्षा देना बन्द करा दिया गया था और वहाँ रूसी का वैसे ही प्रयोग होता था जैसे यहाँ अंग्रेजी का। सभी देशों के तानाशाह एक-दूसरे से मिलते-जुलते हैं।”

आज उसी तरह कुछ अंग्रेजी-प्रेमी सज्जन शिक्षा-संस्थाओं में भारतीय भाषाओं की तुलना में अंग्रेजी को उच्चतर स्थान देना चाहते हैं। इससे भारतीय भाषाओं के विकास में कितनी क्षति होती है, इसकी ओर वे ध्यान नहीं देते। अंग्रेजी भाषा के आधुनिक ‘लिवरल’ हिमायतियों ने ऐण्ड्रूज और बेसेंट के विचारों की तुलना कीजिए तो पता चल जायगा कि इन भद्रजनों का दृष्टिकोण कितना प्रतिक्रियावादी है। राज्यसत्ता जनता के लिए है, जनता राज्यसत्ता के लिए नहीं है, यह सत्य उनकी समझ से परे है। वे राज्यतन्त्र को उसी पुराने नौकरशाही ढंग से चलाना चाहते हैं जिसमें नौकरशाह जनता के नौकर न होकर उसके ग्राह होते थे। यह युग जनतन्त्र का है; जनता अधिक-से-अधिक शासनतन्त्र में भाग लेगी। शासनतन्त्र जनता के उत्पीड़न का मन्त्र न होकर उसकी सेवा का माध्यम बनेगा। इस शासनतन्त्र में जनता अपनी भाषाओं द्वारा और केन्द्रीय राजकाज में हिन्दी द्वारा ही भाग ले सकती है। अंग्रेजी चाहे जितनी समृद्ध हो और हिन्दी चाहे जितनी दरिद्र हो, राजभाषा के रूप में अंग्रेजी का भविष्य अन्धकारमय है, हिन्दी का भविष्य अत्यन्त उज्ज्वल। अंग्रेजी के समर्थक इतिहास की प्रगति से युद्ध कर रहे हैं; इसलिए उनकी पराजय निश्चित है।

राजभाषा की समस्या किसी भाषा के समृद्ध होने की कसौटी पर न तो अन्यत्र हल हुई है, न यहाँ होगी। सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की आवश्यकताओं ने अनेक बुद्धिजीवियों को भारतीय भाषाएँ अपनाने पर पहले भी बाध्य किया था, आगे भी करेंगी। इन आवश्यकताओं में कुछ अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं ने इजाफा किया है। राष्ट्रीय आत्म-सम्मान का निर्वाह शायद देश में इतना आवश्यक नहीं होता जितना विदेश में। अखबारों

के अनुसार स्वाधीन भारत के प्रधानमन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने जनवरी में प्राग्ज्योतिषपुर में कहा था, "मैं अंग्रेजी का पनपाती हूँ। मैं चाहता हूँ कि न केवल भारत में अंग्रेजी पढ़ी जाय बल्कि उसकी शिक्षा का और भी प्रसार हो। लेकिन मैं उनकी कल्पना नहीं कर सकता कि कोई अंग्रेजी को भारत की राष्ट्रभाषा कहे। मैं चाहता हूँ कि लोग इस बात पर ध्यान दें। यह कहना कि अंग्रेजी एक राष्ट्रीय भाषा है, साथ के विरुद्ध है। यह झूठ है। मैं नहीं समझता कि यह दर्जाल कैसे दी जा सकती है। यह धार्मिक विचारणीय है कि हम अब तक अंग्रेजी का व्यवहार करने हैं या व्यावहारिक कारणों से अंग्रेजी और हिन्दी दोनों का काम में लाने हैं।"

इसके बाद अलबारी विवर्ण के अनुसार "श्री नेहरू ने कहा कि विदेश भाषी की हैमियत से जय देनों का कागज-पत्र भेजने हुए वह बड़े अममज्जम में पड़े कि जिन देशों में अंग्रेजी नहीं बाली जाती, उन्हें अंग्रेजी में लिखे हुए कागज-पत्र कैसे भेजे जाएँ। दुनिया अंग्रेजी बोचनेवाले देशों से बड़ी है। बड़े अममज्जम की बात थी। उन्होंने अंग्रेजी में कागज भेजना श्रद्धा कर दिया। अब वह सदा उन्हें हिन्दी में भेजते थे, उनकी मुविधा के लिए अंग्रेजी में अनुवाद साथ रहता था लेकिन मूल हिन्दी में ही भेजा था। जब उन्हें हम या चीन में कोई खरीदा मिलता था, तो वह हमेशा रुमी या चीनी में मिला था। हाँ सकता है, साथ में अंग्रेजी अनुवाद भी रहता था। कुछ भी हो, वह कह यह रहे थे कि दुनिया के सामने भारत में यह घोषित करना बड़ी अजीब बात थी कि भारत की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी है। इस 'कल्पना' में ही मेरा सिर अकरा उठता है।"

अंग्रेजी-प्रेमियों के दुर्भाग्य से दुनिया अंग्रेजी भाषी देशों से बहुत बड़ी है। इस अंग्रेजी बिहीन दुनिया में साठ करोड़ आवादी का महादेश चीन है। इसमें सत्तार के छोटे भाग में फैला हुआ समाजवादी सोवियत देश है। सोवियत साथ, चीन और भारत में जो भाषा न चले, उसे विश्वभाषा नहीं कहा जा सकता। इन तीन देशों में एशिया और यूरोप का अधिकांश भाग घिरा हुआ है। इनके साथ अफ्रीका और दक्षिण अमरीका को मिला लीजिये यूरोप से जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन और पूर्वी यूरोप के देशों को भी गिन लीजिये तो पता चल जाएगा कि अंग्रेजी का विश्वभाषा होना किना सार्थक है।

अस्तु, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों ही तरह के कारणों से अंग्रेजी को राज-भाषा का पद छोड़ना होगा। जो लोग भारतीय जीवन के कल्पित या वास्तविक अन्त-विरोधों के कारण अंग्रेजी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित रखना चाहते हैं, वे लिबरला, अंग्रेज-भक्तों, अन्यसम्बन्धों के उन तयामयित प्रतिनिधियों का अनुसरण करते हैं जो अंग्रेजी राज को आवश्यक बनाकर, अंग्रेजी को न्यायकर्ता बनाकर पराधीनता के बंधनों को दृढ़ करते रहे थे। भारतीय जनता की राष्ट्रीय भावना इन भारतवासियों के अंग्रेजी-प्रेम पर अवश्य विजय पायेगी।

## बहुजातीय राष्ट्रीयता और राष्ट्रभाषा हिन्दी

विश्वविद्यालयों की शिक्षा और राष्ट्रीय एकता के सम्बन्ध में भाषण करते हुए समाचारपत्रों के अनुसार दिल्ली में श्री हुमायूँ कबीर ने कहा कि हिन्दी-भाषी लोग जब हिन्दी को राजभाषा बनाने पर जोर देते हैं, तब कम-से-कम अंशतः उनके मन में यह कामना रहती है कि वे सार्वजनिक जीवन और नौकरियों के मामले में अहिन्दी-भाषियों के मुकाबले में फायदे में रहेंगे।

देश ने अब इतनी प्रगति कर ली है कि कोई भी माँग जातीय स्वार्थ से परे नहीं समझी जा सकती ! हिन्दी-भाषी जनता हिन्दी के राजभाषा बनाने की माँग करती है तो यह भी नौकरियाँ पाने के लिए ! अहिन्दी क्षेत्रों में हिन्दों के एक प्रचारक महात्मा गांधी भी थे। पता नहीं, नौकरी पाने की किस छिपी हुई कामना से उन्होंने हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए प्रचार किया था !

श्री कबीर ने कहा कि देश की सभी मुख्य भाषाओं को समानता का दर्जा मिले तो परस्पर शंका और संघर्ष की भावना दूर हो जाय। यह बहुत नेक सलाह है और हम उसका समर्थन करते हैं। किन्तु विभिन्न भाषाओं के बोलनेवालों में जो संघर्ष और मतभेद दिखाई देता है, उसका कारण भाषा ही नहीं है, हिन्दी भाषा तो और भी नहीं। पिछले दिनों आंध्र प्रदेश में जातीय एकीकरण के लिए प्रबल आन्दोलन उठा। इसका कारण भाषा न थी; हिन्दी भाषा और भी नहीं। बम्बई को लेकर गुजरात-महाराष्ट्र में, अलग राज्य (अथवा प्रान्त) बनाने की माँग को लेकर केन्द्रीय सत्ता और इन प्रदेशों की जनता में जो तनातनी अभी तक बनी हुई है, उसका कारण हिन्दी नहीं है। इस तरह के और बहुत-से झगड़े हैं जिनका सम्बन्ध जातीय प्रदेशों के एकीकरण, सीमा-निर्धारण, उद्योगीकरण आदि से है। इन सारे मतभेदों को भाषा-सम्बन्धी विवाद के खाते में नहीं डाला जा सकता। इनसे स्पष्ट है कि देश में राष्ट्रीय एकता को कमजोर करनेवाले जातीय भेद के जो चक्र चल रहे हैं, उनसे हिन्दी का बहुत कम सम्बन्ध है। राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा हिन्दी से नहीं है वरन् इस जातीय विद्वेष और अलगाव की भावना से है। तमिलनाडु में तमिल राजभाषा है किन्तु वहाँ का एक दल इस प्रदेश को भारत से अलग करने की माँग करता है। उत्तर में कश्मीर और दक्षिण में तमिलनाडु—इन दो प्रदेशों में कुछ दलों का

भारत में जनजातों के नाते लगाना परिस्थिति की गम्भीरता की सूचना देता है।  
 स्पष्ट बात सही है कि एक भाषा जनजातों में किसी भाषा को विशेषाधिकार न मिलने चाहिए। किन्तु यह बात सही नहीं है कि हिन्दी को राजभाषा बनाने के विरोधी अंग्रेजी के विशेषाधिकारों के बारे में चुप रहें, उन्हें मिर मुजावर स्वीकार कर लें, अंग्रेजी को अन्तराष्ट्रीय और विश्व भाषा कहकर उन विशेषाधिकारों की रक्षा करें, इसमें उनके जनवादी अन्तःकरण को उरा भी काट न दें। किन्तु हिन्दी के विशेषाधिकार प्राप्त करने की सम्भावना मात्र में वे आसमान मिर पर उड़ा लें। यह मनोवृत्ति मुस्लिम लीग के उन नेताओं की याद दिलाती है जो बहुसंख्यक हिन्दुओं के शासन भय से अंग्रेजी राज की शरण लेते थे।

भारत एक बहुजातीय राष्ट्र है। राष्ट्रीयता और बहुजातीयता—इन दो पक्षों में एक का नौ बुलाना घातक हाथ। आसोग राष्ट्र का यह अर्थ लगाने हैं कि उसमें एक ही भाषा बोलनेवाले रहते हों, वे भारतीय राष्ट्रीयता के विकास का आर्थों से ओझल कर देते हैं। गतागिन्या में यहाँ विभिन्न भाषाएँ बोलनेवाले लोग रहते आये हैं। आज यह तथ्य आर भी स्पष्ट है—प्राचीन जनों की समस्याओं की तरह अस्पष्ट और विषादास्पद नहीं वर्तमान के उन्नत सत्य के समान असंदिग्ध है। इन जातियों की सीमाएँ खोई कोई मिटाना भी चाहता वह सपना न होगा। उनकी समानता, भाईचारे, परस्पर सहयोग और एकता के बंध पर ही राष्ट्रीय एकता दृढ़ हो सकती है।

मात्र ही भारत देश एक राष्ट्र है, 'मित्र-काटीनन्ट' (उप-महाद्वीप) नहीं है। यहाँ नावियत देश की तरह मजदूर वर्ग द्वारा भत्ता प्राप्त करने के बाद विभिन्न जातियों द्वारा स्वच्छा में मध्य बनाने का प्रयत्न नहीं उठता। भारत विभिन्न जातियों द्वारा निर्मित सभ्यता है वह ऐतिहासिक विकासक्रम में समष्टि एक राष्ट्र है। भारतीय जनता में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास विश्व इतिहास की अमूल्य घटना है। समाजवादी सत्ता कायम होने में पहले इन तरह की बहुजातीय राष्ट्रीयता का विकास किसी देश में नहीं देखा गया। चीन में गैर-चीनी जातियों की स्थिति हमारे यहाँ के बोल भीलों की दशा से मिलती-जुलती थी। वहाँ उस तरह की बहुसंख्यक और विकसित गैर-चीनी जातियाँ नहीं रहीं जैसी भारत में गैर हिन्दी जातियाँ हैं। यूरोप के पूँजीवादी देशों में जो बहुजातीय राष्ट्र कायम किये उनमें शासक जाति में भिन्न सभी जातियाँ दामा की स्थिति में होती थी।

भारतीय राष्ट्र की एकता की भावना अंग्रेजों की देन नहीं है, वह अंग्रेजों के आने में बहुत पहले की है। यह धार्मिक भावना मात्र नहीं है क्योंकि इसका सम्बन्ध एक ही धर्म में नहीं रहा। धार्मिक सहनशीलता और उदारता के कारण यहाँ प्राचीन काल से अनेक धर्म—अनीश्वरवादी धर्म तक—पुलकित होते रहे किन्तु यह देश भीड़ों, जना या हिन्दुओं का राष्ट्र नहीं माना गया। यह एकता केवल भौगोलिक नहीं है। यहाँ के राज्यों की, विशेषकर उत्तर भारत के राज्यों की सीमाएँ देश से बाहर उत्तर-पश्चिम में दूर तक फैली रहीं हैं। यदि भौगोलिक एकता निरामक कारण होनी तो भारत-विभाजन की नीव

न आती। भौगोलिक और धार्मिक कारण भी रहे हैं किन्तु मुख्य कारण है यहाँ की जातियों का सामान्य इतिहास, उनकी सांस्कृतिक समानताएँ, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में उनका परस्पर सम्बद्ध और मिला-जुला विकास। इस ऐतिहासिक आधार पर ही यहाँ की राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ है।

मार्क्सवाद ने जातियों के विकास पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया है। लेनिन और स्तालिन के अनुसार जातियाँ पूँजीवाद के अभ्युदय-काल की देन हैं। किन्तु मार्क्सवाद की किसी पुस्तक में भारत-जैसी बहुजातीय राष्ट्रीयता के विकास की व्याख्या नहीं मिलती। कुछ लोग यांत्रिक ढंग से यहाँ की परिस्थितियों पर मार्क्सवाद लागू करते हुए इस परिणाम पर पहुँचे थे कि यहाँ हर जाति अपनी सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न विधान सभा बनाये, फिर ये विधान सभाएँ यहाँ अपना संघ निर्मित करे। इस तरह के विचारकों के अनुसार सन् सत्तावन की राज्यक्रान्ति में राष्ट्रीय चेतना का अभाव था; कारण यह कि राष्ट्रीयता का आधार रेल-तार थे जिनका पूरी तरह चलन न हुआ था! भारतीय इतिहास की वास्तविकता पर ध्यान दिए बिना यह कभी सम्भव में न आयेगा कि माधवजी सिन्धिया ने पेशवा को मुगल बादशाह का नायब क्यों घोषित किया, १८५७-५८ में देश के विशाल भाग की जनता शाही झण्डे के नीचे क्यों लड़ी, भाँसी में 'मुल्क बादशाह का, अमल रानी लक्ष्मीबाई का' की डुंगी क्यों पीटी गई। सी०एफ० ऐण्ड्सूज जैसे विदेशी लेखकों ने ज्यादा सचाई से लिखा था कि अंग्रेजों के आने के बाद राष्ट्रीय चेतना दृढ़ भले हुई हो, वह विद्यमान पहले से थी।

वर्तमान काल में जातियों की एकता और समानता की जो समस्या हमारे सामने है, उसका घनिष्ठ सम्बन्ध इस राष्ट्रीय चेतना के ऐतिहासिक विकास से है। हम जातीय समस्या और भाषा की समस्या को अपना इतिहास भुलाकर हल करेंगे या उसे राष्ट्रीयता के सन्दर्भ में हल करेंगे? राष्ट्रीयता के सन्दर्भ को भुलाकर जब हम उसे हल करते हैं, तब सीमान्त पर साम्राज्यवादी अड़डे कायम होते हैं। दस साल में एक बार भी आम चुनाव नहीं होता, जनतन्त्र के बदले धर्म-विशेष का राज्य कायम किया जाता है। लाखों की तादाद में नर-नारी वेधर-वार होकर खुद तबाह होते हैं और देश के अर्थतन्त्र को सकट में डाल देते हैं। यह जातीय अलगाव बहुत जल्दी साम्राज्यवादी पड़्यन्त्र का अंग बन जाता है। जिन उपनिवेशों पर साम्राज्यवाद ने शासन किया है, उन्हें वह स्वाधीन नहीं देखना चाहता। एक साम्राज्यवादी ताकत गई तो दूसरी उसे हड़पने को तैयार रहती है। अलगाव का नारा राष्ट्रीय एकता को कमजोर करनेवाला और साम्राज्यवाद तथा युद्ध की ताकतों को सहजोर करनेवाला है।

इसलिए जातीय समस्या और भाषाओं के समान अधिकारों की समस्या राष्ट्रीय एकता के सन्दर्भ में हल करनी होगी।

भारत में प्रत्येक भाषा को अपने क्षेत्र में राजकीय और सांस्कृतिक कार्यों में पूर्ण अधिकार प्राप्त होने चाहिए। साधारण हिन्दी जनता, हिन्दी का शिक्षित वर्ग और लेखक

एक स्थिति के पक्ष में हैं। हिन्दी-भाषी में यह बार-बार कहा गया है कि हिन्दी किसी भाषा के अधिकार नहीं छीनना चाहती, अहिन्दी भाषी आन्दोलनों के परम्परा व्यवहार के विना अंग्रेजी की जगह हिन्दी होनी चाहिए।

कई रचनात्मकता में देश की विविध परिस्थितियों के कारण हिन्दी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार की भाषा बनती रही है। उत्तर भारत में केन्द्रबद्ध मुगल शासन का होना, यहाँ आगरा जैसे व्यापार के बड़े-बड़े केन्द्रों का निर्माण, उन्नीसवीं सदी से पूर्व ही यहाँ के लोगों का विभिन्न प्रदेशों में फैलना ऐसे ही कारण थे। अंग्रेज व्यापारी भी उस समय अपनी सुविधा के लिए हिन्दी सीखते थे। वर्तमान काल में दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, सर्वत्र ऐसे व्यापारी और पूँजीपति मिलेंगे जिनकी सांस्कृतिक भाषा हिन्दी है। हिन्दी के प्रसार का एक बहुत बड़ा कारण बलकला-बम्बई जैसे केन्द्रों में सान्नों 'हिन्दुस्तानी' मजदूरों का विकास है। इन बड़े-बड़े नगरों के अतिरिक्त प्रत्येक आन्तरीय प्रदेश में अल्पसंख्यकों के रूप में हिन्दुस्तानी मिलेंगे। विभाज्य आगरा में हैदराबाद और उनके आस-पास हिन्दुस्तानियों का भारी जमावट है। अहिन्दी प्रदेशों में हिन्दी-भाषियों के इन प्रकार से हिन्दी की अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार की भाषा बनाने में सुविधा मिलती है।

इसके अतिरिक्त गीतानन्द रेडियो और विविध भाषाओं (और पाकिस्तान रेडियो भी) की कृपा से फ़िल्मी मशीन द्वारा देश के चारों कोना तक रोज़ ग़ाम-सबरे हिन्दी ग़ज़नी रहती है। कभी इन फ़िल्मी गानों की प्रशंसा करनेवालों के नाम सुनिए। जितने हिन्दी-भाषी प्रयोग के होते हैं, उतने ही अहिन्दी-भाषी प्रदेशों के। स्वयं गायक और गायिकाओं में एक अच्छी संख्या अहिन्दी ब्राह्मणों की रहती है। विज्ञान हिन्दी-भाषी प्रदेश फ़िल्मों के लिए सबसे अच्छा बाजार है। ये व्यावसायिक परिस्थितियाँ बहुतों के न चाहने पर—और शायद उनके न जानने पर भी—हिन्दी को राष्ट्रभाषा बना रही हैं।

इनके विवाध हिन्दी भाषा विधि और साहित्य की कुछ विवेचनाएँ हैं जो इस काम में सहायता करती हैं। हम यहाँ उनका उल्लेख नहीं करते।

हिन्दी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार की भाषा बन रही है, जनसाधारण के लिए अभी भी वह ऐसी भाषा है। वह केन्द्रीय राजकाज की भाषा भी जल्दी बन सकती है। इसमें एक बाधा है हिन्दी भाषियों का असंगठन, उनमें जातीय चेतना की कमी। हिन्दी भाषी प्रदेशों के राज्यों में भी हिन्दी अभी पूरी तरह राजकाज की भाषा नहीं बननी है। दक्षिण के लोगों की यह आपत्ति अनुचित नहीं है कि पहले अपने घर में हिन्दी को राजभाषा बना लो, फिर उसे ग़ार देश की राष्ट्रभाषा बनाना। यदि हिन्दी भाषी जनता संगठित हो, यदि वह अपने प्रदेश में हिन्दी का पूर्ण रूप में राजकाज की भाषा बनाये तो यह अग्रगण्य है कि यह विभाज्य प्रदेश और उनकी बहुसंख्यक जनता सागरे देश को अपने साथ खींचकर न ले पा सके।

✓ इस दृष्टि से भारतीय एकता के लिए हिन्दी-भाषी जनता की एकता आवश्यक है। देश की भाषागत समस्याएँ सुलझाने के लिए हिन्दी भाषा के लेखकों का संगठन आवश्यक है। हिन्दी को केन्द्रीय राजकाज की भाषा बनाने के लिए उसे अपने प्रदेश में पूर्ण रूप से शासन और संस्कृति की भाषा बनाना आवश्यक है। हिन्दी-भाषी जनता और उसके लेखक अपना यह उत्तरदायित्व दूसरों पर नहीं डाल सकते। ✓ (१९५८)



## हिन्दी की व्याकरण-सम्बन्धी कठिनाइयाँ

हिन्दी की व्याकरण-सम्बन्धी कठिनाइयाँ में कुछ अंग्रेजी-प्रेमी भारतवासी इतने परधान हैं कि वे कभी-कभी उसके कल्पना-बम्बई जैसे नगरों में कुछ अहिन्दी भाषियों द्वारा व्यवहृत रूप को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने की बात करते हैं। इनमें राजनीतिक नेताओं के अलावा कुछ प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक भी हैं जिन्होंने यथेष्ट सम्भारता से यह प्रस्ताव रखा है। अंग्रेजी के सम्पर्क में आनेवाले हिन्दुस्तानी खानसामा भी अंग्रेजी का एक सरल रूप काम में लाते थे जो साहब और उनके बीच की सांस्कृतिक आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए पर्याप्त होता था। कुछ देशों के कुलियो आदि ने इसी तरह अंग्रेजी को सरल करके अपना काम निकाला है। लेकिन इस देश में न तो हिन्दी भाषी जनता अंग्रेज साहबों की स्थिति में है, न अहिन्दी भाषी जनता कुलियो और खानसामाओं की। इस कारण जो लोग हिन्दी के तथाकथित सरल व्याकरण विहीन रूप को अपनाने की बात करते हैं, वे अपने और हिन्दी भाषियों के प्रति अय्याय हो करत हैं। कहना न होगा कि खानसामा अंग्रेजी को भारत की त्रिगुणा-माझ्या या विश्वभाषा बनाने की बात नहीं की जाती। इसके विपरीत इस कोटि के राष्ट्रभाषा प्रेमी अंग्रेजी शिक्षा का स्तर गिरने से नितान्त व्यथित रहते हैं और आए दिन इस स्तर को उठाने के लिए नये-नये उपाय भी सुझाया करते हैं। यह बात भी कम मनोरञ्जक नहीं है कि एक ओर वे हिन्दी के दरिद्र होने की, उसमें उच्च कोटि के साहित्य के अभाव की घोषणा करते हैं, दूसरी ओर व्याकरण की कठिनाइयाँ से मुक्त हिन्दुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाने का 'जनताधिक' सुझाव भी देते हैं।

अंग्रेजी भाषा में व्याकरण-सम्बन्धी कठिनाइयाँ कम नहीं हैं। डेढ़ सौ साल से लगातार अंग्रेजी पढ़ने के बाद भी इस भाषा को सीखने का स्तर जो गिरता नज़र आ रहा है, उसका कारण विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिभा के अलावा उस भाषा की खूबियाँ भी हैं। किन्तु अंग्रेजी प्रेमी देशभक्त अपनी प्रिय भाषा की व्याकरणगत कठिनाइयों से जरा भी विचलित नहीं होते, उन्हें शिकायत है हिन्दी की कठिनाइयों से। इनमें भी सारे फगाद की जड़ उनकी समझ में हिन्दी का लिए भेद है।

हिन्दी शब्दों को लिए-सम्बन्धी कठिनाई वास्तविक है। यह कठिनाई अहिन्दी-भाषियों के लिए ही नहीं है, भागपुरी आदि पूर्वी बोलियों के क्षेत्रों में हिन्दी बोलनेवाला

के लिए भी यह कठिनाई विद्यमान है। इतिहासकारों का कहना है कि एक बार दिल्ली के कलेआम में 'खारा पानी' कहनेवालों को पछाँह का सभ्रम कर छोड़ दिया गया; 'खारी पानी' कहनेवालों को पूरव का मानकर उन्हें तलवार के घाट उतार दिया गया। इस कठिनाई से ऐसे नतीजे भी निकल सकते हैं !

भाषा का निर्माण किसी अकादमी में नहीं होता, न उसका व्याकरण बनाने का काम राजनीति-विशारद करते हैं, बरना यह कठिनाई दूर हो जाती। संस्कृत के महान् वैयाकरण भी, जो भाषा को व्यवस्थित करने में अपना सानी नहीं रखते, इस कठिनाई से पार न पा सके। शत्रु पुल्लिङ्ग, मित्र नपुंसक लिङ्ग ! वृक्ष जैसा जड़ पदार्थ पुल्लिङ्ग, हृदय जैसा तरल और गतिशील पदार्थ नपुंसक लिङ्ग ! पांशु (धूल), परशु, इषु (वाण) जैसे निर्जीव पदार्थ पुल्लिङ्ग हैं; शरीर और शीर्ष जैसे सजीव पदार्थ नपुंसक लिङ्ग हैं।

इस देश के सांस्कृतिक इतिहास में संस्कृत का जो महत्त्व रहा है, उसे सभी लोग जानते हैं। भारत की भाषाओं पर उसका जो व्यापक प्रभाव पड़ा है, वह भी किसी से छिपा नहीं है। संस्कृत शब्दों की लिङ्ग-सम्बन्धी कठिनाई से उसके प्रसार में कोई बाधा नहीं पड़ी। सम्भव है, कुछ सज्जन कहे कि इस कठिनाई के कारण ही वह मृतभाषा हुई। यदि ऐसा होता तो संस्कृत-भाषी प्रदेश की भाषाएँ—जिनमें हिन्दी सर्वोपरि है—इस कठिनाई से मुक्त होतीं।

संस्कृत के समान यूरोप की भाषाओं और संस्कृति पर प्राचीन यूनान की भाषा—वहाँ अनेक भाषाएँ थी, हमारा तात्पर्य एथेन्स की भाषा से है—का प्रभाव पड़ा। किसी समय वह भूमध्य सागर के तट पर फैले हुए अनेक यूनानी उपनिवेशों के कारण एक विशाल भूभाग में फैल गई थी। इस भाषा में अस्तु और अफलातून जैसे विचारकों ने, सोक्रोक्लीज, यूरिपिदीज जैसे नाटककारों ने, हेराक्लितस जैसे दार्शनिकों ने अपनी रचनाएँ कीं जिनके आधार पर यूरोप की संस्कृति का प्रासाद निमित्त हुआ। इस भाषा में गेनीस (संस्कृत जन) नपुंसक है किन्तु दिमीस (जनता) पुल्लिङ्ग है ! धूरा (द्वार), माखइरा (तलवार), अकन्या (काँटा) जैसी वोजान चीजें स्त्रीलिङ्ग हैं। यदि आप कहें ये आकारान्त हैं, इसलिए स्त्रीलिङ्ग हैं, तो देखिए म्नीमा (समाधि), ओइको-दोइमा (भवन) आदि नपुंसक लिङ्ग हैं। नेत्रीस (शव) तो पुल्लिङ्ग है, पाइदिओन (शिशु) नपुंसक लिङ्ग है !

प्राचीन यूनानी के समान और भी बड़े पैमाने पर लैटिन व्यवहार में आई। वह शताब्दियों तक इटली ही नहीं, यूरोप की धार्मिक और सांस्कृतिक भाषा रही। इसमें भी यूनानी भाषा की तरह लिङ्गभेद वर्तमान था। अग्नि के लिए दो शब्द हैं, 'इन्केण्डियम' और 'इग्निस'; पहला नपुंसक, दूसरा पुल्लिङ्ग है। जनता के लिए दो शब्द हैं, गेन्स (जन) और पोपूलस; पहला स्त्रीलिङ्ग है, दूसरा पुल्लिङ्ग। इम्पेर (वर्षा), टूरिस (मीनार), मारे (समुद्र) तीनों को स्वभावतः नपुंसक लिङ्ग होना चाहिए किन्तु ये क्रमशः पुल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग और नपुंसक लिङ्ग हैं। अकीला (वाज) और अग्रिकोला (कृषक) देखने में एक-से आकारान्त शब्द हैं किन्तु पहला स्त्रीलिङ्ग है, दूसरा पुल्लिङ्ग

लैटिन की उत्तराधिकारिणी भाषाओं में फ्रांसीसी भाषा भी है। वह यूरोप में अन्तर्जातीय व्यवहार की भाषा रही है। उसमें घर के लिए दो शब्द हैं, मँडों, बानीमों, पहना स्त्रीलिंग है दूसरा पुल्लिंग। इसी प्रकार घरों के लिए तैपर और गेपी, भाग के लिए बत और गमी आदि में पहना स्त्रीलिंग है, दूसरा पुल्लिंग। प्रसूतीघोस्योम सबत जैंगी विशाल परतु (मानाजा) का स्त्रीलिंग विभाजित करते हैं, गुनक जैंगी छोटी चीख (चौत्र) का पुल्लिंग।

यूरोप का एक विशाल प्रदेश में व्यवहृत फ्रांसीसी की तरह एक हद तक अन्तर्जातीय व्यवहार की भाषा जर्मन है। उसमें सम्स्कृत के समान ही लिंगभेद है। परधर (स्टादन), वृष (वाउम), जूता (गु) जैसे निर्जैव पदार्थ पुल्लिंग हैं, जन्ता (पोन्व), मारी (इनके लिए एक शब्द स्टादप भी है), लडकी (मंडेसन) आदि मजीव वस्तुएँ नपुंसक लिंग हैं। सम्स्कृत के समान जर्मन में तीनों लिंग विद्यमान हैं और शब्द के अर्थ या रूप से उन्हें पहचानना आसान नहीं है।

समाद के बड़े भाग में पड़े हुए मोविषन सप की अन्तर्जातीय व्यवहार की भाषा रूसी है। इसमें भी सम्स्कृत और जर्मन की तरह तीनों ही लिंग हैं। अधिकतर निर्जैव पदार्थ नपुंसक लिंग होते हैं किन्तु पुस्तक (बनीगा), होठन (गस्तीगिस्ता), पुस्तकालय (विनियोतका) आदि शब्द स्त्रीलिंग हैं। यद्यपि शब्दों के रूप से उनका लिंग पहचाना जा सकता है, फिर भी इन विषय में निश्चय के अनेक अपवाद हैं।

प्राचीन काल से आज तक सत्तार की अनेक और प्रमुख भाषाएँ शाब्द में लिंगभेद करती रही हैं। यह भेद वास्तविक न होकर—शब्दों द्वारा विज्ञापित वस्तु के लिंग का अनुसरण न करके—बहुधा शब्दों के रूप के अनुसार होता है। शब्दों का रूप देखकर उनका लिंग निश्चित करना मंदा सरल नहीं होता। इस सम्बन्ध में कुछ मोटे नियमों का पालन किया जाता है किन्तु उनमें अपवादों की संख्या कम नहीं है। भाषा सत्तार के पदार्थों, मनुष्य के व्यवहार और चिन्तन की अभिव्यक्ति के लिए ही विकसित हुई है। वह इस भौतिक जगत् और मनुष्य के भौतिक जीवन में विलग होकर विकसित नहीं हुई। उसकी जड़ें इसी भौतिक जीवन और जगत् में हैं। किन्तु भाषा भौतिक जगत् से मनुष्य का सम्बन्ध विज्ञापित करने का साधन ही नहीं है। जैसे समीत में विभिन्न प्रदेशों की जातियों का स्वरा का विशेष गामजस्य, उनका विशेष आरोह-अवरोह पसन्द आता है, वैसे ही भाषा के क्षेत्र में विभिन्न जातियाँ शब्दों के साथ विशिष्ट रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करती हैं। एक ही वस्तु के लिए विभिन्न भाषाओं के पर्यायवाची शब्दों में लिंग-सम्बन्धी अन्तर होता है। एक ही भाषा में किसी वस्तु के लिए भिन्न लिंग वाले पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग देना जा सकता है। दूसरों के लिए इस वैचित्र्य के कारण भाषा कठिन हो जाती है किन्तु उससे बालनेवालों के लिए इस वैचित्र्य का रागात्मक मूल्य है। भाषा के समस्त ऐतिहासिक विकास के फलस्वरूप यह विभिन्नता उत्पन्न होती है। वह भाषा की मजीव परम्परा का अंग होती है। उसे समाप्त करना वैसे ही अगम्य है जैसे

मुहावरों को समाप्त करना। मुहावरों की तरह लिंग-भेद सीखना होता है। अन्तर्जातीय व्यवहार की कठिनाइयाँ दूर करने के लिए भाषा के रूप को न तो आज तक कहीं बदला गया है, न अब बदला जा सकता है। अन्य भाषाओं और जातियों के सम्पर्क में आने से भाषा में परिवर्तन होते हैं। किन्तु इन परिवर्तनों का सम्बन्ध व्याकरण में सबसे कम होता है। अंग्रेजों ने संसार की अनेक भाषाओं से शब्द लिये हैं—चास्त्व में जर्मन या रूसी की तुलना में उसकी अपनी पूंजी नगण्य है—किन्तु उसके व्याकरण में कितना परिवर्तन हुआ है? उसने शब्द दूसरों से लिए किन्तु व्याकरण के रूप अपने रखे। उसका शब्द-भण्डार जितना मिश्रित है, उसका व्याकरण उतना ही अपेक्षाकृत विशुद्ध।

खड़ी बोली ने अरबी-फारसी से मँकड़ों शब्द लिये, उसका उर्दू रूप विकसित हुआ। कुछ विद्वानों का विचार है कि बाहर से आनेवाले मुसलमान यहाँ की भाषा समझते न थे, उनकी अपनी भाषाओं और यहाँ की बोलियों—अथवा खड़ी बोली और फारसी—के मिश्रण से फीजी रोमों और बाजारों में उर्दू का जन्म हुआ। बाहर से आनेवाले मुसलमानों की भाषा क्या थी, एक थी या एक से अधिक थी; बंगाल, कश्मीर, पंजाब, केरल आदि प्रदेशों में मुसलमान वहाँ की भाषा कैसे समझने लगे, इन प्रश्नों का विवेचन न करके हम केवल इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करेंगे कि उर्दू को जन्म देनेवाले मुसलमानों को यहाँ का शब्द-भण्डार स्वीकार करने में चाहे जो कठिनाई हुई हो, खड़ी बोली के व्याकरण-रूपों को उन्होंने सप्रेम स्वीकार कर लिया। इन रूपों में लिंग-भेद भी है। ऐसा नहीं हुआ कि लिंग-सम्बन्धी कठिनाई दूर करके बाहर से आनेवाले मुसलमानों ने खड़ी बोली को अपनाया हो। उन्होंने यहाँ की व्याकरण-परम्परा को—जिसे सीखना शब्दों को ग्रहण करने से ज्यादा कठिन था—स्वीकार किया। भारत की अनेक भाषाएँ—जैसे बँगला—शब्द-भण्डार की दृष्टि से हिन्दी के जितना निकट है, उतना उर्दू नहीं है। यदि बाहर से आनेवाले मुसलमान यहाँ के लिंग-सम्बन्धी भेद सीख सकते थे तो शब्द-भण्डार की इतनी समानता रहने पर बंगाली मित्र उनसे क्यों पार नहीं पा सकते? इस कारण 'भारतीय आर्यभाषा और हिन्दी' में डॉ० सुनीतिकुमार चाटुर्ज्य द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित सुझाव अभी तक अग्राह्य रहा है: 'परन्तु यदि ये व्याकरण-विषयक विनिष्टताएँ, जो वाकी के भारतवासियों के लिए वास्तविक कठिनाइयाँ बन रही हैं, कम कर दी जायँ, जैसा कि पूर्वी हिन्दीवालों तथा बिहारियों ने किया है (?!), तो संस्कृतनिष्ठ प्रचलित हिन्दुस्थानी, एक अत्यन्त सहज, सुबोध तथा ओजपूर्ण भाषा बन जाती है। इस सहज बनी हुई हिन्दुस्थानी का सारा व्याकरण एक पोस्टकार्ड पर लिखा जा सकता है। 'वाज़ारू हिन्दुस्थानी' के सदृश सुगठित तथा ओजपूर्ण भाषा को हाट-वाज़ार से, जहाँ पर कि उसका स्वतन्त्र, अनवरुद्ध जीवन-प्रवाह पंडितों की धृणा की परवाह न करते हुए अनवरत रूप से बहा चला जा रहा है, उठाने की आवश्यकता है। हमें उसे आदरपूर्ण आन्तर्जातिक या आन्तर्देशिक भाषा के इतने उच्च स्तर तक उठाना होगा कि वह कम-से-कम सार्वजनिक सभा-सम्मेलनों आदि में प्रयुक्त होने योग्य बन

जाय। इसमें साहित्य का सूक्ष्म ब्यापन हो सकता है—आगे चलकर होगा ही (१)। परन्तु वह गहरी अविवेक की बात है। अभी हमें के लिए इसे एक द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है, जिसमें सबभाषाधारण को परिचित हो जाने के लिए कहा जा सकता है। यह उम्मीद फारसी-युक्त उर्दू तथा नागरी-हिन्दी के साथ-साथ प्रयुक्त होती रहेगी, जैसे आज होती है।"

अस्तु परिणाम यह निकला कि हिन्दी की विषम-सम्बन्धी कठिनाइयाँ दूर करने उसे सरल नहीं बनाया जा सकता। जिस तरह खानसामा-अंग्रेजी को राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिला, उसी तरह अहिन्दी-भाषी प्रदेशों में कुछ लोग द्वारा व्यवहृत हिन्दी के टट-फट रूप का देश के राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवहार की भाषा नहीं बनाया जा सकता। यह सही है कि हिन्दी-भाषियों को दूसरा की श्रुतियों पर हँसना न चाहिए, वरन् भाषा-सम्बन्धी अपने प्रयागों के प्रति उन्हें अधिक संवेत होना चाहिए। साथ ही यह भी सही है कि कुछ अहिन्दी भाषी मित्र हिन्दी की व्याकरण-सम्बन्धी कठिनाइयाँ को दुर्लक्ष्य बतलाकर, उन्हें दूर करके भाषा को सरल करने का सुझाव देकर अन्तर्जातीय व्यवहार की भाषा-समस्या हल नहीं कर सकते। धैर्य, उदारता और परिश्रम से ही इस कठिनाई पर विजय प्राप्त हो सकती है।

(१६५८)

## उर्दू की समस्या

प्रधानमंत्री श्रीजवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस की कार्यकारिणी तथा अन्य राजनीतिक संस्थाओं ने पिछले दिनों उर्दू के संरक्षण की समस्या की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया है। उनके वक्तव्यों का यह मूल्य है कि उन्होंने एक महत्त्वपूर्ण समस्या पर ध्यान केन्द्रित किया है जिसके प्रति साधारणतः हिन्दी-भाषी जनता उदासीन हो गई थी। इससे सिद्ध यह होता है कि भारत के साम्राज्यवादी विभाजन से जो अनेक समस्याएँ नहीं सुलझीं, उनमें उर्दू की भी एक समस्या है। दुर्भाग्य से इन वक्तव्यों में यह नहीं बतलाया गया कि उर्दू के अक्षय या दमन के लिए उत्तरदायी कौन है, विभाजन के बाद यह समस्या अब भी क्यों बनी हुई है, उर्दू के संरक्षण के लिए कौन से उपाय किये जानेवाले हैं, इत्यादि। संक्षेप में स्थिति यह है कि भावुकता के अलावा वैज्ञानिक स्तर पर इस समस्या पर इन वक्तव्यों में कुछ नहीं कहा गया।

एक समय था जब कांग्रेस का नेतृत्व हिन्दी-उर्दू को मूलतः एक भाषा मानता था, उनमें अनावश्यक संस्कृत और अरबी शब्द भरने का विरोधी था, हिन्दुओं और मुसलमानों की मिली-जुली भाषा को कौमी जवान कहता था और उसे राजभाषा बनाने पर जोर देता था। आज स्थिति बदल गई है। कौमी जवान की बात करना तो महापाप है; जो सबसे प्रगतिशील बात कही जा सकती है, वह यह कि उर्दू को दबाया न जाय। और कौमी जवान के राष्ट्रभाषा बनने का सवाल नहीं, शुद्ध राष्ट्रभाषा हिन्दी भी राजभाषा नहीं बन पाई; सारे देश में नहीं बन पाई, और अपनी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश—तथा अन्य हिन्दी-भाषी राज्यों—में भी वह राजभाषा नहीं बन पाई।

देश के राष्ट्रीय नेताओं ने साम्प्रदायिक समस्या को हल किया साम्प्रदायिक मांगों को स्वीकार करके। साम्प्रदायिकता के आधार पर किये हुए समझौते के वृक्ष में राष्ट्रीयता के फल न लगे तो इसमें आश्चर्य क्या? उर्दू का नाम सुनते ही बहुत से हिन्दी-प्रेमी स्वभावतः परेशान हो उठते हैं : आखिर इन्हीं समस्याओं को हल करने के लिए तो पाकिस्तान बना और यह उर्दू का बखेड़ा अब भी बना हुआ है !

उर्दू-प्रेमियों ने अलग परेशान होकर कौमी जवान को इलाकाई जवान बनाने के लिए दस्तखत इकट्ठे किये। उन्होंने उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में अंग्रेजी को हटाने के

लिए आन्दोलन करना जरूरी नहीं समझा। न उन्होंने इस आन्दोलन की नीति निर्धारित करने के लिए हिंदी प्रेमियों से सहाय-सपरिवार किया। इसलिए वैधानिकता का जमा पहनने पर भी यह एक मौमिन साम्प्रदायिक आन्दोलन ही रहा।

जब क सम्बन्ध में जनक मनन धारणाएँ हिंदी प्रेमियों और उर्दू प्रेमियों दोनों के मन में बनी हुई हैं। इन पर स नेप म रिचार करना आवश्यक है।

एक धारणा यह है कि मुसलमानों ने यहाँ आकर उर्दू नाम की एक नई भाषा को जन्म दिया। बहुत से मुसलमानों को उर्दू से एक प्रकार का धार्मिक प्रेम है, वे उसे अपने घम और विशेष सस्कृति की भाषा समझते हैं। बहुत से हिंदू इस धारणा को स्वीकार करते हैं। उनकी दृष्टि में मुसलमान कभी हिन्दुस्तानी नहीं बना, इसलिए उर्दू भी 'अरब जहादिया' का कीर्ति-स्तम्भ है। हिन्दुओं और मुसलमानों में जो चरम साम्प्रदायिकता-वादी हैं वे उसने प्रति एक-सा ही प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण अपनाते हैं। यही इन बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि जनेर साम्राज्यवादी भाषा-वैज्ञानिकों का भी यह मत रहा है कि उर्दू इस्लाम की भाषा है।

यदि उर्दू इस्लाम की भाषा है तो पूर्वी बंगाल के मुसलमान बंगला क्यों बोलते हैं? उन्होंने उर्दू के एकमात्र राजभाषा बनाय जाने के विरुद्ध संघर्ष क्यों किया? बंगाल के अनाया करल, तमिलनाडु महाराष्ट्र, गुजरात, कश्मीर आदि प्रदेशों के मुसलमान घर में उर्दू क्या नहीं बोलते? और हिन्दुस्तान-पाकिस्तान से बाहर तुर्की, ईरान, ईराक आदि राष्ट्रा में उर्दू क्या नहीं बोली जाती?

स्पष्ट है कि समाज में एक हिन्दुओं की भाषा, एक मुसलमानों की भाषा, एक बौद्धों या ईसाइयों की भाषा नहीं है। भाषाओं का निर्माण और विकास घर्म के आधार पर नहीं हुआ। धार्मिक विचारधाराओं के कारण उनके लिखने-बोलनेवालों ने उनमें कुछ नई विशेषताएँ पदा की हा, वह दूसरी बात है। भाषा का सम्बन्ध जातीयता से है, किसी जाति के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास से है। जाति और घर्म एक वस्तु नहीं हैं। ईरानी, ईराकी तुर्की जानिया इस्लाम घम मानती हैं किन्तु उनकी भाषाएँ अलग-अलग हैं। इसी प्रकार भारत की विभिन्न जातियों की अपनी-अपनी भाषाएँ हैं उन जातियों के प्रदेशों में हिन्दू मुसलमान दोनों ही उन भाषाओं को बोलते हैं, उनमें अपना और सब सांस्कृतिक काम-काज करते हैं। उर्दू का व्यवहार कहीं के मुसलमान करते हैं? सबने पहले हिंदी भाषी प्रदेश व उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मध्यप्रदेश आदि के। कारण यह कि उर्दू यदि वही की जातीय भाषा है तो हिंदी-भाषी प्रदेश की ही। इसके बाद कलकत्ता, हैदराबाद, बम्बई जैसे नगरों में मुसलमानों की वस्तियाँ हैं जो अपने मूल प्रदेश से वहाँ पहुँचे हैं या जिनने पुरखे पहले कभी पहुँचे थे। इनके बाद कश्मीर आदि प्रदेशों के मुसलमान हैं जिनकी मातृभाषा कश्मीरी है या अन्य कोई भाषा है और जो उर्दू भी जानते हैं और उसे काम में लाते हैं।

घर्म के आधार पर उर्दू की रक्षा की बात करना या उसे इस्लाम की भाषा समझने

कर उसका नाश करने की बात सोचना एक अवैज्ञानिक और प्रतिक्रियावादी कार्य है।

उर्दू इस्लाम की भाषा है, इस धारणा से भिन्न एक दूसरी स्थापना है जो प्रगतिशील और राष्ट्रीय समझी जाती है। वह यह है कि उर्दू हिन्दुओं और मुसलमानों के मेल से बनी है। दूसरे शब्दों में उर्दू केवल इस्लाम की भाषा नहीं, वह इस्लाम और हिन्दू धर्म दोनों की भाषा है। यह स्थापना देखने में प्रगतिशील मालूम होती है क्योंकि वह राष्ट्रीयता के लिए आवश्यक हिन्दू-मुस्लिम-एकता की ओर सकेत करती है। इस स्थापना का सहारा लेकर ही अनेक राष्ट्रीय नेताओं और विचारकों ने भाषा-समस्या हल करने का प्रयत्न किया था और उसमें असफल भी हुए थे।

यदि हिन्दुओं और मुसलमानों के मिलने से उर्दू बनी होती तो बम्बई से कलकत्ता तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जातीय प्रदेश में उर्दू ही बोली जाती; बंगला, मराठी, कश्मीरी, मलयालम आदि भाषाओं का अस्तित्व ही न होता। उर्दू एक विशेष जातीय प्रदेश की भाषा है, भारत के सभी जातीय प्रदेशों की नहीं। उसे मातृभाषा के रूप में काम में लानेवाले वही लोग हैं जो हिन्दी-भाषी प्रदेश के निवासी हैं या यहाँ से जाकर दूसरे प्रदेशों में बस गए हैं। हिन्दी-उर्दू एक ही जातीय प्रदेश की भाषा हैं, इसीलिए उनका बोलचाल का रूप एक-सा है या प्रायः एक-सा है।

भारत में जो मुसलमान आये उनमें कोई पश्तो बोलता था, कोई तुर्की, कोई अरबी, कोई फारसी। उनकी भाषाएँ कम-से-कम तीन भिन्न परिवारों की हैं। तुर्की, अरबी, फारसी एक-दूसरे से भिन्न भाषा-परिवारों की हैं। यदि उर्दू का निर्माण हिन्दुओं-मुसलमानों के मिलने से होता तो उसमें तुर्की के उतने ही शब्द होते जितने फारसी के। या इस्लाम धर्म का सम्बन्ध विशेष रूप से अरबी से जोड़ा जाय तो उर्दू में तुर्की-फारसी का बहिष्कार और अरबी-संस्कृति का बराबर सम्मिश्रण होना चाहिए था। बाहर से आनेवाले मुसलमानों ने राजभाषा के लिए अरबी नहीं, फारसी को चुना। उनका धर्मग्रन्थ अरबी में है, फारसी में नहीं। फारसी पर अरबी का प्रभाव है, फिर भी वह मूलतः भारत-यूरोपीय परिवार की भाषा है और अरबी की अपेक्षा वह संस्कृत के अधिक निकट है। मुसलमान सामन्तों ने अरबी को राजभाषा क्यों न बनाया? इस पद के लिए उन्होंने फारसी को क्यों चुना? इसलिए कि वे सामन्त अनेक वर्वरताओं के बावजूद मुस्लिम लोग के नेताओं से अधिक उदार थे। फारसी को चुनने में धार्मिक नहीं, सांस्कृतिक कारण प्रधान थे। सांस्कृतिक दृष्टि से ईरान समृद्ध राष्ट्र था; मध्य एशिया और मध्यपूर्व के देशों पर ईरानी संस्कृति की छाप थी। बाहर से आनेवाले मुसलमान यह छाप अपने साथ लाए थे। मुगल सम्राटों के यहाँ दरबारियों में काफी ईरानी होते थे; फारसी बोलचाल की भाषा थी। इस कारण मुगल राज्यसत्ता में फारसी का बोलचाल रहा।

मुसलमान सामन्तों ने ब्रजभाषा में रचनाएँ कीं, अनेक सूफियो ने अवधी में काव्य लिखे, रसखान और रहीम जैसे कवियों ने ऐसी सरस कविताएँ लिखीं कि वे आज भी गाँवों में लोगों की जवान पर हैं। हिन्दीभाषी प्रदेश से बाहर कश्मीरी, पंजाबी, बंगला आदि



भाषाओं और उनके वाच्य साहित्य के उत्पादन और विभाग में मुसलमानों ने महत्वपूर्ण योग दिया। आजकल बहुत से हिन्दू मुसलमान इस बात को याद करता पसन्द नहीं करते। उनमें एक अनवादा परिणाम निकलता है कि मुगल साम्राज्य में फारसी के राजभाषा रहने हुए भी यहाँ की जातीय भाषाओं ने अभूतपूर्व उत्थान की और इस उत्थान में मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ था। हिन्दू साम्प्रदायिकों को यह निष्पत्ति पसन्द नहीं है क्योंकि उनके अनुसार मुसलमानों ने भारत का कभी अपना दश नहीं समझा, फिर वे यहाँ की भाषाओं और उनके साहित्य की उत्थान में काम कैसे दे सकते थे? मुस्लिम साम्प्रदायिकों को यह निष्कर्ष पसन्द नहीं क्योंकि ज्ञाताय भाषाओं के विकास के इस घोरुटे में उनकी उद्गमस्थली धारणाएँ फिट नहीं होती।

तब उद्ग का विकास क्या साम्प्रदायिक कारणों से हुआ? या उद्ग हमारी जातीय भाषा थी और उसका मुकामल में हिन्दी का विकास साम्प्रदायिक कारणों से हुआ?

उद्ग का बोलचाल वाला रूप वही है या प्रायः वही है जो हिन्दी का। इस रूप का एक नाम खड़ी बोली है। इस बोलनेवाले हिन्दू, मुसलमान, जैन, बौद्ध, ईसाई अनेक धर्मों के लोग हैं। इस रूप को न तो मुसलमानों ने जन्म दिया, न उसे अवध और बिहार में पंजाब में एकमात्र उद्गाने भाषा बनाया। फारसी के राजभाषा रहने के कारण इस खड़ी बोली में फारसी के संकट शब्द आय। फारसी के माध्यम में संकटों अरबी शब्द भी खड़ी बोली में आय। उद्ग का समयका कहना है कि उद्ग को संवारन और मिलाने वाले हिन्दू भी थे। यह बात सही है। इन मिलावों को इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए कि उद्ग को संवारन में हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों ने हिस्सा लिया, फिर भी खड़ी बोली का एक दूसरा रूप हिन्दी क्यों विकसित हुआ? प्रेमचन्द जैसे देशभक्त उद्ग-प्रेमी लेखकों ने हिन्दी-नेवा क्या की?

बहुत से उद्ग-प्रेमियों को यह धारणा है कि एक अच्छी-भासी मुसलमान जवान बन गई थी, हिन्दीवालों ने एक साम्प्रदायिक आन्दोलन चलाया और अरबी-फारसी के शब्दों को जगह सहृदय के भारी भरकम शब्द रखकर एक नकली जवान गढ़ ली। उसी साम्प्रदायिक भाषा को अब लोग राष्ट्रभाषा कहने लगे हैं। हिन्दुओं की साम्प्रदायिकता और विश्वासघात के कारण उद्ग का गला घोंटा जा रहा है।

ये मित्र दो-तीन बातें भूल जाते हैं। खड़ी बोली में अरबी-फारसी के शब्दों की आमद हिन्दुओं और मुसलमानों के मिलन का परिणाम नहीं है बल्कि यहाँ फारसी के राजभाषा बनाये जाने का परिणाम है। फारसी यहाँ के किसी प्रदेश की भाषा नहीं थी, न वह बाहर से आनेवाले सभी मुसलमानों की भाषा थी, न वह भारत के हिन्दुओं और मुसलमानों के मेल में बनी हुई भाषा थी। ईरान के प्रति अपनी सांस्कृतिक गुलामी के कारण उन सामंतों ने उसे राजभाषा बनाया जिसकी मातृभाषा तुर्की या कोई अन्य गैर-फारसी भाषा थी। फारसी को राजभाषा बनाना यहाँ की भाषाओं के साथ अन्याय करना था। इस अन्याय में मुसलमानों के साथ अनेक हिन्दू सामन्त और उनके आश्रित तमंचारी

भी शामिल थे। किसी विदेशी भाषा का राजभाषा बनाना जातीय उत्पीड़न का एक रूप है। इस तरह के जातीय उत्पीड़न में पूंजीपति ही नहीं, उनसे पहले सामन्त भी भाग ले चुके हैं। इस उत्पीड़न में बहुत से हिन्दू शामिल हुए किन्तु इनके विपरीत बहुत से हिन्दू अपनी पहले से चली आती हुई भाषा या भाषाओं के लिए लड़े भी। उन्होंने फारसी के बदले ब्रज या अवधी में रचनाएँ की। इन हिन्दुओं के साथ बहुत से मुसलमान भी थे। सामन्त-वर्ग और जनसाधारण—इन दोनों की सांस्कृतिक नीति अलग-अलग थी। सामन्त-वर्ग मुख्यतः ईरानी संस्कृति का मुँह जोहता था; जनसाधारण अपनी भाषा और लोक-संस्कृति के विकास में लगा हुआ था।

अंग्रेजों ने अंग्रेजी लादकर जातीय उत्पीड़न को और तीव्र किया। अंग्रेजी और फारसी राजभाषाएँ रहीं लेकिन दोनों के उत्पीड़न में अन्तर था। फारसी एशिया की ही और हमारे पड़ोस की एक भाषा थी। उसे राजभाषा बनानेवाले हिन्दी या ब्रज में कविताएँ करते थे, यहाँ की भाषाओं को प्रोत्साहन देते थे, विशेष रूप से संगीत में उन्होंने यहाँ की समूची परम्परा को अपना लिया। उर्दू की तरह संगीत में अरबी-फारसी तानों से लदी हुई शैली का चलन न हुआ। राजभाषा अंग्रेजी की तुलना में राजभाषा फारसी का उत्पीड़न बहुत सीमित था।

सामन्तकाल में शिक्षा का काम पुरोहित वर्ग के हाथ में रहता है। इसलिए शिक्षा के नाम पर संस्कृत या अरबी-फारसी की पढ़ाई होती रही। इस कारण शिक्षित वर्ग में फारसी पढ़े लोग दर्शन, साहित्य आदि की विशिष्ट शब्दावली के लिए फारसी से शब्द लेने लगे। नौकरी के लिए फारसी या उर्दू की जानकारी आवश्यक होती थी, इसलिए हिन्दू-मुसलमान दोनों काफ़ी संख्या में फारसी-उर्दू सीखते थे। किन्तु यह हिन्दू-मुस्लिम-एकता विशेष आर्थिक और सामाजिक कारणों से पैदा हुई थी। इसलिए वह टिकाऊ न हुई।

उर्दू ने दर्शन, साहित्य, राजनीति आदि के लिए, या सम्य व्यवहार के लिए केवल अरबी-फारसी से शब्द लिये। उसके बोलचाल के रूप में तो हिन्दी-शब्दों की भरमार थी लेकिन सम्य व्यवहार के रूपों में—‘तशरीफ़ लाइये, नोश फ़रमाइये’ वाले रूपों में—और साहित्य में जो नये शब्द आये, वे सब-के-सब अरबी-फारसी से। इस तरह उर्दू के बोल-चाल के रूप में तो भाषा की जातीय परम्परा कायम रही लेकिन उसके सांस्कृतिक रूप में वह नष्ट हो गई।

उर्दू ने अपने इस नये विकसित रूप को दो धाराओं से अलग कर लिया। एक तो वह हिन्दी की बोलियों—अवधी, ब्रज, बुन्देलखण्डी, भोजपुरी और खड़ी बोली के ही ग्रामीण रूप—से बहुत दूर चली गई। दूसरे, वह भारत की अन्य भाषाओं—बंगला, मराठी, गुजराती आदि की सामान्य विशेषताओं से दूर जा पड़ी। संस्कृत के कठिन शब्दों के नाम पर उसने उन तमाम शब्दों का बहिष्कार करना शुरू किया जो भारत की अन्य सभी भाषाओं की सामान्य निधि हैं। इस तरह उर्दू-प्रेमियों ने यहाँ के हिन्दी-भाषियों से ही

अलग-अलग पैदा नहीं किया गगन दगना आदि नागार्थ बोलनेवाले मुनगमानों से भी अलग-अलग पैदा कर लिया।

इसीलिए हिंदी का जादूदान जोर पकड़ता गया, हिंदू मुस्लिम एकता का सीमित आधार गगन पर भी उड़ू अपना स्थान सुरंगित रखने में सफल न हुई और प्रेमवाद, बालमुकुट गन, प्रतापनारायण मिथ, भारनेन्दु हरिश्चन्द्र, पद्यगिह दामि आदि अनेक लखकान उड़ू में परिचय और प्रेम होते हुए भी हिंदी की मेला की। हिंदी के प्रति गगन पारणाओं के कारण उड़ू-प्रेमी सज्जा हिंदी के सहयोग में कोई आन्दोलन नहीं चला सके। दणक विमानन के बाद अब उनमें उड़ू की बोली उवान बनाने का माहम नहीं रहा। उहान पम्पी के कारण उगे दत्ताकाई उवान बनाने का नाग दिया। उड़ू का पढ़ने पढ़ान और उगके व्यवहार के लिए मुविपाए होनी चाहिए, हम इस मांग का समर्थन करते हैं। किन्तु अपने बोलचाल के रूप में वह किसी विशेष इराके की उवान नहीं है। इराकाई उवान का नारा जानीय अलग-अलग और विघटन का नारा है, इसलिए हम उगका विरोध करते हैं। उत्तर प्रदेश और अय हिंदीभाषी राज्यों से अवेबी जाय, उसकी जगह हिंदी को राज्यभाषा बनाया जाय, हिंदी के गाय अल्पगण्यको—जिनमें मुनगमाना के साथ कुछ हिंदू भी गिना जाएंगे—की भाषा के रूप में उड़ू का संरक्षण किया जाय, इन आपात पर हिंदी उड़ू-प्रेमी अब भी एक मंच पर मगुन आन्दोलन कर सकते हैं।

आगे चलकर क्या होगा? उड़ू रहेगी या मिट जायगी? उड़ू का बोलचाल वाला रूप मिट नहीं सकता, क्योंकि वह कुछ गिगित व्यक्तिया तक सीमित नहीं है। यह रूप हिंदी के बोलचाल वाले रूप जसा है और हिंदी लेखक उसे जपनावर हिंदी की समर्थ बना सकते हैं। उड़ू का साहित्यिक रूप हिंदी को काफी प्रभावित कर सकता है, अभी भी कर रहा है। अनेक हिंदी-वक्तियों की दृष्टि-योजना और शली पर उड़ू का प्रभाव देखा जा सकता है। यह प्रभाव कितना अधिक पड़ता है, यह उड़ूवादा पर भी निर्भर है। उड़ू-लेखक जितना ही अपना सीमित दायरा छोड़कर अपना साहित्य जनता के लिए लिखेंगे और देवनागरी के माध्यम से उा तक पहुँचायेंगे, उतना ही वे हिंदी के विकास को प्रभावित कर सकेंगे।

हमारी समझ में उड़ू से प्रभावित होकर हिंदी का बोलचाल वाला रूप पुष्ट होगा और हिंदी में प्रभावित होकर उड़ू के 'गम्य' अरबी फारसीवाले रूप में काफी परिवर्तन होगा। यह कहना आवश्यक है कि उड़ू में काफी देशभक्तिपूर्ण और जनताधिक माहिय है। सन्दावनी के कारण साहित्य की विषयवस्तु नहीं बदल जाती। हिंदी प्रेमी काफी उड़ू-साहित्य पढ़ते हैं, उर्व प्रेमियों को इस विषय में उनमें होठ करनी चाहिए।

उड़ू की रखा करना और उगकी स्वस्थ विवेचनाओं से सीखना हिंदी के हित में है। उसकी बोलचाल का रूप, कहावतें और मुहावरे हमारी भाषा की सम्पत्ति हैं। संकडा शेर या उगने दुकडे कहावना का रूप से चुने हैं। वे हमारी साहित्यिक सम्पत्ति का अंग हैं।

उर्दू में अरबी-फारसी के शब्द होने से उसके लिखने-बोलनेवाले देशद्रोही नहीं हो जाते ।

दरो दीवार पै हसरत से नजर करते हैं ।

खुश रही अहलेवतन हम तो सफर करते हैं ॥

इस तरह के जेर उन लोगों ने गुनगुनाये थे जिन्होंने अपना रक्त देकर अपनी देशभक्ति प्रमाणित की थी । हमारा उद्देश्य हिन्दीभाषी प्रदेश की सांस्कृतिक एकता को दृढ़ करना, उसके साहित्य की जनता के हित में विकसित करना है । इसीलिए हम चाहते हैं कि हिन्दी-उर्दू-प्रेमी एक-दूसरे के निकट आएँ, यहाँ अंग्रेजी की जगह अपनी भाषा प्रतिष्ठित करे और उसके विकास में मिल-जुलकर योग दें ।

स्वर्गीय पद्मसिंह शर्मा ने अपने ‘हिन्दी, उर्दू, हिन्दुस्तानी’ वाले प्रसिद्ध भाषण में हिन्दी-उर्दू की एकता के सम्बन्ध में कहा था, “कुटुम्ब के बँटवारे की तरह भाषा का यह बँटवारा भी कुटुम्ब-कलह और सम्पत्ति-विनाश का कारण है, बहुत-से सम्पन्न घराने बँटवारे की वदौलत टुकड़े-टुकड़े होकर बिगड़ गये, राज-परिवार भिखारी बन गये... यदि हिन्दी-उर्दू दोनों संयुक्त परिवार की दशा में आ जाएँ, तो फिर इसकी साहित्य-सम्पत्ति का संसार की कोई भाषा मुकाबला न कर सके ।” इसमें सन्देह नहीं कि हमारे प्रदेश के हिन्दुओं, मुसलमानों तथा अन्य धर्मवालों में रचनात्मक प्रतिभा की कमी नहीं है । उर्दू किसकी सेवा करेगी ? पाकिस्तान के पंजाबियों, बंगालियों, पठानों और सिंधियों की या अपने प्रदेश के लोगों की ? यह युग जनतन्त्र का है । हिन्दी-उर्दू एक ही जनता की सेवा करेंगी, इसलिए उनका संयुक्त परिवार बनना अनिवार्य है ।

(१९५८)

## जातीय प्रतिद्वन्द्विता और हिन्दी

देश के स्वाधीन होने के बाद जातीयता का भाव तेजी से बढ़ा है। हम गुजराती हैं, पंजाबी हैं, मलयाली या आंध्र हैं—अपने प्रदेश, भाषा और सभ्यता के सम्बन्धित दाय भाव को हम जातीयता का भाव कहते हैं। कुछ वर्ष पहले पढ़े गिने लोगों की मान्यता में एक शब्द अक्सर सुनाई देता था—'प्रोविन्स'। जब हम किसी को अपनी भाषा और साहित्य की बहद बड़ाई करने देखते थे तो कहते थे—ये लोग बड़े प्रोविंसियल होते हैं।

अपनी भाषा, जाति, प्रदेश, उसकी सभ्यता आदि पर गर्व करना बुरी बात नहीं है। इन जनक जातियों से ही भारत राष्ट्र की रचना हुई है। इन प्रदेशों की विभिन्न सभ्यताओं से मिलकर ही भारतीय सभ्यता का निर्माण होता है। इसलिए अपने प्रदेश और उसकी सभ्यता को भुलाकर राष्ट्रीयता और भारतीय सभ्यता की बात करना सम्भव नहीं है।

इसमें एक परिणाम यह भी निकलता है कि अपनी भाषा और उसके साहित्य को ही श्रेष्ठ समझने का एक देश की प्रगति के लिए हानिकार हो सकता है। हम एक-दूसरे से सीखकर, मिल जुलकर आगे बढ़ने के बदले जातीय प्रतिद्वन्द्विता में फँस जायेंगे और अपनी शक्ति का बड़ी भाग अपनी जातीय श्रेष्ठता सिद्ध करने में व्यय करेंगे। अपनी जातीयता के इस सतरे को स्वीकार करत हुए यह मानना होगा कि उचित मात्रा में जातीयता की चेतना विकास के लिए आवश्यक है। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि हिन्दी भाषिकों में—विशेषकर पढ़े लिखे मध्यम वर्ग के लोगों में—यह जातीयता का भाव उचित मात्रा में विद्यमान है या नहीं।

जातीयता की बात करने पर कुछ मित्र कहते हैं—हिन्दी राष्ट्रभाषा है, हम सारे राष्ट्र की बात साजते हैं, किसी प्रदेश के बारे में सोचने की सखीयता क्या दिखाएँ?

देश की परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो हिन्दी-भाषियों में चाहते पर भी जातीयता का भाव उत्पन्न करती हैं। इनमें एक उत्पत्तनीय परिस्थिति अहिन्दी भाषियों से हमारा सम्पर्क है। यानायात के माधनों के विभिन्न होने और आर्थिक कारणों से हजारों आदिमियों को

एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है या अपने प्रदेश में ही अन्य भाषाएँ बोलनेवालों से मिलना पड़ता है। इन जातीय प्रतिद्वन्द्विता का एक बहुत बड़ा केन्द्र कलकत्ता है। इन नगर में हिन्दी का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। 'भारत-मित्र' और 'मतवाला' जैसे पत्र यहीं से निकले हैं, निराना और उग्र जैसे लेखक यहाँ अपनी साहित्य-नायना कर चुके हैं। आज भी हिन्दी-भाषा और साहित्य की प्रगति में कलकत्ता की भूमिका नगण्य नहीं है। यहाँ आकर हिन्दी-भाषी व्यक्ति को यह बार-बार मुनने को मिनता है कि वह हिन्दुस्तानी है। हिन्दी-भाषी प्रदेश के लिए 'हिन्दुस्तान' शब्द का प्रयोग काफी पुराना है। हिन्दी-भाषियों कीने तना में यह शब्द सारे देश का वाचक ही रहा है। हिन्दी-भाषी प्रदेश का कोई विशेष नाम प्रचलित नहीं है। इन नाम के अभाव में हिन्दी-भाषी जाति का अस्तित्व मिट नहीं जाता। अन्य जातियों के सम्पर्क में आने में हिन्दी-भाषी व्यक्ति को विवश होकर सोचना पड़ना है कि उनकी जाति क्या है। ऐसी परिस्थिति में अपनी जातीयता में सम्बन्धित कुछ बातें स्मरण रखना आवश्यक है।

मगने पहले हिन्दी-भाषी जनता में जातीय चेतना के अपेक्षाकृत अभाव पर ध्यान देना चाहिए। जिस समय सारे देश में भाषा के आधार पर प्रान्त अथवा राज्य-निर्माण चर्चा चलनी रही है, हमारे प्रदेश में अनेक राज्यों की मिलाकर विशाल हिन्द प्रदेश के गठन का आन्दोलन नहीं चला। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश को ही विभाजित करने की बात कुछ राजनीतिज्ञों में सुनाई दी। अन्यत्र भाषाओं के आधार पर प्रान्त-निर्माण करने से—विशेषकर दक्षिण में—छोटे राज्यों का चित्र सामने आता था। किन्तु हिन्दी-भाषियों को एक प्रदेश में संगठित करने में अनेक राज्यों में एक बड़ा राज्य बनता था। विभाजन के बदले स्पष्ट ही देश की एकता दृढ़ होती थी। किन्तु इस ओर किसी राजनीतिक दल ने ध्यान नहीं दिया। यह स्थिति हमारे प्रदेश में जातीय चेतना के अपेक्षाकृत अभाव का प्रमाण है।

इस स्थिति के अनेक कारण हैं। हिन्दी-भाषी प्रदेश असाधारण रूप से विशाल हैं। उसमें भारत के किसी भी भाषा-क्षेत्र की तुलना में बोलियों की संख्या अधिक है। इस क्षेत्र में ब्रज, अवधी और मैथिल जैसी बोलियाँ हैं जिनका अपना विशाल साहित्य-भण्डार है। अनेक लोगों के मन में अब भी यह दुविधा है कि वे बोलियाँ दरअसल बोलियाँ हैं या हिन्दी से स्वतन्त्र भाषाएँ हैं। यातायात के साधनों का समुचित विकास न होने और उद्योग-धन्वों और व्यापार में हमारे प्रदेश के अनेक भागों के पिछड़े रहने से यह जातीय एकता का भाव विशृंखल-सा रहा है। इन बोलियों की समस्या के अलावा हमारे यहाँ हिन्दी-उर्दू की विशेष समस्या रही है। बोलचाल की भाषा के दो शिष्ट या साहित्यिक रूप होने से जातीय गठन में बाधा पड़ती रही है। एक ही दिशा में बढ़ने के बदले सांस्कृतिक शक्तियाँ दो दिशाओं में बँट गई थी। ये परिस्थितियाँ अब धीरे-धीरे बदल रही हैं।

इस प्रदेश के इतिहास के बारे में दो-चार बातें उल्लेखनीय हैं। संस्कृत भाषा और

साहित्य में हमारे प्रदेश का घनिष्ठ जातीय सम्बन्ध है। भाषाशास्त्र की दृष्टि से मस्कृत से जिनका सम्बन्ध हिन्दी और उसकी बोलिया का है उनका अर्थ भारतीय भाषाओं और उसकी बोलिया का नहीं। मस्कृत साहित्य के विज्ञान भण्डार में भारत के सभी पक्षों के विद्वानों ने अपनी गानराशि संचित की है। फिर भी इस साहित्य के अधिकांश भाग की रचना उन लोगों की है जो वर्तमान हिन्दी-प्रदेश के निवासी थे। पानी प्राकृत और अपभ्रंस के साहित्य के सम्बन्ध में भी यही बात बड़ी आसानी है।

जब चमकर तुर्की बोलनेवाली अनेक जातियाँ यहाँ आईं। पन्थों, फारसी आदि अन्य विभिन्न भाषाएँ बोलनेवाले जन भी यहाँ आये। मस्कृतों की दौड़ के बाद वे अपनी पूर्व जातीयता स्वीकार यहाँ के लोगों में घुल-मिल गए। इसका एक राक्षस प्रमाण बाबर-नामा में तुर्की भाषा का गायब होना है। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी किन्तु उसके बंशज घर में तुर्की न बोलते थे। फारसी उनकी मातृभाषा नहीं थी, सांस्कृतिक और राजनीतिक श्रेष्ठ व्यवहार के लिए स्वीकार की हुई वह एक विदेशी भाषा थी—यद्यपि वह फारसी की ही भाषा थी और मस्कृत में उसका घनिष्ठ सम्बन्ध था। सभी मुसलमानों की भाषा फारसी नहीं थी—यह तथ्य स्मरण रखना चाहिए। भारत के विभिन्न भाषा-क्षेत्रों में मुसलमानों की वही भाषा थी जो वहाँ के हिन्दुओं या जयधमवाला की थी। इसलिए यह समझना कि हिन्द-प्रदेश के मुसलमान किसी फारसी बोलनेवाली जाति के थे अथवा उनकी अलग जातीयता आज तक सुरक्षित है, सही नहीं है।

तीसरा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य १८५७ के स्वतंत्रता संग्राम में सम्बन्धित है। भारतीय जातियों का परम्परा सम्बन्ध भीषण पड़ने आज से भिन्न था। १८५७ में आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से हिन्द-प्रदेश भारतीय जीवन की घुरी था। नन् सत्तावन का स्वाधीनता संग्राम हिन्द-प्रदेश तक सीमित नहीं था। पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, हैदराबाद आदि प्रदेशों में भी मधुप हुए किन्तु मुख्य समरभूमि दिल्ली, जूनी और गाहाबाद के विनाल त्रिवाण में सम्बद्ध थी इसमें सन्देह नहीं। नन् सत्तावन के संग्राम की मुख्य शक्ति हिन्द प्रदेश की हिन्दू मुसलमान जनता थी। अंग्रेज साम्राज्यवादियों ने यहाँ के नगरों को उतार डाला यहाँ का व्यापार नष्ट कर दिया, भयंकर नरसंहार द्वारा उन्होंने यहाँ का जनता को भ्रम और जातकित करने में कुशल उठा न रखा। तब से जातीय अनुत्पन्न बढ़ने लगा। महान में विनाल होने पर भी आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से हमारी जाति बहुत-कुछ पिछड़ी रही। यह स्थिति धीरे धीरे बदल रही है।

भारत की अनेक समृद्ध भाषाओं की सुनना में हिन्दी गद्य का विकास विलम्ब से हुआ। यद्यपि बोली का शिष्ट और सुसम्पन्न रूप पढ़ने उर्दू के माध्यम से सामने आया। यदि हिन्दी गद्य का स्वतंत्र विकास न होता, यदि उर्दू वास्तव में हमारी जातीय भाषा की भूमिका पूरी कर पाती तो हमारा गद्य-साहित्य आज बहुत समृद्ध होता। किन्तु हिन्दी शब्दों के बहिष्कार और फारसी-अरबी से ज्यादा शब्द उधार लेने के कारण उर्दू का

विकास भारत की अन्य भाषाओं से अलग एक निराली दिशा में हुआ। उर्दू में केवल दरबारी साहित्य नहीं है; खड़ी बोली के इस साहित्यिक रूप में राष्ट्रीय भावना और नये युग की चेतना प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। फिर भी शब्द-भण्डार की विशिष्टता के कारण वह हमारे जनपदों की बोलियों से दूर होती गई और हिन्दी गद्य का विकास अनिवार्य हो गया। यह प्रसन्नता की बात है कि उर्दू की बहुत ही पुस्तकें देवनागरी अक्षरों में छप रही हैं और हिन्दी साहित्य से सम्बन्धित बहुत-सी पुस्तकें उर्दू में निकली हैं। इनसे हमारी भाषा के दोनों साहित्यिक रूप एक-दूसरे के निकट आते हैं और एक मिली-जुली साहित्यिक भाषा की ओर बढ़ने की सम्भावनाएँ उत्पन्न होती हैं।

जातीय प्रतिद्वन्द्विता का सामना करने के लिए यह आवश्यक है कि हिन्दी के सरल और मुहावरेदार रूप को ज्यादा-से-ज्यादा काम में लाया जाय। विशेष रूप से कथा-साहित्य में भाषा का साफ-सुथरा रूप आना जरूरी है। हिन्दी कथाकार जान-बूझकर कठिन भाषा नहीं लिखते। लेकिन सरलता ही काफ़ी नहीं है। बालमुकुन्द गुप्त और प्रेमचन्द की शैली ही की तरह भाषा इतनी आकर्षक होनी चाहिए कि पाठक स्वतः उसकी ओर खिंचें। संस्कृत शब्दावली का प्रयोग करने से सारे भारत में हिन्दी लोकप्रिय हो जाएगी—यह धारणा कथा-साहित्य पर निगाह डालने से मिथ्या साबित होती है। हिन्दी और अहिन्दी-प्रदेशों में उन्हीं कथाकारों की रचनाएँ अधिक पढ़ी जाती हैं जो सरल और मुहावरेदार भाषा लिखने में सबसे आगे हैं।

आधुनिक हिन्दी-साहित्य का विकास विलम्ब से हुआ, फिर भी यह विकास असाधारण वेग से हुआ है। पिछले साठ-सत्तर वर्षों में हिन्दी ने प्रेमचन्द जैसे उपन्यासकार, निराला जैसे कवि, प्रसाद जैसे विचारक, कवि और नाटककार, बालमुकुन्द गुप्त जैसे व्यंग्य लेखक, हरिश्चन्द्र और बालकृष्ण भट्ट जैसे पत्रकार, महावीरप्रसाद द्विवेदी जैसे आलोचक और सम्पादक, बृन्दावनलाल वर्मा जैसे ऐतिहासिक उपन्यासकार उत्पन्न किए हैं। इन सबकी रचनाएँ न केवल हिन्दी साहित्य बरन् भारतीय साहित्य के इतिहास में उल्लेखनीय रहेंगी। साठ-सत्तर वर्ष की छोटी अवधि में हिन्दी साहित्य की कुछ जातीय विशेषताएँ उभरकर सामने आती हैं। इनमें प्रमुख विशेषता है जिन्दादिली। भारतेन्दु-युग के साहित्यकारों की जिन्दादिली का कहना ही क्या? भयानक कठिनाइयों का सामना करने पर भी वे अपनी विनोदप्रियता और उत्साह की रक्षा कर सके। कुछ लोग कहते हैं कि हिन्दी में हास्यरस का अभाव है लेकिन हिन्दी का शायद ही कोई लेखक हो जो व्यंग्य-विनोद से पूरी तरह वंचित न हो। गम्भीर आलोचक रामचन्द्र शुक्ल तक रीतिकालीन कवियों की चर्चा होने पर अपनी विनोदप्रियता का दमन न कर पाते थे। छायावादी लेखक निरालाजी के रेखाचित्रों—‘देवी’, ‘चतुरी चमार’ आदि—और अनेक आलोचनात्मक निबन्धों—‘कला के विरह में जोशीबन्धु’ आदि—में उनका व्यंग्य-विनोद देखते ही बनता है। प्रेमचन्द के कथा-साहित्य में—विशेषकर उनकी कहानियों में—उनका व्यंग्य अन्तर्धारा के समान प्रवाहित है। हम कह सकते हैं कि जिन्दादिली



हिन्दी-साहित्य की एक जातीय विशेषता है।

इसी महत्वपूर्ण विशेषता हिन्दी लेखकों का राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन से सम्बन्धित विशेषकर ग्रामीण जीवन में उनका गहरा सम्बन्ध है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और उनके पुत्र न. चिन्तामणि लेखक देश में स्वाधीनता-प्रेम और नई राष्ट्रीय चेतना का प्रसार करने वाले थे। किसान-जीवन में प्रेमचन्द का कितना गहरा सम्बन्ध था, इसे सभी लोग जानते हैं। यही कारण है भारतीय साहित्य में एक नये यथार्थवाद की प्रतिष्ठा कर सके। प्रमाण कम साहित्यकार ने भी 'नितली' में प्रेमचन्द के समान किसानों का चित्रण किया। साहित्यिक उपग्रामकार ब. दावतलाल वर्मा की रचनाओं में बुन्देलखण्ड की लोक-संस्कृति का बलवर्धन को मिलता है। नागार्जुन जैसे लेखकों ने इस परम्परा को सुरक्षित रखा है। जमनालाल बाग्य ने निम्न मध्यवर्ग और ध्वस्त होती हुई सामन्ती संस्कृति के अनुपम चित्र देकर इस यथार्थवाद को व्यापक और प्रगल्भ बनाया है। हिन्दी साहित्य की मुख्य धारा समाज निरपेक्ष होकर समाज में पूर्णतः सम्मिलित है। हिन्दी साहित्य का यह यथार्थवादी पक्ष उसका सर्वोत्तम पक्ष है और हम उस पर उचित अभिमान कर सकते हैं।

हिन्दी साहित्य की इस प्रगति और जातीय प्रतिद्वन्द्विता में हिन्दी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए नई कविता में मन्तोप नहीं किया जा सकता। यह धारा अन्तर्मुखी, सामाजिक जीवन की उपस्था करनेवाली और कलात्मक मोन्दर्य से हीन है। हिन्दी को शान्ताम्बुद प्रभाव के लिए पारिभाषिक शब्दावली के कुछ भ्रमों और नई कविता की कुछ पठित पवित्रता उद्धृत करना काफी होता है। नई कविता के समर्थक वर्तमान काल में हिन्दी के जातीय और राष्ट्रीय दायित्व को पहचानते हैं, यह नहीं कहा जा सकता। आधुनिक हिन्दी कविता को समृद्ध करनेवाले ऐसे बहुत से कवि हैं जो नई कविता के रंग-रस में दूर हैं। फिर भी यह मानना होगा कि दिनकर, सुमन, नरेन्द्र के बाद के कवियों की पीढ़ी उनकी समर्थ नहीं है। आधुनिक हिन्दी कविता की तुलना में हिन्दी क्या साहित्य जाने बढ़ा हुआ है।

हिन्दी पढ़ने लिखनेवाले अहिन्दी-भाषिया की समस्या तेजी से बढ़ रही है। वे जब हिन्दी पढ़ते हैं तब अपनी भाषा के साहित्य से हठान उनकी तुलना भी करने हैं। उनका दृष्टिकोण हमसे अधिक आलोचनात्मक होता है। ऐसे लोगों की सख्या निकट भविष्य में और भी बढ़ेगी। इसीलिए जातीय प्रतिद्वन्द्विता के इस युग में हिन्दी लेखकों का दायित्व बढ़ता बढ़ गया है। साहित्य के हर क्षेत्र में उनसे असाधारण परिश्रम की अपेक्षा है। आधुनिक साहित्य के विकास में हम कुछ देर से घामिल हुए हैं। विलम्ब से होनेवाली शक्ति पूरी करनी है। हमारी जानि सख्या में भारत की सभी जातियों से बढ़ी है और विद्वत् की तीन चार भाषाओं में—जिनके बोलनेवालों की सख्या सबसे अधिक है—हिन्दी भी है। परिमाण से मन्तोप न करके उसे गुणात्मक रूप से समृद्ध करना हमारा कर्तव्य है। व्यापार के प्रसार से हिन्दी में पुस्तक प्रकाशन खूब बढ़ा है। शोध प्रयोगों से लेकर उपन्यासों तक सैकड़ों पुस्तकें हर साल प्रकाशित होती हैं। जल्दी लिखने और पुस्तकें छापने का मोह

अनेक लेखकों की खींचता है। साधना के बिना साहित्य का स्तर ऊँचा नहीं हो सकता। पुस्तकों की भारी संख्या साहित्य की गरिमा का प्रमाण नहीं है। यदि सम्भव हो तो प्रत्येक हिन्दी लेखक को कुछ दिन के लिए अपना प्रदेश छोड़कर किसी अन्य भाषा-क्षेत्र में जाना चाहिए, वहाँ की साहित्य गतिविधि से परिचित होना चाहिए, छिट्छान्तेपग के बदले वहाँ की अच्छी बातें सीखने का प्रयत्न करना चाहिए और धैर्य से हिन्दी के सम्बन्ध में अहिन्दी-भाषियों की राय सुननी चाहिए। इससे आत्मसन्तोष की गलत भावना कम होगी और नई लगन से साहित्य-साधना करने की प्रेरणा मिलेगी। देश की वर्तमान परिस्थितियों में केवल हिन्दी-भाषी प्रदेशों तक—उनमें भी केवल बिहार या उत्तर प्रदेश तक, और इनमें भी अक्सर इलाहाबाद, बनारस या पटना तक—अपना दृष्टिकोण सीमित करके साहित्य-कार विशेष प्रगति नहीं कर सकते। अपनी जातीय संस्कृति पर उचित गर्व करते हुए उन गर्व को अहंकार और दम्भ में परिवर्तित होने से बचाते हुए, भारत की सभी जातियों में सद्भावना और मैत्री को बढ़ाते हुए एक उदार दृष्टिकोण के आधार पर हम अपने प्रदेश के साथ समग्र देश की प्रगति में सहायक हो सकते हैं।

(१९५६)

## राष्ट्रभाषा अंग्रेजी

सब-प्रभुत्व-सम्पन्न भारतीय गणराज्य की लोकमता में पिछले महीने इस प्रश्न पर निरवस्था बहस हुई कि अंग्रेजी को भारत की एक राष्ट्रभाषा माना जाय या नहीं। हिन्दी में जब हम राष्ट्रभाषा की बात करते हैं तब उसका अर्थ यह होता है कि सारे राष्ट्र के विभिन्न प्रदेशों में परस्पर-व्यवहार की भाषा। पहले अंग्रेजी भाषा के माध्यम से भारतीय समन्ताओं पर विचार करनेवाले विद्वान् इसी अर्थ में (अथवा प्रायः इस अर्थ में) 'द नेशनल' पत्रिका की सलाह करने लगे। लेकिन अब वही या उनमें से अनेक विद्वान् 'ए नेशनल लैंग्वेज' की बात करने लगे हैं अर्थात् भारत राष्ट्र में जितनी भाषाएँ बोली जाती हैं, वे सभी राष्ट्र के अंदर ही वाली जाने से राष्ट्रभाषाएँ हैं।

एक विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में पुस्तकें संग्रहित का काम अर्थशास्त्र के एक प्राध्यापक का मौखिक काम था। वह अंग्रेजी में लिए निर्धारित रकम भी अध्यापन की पुस्तकें के लिए खर्च कर देता था। आपत्ति करने पर उन्होंने उत्तर दिया— आप देखते नहीं, ये अर्थशास्त्र की पुस्तकें भी तो अंग्रेजी में लिखी हुई हैं।

उसी तरह राष्ट्र में जो भाषा भी बोली जाती है, वह राष्ट्रभाषा है।

वस्तुतः राष्ट्र के लिए अंग्रेजी में कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेशन और नेशनल के लिए राष्ट्र और राष्ट्रीय शब्दों का प्रयोग होता है किन्तु इन प्रयोगों को उचित मानें तो 'नैशनल नेशनल क्लब' का अनुवाद बहुराष्ट्रीय राष्ट्र हागा (अर्थात् एक देश में अनेक राष्ट्र हैं)। हिन्दी में राष्ट्र शब्द देश के समकक्ष है, उसमें घटकर नहीं है। यह भी हिन्दी का दावा है कि अंग्रेजी जैसी समुदाय भाषा में हिन्दी जैसी दरिद्र भाषा के राष्ट्र शब्द का कोई न्याय-युक्त पर्याय नहीं है। और हो भी क्यों? राष्ट्र कहने ही कुछ दक्षिणानुसूचित की गरिमा नहीं जाती क्या जंग हिन्दी कहने ही देशानुसूचित की बुआने लगती है?

अंग्रेजी 'नैशनल' 'नेशन'। जितने राष्ट्र सुघरे गन्दे हैं। मुँह से निकलने ही बेहतर गन्ध उठता है। इसलिए अंग्रेजी 'ए नेशनल लैंग्वेज' भी है, 'द नेशनल लैंग्वेज' भी है। वह भारत राष्ट्र में बोली जानेवाली अनेक भाषाओं में एक है और इन अनेक में एकमात्र एक भाषा है।

ऐसा इंडियन-कुल-नगर दिवाकर श्री प्रो० ऐष्टनी एम० पी० ने लोकमता में

कहा कि कुछ लोग अंग्रेजी का नाश करने पर तुले हुए हैं। इनमें अग्रगण्य वे हैं जिनकी मातृभाषा हिन्दी है। ये हिन्दी-प्रेमी समझते हैं कि हिन्दी तब तक राजकाज की भाषा न बनेगी, जब तक अंग्रेजी का नाश न किया जाएगा।

श्री ऐण्टनी ने यह नहीं कहा कि अंग्रेजी को राजभाषा बनाये रखने के लिए हिन्दी का नाश करना जरूरी है। किन्तु इससे पहले अनेक अवसरों पर वह हिन्दी के लिए लोक-सभा में जिन विरोधों का प्रयोग कर चुके हैं, उनसे यही ध्वनि निकलती है।

श्री ऐण्टनी इतिहास में भी देखल रखते हैं। उन्होंने राष्ट्रभाषा-समस्या के दायरे से बाहर निकलकर भारतीय इतिहास का विहंगावलोकन करते हुए घोषित किया, “द हिस्ट्री ऑफ़ इंडिया विफोर द ऐडवेंट ऑफ़ इंग्लिश बाज द हिस्ट्री ऑफ़ ट्राइबलिज्म।” (६ अगस्त, १९५६ के ‘टाइम्स ऑफ़ इंडिया’ में प्रकाशित विवरण)। अर्थात् अंग्रेजों के आने से पहले भारत का इतिहास कबीलों का इतिहास था।

कबीलों को शिक्षित करने, उन्हें राष्ट्रीय एकता का पाठ पढ़ाने, उनकी आदिम वर्चस्वता को दूर करने का काम अंग्रेजों ने किया। अंग्रेज शासकों को राष्ट्रीयता से इतना प्रेम था कि यहाँ से विद्रोह होते समय वे एक के बदले दो राष्ट्र बना गए !

श्री फ्रैंक ऐण्टनी ने अपनी सहज विनम्रता से यह नहीं कहा कि सम्यक्ता के बाहन अंग्रेज शासकों के नामलेवा और पानीदेवा ऐंग्लो-इंडियन सम्प्रदाय के ऐण्टनी जैसे नेता अभी बचे रह गए हैं।

लेकिन ऐण्टनी महोदय देशभक्ति में किसी से पीछे नहीं। आज जब देश के अनेक कर्णधार जनता को यह समझाते नहीं थकते कि अंग्रेजों की पुरानी अत्याचार-गाथा भूल जाओ, नये सिरे से नए और अहिंसा के आधार पर उनसे मैत्री-सम्बन्ध कायम करो, तब भारतीय गणतंत्र की लोकसभा में श्री फ्रैंक ऐण्टनी ने माननीय सदस्यों को सूचित किया कि वह ऐंग्लो-इंडियन सम्प्रदाय का इतिहास लिख रहे हैं और वे ही जानते हैं (उनका दिल जानता है ! ) कि अंग्रेजी राज ने जितना नुकसान ‘ऐंग्लो-इंडियन कम्युनिटी’ का किया है, उतना और किसी का नहीं ! उन्होंने सख्त निवेदन किया कि १८०६ से पहले ऐंग्लो-इंडियन कम्युनिटी के सदस्य सैनिक और श्रेष्ठी (मर्चेन्ट-प्रिसेज) होते थे (और इस रूप में भारत राष्ट्र की सेवा करते थे ! ) किन्तु १८०६ के बाद वे उस गौरवशाली स्थान से हटा दिये गए। श्री ऐण्टनी के अनुसार अंग्रेज शासकों को सन्देह था कि वे हिन्दुस्तानियों से मिलकर किसी दिन विद्रोह कर देंगे।

उदारमना, सुसंस्कृत अंग्रेज शासकों की राज्यसत्ता का आधार शायद इतना व्यापक था कि उन्हें भारतीय जनता से ही भय नहीं था, वरन् उनसे भी संकट की आशंका थी जो अपने को अंग्रेजों का वंशज मानने में गर्व और गौरव का अनुभव करते थे, भले ही अंग्रेज रक्त सम्मिश्रण का सन्देह करके घृणा से मुँह फेर लेते हों। ऐंग्लो-इंडियनों से विद्रोह की शंका निर्मूल थी। १८०६ के पचास साल बाद, सन् अठारह सौ सत्तावन के साल अनेक ऐंग्लो-इंडियन देशभक्तों ने, हैदराबाद के निजाम और नेपाल के राना जंगबहादुर जैसे दूरदर्शी

राजनीतिज्ञों के समान ही प्रगतिशील अंग्रेजों की राज्यसत्ता फिर से स्थापित करान में ऐंडो-चोटी का समीना एक कर दिया। १९३० में हर्बर्ट एरिक स्टार्क नाम के एक ऐंग्लो-इंडियन सम्मेलन में 'द वान जाफ द थ्रंड' (धून की पुकार) नाम की पुस्तक लिखी थी। उसमें उन्होंने १८५७ में ऐंग्लो-इंडियनों की राष्ट्र-सेवा का चित्रण किया था। इसकी भूमिका में उन्होंने इस बात पर खेद प्रकट किया था कि १७८६ के बाद (श्री ऐण्टनी के दिए हुए मन में कुछ बच पड़न) ऐंग्लो-इंडियनों को इस बात की मनाही कर दी गई थी कि वे उमीन खराद या फात्र और मिविल मविस में ऊंची जगह पाएँ। फिर भी धून की पुकार तो धून की ही है, विगुड़ अंग्रेज उसे बैगा भी धून समझें। स्टार्क ने गर्व से लिखा है कि लामार्टीनियर कॉलेज, लखनऊ के (ऐंग्लो-इंडियन) छात्रों ने रेजीडेंटों के घेर के समय अंग्रेज सैनिकों के साथ रहकर उनकी अनुपम सेवा की, उनकी जूटी रफावियाँ और गप्पे कपड़े धोये, चक्की पीसी, खाना पकाया और पचा खींचा। इस सेवा का पुरस्कार छात्रों का क्या मिला, मालूम नहीं, लामार्टीनियर के प्रिंसिपल महादय को ताल्लुकदार अवश्य बना दिया गया।

१८५७ में भारतीय सेना के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़नेवाले वृद्ध गोरे अप्सर भी थे। उनका उल्लेख करते हुए स्टार्क ने मगध लिखा है—अंग्रेजों में अंग्रेज तक लड़े, नहीं लड़े तो केवल ऐंग्लो-इंडियन।

श्री प्रक ऐण्टनी भी कह सकते हैं—अंग्रेजों ने भी चाहे हिन्दी का राजभाषा स्वीकार कर लिया हो, नहीं स्वीकार किया है तो उन-जैसा ऐंग्लो-इंडियनों ने।

श्री ऐण्टनी के भाषण के समय चारों ओर से मदम्यों ने उग्र पर आपत्ति की और अपना तीव्र विरोध प्रकट किया। किन्तु प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों के भविष्य के सम्बन्ध में श्री ऐण्टनी का यथेष्ट आश्वासन दिया। कहना चाहिए, आश्वासन यथेष्ट में भी अधिक था क्योंकि प्रधानमंत्री के भाषण के बाद श्री ऐण्टनी ने सन्तुष्ट प्रकट करते हुए कहा कि उन्होंने जितने की आशा की थी, उससे भी अधिक प्रधानमंत्री से उन्होंने पाया।

प्रधानमंत्री अत्यन्त उदारवैता व्यक्ति हैं। सकीर्णता उनके स्वभाव के प्रतिबिम्ब है। उनका अन्तराष्ट्रीय दृष्टिकोण जितना व्यापक है, उतना ही और उसमें कुछ अधिक ही व्यापक उनका राष्ट्रीय दृष्टिकोण है। विशेष रूप से उनका हिन्दी-सम्बन्धी दृष्टिकोण इतना व्यापक हो गया है कि अब वह कोण न रहकर रेखा बन गया है जिसमें चौड़ाई सीधे होकर लम्बाई में परिवर्तित हो गई है।

— भारत में मुख्यतः हिन्दी के द्विभाषी हैं, कुछ लाग अंग्रेजी के। पक्षशील का तकाड़ा है कि दोनों का दानिपूण सह अस्तित्व कायम रहे। जैसे भारत की स्वाधीनता-रण के साथ राष्ट्रीय सरकार ने देश में ब्रिटिश पूँजी के मुनाफे की रक्षा का भार भी लिया है, उसी तरह क्या अंग्रेजी का राजभाषा बना रहना हिन्दी के राष्ट्रभाषा बनने में महापक् नहीं हो सकती? असली बीज है, दोनों के अलग अलग लोगों को पहचानना। यह पहचान

हासिल हो तो संघर्ष की नीवत ही न आए। भाषाएँ 'ओवरलैप' करती हैं; ओवरलैप करने से प्रधानमन्त्री का आग्रह क्या है, यह जितना हम समझते हैं, उतना अखबार पढ़कर आप भी समझ सकते हैं। 'लैंग्वेज हू ओवरलैप'—प्रधानमन्त्री के इस भाषाविज्ञानी सूत्र की व्याख्या करना हमारा काम नहीं।

प्रधानमन्त्री ने बताया कि पहले अंग्रेजी एक लादी हुई भाषा थी। फिर भी उसने आधुनिक ज्ञान के द्वार खोल दिये।

इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वर्तमान समय में जो लोग उस लादी हुई भाषा का लदाव अस्वीकार करके स्वेच्छा से उसे ढोते हैं, वे और भी जल्दी आधुनिक ज्ञान-भण्डार तक पहुँच जाएँगे। उनके लिए द्वार खोलने का सवाल भी न उठेगा; वे खिड़की या रोशनदान से ज्ञान-मन्दिर के आँगन में कूद पड़ेंगे !

प्रधानमन्त्री ने कहा कि 'एंग्लो-इंडियन सम्प्रदाय' को पूर्ण अधिकार है कि वह अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा पाये। इसके सिवाय उन्होंने एक बात मार्को की और कही—“एंग्लो-इंडियन्स शुड बी गिविन एनी फ्रैंसिलिटी टु डिवेलप इंग्लिश लैंग्वेज।” एंग्लो-इंडियनों को यह पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए कि वे अंग्रेजी भाषा को विकसित कर सकें। अभी तक हम सुनते थे कि हिन्दी को ही भाषा-रूप में विकसित करना आवश्यक है, वह पिछड़ी हुई भाषा है, उसका भाषागत अथवा साहित्यिक महत्त्व नहीं है, महज सुविधा के लिए, बोलनेवालों की विशाल संख्या के ही कारण उसे राष्ट्रभाषा या राजभाषा बनाना है, इसलिए उसे विकसित करना होगा। किन्तु सर्वज्ञान-समृद्ध, आधुनिकता की खान, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महाभाषा अंग्रेजी को 'डिवेलप' कराना जरूरी है, और वह भी भारत के एंग्लो-इंडियन सम्प्रदाय द्वारा—इससे बड़ी सूझ-बूझ की बात लोकसभा में स्वयं प्रधानमन्त्री भी आगे कहेंगे, इसमें सन्देह है।

प्रधानमन्त्री ने अपनी नीति के समर्थन में कहा कि पांडिचेरी प्रदेश ('पांडिचेरी-टेरीटरी') की भाषा फ्रांसीसी है।

भले ही इस पांडिचेरी प्रदेश की भारतीय जनता की भाषा फ्रांसीसी न हो, लेकिन अगर एक यूरोपीय भाषा होने के नाते वहाँ उसे राजभाषा का पद मिल सकता है, तो सारे भारत में अंग्रेजी को राजभाषा—अथवा हिन्दी के साथ अतिरिक्त राजभाषा (और व्यवहार में एकमात्र राजभाषा) का पद क्यों नहीं दिया जा सकता ?

प्रधानमन्त्री ने कहा कि जो प्रदेश पुर्तगालियों के अधिकार में है, एक दिन वह भी भारत राज्य में मिल जाएगा। तब पुर्तगाली भी 'ए लैंग्वेज ऑफ़ इंडिया' (भारत की एक भाषा) होगी।

इससे स्पष्ट परिणाम निकला कि सविधान में उल्लिखित भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी का नाम न होने पर भी वह है भारतीय भाषा ही !

लोकसभा के एक दक्षिण भारतीय सदस्य ने श्री ऐण्टनी के समर्थन में कहा कि दो शताब्दियों से भारत का बुद्धिजीवी वर्ग अंग्रेजी को अपनी भाषा के रूप में अपनाये

हुए है। देश की एकता के लिए यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम एक ही भाषा अर्थात् अंग्रेजी हो। प्रधानमंत्री ने माननीय सदस्य की बात की चर्चा करते हुए कहा कि वह स्वयं भी चाहते हैं कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम एक ही भाषा अर्थात् अंग्रेजी रहे लेकिन उन्हें यह किमी तरह के दबाव से नफरत है, इन सब चीजों का महज विकास ही वाछनीय है। उन्होंने कहा कि हिन्दी के हिमायती जब दूसरों पर हिन्दी लागू करना चाहते हैं तो वह भी उन्हें नापसन्द है और अंग्रेजी के हिमायती अंग्रेजी लाते तो वह भी नापसन्द है।

नतीजा यह कि इन दो नापसन्दगियों के बीच अंग्रेजी हमारी पसन्द में, बिना किमी पर लद हुए राजभाषा बनी रहनी है।

अंग्रेजी के राजभाषा न रहने से क्या होगा ? प्रधानमंत्री के अनुसार अंग्रेजी आधुनिक सभार की ओर खुलनेवाली बड़ी खिडकी है। 'बी डेयर नॉट क्लोज दैट विंडो। इफ वी क्लोज दैट इट इज गेट द पेरिज आफ अवर फ्यूचर।' (यह खिडकी हमें हार्जिज बन्द न करनी चाहिए। उसे बन्द किया तो हमारा भविष्य सड़क में पड़ जाएगा।)

भारत का भविष्य यहाँ की नियानवे फीमदी जनता पर निर्भर नहीं है। भविष्य निर्भर है डेड फीमदी अंग्रेजी जाननवानों पर, जो इस खिडकी से आधुनिक सभार की ओर भाँकते हैं। इन डेड फीमदी में भी बहुतों का खिडकी तक पहुँचने और बाहर भाँकने का सोभाग्य नहीं मिलता। अंग्रेजी व्याकरण, उसके बाद उच्चारण और उससे भी बढ़कर गणना के लेखन की ऐसी बाधाएँ हैं जो उन्हें भाँकने में रोकती हैं। इसी कारण कुछ प्रदेशों के मंत्री और उपमंत्री तक बहुधा अपने अंग्रेजीदाँ सेक्रेटारियों की पीठ का सहारा लेकर ही खिडकी से भाँकते हैं। नौकर यह क्या पाने हैं, यह कहना बठिन है क्योंकि जनता से अधिक भाग्य-नश्वरता पर भरोसा होने के कारण वे ज्योतिष-शास्त्र को आधुनिक विज्ञान की चरम उपलब्धि मानते हैं।

प्रधानमंत्री की युक्तिपूर्ण बातों कुछ समाचारपत्रों की सम्मेलन में नहीं आईं। इनमें ऐसे पत्र भी हैं जो हिन्दी के समर्थकों की आलोचना करते हैं और जिनकी भाषा अंग्रेजी है। उदाहरण के लिए, 'टाइम्स ऑफ इंडिया' ने १४ अगस्त की सम्पादकीय टिप्पणी में लिखा था, 'राजभाषा के सम्बन्ध में लाकम्भा की समिति ने अपने अत्यन्त तर्कमग्न विवरण में 'हिन्दी साध्यायवाद' के भय को निर्मूल कर दिया था। उसके बाद प्रधानमंत्री द्वारा अधिक आश्वासन की अपेक्षा नहीं थी। जो भय दूर हो चुके थे, उन्हें फिर से दूर करने के प्रयास में श्री नेहरू ने ऐसी बातें कही जो उन चरम-पथियों के हाथ मजबूत करती हैं जो इस स्थिति को अस्वीकार करते हैं कि हिन्दी देश की राजभाषा हो।'

यह अखबार मानता है कि आधुनिक सभार को देखने के लिए अंग्रेजी खिडकी आवश्यक है लेकिन उसे खेद है कि श्री नेहरू आवश्यकता से अधिक आश्वासन दे गए। और हमें खेद है प्रेमचन्द की बुद्धि पर जो अंग्रेजी का राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व न समझकर उसे राष्ट्रभाषा माननेवाले देशभक्तों के लिए कह गए थे—“वे इतनी बुलन्दी

पर पहुँच गए हैं कि नीचे की धूल और गर्मी उन पर कोई असर नहीं कर सकती। वे मुअल्लक हवा में लटके रह सकते हैं। लेकिन हम सब तो हजार कोशिश करने पर भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। हमें तो इसी धूल और गर्मी में जीना और मरना है। इटैलीजेनिया में जो कुछ शक्ति और प्रभाव है वह जनता ही से आता है। उससे अलग रहकर वे हाकिम की सूरत में ही रह सकते हैं, खादिम की सूरत में जनता के होकर नहीं रह सकते। उनके अरमान और मंसूबे उनके हैं, जनता के नहीं। उनकी आवाज उनकी है, उसमें जनसमूह की आवाज की गहराई और गरिमा और गम्भारता नहीं है। वह अपने प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि नहीं।”

(१९५६)



## सोवियत सघ में भाषा-समस्या-समाधान

तात्स्ताय ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास 'बूढ़ और शान्ति' में एक कल्प की चर्चा की है जिसकी व्यापना इस उद्देश्य में की गई थी कि उनका मद्स्य रूसी बोलें, जो हमी न बाने बह जुमाना द। यह मस्या राष्ट्रीयता के जावेद में सब कायम की गई थी जब गेरालियन भास्को के निवृत्त पहुँच गया था। एक महिला मद्स्य बोल म फामीसी बोलने लानी है और फिर भूत सुपायकर कहनी है, जात्रि इस बात को हमी म कैसे ध्यस्त कर। इस के अभिज्ञान का की यह फामीसी भक्ति भारत के बहुत से लोकरी-मेरा, नेता-पगा भद्रजनों की अग्रेखी-भक्ति से तुलनीय है। समाजवादी क्रान्ति में यह विदेशी भाषा भक्ति खत्म कर दी।

समाजवादी क्रान्ति के बाद साम्यवादी नेता इस बात का इन्तज़ार नहीं करते रहे कि हमी भाषा विकसित होकर फामीसी या जर्मन के बराबर हो जाय तब उसे राजभाषा बनाएँ। उन्होंने रूसी को ही राजभाषा नहीं बनाया, उर्ज़नी, जात्रिपाई, वेनोत्सी आदि भाषाओं का भी राजभाषा बनाया। मोवियत सघ गणराज्यों का सघ है और प्रत्येक गणराज्य की अपनी राजभाषा है। जो जानियाँ पिछड़ी हुई थी, जिनकी भाषाओं की निधि नहीं थी, उन्हें भी निधि-व्याकरण आदि में दुरुस्त करके स्वायत्त शासन के कार्यों के लिए चालू किया गया। जैसा कि गांधीजी ने कहा था, भारतीय भाषाओं के विछोपन को दुहाई देकर अंग्रेजी की बरकरार रचना आत्मश्रुति की निशानी है।

विभिन्न जातियों के बीच आपसी व्यवहार और केन्द्रीय राजकाज के लिए कोई भाषा हो या न हो? हम में जातीय उत्पीड़न नीर था, इसलिए लेनिन ने यह नारा दिया कि कोई भी अनिवार्य केन्द्रीय राजभाषा न होनी चाहिए। साथ ही लेनिन ने अपने भाषा-सम्बन्धी लेखों में यह भी कहा कि सम्म देश में सगल उन जाति की भाषा को अपनी व्यवहार के लिए स्वीकार करेंगे जिनके बीचनेवाला की मर्यादा जराश होगी। इस तरह केन्द्रीय पार्टी-कार्यों और केन्द्रीय राजकाज के लिए रूसी भाषा का व्यवहार बराबर होता रहा।

पूनीवादी बहुजातीय देनों और सोवियत सघ में केन्द्रीय भाषा की स्थिति में अन्तर है। मोवियत सघ में कानून से रूसी को केन्द्रीय भाषा नहीं बनाया गया, यह स्वेच्छा में

स्वीकृत हुई है। स्वेच्छा से स्वीकृत होने का सामाजिक आधार यह है कि किसी जाति के पूँजीपति दूसरी जाति के अधिकारों का दमन करने को नहीं बचे। इसके अलावा रूस में गैर-केन्द्रीय भाषाओं को जितने अधिकार प्राप्त है, उतने किसी भी बहुजातीय पूँजीवादी देश में गैर-केन्द्रीय भाषाओं को प्राप्त नहीं है। प्रत्येक गणराज्य (या रिपब्लिक) में उसकी अपनी राजभाषा है। स्वायत्त शासन-क्षेत्रों में अन्य छोटी जातियों की भाषाओं में राजकाज होता है। युद्धकाल में कानीनिन ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं से कहा था कि वे सैनिकों से उन्हीं की भाषा में बातचीत करें, तभी उनका प्रचार-कार्य सफल होगा। यू० एन० ओ० तक में उक्रेनी सदस्य अपनी भाषा का व्यवहार कर चुके हैं।

सोवियत संघ बहुजातीय देश है किन्तु वहाँ गणराज्यों की सरकारों के अलावा केन्द्रीय सरकार भी है। देश के राजकाज का संचालन करनेवाली पार्टी है जिसका संगठन-सिद्धान्त है जनवादी केन्द्रीयता। स्तालिन जार्जिया के थे लेकिन केन्द्रीय शासन और पार्टी-कार्य के लिए रूसी बोलते और लिखते थे। लुश्चेव उक्रेनी हैं लेकिन पार्टी-कांग्रेसों आदि में रूसी बोलते हैं। मिंकोयान आर्मीनियन है। उनकी स्थिति भी वही है। रूसी जाने और उसका व्यवहार किये बिना वहाँ कोई राष्ट्रीय नेता नहीं बन सकता। इससे जो निष्कर्ष निकलते हैं, वे भारत के प्रगतिशील नेताओं के ध्यान देने योग्य हैं।

सोवियत संघ में सी से ऊपर जातियाँ हैं लेकिन इनके सोलह प्रजातन्त्र या गणराज्य ही हैं। प्रत्येक भाषा को लेकर एक राज्य क्यों नहीं बना? इसका कारण यह है कि रूसी नेताओं ने भाषा-समस्या को मूल सामाजिक समस्या के अधीन माना है, उससे स्वतन्त्र नहीं। मूल समस्या है, किसान-मजदूरों की मुक्ति की, समाजवाद के विकास की। आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से यदि किसी जाति का गणराज्य निर्बल पड़ता है तो उसे दूसरे के साथ मिलकर रहना होगा, अलबत्ता उसका अपना स्वायत्त शासन-क्षेत्र होगा जिसमें उसकी अपनी भाषा का व्यवहार जायज होगा। भारत में प्रत्येक भाषा को लेकर एक राज्य बने या न बने—यह प्रश्न मूल सामाजिक समस्या से अलग रखकर हल नहीं किया जा सकता।

सोवियत संघ में प्रत्येक जाति की भाषा को विकास की सुविधाएँ प्राप्त हैं। फिर भी ये अधिकार और जातीय समानता हर जगह सौ फीसदी एक-से नहीं हैं। रूसी भाषा हर नागरिक को सीखनी होती है; रूसी-भाषियों को दूसरी भाषाएँ उसी तरह नहीं सीखनी पड़ती। गणराज्य की भाषा वहाँ के प्रत्येक नागरिक को सीखनी होती है। जिनकी वह मातृभाषा नहीं है, उन्हें भी वह सीखनी होती है। यथा उक्रेनी गणराज्य में उक्रेनी-भाषियों को मातृभाषा के अलावा रूसी सीखनी होगी; वहाँ उजबेक हों तो वे उजबेक के अलावा रूसी और उक्रेनी सीखेंगे। इस तरह हर नागरिक को बराबर भाषाएँ नहीं सीखनी होती; किसी को एक, किसी को दो, किसी को तीन या अधिक परिस्थिति के अनुसार सीखनी होती हैं।

सोवियत संघ में हर भाषा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम नहीं है। निम्न-

स्तर के राजकाज और सामूहिक कार्योंवाहों के लिए मातृभाषा का ही व्यवहार किया जाता है। उच्च शिक्षा का माध्यम बनानेवाली भाषाओं की संख्या सीमित है और इनमें भी जितना उच्च अनुसंधान और शिक्षा-कार्य रुझाव में होता है, उतना अन्य भाषाओं में नहीं। इस बात का ज्ञान मरतन से राजस्थानी, पंजाबी आदि भाषाओं के प्रति न्याय करने की समस्या हम की जा सकती है। साथ ही इन बातों पर डार देना आवश्यक है कि सभी साक्षित विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम रुझाव नहीं है। उर्दू की विज्ञान-अकादमी अपना स्वरूप जाति उर्दू की न ही प्रकाशित करती है।

मृत्यु बात यह है कि साक्षित-विज्ञान जनता की सेवा के लिए है, साक्षित शिक्षा जनता का सुनस्त्र करके उसे साम्यवाद की ओर ले जाने के लिए है। पूँजीवादी शोषण का समाप्त कर देना में साक्षित मध्य में भाषा और धर्म को लेकर दूरी नहीं होने, सभी जातियों परस्पर सहानुभूति और सहयोग का जीवन बिताती हैं। इसलिए वहाँ भाषा-समस्या भी मन्तापजनक रूप में हल कर ली गई है।

(१६६१)

## हिन्दी-उर्दू की बुनियादी एकता

किसी जाति की भाषा-समस्या पर विचार करते हुए हमे सबसे पहले उसके बोलचाल के रूप पर ध्यान देना चाहिए। क्या बोलचाल के रूप में भी हिन्दी-उर्दू दो भाषाएँ हैं ? इसमें सन्देह नहीं कि बहुत कठिन हिन्दी और बहुत कठिन उर्दू बोली जा सकती है ; लेकिन आम लोग उन्हें बोलते नहीं हैं। इसलिए प्रेमचन्दजी का यह कहना ठीक था कि “बोलचाल की हिन्दी और उर्दू प्रायः एक-सी है।” उर्दू-हिन्दी के सर्वनाम एक हैं—वह, मैं, तू, हम इत्यादि। हिन्दी-उर्दू की क्रियाएँ एक ही हैं—जाना, सोना, खाना, पीना, करना, मरना, जीना, लिखना, पढ़ना इत्यादि। आजमाना, गुजरना, लरजना जैसी क्रियाएँ बहुत थोड़ी हैं, कुल मिलाकर एक दर्जन से ज्यादा नहीं, जो फारसी-अरबी शब्दों के आधार पर बनी हैं। वे हिन्दी में मतल्क (उपेक्षित) नहीं हैं। बोलचाल में उनका प्रयोग बराबर होता है। हिन्दी-उर्दू के सम्बन्धवाचक शब्द—मे, पर, से, का आदि—वही हैं जो हिन्दी के। दोनों का मूल शब्द-भण्डार भी एक है; लेकिन यहाँ बहुत दिनों तक फारसी के राजभाषा रहने से हिन्दी शब्दों के फारसी या अरबी पर्यायवाची शब्द प्रचलित हो गए हैं—जैसे देश-मुल्क, आकाश-आसमान, धरती-जमीन, भाषा-जवान, किसान-काश्तकार, नदी-दरिया, रोगी-बीमार इत्यादि।

इन शब्दों का व्यवहार बोलचाल की हिन्दी-उर्दू में बिना किसी भेदभाव के होता है। देश, आकाश, धरती जैसे शब्द उर्दू-साहित्यकारों की रचनाओं में मिलेंगे और मुल्क, आसमान, जमीन जैसे शब्द हिन्दी-साहित्यकारों की रचना में। इसके सिवाय हल, ब्रैल, खेत, खलिहान, बीज, जुताई, बुवाई, कारखाना, मजदूर, काम, छुट्टी आदि हजारों ऐसे शब्द हैं, जिनके पर्यायवाची शब्द बोलचाल की भाषा में व्यवहृत नहीं होते, साहित्यिक भाषा में भले होते हों। लखनऊ और हैदराबाद के हिन्दू-मुसलमान बोलचाल की भाषा में फारसी शब्दों का व्यवहार ज्यादा करेंगे, उन्हीं फारसी शब्दों की जगह बिहार और मध्य प्रदेश के मुसलमान हिन्दी या संस्कृत शब्दों का प्रयोग करेंगे। यह स्थानीय भेद हुआ, इससे दो भाषाओं का निर्माण नहीं होता। हिन्दी-उर्दू का व्याकरण एक, वाक्य-रचना एक-सी, शब्द-भण्डार और क्रियाएँ एक-सी—इसीलिए हिन्दी-उर्दू-भाषियों की दो काँमें नहीं हैं। उनकी जाति एक है और बोलचाल की भाषा एक है।

हिन्दी उर्दू में सबसे पहला भेद लिपि का है। लिपि लिखने के काम आती है, न कि बोलने के। इसीलिए लिपि भेद को हम वृत्तियादी भेद नहीं मानते। हिन्दी-उर्दू में दूसरा भेद है गाना-भङ्गार का। यह भेद माधारेण लोगों की बोलचाल में बिलकुल नहीं है, परन्तु भिन्न भाषा में बहुत राडा है और भाषा के लिखित रूपों में बहुत ज्यादा है। बोलचाल में ना गाना सामान्य परिणति है, लिखन समय उनमें भी अलग-अलग करने की प्रवृत्ति देखी जाती है। धान्नी, गङ्गा, किसान, नदी, भाषा, रोगी, दण जैसे शब्द उर्दू में कम मिलेंगे। काश्मीर, दक्षिण, आम्रान, अवान जैसे शब्द साहित्यिक हिन्दी में कम मिलेंगे।

लेकिन मूल भेद दूसरा है। इसमें, राजनीति, साहित्य आदि में जब हम ऐसी गाना की जरूरत होती है, आ किनासा-मजदूरों की बोलचाल में नहीं है, तो उर्दू लेखक अर्बो-फारसी से उधार लेते हैं, हिन्दी लेखक संस्कृत में। राजनीति विज्ञान, साहित्य-अथवा लिपि सम्बन्धित, भाषाविज्ञान-लमानियात, आलोचना-ननवीद, अन्तराष्ट्रीय-अनुसन्धकामी, इतिहास-नारीय जनन-प्र-अभिरूपन, कोश-अनुगत—मुख्यतः इस तरह की गानावली हिन्दी-उर्दू में अलग-अलग करती है।

पहले यह समझ लेना आवश्यक है कि हिन्दी-उर्दू का यह अलग-अलग हमारे जातीय विकास के लिए घातक है। पहले लिखे लोग की शक्ति एक जगह सिमटकर पूरी जाति को जाग बटान के बढने बिगरे जाती है और लिपि के आधार पर पाठक-का दो हिस्सों में बट जाता है। यदि भाषा और साहित्य उच्च वर्गों के धोने-से पढ़े-लिखे आदिमियों के लिए हो रहा, तो वे चाहें उर्दू में मनोरञ्जन करें, चाहे हिन्दी में, बाकी जनता इस मनोरञ्जन से दूर रहती। लेकिन सवाल है दण के माधारेण लोगों का, मेहनत में अन्तर्पेश करने-वालों और पचकपीय योजनाएँ पूरी करनेवाला का। भाषा और साहित्य इनके लिए हैं। समाजवादी व्यवस्था में सबसे पहले डही के लिए परिवर्तन होंगे। तब यह भाषा और लिपि का बटवारा कब तक चलता ?

समाजवादी व्यवस्था के निर्माण के लिए जनता का संगठन, उसकी शिक्षा और आन्दोलन जरूरी है। यदि एक ही कारखाने के मजदूर दो लिपियों से काम लेते हैं, तो इससे उनकी शक्ति कम होगी, उनकी संस्कृति में दरारें पड़ेंगी। इनके सिवाय हिन्दुस्तानी जाति दुनिया की सबसे बड़ी जातियों में है। अंग्रेजी बोलनेवाले बहुत हैं, लेकिन वे अनेक जातियों के हैं। एक ही भाषा बोलनेवाली कोई जाति हमसे संख्या में बड़ी हो सकती है, तो चीनी है। भारत की सभी जातियों में हमारी जाति सबसे बड़ी है, यह निर्विवाद है। ऐसी स्थिति में हमारी भाषा का राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय महत्त्व है। स्पष्ट है कि हमारी भाषा अपनी पूरी ताकत से सभी प्रगति कर सकती है, जब उसमें जाति के सभी तत्वों का संयोग हो।

हिन्दी-उर्दू को एक होना चाहिए—यह हमारे ऐतिहासिक विकास की मांग है। इसके लिए आवश्यक सांस्कृतिक आधार यह है कि साधारण जनता की बोलचाल की भाषा एक है। हमें इस एकता की ओर बढ़ने के लिए मजबूर करनेवाला सामाजिक कारण

देग का पिछड़ापन, जनता की गरीबी, समाजवादी निर्माण की आवश्यकता है। इसके सिवाय यह भी याद रखना चाहिए कि भारत के हर प्रदेश का सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन अलग-अलग रहकर विकसित नहीं होता, वह अखिल भारतीय जीवन-प्रवाह की एक धारा है। और उस प्रवाह के साथ ही आगे बढ़ता है। यहाँ की भाषाएँ भी एक-दूसरे को प्रभावित करती रही हैं और करेंगी। भारत के हर जातीय प्रदेश की भाषा और लिपि एक हो, लेकिन हिन्द-प्रदेश की दो लिपियाँ और दो भाषाएँ हों, यह सम्भव नहीं है।

उर्दू बलग किसी कौम की भाषा नहीं है। इसलिए उसे इलाकाई जवान मनवाने के आन्दोलन का विरोध करना उचित है। किन्तु वह सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की साहित्यिक भाषा है, इसलिए उसे पढ़ने-पढ़ाने और उसका व्यवहार करने की सुविधा मिलनी चाहिए। राजभाषा के रूप में हिन्दी होनी चाहिए, राजकाज के लिए दो लिपियाँ और उनमें लिखी हुई दो भाषाएँ नहीं हो सकती। हिन्दी-उर्दू के शब्द-भण्डार में काफ़ी आदान-प्रदान की गुंजाइश है। हिन्दी में बोलचाल के बहुत से शब्द साहित्यिक कृतियों में छोड़ दिये जाते हैं। बहुत से मुहावरे, कहावतें, बोलचाल के शब्द ऐसे हैं जो उर्दू में हैं, लेकिन जिनका प्रयोग हिन्दी में नहीं होता, कम होता है या ग़लत भी होता है। यह सब उर्दू से हिन्दी में आएगा। हमारी साहित्यिक भाषा ज्यादा सरल और मुहावरेदार होगी।

उर्दू में संस्कृत शब्दों से जो परहेज है, उसे कम होना है। भारत की भाषाओं के लिए अरबी-फारसी का वही महत्त्व नहीं है, जो संस्कृत का है। व्याकरण और मूल शब्द-भण्डार की दृष्टि से उर्दू संस्कृत-परिवार की भाषा है, न कि अरबी-परिवार की। इसलिए अरबी से पारिभाषिक शब्द लेने की नीति ग़लत है, केवल अरबी से शब्द लेने और संस्कृत शब्दों को मतलब समझने की नीति और भी ग़लत है। भारत की भाषाएँ प्रायः संस्कृत के आधार पर पारिभाषिक शब्दावली बनाती हैं। उर्दू इन सब भाषाओं से न्यारी रहकर अपनी उन्नति नहीं कर सकती। जहाँ तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है, यह याद रखना चाहिए कि वहाँ की भाषाएँ सिन्धी, पंजाबी, पश्तो, बंगाली आदि हैं। उर्दू उनके अधिकार छीननेवाली राजभाषा है। पाकिस्तान में उर्दू का सामाजिक आधार बहुत ही संकुचित है। इसमें ज़रा भी सन्देह न होना चाहिए कि सिंध, पंजाब, पूर्वी बंगाल आदि प्रदेशों की जनता अपनी भाषाओं की रक्षा करेगी और उन्हीं के माध्यम से अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति करेगी। इसलिए यदि कोई यह सोचे कि पाकिस्तान उर्दू की रक्षा करेगा, तो यह उसका भ्रम है। पाकिस्तान बनने से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की न सामाजिक समस्याएँ हल हुईं, न उनकी भाषा-समस्या हल हो सकती है। इसीलिए उर्दू की समस्या का हल कहीं है, तो इसी हिन्द-प्रदेश में है, जहाँ की जनता में उसकी बोल-चाल का रूप कायम है।

शब्द-भण्डार में आदान-प्रदान सम्भव है, लेकिन लिपि में इसकी सम्भावना विलकुल नहीं है। उर्दू से अलिफ और हिन्दी से 'इ' लेकर कोई नई लिपि नहीं बनाई जा सकती। रोमन लिपि का सवाल नहीं है। हम अपनी लिपि छोड़कर रोमन लिपि न

अपनाएंगे। यदि रोमन लिपि कोई बहुत पूर्ण और वैज्ञानिक लिपि होनी, तो उस पर विचार भी किया जाना। हिन्दी-उर्दू के लिपि-भेद को दूर करने के लिए रामन लिपि को अपनाना वैसे ही है, जैसे हिंदी-तमिल, मराठी गुजराती या बंगला-असमिया के भगडों को दूर करने के लिए अंग्रेजी का यहाँ राजभाषा बनना।

उर्दू लिपि के व्यवहार के लिए पूर्ण स्वाधीनता देने हुए प्रगतिशील विचारकों को चाहिए कि उर्दू-नामियों का देवनागरी लिपि सिगाएँ। देवनागरी लिपि में उर्दू की जिह्नी किताब छप रही है, उन्हें देखते हुए यह अनुमान होता है कि आगे चलकर देवनागरी लिपि में ही उर्दू के लेखकों की रचनाएँ छपेंगी। मापन-प्रसार के साथ और दक्षिण में हिन्दी प्रचार के साथ हिन्दी पुस्तकों के लिए एक बहुत बड़ा बाजार तैयार हो गया है। यह तामसिक है कि उर्दू के हाशियार पंजाबी लेखक इस म्युनि में पायदा न उठाएँ। सीधो मुनाफे की बात है। उर्दू में किताब छपेगी कम विकेगी, हिन्दी में छपेगी ज्यादा विकेगी। यह एक तरह का जायिक दवान है, जिसमें देवनागरी लिपि को उर्दू लेखक अपनाएँगे।

इस प्रकार सामाजिक जीवन की परिस्थितियाँ हिन्दी-उर्दू को बराबर एक-दूसरे के नजदीक लानी गयी हैं। सिनेमा और रंगमंच के लिए लिखनेवाले शुद्ध हिन्दी-उर्दू का ख्याल रखें तो उनकी रचनाएँ असफल होंगी। किरानों और मजदूरों में राजनीतिक काम करनेवाला का मजदूरन ऐसी सरल भाषा का प्रयोग करना पड़ता है, जिसे हिन्दू-मुसलमान दोनों समझें। जन-आन्दोलन की एकता हिन्दी-उर्दू के रूप पर बराबर असर डाल रही है, और इसीलिए हम यह दृढ़ विश्वास है कि ये दोनों रूप अपने अन्तर्गत एक ही साहित्यिक भाषा के विकास में सहायता करेंगे।

(१९६१)

## राष्ट्रीय एकता और अंग्रेज़ी

राष्ट्रभाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे देश की बहुसंख्यक जनता जानती हो और जो लोग उसे न जानते हों, वे उसे आसानी से सीख सकें। यह दृष्टिकोण राष्ट्रीय ही नहीं जनतांत्रिक भी है क्योंकि बहुसंख्यक जनता द्वारा बोली-समझी जानेवाली भाषा के पक्ष में दिये जानेवाले तर्कों के पीछे भावना यह है कि राष्ट्रीयता मुट्ठी-भर अंग्रेज़ी पढ़े-लिखे लोगों को बपीती नहीं है, उसका सम्बन्ध देश की बहुसंख्यक जनता से है।

पं० जवाहरलाल नेहरू ने बीस-वाइस साल पहले लिखा था, "प्रान्तीय भाषाओं के अधिकार-क्षेत्र की सीमाओं का जरा भी उल्लंघन किये बिना हमारे लिए आवश्यक है कि अखिल भारतीय व्यवहार की एक सामान्य भाषा हो। कुछ लोग सोचते हैं कि अंग्रेज़ी ऐसी भाषा बन सकती है; एक हद तक हमारे उच्च वर्गों के लिए और अखिल भारतीय राजनीतिक कार्यों के लिए अंग्रेज़ी ऐसी भाषा बनी भी है। किन्तु यदि हम आम जनता को ध्यान में रखकर सोचें तो यह बात स्पष्ट ही असम्भव प्रतीत होगी। हम करोड़ों लोगों को एक नितान्त विदेशी भाषा द्वारा शिक्षित नहीं कर सकते।" (नेशनल लैंग्वेज फॉर इंडिया—ए सिम्पोजियम, इलाहाबाद, १९४१; पृ० ४६-५०)

यदि राष्ट्रीयता उच्च वर्गों तक सीमित कर दी जाय, यदि जनतंत्र का उद्देश्य मुट्ठी-भर लोगों का ऊँची सरकारी नौकरियाँ पाना हो, तो अवश्य अंग्रेज़ी ही राष्ट्रभाषा रहेगी जैसे कि वह पिछले पन्द्रह वर्षों (या और भी पहले से) रही है। अंग्रेज़ी को हटाने और हिन्दी को व्यवहार में राष्ट्रभाषा बनाने का प्रश्न राष्ट्रीयता को व्यापक बनाने, राज्यसत्ता को जनतांत्रिक रूप देने का प्रश्न है। जितने ही दिन अंग्रेज़ी अमली राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित रहती है, उतने ही दिन राष्ट्रीयता का आधार क्रमशः संकुचित होता जाएगा, राज्यसत्ता जनता का विशद सम्पर्क और समर्थन खोती जाएगी। अनिश्चित काल के लिए अंग्रेज़ी को राष्ट्रभाषा बनाये रखने का अर्थ है, निश्चित रूप से जनतंत्र के आधार को संकुचित करते जाना और अन्त में उसे निर्मूल कर देना।

पराधीन भारत में ऊँची सरकारी नौकरियाँ पाने का अर्थ होता था, जनता पर हुकूमत करना। स्वाधीन भारत में सरकारी नौकरियों का अर्थ होना चाहिए जनता की सेवा करना। जिस भाषा को देश की जनता का एक प्रतिशत भाग समझता है, उससे



विज्ञान जनता की सेवा कैसे हो सकती है ? आज भी बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में—पंजाब और कानौर की तो बात ही क्या—विज्ञान लोग हिन्दी समझते हैं, उन्हें अग्रजो नहीं। अंग्रेजी न जाननेवाले इन करोड़ों अहिन्दी भाषियों की सेवा कैसे की जा सकती है ? जो लोग जानते हैं हिन्दी के माध्यम में अधिक कर सकते हैं या अंग्रेजी द्वारा

कम मात्र राष्ट्रीय एका—या भाषा एक एका—अंग्रेजी के माध्यम से दुः  
करन या स्वयं करने हैं। यदि राष्ट्रीय एका का अर्थ मुट्ठी भर अंग्रेजी पढ़-लिख समी  
का करना है तो सम्भव है, वह अंग्रेजी से दुः हो। यद्यपि अंग्रेजी में ज्ञान की बसत देख-  
कर यह सम्भवना भी बहुत विवर्तनीय नहीं जान पड़ती। किन्तु यदि राष्ट्रीय एका का  
अर्थ जन-साधारण की एका है तो उसे दुः करने में अंग्रेजी बाधक ही हो सकती है,  
साध्य नहीं।

राष्ट्रीय गौरव की भावना के बिना भाषा एक एका की कल्पना नहीं की जा  
सकती। जिस राष्ट्र की अपनी भाषा न हो, जो राष्ट्र भाषा के पद पर एक विदेशी भाषा  
को बिठाए हो उसका नागरिकों में राष्ट्रीय गौरव की भावना कैसे दुः हो सकती है ?

अंग्रेजी के पक्ष में जो मुख्य तर्क दिया जाता है कि अंग्रेजी एक विकसित और समृद्ध भाषा है किन्तु हिन्दी तथा अन्य सभी भारतीय भाषाएँ अविकसित और दरिद्र हैं—राष्ट्रीय गौरव की भावना पर कुठाराघात करता है। अंग्रेजी के विकास और समृद्धि  
ए गीत गाकर राष्ट्रीय गौरव को जगाने और भावात्मक एका दुः करने के लिये मेधावी लोग  
विपणन करके अमर होने का स्वप्न देख रहे हैं। यदि महात्मा भारती, रवीन्द्रनाथ ठाकुर,  
बालगंगाधर तिलक, प्रेमचन्द आदि साहित्यकार अंग्रेजी की समृद्धि से इसी तरह आकर्षित होते  
तो भारतीय साहित्य का बड़ा संभवधार म कभी का डूब चुका होता।

हम न दूसरा ही तुलना में अपने का अकारण दशा बताकर डींग हाँकी हैं, न धीनभाव से अकारण अपने को सबसे पिछड़ा हुआ मानने को तैयार हैं। पश्चिमी यूरोप ने विज्ञान में अधिक उल्लस की है किन्तु साहित्य में हम यूरोप से बचकर नहीं तो घटकर भी नहीं हैं। विशेषकर पिछले सौ वर्षों में भारतीय साहित्य ने जो उन्नति की है, वह पश्चिमी यूरोप के किन्हीं भी देश के लिए स्तब्धीय हो सकती है।

वास्तव में समस्या साहित्यिक समृद्धि की नहीं है समस्या है राष्ट्रीय आत्मगर्मान और जनता की सेवा भावना की। जिस देश हमसे अधिक विकसित नहीं है किन्तु वहाँ की राष्ट्रभाषा अरबी है। सोवियत संघ में कजाख उजबेक ताजिक आदि भी अपनी भाषाओं की शिक्षा, राजनीतिक कार्यों आदि के लिए प्रयुक्त करते हैं। चीन तकने चीनी का राष्ट्रभाषा बना रखा है। समार में सबसे प्राचीन लिपि का धनी भारत स्वाधीन होने पर भी अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा बनाये रहे, इससे अधिक सज्जात्पद बात और क्या हो सकती है ?

यह ध्यान देने की बात है कि जो लोग अंग्रेजी को विकसित और समृद्ध कहकर उन

राष्ट्रभाषा बनाये रखना चाहते हैं, वे न केवल हिन्दी को, वरन् सभी भारतीय भाषाओं को न्यूनाधिक दरिद्र और अविकसित मानते हैं। हिन्दी के लिए हमारा संघर्ष, अंग्रेजी के विरुद्ध सभी भारतीय भाषाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष है। अंग्रेजी भारत में साम्राज्यवादी ढंग से प्रतिष्ठित है। वह प्रत्येक प्रदेश में वहाँ की भाषा के अधिकार छीनती है, उसे उच्च शिक्षा का माध्यम बनने से रोकती है; राजकाज में, उच्च न्यायालयों में वहाँ की भारतीय भाषा को अपदस्थ करती है। अंग्रेजी की यह साम्राज्यवादी स्थिति सारे देश में देखी जा सकती है; कागज पर कुछ भी लिखा हो, व्यवहार की बात दूसरी ही है।

इसके विपरीत हिन्दी के समर्थकों का कहना है कि प्रत्येक प्रदेश में वहाँ की भाषा को उचित अधिकार मिले, वहाँ के समस्त राजकाज में, शिक्षा-केन्द्रों, न्यायालयों आदि में वह प्रयुक्त हो, केवल विभिन्न प्रदेशों में आपसी व्यवहार के लिए, केन्द्रीय राज्य-सत्ता और उसकी संस्थाओं के लिए हिन्दी का व्यवहार हो। यह स्थिति साम्राज्यवादी नहीं है, वरन् जनताधिकार और राष्ट्रीय है। प्रत्येक प्रदेश की भाषा को अंग्रेजी के स्थान पर राजनीतिक-सांस्कृतिक कार्यवाही का माध्यम बनाना जनतन्त्र की भावना के अनुकूल है। इन विभिन्न प्रदेशों के बीच तथा केन्द्र में हिन्दी का व्यवहार करना राष्ट्रीयता की भावना के अनुकूल है। भाषागत साम्राज्यवाद अंग्रेजी का है, न कि हिन्दी का। विभिन्न भारतीय भाषाओं के अधिकारों को इस समय पददलित कर रही है अंग्रेजी, न कि हिन्दी। अंग्रेजी की वास्तविक साम्राज्यवादी स्थिति को भुलाकर जो लोग कल्पित हिन्दी-साम्राज्यवाद से जनता को आतंकित करते हैं, वे राष्ट्रीय एकता दृढ़ करने के बदले राष्ट्रीय विघटन को जबरदस्त प्रोत्साहन देते हैं।

अंग्रेजी से सभी भारतीय भाषाओं के हित टकराते हैं, हिन्दी से किसी भी भारतीय भाषा के हित नहीं टकराते; अंग्रेजी के जानने-समझनेवाले मुट्ठी-भर हैं, हिन्दी बोलने-समझनेवाले करोड़ों हैं; अंग्रेजी कायम रखने में जनता पर हुकूमत करनेवालों का निहित स्वार्थ है; हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने से विशाल जनता की सेवा करने का अवसर मिलता है; अंग्रेजी राष्ट्रीय गौरव की भावना पर कुठाराघात करती है, हिन्दी राष्ट्रीय आत्मसम्मान को जाग्रत और पुष्ट करती है इसलिए हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि अंग्रेजी अनिश्चित काल के लिए एकमात्र या सह-राष्ट्रभाषा नहीं रहेगी, निश्चित और सीमित अवधि में ही उसे अपना स्थान छोड़ना होगा।

राष्ट्रभाषा हिन्दी के विरुद्ध जितने तर्क दिये जाते हैं, उनमें जरा भी मौलिकता नहीं है, वे पराधीन भारत में भी दिये जाते थे, अन्तर केवल इतना है कि तब ऐसे तर्क देने-वालों को अराष्ट्रीय कहा जाता था। अंग्रेजों के चले जाने पर मुसलमानों और अच्छतों को सर्वण हिन्दू खा जाएंगे, दक्षिणवालों पर उत्तरवाले अपना आतंक फैलाएंगे, हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने से भारत की सांस्कृतिक उन्नति रुक जाएगी—ये सब तर्क ऊँची सरकारी नौकरियों के अंग्रेज-भक्त उम्मीदवार पहले भी दिया करते थे। अब इस तरह के तर्क अंग्रेजी-भक्त शासक या शासकपद के उम्मीदवार दिया करते हैं। इन सब तर्कों का सार-

तरफ यह है कि मातृभाषा का बड़ा भी मान्य होगा, कॉलेज में पढ़ेगा और अंग्रेज़ों की तरह अंग्रेज़ी बोलागा, बनावतुल्य आनन्दवाना घर टुकूमन करेगा।

अंग्रेज़ी प्रमाणात्मकता की न्य है कि अंग्रेज़ी के राष्ट्रभाषा न रहने पर राज्यसभा उनके हाथ में न रहता। यह सब इस समय काफी प्रभावशाली है किन्तु देश की विभाजन समस्या का सामना उसकी शक्ति नाश्वर्य है। जो लोग भी अपनी मातृभाषा में प्रेम करते हैं, उनकी मान्यता चाह हिन्दी है, चाह कोई अहिन्दी-भाषा, उनका मतलब है कि विभिन्न प्रान्तों में प्रत्येक की जगह वहाँ की प्रादेशिक भाषाओं को प्रतिष्ठित करें और केन्द्रीय भाषा के रूप में अंग्रेज़ी का जगह हिन्दी का व्यवहार करें।

हिन्दी पिछड़ी हुई भाषा है इसलिए उसे विकसित होने का अवसर देना चाहिए, यह जायसिया का तर्क है। हिन्दी में कितने आवश्यक शब्द हैं तथा कितने और होने चाहिए—इस समस्या की कोई वैज्ञानिक जाँच-पड़ताल अभी तक नहीं हुई। यदि भारत का किसी भी भाषा का समुद्र माना जाय तो हम उसमें पारिभाषिक शब्द लेने की तयारी है क्योंकि जो शब्द ज्ञान पारिभाषिक शब्दों का है, वही उसके शब्दों का होगा—अर्थात् सम्पूर्ण (उत्तर का श्रावण)।

हिन्दी पिछड़ी हुई भाषा है, यह तक के लोग देते हैं, जो भारत की प्रत्येक भाषा का पिछड़ा ज्ञान मानते हैं। राष्ट्र के लिए इससे अधिक अपमानजनक दूसरा दृष्टिकोण हो नहीं सकता। आज से पैंतीस वर्ष पहले अंग्रेज़ भाषाविद प्रियमन ने हिन्दी के बारे में अपने प्रसिद्ध पुस्तक 'लिम्बिन्टिक सर्वे' की भूमिका में लिखा था, "इट हैज ऐन एनारमस नैटिव वर्कबुकरी लैंग्वेज व्हिच नो अपरटस फॉर द एक्स्प्रेसन ऑफ़ ऐम्ब्रुवेट टर्म्स" (देशाभाषा का उसका विभाग शब्द-भण्डार है और सूक्ष्म धारणाएँ प्रकट करने के लिए पूर्ण पारिभाषिक शब्दावली है।) प्रियमन ने उन लोगों की आलोचना की थी, जो हिन्दी शब्दों का छाड़कर मस्तिष्क के कठिन और दुर्लभ शब्दों की ओर भागते थे और इसी प्रसंग में लिखा था—'यट इ ग्राइट आफ हिन्दी पब्लिसिंग सच ए वर्कबुकरी एण्ड ए पावर ऑफ़ एक्सप्लेशन नोट इंपीरियर टु इमिनेट इट हैज विक्रम द फंडेशन' "(यद्यपि हिन्दी के पास ऐसा शब्द भण्डार है और व्यञ्जना-शक्ति में वह अंग्रेज़ी से घटकर नहीं है, फिर भी यह फंडेशन हो गया है)। जो लोग अंग्रेज़िमत में अंग्रेज़ी के कान काटते हैं, वे यह कभी न मानें कि व्यञ्जना शक्ति में हिन्दी अंग्रेज़ी से घटकर नहीं है।

यूरोप और अमरीका में भारतीय मस्तिष्क के अग्रदूत महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने मुद्रांती साहित्य परिषद् के छठे अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था, "आपकी सेवा में खड़ा होकर विदेशीय भाषा कहूँ यह हम चाहते नहीं। पर जिस प्रांत में मेरा घर है वहाँ मैं कभी न कहने लायक हिन्दी का व्यवहार नहीं। महात्मा गांधी महाराज की भी आज्ञा है हिन्दी में कहने के लिए। यदि हम समय होता तब हमसे बड़ा आनन्द और कुछ हुाना नहीं। असमय होने पर भी आपकी सेवा में दासता हिन्दी में बोलूंगा।" ('प्रभा', कानपुर, मार्च, १९२४)

जो लोग उठते-बैठते गांधीजी के नाम की माला जपते हैं और जिन्होंने अखिल भारतीय पैमाने पर रवीन्द्र-जयन्ती-समारोह संगठित किया था, वे कृपया विचार करें कि वे अपने व्यवहार में गांधी-रवीन्द्रनाथ के मार्ग से कितनी दूर आ पड़े हैं। महाकवि ने अपनी असमर्थता प्रकट की, किसी भाषा को असमर्थ नहीं कहा; गांधीजी ने गुजरातियों के बीच उनसे अंग्रेजी में नहीं, हिन्दी में बोलने को कहा।

राष्ट्रीय एकता को दृढ़ करने का यही एक मार्ग सन् '२५ में था, वही मार्ग अब सन् '६२ में भी है। और दूसरे रास्ते सब गलत हैं।

(१९६२)

## राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय प्रभुसत्ता

सन् ६५ में हिन्दी के द्वीय राजकाज की भाषा न बनेगी। बच बनेगी, यह अंग्रेजी-प्रेमी भारतवासियों की इच्छा पर निर्भर है। इस पर भी कुछ सज्जन असन्तुष्ट हैं। असन्तुष्ट इस बात पर हैं कि अंग्रेजी सदा-सर्वदा के लिए भारत की एकमात्र राष्ट्रभाषा घोषित नहीं की गई। हो सकता है, दो-चार शताब्दियों बाद लोग हिन्दी को राष्ट्रभाषा बना दें। इस सम्भावना को रहने ही क्यों दिया जाए ?

एना मोक्षनेवाले सज्जन अंग्रेजी के माध्यम से शासनतन्त्र पर अपना इजारा हमेशा के लिए पक्का कर लेना चाहते हैं। वे और उनके भाई-भतीजे तो इस युग में शासन की बागडोर संभाल ही हुए हैं, वे चाहते हैं कि युगो-युगो तक उन्हीं की तरह उनके वंशज भी—यानी मुट्ठी भर विदेशी भाषा के उपासक—शासन की बागडोर इसी तरह मजबूती में धाम रहे। कुछ दिन हुए ऐसे लोगों को सन्ध करके मद्रास में प्रधानमंत्री ने प्रदत्त किया था—क्या उनमें राष्ट्रीय आत्मसम्मान की भावना का एकदम लोप हो गया है ?

इस प्रश्न से नतीजा यह निकलता है कि जो लोग थोड़े समय के लिए अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा मानते हैं, उनमें उन ही समय के लिए आत्मसम्मान का लोप होता है, जो लोभ मदा के लिए अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा बनाये रखना चाहते हैं, उनमें सदा के लिए आत्मसम्मान का लोप हो जाता है। सदा के लिए आत्मसम्मान खोने से अच्छा है उसे थोड़े समय के लिए खाया जाए। भले ही इस थोड़े समय की अवधि का प्रसार विस्तार होता जाए—सन् '४६ से '६५ तक, '६५ से बीसवीं सदी के अन्त तक, बीसवीं सदी के बाद इक्कीसवीं सदी के अन्त तक, और इसी तरह अनिश्चित काल के लिए आगे भी। मुख्य बात यह है कि अनिश्चित काल को निश्चित न किया जाए, वरना राष्ट्रीय आत्म-सम्मान से या सापेक्ष लोप घातक और निरपेक्ष हो जाएगा।

एक बहुत दिलचस्प सवाल यह पैदा होता है कि 'राष्ट्रीय आत्मसम्मान का यह लोप भाषा के क्षेत्र तक सीमित है या वह देश के राजनीतिक, आर्थिक आदि अन्य क्षेत्रों में भी पाया जाता है ? क्या आगे के इतिहास में किसी ऐसे देश का नाम सुना है जो आर्थिक और राजनीतिक रूप से पूर्ण स्वाधीन रहा हो किन्तु जो भाषा के क्षेत्र में परमुखापेक्षी रहा ? क्या वर्तमान काल में कोई ऐसा देश है जो स्वाधीन होने हुए भी अपनी

भाषा छोड़कर विदेशी भाषा का व्यवहार करता हो ? इन स्वाधीन देशों में इस ज्ञात को लेकर पंचायत नहीं जुड़ता कि विश्व की सबसे समृद्ध भाषा कौन-सी है, देश की भाषा को हटाकर उसके बदले विश्व-भाषा का व्यवहार कब तक किया जाय । आखिर जर्मन, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, इतालवी, स्पेनी आदि भाषाएँ समान रूप से तो समृद्ध हो नहीं सकतीं । किन्तु जहाँ ये भाषाएँ बोली जाती हैं, वहाँ यह प्रश्न कोई नहीं करता कि सबसे समृद्ध विश्वभाषा को राजकाज की भाषा क्यों न बनाया जाय ? यह प्रश्न केवल उन देशों में सामने आता है जो पश्चिमी राष्ट्रों के उपनिवेश हैं, या रह चुके हैं । कुछ लोग कहते हैं कि हिन्दी से चिपके रहना और अंग्रेजी का विरोध करना कूप-मडूकता है । मालूम होता है कि अपनी भाषा से प्रेम करनेवाले तो कुओं में पड़े हैं । केवल भारत के अंग्रेजी-प्रेमी मण्डूक कुएँ से बाहर निकलकर अपनी अनोखी अंग्रेजी-ध्वनि से दशों दिशाएँ गुजरित कर रहे हैं ।

आर्थिक स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए तो पैसा-काँड़ी दरकार होता है, स्वर्ण की आवश्यकता होती है । किन्तु शब्द-ब्रह्म तो अमूल्य है । बात करने में क्या खर्च होता है ? फिर भारत में संस्कृत की कृपा से किसी भी भाषा के शब्द-भण्डार को यथेच्छ भरने में विलम्ब नहीं होता । भाषा के क्षेत्र में परमुखापेक्षी होना परले सिरे की गुलामी है । जो भाषा के क्षेत्र में स्वाधीन नहीं हो सकता, वह अन्य क्षेत्रों में क्या स्वाधीन होगा ? भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, सुब्रह्मण्य भारती, निराला, प्रेमचन्द आदि साहित्यकारों ने देश के पराधीन रहते हुए भी भाषा के क्षेत्र में उसकी प्रभुत्ता की रक्षा की । भाषा के क्षेत्र में भारतीय साहित्यकारों ने अंग्रेजी का प्रभुत्व कभी स्वीकार नहीं किया । स्वाधीनता-नूर्य की किरणों ने सबसे पहले भाषा के क्षेत्र को प्रकाशित किया । आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों के नेता साहित्यकारों के अनुगामी रहे हैं, उनके पथ-निर्देशक नहीं ।

आये दिन जो राजनीतिज्ञ हिन्दी-प्रेमियों को सकीर्ण और संकुचित विचारवाला कहते हैं, जो हिन्दी से विमुख और अंग्रेजी के मुखापेक्षी वसुधैव कुटुम्बकम् का उपदेश देते नहीं सकते, उनसे पूछा जा सकता है—देश में अन्न का क्या हाल है ? भुखमरी से बचने के लिए आपको अन्य राष्ट्रों का दरवाजा तो खटखटाना नहीं पड़ता ? अपनी पंचवर्षीय योजनाओं की पूर्ति के लिए आपको विदेशी वहीखाता में कर्जदार बनकर नाम लिखाना तो नहीं पड़ता ? देश-रक्षा के लिए आप विदेशी अस्त्र-शस्त्रों के मोहताज तो नहीं हैं ? आपके आयात-निर्यात व्यापार में विदेशी पूँजी का ताना-बाना बुना हुआ तो नहीं है ? आप विदेशी दवाव के कारण कश्मीर-जैसे किसी प्रदेश की भूमि का विनिमय करने की ओर तो नहीं बढ़े ?

पुराने जमाने में लोग कहते थे—अंग्रेजी हमारी गुलामी की निशानी है । ऊपर के प्रश्न पढ़कर बताइए वह बात अब भी सही है या नहीं ? क्या आप समझते हैं कि दासता की मनोवृत्ति केवल भाषा के क्षेत्र में प्रतिफलित होती है, अंग्रेजी को हटाने का प्रश्न केवल एक भाषागत समस्या है ? गुलाम तो गुलाम । उसकी गुलामी न केवल उसके बोलने से प्रकट होगी वरन् उसके हर तरह के आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार से प्रकट होगी ।

राष्ट्रभाषा की समस्या कोई विगुड़ भाषा-विज्ञान की समस्या नहीं है। वह मूलतः देश की प्रभुमत्ता की समस्या है। यह तो सम्भव है कि केन्द्रीय राजराज के लिए एक से अधिक भाषाओं का व्यवहार किया जाय, किन्तु देश की प्रभुमत्ता के लिए यह अमम्य है कि सभी भारतीय भाषाओं के अधिकारों को पैंगों तने रोँदकर अंग्रेजी उन सबके ऊपर प्रतिष्ठित हो। जो लोग यह कहते हैं कि हिन्दी के माध्यम से बड़े-बड़े पूजापति छोटी-छोटी अतिरिक्त भाषा जानिया का दवाना है, व यह कभी नहीं कहते कि अंग्रेजी के माध्यम से गांधीजीवादि भाषा की नयी जानिया को दवाना है, यहाँ की सभी भाषाओं के स्वार्थों का अपहरण करना है।

हिन्दी का केन्द्रीय भाषा बनाने में कुछ बड़े पूजापतियों का स्वार्थ हो सकता है, यद्यपि ऐसा नहीं जाना है कि अंग्रेजी के दैनिक पत्रों की शृङ्खलाएँ इन्हीं बड़े पूजापतियों के हाथ में हैं। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि हिन्दी का केन्द्रीय भाषा बनाने में छोटे पूजापतियों तथा धार्मिक जनता का हित सबसे ज्यादा है। हिन्दी के बिना सामान्य जनता गामनन्त्र, केन्द्रीय राजराज में भाग नहीं ले सकती। वह राजनीतिक और सांस्कृतिक कायवाही में अल्पजा के समान दूर रहती जानी है। इस तरह हमारे जनतन्त्र का आधार मकुचित रहता है हमारी राष्ट्रियता मुट्ठी-भर अंग्रेजी पढ़े लोगों के हाथ का तिलीना बनी रहती है।

जो लोग अंग्रेजी को हटाना चाहते हैं, हिन्दी को केन्द्रीय भाषा बनाने के लिए जल्दी करते हैं उन्हें 'हिन्दी-ग्युजिऐस्ट' आदि उपाधियों से विभूषित किया जाता है। माना अपनी भाषा का सम्पन्न करना गुनाह हो, 'अंग्रेजी एग्युजिऐस्ट' होना कोई बहुत बड़ा पुण्य है। केन्द्रीय भाषा के पद में अंग्रेजी को हटाने में किसी एक भारतीय भाषा का स्वार्थ नहीं है। अंग्रेजी की वर्तमान स्थिति से सभी भारतीय भाषाओं की प्रतिष्ठा को घबका लगता है, उनकी अधिकार-मर्यादा नष्ट होती है। इसलिए अंग्रेजी के विरुद्ध सघर्ष आज सभी भारतीय भाषाओं की अधिकार-रक्षा का सघर्ष है। इन भाषाओं के बीच परस्पर आदान प्रदान के लिए हम हिन्दी का व्यवहार चाहते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करते हुए, न कि उनके अधिकारों को रोँदकर। अधिकारों को रोँदने का काम अंग्रेजी कर रही है, न कि हिन्दी।

प्रत्येक जानि का यह जमसिद्ध अधिकार है कि वह अपनी सांस्कृतिक, राजनीतिक, हर तरह की सामाजिक कायवाही अपनी भाषा के माध्यम से सम्पन्न करे। हर तरह के राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय व्यवहार में अपनी भाषा का प्रयोग उसकी प्रभुमत्ता की उभुक्त घोषणा है। जातीय भाषा का व्यवहार राष्ट्र के स्वाधीन होने की पहचान है। भाषा के समृद्ध या दरिद्र होने से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। ससार के किसी देश ने किसी समय यह नियम स्वीकार नहीं किया कि विश्व की सबसे समृद्ध भाषा को वह राष्ट्रभाषा बनावेगा। ऐसा नियम होता तो सारे ससार में संस्कृत, ग्रीक या लैटिन का ही प्रभुत्व होता।

हिन्दी समृद्ध है या दरिद्र है, यह तय करने के लिए कोई वैज्ञानिक कसौटी नहीं अपनायी गई। उदाहरण के लिए, हिन्दी में राजनीतिक शब्दावली कम है या पर्याप्त है, यह जानने के लिए कोई शब्द-गणना नहीं की गई। एक प्रवाद फैला दीजिए, दस राजनीतिज्ञ उस प्रवाद को दोहरा दें, अंग्रेजी अखबारों में वह प्रवाद छप जाय, वस उसे प्रमाणित सत्य मान लिया जाएगा। देश में प्रचार के साधना का इतना केन्द्रीयकरण है कि नक्कार-साने में हिन्दी-सम्बन्धी सत्य की पुकार तूती की आवाज में अधिक कारगर साबित नहीं होती।

शासनतन्त्र चलानेवाले बुद्धिजीवी अंग्रेजी में अथवा किसी देगी भाषा में अंग्रेजी शब्दों की मिलावट करके चिन्तन का काम पूरा करते हैं। उनकी अभिव्यंजना का माध्यम अंग्रेजी या यह खिचड़ी भाषा होती है। आप यह न समझे कि पारिभाषिक शब्दों के अभाव के कारण वे ऐसा करते हैं। उनके वच्चे बोलना सीखते हैं, पापा, डैडी, मम्मी, अंकल, आण्टी जैसे पारिभाषिक शब्दों के ज्ञान के साथ। “जरा फादर को रिसीव करने जा रहा हूँ,” “उसका रिमार्क ऐसा मिला था कि माई ब्लड बिगैन टु बॉयल”; “आजकल आप पोलिटिकल ऐक्टिविटी से इतने इण्डिफरेंट क्यों रहते हैं”; “एजुकेशन का स्टैंडर्ड इतना गिर गया है कि आर्डिनरी एप्लीकेशन लिखने में एम० ए० पास लोग मिस्टेक करते हैं”—इस तरह के वाक्य उत्तर भारत के अनेक शहरों में आप सुन सकते हैं। इन वाक्यों में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग पारिभाषिक शब्दों की कमी के कारण नहीं है। मानसिक शिथिलता, अंग्रेजी शब्दों का मोह, अपनी भाषा के प्रति अवज्ञासूचक दृष्टिकोण—इन कारणों से उस तरह के भोड़े वाक्यों की रचना होती है। इन्हीं कारणों से अंग्रेजी-प्रेमी बुद्धिजीवियों को यह तय करने में देर नहीं लगती कि अंग्रेजी समृद्ध है, हिन्दी दरिद्र है।

एक समिति में लोग आलोचना-सम्बन्धी शब्द-सूची एकत्र कर रहे थे। समिति के अधिकांश सदस्य न हिन्दी के आलोचक थे, न हिन्दी-आलोचना से परिचित थे। फिर भी वे इस काम में लगे हुए थे क्योंकि वे समिति के सदस्य बना दिये गए थे। शब्द-संग्रह करने का तरीका क्या था? आप शायद सोचें कि हिन्दी की आलोचना-पुस्तकों से अथवा संस्कृत के सिद्धान्त-ग्रन्थों से ऐसी शब्द-सूची सकलित की जा रही थी। समिति के सामने काम दूसरा था। काम हिन्दी-शब्दों की सूची बनाना न था, काम था अंग्रेजी शब्दों के हिन्दी पर्याय निश्चित करना। इस तरह की सूची बनाने की जरूरत क्यों हुई? इसलिए कि अंग्रेजी का आलोचना-शास्त्र अधिक समृद्ध है, उसके शब्द-भण्डार के अनुरूप हिन्दी पर्याय स्थिर करके ही राष्ट्रभाषा को समृद्ध किया जा सकता है। आप समझ सकते हैं, समिति में इस पद्धति का विरोध करनेवाले को किसी का समर्थन प्राप्त न हुआ होगा।

प्राकृतिक परिवेश, सामाजिक परिस्थितियाँ, दैनिक जीवन की आवश्यकताएँ विभिन्न देशों में बहुत-कुछ समान हैं। इसलिए उनके शब्द-भण्डार में अर्थ-सम्बन्धी बहुत बड़ी समानता है। किसी भी भाषा के हजारों शब्दों के लिए दूसरी भाषा में उन्हीं के समानार्थी शब्द मिल जाते हैं। यातायात के साधनों में प्रगति होने से, व्यापार, उद्योग-



षाओं और विज्ञान में उन्नति होने से (और उन्नति करने के लिए) अनेक देश एक-दूसरे के अधिक निकट आये हैं। इसलिए ऐसे शब्दों की सख्या बहुत बड़ी है जो रूप में भिन्न हान हुए भी अर्थ में समान हैं। हिन्दी में भी उद्योग, व्यापार, राजनीति आदि से सम्बन्धित हजारों शब्द प्रचलित हैं जो उसी कोटि के अंग्रेजी या जर्मन शब्दों के समानार्थी हैं।

इसके साथ यह भी सही है कि प्रत्येक देश के प्राकृतिक परिवेश, सामाजिक परिस्थिति, दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की अपनी विशेषताएँ हैं। इसलिए प्रत्येक भाषा में हजारों शब्द ऐसे मिलेंगे जिनके ठीक समानार्थी शब्द दूसरा भाषाओं में दुर्लभ होंगे। किन्तु भाषा प्राकृतिक या सामाजिक परिवेश का दर्पण मात्र नहीं है। भाषा प्रत्येक ज्ञान की विविध चिन्तन प्रक्रिया, उसमें रसबोध, भाव सम्बन्धी प्रतिविया का दर्पण भी होती है। इस दृष्टि से विचार करने पर पता चलेगा कि कोई भी भाषा किसी से घटकर नहीं है, प्राणि-जगत् की प्रत्येक जीव योनि के समान सत्कार की प्रत्येक भाषा की अपनी विशेषता है।

इस देश के लोगो ने अनेक शताब्दियों तक मनुष्य के मन पर, उसकी चेतना पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है। दार्शन और मनोविज्ञान के क्षेत्रों में अनेक धारणाओं का जैसा सूक्ष्म भेद सस्कृत शब्द प्रकट करते हैं, वैसा सत्कार की कोई भाषा प्रकट नहीं करती, कम-से-कम ग्रीक, लैटिन और इनमें प्रभावित यूरोप की भाषाएँ तो अवश्य नहीं करती। सस्कृत की वह शब्द-सम्पदा भारत की समस्त भाषाओं की सामान्य सम्पत्ति है। उन लोगो के सामाजिक पतन का अनुमान कीजिए जो 'मिडिलेन' के लिए अपनी शब्द-सूची में 'ध्यान' शब्द बिठाकर यह समझ लेते हैं और दूसरा को समझाने भी हैं कि 'ध्यान' जब 'स्टैण्ड' शब्द हो गया, 'मिडिलेन' का पर्याय बनकर। इसके बाद वे कहते हैं कि जो पुस्तकें लिखी जाएँ या अनुवादित की जाएँ, उनमें 'ध्यान' शब्द उसी अर्थ में प्रयुक्त होना चाहिए जिसमें अंग्रेजी का 'मिडिलेन' शब्द प्रयुक्त होता है। और 'समाधि' के लिए अंग्रेजी का कोई पर्याय न हुआ तो वह बेचारा स्टैण्ड-ध्यान लेकर शब्द-संग्रह के बाहर पड़ा रह गया।

भारतीय शब्द 'राष्ट्र' का ठीक समानार्थी अंग्रेजी शब्द 'नेशन' नहीं है। सोवियत मध्य में एक से अधिक 'नेशन' हैं किन्तु वह 'राष्ट्र' एक है, अनेक नहीं। 'राष्ट्र' में केवल मनुष्यों का बोध नहीं होता जैसा कि 'नेशन' में होता है। 'नेशन' किसी देश की भूमि को नहीं कह सकते, किन्तु 'राष्ट्र' में भूमि का बोध भी होता है। जे० डी० वेट की 'ए डिक्शनरी ऑफ हिन्दी लैंग्वेज' में राष्ट्र का भूमिवाला अर्थ लिया गया है—'एन इनहैबिटेड कण्ट्री, ए रेतम, किंगडम, एम्पायर, रीजन।' अन्त में मनुष्यों से भी सम्बन्धित एक शब्द जोड़ दिया गया है, 'पब्लिक'। इससे उन कोशकारों की कठिनाइया का अनुमान किया जा सकता है जिन्हें हिन्दी शब्दों के अंग्रेजी पर्याय ढूँढने पड़ते हैं। वेचारे 'राष्ट्र' के लिए 'पब्लिक' लिखकर संतोष कर लेते हैं। प्रसिद्ध कोशकार मोनियर विलियम्स को अपने महान् सम्पत्ति-अंग्रेजी कोश की भूमिका में कफियत देनी पड़ी थी कि उन्होंने एक-एक

संस्कृत शब्द के अनेक अंग्रेजी पर्याय क्यों दिये हैं। इसका एक कारण और भी था जिसका उल्लेख उन्होंने नहीं किया। वह यह कि किसी एक संस्कृत शब्द का ठीक समानार्थी शब्द अंग्रेजी में मिलता न था; इसलिए उसके अर्थ के निकट पहुँचनेवाले अनेक शब्द देने पड़ते थे, जिससे अंग्रेजी जाननेवाला विद्यार्थी उन सभी की सहायता से अर्थ-बोध कर सके। यथा 'समाधि' के लिए 'इण्टेन्स ऑप्लीकेशन ऑर फिक्सिग द माइण्ड ऑन, इण्टेन्स, अटेंशन; कन्सप्ट्रेशन ऑफ़ द थॉट्स, प्रोफाउण्ड ऑर एंस्टरैक्ट मेडिटेशन, इण्टेन्स कन्टेम्प्लेशन ऑफ़ ऐनी पर्टीकुलर ऑब्जेक्ट (सो ऐज टु आइडेण्टीफाई द कन्टेम्प्लेटेड विद द ऑब्जेक्ट मेडिटेटेड अपॉन)'। 'समाधि' का समानार्थी शब्द अंग्रेजी में है नहीं। यह भी स्पष्ट है कि 'अटेंशन', 'कन्टेम्प्लेशन', 'मेडिटेशन' आदि शब्द समाधि के निश्चित अर्थ के निकट पहुँचते हैं किन्तु उसे प्रकट नहीं कर पाते। वास्तव में 'समाधि' की अपेक्षा वे 'ध्यान' के अधिक निकट हैं।

मोनियर विलियम्स ने भारतीय वाङ्मय के बारे में लिखा था, "कुछ विषयों में, विशेषकर प्रकृति और पारिवारिक प्रेम के कवित्वमय वर्णनों में वह यूनान और रोम की सर्वश्रेष्ठ कृतियों के मुकाबले हेटा नहीं सिद्ध होता और ज्ञान की गरिमा और नैतिक विचारों की मूर्धन्यता में वह अद्वितीय है।" वैज्ञानिक विषयों का उल्लेख करते हुए उन्होंने आगे उसी भूमिका में लिखा था, "इससे भी बढ़कर यह कि हिन्दुओं ने खगोल-विज्ञान, गणित, बीजगणित, वनस्पति-विज्ञान और औषध में काफी प्रगति की थी; व्याकरण में उनकी श्रेष्ठता का उल्लेख करना अनावश्यक है; और यह सब उस समय जब यूरोप की प्राचीनतम जातियों में भी इनमें से कुछ विज्ञान विकसित न हुए थे।" मोनियर विलियम्स ने संस्कृत के शब्द-भण्डार की बहुविषयक समृद्धि को लक्ष्य करके लिखा है कि उसका कोश बनानेवाले को लगभग सर्वज्ञ होना चाहिए। उनके अनुसार इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी-शिक्षा प्राप्त तरुण संस्कृत की "वैज्ञानिक शब्दावली की सही-सही व्याख्या नहीं कर सकते।" मोनियर विलियम्स ने यह और जोड़ दिया है कि यदा-कदा यह वैज्ञानिक शब्दावली संस्कृत में यूनानियों से उधार ली गई है। किन्तु यहाँ इस पर विवाद नहीं करना कि भारत में यूनान से पहले अनेक विज्ञान विकसित हुए, फिर भी वहाँ के शब्द यहाँ वालों ने क्यों उधार लिये। मुख्य बात यह है कि यूरोप की नवीन और प्राचीन भाषाओं के महापंडित कोशकार मोनियर विलियम्स को यह स्वीकार करना पड़ा था कि इंग्लैंड की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटियों के तरुण ग्रेजुएट—भारत में जिनके रोवदाव की सीमा नहीं है—संस्कृत की वैज्ञानिक शब्दावली ('द साइंटिफिक एक्सप्लेन') की वारीकियों को समझने में असमर्थ थे। आज मालूम होता है, मोनियर विलियम्स प्रभृति विद्वानों द्वारा अभिनन्दित हमारा वह महान् रिषय कहीं खो गया है। सरकारी कोशकार हिन्दी में यूरोप की अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली से पारिभाषिक शब्द उधार लेने की बात करते हैं यद्यपि वे जो विदेशी शब्द लेते हैं वे निरपवाद रूप से अंग्रेजी के ही होने हैं (अर्थात् ऐसे शब्द होते हैं जो ग्रीक-लैटिन के आधार पर गढ़कर अंग्रेजी में

चलाये गए हैं)। ये सम्मान्य सरकारी कोसदार वह अनर्वादीय शब्दावली प्रकाशित कर दें तो यूरोप के भावात्मक एकीकरण में बड़ी सहायता मिले।

एक समय था ज्ञान स्वामी विवेकानन्द जैसे भारतीय सभ्यता के प्रतिनिधि गरज-कर मदाघ यूरोप में कहते थे स्वार्थ लिप्सा न तुम्हें पतन के गर्त में डकेल दिया है, आओ, इस गत से बाहर निकला, ज्ञान की दीप्ता भारत से लो।

विवेकानन्द और रवीन्द्रनाथ का वह भारत आज परमुखापक्षी है, न केवल आर्थिक सहायता के लिए वह पश्चिमी राष्ट्रों का द्वार खटखटाता है बल्कि शब्दावली के लिए भी वह उनका मुँह जोहता है, वह अंग्रेजी के बिना अपनी भाषा-समस्या हल नहीं कर सकता।

(१९६२)

## हिन्दीभाषी प्रदेश में हिन्दी-प्रचार की आवश्यकता

हम हिन्दी-भाषियों में अधिकांश जनो की धारणा यही है कि हिन्दी यदि अभी तक राष्ट्रभाषा नहीं हो पाई तो इसका मुख्य कारण अहिन्दी-भाषियों का अंग्रेजी-प्रेम अथवा हिन्दी-विरोध है। हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में इस विषय पर जो लेख निकलते हैं, उनसे यह प्रकट नहीं होता कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का सर्वाधिक उत्तरदायित्व हमारा है और हम उसे निवाह नहीं रहे हैं।

हमारे देश में एक पूरा वर्ग है, जो राष्ट्रभाषा के पद पर अंग्रेजी को प्रतिष्ठित रखना चाहता है। यह वर्ग किसी प्रदेश-विशेष में सीमित नहीं है बरन् सारे देश में फैला हुआ है; अमर-वेल की तरह वह विशाल हिन्दीभाषी प्रदेश में भी फैला है। आये दिन अपने प्रदेश के शिक्षित जनो के व्यवहार में हम अंग्रेजी का यह महत्त्व देख सकते हैं। हिन्दी-भाषी प्रदेश में इस वर्ग के लोग उतने मुखर नहीं हैं जितने उनके सहयोगी अन्य प्रदेशों में हैं। फिर भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सभी प्रदेशों के अंग्रेजी-प्रेमी एक-दूसरे की सहायता करते हैं।

पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के अनेक नगरों में भावात्मक एकता पर राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों के नेताओं ने भाषण किये, अनेक शिक्षा-संस्थाओं में परिसंवाद आयोजित किये गए। आगरा और मेरठ की दो ऐसी गोष्ठियों में मैंने देखा कि अधिकांश भाषण अंग्रेजी में हुए। ये नेतागण अवश्य ही मन में सोचते होंगे कि अंग्रेजी ही उनके उच्च विचारों का वाहन हो सकती है, अंग्रेजी द्वारा ही वे देश में राष्ट्रीय एकता दृढ़ कर सकते हैं। अभी पिछले महीने चीनी आक्रमण के विरोध में विद्यार्थियों की सभाओं में अध्यापकों के प्रोत्साहन-प्रद भाषण भी अंग्रेजी में हुए ! यदि हमारे प्रदेश के शिक्षा-विचारद भी नवयुवकों को देश-रक्षा का महत्त्व समझाने के लिए अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं, तब अन्य प्रदेशों से हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने की माँग हम किस मुँह से कर सकते हैं ? सभी शिक्षित जनो का व्यवहार ऐसा नहीं होता, काफ़ी लोग ऐसे हैं, जो ऐसे अवसरों पर सचेत ढंग से हिन्दी का ही व्यवहार करते हैं। फिर भी यह मानना होगा कि हिन्दी क्षेत्र के शिक्षित जनो में अंग्रेजी का चलन आवश्यकता से अधिक है।

हिन्दी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों में शिक्षा का सामान्य माध्यम अंग्रेजी है। कुछ

विषया में जहाँ-जहाँ हिन्दी द्वारा शिक्षण भी होता है किन्तु कुल मिलाकर गिना के माध्यम के रूप में हिन्दी का स्थान गौण है, अंग्रेजी का स्थान प्रमुख है। इसी प्रकार मातृ मृत्याओं की कार्यवाही के लिए अंग्रेजी का व्यवहार प्रचुर मात्रा में होता है। जब तक उत्तर प्रदेश विचार और मध्य प्रदेश की सामान्य-सम्प्राप्ति में अम्लीय रूप में हिन्दी राष्ट्रभाषा नहीं बन जाती जब तक समूचे देश में उसका राष्ट्रभाषा बनना स्वप्नवत् ही रहेगा।

हिन्दी-भाषी प्रदेश के शिक्षित जन बग़ाल या तमिलनाडु के लोगों पर अक्सर भाषागत सकीर्णता या प्रान्तीयता का दाव मगाते हैं। वास्तविकता यह है कि बग़ाल या तमिलनाडु के शिक्षित जन अपनी भाषा में जितना प्रेम करते हैं, अपने सामाजिक जीवन में उसका जितना प्रयोग करते हैं, उतना हम नहीं करते। अथ प्रदेशों के शिक्षित जन यदि अपने यहाँ के साहित्य से अपरिचित हों तो उन्हें शर्म आयेगी। हमारे प्रदेश के शिक्षित जन हिन्दी-साहित्य से अपरिचित होने में गब का अनुभव करते हैं। अपने अज्ञान पर गब करने हुए वे सिद्धि नीम यहाँ से गलतार एक की प्रत्येक दोहराते चले आए हैं— हिन्दी में ही क्या ?

हिन्दी-भाषी प्रदेश की जनता से थोड़ा तेजा और उसकी भाषा और साहित्य की मानवियाँ देना कुछ नेताओं का दैनिक व्यवसाय है। हमारे प्रदेश के गिना त जनों में जातीय भावना की कमी है। वे हिन्दी के प्रति उदासीन हैं, इसीलिए वे कुछ राजनीतिज्ञों की अपमानजनक बातों का समुचित उत्तर नहीं दे पाते। यहाँ का राजनीतिज्ञ राजनीति के प्रस्ताव अंग्रेजी भाषा में जनता का नेतृत्व करता है। अंग्रेजी में जितनी पुस्तकें केवल उत्तर प्रदेश के राजनीतिज्ञों में लिखी हैं, उतनी दस भारत के सारे राजनीतिज्ञों ने नहीं लिखीं। अन्य प्रदेशों के नेताओं ने एक पुस्तक अंग्रेजी में लिखी तो दो अपनी भाषा में भी लिखी। यहाँ का राजनीतिज्ञ यदि देवनागरी में हस्ताक्षर कर दे तो सम्मत्ता है कि उसने हिन्दी को कुतार्थ कर दिया।

यह किसी नेता विरोध का प्रश्न नहीं है प्रश्न है एक समूचे अंग्रेजी प्रेमी वर्ग का, जो प्रदेश का शासक है या शासक बनना चाहता है। राजनीतिज्ञ इसी वर्ग का प्रतिनिधि है। एक नेता हट जाएगा तो दूसरा आ जाएगा क्योंकि उसे जन्म देनेवाला वर्ग मौजूद है। इसीलिए हिन्दी-भाषी प्रदेश में हिन्दी प्रचार की आवश्यकता है, हिन्दी-प्रचार द्वारा शिक्षित जन का दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है, उनके सामाजिक व्यवहार में सांस्कृतिक जीवन में, शिक्षा मृत्याओं के अन्तर्गत उनकी कार्यवाही में अंग्रेजी की जगह हिन्दी को प्रतिष्ठित कराने की आवश्यकता है।

मिथ्या जातीय जहकार हानिकार होता है। अपनी भाषा और साहित्य को ही घेष्ठ समझा और दूसरों की भाषा और साहित्य को सदा हीन समझना भ्रष्ट है। किन्तु जातीय भावना से हीन होकर 'बग़वैव कुटुम्बकम्' नामक अपना भी कोई बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता का चिह्न नहीं है। हमारा राष्ट्र अनेक भाषाएँ बोलनेवाली जातियों में भिन्न-भिन्न बना है। राष्ट्रीय एकता के लिए इन जातियों की एकता आवश्यक है। सभी जातियों

मिलकर राष्ट्र को दृढ़ करें, इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक जाति अपने भीतर दृढ़ हो, अपने-आप में एकताबद्ध हो। कोई भी जाति अपने भीतर शिथिल होकर राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने में उचित योग नहीं दे सकती।

हिन्दी-भाषी जाति विभिन्न राज्यों में बँटी हुई है। हिन्दी-भाषी प्रदेश की सीमाएँ अनिश्चित हैं। यही नहीं, भाषागत विवाद जितने यहाँ हैं, उतने किसी अन्य प्रदेश में नहीं हैं। दूसरी जगह विवाद होगा तो बँगला-असमिया या गुजराती-मराठी जैसी दो भिन्न भाषाओं को लेकर। यहाँ के विवाद एक ही भाषाक्षेत्र के अन्तर्गत हैं।

मिथिला के कुछ राजनीतिज्ञ हिन्दी को अपनी जातीय भाषा नहीं मानते। पिछले चुनाव में उन्होंने अपने राजनीतिक प्रचार के पत्र मैथिल और उर्दू में छपवाये। हिन्दी का वहिष्कार किया! भोजपुरी क्षेत्र में जन्म लेनेवाले कुछ हिन्दी के आचार्य भाषा-विज्ञान पर ग्रन्थ लिखकर यह सिद्ध करते हैं कि भोजपुरी हिन्दी से स्वतन्त्र भाषा है। जिन्हें हम हिन्दी की बोलियाँ कहते हैं, उनके क्षेत्रों में हिन्दी-प्रचार आवश्यक है, जिससे वहाँ के शिक्षित-जनों का वह भाग, जो अपनी बोली को स्वतन्त्र भाषा मानता है, जातीय भाषा के रूप में हिन्दी को स्वीकार करे। जब तक साधारण जनता के सामने यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि हिन्दी-प्रदेश की सीमाएँ कौन-सी हैं, उसमें कौन-सी बोलियों का चलन है, उन्हें अब स्वतन्त्र भाषा न मानना चाहिए, तब तक समूचे देश में तथा अपने ही प्रदेश में हिन्दी को उसका उचित स्थान दिलाने के लिए यह विशाल जनता सक्रिय नहीं हो सकती। हिन्दी-प्रचार का एक लक्ष्य होना चाहिए : जातीय प्रदेश का गठन, उसमें सर्वत्र जातीय भाषा के रूप में हिन्दी का चलन।

जातीय भाषा और राष्ट्रभाषा में अन्तर है। महाराष्ट्र, बंगाल या तमिलनाड के लोगों की जातीय भाषा मराठी, बंगला या तमिल है, हिन्दी नहीं। हिन्दी इन लोगों की राष्ट्रभाषा है, जो पारस्परिक आदान-प्रदान का माध्यम बनती है। हिन्दी-भाषियों के लिए हिन्दी जातीय भाषा है जैसे महाराष्ट्र के लोगों के लिए मराठी जातीय भाषा है। जातीय भाषा होने के साथ-साथ हम हिन्दी-भाषियों के लिए हिन्दी राष्ट्रभाषा भी है। मिथिला के कुछ शिक्षित-जन हिन्दी को राष्ट्रभाषा तो मानते हैं किन्तु अपनी जातीय भाषा नहीं मानते। मराठी के समान वे मैथिल को हिन्दी से स्वतन्त्र भाषा मानते हैं।

अनेक अहिन्दी-भाषी अंग्रेजी-प्रेमी विद्वान् इसी तर्क का आश्रय लेते हैं और कहते हैं कि हिन्दी अपने ही क्षेत्र में दूसरों पर लादी गई भाषा है। वे प्रचार करते हैं कि ब्रज, अवधी, बुन्देलखण्डी, भोजपुरी आदि सब स्वतन्त्र भाषाएँ हैं जिन पर कृत्रिम साहित्यिक हिन्दी जबरदस्ती लादी गई है। ये लोग भूल जाते हैं कि इंग्लैण्ड, रूस, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों में अंग्रेजी, रूसी, फ्रांसीसी, जर्मन आदि भाषाओं की वैसे ही बोलियाँ हैं जैसी हिन्दी की। इन सब भ्रान्तियों के निवारण के लिए हिन्दी-भाषी प्रदेश में हिन्दी-प्रचार आवश्यक है।

हिन्दी-उर्दू समस्या को अधिकांश हिन्दी-प्रेमी भूल-से गए थे। रेडियो द्वारा हिन्दी

के सरस्तीकरण ने उह नींद में जगा दिया। भारतेन्दु ने लेकर प्रेमचन्द तक हिन्दी के समान लेखक अपनी भाषा का कठिन बनाते रहे, जिससे जनता उनका साहित्य समझ न पाये, अब उन हिन्दी का सरस बनाने का बीड़ा उठाया है आकाशवाणी ने। यह सरस्तीकरण का प्रश्न उस समय उठाया गया जिस समय अंग्रेजी को अनिदित्व काल के लिए राजभाषा घोषित किया गया। हिन्दी-उर्दू के मगडे में फिर से जान डालकर राष्ट्रभाषा के रूप में अंग्रेजी का नवजीवन दिया गया।

हिन्दी के कुछ विद्वान् मानते हैं कि मुसलमानों की भाषा उर्दू है, जो हिन्दी से स्वतन्त्र है। बगान के मुसलमानों की बगला से स्वतन्त्र कोई भाषा क्यों नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर वे नहीं देने। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हमारे देश की धर्मिक जनता में बड़ी भी घब के आधार पर भाषागत विभाजन नहीं दिखाई देता। कानपुर, लखनऊ, पटना आदि के हिन्दू-मुसलमान मजदूर आपस में एक ही सामान्य भाषा का व्यवहार करते हैं। वे लोग हिन्दुओं और मुसलमानों की दो भाषाएँ मानते हैं, जो हिन्दी और उर्दू की मूलतः दो भाषाएँ मानते हैं, उन्हें यह समझाना चाहिए कि भाषा की आधारभूमि कोटि-कोटि धर्मिक जनता है न कि मुट्ठी भर पढ़े-लिखे लोग।

उर्दू प्रेमियों में इस बात का प्रचार करना आवश्यक है कि उनकी अलग कौम नहीं है व विज्ञान हिन्दी-भाषी जाति का अंग है, प्रत्येक जाति की एक ही भाषा होती है, दो नहीं हिन्दी उर्दू मूलतः एक ही भाषा है इसलिए उनका साहित्यिक रूप दो न होकर एक ही होगा, हिन्दी-उर्दू के अलगाव से हमारी जातीय संस्कृति पूरी शक्ति से विकसित नहीं हो पाती। उर्दू-प्रेमी बचौर, जायसी, ग़ालान, रहीम आदि की साहित्यिक परम्परा में अपना सम्बन्ध जाड़ें, भारत की अन्ध भाषाओं के विकास के अनुकूल उर्दू को मोड़ें, इसमें तुरन्त नहीं किन्तु कुछ समय बाद हमारी सामान्य साहित्यिक परम्परा विकसित होगी। उर्दू प्रेमियों के साथ इस तरह का प्रचार उन हिन्दी प्रेमियों में भी करना आवश्यक है, जो हिन्दुओं और मुसलमानों को दो गिन्न जातियाँ मानते हैं।

हिन्दी भाषी जनता की शक्ति अपार है किन्तु वह असंगठित और बिखरी हुई है। हिन्दी भाषियों के जातीय हित में इन शक्ति को संगठित करना आवश्यक है। सपूने राष्ट्र का एकतावद्ध और दृढ़ करने के लिए हिन्दी भाषी जाति की एकता आवश्यक है। इस एकता के माग में पहली बाधा है अंग्रेज़ों प्रेम। दूसरी बाधा है आधुनिक बोलियों का स्वतन्त्र भाषा मानने की आन्ति। तीसरी बाधा है हिन्दी-उर्दू-प्रेमियों का दो छेमा से बँटकर जातीय संस्कृति का कमजोर करना। इन तीनों बाधाओं के फलस्वरूप अपनी जातीय शक्ति के उपयोग द्वारा हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के अपने उत्तरदायित्व को हम निवाह नहीं पाते।

यदि समस्त हिन्दी भाषी प्रदेशों में शिक्षा सम्थाओं, न्यायालयों, राजकीय कार्यों में हर स्तर पर हिन्दी का व्यवहार हो नये, यदि विधान-परिषदों के सदस्य प्रतिना करें कि वे अपना सार्वजनिक काम हिन्दी में ही करेंगे, यदि लोकसभा के सदस्य तय कर लें कि

वे राजभाषा के रूप में हिन्दी का ही व्यवहार करेंगे तो क्या इसमें किसी को सन्देह हो सकता है कि समूचे राष्ट्र का वातावरण बदल जाएगा और हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनते जरा भी देर न लगेगी ?

हम हिन्दी-भाषी किसी पर हिन्दी लादना नहीं चाहते । जो अंग्रेजी ही बोलना पसन्द करे उससे जबरदस्ती हिन्दी बोलवाना नहीं चाहते । किन्तु हमें भी अंग्रेजी बोलने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता । लोकसभा और राज्यसभा के वे सदस्य और मन्त्री, जो हिन्दी-भाषी प्रदेश से चुने गए हैं, जिस दिन तय कर लेंगे कि अंग्रेजी के बदले हिन्दी का ही प्रयोग करेंगे, उसी दिन हिन्दी व्यवहारतः राष्ट्रभाषा बन जाएगी । यदि ऐसा नहीं होता तो कमजोरी हमारी है । हमें हिन्दी-प्रचार द्वारा स्वयं अपने प्रदेश की जनता को जाग्रत करना है, अपने प्रदेश के नेताओं में हिन्दी की उपेक्षा दूर करनी है, स्वयं अपने प्रतिनिधियों को बाध्य करना है कि वे राजकाज में और सर्वत्र हिन्दी का व्यवहार करें । इस तरह के प्रचार और संगठन द्वारा ही अपनी जातीय शक्ति के अनुरूप हम हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का अपना गहन उत्तरदायित्व पूरा कर सकते हैं । (१९६२)



## सरकारी कोशकार और राष्ट्रभाषा

तीस में अधिक बप हुए, जनवरी, १९३२ की 'सुधा' में अंग्रेजी-हिन्दी कोश-सम्बन्धी एक टिप्पणी प्रकाशित हुई थी। टिप्पणी के अनुसार श्री मुखमम्पतिराय भण्डारी ने 'विद्वान् और विपना की महायता में' लगभग बीस हजार रुपये खर्च करके प्रायः डेढ़ लाख शब्दों का यह कोश नैयार किया या ज़िमकी प्रामा प्रयाग विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉ॰ गंगानाथ झा, पञ्जाब विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉ॰ ए॰ सी॰ वूलनर, डॉ॰ राधा-कुमूद मुकुर्जी, डॉ॰ बी॰ प्रसाद, डॉ॰ सुनीतिकुमार चटर्जी आदि विद्वानों ने की थी और १२ पा० सा० राय ने इसे महान् प्रामनीय साहित्यिक कार्य कहते हुए बंगाली, मराठी और गुजराती भाषा-भाषियों के लिए भी उत्पन्न उपयोग बतलाया है।

हिन्दी भाषी विद्वान इस बात की ओर बहून् पहुँचे से सचेत रहे हैं कि हमारी भाषा आधुनिक विज्ञान तथा सभ्यता में सम्मिलित विचारों को प्रकट करने में सक्षम हो। सरकारी सहायता के अभाव में, अन्तर प्रच्छन्न सरकारी विरोध का सामना करते हुए मुखमम्पतिराय भण्डारी जैसे विद्वानों ने घोर परिश्रम करके पारिभाषिक शब्दों की कमी को पूरा किया। नारी प्रचारिणी मन्त्रालय ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। डॉ॰ सत्यप्रकाश जैसे विद्वानों ने वैज्ञानिक विषयों पर लेख लिखकर और दूसरों से निष्ठा-वर पारिभाषिक शब्दों के प्रचार में महायता की। भारत के स्वाधीन होने पर जब अंग्रेजी को हटाने, भारतीय भाषाओं को उनका स्वत्व देना और परम्परा व्यवहार तथा केन्द्रीय राजकाज के लिए हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का संकल्प सामने आया तब हिन्दी से विज्ञान अन्तर्गत, देवनागरी में लिखनाई से हिन्दी को बोलने वाले देश के अनेक सम्मान्य राजपूतानों ने धापित किया कि हिन्दी को विकसित होना, आधुनिक विचारों की अभिव्यक्ति के योग्य बनने के लिए अभी और समय देना चाहिए। संविधान में इस बात को ध्यान में रखा गया कि हिन्दी को विकसित किया जाय और सम्पूर्ण तथा अन्य भाषाओं में आवश्यकानुसार शब्द लेकर (या नये शब्द गढ़कर) उसे समृद्ध किया जाय।

भारत सरकार ने १९५० में विज्ञान-सम्बन्धी पारिभाषिक शब्द-संग्रह के लिए एक समिति स्थापित की। विज्ञान मन्त्रालय के मुख्यालय में हिन्दी को विज्ञानभाषा और समृद्ध करने का बहून् कार्य बारीक मान तक चला रहा और १९६२ में 'पारिभाषिक

‘शब्द-संग्रह’ नामक सरकारी कोश प्रकाशित हो गया।

भूमिका में सरकारी नीति स्पष्ट कर दी गई है। शिक्षा मन्त्रालय के तत्वावधान में दस वर्षों की अवधि में जितने पारिभाषिक शब्द रचे गए, उन्हें कोशबद्ध किया गया। अंग्रेजी में श्री आर० पी० नायक लिखित इस भूमिका में ‘इबोल्व’ और ‘इवोल्यूशन’ शब्दों का अनेक बार प्रयोग किया गया है। इन शब्दों का आगम्य यही है कि हिन्दी में पारिभाषिक शब्दों का अभाव था, इसलिए शिक्षा मन्त्रालय द्वारा संचालित हिन्दी निदेशालय में नवीन शब्दावली रची गई। एक जगह यह स्पष्ट लिखा है कि १९६१ के मध्य तक विशेषज्ञ-समितियों की संख्या २६ हो गई थी और ‘नव-निर्मित’ शब्दों की संख्या लगभग तीन लाख तक पहुँच गई थी (द टर्म्स क्वायण्ड केम टु नियरली ग्री लैक्स)। ये शब्द ‘क्वायन’ किये गए थे, हिन्दी में ये नहीं, उसे विकसित करने के लिए निदेशालय में ये तीन लाख शब्द ढाले गए थे।

अधिकांश भारतीय राजनीतिज्ञों के लिए जीवन के अनेक स्वीकृत मूल्यों के समान हिन्दी की दरिद्रता भी स्वयंसिद्ध सत्य है जिसे प्रमाणित करने के लिए किसी आयोग या समिति की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी की समृद्धि उसी प्रकार दूसरा ध्रुव सत्य है जिसकी प्रामाणिकता असंदिग्ध है। इन दो ध्रुवों की धुरी पर भारतीय जनतन्त्र की राजनीति अनवरत आवर्तन करती है।

यदि इस सरकारी कोश के सभी या अधिकांश शब्द नये सिरों से गढ़े गए हों, तो वे हिन्दी-भाषी बुद्धिजीवियों के लिए अपरिचित होंगे, कोश के पन्ने पलटने पर ऐसा लगेगा कि हम शब्दों की नई दुनिया में आ गए हैं जिनके रूप और अर्थ में हमारा पहली बार साक्षात्कार हो रहा है। वैसे तो किसी अपारिभाषिक कोश में भी साधारण पाठकों को हज़ारों शब्द मिल जाएँगे जिनसे वे परिचित न होंगे। इसलिए पारिभाषिक कोश में अजनबी लगनेवाले शब्दों का होना आश्चर्यजनक नहीं है। आश्चर्यजनक बात यह है कि हर पृष्ठ पर अनेक ऐसे शब्द मिल जाते हैं जिनसे साधारण पाठक अच्छी तरह परिचित है और जिन्हें नायक साहब के अनुसार ‘क्वायन’ किया गया है।

एक निगाह इन शब्दों पर डालिए : वायुमण्डल, उपलब्धि, आक्रमण, ध्यान, प्रायश्चित्त, मन्त्रिमण्डल, नैतिक, उपहास, त्वचा, बुद्धि, आशय, अभिप्राय, सौन्दर्यशास्त्र, रसायन, विनिमय, द्रव्य, पदार्थ, विषयवस्तु, मनोविज्ञान, मनोविश्लेषण, नापेक्ष, नीति-शास्त्र, पुरातत्व, प्रतियोगिता, घनत्व, प्रत्याख्यान, प्रत्यक्ष, परोक्ष, उद्योग, संक्रमण, आकर्षण, विकर्षण इत्यादि। इस तरह के हज़ारों शब्द इस कोश में हैं जो हिन्दी में वर्षों से प्रचलित हैं और जिनके लिए कोई यह दावा भी नहीं कर सकता कि उन्हें नये सिरों से गढ़ा गया है। इनके लिए यह दावा भी नहीं किया जा सकता कि वे अन्य कोशों में नहीं हैं ! किन्तु हिन्दी को समृद्ध करने, उसे राष्ट्रभाषा-पद के योग्य बनाने के लिए शिक्षा मन्त्रालय और विशेषज्ञ-समितियों ने जो घोर परिश्रम किया, उसमें इस तरह के शब्दों का संग्रह भी शामिल है।

इनके अलावा इस काम में हिन्दी के ऐसे हजारों अतिप्रचलित शब्द हैं जिनमें साधारण बुद्धि के लोग पारिभाषिक स्वीकार ही न करेंगे। प्रचलित शब्द भी पारिभाषिक हो, हम पर आवर्ति नहीं है। प्रश्न दूसरा है। क्या ये शब्द गढ़े गए हैं? क्या ये पहले से हिन्दी में या हिन्दी कागो में थे नहीं? कपूर, अलाप, डेरा, कमरा, खरीदारी, सदी, शताब्दी, खनन निश्चित, नाइत्याना, जादूगर, छपाई, जुड़ाई, उपाय, रोष, याद, भाफी, क्षमा, पुनर्विधान, प्रभावित विनाश, अज्ञापन, मौक, सुपारी, उधार, जोरा, मदिरा, बदली, चरामी किगया, रोजगार कार्यालय, दफ्तर, मुठभेड़, नैरना, आधुनिक, वेस्पासय, चक्का जिलका, मामने, छितराना, मरम्मत करना, प्रयत्न करना, चिपकाना, पर्योत्र, काम शक्ता गपच दिनाता, स्नन मौम, मे, परे, ठोक है, धर्म, छूट देना, छुट्टी पाना, जरा हट क, गिर गया, दोड़ने हुए, हम हानन में, इत्यादि। इस तरह के शब्दों को देखकर यह प्रस्ताव करने की दृष्टि होती है कि काम के द्वितीय मस्तरण में खाना, पीना, उठना, बैठना, चलना, माना, धरती, आकाश, पानी, हवा, धूल, आलू, भटूर, टमाटर, बैंगन, गाजर, मकान, छात्र, फा, दरवाजा, मिर्ची, पिता, पुत्र बहन, भाई, चाचा, ताऊ आदि-आदि शब्दों का भी पारिभाषिकों में गिन लेना चाहिए और भूमिका में अगले दस वर्षों के समृद्धिकरण प्रोग्राम की सफलता के रूप में उन्हें पक्ष कर देना चाहिए। किन्तु सम्भव है, उनमें और इन जैसे अनेक शब्द इस काम में पहले से ही हैं और मैंने उन पर ध्यान न दिया है। जो भी हो, जब तक ये शब्द सरकारी कोश में दर्ज नहीं हुए, तब तक हिन्दी दरिद्र थी। दर्ज हान के बाद भी हिन्दी समृद्ध होकर राष्ट्रभाषा नहीं बनी—वह प्रश्न अलग है।

यह कहा जा सकता है कि ऊपर जिस तरह के शब्दों का उल्लेख किया गया है, वे हिन्दी में थे और किन्तु अर्थ निश्चित नहीं था, पारिभाषिक शब्द-संग्रह करनेवालों ने हिन्दी की यह सेवा की है कि अस्थिर अर्थवाले शब्दों को अंग्रेजी पर्यायों के साथ निश्चित रूप में नयों कर दिया है। भूमिका में भारतीय कोशकारों के प्रयत्नों का उल्लेख करते हुए गाँदा क अरण्य की चर्चा की गई है, जहाँ लेखकों और साधारण जनो को रास्ता नहीं सूचना। किन्तु इन कोश के पन्ने पलटने पर यह समझने में किसी को देर न लगेगी कि यहाँ हजारों अंग्रेजी शब्द ऐसे हैं जिनके एक से अधिक हिन्दी-पर्याय दिये गए हैं। उदाहरण के लिए, न्याय क्षेत्र में 'ऐप्लाइड' शब्द के लिए—विनियोग करना, प्रयोग करना, लागू करना, आवेदन करना, प्रार्थनापत्र देना, जीव-विज्ञान के अन्तर्गत 'लैरिक्स' के लिए—कण्ठ, स्वरपत्र, गैरिकम। 'डस्क' शब्द के आगे यह नहीं लिखा कि वह किस क्षेत्र का पारिभाषिक शब्द है, किन्तु उसके तीन पर्याय दिये गए हैं—गाधूनि, घुरी (?), गार्म। अद्यगम्य के प्रचलित शब्द 'मर्चेंट' के लिए—सौदागर, साधवाह, व्यापारी, बणिक। प्रचलित शब्द 'रिलीव' के लिए—छुट्टी देना, छुट्टी पाना (।), छुट्टी मिलना (नीकरी से), भारमुक्त करना, अवमुक्त करना। 'यूनिट' शब्द के आगे भी सकेत नहीं है कि वह किस क्षेत्र का पारिभाषिक है। उदाहरण—मात्रक, एकक, (इ) कार्ट, दल, एकाग, एकाग,

यूनिट, एकांक !

सरकारी कोश के संरक्षकगण स्वयं देख सकते हैं कि शब्दों की बहुलता कम नहीं हुई, उसमें कुछ इजाफा ही हुआ है। पाठक प्रश्न कर सकते हैं कि इस शब्द-संग्रह में गोधूलि, सांभ, सौदागर जैसे शब्द ही हैं तो उनके संग्रह के लिए इतना परिश्रम क्यों ? नहीं, सांभ, गोधूलि और सौदागर तो सरकारी सस्पर्श से पारिभाषिक बन गए हैं। इनके अलावा ऐसे भी हजारों शब्द हैं जिन्हें देखते ही कोई कह देगा कि वे पारिभाषिक हैं। उदाहरण के लिए, संसक्ति, नम्यता, अविलेयता, गलनांक, वाष्पायन, ऊष्मा, संघनन, विकिरण, प्रच्छाया, उपच्छाया, परावर्तन, अवतल, उत्तल, अक्ष, अण्डाशय, अपचय, अम्ल, क्षार, अणु, परमाणु, चाप, समीकरण, समायवी, अवक्षेपण, द्रव, ज्वलनशील, औत्तिकी, भौत्तिकी इत्यादि—ये सब शब्द आपको इस कोश में मिलेंगे। किन्तु आप यदि थोड़ा-सा परिश्रम करें तो आप देखेंगे कि ये शब्द विद्यार्थियों की उन पाठ्य-पुस्तकों में भी प्रयुक्त हुए हैं जो इस कोश-निर्माण से पहले प्रकाशित हुई थीं ! इन्हें 'इवोल्व' करने या 'क्वायन' करने का दावा इस कोश के सम्पादक लोग नहीं कर सकते।

इस सरकारी कोश में ऐसे भी हजारों शब्द हैं जिन्हें तीस वर्ष पहले ही श्री सुख-सम्पतिराय भण्डारी और उनके सहयोगियों ने 'क्वायन' या 'इवोल्व' कर लिया था। इनमें अणु, परमाणु, धूमकेतु, निरपेक्ष, अमूर्त, सूत्र, मताधिकार, निर्वाचन-क्षेत्र, राष्ट्रीय-करण, समाजवाद, लोकतन्त्र जैसे शब्द हैं। ऐसे शब्द साधारण हिन्दी गद्य में बराबर प्रयुक्त होते रहे हैं। इनके अतिरिक्त विज्ञान-सम्बन्धी शब्द भी हैं, जिनका व्यवहार वैज्ञानिक पुस्तकों में होता है। 'डिफरेंशल इक्वेशन'—अवकल समीकरण; 'डिफ्रैक्शन'—विवर्तन; 'आइसोमेरिज्म'—समावयवता; 'लेटरल'—पार्श्विक; 'वेन'—शिरा; 'वर्टीब्रा'—कशेरुका; 'यूटेरस'—गर्भाशय; 'लैरिक्स'—स्वर-यन्त्र; 'अपेण्डिक्स'—परिशिष्ट; 'कार्टिलेज'—उपास्थि; 'क्लैविकल'—अक्षक; 'कोर्टेक्स'—वल्क; 'डक्ट'—वाहिनी; 'कोन'—शंकु; 'कौर्पस कैलोसम'—महासंयोजक; 'रेडिएशन'—विकिरण; 'मेग्नेटिज्म'—चुम्बकत्व; 'लैगैरियम'—लघुगणक; 'कैलकुलस'—कलन; 'हिप्पोटैज्म'—सम्पोहन; 'इनहिबिशन'—अवरोध; 'साइको-एनैलिसिस'—मनोविश्लेषण; 'एनालौजी'—सादृश्य; 'एल्ट्रूइज्म'—परार्थवाद; 'एनाबोलिज्म'—वय; 'ऑकल्टिज्म'—गुह्यविद्या; 'स्प्लीन'—प्लीहा; 'डेंसिटी'—घनत्व इत्यादि।

इस तरह के हजारों शब्द भण्डारी-कोश और उसके तीस साल बाद के सरकारी कोश में ज्यों-के-त्यों विद्यमान हैं। इनके सिवाय ऐसे भी सैकड़ों शब्द हैं जिनमें सरकारी कोश ने नाममात्र का परिवर्तन किया है। 'डायलेटेगन' के लिए भण्डारी के 'विस्तारन' को यहाँ 'विस्तारण' कर दिया गया है, 'न' का 'ण' ! अथवा 'सिस्टोल' के लिए भण्डारी-कृत 'आकुंचन' सरकारी कोश में 'प्रकुंचन' हो गया है ! 'थोरेसिक' के लिए भण्डारी ने लिखा 'वक्ष-सम्बन्धी'; सरकारी कोश में उसे 'वक्षीय' कर दिया गया ! 'आइसोटोप' के लिए भण्डारी ने लिखा 'समस्थानीय'; सरकारी कोश ने उसे किया 'समस्थानिक' !

इस सरकारी वाग के सम्पादकों-सरभका से यह पूछना अनुचित न होगा कि आखिर वे शब्द कौन-से हैं जिन्हें इस मान में आप लोगो में 'इवोन्व' किया है, या 'क्वायन' किया है, जिनके अभाव में हिन्दी राष्ट्रभाषा न बन सकती थी, दरिद्र थी, आधुनिक जीवन से सम्बन्धित विचारों का प्रकट करन में अक्षम थी ? प्रत्येक हिन्दी प्रेमी को सरकार और उसके मुनाजिमा से यह प्रश्न करना चाहिए कि इस मान में समानार हिन्दी के जिन अभावों की आप घायला कर रहे थे, वे कौन-से हैं, जिन शब्दों की रचना करके आपने उन अभावों की पूर्ति की है ? अपार धन व्यय करके आपने त्रिम कोश की रचना की है, स्पष्ट बताइए कि इसमें कितने शब्द ऐसे हैं जो हिन्दी में पहले से विद्यमान न थे ?

मेरा अनुमान है कि वाग में नये गढ़े हुए शब्दों को बहुत परिश्रम में बूढ़ निकाला जाय ता छपन पर वे पन्द्रह-बीस पृष्ठा में ब्यास जगहन धेगेंगे। यह बात सही हो तो सरकार न की मान केवल डेढ़ या दो पृष्ठा की नवीन मामूली प्रस्तुत की।

यदि किसी को विश्वास है कि नवनिर्मित शब्दों की समस्या पन्द्रह-बीस पृष्ठों में अधिक परिमाण की होगी तो उससे प्रार्थना है कि वह ऐसे शब्दों का सग्रह करे जिन, उन प्रकाशित कर दे, यह हिन्दी की बहुत बड़ी सेवा होगी, एकदम वैज्ञानिक दृष्टि से पता चल जाएगा कि हिन्दी की भाषागत समृद्धि में ठाक-ठीक कितने शब्दों का इजाजा किया गया है।

इस वाग निर्माण के लिए आई० सी० एन० आफिमर, गिन्ना मन्त्रालय के स्टेनन आफिमर ज्ञान ड्यूटी मद्रास, मैसूर, बंगलोर, पुना, कन्नडा, बम्बई, दिल्ली में निकट और दूर व, नगरो में बीमिया विरोधज्ञा का पचासा बार आवागमन, उनके टी० ए० विन, दिन्नी में ठहरन का मना, एक स्थायी कार्यालय और उसके कमचारी — आपहिमाव लागें, फी शब्द सौ टके से कम नहीं पडा। पहले तीन लाख शब्द गढ़े या इकट्ठे किये गए। उनमें बहुत से शब्द दुहराये निहराये गए थे। मनोविज्ञान के शब्द दणन में भी आ गए और भौतिकी के शब्द रसायन में। इन पालनू शब्दों की छेडाई के बाद इस कोश में एक लाख से कुछ ऊपर शब्द बच रहे हैं। कोश पर करोड़ों रुपये खर्च हुए। इतना धन व्यय करने के बाद भी पता नहीं चलता कि नवनिर्मित शब्द दरअसल कितने हैं। गिन्ना मन्त्रालय के उच्च अधिकारियों ने सम्भवतः कोश को पने पलटकर देखा भी नहीं है। वरना श्री आर० पी० नायक तीन लाख 'नये शब्द गढ़ने' की बात में लिलने। कोश में प्रकाशित एक अन्य अंग्रेजी लेख में उन मिद्धान्तों का विवेचन किया गया है जिनके अनुसार शब्द-सग्रह का कार्य सम्पादित किया गया है। इस लेख में बताया गया है कि सम्पादकों ने हिन्दी में पहले से प्रचलित शब्द-राशि से साम उठाया है। इस लेख में लाखों नये शब्द गढ़न का दावा नहीं किया गया। इसमें प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय साहित्य से शब्द लेने की बात भी कही गई है। सरकारी भूमिका में नये शब्द गढ़कर हिन्दी की दरिद्रता दूर करने का जो दावा किया गया है, वह इस लेख की बातों से कट जाता है।

इस लेख में शब्दों के अर्थ निरिचित करने के बारे में कुछ बातें कही गई हैं, जो गलत हैं। जिन प्राचीन शब्दों को खोज निकालने का दावा किया गया है, उनमें 'बैलकुलस'

का पर्याय 'कलन' भी है। यह शब्द भण्डारीजी के कोश में विद्यमान है। इसी तरह 'हीट' के लिए 'ऊष्मा' को निश्चित करने की ओ बात कही गई है, वह सही नहीं है। भौतिकी-पुस्तकों में 'हीट' के लिए ऊष्मा का प्रयोग काफी पहले से होने लगा था। कोश में कुछ प्रचलित शब्दों को छोड़कर नये शब्द गटे गए हैं। यह गड़बड़ अवसर भोंडी हो गई है। 'नव' के पर्याय-रूप में 'स्नायु' हिन्दी का प्रचलित शब्द था। उसे हटाकर 'तन्त्रिका' शब्द स्थापित किया गया है। 'स्नायु-तन्त्र' नुनने में अच्छा लगता है। उसके बदले इस कोश के अनुसार 'तन्त्रिका-तन्त्र' का चलन होना चाहिए ! 'डिप्लोमैनी' के लिए हिन्दी में 'कूटनीति' शब्द प्रचलित है। इसकोश में इसके लिए नया शब्द दिया है—'राजनय' ! 'अनीस्टीसिज्म' का पर्याय दिया गया है 'अनीस्वरवाद', जो गलत है। उसके विपरीत भण्डारीजी के कोश में नहीं शब्द दिया गया है—'अजैयवाद'। 'स्पेस' या 'आउटर स्पेस' का समानार्थी हमारा प्राचीन शब्द है 'अन्तरिक्ष'। उने कोश में जगह नहीं मिली। 'नेशनलिटी' का समानार्थी प्रचलित शब्द है—'जाति'। सरकारी कोश ने भोंडी गड़बड़ की है—'राष्ट्रिकता'।

एक विचित्र बात यह है कि एक ही शब्द से सम्बन्धित शब्द-समूह में पर्यायों की यथेष्ट भिन्नता दिखाई देती। 'स्पेस टाइम' के लिए 'दिक् काल' किन्तु 'स्पेस टाइम कर्ब' के लिए 'अवकाश-समय-वक्र'। ऐसे भी सैकड़ों शब्द हैं जो कोश में नहीं आए—यथा 'एजाल्टेशन', 'पैन्थोइज्म', 'ईस्वेसिया', 'कोस्मोनॉट', 'जनरल स्ट्राइक' इत्यादि।

ज्यादा अच्छा होता कि सरकार ज्ञान-विज्ञान के समस्त क्षेत्रों में हिन्दी को समृद्ध करने का ठेका न लेती। वह शान्त-व्यवस्था, न्याय, व्यापार आदि उन क्षेत्रों के शब्दों का ही संग्रह कराती जिससे उसे आए दिन नायका पड़ता है। आखिर लोकमभा के मदस्य या मन्त्रीगण अपनी राजनीतिक हैसियत से भौतिकी, रसायन या जीवविज्ञान पर तो ग्रन्थ रचेंगे नहीं। हिन्दी को केन्द्रीय राजकाज की भाषा बनाने के लिए देखना यह चाहिए था कि उसमें राजकाज के शब्द हैं या नहीं। यह सीधा-सादा छह महीने में खत्म होनेवाला काम न करके सरकार ने दो पंचवर्षीय योजनाओं का समय लगा दिया, नमस्त विषयों के इस शब्द-संग्रह में।

शब्द-संग्रह तैयार हो गया। धन, समय और शक्ति के अपव्यय के बावजूद यह लाख से ऊपर शब्दों का संग्रह प्रस्तुत है। भारत के डेढ़ फी सदी अंग्रेजीदां बुद्धिजीवी जो पहले अंग्रेजी में सोचते हैं, फिर अपने सोचने का फल किसी भारतीय भाषा में प्रकट करते हैं, इस कोश की सहायता से हिन्दी में अब अपने अमूल्य विचार प्रकट कर सकते हैं। क्या अब केन्द्रीय राजकाज अंग्रेजी के बदले हिन्दी में होने लगा है? नहीं, इसके विपरीत अनिश्चित काल के लिए अंग्रेजी हमारी राष्ट्रभाषा घोषित कर दी गई है।

दो निष्कर्ष स्पष्ट हैं—

(१) हिन्दी में पारिभाषिक शब्दों के अभाव की बात राजनीतिज्ञों का झूठा प्रचार है। सरकारी शब्द-संग्रह के ६६ फी सदी शब्द हिन्दी-पुस्तकों और कोश में पहले से विद्यमान हैं।

(२) कोश-निर्माण द्वारा हिन्दी को समृद्ध करने, उसे राजभाषा पद के योग्य बनाने की मारी प्रक्रिया एक राजनीतिक चाल है, जिसका उद्देश्य है हिन्दी-भाषियों तथा समस्त राष्ट्रभाषा-प्रेमियों की आत्मा में धूल भौंकना।

राष्ट्रीयता और जनता का आधार सङ्कुचित करके अंग्रेजी पढ़े-लिखे मुट्ठी-भर लोग जो भारत के गामन-राज का मचायन करते हैं, वे अपना निहित स्वार्थ छोड़ने को तयार नहीं हैं। उनकी धारणा है कि अंग्रेजी के विदा होने पर उन्हें भी भारतीय रणमंच में विदा नहीं मिलेगी। हिन्दी-भाषी तथा समस्त भारतीय जनता का हित इसी में है कि अंग्रेजी की नौकरगारहा का यह बग जल्दी-से-जल्दी गायन-तन्त्र से दूर हो, तभी देश की समस्त भाषाएँ जनता की सामाजिक और भास्कृतिक उन्नति का साधन बनेंगी और भारत अपनी प्रभुमत्ता को पूरी तरह चरितार्थ करेगा।

(१९६३)

## वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम का मसौदा

### (भाषा-सम्बन्धी नीति की श्रालोचना)

वामपंथियों के कार्यक्रम के मसौदे में भारतीय भाषाओं की समानता के बारे में बहुत-सी और बहुत अच्छी-अच्छी बातें कही गई हैं। लेकिन कहीं यह नहीं बताया गया कि भारत की सभी भाषाओं पर अपना आधिपत्य जमाये हुए जो अंग्रेजी बैठी हुई है, उसके बारे में वामपंथी कम्युनिस्ट क्या करने जा रहे हैं। मसौदे में यह सराहनीय बात कही गई है कि विभिन्न राज्यों तथा वहाँ की जनता के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देकर भविष्य में कायम होनेवाली जनता की जनवादी सरकार भारत की एकता को दृढ़ करेगी। यह एकता दृढ़ करने का काम अंग्रेजी के द्वारा होगा या किसी भारतीय भाषा के द्वारा ?

जहाँ तक हिन्दी का सम्बन्ध है, मसौदे में कहा गया है कि अखिल भारतीय स्तर पर हिन्दी का व्यवहार अनिवार्य न होगा लेकिन विभिन्न राज्यों की सरकारों के बीच सम्पर्क भाषा बनने के लिये हिन्दी को प्रोत्साहन दिया जायगा।

हिन्दी का व्यवहार अनिवार्य न होगा। बहुत अच्छी बात है क्योंकि हिन्दी के व्यवहार को अनिवार्य बनाना जनतन्त्र-विरोधी कार्य होगा। लेकिन अंग्रेजी को हटाना अनिवार्य क्यों न कर दिया जाय ? मातृभाषाओं के व्यवहार पर सही जोर, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर हिन्दी के व्यवहार को लेकर आगा-पीछा—ऐसा क्यों ? जनता की जनवादी सरकार हिन्दी के व्यवहार को प्रोत्साहन देगी ! मानो विभिन्न प्रदेशों की जनता ने अभी तक परस्पर आदान-प्रदान की आवश्यकता का अनुभव ही न किया हो ! मानो वह अभी तक राह देख रही हो कि जनता की जनवादी सरकार बन जाय, तब वह आपसी सम्पर्क का काम शुरू करे ! और विभिन्न राज्यों की सरकारों को ही परस्पर सम्पर्क के लिए हिन्दी को प्रोत्साहन क्यों दिया जायगा ? क्या अन्तर्प्रदेशिक सम्पर्क की आवश्यकता केवल सरकारों को पड़ती है ? जनता की जनवादी सरकार कायम होने पर जनता को इस सम्पर्क की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं ? भारत की सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक एकता दृढ़ करने में जनता का भी कुछ हिस्सा होगा या नहीं ?



जनता के धार्मिक और साम्राज्यवाद के दायें—वामपंथी मसौदे का भारतत्व यही है। जोरों में हिन्दी की अस्वीकृति और अंग्रेजी की स्वीकृति, मात्र के लिए भी और बाज के लिए भी—यह है मसौदे की नीति। मत्रह मान से कांग्रेस जिस नीति पर चलती आई है, उसमें इस वामपंथी नीति में कुछ ज्यादा पकें नहीं दिखाई देता।

साम्राज्यवादों अंग्रेजों के प्रचार और शिक्षण पर कगोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं। भारत के मंत्र पड़े राष्ट्रीय अंग्रेजों में निगलते हैं और उनके मानिक पड़े पत्रापत्र हैं। इनमें अहिन्दी और हिन्दी दोनों तरह के पत्रापत्र हैं। मध्यम के पड़े निम्ने लागू नौकरगारही मर्गिन चलान हैं और उही में से भारत की राजनीतिक पार्टियों के नेता भी बनते हैं। इन पार्टियों का राजनीतिक काम अंग्रेजी में होता है। इनमें से अनेक पार्टियाँ चाहती हैं कि अंग्रेजी जाय लेकिन के अपना अन्तर्प्रदेशिक काम करती हैं अंग्रेजी में। सरकार से यह कहता कि यह करो वह करो, मत्रह तब बिलकुल पिछल है जब तक राजनीतिक पार्टियाँ अखिल भारतीय काम के लिए अंग्रेजी का सहारा लेना नहीं छोड़तीं। वामपंथी कार्यक्रम के मसौदे में कहा गया है कि पालियामेंट के सदस्य अपनी-अपनी भाषा में बात मक्के और भाषणा के सभी भाषाओं में अनुवादित होने की व्यवस्था होगी। वामपंथी कम्युनिस्ट अपनी पार्टी कांग्रेस में इन प्रस्ताव पर असल करके कुछ अपने अन्दर अंग्रेजी का व्यवहार गम बना नहीं कर देने ? भारतीय जनता के किसी भी हिस्से का अंग्रेजी के कायम रहने से लाभ नहीं है। अखिल आन्दोलन में विभिन्न जातियों के मजदूर परस्पर मजबूत के लिए हिन्दी का व्यवहार करते हैं।

आज भारतीय जीवन में मुख्य अन्तर्विरोध हिन्दी और अहिन्दी भाषाओं में नहीं, अंग्रेजी तथा समस्त भारतीय भाषाओं में है। हिन्दी-अहिन्दी भाषाओं में जो भी अन्तर्विरोध हो, उसे शीघ्र मानकर पहले मुख्य अन्तर्विरोध को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। बड़े ममाचारपंथी की भाषा अंग्रेजी, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में अंग्रेजी, विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी, विज्ञान-सम्बन्धी प्रकाशन के लिए अंग्रेजी, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर केन्द्रीय सरकार की व्यवहार-भाषा अंग्रेजी, राज्यों में सरकारी भाषा अंग्रेजी। अब क्या आए, अहिन्दी जातियों की प्रगति के लिए खतरा हिन्दी साम्राज्यवाद से है या अंग्रेजी साम्राज्यवाद से ?

अहिन्दी जातियों के अधिकारों के लिए लड़ना और इस बात का भूल जाना कि अंग्रेजी सब पर हावी है, इस नीति का एक ही कारण है—अलगवा की भावना। आप प्रादेशिक स्तर पर जातियों के गुठल की माँग करते हैं, उनकी भाषाओं के लिए समस्त अधिकारों की माँग करते हैं। लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय एकता का मुद्दा करो, के लिए जाय किसी भारतीय भाषा के लिए अधिकार नहीं माँगे। आप गहारा लेते हैं अंग्रेजी का जिक्र का मतलब है डेढ़ पी सदी भारतवासियों की एजना की मुद्दा करना। इसका मतलब है, सामाजिक और साम्प्रतिक विकास को अखिल भारतीय धारा से तटस्थ हो जाना। आप इस विकास को अंग्रेजी तक सीमित कर देने हैं। आप अपने

प्रदेश की ही भाषा और संस्कृति के विकास की बात सोचते हैं। यही है अलगाव की भावना। अंग्रेजी का सूत्र बहुत कमजोर है और जरा से भटके से टूट सकता है। आपके लिए मजबूत सूत्र है प्रादेशिक भाषा जो आपको प्रदेश से बाँधती है। लेकिन दूसरे प्रदेशों से जो आपको बाँधे वह सूत्र कौन-सा है ? तब क्या आश्चर्य कि द्रविड़ कपगम अलग तमिल राज्य बनाने की माँग करता रहा है, नागा जनों के लिए फ़िजो महाशय अलग राज्य चाहते हैं, शेख अब्दुल्ला कश्मीर के लिए आत्मनिर्णय का अधिकार चाहते हैं। राजाजी, फील्ड-मार्शल बय्यबू खाँ, चाऊ-एन-लाई और अंग्रेजी-भाषी जनतन्त्रों के ब्रिटिश-अमरीकी नेता सभी आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करते हैं।

भारत की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में अलगाव से केवल साम्राज्यवाद का हित होता है। इसीलिए राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना सभी देश-प्रेमियों का सर्वोपरि कर्तव्य है।

आत्मनिर्णय की माँग सार्थक तब होती है जब साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष करती हुई जनता अपनी स्वाधीनता के लिए आत्मनिर्णय की माँग करे। जारशाही रूस में यह माँग सार्थक थी क्योंकि रूसी पूँजीपति गैर-रूसी जातियों का उत्पीड़न करते थे। भारत में यह माँग निरर्थक है। जो लोग शेख अब्दुल्ला को प्रोत्साहन देते हैं या जमकर उसका विरोध नहीं करते, वे देश के प्रति विश्वासघात कर रहे हैं।

अंग्रेजी के कायम रहने से प्रादेशिक भाषाओं को ही नुकसान होता है। फिर किसी भी प्रदेश की भाषा और संस्कृति का विकास अलगाव की हालत में नहीं हुआ। प्रत्येक भाषा में उसके साहित्य की विषयवस्तु का आधार है देशभक्ति, न कि अलगाव-पंथी प्रादेशिकता। इसलिए अपने प्रदेश और उसकी भाषा पर ही जोर देना और राष्ट्रीय एकता की बात भूल जाना हानिकार है।

वामपंथी कम्युनिस्ट राष्ट्र के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। मसौदे में कहा गया है कि छुटपुट संघर्ष बढ़ते-बढ़ते राष्ट्रीय (नेशनल) विद्रोह का रूप ले लेते; मसौदे में राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे आदि का उल्लेख है। इस राष्ट्र की एकता अंग्रेजी से दृढ़ नहीं हो सकती।

वामपंथी मसौदे में यह माँग की गई है कि भाषावार राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी की जाय। राज्य का गठन इस बात को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए कि जनता के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में सुविधा हो। हर भाषा को लेकर केवल राज्य के लिए राज्य बनाना बचकानापन है।

कुछ लोग कहते हैं अंग्रेजों का विरोध करने के कारण राष्ट्रीयता का जन्म हुआ। ऐसा हो तो भी मानना होगा कि साम्राज्यवाद का दबाव अभी बना हुआ है। वामपंथी मसौदे में कहा गया है कि एक ओर साम्राज्यवाद और सामन्तवाद, दूसरी ओर पूँजीपतियों समेत तमाम जनता—इनका अन्तर्विरोध बना हुआ है। इसके अलावा मसौदे में ब्रिटिश-अमरीकी पूँजी की आमद की बात भी की गई है। तब तो राष्ट्रीय एकता को दृढ़ करना

और भी आवश्यक है, प्रादेशिक अन्तर्भाव की भावना को दूर करना और भी महत्त्वपूर्ण है। लेकिन वामपंथी मसीदे में केवल हिन्दी को प्रोत्साहन देने की बात है, वह भी भविष्य में जब जनता की जनवादी सरकार बनेगी। उससे यह नहीं कहा गया कि अंग्रेजी को उसके वर्तमान पद से हटाना—कल नहीं—आज आवश्यक है। सभी राष्ट्रीय नेता एक समय कहने लगे कि आम जनता की एकता अंग्रेजी के द्वारा कभी कायम नहीं हो सकती। इसलिए जो लोग भविष्य में हिन्दी का प्रोत्साहन देने और वर्तमान काल में अंग्रेजी कायम रखने की बातें करते हैं वे विषयवस्तुकारी शक्तियों की प्रशंसा देते हैं। (१९९४)

## राष्ट्र, जाति और मार्क्सवाद

कुछ ऐसे भी विद्वान् इस देश में हैं जो कहते हैं कि भारत राष्ट्र नहीं है। उनके विचार से वह उप-महाद्वीप है। अंग्रेजों के आने से कुछ एकता उत्पन्न हो गई थी ; अंग्रेज गये तो साथ में एकता भी ले गए।

१९५७ में जब लोग अठारह सौ सत्तावन की शताब्दी मना रहे थे, तब अनेक इतिहासकारों ने यह सिद्ध कर दिया कि उस समय न राष्ट्र था, न राष्ट्रीय चेतना। फिर वह राष्ट्रीय स्वाधीनता-संग्राम कैसे होता ? इस कार्य में श्री रमेशचन्द्र मजूमदार ने विशेष प्रसिद्धि पाई। लेकिन इन्हीं श्रद्धेय इतिहासकार ने 'द क्लासिकल एज' नामक पुस्तक में 'मौर्यों के विशाल राज्य और उससे उत्पन्न राजनीतिक एकता' की चर्चा की थी। लिखा था कि "एक शताब्दी तक गुप्त-साम्राज्य आर्यावर्त की एकता और स्वाधीनता का प्रतीक बना रहा।" संस्कृत के आधार पर जो सांस्कृतिक एकता कायम हुई, उसके बारे में लिखा था कि विदेशी सत्ता और अनेक परिवर्तनों के बावजूद "वह आज भी भारतीय प्रजातन्त्र की एकता और राष्ट्रीयता का एकमात्र सुदृढ़ आधार है।"

गुप्त-काल में रामायण और महाभारत को उनका वर्तमान रूप दिया गया। उस समय की राष्ट्रीय एकता की भावना इन महाकाव्यों में प्रकट होती है। भीष्म-पर्व के नवें अध्याय में धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं कि उस भारतवर्ष का वर्णन करो जिसके लिए पाण्डवों और कौरवों ने अपनी सेनाएँ एकत्र की हैं। संजय ने जिस भारतवर्ष का वर्णन किया है, वह श्री मजूमदार के विशुद्ध आर्यावर्त से थोड़ा भिन्न है क्योंकि उसमें म्लेच्छ भी रहते हैं।

भारतवर्ष की नदियों में सिन्धु, गंगा, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि हैं। जनपदों में कश्मीर, आन्ध्र, केरल, कर्नाटक, अंग, वंग, कर्लिंग आदि हैं। कहनेवाले कह सकते हैं कि कवि ने गुप्त सम्राटों को प्रसन्न करने के लिए इन तमाम जनपदों को भारतवर्ष में गिना दिया है। ऐसा हो भी तो इसमें अनुचित क्या है ? शेक्सपियर ने इंग्लैंड के लिए लिखा था—

"यह सम्राटों द्वारा शासित द्वीप..."

यह भव्य प्रदेश, यह घरती, यह राज्य, यह इंग्लैंड,

यह महाराजाओं का सम्मन्धन, यह उनकी धरित्री,  
उनके जन्म लेने में प्रसिद्ध, उनके वंश के कारण शत्रु में भय उत्पन्न करनेवाला।"

फिर कोई भारतीय कवि किमी गुप्त-सम्राट की प्रशस्ति के गीत क्यों न गाएँ ?  
किन्तु महाभाग क कवि ने भारतवर्ष की प्रशस्ति लिखी है, राजाओं और सम्राटों की  
नहीं। राजाजी और सम्राटों के लिए लिखा है कि वे भूमि के लिए वंश ही लड़ते हैं जैसे  
माँ के लिए कुत्ते ।

देवमानुषकामाना काम भूमि परापणम् ।  
अथायस्यावतुष्पति सारमेया यथामिपम् ॥  
राजानो भरतयेष्ट भावनुवामा वसुधगम् ।  
न चापिनन्ति कामाना विद्यनैज्यापि कस्यचित् ॥  
तस्मान पत्रिहे भूमेयतन्ने कुरपाण्डवा ।  
साम्ना भेदन दानत दण्डेनैव च भारत ॥  
पिता भ्राता च पुत्राश्च स दौश्च नरपुंगव ।  
भूमिभवंति भूताः सम्यगच्छिददर्शना ॥

(देव शरीरधारी प्राणियों के लिए और मानव-शरीरधारी जीवों के लिए मयेष्ट  
फल देनवाली यह भूमि उनका परम आश्रय होती है। जैसे कुत्ते माँ के टुकड़े के लिए  
परस्पर लड़ते और एक-दूसरे को भोवते हैं, उसी प्रकार राजा लोग इस वसुधा को भोगने  
की दृष्टि रखकर आपस में लड़ने और लूटमार करते हैं किन्तु आज तक किसी को अपनी  
कामनाओं में तत्पि नहीं हुई। इन अतृप्ति के ही कारण कौरव और पाण्डव माम, दाम,  
भेद और दण्ड के द्वारा सम्पूर्ण वसुधा पर अधिकार करने के लिए यत्न करते हैं। यदि भूमि  
के यथायथ स्वरूप का सम्पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाय तो वह परमात्मा से अभिन्न होने के  
कारण प्राणियों के लिए पिता, भ्राता, पुत्र, आकाशवर्ती पुण्यलोक तथा स्वर्ग भी बन  
जाती है।)

यूरोप के प्राचीन साहित्य में इस मानवतावाद का जवाब नहीं है। होमरसमय  
की राष्ट्रीय गौरव भावना ने यह धरती-जैम बहुत ऊँचा है। इसलिए भारतवर्ष की प्रशस्ति  
सम्राटों की वन्दना नहीं, भारत-भूमि और उसकी जनता की वन्दना है, वह हमारी प्राचीन  
राष्ट्रीय भावना की धोतक है। 'रामायण', 'मेघदूत' और 'कुमारसम्भव' में इसी प्रकार  
राष्ट्रीय चेतना के दर्शन होत हैं।

मावर्तवाद के अनुसार जातियाँ (नेशन) पूँजीवादी युग की देन हैं। लेकिन पूँजी-  
वाद है क्या ? पूँजीवाद उत्पादन की एक पद्धति है। तब क्या होमरसमय के समय में  
उत्पादन की पद्धति बदल चुकी थी ? यदि हाँ तो पगार पानेवाला सवहारा क्या कहें  
गा ? १८४४ में एंगेल्स ने अपने समय के इंग्लैंड के बारे में—'इंग्लैंड के मजदूर-वर्ग की

दशा' नामक पुस्तक में लिखा था, "इंग्लैंड के सर्वहारा-वर्ग का इतिहास पिछली शताब्दी के उत्तरार्द्ध से आरम्भ होता है।" अठारहवीं सदी से पहले इंग्लैंड में सर्वहारा-वर्ग नहीं था। उत्पादन की पद्धति में कोई बुनियादी परिवर्तन न हुआ था। जुलाहे खेती भी करते थे।

धरती से उनका सम्बन्ध टूटा न था। वे घुमन्तू सौदागरों को अपना माल बेचते थे। लेकिन वे अभी बाज़ार में अपनी श्रमशक्ति बेचने को बाध्य न थे। यदि पूंजीवाद केवल उत्पादन की पद्धति है, तो सोलहवीं-सत्रहवीं सदी के अंग्रेज़ जाति के रूप में संगठित न हो सकते थे। लेकिन मिल्टन ने १६४४ ई० में कोमवेल की विजय के बाद लिखा था, "मुझे अपने मनोलोक में दिखाई दे रहा है कि एक शक्तिशाली जाति (नेशन) नींद से उठे हुए सबल मानव के समान अपने केश झटक रही है।"

रूस में पूंजीवादी उत्पादन उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में आरम्भ हुआ, किन्तु लेनिन के अनुसार रूसी जाति का निर्माण सत्रहवीं सदी में हुआ। लेनिन ने रूस के सामाजिक विकास का विश्लेषण करके दिखाया था कि व्यापारियों ने रूस में एक देशव्यापी बाज़ार कायम किया था। यह समझना चाहिए कि पूंजीवाद केवल उत्पादन की पद्धति नहीं, वितरण की पद्धति भी है। मार्क्सवादी भारतीय इतिहास को तब तक सही तौर से न समझ सकेंगे जब तक वे सामाजिक विकास में वितरण की भूमिका का महत्त्व स्वीकार न करेंगे।

एंगेल्स ने एण्टी-ड्यूरिंग में लिखा था कि उत्पादन और विनिमय अर्थतन्त्र की दो घुरी हैं, दोनों के नियम बहुत-कुछ स्वतन्त्र हैं और वे दोनों एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। एंगेल्स ने इस बात पर जोर दिया था कि प्रत्येक समाज-व्यवस्था का आधार उत्पादन और वितरण दोनों हैं। पूंजी के तीसरे खण्ड में मार्क्स (अथवा एंगेल्स) ने बताया था कि औद्योगिक पूंजी का निर्माण तभी होता है जब उससे पहले सौदागरी पूंजी का निर्माण हो चुका हो। मार्क्स ने लिखा था कि सोलहवीं-सत्रहवीं सदी में सौदागरी पूंजीवाद के विकास के साथ भारी क्रान्तियाँ हुईं और सामन्ती उत्पादन से पूंजीवादी उत्पादन के बीच संक्रमण की यह सबसे महत्त्वपूर्ण कड़ी थी। मार्क्स ने लिखा था, व्यापार में क्रान्ति होने से विश्व-बाज़ार कायम हुआ। आश्चर्य की बात होगी, यदि विश्व-बाज़ार तो कायम हो जाय, जातीय बाज़ार (नेशनल मार्केट) कायम न हो।

सोलहवीं-सत्रहवीं सदियों में भारत विश्व-बाज़ार का बहुत महत्त्वपूर्ण अंग था। हमारे यहाँ यूरोप का माल बिकने आता था, यहाँ का माल वहाँ बिकने जाता था। एडम स्मिथ ने लिखा था कि उन दिनों यूरोप का मुख्य व्यापार यह था कि पश्चिमी देश अपनी अनगढ़ चीजें देकर अधिक सम्य देशों का बढ़िया माल लाते थे। आश्चर्य की बात होगी यदि असम्य देशों में तो राष्ट्रीय या जातीय चेतना फैल गई हो और सम्य देशों में उसका अभाव रहा हो।

मार्क्स ने लिखा था कि "प्राचीन काल की व्यापारी जातियाँ ऐपीक्यूरस के

देवताओं की तरह ब्रह्माण्ड व मध्यलोक में रहती थी। जयवा यो कहें जैम पौनड के ममाज में यहूदी भीतर पैठ गए थे।" मार्कम न व्यापारी जानियो (ट्रेडिंग नेगस) का उल्लेख किया है। इसका अर्थ यह है कि व्यापारी पूजोवाद का विकास सोलहवीं-त्रयोदशी सदी से पहले प्राचीन काल में भी हुआ था। जातिवादा का उद्भव आधुनिक पूजोवाद के जन्म से बहुत पहले हो चुका था। 'अथशास्त्र की आलोचना' नामक ग्रन्थ में मार्कम ने प्राचीन काल की जानियो की चला की थी। उन्होंने लिखा था कि प्राचीन काल की व्यापारी जानियो में धन (मनी) की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।

गुप्त युग में भारत के जनपदों में परस्पर आर्थिक विनिमय बढ़ा, उस समय के व्यापारी भारतवर्ष से बाहर निरतकर दक्षिण पूर्वोत्तराशिया और यूरोप तक अपना व्यापार करने लगे। जनपदों में परस्पर सांस्कृतिक सम्पर्क बढ़ा, स्मृतियों द्वारा के एक-दूसरे में विचारों का आदान-प्रदान करते रहे। तब क्या आश्चर्य कि भारतवर्ष में राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ और महाभारत में उसे अभिव्यक्ति मिली ?

प्राचीन यूनान का उदाहरण लीजिए। यह देश छोटे-छोटे राज्यों (जनपदों) में बँटा हुआ था। एथेन्स के लोगो में बड़े-बड़े व्यापारी थे। इन्होंने यूनानी लोगो में राष्ट्रीय चेतना उभारने में बड़ा योगदान किया। यूनान के प्राचीन नाटकों—त्रिसेप्टर ईरानियों में सम्बन्धित ईस्किवस के नाटक में—यह चेतना उभरकर आई है। एथेन्स का नेता परिक्लीड अपने नगर की हेलाम (यूनान) का गिधान कहता था। प्रसिद्ध इतिहासकार थ्यूसीडाइड ने पेलोपनीसम के युद्ध पर अपने ग्रन्थ में बारम्बार राष्ट्रीय भावना का उल्लेख किया है। ग्रन्थ का दूसरे खण्ड के छठे अध्याय में उमने लिखा है, "पेलोपनीसम और एथेन्स दोनों में एथेन्स जीवितान भर हुए थे जो भावहीनता के कारण हथियार उठाने को बड़े उत्साह से थे। बाकी हेलाम अपने प्रमुख नगरों के मध्य का देवकर आन्ध्रवैचित्र्य हो रहा था।" यहाँ पेलोपनीसम और एथेन्स को एक ही राष्ट्र हेलाम का अंग माना गया है। ये दोनों राज्य हैं, परस्पर स्वतंत्र हैं, फिर भी जनता की चेतना में—विनिमय की बढती के कारण और जय महत्वपूर्ण सामाजिक और भाषागत तत्वों के कारण—वे अपने में बड़े इकाई के भाग हैं। लक्सेडैमोन (पेलोपनीसम) का राजदूत मेलेसिप्पस पेरिक्लीड से मिलने की अनुमति न पाकर कहता है "यह दिन हेलाम के महादुर्भाग्य के आरम्भ का दिन है।" ईसा में चार सौ साल पहले यूनान में यह राष्ट्रीय चेतना फैल सकती थी तो क्या इसमें चार सौ साल बाद भारत में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार असम्भव माना जाएगा ?

बहुम वदनेवाले कह सकते हैं कि प्राचीन यूनानियों में राष्ट्रीय चेतना इसलिए फैली कि उन्हें ईरानियों से मुकाबला करना था। ऐसा ही सही। तब प्राचीन भारत में राष्ट्रीय चेतना शत्रुओं और हूणों का मुकाबला करने के लिए पैदा हुई। कारण चाह जो बताया जाय, प्राचीन यूनान और प्राचीन भारत में राष्ट्रीय चेतना के अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता।

फिर भी रूढ़िवादी मार्क्सवादी कहेंगे, 'नेशन' उसे कहते हैं जिसकी भाषा एक हो। यूनान में मिलती-जुलती बोलियाँ बोली जाती थीं। लेकिन यहाँ तो आर्य और द्रविड़ एक-दम भिन्न भाषा-परिवार थे। फिर भारत राष्ट्र कैसे हुआ ?

प्राचीन भारत में अनेक भाषाएँ थीं किन्तु शिक्षित-जन संस्कृत द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर आपस में सम्पर्क बनाये हुए थे। आर्यवर्त से सबसे ज्यादा दूर बंगाल और केरल थे, फिर भी इनकी भाषाओं में संस्कृत के शब्द अपेक्षाकृत अधिक हैं। इससे संस्कृत के देशव्यापी प्रभाव का पता चलता है। प्रकाण्ड पंडित शंकराचार्य केरल ही के थे। बंगाल के न्यायशास्त्री दूर-दूर तक विख्यात हुए। फिर भी प्रश्न बना रहता है कि क्या एक से अधिक भाषाएँ बोलनेवालों को राष्ट्र की संज्ञा दी जा सकती है ?

स्तालिन ने नेशन की जो प्रसिद्ध व्याख्या की थी, उसमें एक से अधिक भाषा की गुंजाइश नहीं है। ब्रिटिश जाति और फ्रांसीसी जातियों की एक-एक भाषा है अंग्रेजी और फ्रांसीसी। फिर भी मार्क्सवादी लेखक 'नेशनल फ्रीडम मूवमेंट' की बात करते हैं, सौभाग्य से वे उसे 'इण्टरनेशनल फ्रीडम मूवमेंट' नहीं कहते।

अंग्रेजी का 'नेशन' शब्द बड़ा भ्रामक है। भारतीय भाषाओं में दो शब्द हैं राष्ट्र और जाति। भारत राष्ट्र, हिन्दी-भाषी जाति। ब्रिटेन राष्ट्र, ब्रिटिश जाति। ब्रिटेन राष्ट्र में एक ही भाषा है। भारत में अनेक भाषाएँ हैं। जाति की भाषा एक ही होती है। राष्ट्र में एक जाति, एक भाषा तथा अनेक जातियाँ, अनेक भाषाएँ हो सकती हैं। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने 'जातीय संगीत' में जाति शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया था।

अंग्रेजी का 'पेट्रियोटिज्म' शब्द राष्ट्रीयता के बहुत निकट है, किन्तु उसके मूल लैटिन शब्द 'पात्रिया' का अंग्रेजी में चलन नहीं है। राष्ट्र को पात्रिया कह सकते हैं, नेशन नहीं। राष्ट्र के लिए 'नेशन' को पर्यायवाची मानें तो 'भारत बहुजातीय राष्ट्र है'—इस वाक्य का अनुवाद होगा—"इंडिया इज ए मल्टीनेशनल नेशन" !

बहुजातीय राष्ट्र में राष्ट्रीयता का आधार क्या है ? उदाहरण के लिए, सोवियत राष्ट्रीयता (सोवियत पेट्रियोटिज्म) का आधार क्या है ? यह राष्ट्रीयता केवल भाव-जगत् की वस्तु नहीं है। मार्क्सवाद के अनुसार जाति की तरह, बहुजातीय राष्ट्रीयता का भी आर्थिक आधार होना चाहिए। क्या इसका आधार समाजवाद है ? सोवियत संघ के अनेक समाजवादी पड़ोसी हैं किन्तु उनकी राष्ट्रीयता या देशभक्ति सोवियत राष्ट्रीयता या सोवियत देशभक्ति से भिन्न है। राष्ट्र की अनेक जातियाँ सामान्य आर्थिक सम्बन्धों, सामान्य देश में निवास, सामान्य ऐतिहासिक परम्पराओं और सामान्य सांस्कृतिक सूत्रों के कारण परस्पर सम्बद्ध होती हैं। भारत देश में निवास करनेवाली जातियों की भाषाएँ, प्रदेश, आर्थिक सम्बन्ध, साहित्य और संस्कृति अलग-अलग हैं। फिर भी उन सबका देश एक है; उन सबका राष्ट्रीय इतिहास एक है, उनकी मिली-जुली परस्पर सम्बद्ध साहित्यिक परम्परा है, उनके आर्थिक सम्बन्ध पहले की अपेक्षा आज और भी दृढ़ हैं। इसलिए जो लोग भारत की तुलना यूरोप से करते हैं, जो देश को उप महाद्वीप कहते हैं, वे एक



ऐतिहासिक मध्य में इन्कार करते हैं। राष्ट्रीयता के विकास में केवल आर्थिक सम्बन्धों की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं होती। ऐसा होना तो चेकोस्लोवाकिया, रूमानिया और पोलैंड मोविमल राष्ट्र व अलगगल हलने। उनकी अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परम्पराएँ हैं जल उनकी राष्ट्रीयता निर्धारित करती हैं।

कल जल नकल है कि दल तरह की बहुजातीय राष्ट्रीयता समाजवाद के अन्तर्गत ही सम्भव है व नींदा में लल जलनल, पूंजीपतियों के प्रभाव के कारण, परस्पर लडा करती हैं। यह दल सही नहीं है। पूंजीवाद के अन्तर्गत 'जलन' का निर्माण होना या नहीं? यह जलन जलद्वारा वल शर व नींपलनल के बीच सघर्ष के कारण विभाजित रहती है या नहीं? विभाजित रहती है किन्तु पूंजीपति और मजदूर एक ही उत्पादन वितरण व्यवस्था में काम करन हैं। इसलिए जलन सम्बद्ध भी रहती है। इनी तरह पूंजीवाद के अन्तर्गत एक नी राष्ट्र की अवल नलनल आपस में स्पर्धा करती हैं, नाथ ही राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था म एक-दूसर न सम्बद्ध भी रहती हैं। इसके अलावा सभी लोग मानने हैं कि देश की विभिन्न नलनल ने जलंजल के विरुद्ध 'राष्ट्रीय' आन्दोलन चलाला या। इसका अर्थ यह है कि विशेष परिस्थितियाँ म जलतियों का आपसी तनाव कम हो जलना है और उनकी राष्ट्रिय एकता उभरकर ललने जल नाली है। यह भी ध्यान देने योग्य दल है कि नलजवादी व्यवस्था म जातीय और राष्ट्रीय अलगाव की भावनाएँ व नीं-व नीं बडा उल रूप धारण करती हैं। मोविमल सघ में यूगोस्लाविया, रूमानिया और चीन के सम्बन्ध नल नल का उलार करते हैं।

भारत एक राष्ट्र है। हमारी राष्ट्रीयता केवल अंग्रेजों का विरोध करने के लिए—नद्वारा 'मक रूप से—कि ही विशेष परिस्थितियों में उत्पन्न नहीं हो गई। उसकी पहले हमारी ऐतिहासिक और आर्थिक परम्पराओं में बहुत गहरी पैंठी हुई है। आज की परिस्थिति म लोग चाहे जिस प्रदेश में रहते हल, उनकी आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रानि राष्ट्रीय एकता के चिला असम्भव है। किसी एक प्रदेश की उन्नति शारे दल की उन्नति पर निर्भर है।

भारत राष्ट्र में प्रेम है तो अंग्रेजों का मोह छोडना होगा। अंग्रेजों का प्रभुत्व राष्ट्र के लिए अपमानजनक है। अथ विदेशी भाषाओं के साथ अंग्रेजी का अध्ययन भी किया जायगा किन्तु वह भारतीय भाषाओं के हक शारकर गही नहीं रह सकनी। सभी प्रदेशों की जनता की अंग्रेजी हटाने के लिए मिलकर प्रयत्न करना चाहिए। जो लोग निली साम्राज्यवाद का अर्थ दिखाने हैं, वे अंग्रेजी का साम्राज्यवाद सुरनिन रखते हैं।

(१९५५)

## ‘अन्तर्राष्ट्रीय’ वैज्ञानिक शब्दावली

बुद्धिजीवियों में, वे चाहे मार्क्सवादी हों चाहे गैर-मार्क्सवादी, ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो समझते हैं कि विज्ञान में कोई अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली प्रचलित है। उनका तर्क यह है कि वर्तमान युग में विज्ञान अन्तर्राष्ट्रीय हो गया है, इसलिए उसकी शब्दावली भी अन्तर्राष्ट्रीय हो गई है। हिन्दी में यदि यह अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली अपना ली जाय, तो पारिभाषिक शब्दावली की समस्या हल हो जाय !

स्थिति यह है कि यूरोप की भाषाओं में बहुत से पारिभाषिक शब्द सामान्य हैं। लैटिन-ग्रीक के आधार पर बनाये हुए ये शब्द एक ही रूप में या थोड़े से रूप-परिवर्तन के बाद विभिन्न यूरोपीय भाषाओं में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे शब्दों को अपनाने में कोई हानि नहीं है। भारत सरकार की ओर से १९६२ में जो पारिभाषिक शब्दकोश प्रकाशित हुआ है, उसमें लगभग हर पृष्ठ पर इस श्रेणी के कुछ शब्द दिये हुए हैं। कोवाल्ड, उरेनियम, उरेनस, उरेडियम, उरेमा, ऑक्सीजन, ऑक्सीनाइट्रेट, यूकलिप्टस, अलकोहल, एथीलीन आदि ऐसे ही शब्द हैं।

इस तरह की सामान्य शब्दावली सीमित है। सीमित संख्या में ही उससे शब्द लिये जा सकते हैं। यूरोप की भाषाओं में प्रयुक्त होनेवाले सभी वैज्ञानिक शब्द अन्तर्राष्ट्रीय नहीं हैं। मास्को से वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों के कई कोश प्रकाशित हुए हैं। जो लोग वैज्ञानिक शब्दावली की अन्तर्राष्ट्रीयता में बड़ी दृढ़ता से विश्वास करते हैं, उन्हें ये कोश अवश्य देखने चाहिए।

उदाहरण के लिए, हवाई जहाजों की उड़ान से सम्बन्धित एक अंग्रेजी-रूसी कोश है। जीवन का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जिसमें सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली की आवश्यकता अधिक हो। लेकिन अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्द अक्सर प्रचलित शब्दों के आधार पर बनाये गए हैं और रूसी से भिन्न हैं। अंग्रेजी में एक प्रचलित शब्द है ‘कौक’। इसको आधार मानकर एयरकौक, एयर एस्केप कौक, वॉलेंस कौक, कंट्रोल कौक, ड्रेन कौक, फ्यूएल कौक, थ्रीटलिंग कौक आदि पारिभाषिक शब्दावली बनाई गई है। रूसी कौक शब्द का प्रयोग नहीं करते। इसलिए वे दूसरी तरह के शब्दों का व्यवहार करते हैं। अंग्रेजी में प्रचलित शब्द है, कंट्रोल। इसे आधार मानकर सकुलेशन कंट्रोल, डेपथ

कटान, डिस्टिंग कटान, इलेक्ट्रिक प्लाइड कटान, एनीवटर कटान, इमर्जेन्सी कटान, पलाटन कटान, ग्राउंड कटान आदि शब्दावली बताते हैं। इसी तरह लडिंग के आधार पर कीमविड नडिंग, डेड एंजिन लडिंग, फोम्ड लडिंग, गनअवे लडिंग आदि, एयरक्राफ्ट के आगार पर कम्पैट एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट, मिगिल एयरक्राफ्ट, जेट एयरक्राफ्ट आदि शब्दावली निर्मित हुई है। इनमें सभी शब्दावली बिल्कुल भिन्न हैं जैसे कटान के लिए हमी शब्द है उग्रावलेनिये एयरक्राफ्ट के लिए सामान्योन इत्यादि।

साम्बा में कुछ पारिभाषिक शब्दकोश ऐसे प्रकाशित हुए हैं जिनमें मात्र भाषाओं में शब्दावली शब्द एक साथ दिए हुए हैं। इस तरह के कोशों का प्रकाशन हो सिद्ध करता है कि यूरोप में कोई सममान्य अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक शब्दावली नहीं है। अफेडा में प्रयुक्त जो शब्द कुछ लोगों का बहुत अन्तर्राष्ट्रीय लग सकते हैं, उनके लिए भी यूरोप में भाषाओं में अलग शब्द हैं। जेट के लिए हमी में स्क्रूया शब्द है, काबन, कार्बन डाई-ऑक्साइड टैंडन, थॉरियम लेबियम गैस्टिक, ओवरी स्नैड, एन्वली और न्यूक्लियर के लिए हमी में क्रमशः उल्गाद उल्गाकीम्बुद् शब्द, मुल्गामीलिये, गूदा, गदा, फ्रेडो बुद, पाइन्चिक, कैलेडा इक्लाच और पाइनाया शब्द हैं। ऑक्सीजन के लिए हमी और जर्मन में अपन शब्द किमेनरोड और जावर स्टीक हैं। नाइट्रोजन के लिए इनालवी, प्रामीमा और हमी में अञ्जाल शब्द का प्रयोग होता है। फोस्फोर के लिए ल्यूमिनोफोर, मुननार्गलिया, लायस्टम्टीक आदि शब्द हैं। टच और जर्मन भाषाएँ एक-दूसरे में बहुत भिन्न हैं। प्रिड के लिए उनके भिन्न शब्द हैं—रोस्टर और गिटर। इग्नाइटर के लिए डच में ओइस्टर, जर्मन में ल्यूटमिस्ट शब्द हैं।

इन विवरण में स्पष्ट है कि भारतीय भाषाओं को अपने पारिभाषिक शब्दों का निर्माण और व्यवहार करने की पूर्ण स्वाधीनता है। वे सीमित सहाय में यूरोपीय भाषाओं में शब्द ले सकती हैं। सममान्य वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली का अस्तित्व वही नहीं है।

(१९६४)

## संस्कृति और भाषा

भाषा को आप चाहे संस्कृति का ही अंग मानें चाहे उससे भिन्न, दोनों के घनिष्ठ सम्बन्ध को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। वाक्य-रचना की पद्धति हमारी चिन्तन-पद्धति पर निर्भर होती है। आप अपनी भाषा में कर्म को क्रिया के पहले विठाते हैं या बाद को, यह आपकी परम्परागत जातीय चिन्तन-प्रक्रिया पर निर्भर है। आप अपनी भाषा में किस तरह के विदेशी शब्द कितने परिमाण में ग्रहण करते हैं, यह आपके जातीय चरित्र पर निर्भर है। आप अपनी भाषा का सम्मान करते हैं, दैनिक जीवन में उसका व्यवहार करते हैं अथवा उसे पैरों तले रौंदते हैं और किसी अन्य भाषा को सिर चढ़ाते हैं, यह आपकी राष्ट्रीय सम्मान की भावना पर निर्भर है।

किसी भी देश में उसकी भाषा या भाषाओं की स्थिति विशुद्ध भाषा-विज्ञान के नियमों से समझ में नहीं आ सकती। वह स्थिति देश की आन्तरिक और बाह्य परिस्थितियों पर निर्भर है। आज संसार के बहुत बड़े हिस्से में अंग्रेजी का बोलवाला है। ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र अमरीका दो देश ऐसे हैं जो अन्य देशों में पूँजी का निर्यात करते हैं, जो प्रच्छन्न और प्रकट रूप से उपनिवेशवाद का पोषण करते हैं, जो अपने प्रभाव को साम-दाम-दण्ड-भेद की बहुरंगी नीति से सुरक्षित करके और व्यापक बनाने में लगे हुए हैं। राजनीति से लेकर शिक्षा और संस्कृति तक जिस देश में जैसे वन पड़ता है, ये घुसने-पैठने, अपनी जड़ जमाने की कोशिश करते हैं। इनकी एक भाषा-सम्बन्धी स्पष्ट नीति है, पहले के समान यहाँ की भाषाओं को दबाकर रखना, उन सबके ऊपर शीर्ष स्थान पर अंग्रेजी को जमा कर रखना। इससे लाभ यह होता है कि आपके मर्मस्थल पर प्रहार करके आपको कमजोर बनाकर वे आपको अपनी स्वार्थ-नीति की ओर आसानी से खींच सकते हैं। मर्मस्थल है, जातीय भाषा के प्रेम का स्थल, जातीय संस्कृति के प्रेम का स्थल, राष्ट्रीय आत्म-गौरव का स्थल। आदमी को इस स्थल पर मारिये, उसे भीतर से निर्बीज कर दीजिये, फिर उस बलि-पशु को चाहे जिस खूँटे से बाँधकर उसका वध कर दीजिए।

आप उस देश की दशा पर विचार कीजिए जो अन्न से लेकर अस्त्र-शस्त्र तक पर-मुखापेक्षी है, जो अपनी स्वाधीनता की रक्षा के लिए उन्हीं लोगों का मुँह जोहता है जो अब

तक उसे मुलाम बनाए हुए थे। इसी नीति के अनुसृत भाषाक्षेत्र में भी हमारे देश के नेता पर-मुखापेगी हैं। जिस अंग्रेजी भाषा न त्रिदोनी राज्यकाल में यहाँ की मापाओं को पदमर्दिन किया, यहाँ की मन्त्रिनि और माहिरय के सहज विकास की पुष्टि न किया अंग्रेजी के जिस आधिपत्य के विरुद्ध भारतीय मनीषियों ने सतत सघष किया, उस अंग्रेजी का हटाकर भारतीय भाषाओं का उनका स्वत्व देने में सामक और गिहामंत्री हिचकिचा रहे हैं।

हमारी सासुनिक पराधीनता भाषा के क्षेत्र में अनेक रूपों में प्रकट होनी है।

हमारे सविधान में लिखा है कि हिन्दी भाषा को विकसित होने के लिए समय दिया जाय। हिन्दी का विकसित करने के लिए एक विनाम निदेशानय चानू है। हिन्दी में क्या कमी है कमी है या नहीं, है तो उसे कम पूरा किया जाय, हिन्दी और भारतीय भाषाओं को दानुने 'विश्वभाषा' अंग्रेजी में नी कोई कमी है या नहीं, है तो उसे कम पूरा किया जाय—एन समका निदान करने के लिए कोई आयोग नहीं बनाया गया, भाषा की निदि-गमूदि जांचने का योग मत्रह साल में नहीं आया। करोड़ों रुपये इस धन निद सय पर खच हो गए हैं कि 'विश्वभाषा' अंग्रेजी विकसित और समृद्ध है और भाषी राष्ट्र-भाषा हिन्दी अविकसित और दरिद्र है।

ममर्दि का काय कोष निर्माण द्वारा सम्पादिन जाना है। कोष निर्माण के लिए अंग्रेजी गड्ड पहले हैं, हिन्दी बाद की। हमारी सामाजिक-सांस्कृतिक आवश्यकता के लिए कौन से शब्द आवश्यक हैं, यह विषय अगोचर ही रहता है। कोष-निर्माताओं में अनेक जन अंग्रेजी से जितना आतकिन रहने हैं, उतना ही हिन्दी की प्रकृति से अनभिन् नी। वे ऐसे 'स्थितिनि और 'गतिन' ऊर्जा वाले शब्द गढ़ने हैं कि 'तत्रिकानत्र' भ्रष्ट हो उठता है और उनकी 'राष्ट्रिकता' को देखकर साधारण पठिन जन यही मोचने हैं कि इसमें तो अंग्रेजी भली। हिन्दी को समृद्ध करने के नाम पर अस्वाभाविक, उच्चारण में दुष्कार शब्दों का निर्माण भाषा के प्रति अवनता का परिचायक है, अज्ञान का तो है ही।

सासुनिक, सामाजिक, राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार में जहाँ हिन्दी बालना चाहिए, वहाँ हम अंग्रेजी से काम लेने हैं। परिवार के भीतर बचपन से अपनी सन्तान को हम डेडी, मग्गी, अकल कहना मिखाने हैं मानो यहाँ भी पारिभाषिक शब्दों की कमी हो। हमारे उच्च मध्यक के लोगो की बहुत बड़ी आकाशा यह रहती है कि बेटा कौं-वेंड में पड़े, फरटि से अंग्रेजी बोने, मजिस्ट्रेट बनकर लोगो पर हुकूमत करे। किसका सेवाभाव, किसने गांधी और बुद्ध। खाने के दात और, दिव्यान के और।

जहाँ तक मुझे मालूम है, इस देश की राजनीतिक पार्टियाँ अपना केन्द्रीय राजनीतिक कार्य, अपने केन्द्रीय मुखपत्र अंग्रेजी में चलाती हैं। हम विश्वभाषा के नाम पर अंग्रेजी पढ़ने पर खोर देते हैं। जहाँ फ्रांस का राज्य था या है, वहाँ विश्वभाषा का दर्जा फ्रांसीसी को मिला है। किस पिछड़े हुए देश ने यूरोप की किस भाषा को विश्व-भाषा माना है, यह हम पर निर्भर है कि उस पर यूरोप के किस देश का आधिपत्य था या है।

हमारे अनेक युगान्तरकारी साहित्यकार अपनी वाक्य-रचना में अंग्रेजी शब्दों की ऐसी भरमार करते हैं मानो हिन्दी में सोचना उन्होंने बन्द कर दिया है। वे न हिन्दी में सोचते हैं, न अंग्रेजी में बरन् इन दोनों से मिली हुई एक नई इंग्लिशतानी भाषा में, जो उसके लिए बहुत स्वाभाविक है किन्तु जो देश की जनता के लिए, हमारे समग्र सामाजिक विकास के लिए घातक है। अनेक लेखक अंग्रेजी मुहावरों का अनुवाद करके अपनी जातीय भाषा को सजाते हैं। अंग्रेजी के शब्दों, उद्धरणों और अनुवादित मुहावरों से वे अपनी—भाव-विचार-अनुभव की—दरिद्रता छिपाते हैं। अपनी सांस्कृतिक परम्परा के लिए, भारतीय भाषाओं और उनके साहित्य के लिए उनके हृदय में अनादर की भावना है। उनमें बड़ी उत्सुकता होती है कि नई अंग्रेजी पुस्तकों की चर्चा करके अपने सुसंस्कृत होने का परिचय दें। वे साधारणतः यूरोप की भाषाओं से अपरिचित होते हैं और यूरोप के साहित्य को अंग्रेजी निगाह से ही देखते हैं।

हिन्दी के अनेक समर्थ साहित्यकार इस भाषा-सम्बन्धी पराधीनता से मुक्त हैं। कुल मिलाकर हिन्दी साहित्य अपने स्वस्थ जातीय मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि छापे की सुविधा से लाभ उठाकर बहुत से लेखक ऐसी भाषा का प्रयोग करने लगे हैं जो हिन्दी के सहज विकास के लिए घातक है।

इनसे भिन्न श्रेणी का एक लेखक-समुदाय और है जो अंग्रेजी के माध्यम से ही अपनी कलात्मक प्रतिभा का परिचय देता है। वे किसान-देश की संस्कृति का उद्धार कर रहे हैं, अंग्रेजी में उपन्यास, कहानियाँ, कविताएँ लिखकर। माना कि अंग्रेजी विश्वभाषा है और उसमें लिखने से अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति जल्दी मिलती है किन्तु नाबे, डेनमार्क, इटली, स्पेन, जैसे छोटे देशों के लेखक इस विश्वभाषा को नहीं अपनाते, उसे अपनाने का ठेका हमारे महान् देश के लेखकों ने लिया है।

हमें अपनी भाषा के जातीय रूप की रक्षा करनी चाहिए। उसमें अंधाधुन्ध अंग्रेजी शब्दों की भर्ती हमारे राष्ट्रीय सम्मान के विपरीत है। हिन्दी की शक्ति उसे अपनाने, प्यार करनेवाली जनता की शक्ति है। दुर्बोध, उच्चारण के लिए विकट शब्दावली से उसे भरसक बचाना चाहिए अर्थात् हमें भरसक अपनी शैली सुगम बनानी चाहिए और वैज्ञानिक शब्दावली में भी भरसक हिन्दी की प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए। हमारा साहित्य इस देश की जनता के लिए है। इसलिए इंग्लिशतानी के बदले हिन्दी का ही प्रयोग करना चाहिए। अंग्रेजी के माध्यम से प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति अस्थायी है। रवीन्द्रनाथ और प्रेमचन्द ने अपनी भाषाओं के माध्यम से जो ख्याति पाई, वही स्थायी है। जातीय संस्कृति से भाषा का घनिष्ठ सम्बन्ध है, यह ध्यान में रखकर हमें अपने व्यवहार में सतर्क रहना चाहिए।

(१९६४)

## भाषा की समस्या—अति आवश्यक

दल की राजनीतिक परिस्थिति की एक विशेषता यह है कि कांग्रेस को मिलने का न बाट दिन-पर दिन कम हो जा रहे हैं और उसी परिमाण में वामपक्षी पार्टियाँ और उनका संयुक्त मार्चा समय होकर जनता के सामने नहीं आ रहे। पिछले दिनों कम्युनिस्ट पार्टी में विघटन के कारण वामपक्ष और भी कमजोर हो गया है। हिन्दी-भाषी प्रदेश में विपक्ष रूप से दक्षिणपक्षी दल उभरते हैं। चूंकि भारत में हर समस्या जन्तरीपन्तीय परिस्थिति में अनुकूल ही हो नहीं होती, इसलिए हर जागरूक नागरिक को फासिस्ट साजिशवादी की संभावना के प्रति सतर्क रहना चाहिए।

जर्मनी के अनुभव ने हमें जाना है और अपने देश का अनुभव भी यही बताना है कि फासिस्ट दल सत्त्वृति के प्रश्न लेकर जनता को गुमराह करते हैं। हिटलर मध्यपूर्व ही नहीं, मजदूर वर्ग के भी एक भाग को गुमराह करने में सफल हुआ था। हमारे देश में साम्प्रदायिक दल सत्त्वृति के प्रश्न विशेष रूप से जनता के सामने रखते हैं। वे अपने की भारतीय सत्त्वृति का एकमात्र रक्षक मानते हैं। सत्त्वृति को टाल बनाकर वे अपनी गलत राजनीति के असर जनता पर चलाते हैं।

कुछ प्रगतिशील लोग समझते हैं कि यदि वे भी सत्त्वृति की बात करेंगे तो उनमें और साम्प्रदायिक दलों में कोई अंतर न रह जायगा। आजकल हिन्दी भाषा के सवाल को लेकर हिन्दीभाषी क्षेत्रों में बड़ी सरगर्मी है। कुछ प्रगतिशील लोग समझते हैं कि अंग्रेजों को व्यवहार में लाना, अंग्रेजों में अपने दस्तावेज तैयार करना, अंग्रेजों में अपने राजनीतिक सम्मेलनों की आवश्यकता सम्पन्न करना, व्यावहारिक राष्ट्रभाषा के रूप में अंग्रेजी को प्रतिष्ठित रखना बहुत बड़ा साम्राज्यवाद विरोध है, राष्ट्रीयता और जनता के हित में है और साम्यवाद के अनुकूल है। इसके विपरीत अखिल भारतीय स्तर से अंग्रेजी को हटाने की माँग करना, हिन्दी को केन्द्रीय राजभाषा की भाषा बनाने के लिए आन्दोलन करना साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन देना है।

कोई भी प्रगतिशील दल भाषा और सत्त्वृति के मामलों में कितना दखल देता है, यह उसके व्यवहार से जाना जाता है। मिसाल के लिए यह विचारणीय है कि मैथिली सरण गुप्त के निधन पर किन राजनीतिक दलों ने कहीं-कहीं शोक प्रस्ताव पास किये।

व्यवहार के अलावा विभिन्न दलों के कार्यक्रम-प्रस्ताव आदि दर्शनीय हैं यह जानने के लिए कि उन्होंने सांस्कृतिक समस्याओं पर कितना विचार किया है।

माना कि सांस्कृतिक समस्याएँ बहुत उलझी हुई हैं। यह भी माना कि राजनीतिक समस्याएँ सुलझाने में ही बहुत से नेताओं की सारी ताकत खर्च हो जाती है। किन्तु भाषा की समस्या करोड़ों आदमियों को प्रभावित करती है। वह व्यापक सामाजिक समस्या बन गई है। उस पर सही दृष्टिकोण अपनाना और सही नीति के अनुसार आन्दोलन करना प्रगतिशील जनों का कर्तव्य है।

सवाल यह नहीं है कि जब कांग्रेसी सरकार के बदले हमारे मन-मुताबिक दूसरी हुकूमत बनेगी तब हम अंग्रेजी को जल्दी हटा देंगे या धीरे-धीरे, देर में हटा देंगे। सवाल यह है कि अभी हम क्या करने जा रहे हैं। और अभी जो कुछ करते हैं, उस पर बहुत-कुछ निर्भर है कि भविष्य में यहाँ जनता की सरकार बनेगी या फासिस्ट तानाशाहों की।

जब अंग्रेजी राज कायम था तब भाषा की समस्या सभी साम्राज्य-विरोधी दलों और उनके नेताओं के सामने उलझी हुई नहीं थी। एक बात पर सभी सहमत थे कि अंग्रेजी जाय; उसके बने रहने से देश की शक्ति और धन का नाश होता है। आजकल अनेक साम्राज्यविरोधी योद्धा इस बात पर एकमत दिखाई देते हैं कि कागज पर चाहे जो छपा रहे, व्यवहार में अंग्रेजी ही राष्ट्रभाषा बनी रहे !

हिन्दी-भाषी प्रदेश में कोई भी दल भाषा के सवाल को नजरान्दाज करके शक्ति-शाली नहीं बन सकता। अंग्रेजी को हटाने और हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने की माँग जनता की न्यायपूर्ण साम्राज्यविरोधी राष्ट्रीय माँग है। प्रगतिशील नेताओं को उसका समर्थन ही न करना चाहिए, आगे बढ़कर उसके लिए आन्दोलन करना चाहिए। वे लोग ही विभिन्न भाषाओं के उचित अधिकारों की रक्षा करते हुए हिन्दी के लिए सही आन्दोलन कर सकते हैं। वे अपना उत्तरदायित्व निवाहेंगे तो दक्षिणपंथी ताकतों को अवसर मिलेगा कि वे सही माँग के लिए गलत ढंग से आन्दोलन चलाएँ, जातीय और साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाएँ और जनवादी पार्टियों के दमन के लिए आवश्यक तैयारी करे। जो प्रगतिशील नेता अब भी बेखबर रहते हैं, वे वस्तुगत रूप से जनतंत्र का नाश करने और तानाशाही को लाने के लिए जिम्मेदार होंगे।

(१९६५)



## अंग्रेजी की सुरक्षा के लिए संघर्ष

पिछले दिना तमिलनाडु में जैसा विरोध और उपसंघर्ष हिन्दी के विरोध में हुआ, वैसा अंग्रेजी का हटाने के लिए भी वहाँ न हुआ था। माना है, जबानव तमिल भाषा पर ऐसी विपत्ति आ गई जैसी उसके सुदीर्घ इतिहास में पहले कभी न आई थी। यदि तमिल पर कोई विपत्ति आए तो हम हिन्दी भाषियों का यह कर्तव्य है कि प्राणपण से तमिल भाषियों की सहायता करें।

तमिल भाषा को वह कौन-सा अधिकार प्राप्त था, जो इन वर्ष २६ जनवरी से छिन गया? तमिलनाडु में क्या उसके व्यवहार पर किसी तरह का प्रतिबंध लगा है? क्या अविल भारतीय स्तर पर कही उसका व्यवहार होता था, जो अब बन्द कर दिया गया है?

किसी वस्तु में, किसी क्षेत्र में यह प्रकट नहीं होना कि तमिल भाषा का कहीं दमन किया गया है। यदि कोई भी यह सिद्ध कर दे कि तमिल भाषा पर जरा भी अंग्रेजी आई है, तो हम अत्याय का विरोध करना में अपना कर्तव्य समझेंगे।

तमिल-मध्यम शैली स्थिति वास्तव में दूसरी है। अंग्रेजी राज में अंग्रेजी के राज-भाषा होने के कारण तमिल के अधिकार छीन लिये गए थे। वह विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम नहीं थी। अब उसे तमिलनाडु के सामाजिक जीवन में हर स्तर पर व्यवहार में आने का अवसर मिला है। अंग्रेजों के बिदा होने से भारत की प्रत्येक भाषा की तरह तमिल को भी फलने-फूलने और विकसित होने का अवसर मिला है।

इस अवसर से तमिलभाषी जनता के नेताओं ने लाभ नहीं उठाया। मद्रास राज्य में तमिल को उच्च शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया गया। एक समाचार के अनुसार पिछले साल विद्याधिया के अभाव में तमिल माध्यमवाला विद्यालय सरकार को बन्द करना पड़ा ('हिन्दी व्लिन्ड', ६ फरवरी, '६५)।

यदि तमिलनाडु में इस आन्दोलन के नेता वास्तव में मानुभाषा से प्रेम करते थे, तो उन्हें सबसे पहले तमिल की शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए संघर्ष करना चाहिए था। ऐसा उन्होंने नहीं किया। तमिल के बदले वहाँ हिन्दी की शिक्षा का माध्यम बनाने की बात होनी, तो भी उनके आन्दोलन को न्यायपूर्ण कहा जा सकता था। किन्तु ऐसी

कोई बात नहीं थी। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि तमिल पर कोई विपत्ति नहीं आई; तमिल-प्रेम की दुहाई देकर वहाँ की जनता को भ्रम में डाला गया है; तमिलनाडु में तमिल के व्यवहार के लिए जो मुद्दिघाएँ प्राप्त हैं, उनका उपयोग वहाँ के हिन्दी-विरोधी नेता नहीं करते।

संघर्ष हिन्दी-तमिल के बीच नहीं है। संघर्ष है हिन्दी-अंग्रेजी के बीच, अंग्रेजी और समस्त भारतीय भाषाओं के बीच, अंग्रेजी और तमिल के बीच।

इस संघर्ष को भारतीय भाषाओं के पक्ष में हल किया जा सकता है, यह एक तरीका हुआ। इस संघर्ष को अंग्रेजी के पक्ष में हल किया जा सकता है, यह दूसरा तरीका हुआ। तमिलनाडु के हिन्दी-विरोधी नेताओं ने दूसरा तरीका चुना है। अर्थात् उनका आन्दोलन तमिल की सुरक्षा के लिए नहीं है, वह अंग्रेजी की सुरक्षा के लिए है। गालियाँ हिन्दी भाषा को दी जाती हैं, साइनबोर्ड हिन्दी के मिटाये जाते हैं, किताबें हिन्दी की जलाई जाती हैं। हित होता है अंग्रेजी का। इन कार्यों से तमिल की स्थिति अधिक सुरक्षित नहीं होती। स्थिति सुरक्षित होती है अंग्रेजी की।

यह बात तमिलनाडु के लोगो को ही नहीं, हिन्दीभाषी प्रदेश की जनता को भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि यह संघर्ष हिन्दी-तमिल का नहीं है, वरन् अंग्रेजी और समस्त भारतीय भाषाओं का है। हिन्दी-तमिल-विरोध के बड़े घातक परिणाम हो सकते हैं। एक बार गृहयुद्ध की आग भड़कने पर उसे रोकना असम्भव हो जाएगा।

इस समय देश में अंग्रेजी की स्थिति क्या है ?

वैधानिक रूप से हिन्दी के साथ अंग्रेजी भी राष्ट्रभाषा है। व्यावहारिक रूप में भारत की एकमात्र राष्ट्रभाषा अंग्रेजी है। स्वाधीनता आन्दोलन के दौरान सभी साम्राज्य-विरोधी पाटियाँ इस बारे में एकमत थी कि राष्ट्रभाषा का स्थान अंग्रेजी को नहीं, किसी भारतीय भाषा को मिलना चाहिए। सन् '४७ में अंग्रेजी को हटाने का अवसर आया। अंग्रेजी को हटाने का काम सन् '६५ तक के लिए स्थगित कर दिया गया। जब सन् '६५ नजदीक आया तब वैधानिक परिवर्तन द्वारा अंग्रेजी को भविष्य में अनिश्चित काल के लिए सहायक राजभाषा बना दिया गया।

तब अंग्रेजी पर अचानक कौन-सा संकट आ गया ? अंग्रेजी के साथ अब हिन्दी भी राजभाषा है, यह संकट है। कम-से-कम कहने को हिन्दी भी राजभाषा है। अहिन्दी प्रदेशों को अंग्रेजी के व्यवहार की पूरी छूट है। किन्तु इससे अंग्रेजी-प्रेमियों को सन्तोष नहीं है। ४ फरवरी को नई दिल्ली में अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा समिति (ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन) ने प्रस्ताव पास किया कि हर राज्य में वैज्ञानिक और प्राविधिक शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही रहेगी। क्या यह भारतीय भाषाओं पर अंग्रेजी लादना नहीं है ? अंग्रेजी को लादना तो राष्ट्रीय एकता के लिए हितकर बताया जाता है; अंग्रेजी की जगह हिन्दी के चलन की बात भी करना साम्राज्यवाद है ! तमिल की जगह तमिलनाडु में ही अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनी रहे, तो इससे राष्ट्र का

विकसित होता है, यदि केन्द्रीय राजकाज के लिए—नमिनताड में नहीं, केवल केन्द्रीय राजकाज के किसी अत्यन्त सीमित दायरे में—हिन्दी के चयन की बात की जाय तो साम्राज्यवाद हो जाता है ।

दश का भना चार्जन वाले अनेक नेताओं और पत्रकारों ने लिखा है, वस्तुतः दिये हैं कि दक्षिणवाला का भय जायज है और उस दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए । यह भय क्या है ? यह यह है कि हिन्दी के राजभाषा होने से अखिल भारतीय सरकारी नौकरियाँ हिन्दावाले इधियाँ नैम दक्षिणवाले टापने रह जायेंगे । राष्ट्रीय एकता और नमिन प्रेम का नम टटना है नौकरियों के मामले पर । किसी समय भारत का उच्च वर्ग अंग्रेजों से माग करता था कि सरकारी नौकरियों उसे भी दी जाए, अंग्रेजों के लिए सुरक्षित न रह । उस उच्च-वर्ग का भारत की स्वाधीनता की चिन्ता नहीं थी, उसकी लड़ाई थी सरकारी नौकरियों के लिए । तमिलनाडु और अन्य प्रदेशों के अंग्रेजी प्रेमी नेताओं की राटी राटों का समझा हल करने की, दश के आर्थिक विकास की चिन्ता नहीं है । उन्हें सबसे बड़ी चिन्ता है सरकारी नौकरियों की । ठीक है । सरकारी नौकरियों की चिन्ता कीजिए । लेकिन राष्ट्रीय एकता के लवाद से इस स्वार्थ का मत ढँकिये । मानूँ भाषा प्रेम का पवित्र भावना जगाकर नौकरियों के इन सधप में भोली भाली जनता का पुलित-नीज की गतिविधि का गिकार न बनाइए ।

अखिल भारतीय नौकरियों के लिए जो परीक्षाएँ होती हैं, उनमें अंग्रेजी और हिन्दी की स्थिति क्या है ? स्थिति यह है कि अभी तक इन परीक्षाओं का एकमात्र माध्यम है अंग्रेजी । इस माध्यम को हटाने की कोई भी योजना नहीं है, कागजों और पर भी नहीं है । मकट केवन यह है कि केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न प्रदेशों के मुख्य मन्त्रियों की राय से एक प्रयोग करने का निश्चय किया है । वह प्रयोग यह है कि यदि हिन्दी को भी अंग्रेजी के साथ—अंग्रेजी की जगह नहीं—कुछ विषयों में (सभी विषयों में नहीं) परीक्षा का माध्यम बनाया जाय तो इससे अंग्रेजी माध्यमवाले पाठे में तो नहीं रहेंगे । यह प्रयोग हुआ नहीं है । उसके होने की बात है । उस प्रयोग से जब अहिन्दी भाषी भी सन्तुष्ट हो जायेंगे कि अंग्रेजी का व्यवहार करने पर उन्हें घाटा न होगा, तब उनके सहमत होने पर कुछ विषयों में अंग्रेजी के साथ हिन्दी भी एक ऐच्छिक माध्यम हो सकती है । अंग्रेजी के लिए इतना ही मकट उत्पन्न हुआ है ।

प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिन्दी-प्रेमियों का अंग्रेजी हटाने में जल्दी न करनी चाहिए । स्वराष्ट्र मंत्री ने कहा है हमें इस मामले में जल्दी न करना चाहिए । कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने सरकार को सलाह दी है कि हिन्दी को राजभाषा बनाने में जल्दी न करनी चाहिए । आखिर वह कौन-सी तेज रफ्तार थी और किस क्षेत्र में थी, जिससे हिन्दी राजभाषा बनी जा रही थी ? आजादी पाने के अठारह साल बाद जो सरकार अखिल भारतीय नौकरियों के लिए हिन्दी को केवल ऐच्छिक माध्यम बनाने के प्रयोग की बात करती है, उसमें भी कुछ बुद्धिमानों को तेज रफ्तार की सलाह नहीं होती है ।

हिन्दी तो एक दिन राजभाषा होगी, लेकिन धीरे-धीरे—ऐसा कहनेवाले वास्तव में अंग्रेजी की हिमायत करते हैं। इसका प्रमाण यह है कि अपना अखिल भारतीय राजनीतिक कार्य ये नेता और उनकी पार्टियाँ अंग्रेजी में करती हैं। व्यवहार में अंग्रेजी; हिन्दीभाषी जनता के वोट लेने के लिए भविष्य में हिन्दी को राजभाषा बनाने के वायदे ! यह दुरंगी नीति ज्यादा दिन नहीं चलेगी।

कुछ दूसरे लोग हैं जो मांग करते हैं कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री ने अंग्रेजी के सम्बन्ध में जो वायदे किये थे, वे संविधान में दर्ज हो जाने चाहिए। यद्यपि वर्तमान प्रधानमंत्री ने उन आश्वासनों को दुहराया है, किन्तु बहुत-से देशभक्तों के लिए इतना काफी नहीं है। वे चाहते हैं कि संविधान में उन आश्वासनों को दर्ज कर दिया जाय।

⑩ अनेक स्थानों में यह नया नारा मुनने को मिला है—‘हिन्दी नेवर, इंग्लिश एवर।’ हिन्दी कभी न आए, अंग्रेजी हमेशा बनी रहे ! दक्षिण में जो उच्चकोटि के प्रतिक्रियावादी नेता हैं, वे यही नारा दे रहे हैं कि भारत की एकमात्र राजभाषा अंग्रेजी हो। अपने आन्दोलन के जरिये वे सबसे पहले तमिल की जड़ काट रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की कृपा से तमिलनाडु में तमिल उच्चशिक्षा का माध्यम नहीं बनी। इसके बाद वे विशाल हिन्दीभाषी प्रदेश पर—तथा अन्य अहिन्दी राष्ट्रभाषा-प्रेमी जनता पर—सदा के लिए अंग्रेजी का प्रभुत्व कायम रखने का पड़्यन्त्र कर रहे हैं। अंग्रेजी के इस वास्तविक साम्राज्यवाद को देश की जनता कभी सहन न करेगी।

यह ध्यान देने की बात है, हिन्दी-विरोधी आन्दोलन ने भयानक उत्पात का रूप केवल तमिलनाडु में लिया है। अंग्रेजी-प्रेमी नेता अन्य प्रदेशों में भी हैं, किन्तु उन्होंने कोई उग्र आन्दोलन नहीं चलाया। इसके दो कारण हैं। पहला यह कि अंग्रेजी-प्रेमी नेता जानते हैं कि वास्तव में अंग्रेजी के लिए कोई खतरा नहीं है, हिन्दी को व्यावहारिक राजभाषा होने में बहुत देर है। इसलिए गर्म या नर्म किसी तरह के आन्दोलन को वे अनावश्यक समझते हैं। दूसरा कारण यह है कि तमिलनाडु को भारत से अलग करने के लिए जैसा आन्दोलन उस प्रदेश में हुआ है, वैसा आन्दोलन अन्य किसी प्रदेश को अलग करने के लिए नहीं हुआ। विघटन के इस प्रचार को राजनीतिक दलों ने सगठित किया। भाषाशास्त्र और इतिहास की झूठी गवाही से उस विघटन की भावना को वर्षों तक फैलाया। केन्द्रीय या तमिलनाडु का शासन अथवा कोई भी राजनीतिक दल उसका समर्थ प्रतिवाद नहीं कर पाया। यही कारण है कि हिन्दी-विरोधी आन्दोलन ऐसा विनाशक रूप केवल तमिलनाडु में ले सका।

इसका अर्थ यह है कि हिन्दी-विरोध एक नकाब है, जिसके नीचे विघटन का देव छिपा हुआ है। नौकरी न मिलेगी यह भय दिखलाकर स्वार्थी नेताओं ने छात्रों को उभारा है और स्वतन्त्र द्रविड़ राज्य कायम करने के लक्ष्य के लिए उनका उपयोग किया है। देश की स्थिति ऐसी है कि कश्मीर, नागालैण्ड या तमिलनाडु कोई भी प्रदेश अलग होता है, तो उसकी हिमायत के लिए साम्राज्यवादी आगे आते हैं। वे अपने फौजी अड्डों का स्वप्न

देसने हैं, भारत का जो हिस्सा मिला उसका उपयोग अपनी समस्या-योजनाओं के लिए करना चाहते हैं। कुछ विदेशी पत्रों ने तमिलनाडु के हिंदी-विरोधी आन्दोलन को लेकर तमिल को लिपि, तमिल भाषा की व्यंजना-चिह्न की बड़ी प्रशंसा की है और हिंदी को तमिल से नीचा ठहराया है। उस प्रचार का उद्देश्य भारत में गृहयुद्ध की आग सुलगाना है।

भारत ने अलग होकर तमिलनाडु या कोई भी प्रदेश न तो साम्राज्यवाद से मुक्त रह सकता है न अपना आर्थिक और सांस्कृतिक विकास कर सकता है। विद्रोहकारी आन्दोलन में सर्वप्रथम उस प्रदेश का अहित होता है, जहाँ ऐसा आन्दोलन चलाया जाता है। उस रात समूचे देश का अहित होता है। अंग्रेजी की सुरक्षा का यह आन्दोलन देश का विघटन का आदेश है। समस्या हिंदी और तमिल की नहीं है, समस्या तमिलनाडु का भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने की है।

यह सम्भव है कि भारत सरकार अंग्रेजी प्रेमियों के दबाव में अंग्रेजी की सुरक्षा के लिए कुछ और नियम कायद बना दे या संविधान में तब्दीली कर दे। इससे अंग्रेजी की वास्तविक स्थिति में कोई अन्तर न पड़ेगा। अंग्रेजी का राजभाषा के रूप में सुरक्षित है ही। भारतीय भाषाओं का उनका उचित अधिकार दिवाने के लिए यह जरूरी है कि सबमें पहले हिंदीभाषी प्रदेशों में अंग्रेजी को राजभाषा और सांस्कृतिक भाषा के पद से पूर्णतः हटा दिया जाय, विश्वविद्यालयों में पूर्णतः हिंदी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाय, जहाँ के न्यायालयों का सारा काम हिंदी में हो, सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन में अंग्रेजी का व्यवहार खत्म किया जाय। इसके बाद जिस दिन हिंदीभाषी जनता सगठित होकर अपने लोक सभा के प्रतिनिधियों को हिंदी में बोलने और सारा राजकाज हिंदी में करने के लिए बाध्य करेगी, उस दिन अंग्रेजी का साम्राज्यवाद खत्म हो जाएगा, उस दिन तमिलनाडु में तमिल भी अपना पूर्ण स्वतंत्र प्राप्त करेगी और राष्ट्रीय एकता को दृढ़ करने में हिंदीभाषी जनता अपनी भूमिका पूरी करेगी। अंग्रेजी को हटाने और राष्ट्रीय एकता दृढ़ करने का भार अब हिंदीभाषी प्रदेश पर है।

(१९६५)

## भाषा की समस्या और राष्ट्रीय विघटन

जिस समय भारत की संविधान सभा ने यह निश्चय किया कि राष्ट्रभाषा हिन्दी हो और तुरन्त नहीं, पन्द्रह साल बाद सन् '६५ में हो, उस समय इस फैसले के पक्ष में वोट देने वाले उत्तर के लोग भी थे, दक्षिण के भी, हिन्दी-भाषी इलाकों के नेता भी थे और अहिन्दी-भाषी प्रदेशों के भी। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि यह फैसला हिन्दी वालों ने दक्षिण या बंगाल पर लादा था।

जैसे-जैसे सन् '६५ निकट आता गया वैसे-वैसे उस फैसले को टालने के लिए भी कोशिशें होने लगीं। संसद ने एक कानून बना दिया जिसके अनुसार सन् '६५ के बाद भी अंग्रेजी सह-राजभाषा बनी रह सकती है। इस फैसले से हिन्दी को धक्का लगा, यह माना जा सकता है। किन्तु उससे किसी अहिन्दी भाषा को हानि हुई यह दावा कोई नहीं करता।

इसके बाद भी स्वर्गीय प्रधानमन्त्री ने आश्वासन दिया कि अहिन्दी-भाषियों की 'मर्जी के बिना अंग्रेजी को नहीं हटाया जाएगा। इस साल २६ जनवरी से दिल्ली सरकार ने अपना राजकाज हिन्दी में नहीं शुरू किया, किसी अफसर को हिन्दी न जानने के कारण निकाला नहीं गया, अखिल भारतीय नौकरियों के लिए परीक्षाएँ हिन्दी में नहीं होने लगीं, न अंग्रेजी को हटाकर उन परीक्षाओं के लिए हिन्दी को एकमात्र माध्यम बनाने का फैसला किया गया, उत्तर-दक्षिण के विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम हिन्दी नहीं बनी, किसी भी केन्द्रीय मन्त्रालय ने अपने कागज-पत्र हिन्दी में तैयार करना नहीं शुरू किया, न इस तरह के कागज-पत्र केन्द्र से राज्यों को भेजे गए, तमिलनाडु या बंगाल से अंग्रेजी में लिखकर भेजा हुआ कोई कागज दिल्ली से वापस नहीं किया गया, कांग्रेस के प्रधान श्री कामराज के तमिल में ही बोलने पर कहीं हिन्दी-जनता ने प्रदर्शन नहीं किया, फिर भी तमिलनाडु में उत्पात खड़ा हो गया !

केन्द्रीय सरकार में उत्तर-दक्षिण, हिन्दी-अहिन्दी सभी प्रदेशों के लोग हैं। इस सरकार का कोई भी काम सिर्फ हिन्दीभाषी जनता का काम नहीं माना जाता। फिर भी अगर कोई ऐसा काम हुआ हो जिससे अंग्रेजी की गौरवमय स्थिति को धक्का लगा हो तो मैं जानना चाहता हूँ कि वह काम कौन-सा है। सन् '६५ में हिन्दी को—कागज पर, दिखावे के लिए—

राष्ट्रभाषा बनाने का फैसला सोलह साल पहले किया गया था। कमना करनेवाले उत्तर-दक्षिणवाले दोनों थे। फिर अचानक अहिंदी भाषियों पर हिंदी आज कैसे तार दी गई ?

बुद्ध लोभा का कहना है कि भारत के सभी राज्यों की भाषाओं को बराबरी का दर्जा दे दिया जाय। मैं कहता हूँ गोक में दीजिए। लेकिन आप जित पार्टी में भी हों, उसका राजनीतिक काम दम-बारह भाषाओं में करने दिया जाए। जो पार्टियाँ अपना केन्द्रीय काम एक भाषा में करती हैं, उन्हें कोई हक नहीं है कि वे केन्द्र में दम भाषाएँ बनाने की बात करें।

बुद्ध बुद्धिमान नेता यह राय देते हैं कि राज्यों में वहीं की भाषाएँ चलें लेकिन केन्द्र में अंग्रेजी चले क्योंकि हिन्दी को अभी और विकसित होना है। दूसरा मतलब यह हुआ कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आदि के राजकाज के लिए तो हिन्दी विकसित है, केवल केन्द्रीय राजकाज के लिए वह अविकसित है। मैं जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश और केन्द्र के राजकाज में वह कौन-सा गुणात्मक अंतर है जिसमें हिन्दी एक जाह्न विकसित मानी जाती है और दूसरी जगह अविकसित।

जसलियत यह है कि अंग्रेजी को देश में कायम रखने के लिए हर दलील ज़रूर है। अंग्रेजी के जरिये हमारा अपना बर्ग साहब बनकर जनता पर हुकूमत करता है। और हर पार्टी के अंदर अंग्रेजी के कारण एक ऊँचे पाये का नेता है जिसने अपने महान् विचार प्रकट करने में किसी भारतीय भाषा को माध्यम बनाते हुए बड़ी कठिनाई होती है। दूसरा नेता छोटे दर्जे का केवल भारतीय भाषाएँ जाननेवाला है। अंग्रेजी के जरिये अपना और जनता, साहब और गुलाम, बड़ा आदमी और छोटा आदमी—दो वर्गों में सारे देश को बाँटने में सफलित होती है। जो लोग कहते हैं कि अंग्रेजी के रहन से राष्ट्रीय एकता कायम रहती है, उनका मतलब यही होता है कि उसके जरिये बाले साहबों की एकता कायम रहती है। इस एकता के कारण आम जनता और हुकूमत के बीच कितना बड़ा फासला कायम रहता है, इसकी चिन्ता उन्हें नहीं होती।

अब यह बिलकुल स्पष्ट है कि लड़ाई तमिल या बंगाल के अधिकारों के लिए नहीं है। लड़ाई है अंग्रेजी के ब्रेजा अधिकारों की रक्षा के लिए। तमिलनाडु के जिन विचार-समूहों में तमिल की शिक्षा का माध्यम बनाया गया उन्हें बन्द कर देना पड़ा। आंध्र के शासकों का कहना है कि तेलुगु को राजभाषा बनाने में दम साज लगेगा। इसमें क्या साबित होता है ? क्या हिन्दी राष्ट्रभाषा बनकर तमिल और तेलुगु के अधिकार छीन ले रही है ? हकीकत यह है कि आंध्र और तमिलनाडु में राजभाषा अंग्रेजी है और उसे हटाने के बदले प्रदेश प्रेमी मज्जन हिन्दी विरोधी आन्दोलन चला रहे हैं।

केन्द्र में अंग्रेजी और प्रदेश में अंग्रेजी—दोना जाह्न के तार आपस में जुड़े हुए हैं। जो केन्द्र में अंग्रेजी हटाने का विरोधी है वह प्रदेश में भी उसे नहीं हटाना चाहता। चात बिलकुल स्वाभाविक है। तमिलनाडु में रहनेवाला जो गृहस्थ अपने बेट को ऑल इंडिया सर्विस में अपना बनाना चाहता है वह उनके लिए तमिल की शिक्षा का माध्यम

क्यों बनाए ? प्रदेश में हर स्तर पर वही की भाषा चालू हो जाय तो होनहार नौजवानों की अंग्रेजी लिखने-बोलने में कठिनाई न होगी ? अंग्रेजी कौन ज्यादा अच्छी बोलेगा— वह जिसकी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रही है या वह जो शिक्षा प्रादेशिक भाषा में पाता रहा है ? इसीलिए गुजरात में आन्दोलन हो रहा है कि अंग्रेजी की शिक्षा को वही दर्जा दिया जाय जो और राज्यों में उसे प्राप्त है ।

जब तक केन्द्र की राजभाषा अंग्रेजी है तब तक प्रदेशों में वहाँ की भाषाएँ पूरी तरह राजभाषा बन नहीं सकतीं । बेटा इंग्लिशियर बनेगा, लोकसभा का सदस्य बनेगा, कहीं का राज्यपाल बनेगा, कलक्टर या कमिश्नर बनेगा । यह सब बनने-बनाने का काम अंग्रेजी से होगा या तमिल और मराठी से ? होनहार नौजवानों के माता-पिता क्या मूर्ख हैं जो प्रादेशिक भाषा में शिक्षा देकर उनका अखिल भारतीय भविष्य नष्ट करेंगे ?

इसलिए वे नेकदिल नेता जो भाषा-समस्या सुलझाने के लिए यह सुझाव पेश करते हैं कि राज्यों में तुरन्त वहाँ की भाषाओं को राजभाषा बनाया जाय और केन्द्र में अंग्रेजी को बहुत धीरे-धीरे हटाया जाय, बहुत भारी भ्रम में हैं । स्वाधीन भारत में शिक्षा का महान् उद्देश्य अब भी अखिल भारतीय नौकरियाँ प्राप्त करना है । बेटों का व्याह आइ० ए० एस० अफसर से हो, मध्यवर्गीय वाप की यह सबसे बड़ी तमन्ना होती है । प्रदेशों में शिक्षा का संगठन इन्हीं अखिल भारतीय नौकरियों को लक्ष्य बनाकर होता है । इसलिए जब तक केन्द्र में अंग्रेजी रहेगी जब तक अखिल भारतीय स्तर पर अंग्रेजी का मौजूदा रोवदाव रहेगा, तब तक प्रदेशों में भी अंग्रेजी हटाई न जाएगी । जो सचमुच अंग्रेजी हटाकर प्रादेशिक भाषाओं को राजभाषा बनाना चाहते हैं, वे केन्द्र में अंग्रेजी के 'समर्थक' हो ही नहीं सकते ।

सरकार की बात जाने दीजिए । मैं उस अखिल भारतीय पार्टी का नाम जानना चाहता हूँ जिसकी प्रादेशिक शाखाएँ अपना सारा काम भारतीय भाषाओं में करती हैं और जो केन्द्र में अंग्रेजी हटाकर धीरे-धीरे हिन्दी लाने के लिए प्रयत्नशील हैं ।

भाषावार राज्यों के पुनर्गठन का आन्दोलन चला । इस आन्दोलन में यह जोरदार आवाज नहीं सुनाई दी कि प्रदेशों में अंग्रेजी हटाई जाय, प्रादेशिक भाषा को राजभाषा बनाया जाय । इसका क्या कारण है ? कारण यह है कि भाषावार राज्य बनाने में प्रादेशिक पूँजीपतियों का भी स्वार्थ था, वे अपने लिये अलग बाजार कायम करना चाहते थे, उन्हें प्रादेशिक भाषाओं से कोई खास मोहब्बत न थी । प्रगतिशील नेताओं ने उनका साथ दिया, ठीक किया । लेकिन प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया जाय, इसके लिए वे कोई सशक्त आन्दोलन नहीं कर सके । क्यों ? आज भी प्रस्ताव पास करने के अलावा प्रदेशों में अंग्रेजी हटाने के लिए कोई आन्दोलन नहीं चलाया जा रहा, न कोई आन्दोलन चलाने का कार्यक्रम है । क्यों ? प्रदेशों में अंग्रेजी हटाने के लिए भाषावार प्रान्त आन्दोलन जैसी कोई चीज सामने क्यों नहीं है ? इसलिए कि प्रादेशिक पूँजीपतियों का साथ देते हुए बहुत से प्रगतिशील नेता भी भटकाव के शिकार हो गए हैं । उन्होंने प्रादेशिक भाषाओं के



निष्ठ आन्दोलन नहीं किया। राष्ट्रीय भाषाओं के लिए मरे-मरे। उन्होंने प्रादेशिकता के आभाव में राष्ट्रीय एकता की आकांक्षा व्यक्त नहीं की। उसी का नतीजा यह कि शास्त्र के प्रयोग में भाषाओं के हटाने की बात करने हैं लेकिन केन्द्र में भाषाओं के हटाने अंग्रेजी का अन्तर्गत करने की बात मानते हैं। नतीजा यह होता है कि अंग्रेजी केन्द्र से हटती न न प्रयोग में आती बल्कि निष्ठ और मही मही हैं, उन्हें पता करने का काम उन्होंने भाषाओं में भाषा और जनता के नतीजा को गौर दिया है। उनकी जिज्ञासा से प्रतिक्रिया-वादी नेता पाता नहीं है, यह देश के बढ़ने का प्रयत्न होकर बनता है—सुख-सुख। जनता का नाम सुधारों और सफाई का है। आचार्य की बात है कि समस्त महापुरुष आन्दोलन में जनता के साथ काम करते हुए जनक प्रगतिशील नेताओं की बात मानकर नहीं हुई। अब केन्द्र ने अंग्रेजी हटाने के मकसद पर वे जागरण का हीका पता करने हैं।

कुछ दिन पहले बंगाल में प्रादेशिक और अग्रगण्योन्त सन्नी दलों ने हिन्दी भाषा में बंगाल के लिए एकल शब्द प्रस्ताव पारित किया। तमिलनाडु में द्रविड़ मुन्नेत्र कदम में 'कन्नड़' का नतीजा तक अंग्रेजी की मुद्रा बनाए रखते हैं। केरल में 'राष्ट्रवादी कम्प्यूटिंग' और तमिलनाडु में तमिल लोग भी सोच-भाँट करने में दक्षिण हैं। भाषा के प्रयोग पर और जनता के भाषा के भाषा के साथ कुछ प्रगतिशील नेताओं ने एक ही बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रस्ताव अंग्रेजी के पक्ष में प्रगतिशील-अग्रगण्योन्त एक हो सकते हैं। केवल केन्द्र में अंग्रेजी हटाने के मकसद पर मुरारजी भाई और जनता के साथ काम करने चाहिए। तमिलनाडु में भाषा का आन्दोलन प्रतिनिधायकता के हाथ में था। उन्होंने जनता के तमिल प्रेम में काम उठाकर पुस्तकालय, स्टेजों और डाकघरों में भाषा लगाई। जब समस्त लीजिए यह गृहमुद्र की भाषा है। उत्तर में मुरारजी भाई नादि अंग्रेजी हटाने का आन्दोलन अपने हाथ में ले रहे हैं। प्रगतिशील नेता दृढ़-दृढ़ देख रहे हैं। अंग्रेजी हटाने का आन्दोलन अपने हाथ में ले कर वे उसे प्रतिनिधायकता को गौर रहे हैं।

प्रगतिशील नेता बहुत नैक सलाह देने हैं कि हिन्दी-भाषी जनता को अन्य राष्ट्रवाद का गिहार न होना चाहिए। सही बात है। हिन्दी जनता का राष्ट्रवाद कैसे जाहिर होता है ? जो लोग समझते हैं कि सारे देश में हिन्दी बोलें ही बनेगी जैसे ब्रिटेन में अंग्रेजी बोलती है, यानी जो भारतीय भाषाओं का मिटाना चाहते हैं और राष्ट्रीय एकता का मतलब यह समझते हैं कि और सब भारतीय भाषाएँ मिट जायें, उनकी जगह हिन्दी ही रहे, वे अन्ध राष्ट्रवादी हैं। किन्तु हिन्दी प्रदेशों से किसी ने यह माँग नहीं की कि तमिलनाडु में तमिल की शिक्षा का माध्यम न बनाया जाय, यह माँग नहीं की कि वहाँ या बंगाल या महाराष्ट्र में हर स्तर पर हिन्दी चलाई जाय। इसके विपरीत होता यह है कि सभी दलों के नेता प्रादेशिक भाषाओं को उनके पूर्ण अधिकार देने के पक्ष में हैं। माँग है अंग्रेजी को हटाने की, न कि अहिन्दी भाषाओं को हटाने की। इसलिए केन्द्र से अंग्रेजी का हटाने का

सवाल पर हिन्दी साम्राज्यवाद का भय दिखाना वास्तव में अंग्रेजी की सुरक्षा के लिए बहुत घटिया किस्म की वकालत करना है।

सरकार क्या करेगी और दूसरी पार्टियाँ क्या करेंगी, ये बड़ी-बड़ी बातें हैं जिन पर इस लेख में कुछ नहीं कहना। मेरी माँग भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से है। आप अपना सारा प्रादेशिक काम भारतीय भाषाओं में कीजिए, एक महीने के अन्दर प्रदेशों में अंग्रेजी की जड़ काट दीजिए। केन्द्र में अपना काम चाहे हिन्दी में कीजिए चाहे हिन्दी को बिल्कुल न रखिये बल्कि वह काम दस-बारह-चौदह अहिन्दी भाषाओं में कीजिये, अगले छः महीनों में अपने केन्द्र से अंग्रेजी का पूर्ण वहिष्कार कीजिये। ऐसा आप कर लें तो मैं समझूँगा कि भारत की भाषा-समस्या हल करने में आपने बहुत बड़ी सक्रिय सहयोगिता दी है। वरना देश जिस विघटन की ओर बढ़ रहा है, उसमें सबसे पहली चोट आप पर होगी और आप यह कहने की हालत में भी न होंगे कि चोट गलत पड़ी।

मध्यवर्ग का सहारा लेने के लिए फासिस्टवाद भाषा और संस्कृति का रक्षक बनकर सामने आता है। हिटलर जर्मन भाषा और जर्मन संस्कृति का बहुत बड़ा समर्थक बनकर रंगमंच पर आया था। तमिलनाडु में तमिल-रक्षा का भार द्रविड़ मुन्नेत्र कण्गन पर उत्तर में हिन्दी-रक्षा का जनसंघ पर और दोनों की रक्षा का भार महान् गणराज्य संयुक्त राष्ट्र अमरीका पर ! भारत का भावी मानचित्र आपको कैसा दिखाई देता है ?

पहले एक देश में दो देश बने, भारत और पाकिस्तान। अब भारत में दो नये राष्ट्रों का निर्माण होगा, एक हिन्दी-राज्य, दूसरा अहिन्दी-राज्य। लेकिन विघटन यही समाप्त न होगा। असम में दंगे हिन्दी-भाषियों के खिलाफ न हुए थे। बम्बई में संयुक्त महाराष्ट्र आन्दोलन के दौरान अन्ध-राष्ट्रवादियों का क्रोध हिन्दी-भाषियों पर न बरसा था। मारे गये थे बंगाली और गुजराती, दोनों अहिन्दी-भाषी। तमिलनाडु और आन्ध्र के शिक्षित लोगों में एक-दूसरे के प्रति वही भाव है, जो असमी-बंगालियों, गुजराती-मराठी-भाषियों में है। कश्मीर और नागा प्रदेश में अलगाव के आन्दोलन से सभी लोग परिचित हैं। द्रविड़ मुन्नेत्र कण्गम मूलतः तमिलनाडु को अलग करने का आन्दोलन करता रहा है, हिन्दी-विरोध को भड़काने और उससे लाभ उठाने की सूक्ष्म वाद की है। मुस्लिम लीग के 'डाइरेक्ट ऐक्शन' से बरत होकर देशप्रेमी नेताओं ने देश का विभाजन स्वीकार किया। उससे साम्प्रदायिक समस्या मुलूक्त गई ? साम्राज्यवाद को अपने फौजी अड्डे बनाने का मौका नहीं मिला ? दीजिये तमिलनाडु को आत्मनिर्णय का अधिकार ! कीजिये कश्मीर और नागा प्रदेश को भारत से अलग ! कहिए कि भारत की अखंडता का नारा जनसंघ का नारा है ! आपके आत्मनिर्णय के अधिकार से साम्राज्यवाद को लाभ होता है या भारत की जनता को ?

भारत के मजदूर वर्ग का संगठन प्रदेशों में बँटेगा नहीं, वह अखिल भारतीय स्तर पर होगा। विकास की पंचवर्षीय योजनाएँ अखिल भारतीय स्तर पर बनेंगी और उन्हीं पर सफल होगी। केरल में अन्न की कमी या बेकारी अन्य राज्यों और केन्द्र के सहयोग

मे हो दूर होगी। राष्ट्रीय विघटन का अर्थ है सच्ची हानि, साम्राज्यवाद का लाभ। राष्ट्रीय एकता का अर्थ है सच्चा लाभ, साम्राज्यवाद की हानि।

यह राष्ट्रीय एकता अब अंग्रेजी जाननेवाले डेढ़ फी सदी लोगों के महारे कायम नहीं रह सकती। अगर केन्द्र में हिन्दी चलाना साम्राज्यवाद है तो अंग्रेजी कायम रखना और भी बड़ा जयाय है। हिन्दी भाषी जनता इसे कभी सहन न करेगी। स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू के चाहे जितने आन्दामतो को कानून का रूप दे दीजिए, वे अंग्रेजी की जगह नहीं कर सकते।

हिन्दी का राष्ट्रभाषा बनाने का आन्दोलन यहाँ अन्तीसवीं सदी में हो रहा है। गांधीजी न हिन्दी-प्रचार को राष्ट्रीय आन्दोलन का अभिन्न अंग बनाया। भारत को स्थापित हुए अठारह साल हो गए। अब और कितने धीरे? कुछ रफ्तार निश्चित कर लीजिए। मालूम तो हो जाय कि अठारह वीस नौ दिन में न करने हैं या अठारह दिन में।

एक अजीब बात हिन्दी के पिछड़ेपन के बारे में है। लेनिन ने आर्याही ऋग की भाषाभाषा का पिछड़ा हुआ न पाया। उन्होंने गैर-रूसी भाषाओं को राजकाज के लिए माध्यम बनाने दिया। चीनी भाषा पिछड़ी हुई नहीं है, माओत्से तुंग और चीनी सरकार के काम आती है। सिर्फ हिन्दी एसी पिछड़ी हुई भाषा है और भारत के बुद्धिजीवी ऐसा भ्रमन चित्त है कि अंग्रेजी के बिना न तो केन्द्रीय सरकार का काम चल सकता है, न किसी पार्टी का अपना राजनीतिक कार्य, विशेषकर उसका केन्द्रीय राजनीतिक कार्य। यह पिछड़ेपन की दलील न केवल हिन्दी-भाषी जाति का अपमान है बल्कि अंग्रेजी की गुलामी का मजबूत प्रमाणपत्र है।

राज्या में प्रादेशिक भाषाएँ और केन्द्र में हिन्दी—ये दोनों लक्ष्य एक ही साथ सिद्ध होंगे। ये दोनों लक्ष्य आज सिद्ध हो सकते हैं यदि राजनीतिक पार्टियाँ अपने व्यवहार में इस नीति का अपना लें। कयनी और कयनी में भेद होना से कोई समस्या हल नहीं हो सकती। जितना हो विलम्ब होगा उतना ही विघटन बढ़ेगा। इसलिए सही नीति के लिए हिम्मत में आम्बोलन करने का समय अभी है, कस न रहेगा।

हिन्दी के लिए धीरे चला, यह गलत है। कहना चाहिए, और तेज चलो। केन्द्र और राज्या में एक साथ अंग्रेजी हटाओ—यही नारा सही है।

केन्द्र में आप हिन्दी नहीं चाहते, न रखिये। लेकिन अंग्रेजी न चलेगी। उसकी जगह भारत की एक भाषा चलाइए, चाहें हम भाषाएँ। केन्द्रीय सरकार में जो भाषा-नीति आन चाना चाहते हो उस अपनी पार्टी के व्यवहार में लाइये। इसी से हमें विश्वास होगा कि आप ईमानदारी से भाषा-समस्या हल करना चाहते हैं। करना बातें बनानेवाले नवाभा की इस देश में कमी नहीं है।

(१९६१)

## भाषा की समस्या और मज़दूर वर्ग

समाज की और दूसरी समस्याओं की तरह भाषा की समस्या पर भी साम्राज्य-वादियों, भारतीय पूँजीपतियों और मज़दूर वर्ग के विचार अलग-अलग हैं।

अंग्रेजों ने इस देश को जीता। लोगों की इच्छा के विरुद्ध शिक्षा और शासन में अंग्रेजी चलाई। भारतीय भाषाएँ पिछड़ी हुई हैं, वे न शासनतंत्र के योग्य हैं, न उनमें आधुनिक शिक्षा दी जा सकती है—यह स्थापना ब्रिटिश उपनिवेशवादियों के प्रतिनिधि लार्ड मेकाले ने शिक्षा-सम्बन्धी अपने प्रसिद्ध लेख में की। अंग्रेजों ने विभिन्न भाषाएँ बोलने-वाली जातियों को आपस में लड़ाया। इस लड़ाई से लाभ उठाकर उन्होंने सभी के ऊपर अंग्रेजी का प्रभुत्व कायम रखा। अंग्रेजी की यह गुलामी राजनीतिक पराधीनता का ही एक हिस्सा थी।

राष्ट्रीय आन्दोलन के आरम्भ काल से अंग्रेजी हटाने की माँग स्वाधीनता का अभिन्न अंग बन गई। गांधीजी ने सितम्बर, १९२१ के 'यंग इंडिया' में लिखा था कि उनके हाथ में तानाशाह की ताकत होती तो वह उसी दिन अंग्रेजी में शिक्षा देना बन्द करा देते और जो अध्यापक इस हुक्म को न मानता, उसे वह नौकरी से हटा देते।

अंग्रेजी से किसी एक भाषा का नहीं, सारे राष्ट्र का अहित होता है। इस बारे में गांधीजी ने ५ जुलाई, १९२८ के 'यंग इंडिया' में लिखा था कि अंग्रेजी ने राष्ट्र की शक्ति का नाश कर दिया है और अंग्रेजी बनी रही तो राष्ट्र की आत्मा का नाश हो जायगा।

भारत में प्रगतिशील साहित्यिक आन्दोलन के जन्मदाता महान् उपन्यासकार प्रमचन्द ने भाषा की गुलामी के बारे में लिखा था, "जवान की गुलामी ही असली गुलामी है।" (प्रेमचन्द, कुछ विचार, पृ० २२१)।

भारत विभाजित हुआ और स्वाधीन हुआ। आजादी मिले एक ही महीना हुआ था कि गांधीजी ने केन्द्र और प्रान्तों से एक साथ अंग्रेजी हटाने की माँग की। २१ सितम्बर, १९४७ के 'हरिजन' में उन्होंने लिखा कि "प्रान्तीय सरकारों के लिए ऐसे कर्मचारी रखना बिल्कुल आसान होना चाहिए जो प्रान्तीय भाषाओं और नागरी या उर्दू लिपि में लिखी जानेवाली अन्तर्प्रान्तीय भाषा हिन्दुस्तानी में सारा काम कर सकें।"

गांधीजी की नीति थी कि केन्द्र और राज्यों से तुरन्त और एक साथ अंग्रेजी हटाई

जाय। इसलिए उन्होंने प्रांतीय सरकारों को सलाह दी थी कि वे ऐसे कर्मचारी रखें जो प्रांतीय भाषा के साथ हिन्दुस्तानी में भी काम कर सकें।

अंग्रेजी हटाने का काम पाँच साल के लिए टाल दिया जाय, इस नीति के वह विरुद्ध थे। जब अंग्रेजी में सुकमान होता है, तब उसे क्यों सामग्री भी चलने दिया जाय? उनकी राय थी, 'इत आवश्यक तन्दीबी में, जो एक-एक दिन बीतता है, उसमें राष्ट्र की सामूहिक हानि होती है।'

जा नाग कहते थे कि तुरन्त पश्चिमी अल्पसंख्यक हैं उनके बारे में गांधीजी का मत यह था, 'हमारे सेपरेटरियटों में भी, कुछ समय बीतने पर तन्दीबी होगी दिमागी बाहिनी के अलावा और कुछ नहीं है।'

गांधीजी की ललकार थी—दिमागी बाहिनी खत्म करो, प्रांतीय और दिक्की से अंग्रेजी को निकालो, भारतीय भाषाओं का व्यवहार करो।

प्रांतीय सरकारों केन्द्र में अंग्रेजी द्वारा सम्पर्क कायम न रखेंगी, इस बारे में उन्होंने लिखा था, "प्रांतों का केन्द्र में काम पड़ेगा। यह काम वे अंग्रेजी में करने की हिम्मत न करेंगे। केन्द्र में यह जन्म समझने की दृष्टि होनी चाहिए कि वह सांस्कृतिक रूप में राष्ट्र पर मुट्ठी-भर भारतवासियों का बोझ न डालेगा। ये लोग इतने आलसी हैं कि उस भाषा का सीखने नहीं जो आसानी से भारे भारत की आम भाषा बन सकती है और जिससे जनता के किसी हिस्से या पार्टी को नालुमी न होगी।"

गांधीजी की भाषा-सम्बन्धी नीति का निचोड़ यह था, "अंग्रेजी में जो सांस्कृतिक डकैती की है, उसे खत्म किया जाय।"

केन्द्र और प्रांतों में तुरन्त अंग्रेजी हटाने के बारे में गांधीजी की जोरदार आवाज हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन की मज्जी और सही आवाज थी। वह मजदूर वर्ग के हित में थी।

लेकिन सांस्कृतिक डकैती जारी तभी रह सकती थी जब एक ओर जनता को तनख्वाही दी जाय कि अंग्रेजी हटा दी जाएगी, दूसरी ओर कुछ ऐसे कारण ढूँढ़ निकाल जाएँ जिनसे अंग्रेजी कायम रहे। भारतीय पूँजीवाद एक ओर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक और राजनीतिक दबाव का विरोध करता था, दूसरी ओर अपने विकास के लिए उससे सहायता भी चाहता था। भारत में ब्रिटिश पूँजी की आमद और ब्यादा हुई, मुनाफा गया वित्तपोषण को, साथ ही देश में उद्योग घरों का निर्माण भी हुआ। पूँजीवाद की इस दुरंगी नीति के अनुष्ण उसकी भाषा नीति थी। भारतीय पूँजीवाद की प्रमुख पार्टी—कांग्रेस—ने यह नीति निकाली कि अंग्रेजी हटाने का बराबर दम भरन रहो लेकिन अल्पसंख्यक में किसी-न-किसी बहाने अंग्रेजी कायम रखो।

पहला बहाना यह था कि हिन्दी पिछड़ी हुई भाषा है। वह अंग्रेजी की जाहले, इनके लिए उसे विकसित हाल का अवसर देना चाहिए। विकास के लिए पाँच साल का अवसर दिया गया।

यह गुड़ बहाना था। लोकसभा में सदस्यों को जीव-विज्ञान या भौतिकी पर बहस

न करनी थी। लेकिन हिन्दी को समृद्ध करने के लिए बड़े-बड़े कोश रचे जाने लगे। किसी ने यह न देखा कि इन कोशों में कितने पुराने ऐसे शब्द दोहराए जा रहे हैं जो हिन्दी में सन् '४७ से पहले ही प्रचलित थे। किसी ने लोकसभा में यह माँग की कि हिन्दी कितनी पिछड़ी हुई है, इसकी जाँच के लिए कम-से-कम एक कमीशन तो बिठा दिया जाय।

अंग्रेजी कायम रखने के लिए दूसरा कारण यह खोज निकाला गया कि वह आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की भाषा है। अंग्रेजी चली गई तो देश आर्थिक और वैज्ञानिक प्रगति में पिछड़ जाएगा।

अंग्रेजी कायम रखने के पीछे एक जानी-बूझी वर्ग-नीति थी। इसे जनता के गले उतारने का काम किया भारत के लोकप्रिय नेता स्वर्गीय पं० जवाहरलाल नेहरू ने। अंग्रेजी को निकालने और साथ ही कायम रखने की नीति उन्होंने सितम्बर, १९४६ में संविधान सभा में इस तरह पेश की :

“अंग्रेजी चाहे जितनी महत्वपूर्ण भाषा हो, हम यह वर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे देश में कुछ तो अंग्रेजी पढ़े-लिखे शरीफ लोग हों और आम जनता अंग्रेजी से महरूम रहे। इसलिए हमारी अपनी भाषा होनी चाहिए। लेकिन आप इस बात को प्रस्ताव में चाहे लिखें, चाहे न लिखें, अंग्रेजी लाजमी तौर से भारत में बहुत महत्वपूर्ण भाषा बनकर रहेगी जिसे बहुत से लोग सीखेंगे और शायद उन्हें उसे जबरन सीखना होगा।”

पाठक १५ सितम्बर, १९४६ के अखबारों में नेहरूजी का यह भाषण पढ़ सकते हैं।

नेहरूजी ने अपने भाषण में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भाषा-सम्बन्धी विचारों की भूरि-भूरि प्रशंसा की। फिर अंग्रेजी हटाने की गांधी-नीति से ठीक उल्टी दिशा में चल दिए।

नेहरूजी भारी जनतन्त्रवादी थे। केरल की जनतांत्रिक साम्यवादी सरकार के खिलाफ जेहाद की शुरुआत भी उन्होंने ही की थी।

नेहरूवाद और मार्क्सवाद पर्यायवाची शब्द नहीं हैं।

भारतीय पूँजीवाद की पार्टी—कांग्रेस—न तो राज्यों से, और न केन्द्र से अंग्रेजा हटाने में समर्थ हुई। उल्टा उसकी नीति से अंग्रेजी और अंग्रेजियत की जड़ें पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गईं।

भारत में भाषावार राज्य बनाने का आन्दोलन चला, हर प्रदेश में उसकी शिक्षा और संस्कृति का विकास उसकी भाषा के माध्यम से हो, यह माँग सही थी। लेकिन आन्दोलन में जितना जोर राज्यों की सीमाओं और क्षेत्रफल पर दिया गया, उतना प्रादेशिक भाषाओं पर नहीं। यह भी पूँजीवादी नीति का ही फल था। नतीजा यह हुआ कि भाषावार राज्य बन गए और इन राज्यों में अंग्रेजी कायम रही।

भाषावार राज्यों का आन्दोलन इस तरह चला कि लोगों के सामने प्रादेशिकता मुख्य और राष्ट्रीय एकता गौण हो गई। इस अलगवा की भावना से लाभ हुआ अंग्रेजी को।

गुजराती और मराठी भाषी आपस में लड़े, अंग्रेजी के समर्थन में दोनों के नेता—विशेष रूप से वामपंथी नेता—एक साथ रहें। असम में भाषा के सवाल को लेकर भयानक दंगे हुए। लड़ाई हुई असमिया-बंगला में। दोनों के ऊपर कायम रही अंग्रेजी।

अंग्रेजी कायम रखने के लिए एक नया बहाना और मिला हिन्दीवाले अहिन्दी-वाला का दवाना चाहते हैं। द्रविड वक्ताम ने नारा दिया कि तमिलनाडु भारत से अलग हो। उसने प्रचार किया कि - ६ जनवरी, १९६१ से हिन्दी राष्ट्रभाषा हो जाएगी और तमिल का नाग कर दोगी। तमिलनाडु के प्रतिक्रियावादी नेताओं ने जनता के सहजतमिल-प्रेम से लाभ उठाकर आपत्त धरपा कर दी। जनतन्त्र और राष्ट्रीय एकता की रक्षा के लिए अंग्रेजी को कायम रखना आवश्यक हो गया।

सन ६५ में अंग्रेजी हट न जाय, इसलिए दिल्ली सरकार ने यह कानून बना दिया था कि अंग्रेजी का भी चलन रहेगा। व्यवहार में देखा यह गया कि अंग्रेजी का ही चलन रहेगा। इस तरह भारत की संविधान सभा के फैसले को बड़े वैधानिक ढंग से भारत के जनतन्त्र-प्रेमियां न पैरा तल रौंदा।

पूँजीपतिया से अलग, अपन आर्थिक और राजनीतिक हितों के अनुकूल, भाषा समस्या पर मजदूर वर्ग का अपना दृष्टिकोण होना चाहिए। मजदूर वर्ग समाज का सबसे क्रान्तिकारी वर्ग है। उसे साम्राज्यवादी विरोध और हमारी गुलामी की प्रतीक अंग्रेजी के खिलाफ सबसे आगे बढ़कर लड़ना चाहिए। अंग्रेजी का हटाने के मामले में वह पूँजी-पतिया की टालमटोल नीति का अनुसरण नहीं कर सकता। वह इस दुरगो नीति पर नहीं चल सकता कि मुह में कहें, 'अंग्रेजी हटाओ, अमल में उसे कायम रखें। वह इस दलील का नहीं मान सकता कि भारत की भाषाएँ पिछड़ी हुई हैं, इसलिए अंग्रेजी कायम रखनी चाहिए। उसके मामले में लेनिन की मिमाल है जिन्होंने रूसी साम्राज्यवाद का दबाव खत्म करने के लिए खुद अपनी मातृभाषा रूसी को राजभाषा पद से हटा दिया था। फिर विदेशी भाषा अंग्रेजी का हटाने में किसी को संकोच क्या हो?

सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी ने किसी जाति की भाषा को पिछड़ा हुआ न माना। उसने सोवियत प्रजातन्त्र में गैर-रूसी भाषाओं को राजभाषा बनाया। हिन्दी पिछड़ी हुई है उसे अभी विकसित होना है या जनता के निकट पहुँचना है, यह मार्क्स-वादियों का तर्क नहीं हो सकता।

मजदूर वर्ग अखिल भारतीय स्तर पर अपनी एकता अंग्रेजी के माध्यम में कायम नहीं कर सकता। यह एकता किसी भारतीय भाषा के द्वारा ही कायम हो सकती है। वह भारतीय भाषा मजदूर वर्ग के नेताओं के अनुसार हिन्दी है। मजदूर वर्ग की एकता खुद उसके लिए ही नहीं, सारे राष्ट्र के लिए जरूरी है। बंगाल-असम में भगड़े कराते हैं पूँजीपति। उनमें एकता स्थापित करता है मजदूर वर्ग। हिन्दी-अहिन्दी के संघर्ष को रोकने की ताकत मजदूर वर्ग में ही है।

मजदूर वर्ग के साथी हैं विमान। विमान-मजदूर-एकता ही वह क्रान्तिकारी शक्ति

है जो देश को सामाजिक प्रगति की राह पर आगे बढ़ा सकती है। किसान अपना अखिल भारतीय संगठन अंग्रेजी के द्वारा मजबूत नहीं कर सकते। कम्युनिस्ट पार्टी खुद अपने अन्दर बहुत-से किसान-मजदूरों को जगह नहीं दे सकती, क्योंकि अंग्रेजी का प्रभुत्व रहने पर वे न तो पार्टी की ऊँची समितियों के सदस्य हो सकेंगे, न उनकी वृहत् में ठीक से भाग ले सकेंगे।

इसीलिए मजदूर वर्ग के हित में एक ही भापा-नीति हो सकती है—राज्यो से और केन्द्र से, दोनों जगह, से एक साथ अंग्रेजी हटाओ।

इस नीति पर मजदूर वर्ग सारे देश को तभी चला सकता है, जब उसकी अपनी पार्टी—कम्युनिस्ट पार्टी—के दफ्तरों से अंग्रेजी निकले। अंग्रेजी का जुआ खुद अपने कन्वों पर लादकर कम्युनिस्ट पार्टी देश को अंग्रेजी की गुलामी से आजाद नहीं करा सकती।

अब देखना चाहिए कि मजदूर वर्ग की पार्टी और उसके द्वारा संचालित जन-संगठनों में अंग्रेजी की हैसियत क्या है।

स्वर्गीय कामरेड अजय घोष ने सरकारी भापा-आयोग की रिपोर्ट पर एक नोट लिखा था। उसमें उन्होंने अंग्रेजी की हैसियत के बारे में ये बातें लिखी थीं—

“आज अधिकांश अखिल भारतीय संगठनों का काम अंग्रेजी में होता है। इनमें किसानों और मजदूरों के संगठन भी शामिल हैं। इसका लाजमी नतीजा यह होता है कि मध्यवर्ग और उच्च मध्यवर्ग के सुशिक्षित लोग ही अखिल भारतीय स्तर पर इन संगठनों के वृहत्-मुवाहसे में भाग ले सकते हैं। अमल में यही लोग इन संगठनों की अखिल भारतीय कार्य-समितियों के सदस्य बन सकते हैं। जिस किसी को भी जन-आन्दोलन का जरा भी तथुर्वा होगा, वह जानता होगा, इससे कितनी कठिनाई पैदा होती है।”

इससे स्पष्ट है कि अंग्रेजी के रहते न तो मजदूर संगठन शक्तिशाली हो सकते हैं, न किसान-मजदूर-एकता दृढ़ की जा सकती है।

सांस्कृतिक क्षेत्र में पार्टी के कर्तव्य बतलाते हुए अजय घोष ने लिखा था, “देश के सभी भागों में जनता को किसी एक भारतीय भापा का अल्पतम आवश्यक ज्ञान कराना होगा जिससे वह भापा जल्दी-से-जल्दी केन्द्र (यूनियन) की भापा बन सके और विभिन्न प्रदेशों की जनता के बीच भी परस्पर आदान-प्रदान का साधन बने। भारत की भापाओं में जो भापा सबसे अधिक बोली और समझी जाती है, वह हिन्दी है और इसी के द्वारा यह काम हो सकता है।”

मजदूर वर्ग और उसकी पार्टी का हित इस बात में है कि केन्द्र और प्रदेशों से अंग्रेजी को निकाला जाय। जल्दी-से जल्दी हिन्दी को भारत सरकार की भापा तथा पार्टी द्वारा संचालित अखिल भारतीय जन-संगठनों की भापा बनाया जाय।

दो वर्ग, दो उद्देश्य, दो भापा-नीतियाँ स्पष्ट हो जाती हैं। उनका भेद आसानी से देखा जा सकता है।



इस समय कम्युनिस्ट पार्टी की नीति क्या है ? राज्या में अंग्रेजी हटाओ, केन्द्र में आगे चक्कर हिंदी हाँगी लेकिन फिन्हाल यही अंग्रेजी चलने दो ।

लालबहादुर शास्त्रीजी और गुनगारीनाल नाराजी क्या कहते हैं ? वे भी यही कहते हैं । हिन्दी धीरे धीरे आएगी । जगन्नी जम्न लेकिन अभी तो अंग्रेजी चलने दो । उम्मा म प्रादिकव तापाया के व्यवहार के लिए उन्होंने भविष्य बनने के समय से ही पूरे छट दे रखी है । अब राज्य उम सुविधा का उपयोग न करे तो इसमें शास्त्रीजी और नाराजी का क्या दाप ?

इस समय भाषा क सवाल पर कम्युनिस्ट पार्टी की अपनी कोई स्वतन्त्र भाषा-नीति नहीं है । वह पूंजीवादी पार्टी—कापस—का पिछलगुआ बनकर चल रहा है । योगीन्द्र शर्माजी जैम कम्युनिस्ट नेता इस पिछलगुएण की नीति को पार्टी की स्वतन्त्र नीति कह-का हममें उम पर गव करने का कहते हैं । मुझे तो अंग्रेजी कायम रखने की इस मजदूर विरोधी, राष्ट्र-विरोधी नीति पर गम आती है, उसमें गव करने की कोई बात नहीं दिखाई देती ।

इसके विपरीत अपना एक लेख में मैंने यह नीति रखी है कि पार्टी को केन्द्र और राज्य दोनों में अंग्रेजी हटाने का आन्दोलन करना चाहिए ।

योगीन्द्र शर्माजी का कहना है कि यह जोर-जबदस्ती वाला हिन्दू राष्ट्रवादी नारा है । वह कहते हैं कि भाषा की समस्या का जनतांत्रिक समाधान होना चाहिए ।

जनतांत्रिक समाधान वही है जिसे सन् '४६ में भारत सरकार अमल में लाती रही है । यानी भविष्य में हिन्दी, वर्तमान में अंग्रेजी । योगीन्द्रजी भी कहते हैं, भविष्य में हिन्दी ही केन्द्रीय राजभाषा होगी लेकिन अभी अंग्रेजी चलने दो । वह प० जवाहरलाल नेहरू की तरह अंग्रेजी की निन्दा भी करते हैं । कहते हैं—अंग्रेजी के जगिये जो राष्ट्रीय एकता कायम की जाती है, वह अंग्रेजी के समय की औपनिवेशिक एकता में बटकर नहीं है । लेकिन उनका अमली नारा है अंग्रेजी के जरिये अभी यह एकता कायम रहने दो ।

जने सन् '४७ से पहले सर तेजबहादुर सप्रू कहते थे कि अंग्रेजी राज तो गम होना चाहिए लेकिन राज महाराज नहीं मानने, जखूत और मुयलमान नहीं मानने, ऐंग्लो इंडियन नहीं मानने, इसलिए फिन्हाल तो अंग्रेजी राज रहेगा ही — वैसे ही सन् '६५ में यह 'फिन्हाल अंग्रेजी चलाने की नीति है ।

यदि यह मान लें कि अहिन्दी-भाषी जनता अंग्रेजी को नहीं छोड़ना चाहती, तो भी अंग्रेजी का कायम रहना जनतांत्रिक नहीं कहा जा सकता । यदि अंग्रेजी को हटाना अहिन्दी भाषियों के साथ अन्याय है, तो उसे कायम रखना हिन्दी-भाषियों के साथ अन्याय है । जनतंत्र का मतलब यह नहीं है कि अहिन्दी-भाषियों की राय ली जाय और हिन्दी-भाषियों को पूछा ही न जाय ।

अहिन्दी भाषियों की राय भी किस जनतांत्रिक उपाय से मालूम की गई ? क्या बमों तोड़ना और स्टेशन जलाना लोकमन सग्रह का बहुत कारगर तरीका है ?

ब्रिटिश कपगम और स्वतन्त्र पार्टी के लोगों ने घुआँधार प्रचार किया कि देश के लिए सबसे बड़ा खतरा हिन्दी से है। हिन्दी-साम्राज्यवाद का हीवा खड़ा करके कौशल से उन्होंने अंग्रेजी के साम्राज्यवाद की रक्षा की। लेकिन भारतीय भापाओं को दवानेवाली भापा हिन्दी नहीं अंग्रेजी है।

इस सम्बन्ध में अजय घोष ने अपने उसी नोट में लिखा था, “बाज जब लोग कहते हैं कि इस या उस भापा से खतरा पैदा हो गया है, तब वे भूल जाते हैं कि देश में जिस भापा का मजबूत प्रभुत्व रहा है, वह अंग्रेजी है। यह प्रभुत्व न केवल राजनीतिक क्षेत्र में रहा है, बल्कि सांस्कृतिक क्षेत्र में भी रहा है। वे भूल जाते हैं कि सांस्कृतिक क्षेत्र में यह प्रभुत्व अब भी बना हुआ है। वे भूल जाते हैं कि भारत के सांस्कृतिक विकास में, हर भारतीय भापा के विकास में यह प्रभुत्व ही सबसे बड़ी बाधा है और इसलिए उसे दूर करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है।”

इससे ठीक उल्टी राय योगीन्द्र शर्माजी की है। उनकी दलील है कि अंग्रेजी की जगह हिन्दी आई तो भारतीय भापाओं का दमन होगा। उन्होंने जोगीले ढग से अपने लेख में पूछा है—

“क्या कोई भी सच्चा देशभक्त, सच्चा जनतन्त्र-प्रेमी इसको स्वीकार कर सकता है जिस तरह अभी तक—अंग्रेजी भारत की तमाम भापाओं का दमन और दहन करती रही, उसी तरह उस काम को अब हिन्दी करे ?”

उन्होंने यह नहीं बताया कि संविधान की किस धारा के अनुसार हिन्दी तमिलनाडु से तमिल को बाहर कर देगी।

उनकी राय है कि अंग्रेजी की तरह हिन्दी भी तमाम भापाओं का दमन न करे, इसलिए अंग्रेजी को ही यह दमन करने दिया जाय !

हिन्दी से भारतीय भापाओं को खतरा है, यह साबित करने के लिए उन्होंने ‘कम्युनिस्ट’ में प्रकाशित सन् ’४६ वाले मेरे पुराने लेख को ढूँढ़ निकाला है। इस लेख को उन्होंने अतिवादी और अराजकतावादी कहा है और उसी से उन्होंने हिन्दी का खतरा भी साबित कर दिया है !

सन् ’४८ में कम्युनिस्ट पार्टी की दूसरी कांग्रेस ने अपने राजनीतिक प्रस्ताव में भारत के बड़े पूँजीपतियों को उत्पीड़क वर्ग कहा था। उस स्थापना से यही नतीजा निकलता था कि बड़े पूँजीपतियों की सरकार केन्द्रीय राजभापा के जरिये प्रदेशों को दवाना चाहती है। कम्युनिस्ट पार्टी ने यह मान्यता बदल दी है। क्या योगीन्द्र शर्माजी अभी भी समझते हैं कि सरकार बड़े पूँजीपतियों की सरकार है और ये बड़े पूँजीपति साम्राज्यवादी हैं ? यदि नहीं तो बतलाए कि हिन्दी के खतरे का ठोस सामाजिक आधार क्या है।

अंग्रेजी हटाने का विरोध साम्राज्यवाद के खुले और छिपे समर्थक स्वतन्त्र पार्टी और ब्रिटिश कपगम के नेता करते हैं। हिन्दी द्वारा अहिन्दी भापाओं के दमन का हीवा खड़ा करते हैं। योगीन्द्र शर्माजी भी उनके प्रचार में शामिल हो गए हैं।

अंग्रेजी कायम रखने के लिए एक निश्चित ढंग से विस्तार राष्ट्रीय समुक्त मोर्चा बन गया है। इस मोर्चे में स्वतंत्र दल के नेता हैं, द्रविड़ कथगम वाले हैं। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के अनेक नेता भी इसमें हैं। लेकिन यह मोर्चा बना है बालू की भीत पर। उसके पीछे भारत के किसान और मजदूरों की ताकत नहीं है। वह क्यादातर बाबू लोग का समुक्त मोर्चा है। इसमें कुछ तो अंग्रेजी पढ़े हैं और बाकी बिना पढ़े ही उसका समर्थन करते हैं। ग्राम दान यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी की दोना धावाएँ इस समुक्त मोर्चे में शामिल हैं।

अहिन्दी भाषी क्षेत्र के बाबूआ को डर है कि अंग्रेजी चली गई तो अखिल भारतीय नौकरियाँ हिन्दीवाले इधिया लें। अखिल भारतीय नौकरियों की समस्या पूरे मध्यवर्ग की समस्या नहीं है। कुछ थोड़े-त तो लग—जो हरमानी में तेज होना हैं—ये नौकरियाँ पान हैं। बाकी उम्मीदवार नाउम्मीद होकर कहीं मास्टरी या कनर्की करने हैं या बेकारी में चप्पलें चटवाने हुए घूमन हैं। कम्युनिस्ट पार्टी अपनी भाषा नीति इन मुद्दों भर पड़े-निछे बाबूओं की राय में निर्धारित नहीं करता। उसके सामन होना चाहिए किसान और मजदूरों का हित।

बालूक म मध्यवर्ग का हित भी अंग्रेजी कायम रखने में नहीं है। निधानवे की तदो अंग्रेजी-पढ़े बाबूआ को छोटी-मोटी नौकरिया में ही मन्तोप करना पड़ता है। लागों की तादाद में व हर साल अंग्रेजी के कारण पेन होते हैं। अंग्रेजी के कारण शिक्षा उनके लिए हर तरह में महंगी पड़ती है। अखिल भारतीय नौकरिया के लिए अंग्रेजी आवश्यक है, इसलिए राज्यों में भी अंग्रेजी चलती है। फन भूतना पड़ता है तमाम निम्न मध्यवर्ग की गरीब जनता की।

जब तक केन्द्र म अंग्रेजी चलती है, तब तक राज्या में अंग्रेजी की जड़ नहीं बट सकती। राज्या म अंग्रेजी की पत्तियाँ नोचने में उसकी केन्द्रीय जड़ पर कोई असर न पड़ेगा। पिछले सोलह साल का अनुभव यही सिद्ध करता है। केन्द्र के कारण ही राज्या में अंग्रेजी का प्रमुख है। इसमें तमिलनाडु में अभी तक तमिल उच्च शिक्षा का माध्यम नहीं बन पाई।

जो लोग अखिल भारतीय नौकरियों के उम्मीदवार हैं, उनका भय आसानी से दूर किया जा सकता है। यह नियम बनाना चाहिए कि अखिल भारतीय नौकरियों के लिए अहिन्दी भाषा सीखना अनिवार्य होगा। अहिन्दी भाषा का समुचित ज्ञान अनिवार्य कर देने से हिन्दीवालों को कोई विरोध सुविधा न मिलेगी। पार्टी इस नियम के लिए और अंग्रेजी टटाने के लिए एक साथ आन्दोलन कर सकती है। लेकिन नौकरियों की समस्या हल न कर पाने के कारण केन्द्र म अंग्रेजी कायम रखने की बात करना भावमवाद को ठुकराकर मध्यवर्ग के बाबूआ का दृष्टिकोण अपनाता है।

अंग्रेजी कायम रखने में भारत के किसी वर्ग का हित नहीं है—न मजदूर वर्ग का, न किसानों का, न गहरों के मध्यवर्ग का। अंग्रेजी में न अहिन्दी प्रदेश का हित होता है, न

हिन्दी प्रदेश का । उससे केवल साम्राज्यवादियों का हित होता है । ब्रिटिश और अमरीकी पूँजीपति हमारे अर्थतन्त्र पर हर तरह से प्रभाव डालते हैं । उनके आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव को दृढ़ करने का साधन है—अंग्रेजी का प्रभुत्व । वे करोड़ों रुपये तरह-तरह से यहाँ अंग्रेजी के प्रचार और प्रसार पर खर्च करते हैं । अंग्रेजी को कायम रखना 'जनतन्त्र' के नाम पर साम्राज्यवाद की सेवा करना है ।

अंग्रेजी हटाने का सवाल राष्ट्रीय एकता के प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ है । भारत बहुजातीय राष्ट्र है । भारतीय भाषाएँ बोलनेवाली विभिन्न जातियाँ ब्रिटेन और फ्रांस की तरह एक-दूसरे से अलग स्वतन्त्र जातियाँ नहीं हैं । ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक नृत्तों से बँधी हुई वे एक ही राष्ट्र का अविभाज्य अंग हैं । जिस तरह हर प्रदेश में उसकी अपनी भाषा को सभी अधिकार मिलने चाहिए वैसे ही इन सबको जोड़नेवाली राष्ट्रभाषा हिन्दी को भी केन्द्र में पूर्ण अधिकार मिलने चाहिए ।

जो लोग अंग्रेजी हटाने का विरोध करते हैं, वे राष्ट्रीय एकता का विरोध करते हैं । विभिन्न प्रदेशों की जनता एक-दूसरे के नज़दीक हिन्दी के जरिये ही आ सकती है । अंग्रेजी के जरिये पढ़ा-लिखा बाबूवर्ग दिन-पर-दिन साधारण जनता से दूर होता जा रहा है ।

पिछले पन्द्रह साल में अंग्रेजियत बढ़ी है और उसके साथ भारतीय भाषाओं की उपेक्षा आम तौर से, और हिन्दी की उपेक्षा खास तौर से, बढ़ी है । यह उपेक्षा हिन्दी और अहिन्दी दोनों क्षेत्रों में है । डैडी, ममी और अंकलजी का चलन हिन्दी बाबूओं के घर में पिछले वर्षों ज़्यादा हुआ है । अमरीकी-साहित्य के नवकालो की हिन्दी में अंग्रेजी के अपच शब्दों की बाढ़ आ गई है ।

हिन्दी की उपेक्षा कांग्रेस में ही नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी में भी है—हमें इस कटु सत्य का सामना करना चाहिए । आज से इकतीस साल पहले प्रेमचन्द ने हमारे नेताओं के अंग्रेजी-प्रेम को अच्छी तरह परखा था और उसकी तीखी आलोचना की थी । बम्बई के राष्ट्रभाषा-सम्मेलन में उन्होंने कहा था—

“हमारी कौमी सभाओं में सारी कार्रवाई अंग्रेजी में होती है, अंग्रेजी में भाषण दिये जाते हैं, लेख लिखे जाते हैं, प्रस्ताव पेश किये जाते हैं, सारी लिखा-पढ़ी अंग्रेजी में होती है, उस संस्था में भी, जो अपने को जनता की संस्था कहती है । यहाँ तक कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट भी, जो जनता के खामुलखास भंडे-वरदार हैं, सभी कार्रवाई अंग्रेजी में करते हैं ।”

प्रेमचन्द की आलोचना का कोई असर कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं पर नहीं हुआ । वे जहाँ सन् '३४ में थे, वही सन् '६५ में हैं । इस स्थिति पर कौन गर्व कर सकता है ?

प्रेमचन्द ने बहुत सही सवाल उठाया था कि पार्टियाँ अपनी कार्रवाई किस भाषा में करती हैं । यही सवाल अपने एक लेख में मैंने भी उठाया था ।

मेरा अनुभव है कि राज्यों में कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता अपने मसौदे अंग्रेजी में तैयार करते हैं । अक्सर राज्यों के पत्रों में उनके अंग्रेजी लेखों के अनुवाद छपते हैं । योगीन्द्र

समाजी का कहना है कि राज्या में पार्टी का सारा काम प्रादेशिक भाषाओं में होता है। उसका स्वागत करना है। पार्टी के नेताओं को बधाई देना है कि कम-से-कम राज्यों में उहाँ पहल की और दूसरी पार्टियों के मामले एक आदम गया।

संविन कम्युनिस्ट पार्टी अपने केन्द्रीय दफ्तर से अंग्रेजी क्यों नहीं निताल पार्टी ? इसका मूल कारण है स्वयं पार्टी के नेताओं में हिन्दी के प्रति उपेक्षा का भाव।

यदि अखिल भारतीय स्तर पर मजदूर वर्ग की शक्ति हिन्दी के जरिये ही कायम हो सकती है, तो हिन्दी की यह उपेक्षा मजदूर वर्ग की ही उपेक्षा है।

कामगढ़ गांधीन लोचसभा में बाहर चले गए क्योंकि कोई मंत्री हिन्दी में बोला था। उनका मजदूर-प्रेम हिन्दी में चिट्ठा है, अंग्रेजी की मिर चढ़ाता है। बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी की दाना गान्ताओं न विधानसभा में कांग्रेस के साथ मिलकर हिन्दी के विरुद्ध प्रस्ताव पास किया, केन्द्र में अंग्रेजी उन्हें सप्रेम स्वीकार है।

पार्टी के नेता जो निम्न राज्या में अंग्रेजी हटाने की बात करते हैं, इसका कारण हिन्दी के प्रति यही उपेक्षा-भाव है। मराठी, उगला, तमिल के चलन की बात तो वे कर सकते हैं हिन्दी के चलन की बात कैसे करें ?

कहा जा सकता है कि हिन्दीभाषी क्षेत्र में कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर है, इसलिए पार्टी-केन्द्र में हिन्दी का चलन नहीं है।

संविन भारत का वह अंग्रेजी भाषी क्षेत्र कौन-सा है जहाँ कम्युनिस्ट आन्दोलन मजबूत होने से पार्टी-केन्द्र में अंग्रेजी चलनी है ? वह अंग्रेजी-भाषी क्षेत्र ऊपर के कुछ नेताओं तक सीमित है। भारत की घरेलू से उल्टा हुआ यह क्षेत्र विगड़ की तरह आसमान में लटका हुआ है। इस हवाई क्षेत्र की भाषा—अंग्रेजी—पार्टी-केन्द्र में चल सकती है। भारत की एक-तिहाई जनता की भाषा हिन्दी नहीं चल सकती।

कम्युनिस्ट पार्टी के बोर्डर में जो पिछलेतर की मदी अहिन्दी-भाषी हैं, उनमें अंग्रेजी जाननेवाले एक की मदी भी नहीं हैं। फिर भी पार्टी-केन्द्र में चलेगी अंग्रेजी !

हमारे आन्दोलन के विकास और फैलाव की वह कौन-सी विशेषता है जिसमें अंग्रेजी-भाषी न होने हुए भी हमारे नेता बदरिया के मुँह बच्चे की तरह अंग्रेजी की छान्नी से चिपकाये हुए हैं ? वह विशेष अवस्था है, हिन्दी की उपेक्षा।

दस स्थिति से लाभ उठाते हैं जनसम के नेता। वे जनता की सही माँग का समर्थन करके अपनी जन विरोधी नीति के लिए लोकप्रियता हासिल करते हैं। उनका उद्देश्य होता है, पूँजीवाद का मजबूत करना, तटस्थता की नीति खत्म करके भारत का साम्राज्यवादी घेमे में डकेन देना।

केन्द्र में अंग्रेजी कायम रखना समस्त भारतीय जनता के साथ अन्याय है, हिन्दी-भाषी जनता के साथ विशेष अन्याय है। अंग्रेजी चापू रखने की नीति का समर्थन करके कम्युनिस्ट पार्टी हिन्दी भाषी जनता में अपना अलगाव बढ़ाएगी, कम्युनिस्ट आन्दोलन का आवश्यकतानुसार शक्तिशाली नहीं बना सकता।

पिछले वर्षों का अनुभव बतलाता है कि जनता के असन्तोष से लाभ उठाकर प्रतिक्रियावादी दलों ने अपनी ताकत जितनी बढ़ाई है, उतना कम्युनिस्ट पार्टी ने नहीं। तब कम्युनिस्ट पार्टी संयुक्त थी; अब विभक्त है। सोच लीजिए, क्या नतीजा होगा।

अंग्रेजी के विरुद्ध हिन्दी जनता के असन्तोष को दक्षिण और बंगाल की ओर मोड़ना बहुत आसान है। जैसे कुछ लोग तमिल-प्रेम को हिन्दी-विरोध का रूप देते हैं, वैसे ही हिन्दी-प्रेम को तमिल-विरोध का रूप देना मुश्किल नहीं है। गृहयुद्ध की इस परिस्थिति में अंग्रेजी के बल पर राष्ट्रीय एकता की रक्षा नहीं की जा सकती।

समस्या का एक ही हल है : केन्द्र में हिन्दी हो, राज्यों में प्रादेशिक भाषाएँ।

इस पर भी यदि कोई कहे कि अंग्रेजी हटाने से अहिन्दी भाषाओं का दमन होता है तो निवेदन है, लोकसभा में सभी भाषाएँ चलाइए। हमें इस बात का मोह नहीं है कि भारत सरकार का काम हिन्दी में हो। धृणा इस बात से है कि उसका काम अंग्रेजी में होता है। केन्द्र में चाहे एक भारतीय भाषा चलाइए, चाहे दस; विदेशी भाषा अंग्रेजी को निकालिए।

मैंने योगीन्द्र शर्माजी से पूछा था, “पार्टी-दफ्तर में सभी भारतीय भाषाओं का चलन करने में क्या व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं ?”

उन्होंने उत्तर दिया है, “पार्टी के केन्द्रीय-दफ्तर में अंग्रेजी की जगह सभी भारतीय भाषाओं को बराबर जगह देने में व्यावहारिक कठिनाइयाँ अवश्य हैं। व्यावहारिक कठिनाइयाँ में मुख्य कठिनाई है बहुभाषी स्टाफ कायम करने की—तमाम भारतीय भाषाओं से अनुवाद करने की व्यवस्था की।”

पार्टी-केन्द्र में हिन्दी इसलिए नहीं चलती कि हिन्दी प्रदेश में कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर है ! अनेक भारतीय भाषाएँ इसलिए नहीं चल सकतीं कि उपयुक्त स्टाफ नहीं है ! इसलिए अंग्रेजी की गुलामी से पार्टी-केन्द्र मुक्त नहीं हो सकता !

योगीन्द्रजी ने मुझे आश्वासन दिया है कि लोगों को तमाम भाषाओं में बोलने की आजादी है। केन्द्रीय दफ्तर में तमाम भाषाओं में चिट्ठियाँ, रिपोर्टें आदि आती हैं। भविष्य में पार्टी-केन्द्र की भाषा हिन्दी ही होगी लेकिन जहाँ तक वर्तमान का सम्बन्ध है, उन्हीं के शब्दों में—“तमाम भारतीय भाषाओं की इस आजादी और बराबरी के बावजूद ‘फिलहाल’ अंग्रेजी प्रधान और सम्पर्क-भाषा है।

असली समस्या इसी ‘फिलहाल’ की है।

पार्टी के जो नेता अपने केन्द्र से अंग्रेजी निकालने में असमर्थ हैं, वे भारत में अंग्रेजी का प्रभुत्व कभी खत्म नहीं कर सकते।

हिन्दी-भाषी जनता से भड़कानेवाले कहते हैं, यह उत्तर और दक्षिण की लड़ाई है। दक्षिणवाले हिन्दी नहीं चाहते तो उन्हें उत्तर भारत से निकाल दो।

इस गृहयुद्ध की नीति के खिलाफ ‘धर्मयुग’ के अपने लेखों में मैंने हिन्दी-भाषी जनता के सामने यह कार्यक्रम रखा है : लड़ाई तमिल-हिन्दी की नहीं है, लड़ाई तमाम

भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी की है। इस संधप में हम हिन्दी भाषियों को पहल करनी चाहिए। हमें अपने हिन्दी-भाषी राज्यों में हर जगह हर स्तर पर हिन्दी को अमल में राजभाषा बनाना चाहिए। हमें अपने नेताओं को बाध्य करना चाहिए कि वे लोकसभा में हिन्दी में बोलें। भारत की एक तिहाई जनता के प्रतिनिधि केन्द्र और राज्यों में अपना सारा काम हिन्दी में करेंगे तो हिन्दी बहुत जल्दी राष्ट्रभाषा बन जाएगी।

इस कार्यक्रम के विपरीत हिन्दीभाषी जनता से कहना कि केन्द्र में अंग्रेजी कायम रहने दो, उसे तमिल-विरोध की ओर बढ़ने की राह देना है। कांग्रेस सरकार की भाषा-नीति में मुख्य हिन्दी-भाषी जनता के सामने जब अंग्रेजी से सदन की नीति न रहेती, सब वह अहिन्दी भाषियों के खिलाफ ज़रूर भड़काई जाएगी।

मैं हिन्दी-शोध क मताओं से भी लोकसभा में हिन्दी बोलने को कहता हूँ तो यागीन्द्र शर्माजी को लगता है कि मैं अहिन्दी-भाषियों पर हिन्दी सादन की बात कर रहा हूँ। अंग्रेजी को हटाने की ललकार उन्हें गृहयुद्ध की ललकार मानूम होती है।

लोकसभा में अहिन्दी भाषी नेता शोक से अपनी-अपनी भाषाएँ बोलें। हिन्दी भाषी नेता हिन्दी में बोलें। कम्पुनिस्ट मदस्य लोकसभा में अपने व्यवहार से इस नीति की मिलाव कायम करें।

लेकिन हमारे पार्टी-नेता अंग्रेजी में बोलना पसन्द करते हैं। लोकसभा में सभी भारतीय भाषाओं में बोलने की सुविधा के लिए यही सड़ते। सब वैसे जब उनके अपने केन्द्र में अंग्रेजी चलती है।

साम्राज्यवादी प्रचारक कहने में कि भारतीय भाषाएँ पिछड़ी हुई हैं इसलिए अंग्रेजी चलेगी। इस प्रचार का नया रूप यह है हिन्दी जनता से दूर खली गई है, पड़िताऊ हो गई है, रघुवीरी है, इसलिए अंग्रेजी चलेगी।

यदि मान लें कि डॉ० रघुवीर इने बड़े सूरमा थे कि भारतेन्दु से लेकर अमृत-लाल नागर तक चली आती हिन्दी की प्रचलित धारा को मोड़कर उन्होंने उसे पड़िताऊ बना दिया तो क्या इसने अंग्रेजी का कायम रहना उचित हो जाएगा ?

मझे की बात यह है कि राज्यों में हिन्दी चल सकती है। कठिनाई होती है, उसके दिल्लीवाले दफ्तरों में घुमने पर।

साम्राज्यवादी प्रचारक हिन्दी उर्दू को सहाकर अंग्रेजी का पाया मजबूत करने में। उस नीति का नया रूप यह है हिन्दी ने अपनी बहुत और महेली उर्दू का दमन किया है, उस अपने ही घर से निकाल दिया है। इसलिए केन्द्र में अंग्रेजी चलनी चाहिए।

'जनशक्ति' और 'जनयुग' के उर्दू-सम्बरण निकालिए। इच्छा हो तो दोनों में एक ही भाषा 'हिन्दुस्तानी' बनाइए। पटना और लखनऊ के पार्टी-दफ्तरों में हिन्दी-उर्दू दोनों को बराबर जगह दीजिए। लेकिन उर्दू-दमन के नाम पर अंग्रेजी चलाने की कोशिश मत कीजिए।

केन्द्र और राज्यों से एक साथ अंग्रेजी हटाने की माँग करना उग्र हिन्दी राष्ट्रवाद के उन्माद में आत्मविभोर होना नहीं है। उग्र हिन्दी राष्ट्रवाद का नारा है : एक भाषा, एक राष्ट्र। मेरी नीति इससे बिलकुल उल्टी है। उस नीति का मूल सूत्र यह है : भारत बहुजातीय राष्ट्र है। बहुजातीय है, इसलिए राज्यों में वहीं की भाषाएँ राजभाषा होंगी ; राष्ट्र है; इसलिए सब जातियों को मिलानेवाली केन्द्रीय भाषा हिन्दी होगी। इन दोनों बातों में किसी एक को भूल जाना राष्ट्रीय विघटन को बुलावा देना होगा। (१९६५)



## भारत की राजमाया अंग्रेजी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा

गान्धी शर्माजी ने ठीक लिखा है कि सिद्धान्त और नीति की जो बातें मैंने उद्घाई हैं, उनकी अवहेलना नहीं की जा सकती और वे बानें अपने-आप में भी महत्वपूर्ण हैं। इस विषय पर मैं जो कुछ आगे लिख रहा हूँ, पाठक उसे नीति और सिद्धान्त का आवश्यक विवेचन समझकर पढ़ेंगे।

### अंग्रेजी के प्रभुत्व से हानि

गान्धी शर्माजी मानते हैं कि अंग्रेजी का प्रभुत्व कायम रहने से हानि होती है। इस हानि से देश को कितने बड़े मुकट का सामना करना पड़ सकता है, मजदूर वर्ग और कम्युनिस्ट पार्टी ने इस हानि का सम्बंध क्या है, इस बारे में उनका और मेरा विस्तरेण एक भा नहीं है।

उनका कहना है, "अंग्रेजी के आधार पर भारत की एकता बँधी हो होगी जैसी अंग्रेजी शासन के मानहृत थी।"

इतना कहना काफी नहीं है। अंग्रेजी के आधार पर आज भारतीय पूँजीवाद औद्योगिक एकता भी कायम नहीं रख सकता।

सामाज्यवाद फौज, पुलिस और अंग्रेजी जाननेवाले नौकरशाह वर्ग के द्वारा जनता का शोषण करने के लिए उपनिवेश भारत की एकता कायम किये हुए था। अब नौकरशाह वर्ग का मालिक है भारतीय पूँजीवाद जिसमें बाजारों के लिए सड़नेवाले विभिन्न प्रदेशों के पूँजीपति हैं तथा इनमें कुछ इजारेदार हैं, सेम गैर-इजारेदार पूँजीपति हैं। इन अतिबिरोधी ने पीटित पूँजीवाद औपनिवेशिक एकता की रक्षा नहीं कर पा रहा है। उसकी शक्ति भारतीय पार्टी में समानक गुटबन्दी है और उसका सामाजिक आधार दिन-पर-दिन संकुचित होना जा रहा है।

गोविन्द शर्माजी मानते हैं कि भारत का पूँजीपति वर्ग "विभिन्न भाषा-समूहों में बँटा हुआ है, विभिन्न जातियों में विभक्त है। वह एक-दूसरे की कीमत पर अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाहता है।" इसीलिए वह अंग्रेजी के सहारे देश की पुरानी औपनिवेशिक एकता को भी बचा नहीं पा रहा।

देश की एकता पूँजीपति वर्ग के हित में है। योगीन्द्रजी का कहना है, “पूरे देश के बाजार और राजशक्ति की आवश्यकता उनको राष्ट्रीय एकता का हिमायती बनाती है।” भारतीय इतिहास के अनुभव को सभी लोग जानते हैं कि यहाँ के पूँजीपति वर्ग ने साम्राज्यवादी योजना स्वीकार की और ‘पूरे देश के बाजार’ को अपने वर्ग-हितों के विरुद्ध, बँट जाने दिया।

देश की एकता की रक्षा के लिए पूँजीपति वर्ग की एकता का भरोसा न करके श्रमिक जनता की एकता दृढ़ करनी चाहिए। यह एकता अंग्रेजी के जरिये दृढ़ नहीं की जा सकती। अंग्रेजी का प्रभुत्व इस एकता के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। अंग्रेजी के कायम रहने से भारतीय जनतंत्र का आवार संकुचित होता है और फासिस्टवाद का खतरा बढ़ता है।

‘भाषा और समाज’ में मैंने लिखा था :

“एक छोटा-सा वर्ग जो अंग्रेजी अखबार पढ़ता है, अंग्रेजी के माध्यम से नौकरी पाता है, अंग्रेजी के माध्यम से पार्लियामेंटरी डिमोक्रेसी और सोशलिस्ट पैटर्न के प्रयोग करना है वही ‘नेहरू के बाद क्या होगा’—यह समस्या उठाकर परेशान भी हो लेता है ‘...जनतन्त्र का यह संकुचित वर्ग-आधार खुद तो नष्ट होगा ही, खतरा यह है कि अपने विनाश के साथ वह देश की बागडोर किसी अय्यूव खाँ को न सौंप दे !” (पृ० ४१५)

इस देश में हर चीज के लिए आन्दोलन होते हैं। भाषावार राज्यों के आन्दोलन में कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने पूरी ताकत लगा दी। केवल केन्द्र से अंग्रेजी हटाने का आन्दोलन नहीं होता, केवल इस तरह का आन्दोलन पार्टी के नेताओं को पसन्द नहीं है। इसका कारण यह है कि संयुक्त महाराष्ट्र या विशाल आन्ध्र के निर्माण को वे जितना आवश्यक समझते थे, उतना अंग्रेजी के प्रभुत्व को खत्म करना नहीं।

मैंने लिखा था, “अंग्रेजी सीखना और बात है; उसे सीखकर लाभ उठाया जा सकता है...लेकिन उसे सभी भारतीय भाषाओं के ऊपर केन्द्रीय और सांस्कृतिक भाषा बनाने से ऐसे वर्ग का ही सृजन होगा जो जनता से दूर होगा, जो अंग्रेजी ज्ञान के बल पर—न कि ईमानदारी, देशभक्ति, कार्यक्षमता के बल पर—शासनकार्य चलाएगा। इससे देश की अपार क्षति होगी और हो रही है।” (उप०, पृ० ४५३)

स्पष्ट है, अंग्रेजी से होनेवाली हानि के बारे में योगीन्द्रजी के और मेरे विचारों में अन्तर है।

## कांग्रेस और अंग्रेजी

देश में जो भाषा-सम्बन्धी द्वेषभाव फैला है, उसके लिए सबसे पहले कांग्रेसी नेता जिम्मेदार हैं। उन्होंने भाषावार राज्यों का विरोध किया और अपने वक्तव्यों में प्रादेशिक भाषाओं को उचित महत्त्व नहीं दिया—यह स्थिति का एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि सन् ४६ से अब तक तरह-तरह के बहाने करके वे अंग्रेजी का प्रभुत्व कायम किये

हुए हैं। इस दूसरे पहलू पर योगीन्द्रजी का ध्यान कम जाता है।

मुख्य अन्तर्विरोध हिन्दी और अहिन्दी भाषाओं में नहीं, बरबडी तथा समस्त भारतीय भाषाओं में है। कांग्रेसी नेताओं ने जहाँ भी वेस्ट में हिन्दी चलाने की बात की, योगीन्द्रजी उनकी सख्त आलोचना करते हैं। वे अठारह साल में अंग्रेजी बोल रहे हैं, इसकी गहन जानकारी वह नहीं करते।

उन्होंने लिखा है, “केन्द्रीय सरकार ने २६ जनवरी ने हिन्दी को ‘राष्ट्रभाषा’ बनाने की जा पासबन्द और उक्तावे की घोषणा की, उससे और-हिन्दीभाषी लोगों में, विशेषकर तमिलनाडु में विरोध का तूफान पैदा हो गया।”

कांग्रेस के कणधार चाहते हैं कि अंग्रेजी न आज हट, न बन। हिन्दी-भाषी जनता ने ही कांग्रेस का सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं। उसे सुन बनने के लिए वे राष्ट्रभाषा की बातें करते हैं, हिन्दी को समृद्ध करने के लिए साक्षी रूप रखते हैं। उनके इस पासबन्द पर योगीन्द्रजी को विरोध कम नहीं आता।

योगीन्द्र शर्माजी के विपरीत हर मजिल पर मैंने कांग्रेसी नेताओं के इस पासबन्द की बराबर आलोचना की है।

सन् '४६ में मैंने लिखा था

“भारतीय जनता न मांगेगी भी कि शिक्षा, अदालत-कचहरी शासन इत्यादि में अंग्रेजी की जगह उसकी अपनी भाषा चले। यह बिल्कुल न्यायपूर्ण मांग थी। राष्ट्रीय नेताओं से आशा की जाती थी कि सन् '४७ में आजादी पाने के बाद इस मांग को वे पूरा करेंगे। लेकिन विभिन्न कारणों से वे उसे पूरा नहीं कर सके। दस साल तक उद्योग-धन्दा का राष्ट्रीयकरण न हुआ। बीते ही पाँच या दस साल तक आम जनता की उच्च शिक्षा, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यवाही उसकी अपनी भाषा में न होगी” (‘कम्युनिस्ट’)

पाँच साल बाद राजभाषा के सवाल पर मैंने एक पुस्तिका लिखी जो पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस द्वारा प्रकाशित हुई। उसमें कांग्रेसी नेताओं की दुरमी नीति के बारे में मैंने लिखा था, “कांग्रेसी नेताओं की कोई मस्या नहीं थी कि अंग्रेजी हटाने के लिए जमकर कोशिश करें। उन्होंने स्पष्ट ही अपने सामने यह सम्भावना रखी थी कि पन्द्रह साल के बाद भी अंग्रेजी जारी रहेगी, शायद उनके अगले पन्द्रह साल तक जारी रहेगी, हो सकता है इसके आगे भी जारी रहे।”

सन् '६५ में बिल्कुल यही स्थिति हमारे सामने है।

नेहरूजी के अंग्रेजी-भयन की चर्चा करते हुए उसी पुस्तिका में लिखा था, “संविधान मसौदा समिति के अध्यक्षों के पीछे यह निर्मम निश्चय साफ़ दिखाई देता है कि समस्त भारतीय भाषाओं की हानि करते हुए अंग्रेजी को अनिवार्य राजभाषा के रूप में बालू रखा जाय। श्री नेहरू ने बड़ी स्पष्टता से कहा है कि ‘आप इस बात को प्रस्ताव में चाहें नहीं, चाहें न लीजें, अंग्रेजी लाजमी तौर से भारत में बहुत महत्वपूर्ण

भाषा बनकर रहेगी जिसे बहुत लोग सीखेंगे और शायद उन्हें उसे जबरन सीखना होगा।' लोग इन तमाम वर्षों में अंग्रेजी जबरन सीखते आए हैं। अब उनके सामने एकमात्र यह संभावना पेश की गई है कि अंग्रेजी के बिना हमारी कला और विज्ञान का पतन हो जाएगा और देश का विघटन होगा, उसका नाश हो जाएगा।"

'भाषा और समाज' में मैंने जहाँ भाषावार राज्य-आन्दोलन के दमन की निन्दा की है, वहाँ अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा बनाये रखने की कांग्रेसी नीति की आलोचना भी की है। लिखा था :

"अंग्रेजी भारत की राष्ट्रभाषा रहे तो सबसे अच्छा। दूसरे देशों के सामने शर्म के मारे उसे राष्ट्रभाषा न कह सकें और झूठ मारकर हिन्दी का व्यवहार करना पड़े तो अंग्रेजी और हिन्दी दोनों को राष्ट्रभाषा का दर्जा देना चाहिए। यदि हिन्दी को ही राष्ट्रभाषा रखने की प्रतिज्ञा करनी पड़े, तो भी जहाँ तक हो सके, सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यों के लिए अंग्रेजी का व्यवहार होना ही चाहिए... भारत को आज़ाद करने की मुख्य प्रेरणा अंग्रेजी से ही मिली लेकिन आज़ादी पाने के लिए भी अंग्रेजी की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी अब समाजवादी भारत के निर्माण के लिए है।" (पृ० ४१३)

पिछले अठारह साल में कांग्रेस की जो नीति रही है, उसी का अनुसरण करते हुए उसके नेताओं ने नया प्रस्ताव पास किया है। इस प्रस्ताव के अनुसार प्रादेशिक भाषाएँ पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं का ऐच्छिक माध्यम बनेंगी, अखिल भारतीय नौकरियों का अनिवार्य माध्यम रहेगी अंग्रेजी।

गांधीजी भाषाओं के आधार पर प्रान्तों के नवनिर्माण के पक्ष में थे। नेहरूजी भाषावार राज्य बनाने के प्रबल विरोधी थे। गांधीजी केन्द्र से अंग्रेजी हटाने के पक्ष में थे, नेहरूजी उसे वहाँ जमाये रखने के पक्ष में थे। केन्द्र और राज्य—दोनों जगह गांधीजी और नेहरूजी की भाषा-नीति में अन्तर था। नेहरूजी ने देश के लिए बहुत से अच्छे काम किए लेकिन उनकी अंग्रेजी कायम रखने की नीति ग़लत थी। देश में अंग्रेजी कायम रखने के लिए जिम्मेदार है कांग्रेस।

## भाषागत द्वेष और गृहयुद्ध की सम्भावना

ज़ारशाही रूस में रूसी पूँजीवाद ने साम्राज्यवाद का रूप ले लिया था। रूसी पूँजीपति गैर-रूसी इलाकों का शोषण करते थे, वहाँ की भाषाओं का दमन करते थे। सन् '४८ में कम्युनिस्ट पार्टी की दूसरी कांग्रेस ने अपने राजनीतिक प्रस्ताव में भारत को भी ज़ारशाही रूस की तरह जातियों का कारागार मान लिया था। इसीलिए उत्पीड़क पूँजीवादी गुट के विरुद्ध केरल, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों के लिए आत्मनिर्णय की माँग की गई थी।

प्रस्ताव में कहा गया था, "कांग्रेसी नेतृत्व ने अपनी समझौतावादी नीति के कारण आत्मनिर्णय के अधिकार का विरोध करने की वजह से देश का घातक विभाजन करा दिया है। आज इंडियन यूनियन में वह फिर वही अपराध कर रहा है, उत्पीड़क पूँजीपति वर्ग के

हित में यह महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु आदि जातीय प्रदेशों के आत्मनिर्णय का अधिकार सम्बोधित करना है।”

भारतीय परिस्थिति के मद्देन में आत्मनिर्णय की यह बात समस्त भी और मात्र भी है। आत्मनिर्णय की माँग की जानी है साम्राज्यवाद के उन्नास, उन प्रदेशों के लिए जहाँ विदेशी पूँजीपतियों ने अपने उपनिवेश कायम किये हैं।

भारत में अहिन्दी भाषाओं के दमन की आग का कुछ लोगों के मन में है, लेकिन दमन का कोई ठोस सामाजिक आधार नहीं है। यदि हिन्दीभाषी क्षेत्र का पूँजीवाद साम्राज्यवाद का रूप ले रहा हो, यदि किसी एक प्रदेश के पूँजीपतियों ने अन्य प्रदेशों को अपना उपनिवेश बनाना आरम्भ कर दिया हो तो मानना होगा कि अहिन्दी भाषाओं के दमन का सामाजिक स्वतन्त्रता है। ऐसी स्थिति नहीं है, इसलिए शक-शुबह की बात की जा सकती है; भाषाओं के दमन की बात करना जलजल में हिन्दी के प्रति द्वेष फैलाना है।

योगीन्द्रजी ने शक-शुबहों और सामाजिक खतरों को मिलाकर एक कर दिया है। उन्होंने आरम्भाही रूप और भारत के पूँजीवाद का फल नहीं देखा। यह अहिन्दी भाषाओं के दमन की बात इस तरह करने है मानो दिव्यी सरकार केवल हिन्दी क्षेत्र के पूँजीपतियों की सरकार हो। उन्होंने पूछा है, ‘१९४६ में दक्षिण भारत की जन्मा हिन्दी को एक दबाने-वाली भाषा के रूप में देखनी थी या नहीं?’ इसका उत्तर है कि कुछ लोग दक्षिण में हिन्दी को दबानेवाली भाषा के रूप में देखते थे। यह उनकी आशंका थी। उस आशंका के कारण थे। लेकिन हिन्दी दबानेवाली भाषा न तब थी, न आज है। दबानेवाली भाषा बाल्त्व में अफेड़ी थी, मात्र भी है।

योगीन्द्रजी ने पूछा है कि पाटी ने अपनी जनत नीति सुधार ली, तब सन् ‘६१ में मैंने वही जनत बात क्यों दुहराई।

उन्हें भ्रम है कि सन् ‘६१ में मैंने सन् ‘४६ की बातें दुहराई हैं। सन् ‘४६ में मैंने केन्द्रीय राजभाषा का विरोध किया था, सन् ‘६१ में उसका समर्थन किया था। सन् ‘४६ में जातीय उन्माद का सामाजिक स्वतन्त्रता है, मैं यह मानता था। सन् ‘६१ में शक-शुबहों की बात थी, भाषाओं के सामाजिक दमन की बात नहीं थी। इन शक-शुबहों का सम्बन्ध मुख्यतः नौकरशाही मध्यमों के लोगों से है। इनके बारे में ‘भाषा और समाज’ में मैंने लिखा था।

“देश के विभिन्न वर्गों का जैसा सामाजिक दृष्टिकोण है, उसी के अनुकूल वे भाषा-समस्या का समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। इनमें सबसे पहले यह वर्ग है जो साम्राज्यवादी व्यवस्था में शिक्षा के कारण ऊँची नौकरियाँ पा सका था और अब स्वाधीन भारत में वह उसी शिक्षा के आधार पर अपने लिए उन नौकरियों को बरकरार रखना चाहता है। इनमें विभिन्न प्रदेशों के उच्च मध्यमवर्गीय शिक्षित लोग हैं जो समझते हैं कि अफेड़ी के न रहने से हिन्दीवाने बाड़ी मार ले जाएँगे। इनकी तो मातृभाषा हिन्दी है, दूसरों को उसी को सीखना पड़ेगा। इस तरह के तर्क साम्राज्यवादी अवस्थाओं को बाहिर करते हैं।”

(पृष्ठ ४४३)

इस भय को दूर करने का उपाय मैंने यह बताया था, “ऊँची नौकरियों के लिए हिन्दी-भाषियों को तभी लेना चाहिए जब उन्हें एक अहिन्दी भाषा का अच्छा ज्ञान हो।”

(पृ० ४५७)

‘जनशक्ति’ में यही प्रस्ताव मैंने दोहराया था, “अहिन्दी भाषा का समुचित ज्ञान अनिवार्य कर देने से हिन्दीवालों को कोई विशेष सुविधा न मिलेगी।”

जो लोग सचमुच अंग्रेजी का प्रभुत्व खत्म करना चाहते हैं, वे इस प्रस्ताव पर गम्भीरता से विचार करेंगे। जो हठधर्मी से केन्द्र में अंग्रेजी चलाते रहने के पक्ष में हैं, वे उसके बारे में चुप रहेंगे।

तमिलनाडु में जो आन्दोलन चला उसमें शक-शुबहों से लाभ उठाया गया, तिल का ताड़ बनाकर जनता को गुमराह किया गया। आन्दोलन के सूत्रधार वे थे जो द्रविड़ भारत या तमिलनाडु का अलगाव चाहते हैं, जो कश्मीर से लेकर नागालैंड तक अलगाव के हर आन्दोलन का साथ देते हैं।

भारत में गृहयुद्ध का खतरा पैदा होता है उन लोगों से जो देश के नये विभाजन के लिए प्रयत्नशील हैं। भाषाओं के दमन की बात वे अपना असली उद्देश्य छिपाने के लिए करते हैं। उनकी इस नीति का पर्दाफाश करके जनता को उनके प्रभाव से निकालना चाहिए, न कि उनके सुर में सुर मिलाकर कहना चाहिए कि हिन्दी भाषा अहिन्दी भाषाओं का दमन कर रही है।

अपने धर्म से प्रेम करना बुरा नहीं है। मुस्लिम लीग ने कहा—इस्लाम खतरे में है। मुसलमानों को हिन्दू खा जाएँगे। लीग ने ‘डायरेक्ट ऐक्शन’ का रास्ता अपनाया। आत्मनिर्णय के नाम पर देश का विभाजन हुआ।

अपनी भाषा से प्रेम करना बुरा नहीं है। द्रविड़ मुन्नेत्र कण्णम ने कहा—तमिल खतरे में है; तमिल-भाषियों को हिन्दीवाले गुलाम बना लेंगे। कण्णम ने ‘डायरेक्ट ऐक्शन’ का रास्ता अपनाया। हिन्दी तमिल का दमन न करे इसलिए केन्द्र में अनिश्चित काल के लिए अंग्रेजी कायम रहेगी !

## केन्द्र और राज्य—पहले और बाद का सवाल

योगीन्द्रजी ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि पहले राज्यों से अंग्रेजी हटाना जरूरी है। राज्यों के विश्वविद्यालयों, सरकारी दफ्तरों आदि में पूरी तरह प्रादेशिक भाषाओं का चलन हो जाने के बाद ही केन्द्र से अंग्रेजी हटाने की बात की जा सकेगी। उन्होंने गांधीजी का यह कथन उद्धृत किया है, “सबसे पहले उन समृद्ध प्रादेशिक भाषाओं को पुनर्जीवित करना है जो भारत को सुलभ है।”

इसका अर्थ उन्होंने यह लगाया है कि जब तक राज्यों से अंग्रेजी निकल न जाय, तब तक केन्द्र में अंग्रेजी चलती रहे ! इसके विपरीत गांधीजी ने प्रस्ताव किया था कि प्रान्तों में ऐसे कर्मचारी रखे जाएँ जो प्रान्तीय भाषा के साथ केन्द्रीय भाषा भी जानते हों।

इसीलिए उन्होंने लिखा था कि “प्रान्ता को वेद में काम पड़ेगा। यह काम वे अंग्रेजी में करने की हिम्मत न करेंगे।”

‘भाषा और समाज’ में गांधीजी के बारे में मैंने लिखा था, “वह भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। वह न इन भाषाओं पर हिन्दी लादना चाहते थे, न हिन्दी लादने का होवा मड़ा करके अंग्रेजी बनाये रखने के पक्ष में थे।” (पृ० ४१३) गांधीजी की भाषा-नीति की यही व्याख्या मैं अब भी करता हूँ।

योगीन्द्रजी ने ‘भाषा और समाज’ से वे अंश उद्धृत किये हैं जहाँ भाषावार राज्यों के विरोध की निन्दा की गई है, जहाँ इस विरोध के कारण कुछ अहिन्दी भाषी लोगों ने हिन्दी के प्रति भय उत्पन्न होने की बात कही गई है, जहाँ राज्यों से अंग्रेजी हटाकर इस भय को दूर करने की बात की गई है। उन्होंने ये अंश छोड़ दिये हैं जहाँ मैंने लिखा था कि इस भय का बहाना बनाकर वेद में अंग्रेजी कायम रखना चलन है।

मैंने स्पष्ट लिखा था, “भाषावार राज्यों के निर्माण का विरोध करके कांग्रेसी नेतृत्व ने काफी हद तक यह भय उत्पन्न किया है। इसका यह अर्थ नहीं कि अहिन्दी भाषी अंग्रेजी की शरण लें।” (पृ० ४६६-६७)

मानुभाषाओं की दुहाई देकर अंग्रेजी की शरण लेनेवालों के बारे में मैंने लिखा था, “अहिन्दी क्षेत्रों के लोग अंग्रेजी में चिपके रहना चाहते हैं, वे मानुभाषाओं की सेवा नहीं करते। उह हर बात में अंग्रेजी अपनी मानुभाषाओं से श्रेष्ठ समझती है। इसलिए उसे वे वेद में ही नहीं अपन यहाँ भी सबसे ऊँचे आसन पर बिठाये रखना चाहते हैं। मानु-भाषाओं की दुहाई देकर अंग्रेजी का प्रभुत्व स्वीकार नहीं किया जा सकता।”

(पृ० ४४४)

गांधीजी के लेख को प्रकाशित हुए अठारह साल हो गये। योगीन्द्रजी के लिए अभी ‘समृद्ध प्रादेशिक भाषाओं को ‘पुनर्जीवित’ करने का सवाल बना हुआ है। तमिल, तेलुगु, मराठी आदि भाषाओं के आधार पर तमिलनाडु, आन्ध्र, महाराष्ट्र आदि राज्य कभी क बन गये। योगीन्द्रजी समझते हैं कि भाषावार राज्यों के विरोध से जो भय उत्पन्न हुआ था, उसे दूर करना अभी बाकी है। तमिलनाडु में तमिल माध्यमवाले विद्यार्थी खोते गये। छात्रों के अभाव में उन्हें बन्द कर देना पड़ा। इसलिए कि दिल्ली सरकार हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहती थी।

ध्यान देने की बात है कि तमिलनाडु में भाषावार राज्य बनाने के लिए कोई आन्दोलन नहीं हुआ। आन्दोलन हुआ आन्ध्र और केरल में जहाँ तमिलनाडु की तरह तोड़-फोड़ की कोई आवश्यकता नहीं हुई। भाषावार राज्य-आन्दोलन का दमन किया गया महाराष्ट्र और गुजरात में जहाँ हिन्दी विरोधी आन्दोलन का अभाव है। अहिन्दी भाषी प्रदेशों में महाराष्ट्र और गुजरात ऐसे राज्य हैं जहाँ हिन्दी को राजभाषा बनाने के लिए जोरदार आवाज उठी है।

भाषावार राज्यों के आन्दोलन में कम्युनिस्ट पार्टी ने सक्रिय भाग लिया था।

तमिलनाडु के हिन्दी-विरोधी आन्दोलन को प्रेरणा देनेवाले दो मुख्य दल थे—स्वतन्त्र पार्टी और द्रविड़ कपणम। भाषावार राज्यों के दमन से अहिन्दी-भाषियों में हिन्दी के प्रति भय उत्पन्न हुआ है, इस सूत्र का आज की परिस्थिति से कोई भी सम्बन्ध नहीं है।

आज यह विलकुल स्पष्ट है कि राज्यों की सरकारों के सामने प्रादेशिक भाषाओं के व्यवहार को रोकनेवाली कोई भी वैधानिक कठिनाई नहीं है। केन्द्रीय नौकरियों में अंग्रेजी चलती है। इनके प्रभाव से राज्यों के शिक्षाक्रम में अंग्रेजी की पढ़ाई अनिवार्य हो जाती है।

‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ के विशेष संवाददाता ने उस पत्र के ७ जुलाई के अंक में लिखा है कि राजस्थान सरकार ने अनेक विभागों में हिन्दी के व्यवहार का निर्देश किया है किन्तु योजना सेक्रेटेरियट जैसे विभागों को छोड़ दिया गया है। “जब तक योजना आयोग (प्लानिंग कमीशन) ही हिन्दी के व्यवहार का फैसला नहीं करता, तब तक राज्य को मजबूर होकर अंग्रेजी का व्यवहार जारी रखना पड़ेगा। इस पृष्ठभूमि में यह महसूस किया जा रहा है कि यदि अंग्रेजी की पढ़ाई पर जोर कम दिया जाएगा तो राजस्थान और उसके नौजवानों के हितों की हानि होगी।”

जब राजस्थान का यह हाल है तब अहिन्दीभाषी राज्यों की स्थिति की कल्पना की जा सकती है। कौन राज्य नहीं चाहता कि उसके नौजवान ज्यादा-से-ज्यादा संख्या में केन्द्रीय सेवाओं में लिये जाएँ? इन केन्द्रीय सेवाओं के लिए अंग्रेजी का ज्ञान अनिवार्य है। इसलिए केन्द्रीय सेवाओं का मेवा लूटने के लिए राज्य एक-दूसरे से होड़ करते हैं कि कौन अंग्रेजी ज्यादा पढ़ाता है।

इसीलिए आज की परिस्थिति में केन्द्र से अंग्रेजी हटाये बिना राज्यों में अंग्रेजी का प्रभुत्व खत्म नहीं किया जा सकता।

यद्यपि योगीन्द्र शर्माजी ने अपने लेख में राज्यों में पहले अंग्रेजी हटाने पर बहुत जोर दिया है किन्तु केन्द्र में उतने परिवर्तन की बात उन्होंने मान ली है जितना कांग्रेस को स्वीकार है। कांग्रेस का कहना है कि केन्द्रीय सेवाओं की परीक्षाओं में प्रादेशिक भाषाओं को ऐच्छिक माध्यम बनाया जाय। योगीन्द्रजी इसे स्वीकार करते हैं। जब तक राज्यों से अंग्रेजी हट न जाय तब तक केन्द्र में कोई परिवर्तन न हो—यह सिद्धान्त उन्होंने खुद काट दिया। मेरा भी कहना है, केन्द्र और राज्य—दोनों जगह से अंग्रेजी हटाई जाय।

योगीन्द्रजी जब केन्द्र में इतना परिवर्तन मान लेते हैं—कि परीक्षाओं में प्रादेशिक भाषाएँ ऐच्छिक माध्यम हों, तब दो कदम आगे और बढ़ें और यह माँग करें—केन्द्र में अंग्रेजी की जगह भारतीय भाषाओं का व्यवहार हो, अंग्रेजी का चलन खत्म करने की अवधि निश्चित हो।

केन्द्र में अंग्रेजी चलती है, इस कारण राज्यों में भी उसकी जड़ जमी हुई है। जो भी प्रादेशिक भाषाओं का हित चाहता है, वह केन्द्र से अंग्रेजी हटाने की माँग का समर्थन करेगा।



## कम्युनिस्ट पार्टी और अंग्रेजी

कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को कोई ताल्लु नहीं है कि केन्द्रीय सरकारों नीचे-गियां उन्हें भी मिल जाएं। उह कोई भय नहीं है कि पार्टी-केन्द्र से हिन्दी का चलन हुआ तो राज्या में पार्टी-नाम के लिए प्रादेशिक भाषाओं का व्यवहार न हा पाएगा। फिर भी पार्टी-केन्द्र की भाषा अंग्रेजी है।

यामिन्द्र शर्माजी के अनुसार राज्यों का सारा पार्टी-कार्य प्रादेशिक भाषाओं में होता है। जहाँ तक पार्टी का सम्बन्ध है, राज्यों में अंग्रेजी हटाने का कार्यक्रम पूरा हो गया है। फिर भी पार्टी-केन्द्र से अंग्रेजी नहीं निकाली जा रही। इसके कारण उद्भूत होते लेकिन जो कारण कम्युनिस्ट पार्टी के सामने हैं, उनसे लगड़े कारण कार्रवाई हो रही है। राज्यों में अंग्रेजी-विरोधी क्रान्ति जाय पूरी कर लेंगे और उसके बाद उस क्रान्ति का भण्डा केन्द्र में गढ़ेंगे—यह बात मैं कैसे मानूँ ?

ब्रिटिश राज में कम्युनिस्ट पार्टी पर यह पावन्दी नहीं कि वह अपना काम अंग्रेजी में करे। कांग्रेसी राज में भी उस पर कोई ऐसी पावन्दी नहीं रही। उसका जन्म हुए चालीस वर्ष हो गये। कानूनी जीवन बिताते हुए बीस साल से ऊपर हुए। वह सरीर जन्म की पार्टी है, श्रमिकवर्ग की पार्टी है। योशीन्द्र शर्माजी के अनुसार वह साम्प्रतिक क्रान्ति की पार्टी है। लेकिन पार्टी के नेता अभी तक अपनी केन्द्रभूमि में इन साम्प्रतिक क्रान्ति का बीजारोपण नहीं कर सके। वे पार्टी-केन्द्र में अंग्रेजी की विपत्तियों की उड़ नहीं तोड़ पाये। तब पूजीवादो पाठियों से क्या आशा की जाय ?

भारत की राजभाषा हिन्दी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा। मुन्ने में बहुत अच्छा लगना है। लेकिन सोचने की बात है जब पार्टी के नेता खुद अपने लिए हिन्दी को सम्पर्क-भाषा नहीं बना पाये, तब राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चे में उसका प्रवेश के किस द्वार से करायें ? मोर्चा घोषित करेगा कि भविष्य में भारत की राजभाषा होगी हिन्दी लेकिन वर्तमान काल में खुद मोर्चे की भाषा होगी—अंग्रेजी।

अंग्रेजी ने अपनी हुकूमत बनाने के लिए आई० सी० एस० अधिकारों के लिए हिन्दुस्तानी मीलना अनिवार्य कर दिया था। मेरा प्रस्ताव है कि देश की सेवा के लिए—मजदूर वर्ग की एकता दृढ़ करने के लिए—कम्युनिस्ट पार्टी की नेतृत्व कौमिल के सदस्य हिन्दी सीखें। यह नियम बना दिया जाय कि जिसे हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान न होगा वह राष्ट्रीय कौमिल का सदस्य न हो सकेगा।

योशीन्द्रजी ने 'भाषा और समाज' से एक वाक्य उद्धृत किया है जिसमें पार्टी के नेताओं द्वारा हिन्दी बोलने की तारीफ है। वाक्य है, "भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि मास्को और पेकिंग के कम्युनिस्ट सम्मेलनों में हिन्दी का व्यवहार कर चुके हैं।"

यह तारीफ मैं वापस नहीं ले रहा हूँ। निवेदन यह है कि मास्को और पेकिंग में ही नहीं, पार्टी के नेता दिल्ली में भी हिन्दी बोले।

योगीन्द्र शर्माजी 'भाषा और समाज' के इन वाक्यों पर विचार करें : "जब हम बाहर जायेंगे, किसी अन्य राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे, तब (कभी-कभी, हमेशा नहीं) हम हिन्दी का व्यवहार करेंगे। लेकिन अपने घर में हमारे मुखपत्र अंग्रेजी में प्रकाशित होंगे, हमारी कार्यकारिणी का अविवेशन होगा तो उसमें विचार-विनिमय अंग्रेजी में होगा, नेताओं का अन्य नेताओं और उपनेताओं से पत्र-व्यवहार अंग्रेजी में होगा।" (पृ० ४१३)

यह आलोचना कांग्रेसी नेताओं पर ही नहीं, कम्युनिस्ट नेताओं पर भी लागू होती है।

स्तालिन, एरुश्चेव और मिर्कोयान की मातृभाषा रूसी नहीं थी। फिर भी सारे देश में राजनीतिक कार्यवाही के प्रसार और संगठन के लिए उन्होंने रूसी भाषा को अपनाया, इस तथ्य का उल्लेख करते हुए मैंने 'भाषा और समाज' में लिखा था, "भारत में हिन्दी का व्यवहार किये बिना कोई अखिल भारतीय नेता नहीं बन सकता।"

(पृ० ४१४)

और भी—“लोग कहते हैं, नेहरू के बाद कोई ऐसा नेता नहीं दिखाई देता जिसकी बात सारा देश ध्यान से सुने। इसका कारण जहाँ हिन्दीभाषी प्रदेश का राजनीतिक पिछड़ा-पन है, वहाँ अहिन्दीभाषी नेताओं द्वारा हिन्दी के प्रति उदासीनता भी है। वे हिन्दी के माध्यम से जन-साधारण में राजनीतिक कार्यवाही का महत्त्व नहीं समझ पाये।”

(पृ० ४१४)

यही उदासीनता का भाव अनेक अहिन्दीभाषी नेताओं में तीव्र उपेक्षा का भाव बन जाता है। इसी उपेक्षा की निन्दा मैंने अपने एक लेख में की थी।

कम्युनिस्ट पार्टी के सामने सबसे बड़ा सवाल श्रमिक जनता की एकता का है। यह एकता अंग्रेजी के माध्यम से दृढ़ नहीं हो सकती। अंग्रेजी की प्रधानता होने से खुद कम्युनिस्ट पार्टी के अन्दर गरीब किसान और मजदूर जिम्मेदारी के पद नहीं संभाल सकते। यह इतिहास का व्यंग्य है कि कुछ समय के लिए केन्द्र में अंग्रेजी कायम रखकर योगीन्द्रजी देश को गृहयुद्ध से बचाना चाहते हैं। लेकिन गृहयुद्ध की-सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई स्वयं कम्युनिस्ट पार्टी के अन्दर। पार्टी बीच से टूटी; उसके दो हिस्से हो गये। इस परिस्थिति के लिए एक हद तक पार्टी के अन्दर वे मध्यवर्गी तत्त्व भी जिम्मेदार हैं जो अपनी अंग्रेजीयत के कारण पार्टी-नेतृत्व का दरवाजा मजदूरों के लिए बन्द किये हैं।

यह परिस्थिति अब बदलनी चाहिए।

कांग्रेस सरकार ने केन्द्र से अंग्रेजी हटाने के लिए पन्द्रह साल की मियाद रखी थी। उसने अपना वायदा तोड़ दिया। कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने अपने केन्द्र से अंग्रेजी हटाने के लिए कोई मियाद न रखी थी। इसलिए उन पर वायदा तोड़ने का आरोप भी नहीं लगाया जा सकता।

नेहरूजी ने कहा—हिन्दी अविकसित भाषा है, पहले उसे विकसित करो। फिर वह राजभाषा बनेगी। पार्टी के नेताओं ने कहा—ठीक। हिन्दी को विकसित होने दो।

दूसरी प्रादेशिक भाषाएँ हैं, उनसे विकास पर भी रुपये खर्च होने दो। नेहरूजी ने कहा—अहिन्दी-भाषी नहीं चाहते कि अंग्रेजी हटाई जाय। पार्टी के नेताओं ने कहा—ठीक। चारा ही क्या है ? फिलहाल केन्द्र में अंग्रेजी ही चले !

कांग्रेस कार्यमिति ने प्रस्ताव पाम किया कि पब्लिश मविस् कमिशन की परीक्षाओं के लिए प्रादेशिक भाषाओं का व्यवहार भी हो सकता है। पार्टी के नेताओं ने कहा—बहुत अच्छा, यही तो हम भी चाहते थे।

इन अखिल भारतीय सभाओं में अंग्रेजी का व्यवहार अनिवार्य होगा—इस बारे में वे चुप रहे। अपने विद्यते लोग में इस प्रश्नाव की चर्चियाँ देन हुए मोतीलालजी ने अंग्रेजी का नाम ही नहीं लिया, मानो अंग्रेजी में उसका कोई सम्बन्ध ही न हो।

हमें माँग करना चाहिए कि हर स्वाधीन देश की तरह भारत के शिक्षात्म में भी अंग्रेजी की पड़ाई बैकलिफ हो। हमें माँग करना चाहिए कि सरकार केन्द्र और राज्यों से अंग्रेजी हटाने की अवधि निर्दिष्ट कर। हिन्दी को अभी और समृद्ध करने, प्रादेशिक भाषाओं को समृद्ध करने के बाद अंग्रेजी हटाने के कांग्रेसी पान्थ का सौत्र खण्डन करना चाहिए। यह न करने योगीन्द्रजी उसका समर्थन करते हैं। उनकी स्वतन्त्र नीति केवल इस बात में प्रकट होती है कि वे इस एतल प्रस्ताव को यही-सही अमल में लाने पर जोर देंगे।

पार्टी-केन्द्र से अंग्रेजी हटाने का मवाल अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इस सवाल के जवाब से ही मानूम हागा कि जातिकारी सफाई और जातिनारी अमल में क्या फर्क है।

## लेनिन की सोल—फिलहाल अंग्रेजी

लेनिनवाद के अनेक भाष्य, अनेक व्याख्याएँ समार में प्रचलित हैं। स्तालिन ने जो कुछ किया लेनिनवाद के नाम पर। झुइचेव ने उनकी कन्नगोदी—लेनिनवादी नीति की रक्षा के नाम पर। ब्रेझ्नेव और कोसीगन ने झुइचेव की हटाया—लेनिनवाद को ही अमल में लाने के लिए। पेरिंग के नेता सोवियन संघ की अमरीकी साम्राज्यवाद का समर्थक कहते हैं—महान् जातिकारी लेनिन की विरासत की रक्षा करने के नाम पर। इसलिए यदि कोई भारत में कह कि लेनिन की यह सोल है कि फिलहाल केन्द्र में अंग्रेजी कायम रहे तो हमसे आश्चर्य की कोई बात नहीं है।

जाराहाही हम के अभिजात वर्ग में फ्रांसीसी भाषा का बहुत व्यवहार होता था। यूरोप की अन्तर्राष्ट्रीय भाषा फ्रांसीसी थी। लेनिन ने यह नहीं कहा कि लोग केन्द्र में इसी भाषा नहीं चाहते, इसलिए फिलहाल वही फ्रांसीसी भाषा चलने दो जाय।

लेनिन का समाधान यह था कि किसी भी भाषा को अनिवार्य केन्द्रीय राजभाषा का पद न दिया जाय। इस समाधान को यदि भारत में लागू किया जाय तो अंग्रेजी को हटाकर उसकी जगह सभी प्रादेशिक भाषाओं को बराबरी की जगह देनी होगी।

योगीन्द्रजी इस बात की कल्पना ही नहीं करते कि केन्द्रीय राजभाषा के बिना भी काम चल सकता है। इसीलिए उन्होंने मेरे वारे में लिखा है, “किसी भाषा के जोर-जबर्दस्ती लादे जाने के वे ऐसे कट्टर विरोधी थे कि उस समय वे क्रान्ती राज्यभाषा के सिद्धान्त का ही विरोध करते थे...वे १९५०-५५ में भाषा के सवाल पर अराजकतावादी छोर पर थे...”

केन्द्र में अनेक राजभाषाएँ चलाने का सिद्धान्त अराजकतावादी नहीं है। लेनिन ने समाजवादी क्रान्ति के बाद न तो रूसी को केन्द्रीय राजभाषा बनाया, न और किसी भाषा को। यह अराजकतावाद नहीं था।

यदि भारत के लिए हम कहें कि केन्द्रीय राजकर्मचारियों को समस्त प्रादेशिक भाषाएँ सीखनी होंगी तो यह अराजकतावादी बात होगी। किन्तु केन्द्र में सभी भारतीय भाषाओं को समानता के अधिकार देने के और भी उपाय है। इनमें मुख्य उपाय है अनुवाद की व्यवस्था का।

४ जुलाई के ‘जनयुग’ में श्री मामूम रज़ा राही ने यह प्रस्ताव रखा है, “केन्द्रीय सरकार के पास एक अनुवाद-विभाग हो। अन्य प्रान्तों से होनेवाले पत्र-व्यवहार की भाषा तो हिन्दी हो जाय और प्रान्तीय सरकारों की भाषा उस समय तक उस क्षेत्र की भाषा बनी रहे जब तक कि वह क्षेत्र हिन्दी को स्वीकार न कर ले।”

यदि कम्युनिस्ट पार्टी के नेता एक बार यह तय कर लें कि अंग्रेजी की जगह केन्द्र में भारतीय भाषाएँ चलानी हैं तो अनुवाद की समुचित व्यवस्था क्या हो, वे यह तय कर लेंगे। केन्द्र में सभी भाषाओं को बराबरी का दर्जा देने से वे शक-शुबह बहुत जल्दी दूर हो जाएँगे जिनके मारे योगीन्द्रजी परेशान हैं। अभी उनके पास कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिससे हिन्दी भाषा को केन्द्र में चालू करने की ‘स्वेच्छा’ अहिन्दीभाषी नेताओं में उत्पन्न हो। मेरा प्रस्ताव उस ‘स्वेच्छा’ को उत्पन्न करने में सहायक होगा।

केन्द्र में अनेक भाषाओं के चलन का सिद्धान्त बीजरूप में कांग्रेस ने स्वीकार किया है। उसने केन्द्रीय सेवाओं की परीक्षाओं के लिए प्रादेशिक भाषाओं को माध्यम रूप में मान्यता दी है। योगीन्द्रजी कांग्रेस के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। बीजरूप में अनेक राजभाषाओं के चलन की बात वह भी मानते हैं। इसलिए अंग्रेजी को हटाकर प्रादेशिक भाषाओं को केन्द्र में जगह देने की बात उन्हें अमान्य न होनी चाहिए।

इस समय अनेक दलों के नेताओं ने यह प्रचार कर रखा है कि केन्द्र से अंग्रेजी हटाते ही गृहयुद्ध छिड़ जायगा। इनमें कुछ लोग कहते हैं, अंग्रेजी अनन्त काल तक रहनी चाहिए। दूसरे कहते हैं, अनन्त काल तक नहीं, अनिश्चित काल तक रहनी चाहिए यानी तब तक जब तक अहिन्दीभाषी लोग हिन्दी को स्वीकार न कर लें।

आन्ध्र के मन्त्री श्री अलपति वेंकटरामैया ने कहा है कि “हिन्दी को अंग्रेजी की जगह लेने में पचास साल लगेंगे।” (नार्दन इंडिया पत्रिका, १६ फरवरी, '६५)

ये औरों से फिर अच्छे हैं। पचास साल की निश्चित अवधि की बात तो करते हैं।

अनिश्चित बान बाना का राम ही मालिक है !

जनतांत्रिक समाधान एसा होना चाहिए जो हिन्दीभाषियों को भी स्वीकार हो। कुछ लोगों का हिन्दी पसन्द नहीं है औरों को अप्रेञ्ची पसन्द नहीं है। हिन्दी-अप्रेञ्ची के इस संघर्ष में सन्नितवाद का फैसला अप्रेञ्ची के पक्ष में होना चाहिए। फैसला होना चाहिए भारतीय भाषाओं के पक्ष में।

योगेन्द्र शर्माजी की निगाह गृहयुद्ध की सम्भावना के एक पक्ष पर है। वह यह कि हिन्दी का राजभाषा बनाने में अहिन्दी भाषी विद्रोह कर देंगे। उन्होंने गृहयुद्ध की सम्भावना के दूसरे पक्ष पर विचार नहीं किया। हिन्दी-भाषियों की इच्छा के विरुद्ध केन्द्र में अप्रेञ्ची चलता रहना ज़रूरी है। वे भी अप्रेञ्ची के चलन के विरुद्ध विद्रोह कर सकते हैं।

स्थिति यह है कि अप्रेञ्ची के प्रमुख के कारण दक्षिण में द्रविड कपगम और उत्तर में जनसम शक्तिशाली होना जा रहा है। इनके शक्तिशाली होने के कारण असम-असम हैं लेकिन भाषा-समस्या से उनका गहरा सम्बन्ध है। यदि केन्द्र में तमिल को हिन्दी के बराबर जगह दी जाय तो द्रविड कपगम का तमिल-प्रेम का मण्डा उठाने का मौका न मिले।

कांग्रेसी और कम्युनिस्ट बना जितने दिन केन्द्र में अप्रेञ्ची चालू रखने की नीति का समर्थन करते हैं, उतने ही दिन के द्रविड कपगम और जनसम का भाषा विवाद से फायदा उठाकर शक्तिशाली बनने का मौका देने हैं। जनता में इन प्रतिक्रियावादी इत्तों के प्रभाव का खतम करने का एक अच्छा उपाय है, केन्द्र में अप्रेञ्ची की जगह प्रादेशिक भाषाओं का व्यवहार।

यह अस्थायी समाधान है। जब तक अहिन्दीभाषी नेता केन्द्र में हिन्दी का चलन स्वीकार न करें, तब तक यह समाधान लागू करना चाहिए।

### तर्क पद्धति और निष्कर्ष

मैं समझता हूँ कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य जनवादी पार्टियाँ मिलकर प्रयत्न करें तो अगले पाँच वर्षों में वे हिन्दी को केन्द्रीय राजभाषा बना सकती हैं। द्रविड कपगम और स्वतंत्र पार्टी इतनी समर्थ नहीं हैं जितनी वे मान्य होती हैं। उन्होंने जनता के मान्यभाषा-प्रेम से लाभ उठाकर उसे बरगलाया है। यदि उस जनता को बताया जाय कि केन्द्रीय सेवाओं के लिए अहिन्दी-भाषियों को हिन्दी सीखनी होगी और हिन्दीभाषी अफसरों को वैसे ही एक अहिन्दीभाषा का ज्ञान प्राप्त करना होगा, तो जनता के गुमराह अंशों को राह पर लाया जा सकता है।

लेकिन केन्द्रीय सेवाओं के हिन्दी-भाषी उम्मीदवार एक अहिन्दी भाषा का ज्ञान प्राप्त करें—मेरे इस प्रस्ताव पर योगीन्द्रजी ने ध्यान ही नहीं दिया, उस पर एक सन्देह भी नहीं कहा। तब कांग्रेसी नेताओं से मैं क्या आशा करूँ ?

इसलिए मैंने अपने लेख में यह विवरण रखा है कि केन्द्र में हिन्दी के साथ अन्य

भाषाओं का व्यवहार भी हो। इससे पहले भी मैंने 'जनशक्ति' में लिखा था, "समस्या का एक ही हल है : केन्द्र में हिन्दी हो, राज्यों में प्रादेशिक भाषाएँ। इस पर भी यदि कोई कहे कि अंग्रेजी हटाने से अहिन्दी भाषाओं का दमन हुआ तो निवेदन है, लोकसभा में सभी भाषाएँ चलाईए। हमें इस बात का मोह नहीं है कि भारत सरकार का काम हिन्दी में हो। यृष्णा इस बात से है कि उसका काम अंग्रेजी में होता है। केन्द्र में चाहे एक भारतीय भाषा चलाईए, चाहे दस, विदेशी भाषा अंग्रेजी को निकालिए।"

लोकसभा के लिए मैंने विशेष रूप से लिखा था, "लोकसभा में अहिन्दी-भाषी नेता शोक से अपनी-अपनी भाषाएँ बोलें। हिन्दी-भाषी नेता हिन्दी में बोलें। कम्युनिस्ट सदस्य अपने व्यवहार से इस नीति की मिसाल कायम करें।"

मेरे यह सब लिखने पर भी योगीन्द्र शर्माजी ने बड़े आग्रह से यही सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि मैं अहिन्दी भाषाओं को दबाना और केन्द्र में जबरदस्ती हिन्दी चलाना चाहता हूँ।

उन्होंने १४ मार्च के 'धर्मयुग' में प्रकाशित मेरे लेख का दो बार हवाला दिया है। यह लेख उन्हें विशेष उपयोगी जान पड़ता है; उसमें गृहयुद्ध की ललकार उन्हें ज्यादा स्पष्ट सुनाई पड़ती है।

मैंने लिखा था, "यह संघर्ष हिन्दी-तमिल का नहीं है, अंग्रेजी और समस्त भारतीय भाषाओं का है। हिन्दी-तमिल-विरोध के बड़े घातक परिणाम हो सकते हैं। एक बार गृहयुद्ध की आग भड़कने पर उसे रोकना असम्भव हो जाएगा।"

गृहयुद्ध की ललकार का इससे अधिक पुष्ट प्रमाण और क्या होगा ?

मैंने लिखा था, "भारतीय भाषाओं को उनके उचित अधिकार दिलाने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले हिन्दी-भाषी प्रदेश में अंग्रेजी को राजभाषा और सांस्कृतिक भाषा के पद से हटा दिया जाय।"

योगीन्द्रजी का विचार है कि मैं भारतीय भाषाओं के अधिकारों को कुचलकर हिन्दी को राजभाषा बनाने के पक्ष में हूँ !

मैंने लिखा था, "इसके बाद जिस दिन हिन्दीभाषी जनता संगठित होकर अपने लोकसभा के प्रतिनिधियों को हिन्दी में बोलने और सारा राजकाज हिन्दी में करने के लिए बाध्य करेगी, उस दिन अंग्रेजी का साम्राज्यवाद खत्म होगा, उस दिन तमिलनाडु तमिल भी अपना पूर्ण स्वत्व प्राप्त करेगी और राष्ट्रीय एकता को दृढ़ करने में हिन्दी-भाषी जनता अपनी भूमिका पूरी करेगी।"

यह वाक्य उन्होंने उद्धृत किया है लेकिन उसका वह टुकड़ा निकालकर जिसमें मूल के पूर्ण स्वत्व प्राप्त करने की बात है। कारण स्पष्ट है। पूरा वाक्य उद्धृत करने से ऊपर तमिल-दमन का आरोप लगाने में असुविधा होती।

वह अंश निकाल देने पर भी गृहयुद्ध की ललकार का आरोप लगाना सरल नहीं

था । इसपर उद्देश्य 'लेकिन यदि' का सहारा लिया—“लेकिन यदि यही बात पूरा देश में लिए कही जाय तो ” इस तरह 'लेकिन यदि' लगाकर किसी भी वाक्य में कोई भी नतीजा निकाला जा सकता है ।

योनि-प्रज्ञी ने मूढ पर यह आरोप लगाया है कि अजय धोप के लेख में मैंने वे मानें छाड़ दी हैं जो मेरी नीतियों के विरुद्ध हैं। ये कौन-सी बातें हैं ? अजय धोप के लेख से उन्होंने जो अंश उद्धृत किया है उसमें कहा गया है भाषा-आयोग के सदस्य प्रादेशिक भाषाओं को एक जनिताप के रूप में देखते हैं। वे नहीं मानते कि भाषा वह माषी दस है। उन्होंने जनतन्त्र के इस प्रारम्भिक सिद्धान्त को विचार में बाहर रखा है कि शासन, विधि-याय की भाषा, प्रत्येक क्षेत्र में सभी स्तरों पर वह भाषा होनी चाहिए जिसका जनता आम तौर पर बोलती और समझती है।

योगीश्वरी का विश्वास है कि मैं अत्रय धोप की उपयुक्त नीति का विरोधी हूँ।  
मानी प्रदत्ता में वहाँ की भाषाओं के बदले हिन्दी का ही चलन करना चाहता हूँ।

‘जनगणित’ में मैंने लिखा था—

(क) "भारत में भाषावार राज्य बनाने का आदोष <sup>हटा</sup> जाता है। हर प्रदेश में उसकी शिक्षा और संस्कृति का विकास उसकी भाषा के माध्यम से हो, यह मांग सही थी।"

(ख) "जिस तरह हर प्रदेश में उसी अपनी भाषा का सभी अधिकार मिलने चाहिए, वैसे ही इन सबको आनेवाली राष्ट्रभाषा हिन्दी को भी केन्द्र में पूर्ण अधिकार मिलने चाहिए।"

(ग) "इस पर भी यदि कोई कह कि अंग्रेजी हठाने से अहिन्दी भाषा का दमन होता है तो निवेदन है, लोकनभा में सभी भाषाएँ बराबर।"

अजय घोष ने अहिंसी नापाका को केवल प्रदेशों में पूर्ण अधिकार देने का वादा नहीं की। मैं उन्हें केन्द्र में हिंसी के बराबर स्थान देने की बात कहता हूँ। लेकिन विरोधी आन्दोलकों का मुझ वन्द करने के लिए योगीन्द्र शर्माजी ने सीधी रणनीति निकाली है। उन पर जन्म हिन्दी राष्ट्रवाद का आरोप लगा दो, केन्द्र में पिलहाल अंग्रेजी चलान की नीति अपने-आप सही साबित हो जाएगी।

मैंने लिखा था, “जपेडी कायम रखने के लिए जो विनाश सयुक्त मोर्चा बना है, उसमें स्वतंत्र दल व नेता हैं, इविड कपयम वाले हैं। ‘काप्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी’ के अनेक नेता भी इसमें हैं।” योगी इन्हीं ने अनेक का अर्थ किया सम्पूर्ण और माराज होकर लिखा, “इन्हीं की पक्ष में सम्पूर्ण काप्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी को खड़ा कर देना भारतीय राष्ट्रीयता और अखिल का बलिदान करना है मर्यादा के मुद्दे पर समाज का भारना है।”

१७ फरवरी, '६२ को पी० टी० वाई० द्वारा नई दिल्ली से प्रसारित समाचार के

अनुसार ३४ संसद-सदस्यों ने एक वयान जारी किया जिसमें कहा गया था कि संविधान की वह धारा बदल देनी चाहिए जिसमें हिन्दी को राजभाषा घोषित किया गया है। पी० टी० आई० के अनुसार इन संसद-सदस्यों में कम्युनिस्ट पार्टी, द्रविड़ कपगम, स्वतन्त्र पार्टी, आर० एस० पी० तथा मुस्लिम लीग के नेता थे।

योगीन्द्र शर्माजी विचार करें, भारतीय राष्ट्रीयता और जनतन्त्र को कौन कलंकित करता है, सच्चाई के मुँह पर तमाचा कौन मारता है।

मैंने कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं की भाषा-नीति की आलोचना की थी। इसे उन्होंने 'हिन्दी भाषा और भारत देश को शाप' देना कहा है।

गद्य में अतिशयोक्ति अलंकार उन्हें बहुत प्रिय है और उसके व्यवहार पर वह कोई भी प्रतिबन्ध लगाना अनुचित समझते हैं।

'भाषा और समाज' से लम्बा उद्धरण देकर उन्होंने यह नतीजा निकाला है कि पहले मैं पंडिताऊ हिन्दी का विरोधी था, अब उसका समर्थक हो गया हूँ। अपनी रणनीति के अनुसार मेरी पुस्तक के वे अंश उन्होंने छोड़ दिए हैं जहाँ मैंने सुगढ़ पारिभाषिक शब्दों के निर्माण की प्रशंसा की थी। मैंने लिखा था—

“लेकिन पारिभाषिक शब्दावली में ऐसे भी बहुत से शब्द हैं जो बोलने में हिन्दी प्रवृत्ति का उल्लंघन नहीं करते और जिनके लिए विश्वास से कहा जा सकता है कि वे अवश्य लोकप्रिय होंगे। केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित कृषि-सम्बन्धी शब्दावली से हम कुछ शब्द ले सकते हैं।” (पृ० ४३३)

खास बात यह है कि मैंने उन लोगों का विरोध किया था जो पारिभाषिक शब्दावली को असन्तोषजनक बताकर केन्द्र में अंग्रेजी चलाते रहने का समर्थन करते थे। मैंने लिखा था—

“हिन्दी में काफ़ी पारिभाषिक शब्दों का निर्माण हो चुका है। इनमें बहुत से अपने-अपने विषय की हिन्दी पुस्तकों में व्यवहृत भी होते हैं। जहाँ तक राजकाज का सम्बन्ध है, इस विषय के शब्दों का निर्माण विज्ञान की शब्दावली बनाने से आसान है। इसलिए विज्ञान में चाहे हिन्दी का प्रयोग कुछ दिन रुका भी रहे, राजभाषा के रूप में हिन्दी का व्यवहार रुके, इसका कोई कारण नहीं है।” (पृ० ४३३)

योगीन्द्रजी ने इससे उलटा निष्कर्ष निकाला है।

इस तरह की तर्क-पद्धति वे अपनाते हैं जो हठधर्मी से गलत नीति को भी सही साबित करने के लिए कमर कस लेते हैं। इस तरह विरोधी आलोचकों की बातों को तोड़-मरोड़कर पेश करने से जनवादी तत्त्वों में एकता स्थापित नहीं की जा सकती।

योगीन्द्रजी ने अन्ध-राष्ट्रवाद की बात बहुत बार की है। वह 'भाषा और समाज' के इस वाक्य पर भी गौर करें—

“वर्तमान अन्ध-राष्ट्रवाद की विशेषता यह है कि यह दूसरी भारतीय भाषाओं के



प्रति घृणा फैलाता है और अंग्रेजी को गले लगाता है।" (पृ० ४२५)

मैं चाहता हूँ कि पार्सी के नेताओं में हिन्दी के प्रति जो उपेक्षा-भाव है, वह खत्म हो। वे अपने सिद्धान्त और व्यवहार में एकता स्थापित करें। शासन-केन्द्र में चाहे एक भाषा चलाएँ चाहे अनेक, निश्चित अवधि में अंग्रेजी का चलन बन्द हो—यह माँग करें। अंग्रेजी को अनिश्चित काल के लिए भारत की राजभाषा बनाकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चे का निर्माण नहीं हो सकता।

(१९६५)

## देश का विघटन और अंग्रेजी

एक ज़माना था जब लोग समझते थे कि अंग्रेजी सभी भारतीय भाषाओं पर साम्राज्यवादियों द्वारा लादी हुई भाषा है। राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान किमी भी देशभक्त को इस बारे में गक नहीं था कि अंग्रेजी की गुलामी अंग्रेजों की ही गुलामी का एक अंग है। उस समय राष्ट्रीय नेता मानते थे कि अंग्रेजी का प्रभुत्व राष्ट्र के लिए अपमानजनक है। वे जानते थे कि अंग्रेजी शिक्षा के कारण देश की शक्ति और धन का अपार अपव्यय होता है। वे कहते थे कि देश पर मुट्ठी-भर अंग्रेजी-पढ़े हुकूमत करे, यह जनतन्त्र का मज़ाक है। उस ज़माने में राष्ट्र के नेता भाषा की समस्या पर आम जनता के दृष्टिकोण से विचार करते थे। वे घोषित करते थे कि राष्ट्रीय एकता का अर्थ है भारत के करोड़ों श्रमिक जनों की एकता। यह एकता हिन्दी और केवल हिन्दी के द्वारा कायम हो सकती है।

स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद वे बातें अब पुरानी हो गईं। जो अंग्रेजी की हिमायत करता है, वह उदार और प्रगतिशील माना जाता है। जो अंग्रेजी हटाने की बात करता है, वह पुराणपन्थी और हिन्दी-उन्मादी कहलाता है। राष्ट्रीय एकता के लिए सबसे आवश्यक है अंग्रेजी ! अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क के लिए एकमात्र विश्वभाषा है अंग्रेजी ! ज्ञान-विज्ञान के लिए अनिवार्य माध्यम है अंग्रेजी !

अब राष्ट्रीय एकता का अर्थ जन-साधारण की एकता नहीं है। राष्ट्रीय एकता का अर्थ है अंग्रेजी-पढ़े नेताओं और नौकरशाहों की एकता। अब राष्ट्रीय एकता का प्रश्न जुड़ा हुआ है अखिल भारतीय नौकरियों के साथ।

तमिलनाडु में इतना उत्पात हुआ, तमिल की रक्षा के लिए ? नहीं; लोगों को भय दिखाया गया कि सरकारी नौकरियाँ हथिया लेंगे हिन्दीवाले, दक्षिणवाले टापते रह जाएंगे। हिन्दी के अत्याचार से बचने के लिए कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि हर राज्य के लिए नौकरियों का 'कोटा' निश्चित कर दिया जाय।

पिछले छः महीने से यह नौकरियों का सवाल अंग्रेजी-पढ़े वावुओं के सामने है। उनके लिए यह सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समस्या है। अंग्रेजी-पढ़ा नौकरशाह वर्ग आम जनता से कितनी दूर है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि इस समुदाय के सामने भाषा-समस्या का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है—नौकरी !

देश की राष्ट्रीय समस्या कांग्रेस के नेता भाषा-समस्या पर विचार करते हैं तो उनके सामने मुख्य प्रश्न होता है अखिल भारतीय नौकरियों की परीक्षाएँ कितनी भाषाओं में होगी ?

यह मानते हुए कि अपनी जगह नौकरियों की समस्या का भी महत्व है, हमें राष्ट्रीय एकता के प्रश्न को सरकारी नौकरियों के दायरे में बंद कर देना चाहिए। विभिन्न प्रदेशों की श्रमिक जनता की एकता किस तरह कायम की जाय, शासन-तंत्र में आम जनता किस तरह भाग ले, राज्यसत्ता कुछ ऊपरवाले निहित स्वार्थों के हाथ में बँधनुंती बनकर न रहे जाय—भाषा की समस्या पर विचार करते हुए इन प्रश्नों को हमें सामने रखना चाहिए।

कांग्रेस कार्यसमिति ने फैसला किया है कि अखिल भारतीय नौकरियों की परीक्षाएँ अंग्रेजी, हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में होंगी। कुछ वर्षों अंग्रेजी और हिन्दी में अनिवार्य होंगे। जिन उम्मीदवारों की भाषा हिन्दी होगी, उनके लिए एक पर्वी क्विज़ अहिन्दी भाषा में होगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक राज्य की भाषा, शासन और शिक्षा का माध्यम बनेगी। हिन्दी-शिक्षण के स्तर को ऊँचा किया जाएगा। "अंग्रेजी ऐसी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती रहेगी, जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।" तीन भाषाएँ सीखने की नीति दृढ़ता से लागू की जाएगी। हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं का विकास किया जाएगा।

जिन लोगों ने कांग्रेस कार्यसमिति के फैसले का स्वागत किया है, उनका विचार है कि अब अंग्रेजी की जगह प्रादेशिक भाषाओं का चलन हो जाएगा।

इस आशा का आधार क्या है ?

प्रादेशिक भाषाएँ केवल परीक्षाओं का माध्यम बनेंगी, केन्द्रीय राजकाज का माध्यम नहीं। राजकाज होगा अंग्रेजी में। अखिल भारतीय सेवाओं में यह तो होगा नहीं कि परीक्षा में जिसका माध्यम तमिल है, उसे नौकरी तमिलनाडु में ही करनी होगी। अखिल भारतीय नौकरियों का मतलब ही यह है कि किसी भी अफसर को एक राज्य में दूसरे राज्य में भेजा जा सकता है। तब यह विभिन्न प्रदेशों का कार्य किस भाषा में होगा ? क्या तमिलभाषी अफसर दिल्ली में अपना दफ्तर तमिल में चलाएगा ? या बंगलाभाषी अफसर मद्रास में अपना काम बँगला में करेगा ?

स्पष्ट है कि अखिल भारतीय नौकरियों का माध्यम अंग्रेजी ही रहेगी।

कांग्रेस कार्यसमिति ने यह फैसला नहीं किया कि केन्द्रीय सरकारी नौकरियों में अंग्रेजी की जगह प्रादेशिक भाषाओं का व्यवहार होगा। फैसला यह किया है कि परीक्षाओं में अंग्रेजी के साथ प्रादेशिक भाषाएँ भी माध्यम बन सकती हैं।

इसलिए यह आशा लगाना व्यर्थ है कि केन्द्रीय राजकाज में अंग्रेजी की जगह प्रादेशिक भाषाओं का व्यवहार होने लगेगा, या अंग्रेजी के साथ उन्हें चही बालिस्त-भर जगह भी मिल जाएगी।

परीक्षाओं के लिए भी प्रादेशिक भाषाओं को अनिवार्य माध्यम नहीं बनाया गया। माध्यम बनने के लिए उन्हें विकसित होना है, अपने प्रदेश में राजभाषा बनना है, विश्वविद्यालयों में उच्चतम शिक्षा का माध्यम बनना है। बनने-बनाने का यह सारा क्रम कब समाप्त होगा, इसकी कोई अवधि निश्चित नहीं की गई।

भारत सरकार पन्द्रह साल से हिन्दी के विकास में लगी है, लेकिन अभी कही उस विकास का छोर नहीं दिखाई देता। बड़े-बड़े कोश बन जाने के बाद भी कार्यसमिति के प्रस्ताव में हिन्दी को अभी और विकसित करने की बात कही गई है।

यह अद्भुत राष्ट्रभाषा-प्रेम है ! हिन्दी के विकास से वह कभी सन्तुष्ट नहीं होता ! विकास के अपूर्ण होने से वह अंग्रेजी को ही राष्ट्रभाषा बनाए रहता है !

प्रादेशिक भाषाओं के प्रेमी समझ ले, उन्हें अपनी भाषाओं के विकास के लिए कितनी लम्बी प्रतीक्षा करनी होगी।

प्रादेशिक भाषाओं को पन्द्रह साल से यह अधिकार प्राप्त है कि वे उच्च शिक्षा का माध्यम बनें, प्रदेशों की राजभाषा बनें। लेकिन इस अधिकार का उपयोग क्यों नहीं हुआ ? कांग्रेस के प्रस्ताव में कही इस बात की कौफियत नहीं दी गई कि, हर राज्य में शासन की बागडोर कांग्रेस के हाथ में होने पर भी, उस अधिकार का पूरी तरह उपयोग क्यों नहीं किया गया।

जिस अधिकार का उपयोग पन्द्रह साल में नहीं हुआ, इस प्रस्ताव के बाद उसका उपयोग होगा ही, इसका क्या प्रमाण है ? इसके विपरीत उसका उपयोग आगे भी न होगा, इसका प्रमाण है।

केन्द्र में जब तक अंग्रेजी का बोलवाला रहेगा, तब तक राज्यों में प्रादेशिक भाषाओं को पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। अंग्रेजी-पढ़ा उम्मीदवार पहले अखिल भारतीय अफसर बनने की कोशिश करता है। इस कोशिश में असफल होता है तब प्रादेशिक अफसर बनने का प्रयत्न करता है। यहाँ भी नाकामयाब रहा तो मास्टरी या क्लर्की करता है। स्थिति यह है कि रेल, बैंक, डाक, तार, फौज, पुलिस, प्राइवेट फर्म—कहीं भी मामूली क्लर्की अंग्रेजी के बिना नहीं मिलती। लाखों नौजवान हर साल फेल होते हैं, अंग्रेजी की वजह से। देश में शिक्षा बेहद महँगी है, अंग्रेजी के कारण।

इसलिए जो लोग धन और श्रम-शक्ति के इस अपव्यय को बन्द करना चाहते हैं, जो राज्यों में प्रादेशिक भाषाओं को उनके पूर्ण अधिकार दिलाना चाहते हैं उनके सामने एक ही कर्तव्य हो सकता है—केन्द्र में अंग्रेजी के प्रभुत्व को खत्म करना।

जो लोग सोचते हैं कि केन्द्र में अंग्रेजी के हटने से नौकरियाँ हिन्दीवालों के ज्यादा मिल जाएँगी, उनका भय दूर करना कठिन नहीं है। हिन्दीभाषी उम्मीदवारों के लिए एक आधुनिक अहिन्दी भाषा का ज्ञान अनिवार्य कर देना चाहिए। कांग्रेस कार्यसमिति के प्रस्ताव में यह नियम शामिल किया गया है कि हिन्दी-भाषियों के लिए एक पर्चा अहिन्दी भाषा का होगा। देश की भावात्मक एकता के लिए मुख्य जोर आधुनिक

प्रादेशिक भाषाएँ सीखने पर होना चाहिए ।

किन्तु कांग्रेस के तीन भाषा वाले मूच में मुख्य जोर है अंग्रेजी पर । इसीलिए उस मूच को अमल में लाना कठिन होता है । वह झिल तरह अमल में लाना गया है, उसने किसी को मन्ताप नहीं है । मन्तोष इसलिए नहीं है कि अमल में लानेवालों की निगाह अंग्रेजी पर पड़ने है हिन्दी और भारतीय भाषाओं पर बाद की ।

श्री सादिक जली बादेस के जाने-माने नेता हैं । कांग्रेस के सगठन-काय से उनका विंगोप सम्बन्ध रहा है । उन्होंने कायमामिनि के प्रस्ताव की व्याख्या करने हुए ७ जून के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में एक लेख लिखा है । उनमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि तीन भाषाओं वाला फामूला लागू करने से अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार और भी अधिक होगा ।

निरा है "सन्देहवादी लोग कह सकते हैं कि तीन भाषाओं वाले फामूले को कारगर तरीके से लागू करने की गुंजाइश कम है । इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता । लेकिन मैं यह जानता हूँ कि तीन भाषाओं वाले फामूले में अंग्रेजी वाला हिस्सा कारगर तरीके से उबर लागू किया जाएगा ।"

अंग्रेजी, और अधिक अंग्रेजी—यह है हमारे राष्ट्रीय नेताओं का दृष्टिकोण ।

श्री सादिक जली का विचार है, 'यह अच्छी बात है कि हमारे विद्यालयों में अंग्रेजी जानने की व्यापक इच्छा है ।'

ऐसा है तो अंग्रेजी बैकल्पिक कर दीजिए । फिर देखिए, कितने लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं । आगरा विश्वविद्यालय ने जब से बी० ए०-सी० की परीक्षाओं में अंग्रेजी को बैकल्पिक कर दिया है, तब से लगभग नब्बे की सदी विद्यालयों ने 'अनरल इनिश' की परीक्षा देना बन्द कर दिया है ।

श्री सादिक जली का मत है, 'सही दृष्टिकोण यह है कि अंग्रेजी को उसका न्यायोचित स्थान (राइटफुट प्लेस) दिया जाए जिसने देश की सम्मिलित इच्छा शक्ति के सहारे बढ़ बने-फूले । इस तरह उनके सामने ज्यादा सुन्दर, ज्यादा महान, ज्यादा रचनात्मक भविष्य होगा ।"

न्यायोचित स्थान देना है अंग्रेजी को ! रचनात्मक भविष्य है अंग्रेजी का ! देश की सम्मिलित इच्छाशक्ति सहारा देने अंग्रेजी को ।

शासक वर्ग अपनी भाषा-नीति किस उद्देश्य से निर्धारित कर रहा है यह श्री सादिक जली के वक्तव्य में स्पष्ट हो जाता है ।

सार्वभौम सत्ता होगी अंग्रेजी की । प्रादेशिक भाषाएँ होगी उसकी दानियाँ ।

उद्देश्य और इच्छाओं के प्रभाव हिन्दी-अहिन्दीभाषी राज्यों की यह अधिकार प्राप्त है कि जब तक उनके विधान-सभा, लोक-सभा तथा राज्य-सभा में प्रतिनिधि अपनी मांगी बहुमत से अंग्रेजी हटाने का प्रस्ताव पास न करें तब तक—माती अनिश्चित काल के लिए—अंग्रेजी ही भारत की राष्ट्रभाषा रहेगी ।

इस पर भी कुछ लोगों को यह दुःख्य होना है कि कांग्रेस के प्रभाव से हिन्दी

साम्राज्यवाद के लिए रास्ता साफ हो गया है। यदि लोकसभा यह प्रस्ताव पास कर दे कि भारत में सदा-सर्वदा के लिए अंग्रेजी एकमात्र राजभाषा रहेगी, तब भी ये लोग कहेंगे, उत्तरवाले दक्षिणवालों पर राज्य कर रहे हैं। जिन लोगों की नीति है कि हर वहाने 'द्विविद्-भारत' को 'आर्य-भारत' से अलग कर दिया जाय, वे अंग्रेजी के बारे में किसी भी आश्वासन से सन्तुष्ट नहीं हो सकते।

अंग्रेजी की जड़ मजबूती से जमी है। कांग्रेस कार्यसमिति के प्रस्ताव को कानूनी रूप देने से वह और भी पुख्ता हो जाएगी। किसी को यह भय न होना चाहिए कि प्रादेशिक भाषाओं को नये अधिकार मिल गए हैं और अब अंग्रेजी के अभाव में राष्ट्रीय एकता छिन्न-भिन्न हो जाएगी।

यदि अंग्रेजी से राष्ट्रीय एकता दृढ़ होती थी तो भविष्य में वह और भी सुदृढ़ हो जाएगी।

किन्तु क्या सचमुच अंग्रेजी से राष्ट्रीय एकता दृढ़ होती है ?

सन् '४७ में जब एक राष्ट्र से दो राष्ट्र बने, तब अंग्रेजी-पढ़े लोग ही विघटनकारी प्रचार के अगुआ थे। बम्बई में संयुक्त महाराष्ट्र आन्दोलन के दौरान गुजरातियों और मराठी-भाषियों में संघर्ष हुआ। इसके नेता भी अंग्रेजी-पढ़े लोग थे। असमय में बंगालियों और असमियों के बीच दंगे हुए। यहाँ भी भाषा-सम्बन्धी आन्दोलन के नेता थे अंग्रेजी-पढ़े भद्र लोग। तमिलनाडु में जो उत्पात हुआ, उसके सूत्रधार अंग्रेजी-प्रेमी सज्जन थे। कश्मीर में अलगाव के नेता विलायत जाकर अंग्रेजी में भाषण देनेवाले लोग हैं। नागालैण्ड के अलगाव-पन्थी नेता विलायत ही में निवास करते हैं।

अंग्रेजी-पढ़ा वर्ग भारत में विघटन-प्रक्रिया रोकने में असमर्थ है। दिवालिये राजनीतिज्ञ राष्ट्रीय एकता कायम रखने के लिए जितना ही इस समुदाय का भरोसा करते हैं उतना ही विघटनकारी शक्तियाँ प्रबल होती जाती हैं।

राष्ट्रीय एकता को दृढ़ करने का दूसरा तरीका है जन-साधारण का भरोसा करना, मौलाद ढालनेवालों और धन पैदा करनेवालों की एकता के बल पर राष्ट्र को मजबूत करना। इस तरह की स्थायी और अपराजेय एकता हिन्दी से कायम हो सकती है, अंग्रेजी से नहीं।

कांग्रेस कार्यसमिति के प्रस्ताव में इस तरह की एकता पर ध्यान नहीं दिया गया। उसमें भरोसा किया गया है अखिल भारतीय सेवाओं में लगे हुए नौकरशाहों का। प्रस्ताव में एकता का माध्यम हिन्दी नहीं, अंग्रेजी है। अंग्रेजी को हटाने के लिए कोई अवधि निश्चित नहीं की गई। इसलिए इस प्रस्ताव का विरोध ही किया जा सकता है, स्वागत नहीं।

समस्त प्रादेशिक भाषाओं को अंग्रेजी की गुलामी से मुक्त करने के दो उपाय हैं—

(१) केन्द्र में अंग्रेजी की जगह हिन्दी हो, राज्यों में प्रादेशिक भाषाएँ राजभाषा हो;

(२) राज्यों में तो प्रादेशिक भाषाएँ राजभाषा हों हों, केन्द्र में भी अंग्रेजी की जगह उस सबका व्यवहार हो।

पहला उपाय ज्यादा व्यावहारिक है, संविधान के अनुकूल है। अनेक राजनीतिक दल उसका समर्थन भी करते हैं। किन्तु जब प्रश्न उठता है, जब तक अंग्रेजी हटाई जाएगी, तब परिचयन की अवधि अनिश्चित हो जाती है। नेताओं के सामने सीधा-सा बहाना है। अहिंदीभाषी नहीं चाहते कि हिंदी केन्द्रीय राजभाषा हो, इसलिए भ्रमहास अंग्रेजी ही चलेगी।

तेसी स्थिति में अंग्रेजी हटाने के दूसरे उपाय पर भी विचार कर लेना चाहिए। यह उपाय कठिन है, व्यय-साध्य है किन्तु संभव नहीं है। स्विट्जरलैंड में जर्मन, फ्रांसीसी और इतालवी की समान अधिकार प्राप्ति है। हमारे यहाँ भी केन्द्र में सभी भारतीय भाषाओं का चयन हो सकता है।

कांग्रेस के नेता कहते हैं, जब तक अहिंदीभाषी राज्य हिंदी को स्वीकार नहीं करते, तब तक केन्द्र में अंग्रेजी चलेगी।

हिंदीभाषी जनता उनसे कह सकती है जब तक अहिंदीभाषी राज्य हिंदी का स्वीकार नहीं करते, तब तक केन्द्र में सभी भारतीय भाषाओं का व्यवहार होने दीजिए।

यदि देश के नेताओं को प्रादेशिक भाषाओं से सच्चा प्रेम है तो वे केन्द्र में अंग्रेजी की जगह उनका व्यवहार क्या नहीं करते ?

यदि भाषाओं के अविकसित होने का खवाल हो, तो कमीशन बिठाकर इस बात की जाँच कराएँ कि भारतीय भाषाओं के विकास में कौन-सी कमी रह गई है।

जो नेता भारतीय भाषाओं के अविकसित होने से परेशान हैं, उन्हें अपनी गिना के स्तर पर भी ध्यान देना चाहिए।

विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में पारिभाषिक शब्दों से सम्बन्धित कठिनाई हो सकती है। लेकिन यहाँ मवाल राजकाज के लिए भारतीय भाषाओं के व्यवहार का है। क्या लोकसभा में आज तक कोई ऐसा आपण हुआ है जिसके लिए अंग्रेजी ही माध्यम बन सकती थी जिसकी विषयवस्तु प्रकट करने की क्षमता भारतीय भाषाओं में नहीं थी ? क्या इस बात पर विश्वास किया जा सकता है कि जिन भाषाओं में रवीन्द्रनाथ ठाकुर, मुद्राभाष्य भारती, बन्धनान्त, प्रेमचंद आदि ने अपनी महान् साहित्यिक रचनाएँ की हैं, उनमें श्री लालबहादुर शास्त्री, या श्री हीरेन मुखर्जी, या अन्य राजनीतिज्ञ अपना मन्त्र्य प्रकट नहीं कर सकते ?

जमल में बात यह है कि अधिकांश राजनीतिक पार्टियाँ अपने जन्मकाल से अब तक अपना जन्म भारतीय राजनीतिक कार्य-अंग्रेजी में ही करती रही हैं। इनके नेता तरह-तरह के बहाने करते हैं, अपने अनुयायियों को तरह-तरह से बहकाते हैं। वे अपने दफ्तरों में अंग्रेजी निकाल नहीं पाते। अब तब जनता इनके दफ्तरों के सामने प्रदर्शन न करेगी, इनके केन्द्रीय भवनों से अंग्रेजी निकालने के लिए इन पर दबाव न डालेगी, तब तक ये नेता

अपनी नीति से बाज न आएँगे। भारतीय जनतन्त्र के संचालक ये ही लोग हैं। वे अपने पार्टी-कार्यों में अंग्रेजी से चिपके हुए हैं। तब सरकारी दफ्तरों और विश्वविद्यालयों से अंग्रेजी क्या खाकर निकालेंगे ?

इस समय नेता लोग देश में हवा बाँधे हैं कि अंग्रेजी के बिना न राष्ट्रीय काम चल सकता है, न अन्तर्राष्ट्रीय। यह हवा सिर्फ ऊपर-ऊपर है। गरीब जनता का काम तो अंग्रेजी के बिना ही चलता है। ऐसी हालत में जो राजनीतिक पार्टी अपने केन्द्रीय राजकाज में अंग्रेजी का चलन खत्म करती है, वह देश की बहुत बड़ी सेवा करती है। वह लोगों में आत्मनिर्भरता की चेतना दृढ़ करती है। वह अंग्रेजी-प्रेमियों को दिखला देती है कि अंग्रेजी के बिना भी काम चल सकता है।

श्री कामराज नाडार कांग्रेस के अध्यक्ष होते हुए भी तमिल में भाषण करते हैं। इससे देश में विघटन पैदा नहीं हो गया। क्या ही अच्छा हो यदि राष्ट्रसंघ में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के नेता एक बार श्री कामराज हों और वहाँ जाकर तमिल में भाषण करें।

सोवियत संघ के प्रतिनिधि मन्बूल्स्की ने एक बार राष्ट्रसंघ के सामने उक्रेनी में भाषण किया था। तब श्री कामराज वहाँ तमिल में भाषण क्यों नहीं कर सकते ? मित्त के अध्यक्ष श्री नात्तिर राष्ट्रसंघ के सामने अरबी में भाषण कर सकते हैं तो हमारे सम्मान्य प्रधानमन्त्री अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन के सामने हिन्दी में भाषण क्यों नहीं कर सकते ? भारतीय भाषाओं के व्यवहार से अन्तर्राष्ट्रीय भाईचारा कमजोर नहीं होता, वरन् मित्र-देशों में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। पिछले दिनों जब प्रधानमन्त्री सोवियत संघ गए, तब जगह-जगह हिन्दी वाक्यों से सजे हुए वन्दनवारों से उनका स्वागत किया गया। इससे सोवियत-भारत-मैत्री कमजोर नहीं हो गई।

क्या ही अच्छा होता यदि कांग्रेस कार्यसमिति स्वयं अपने लिये एक प्रस्ताव पास करती कि भविष्य में उसका काम अंग्रेजी में न होगा, भारतीय भाषाओं में ही होगा !

भारतीय जनतन्त्र के कर्णधार हमारे सीमित साहित्यिक अनुभव की ओर भी दृष्टिपात कर लें।

भारतीय भाषाओं ने एक-दूसरे को प्रभावित किया है, विभिन्न प्रदेश सांस्कृतिक स्तर पर एक-दूसरे के निकट आए हैं; रवीन्द्रनाथ ठाकुर से लगभग सभी आधुनिक भाषाओं के लेखक न्यूनाधिक प्रभावित हुए हैं, शरत्चन्द्र और प्रेमचन्द की रचनाओं से करोड़ों पाठक परिचित हैं—यह सब अंग्रेजी के कारण सम्भव नहीं हुआ। जो गीत श्रीनगर से कन्या-कुमारी तक—और देश की सीमाएँ पार करके पेशावर से सिंहल तक—गूँजे हैं, वे अंग्रेजी के सम्पर्क-भाषा होने के कारण नहीं।

अंग्रेजी के बिना भी काम चल सकता है। अंग्रेजी के बिना ही काम चलेगा। स्वाधीन भारत में अंग्रेजी नहीं चलेगी।

भारत सरकार लोकसभा में सभी भाषाओं में बोलने और भाषणों के अनुवाद की व्यवस्था करे। लोकसभा, राज्यसभा की कार्यवाही, कानून, मसौदे—सभी भारतीय भाषाओं



में प्रकाशित हो। अन्तिल भारतीय सेवाओं में भारतीय भाषाओं का व्यवहार हो। कांग्रेस की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि इस मारे परिवर्तन का भार उठाये। अहिन्दीभाषी जनता हिन्दी नहीं चाहती, यह कहकर यह अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती।

एक बार लोकमता में जब हमारे प्रतिनिधि भारतीय भाषाओं में बोलेंगे, तब उनका अपेक्षी-माह कम होगा। तब उन्हें बोल होगा कि हिन्दी में अब भाषाओं का दमन नहीं होना, वरन् उससे राष्ट्रीय एकता दृढ़ होगी है। एक बात जब उन्हें विश्वास हो जाएगी कि उनकी भाषा को बड़ी अधिकार प्राप्त है, जो हिन्दी को है, तब वे स्वेच्छा से हिन्दी बोलेंगे। जब तक अपेक्षी अनिवार्य राजभाषा बनी हुई है, तब तक स्वेच्छा से हिन्दी बोलने की बात उनकी समझ में न आती।

जो लोग सचमुच जानते हैं कि अहिन्दीभाषी राजनीतिज्ञ स्वेच्छा से हिन्दी को केन्द्रीय भाषा मानें, वे अब तक जनता के सामने कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं रख सके जिससे इस उद्देश्य की पूर्ति हो। वे समझते हैं कि 'फिरहाब अपेक्षी' कार्यक्रम रखने से अपने-आप अहिन्दीभाषियों में स्वेच्छा उत्पन्न हो जाएगी। पिछले पन्द्रह साल का अनुभव कुछ दूसरा है। अपेक्षी की जड़ें और मजबूत हुई हैं। सिमित्त वों के नामों से स्वेच्छापूर्वक हिन्दी अपनाने की बात दूर चली गई है। इस स्थिति का मूल कारण है अपेक्षी को पाल पामकर मजबूत करने की नीति। अहिन्दीभाषी राजनीतिज्ञों के हिन्दी-विरोध का कारण यह नहीं है कि उन पर जबरदस्ती हिन्दी लादी गई है। हिन्दी विरोध का कारण यह है कि वे 'स्वेच्छा' से अपने ऊपर अपेक्षी नादे रखना चाहते हैं।

इसी समस्या को बदलना है।

सभी भारतीय भाषाओं को केन्द्र में समान अधिकार प्राप्त हो — इस आधार पर अपेक्षी के विरुद्ध सभी सच्चे भारतीय भाषा प्रेमियों की एकता स्थापित की जा सकती है।

राष्ट्र के नेताओं से निवेदन है जब तक अहिन्दीभाषी नेता केन्द्रीय राजभाषा के रूप में हिन्दी को स्वीकार नहीं करते, तब तक सभी भारतीय भाषाओं को केन्द्रीय राजभाषा बनाए रहिए। अपेक्षी हटाने का यह कार्यक्रम जगने पाँच वर्ष में पूरा कीजिए। पूर्व-निश्चित अवधि के पन्द्रह वर्ष पहले ही बीत चुके हैं। पाँच वर्ष की अनिश्चित अवधि काफी है। शिक्षाक्रम में अपेक्षी को वैकल्पिक बनाइए। केन्द्रीय सेवाओं तथा विश्वविद्यालयों में अपेक्षी की अनिवार्यता पाँच साल में खत्म कीजिए।

अपेक्षी की दायता से भारतीय भाषाओं को मुक्त करना हर देशभक्त का पवित्र कर्तव्य है। इस कर्तव्य को पूरा करने राष्ट्र के नेता जनता के श्रद्धाभाजन बनें। इससे विपरीत यदि उन्होंने अपेक्षी को राजभाषा बने रखने दिया तो भावी विघटन के लिए उन्होंने जो जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

(१९६५)

## प्रगतिशील साहित्यकार और भाषा-समस्या के जनतांत्रिक समाधान

प्रगतिशील साहित्यिक आन्दोलन के आरम्भ में उसकी भाषा-सम्बन्धी मान्यताएँ वही थीं जो गांधीजी के नेतृत्व में चलनेवाले राष्ट्रीय आन्दोलन की थी। अंग्रेजी की जगह हिन्दी या हिन्दुस्तानी राष्ट्रभाषा होगी; हिन्दी-उर्दू मूलतः एक ही भाषा हैं और उन्हें मिलाना प्रगतिशील लेखकों का कर्तव्य है, ये मान्यताएँ प्रेमचन्द के भाषणों में थी। उस समय हिन्दी-उर्दू-हिन्दुस्तानी को लेकर जोरदार वहस होती थी। हिन्दी-उर्दू बुनियादी तौर से एक ही भाषा हैं, इस बात को प्रायः सभी लेखक मानते थे। यह मान्यता नयी नहीं थी। बालमुकुन्द गुप्त जैसे लेखक बहुत पहले इस मान्यता को स्पष्ट शब्दों में प्रकट कर चुके थे। वहस इस चीज को लेकर थी कि हिन्दुस्तानी भाषा बन चुकी है या बनाई जाय, उसका रूप उर्दू के अधिक निकट है या हिन्दी के, हिन्दी-उर्दू को मिलाने के लिए लिपि कौन-सी हो।

हिन्दीभाषी प्रदेश में उस समय प्रगतिशील साहित्यिक आन्दोलन के संगठनकर्ता और संयोजक ज्यादातर उर्दू के लेखक थे। प्रेमचन्द हिन्दी-उर्दू दोनों के लेखक माने जाते थे। सन् '३६ में, इस नये साहित्यिक आन्दोलन के आरम्भ में ही, उनका देहान्त हो गया। अब इसके नेताओं में ऐसे लोग रह गये जो या तो उदीयमान साहित्यकार थे जैसे श्री अली सरदार जाफरी या जो साहित्यकार कम और आन्दोलनकारी ज्यादा थे जैसे डॉ० अब्दुल-अलीम और श्री सैयद सज्जाद जहीर।

१९३८ में कलकत्ता में दूसरा अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक-सम्मेलन हुआ। इसमें डॉ० अब्दुल अलीम ने 'हिन्दुस्तानी की समस्या' नाम से अंग्रेजी में एक निबन्ध पढ़ा। इसमें उन्होंने कहा कि हिन्दी-उर्दू दो भाषाएँ नहीं हैं वरन् वे एक ही भाषा के दो साहित्यिक रूप हैं। हिन्दुस्तानी उस प्रदेश की भाषा है जिसे पुराने ज़माने में लोग हिन्दुस्तान कहते थे। इस प्रदेश के उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में विन्ध्याचल, पश्चिम में पंजाब और पूर्व में बंगाल है। मुग़ल छावनियों की ज़बान को ज़बान-ए-उर्दू-ए-मुग़ल्ला, संक्षेप में उर्दू, कहा जाता था। "इसका प्रचलित नाम हिन्दी था जो प्रारम्भिक मुस्लिम विद्वानों का दिया हुआ था और जिसका अर्थ था हिन्द की भाषा।" अकबर के ज़माने में

प्राकृता पर फारसी का असर पड़ने लगा। "यह असर डालनेवाले पन्नी और कापम्य थे जिन्होंने फारसी सीखी। फारसी राजभाषा थी। वे अपनी आम बोलचाल में फारसी के लफ्ज जैसे ही इस्तेमाल करने लगे जैसे कि ज्यादातर पढ़े-लिखे लोग आजकल अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल करते हैं।" १७१६ ई० में दक्खिन के शायर बली का काव्य-संग्रह दिल्ली पहुँचा। उत्तर के प्रारम्भिक मुस्लिम कवियाँ ने ज्यादातर पुराने भारतीय छन्दा का प्रयोग किया था। दक्खिन के कवि फारसी की वहाँ इस्तेमाल करते थे। "आश्चर्य की बात है कि उत्तर के शायरों को कविता का यह नया ढंग इतना अच्छा लगा कि वे दिन्नी की ज्यादा शुद्ध भाषा में (यानी उस भाषा में जो ज्यादा फारसी मिश्रित नहीं थी) बनी के रंग-रंग की नकल करने लग। तभी से दोनों में भेद स्पष्ट हुआ जो अब बटने-बटने बहुत चौड़ी खाई बन गया है।"

डा० अलीम की ये स्थापनाएँ बहुत महत्वपूर्ण थीं। वह एक खाम प्रदेस की भाषा को हिन्दुस्तानी कहते थे। इस प्रदेश का पुराना नाम हिन्दुस्तान था, यह उन्होंने ठीक कहा था। तुर्क लेखका-शासकों-इतिहासकारों ने हिन्दुस्तान शब्द का बराबर प्रयोग किया है। डॉ० अलीम ने भाषा का सम्बन्ध किसी धर्म से नहीं जोड़ा। उन्होंने बोलचाल की भाषा में फारसी शब्दों की आमद का बहुत सही कारण बतलाया। उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम सभ्यताओं के मिलन से नयी भाषा बनने की बात नहीं की। फारसी के शब्द बोलचाल की भाषा में इसलिए नहीं आ गए कि वे हिन्दू मुस्लिम मिलन के लिये आवश्यक थे। वे इसलिए आए कि फारसी राजभाषा थी और इस राजनीतिक-सांस्कृतिक प्रभाव के कारण बोलचाल की भाषा में बहुत से फारसी शब्द घुल मिल गए। लेकिन बोलचाल की भाषा का साहित्यिक रूप एक ही था। उसके दो रूप तब हुए जब बली की नकल करनेवाले उत्तर के कवियों की रचनाओं में फारसीयन का रंग गाढ़ा होने लगा। उर्दू का यह साहित्यिक विकास अठारहवीं सदी की घटना है और मुसलमानों के भारत आने से, भारत में हिन्दू-मुस्लिम सभ्यताओं के मिलन से या इस्लाम से उसका कोई सम्बन्ध न था।

यह एक सही वैज्ञानिक और साम्राज्य विरोधी दृष्टिकोण था। गिलब्रिस्ट और ग्रियसन उर्दू-हिंदी का सम्बन्ध घम से जोड़ चुके थे। डॉ० अलीम ने उस सम्बन्ध को अस्वीकार करके भाषा-समस्या के वैज्ञानिक विवेचन और सही समाधान की ओर महत्वपूर्ण कदम उठाया था। धर्म को आधार मानकर कोई समस्या हल नहीं की जा सकती, न निषिद्ध की, न शब्दों के चुनाव की। हिन्दी-उर्दू समस्या पर जा भी विचार करे, उसे शुद्धान्त इस सूत्र से करनी चाहिए कि वे एक ही जाति की भाषा हैं, घम के आधार पर हिन्दू-मुस्लिम दो कौनों नहीं, उर्दू और हिंदी का बुनियादी बोलचाल का रूप एक है।

हिन्दी-उर्दू में भेद होते हुए भी उनके साहित्य में बहुत बड़ी समानता है। डॉ० अलीम के लेख में इस समानता पर ख़ोर नहीं है। उन्होंने हिंदी और उर्दू को वृत्ति रूप कहकर घटा बता दी। इससे हिन्दी और उर्दू के प्रगतिशील लेखक हिंदी-उर्दू साहित्य को प्रभावित करने के बदले उससे अपने को अलग कर सकते थे। उन्होंने भीर अम्न और

लल्लूजी लाल के बाद तमाम साहित्यिक विकास को हिन्दुस्तान के विकास के लिए धातक बताया। उन्होंने कांग्रेस को फटकारा कि इतने दिन से हिन्दुस्तानी की माला जपने के बाद भी उसके विकास के लिए उसने कुछ नहीं किया। उन्होंने इलाहाबाद की हिन्दुस्तानी अकादमी को सुझाया कि वह हिन्दुस्तानी के विकास की योजना बनाए। उन्होंने 'हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी' के शब्दों का व्यवहार हानिकारक बताया (क्योंकि इससे हिन्दुस्तानी का सम्बन्ध हिन्दी से जुड़ता था)। प्रगतिशील लेखकों से उन्होंने कहा, मुख्य समस्या यह है कि हिन्दुस्तानी अभी विकसित साहित्यिक भाषा नहीं है; आप लोगों को उसे विकसित कर देना चाहिए। पारिभाषिक शब्द अंग्रेजी से लेने की सलाह दी जो उनकी समझ में अधिकांश सम्य देशों की भाषाओं में सामान्य थे। लिपि की समस्या. डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी की राय का समर्थन करते हुए, उन्होंने रोमन लिपि अपनाकर हल करने की सलाह दी।

रोमन लिपि अपनाने में उन्हें सबसे बड़ा लाभ यह दिखाई दिया, "इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि अपनी लिपियों को छोड़ देने से अपने बहुत से पुराने साहित्य से हमारा सम्बन्ध अपने-आप टूट जाएगा। धार्मिक पुनरुत्थानवादी इसे वर्दाश्वित नहीं कर सकते। हमलोग अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं के आमूल परिवर्तन में विश्वास करते हैं। हम अपने साहित्य को बुद्धिसंगत बनाने में (इन रेशनलाइजिंग अवर लिटरेचर) विश्वास करते हैं। इसलिए यह हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसी लिपि अपनाएँ जो सबसे ज्यादा वैज्ञानिक हो और जिसे अपनाकर हम आधुनिक संसार की आवश्यकताएँ पूरी कर सकें।"

इस प्रकार डॉ० अलीम का दृष्टिकोण पुरानी साहित्यिक विरासत की तरफ बिलकुल अस्वीकृति का था। यह दृष्टिकोण वास्तव में साम्राज्यवादी लेखकों का रहा है जो भारत की सांस्कृतिक उपलब्धियों को हमेशा अमान्य करते रहे हैं। लार्ड मैकाले ने कुछ ऐसी ही बातें अपने प्रसिद्ध निबन्ध में कही थीं। डॉ० अलीम भारत की अन्य भाषाओं के साहित्य से अपरिचित थे; वह हिन्दी पढ़ लेते हैं लेकिन कम-से-कम सन् '३८ में जब उन्होंने यह निबन्ध लिखा था, तब वह हिन्दी साहित्य के विकास से अपरिचित थे। उनके मुख्य सलाहकार श्री मुल्कराज आनन्द भारतीय साहित्य की प्रगति से और भी कोरे थे। प्रेमचन्द के अभाव में ऐसा कोई लेखक नहीं था जो इन्हें संकीर्णतावाद से वचाता। राष्ट्रीय आन्दोलन से आधुनिक साहित्य का सम्बन्ध न समझने के कारण उन्होंने हिन्दी-उर्दू के साहित्य के प्रति यह संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाया। राष्ट्रीय आन्दोलन और भारतीय साहित्य में नव-जागरण को न समझने के कारण वे बहुत जल्दी ऐसे नेताओं के प्रभाव में आ गए जो आत्मनिर्णय के नाम पर मुस्लिम लीग और पाकिस्तान का समर्थन करते थे।

इन नये नेताओं में श्री सैयद सज्जाद ज़हीर मुख्य थे। सन् '३८ में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के मंत्री डॉ० अब्दुल अलीम थे; द्वितीय महायुद्ध के दौरान उसके मंत्री हुए सज्जाद ज़हीर साहब। डॉ० अलीम की तुलना में वह साहित्यकार कुछ ज्यादा थे। उनका 'लन्दन की एक रात' उपन्यास सन् '३८ के आस-पास छप चुका था। सन् '४३

मे १९७३ तक वह कम्युनिस्ट पार्टी के भूतपूर्व नेता श्री पूरन जोशी के दाहिने हाथ रहे। मुस्लिम-समस्या पर उन्हें नज़ाह देन के अलावा श्री जोशी की आत्मनिर्णय वाली नीति का वह मुसलमानों में लागू भी करना थे। उस समय कम्युनिस्ट पार्टी का नारा था, 'बायेंस-नॉंग एव' हो। यह नारा इस समय के आधार पर दिया गया था कि भारत में दो राष्ट्र या दो तरह की राष्ट्रीयता विद्यमान होनी रही हैं—एक हिंदुओं की, दूसरी मुसलमानों की। इन दोनों को भिन्न-भिन्न अर्थों से मिला देने की मांग करनी चाहिए।

मुसलमानों की अलग कौम है, उसे आत्मनिर्णय का अधिकार दानी देना से अलग होकर अपना राज्य बनाने का हक मिलना चाहिए, इस निष्ठान्त को भाषा-क्षेत्र में लागू किया जाय तो यह नतीजा निकलेगा ही कि हिन्दुओं की भाषा हिन्दी है, मुसलमानों की भाषा उर्दू है।

हिन्दी-उर्दू में भेद क्या हुआ? इसलिए कि हिन्दुओं ने उर्दू का ढाँचा लेकर उसमें उन शब्दों का भरपूर जिनका सम्बन्ध हिन्दू सभ्यता से था।

'हिन्दी-उर्दू-हिन्दुस्तानी समस्या का हल' नाम के निबन्ध में श्री मज्जाद जहीर ने लिखा, "आधुनिक हिन्दी ने खड़ी बोली का ढाँचा उर्दू से लिया और उसमें उसने उन शब्द-योजनाओं और परम्पराओं में उसे अनुप्राणित किया, जो हिन्दू सभ्यता के अभिन्न अंग थे।"

✓ आधुनिक युग में राष्ट्रीयता का अभ्युदय कैसे हुआ? राजा राममोहन राय ने 'अंग्रेज़ ईसाई मिशनरियों के हमले में हिन्दू धर्म को बचाने के लिए ब्राह्म-समाज की नींव डाली। इसका प्रभाव आधुनिक बंगाली सभ्यता के विकास पर पड़ा और बंगाल के 'इन्दी आन्दोलन' में प्रभावित होकर हिन्दी साहित्य के प्रथम महारथी भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने अपना आन्दोलन शुरू किया। उनकी रचनाओं ने 'मध्यवर्ग' के शिक्षित हिन्दुओं के हृदय में वह नैराश्य और विषाद दूर कर दिया जो पराधीनता के कारण देश में छा गया था। भारतेन्दु ने 'प्राचीन हिन्दू महापुरुषों और देवताओं को रंगमंच पर लाकर हिन्दुओं को उनके विगत वैभव' की याद दिलाई, 'हिन्दू-समाज की बुराईयों' की आलोचना की।

इस प्रकार "हिन्दी उत्तर भारत में (विशेषकर युक्त प्रान्त, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रांत के हिन्दुस्तानी भाग में) हिन्दू राष्ट्रीय जागरण का—जिसके विभिन्न पक्ष अथवा रूप धर्माधार, धर्म-मुधार, समाज-मुधार और नवीन शिक्षा प्रचार हैं—एक शक्तिशाली माध्यम बन गई।"

श्री मज्जाद जहीर ने भारतेन्दु युग के साहित्य में जो साम्राज्य-विरोधी तत्त्व थे, जिनका सम्बन्ध हिन्दू-समाज से ही नहीं, सारे भारत से था, उन्हें नज़रन्दाज़ किया। उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि भारतेन्दु प्रतापनारायण मिश्र और बालमुकुन्द गुप्त जैसे हिन्दी लेखक उर्दू में भी लिखते थे। उन्होंने ग़ैलफ़िख़्त और प्रियतन से दो कदम आगे बढ़कर धर्म के आधार पर साहित्य और भाषा का बँटवारा कर दिया। जो धार्मिक आकाशवाणी पुराने साहित्य में रही है, उसे उस साहित्य का एक पक्ष न मानकर, उन्होंने उन

भाषनाओं को राष्ट्रीय जागरण का मुख्य चिह्न मान लिया।

कहीं उनके दिमाग में एक पुराना कीड़ा भी रेंग रहा था। यह मुश्तर्का जवान का कीड़ा था। हिन्दुओं और मुसलमानों के मेल-जोल ने उर्दू का जन्म और विकास हुआ। इस सम्मिलित विकास को खत्म कर दिया सम्प्रदायवादी हिन्दुओं ने!

“उर्दू अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी में उत्तर और मध्य भारत के सम्मिलित सामाजिक जीवन के सांस्कृतिक आदान-प्रदान की स्वाभाविक माध्यम बन गई थी।” उर्दू लेखकों में रतननाथ सरस्वार जैसे हिन्दू थे। पुराने पश्चिमोत्तर प्रान्त—आज के उत्तर प्रदेश—में १८६६ में चौबीस पत्र निकलते थे, उन्नीस उर्दू में, तीन हिन्दी-उर्दू दोनों में। इनमें अधिकांश के मालिक और सम्पादक हिन्दू थे। १८७१ में अवध में जो विद्यार्थी उर्दू पढ़ते थे, उनमें ज्यादातर हिन्दू थे। “अतः उर्दू भाषा और उसकी लिपि के विरोध और वहिष्कार को लेकर जो हिन्दी नागरी आन्दोलन आरम्भ हुआ, इसको अपने समाज और संस्कृति पर हिन्दुओं की ओर से अन्यायपूर्ण, संकुचित, साम्प्रदायिक प्रहार समझना मुसलमानों के लिए स्वाभाविक था।”

हिन्दुओं और मुसलमानों के सांस्कृतिक आदान-प्रदान का माध्यम उर्दू बनी। यह कार्य भी स्वाभाविक था। हिन्दी-आन्दोलन को मुसलमानों ने अन्यायपूर्ण समझा, यह भी स्वाभाविक था। हिन्दी हिन्दुओं की सांस्कृतिक भाषा बनी, यह भी स्वाभाविक था।

ये तीन स्वाभाविक क्रियाएँ एक साथ कैसे हो गईं? जहीर साहब के अनुसार हिन्दुओं और मुसलमानों की मूलतः दो संस्कृतियाँ हैं। इनको आगे अलग-अलग विकसित होना ही था। “आरम्भ से ही मुसलमानों के निकट हिन्दी और देवनागरी लिपि आन्दोलन हिन्दुओं की कट्टर साम्प्रदायिकता और मुस्लिम संस्कृति-विरोध का द्योतक रहा है।” इसलिए “१९०० में जब देवनागरी भी उर्दू के समान अदालतों में जारी हो गई, तो सर सैयद को विश्वास हो गया कि ‘अब हिन्दुओं और मुसलमानों का एक राष्ट्र होकर अपने अन्धमूढान के लिए सम्मिलित प्रयत्न करना असम्भव हो गया है।’ उसी समय उर्दू-रक्षा-समिति सर सैयद के तत्वावधान में कायम हुई।”

मुसलमानों का अलग राष्ट्र हो, उर्दू की रक्षा का प्रयत्न किया जाय—दोनों बातों का उल्लेख साथ-साथ किया गया है। श्री सज्जाद जहीर के पास हिन्दी-उर्दू विरोध का हल क्या है? या अठारह साल पहले उनके पास कौन-सा हल था? उनके पास वही हल था जो सर सैयद अहमद ख़ाँ ने बताया था और जिसका सर मुहम्मद इकबाल ने नये सिरे से प्रचार किया था।

उर्दू हिन्दुओं और मुसलमानों की एकमात्र मिली-जुली भाषा न रह सकी। कारण था हिन्दुओं की साम्प्रदायिक कट्टरता। इसलिए हिन्दू अलग, मुसलमान अलग; एक राष्ट्र की भाषा हिन्दी, दूसरे की उर्दू।

जिसे राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान साम्प्रदायिकता कहा जाता था, उसी को श्री सज्जाद जहीर और उनके सहयोगी श्री पूरनचन्द जोशी राष्ट्रीयता कहने लगे। हिन्दू

गण्टवाद, मुस्लिम राष्ट्रवाद—य दो नये ढंग के राष्ट्रवाद सामने आए। एक का प्रचार मुस्लिम लीग ने किया। दूसरे का, उनम पीछे, उसने पण्डितजी पर उतरकर, हिन्दू महासभा जीर जनगण ने। इन्हें मातृवाद के नाम पर वैज्ञानिक ठहराया श्री मज्जाद जहीर ने।

मुगलमानों ने हिन्दी-आन्दोलन का विशेष किया। “इस व्यापक विराघ का समझने के लिए हमें यह जानना चाहिए कि मुगलमानों के लिए उस समय यह समझना कठिन था कि हिन्दी नागरी आन्दोलन हिन्दुओं के देशव्यापी साम्प्रतिक नवोद्योग का ही एक अंग था।” यह हिन्दुओं का नवोद्योग जानी रहा और उसे आगे बढ़ाया महात्मा गांधी ने।

चीकने की बात नहीं है। गांधीजी के राष्ट्रीय आन्दोलन को जिना माहव हिन्दू आन्दोलन कहते थे या नहीं? फील्ड मार्शल अय्यूब खाँ हिन्दू भारत में मुस्लिम काशीर को आजाद बनने के जेहाद शुरू कर चुके हैं या नहीं? ब्रिटिश प्रचारक कहते हैं या नहीं कि श्री लालमहादुर शास्त्री पाकिस्तान में इसलिए लड़ रहे हैं कि वह हिन्दू हैं?

जहीर माहव के वैज्ञानिक विवेचन के अनुसार “सन् १९२० में जब राष्ट्रीय जागरण की एक नयी लहर काश्मिर और महात्मा गांधी के नेतृत्व में उठी, तो इसके बाद हिन्दुओं में हिन्दी को और भी अधिक प्रोत्साहन मिला। धातू मैथिलीकरण गुप्त ने अपना मुद्रापिड काव्य ‘भारत-भारती’ इसी युग के आस पास (सन् १९१३) में लिखा। यह कविता उन गांधीवादी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है जो इस समय उत्तरी भारत के हिन्दुओं को आन्दोलित कर रही थीं।”

सन् ‘२० में जो राष्ट्रीय जागरण की नयी लहर उठी, उसने मातृ मातृ पहले की रचना ‘भारत-भारती’ को प्रभावित किया और इसमें वे गांधीवादी भावनाएँ हैं जो उस समय के हिन्दुओं को आन्दोलित कर रही थीं।

उधर ‘हिन्दुओं के ही समान उत्तरी भारत के मुसलमानों में राष्ट्रीय जागरण’ की लहर उठ रही थी। इन राष्ट्रीय जागरण का सम्बन्ध गांधीजी के आन्दोलन में नहीं है। बीसवीं सदी के आरम्भ में “राजनीतिक जागरण के साथ-साथ स्वतन्त्रता का भाव भी मुसलमानों में जागने लगा।” राजनीतिक जागरण? क्या यह गांधीजी के आन्दोलन में बाहर कोई जागरण था? स्वतन्त्रता का भाव? किसमें? अंग्रेजों में या हिन्दुओं में या दोनों में? उर्दू साहित्य ने नई कण्ठस्थी “और शिवनी जफर अली खाँ, अबुल कलाम और जतम दखान ने मुसलमानों के मज्जीन जागरण को व्यक्त किया।”

अबुल कलाम आजाद मुसलमानों के ‘राष्ट्रीय’ जागरण के नेता कैसे बने, यह नहीं बताया गया। मुझे याद है सन् ‘४७ के आस-पास इस तरह के ‘राष्ट्रीय’ जागरण की चर्चा करनेवाले समझते थे कि कांग्रेस और गांधीजी का साथ देनेवाले मुसलमान गुमराह हैं। वे मुस्लिम इतिहास को तोड़नेवाले लोग हैं। मुसलमानों के अगली नेता कांग्रेस जिना और अन्य मुस्लिम लीग हैं। इसीलिये राष्ट्रीयता के साथ गहरी करके

साम्प्रदायिकता को अपनाया, स्वभावतः उसकी आलोचना श्री जहीर के लेख में नहीं है यद्यपि बहुत से उर्दू लेखकों ने इसके लिए इकबाल की आलोचना की थी।

नतीजा यह कि “आधुनिक उर्दू की तरक्की हिन्दुस्तानी मुसलमानों के विगत सौ वर्षों के राष्ट्रीय जागरण से सम्बद्ध है।” राष्ट्रीय जागरण से सम्बद्ध है तो नया राष्ट्र बनेगा ही; जहीर साहब के अनुसार उर्दू का सारा विकास पाकिस्तान की ओर—भारत के विभाजन की ओर संकेत करता था। हिन्दू सम्प्रदायवादी भी उर्दू के दमन के पक्ष में यही तर्क देते थे। मुश्किल यह थी कि उर्दू के लेखकों में प्रेमचन्द भी थे; वह दोनों राष्ट्रीय जागरणों में हिस्सा बँटा रहे थे। क्या कारण है कि किसान-जीवन के अमर चित्रकार प्रेमचन्द के सामने होते हुए श्री सज्जाद जहीर जैसे मार्क्सवादी हिन्दी-उर्दू साहित्य का सम्बन्ध हिन्दू और मुस्लिम राष्ट्रवाद यानी सम्प्रदायवाद से जोड़ने लगे? कारण है आम जनता से बलगाव। उनका जन्म अभिजात वर्ग में हुआ। अपने वर्ग के संस्कार मिटाने के लिए उन्हें आम जनता से जैसा सम्पर्क कायम करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। आम जनता में काम किए बिना ही वह बहुत जल्दी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बन गए। श्री पूरनचन्द जोशी हमेशा ऐसे लोगों की तलाश में रहे हैं जो आला खानदान के हो, विलायत जाकर पढ़े हों, दिमाग के कच्चे हों जिससे कि उनकी नयी-नयी स्थापनाएँ आसानी से मान लें। श्री सज्जाद जहीर बहुत अच्छे लेखक, बहुत अच्छे राजनीतिक कार्यकर्ता बन सकते थे यदि श्रीमान् पूरनचन्द जोशी ने उन्हें बिगाड़ा न होता।

इसलिए ‘गोदान’ की तारीफ करने के बाद इस सम्प्रदाय के तरक्की-पसन्द अदीब कहते थे कि जब प्रेमचन्द तरक्की-पसन्द बन रहे थे, तभी वह स्वर्गवासी हो गए। प्रेमचन्द के विकास को वे बिल्कुल न समझते थे। उनका साहित्य हर तरह के सम्प्रदायवाद पर कितना जवर्दस्त प्रहार है, यह उन्हें बिल्कुल दिखाई न देता था। एक मित्र ने छ-सात साल पहले अपने एक भाषण में कहा था कि प्रेमचन्द हिन्दुओं की आलोचना तो कर लेते थे, मुसलमानों की आलोचना करते जैसे उन्हें डर लगता था। मैंने ‘समालोचक’ में इन हिन्दी लेखक मित्र के आरोप का विस्तार से जवाब दिया था। उन्होंने की तरह ‘४३-’४७ में बम्बई के कुछ राजनीतिज्ञ प्रेमचन्द के बारे में कहते थे कि वह महज हिन्दू समाज-सुधारक थे।

दिलचस्प बात है कि ‘भारत-भारती’ पर जहीर साहब ने स्वर्गीय रामचन्द्र शुक्ल की सम्मति उद्धृत की है। इस सम्मति में कहा गया है, “सत्याग्रह, अहिंसा, मनुष्यतावाद, विश्वप्रेम, किसानों और श्रमजीवियों के प्रति प्रेम और सम्मान, सबकी भूलक हम पाते हैं।”

इसे भी उन्होंने हिन्दुओं को आन्दोलित करनेवाली गांधीवादी भावनाओं के प्रमाणस्वरूप पेश किया है।

आधुनिक उर्दू साहित्य में फिराक गोरखपुरी, कृष्णचन्दर, राजेन्द्रसिंह वेदी जैसे गैर-मुसलमान लेखक भी हैं। सम्प्रदायवादी कहते हैं कि ये आवे मुसलमान हैं। जहीर साहब की राय यह थी कि “उर्दू साहित्य का अविकाश पहले भी, और आज और भी



अधिनगर मुसलमानों से सम्बन्ध रखता है, और इसी कारण उर्दू साहित्य के अधिकांश भाग पर मुसलमानों की सम्प्रति और सत्कृति की छाव है। विलकुल ऐसे ही हिन्दी के अधिकांश भाग पर हिन्दू सम्प्रति के प्रभाव स्पष्ट हैं।" इस तरह प्रेमचन्द, फिराक, बेरी, हुसैनवादी वगैरह-वगैरह के वाक्पुद्गल श्री सज्जाद जहीर ने साहित्य की हिन्दू-मुस्लिम सम्प्रति के आधार पर दो हिस्सों में बाँट दिया।

उनके दिमाग पर धार्मिक पुनरुत्थानवाद का इतना गहरा रंग चढ़ा हुआ था कि हिन्दी-उर्दू साहित्य में उन्हें हिन्दू मुस्लिम सम्प्रति के अन्तर और कुछ दिखाई ही न देता था।

हिन्दू सम्प्रदायवादियों में जब कोई कहता है कि आप हिन्दू धर्म का प्रचार करते हैं धार्मिक सकीर्णता फैलाने हैं, तो वे जवाब देते हैं कि हमारा सात्त्विक धर्म से नहीं है, हिन्दुत्व एक जीवन-मार्ग है, वह इस देश की जीवन-मार्ग है, जो उसे माने वह हिन्दू।

जहीर माहव ने लिखा था, "जब मैं हिन्दू सत्कृति या मुस्लिम सत्कृति का नाम लेता हूँ तो मेरा सात्त्विक उनके धार्मिक भेदों से नहीं है। भारतीय सम्प्रति को हम देश के विभिन्न भागों में विभिन्न रूप में देखते हैं, और इनमें हमें अनगिनत समानताएँ मिलती हैं। फिर भी उन इलाकों में जहाँ उर्दू या हिन्दी आम तौर से बोली जाती है, हिन्दू और मुस्लिम सत्कृति का भेद, हमें उर्दू और हिन्दी के साहित्यिक रूपों में स्पष्ट दिखाई देता है।"

हिन्दू सम्प्रदायवादी कहते हैं कि सारे भारत में एक ही सत्कृति है, हिन्दू सत्कृति। जहीर माहव कहते हैं, एक नहीं, दो सत्कृतियाँ हैं। हिन्दू सत्कृति तो है ही, एक मुस्लिम सत्कृति भी है।

मुस्लिम सत्कृति किन इलाकों में है? उन इलाकों में जहाँ उर्दू बोली जाती है। क्या सिन्ध और पूर्वी बंगाल की भाषा उर्दू है? नहीं। फिर भी मुस्लिम सत्कृति के नाम पर भारत का वह सारा हिस्सा अलग किया गया जहाँ किसी की भी मातृभाषा उर्दू नहीं है। जिनकी मातृभाषा उर्दू है वे भारत में ही हैं, इसलिए इलाकाई खान की समस्या फिर भी बनी रह गई।

उर्दू में अब भी बहुत से अन्तर्धार निहित हैं जिनमें मुसलमान हिन्दू सम्प्रदायवाद का प्रचार होता है। जो उर्दू में लिखे वह आधा मुसलमान हो जाय यह आवश्यक नहीं है। एक ही भाषा में हर तरह के विचार व्यक्त किए जा सकते हैं। भाषा और धर्म दो अलग चीजें हैं। उर्दू में फारसी के जो शब्द आए हैं, वे ईरान के सांस्कृतिक प्रभाव के कारण, धर्म के कारण नहीं। फारसी मुसलमानों की धार्मिक भाषा नहीं है। उनका धर्म-ग्रन्थ खुराँ में है। यह जगहो इस्लाम से पहले भी थी, उसका जन्म इस्लाम के साथ नहीं हुआ। धर्म धर्माध्य व्यक्ति ही धर्म के साथ भाषा का सम्बन्ध जोड़ सकता है। उर्दू के इन रक्षकों को यह नहीं दिखाई देता कि कश्मीरी, सिन्धी, बंगला आदि भाषाएँ बोलनेवाले लोग मुसलमान हैं जिनका उर्दू से कोई सम्बन्ध नहीं है।

और भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जिन्होंने हिन्दी-आन्दोलन और हिन्दू राष्ट्रवाद को जन्म दिया, कैसी हिन्दी लिखते थे ? क्या उनकी भाषा में सभी शब्द हिन्दू होते थे ?

जहीर साहब ने भारतेन्दु की भाषा-शैली का बहुत सही वर्णन किया है। लिखा है, “भारतेन्दुजी की भाषा पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो उसमें प्रवाह और ओज के साथ-साथ यह भी देखते हैं कि वह अपनी हिन्दी में अरबी और फारसी के प्रचलित शब्द निस्संकोच प्रयोग करते हैं। उनकी रचना हिन्दी होती है, उसमें संस्कृत का मिश्रण होता है, और वह ब्रज और अवधी की परम्पराओं का भी दामन नहीं छोड़ती। इस दृष्टि से इसमें और संप्रति प्रचलित उर्दू गद्य की शैली में काफी अन्तर है।”

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने अरबी-फारसी के प्रचलित शब्दों को छोड़ा नहीं, उनकी भाषा में संस्कृत शब्द भी होते हैं, ब्रज, अवधी आदि की जनपदीय और साहित्यिक परम्पराएँ उससे जुड़ी हुई हैं—क्या हिन्दी-उर्दू की मिली-जुली साहित्यिक परम्परा इससे भिन्न किसी और तरह की भाषा अपना सकती है ? इस तरह की भाषा पर हिन्दू राष्ट्रवाद का कौन-सा ठप्पा लगा हुआ था ? इस भाषा से उर्दू की रक्षा का मतलब क्या होता है ? संस्कृत शब्दों का वहिष्कार, सांस्कृतिक शब्दावली केवल अरबी-फारसी से ली जाय, जनपदीय बोलियों और हिन्दी की पुरानी साहित्यिक परम्परा से अलगाव। यह उर्दू की रक्षा नहीं, उसके विनाश का मार्ग है।

दो तरह की संस्कृतियों, दो तरह के ‘राष्ट्रीय’ जागरणों की मान्यताएँ प्रस्तुत करने के बाद भी जहीर साहब ने फ़िल्मों में और मजदूर नेताओं के भाषणों में हिन्दी-उर्दू का मिला-जुला रूप देखा, यह उनकी शराफ़त थी। जब संस्कृतियाँ हिन्दू और मुस्लिम क्षेत्रों में विभाजित थीं, तब यह मिली-जुली भाषा कौन-सी संस्कृति को प्रतिबिम्बित करती थी, जो न हिन्दू थी, न मुसलमान—यह उन्होंने नहीं बताया।

कांग्रेस-लीग एक हो, यह नारा भाषा के क्षेत्र में लागू करते हुए उन्होंने राय दी—“भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी और उर्दू दोनों हों।”

उन्होंने उदारता से लिखा, “उर्दू और हिन्दी के आज के पार्थक्य को स्वीकार करते हुए हमें प्रयत्न करना चाहिए कि यह पार्थक्य कम हो।

“इसलिए आवश्यक है कि इस समय हिन्दी और उर्दू का यह भाषा-क्षेत्र जो समान रूप से दोनों का एक है, जिसे सरल उर्दू, सरल हिन्दी या हिन्दुस्तानी का नाम दिया जाता है, कायम रहे और उसकी सीमा बराबर बढ़ाने का प्रयत्न किया जाय।”

हिन्दी और उर्दू वुनियादी रूप में एक हैं; उनके साहित्यिक, शिष्ट रूप में आज भेद है, उसे दूर करना चाहिए। दोनों का भाषा-क्षेत्र एक है। दोनों का सामाजिक परिवेश एक है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए यदि श्री जहीर ने जाति की मार्क्सवादी व्याख्या पर विचार किया होता तो वह इस नतीजे पर अवश्य पहुँचते कि हिन्दी-उर्दू एक ही जाति की भाषा हैं, दोनों का साहित्य एक ही जाति का साहित्य है, उनमें एक ही राष्ट्रीय जागरण की भूलक है, दो राष्ट्रों के जागरण की नहीं। मार्क्सवाद में कही भी इसका

प्रमाण नहीं है कि धर्म के आधार पर भाषा या जाति का निर्माण स्वीकार किया गया हो।

यदि हिन्दा-उर्दू का इलाका एक था, तो बंगाल और मिथ में आ-मिश्रण का अधिकार किसके लिए ? फिर पाकिस्तान का समयन क्यों ?

उन प्रश्नों का उत्तर यह है इलाका तो एक है लेकिन 'उसकी सीमा बराबर बढ़ाने का प्रयत्न किया जाय'।

उद्दीर्ग साहब के दिमाग में तबसा यह है कि मुसलमानों की भाषा एक है उर्दू। जो मुसलमान उर्दू नहीं बोलते, वे भी आगे चलकर उर्दू बोलने लगेंगे। मुस्लिम सभ्यता में 'दूसरा सम्प्रदाय जोड़ने का एक ही नतीजा होगा भारत के सभी मुसलमानों की भाषा उर्दू हो। इसलिए धीरे-धीरे इलाका बढ़ाने जाओ। एक दिन सब मुसलमान उसमें मिल जायेंगे। फिर हिन्दुओं की राष्ट्रभाषा होगी हिन्दी। हिन्दू सभ्यता से हिन्दी का सम्बन्ध है, इसलिए हिन्दू मानें की एक भाषा होगी हिन्दी। हिन्दू राष्ट्र में बंगला मराठी, तमिल आदि भाषाएँ कायम रही तो वे राष्ट्र का सण्डल करेंगी—यही सम्प्रदायवादियों का दृष्टिकोण रहा है।

श्री सज्जाद उद्दीर्ग की मायनाओं की श्री शिवदानमिह चौहान ने और भी पुष्टि और पल्लवित किया।

'राष्ट्रभाषा विवाद और समाधान नाम के निबंध में शिवदानमिहजी ने पहले तो सम्प्रदायवादियों को फटकार बनाई, कहा कि १४० साल से यह हिन्दी-उर्दू की घटस राजनीति के उतेजना और 'धार्मिक-साम्प्रदायिक' उमाद के वातावरण में अद्वितीय बनती आई है', "प्रतिपक्षिया न अपनी तर्कबली को रुक बना रखा है, उन्होंने सावधान किया कि वे दिन गये जब " 'आय भाषा' हिन्दी के समर्थक उसे हिन्दुओं की परम्परागत भाषा कहकर " उसका चलन कचहरियों और क्षणों में कराना चाहते थे, उन्होंने किंचित् छेद प्रकट किया कि "हिन्दी का नवत्व विशेषकर हिन्दू राष्ट्रवादियों के हाथ में है," उधर "उर्दू का नवत्व विशेषकर मुस्लिम राष्ट्रवादियों के हाथ में है।" इसके बाद उन्होंने प्रगतिवादियों की खबर ली जिन्होंने मिनी-मुनी भाषा हिन्दुस्तानी का समयन किया, 'उसमें उन्हें राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर गहराई से सोचने से जैस छुट्टी मिल गई और सरल समाधानों को ही स्वीकार कर उन्होंने अपनी इतिवर्तव्यता मान ली।"

भाषा-समस्या पर गहराई से विचार करके, सरल समाधानों को रास्ते से हटा कर सदृष्ट समाधानों की आर साहस से बदम उठाते हुए श्री चौहान ने अपनी ये मायनाएँ प्रस्तुत की—

—'सर्वप्रथम यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि हिन्दी और उर्दू दो भिन्न भाषाएँ हैं।'

—'हिन्दी और उर्दूवालों को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये दोनों अलग-अलग स्वतंत्र भाषाएँ हैं।'

—“ये दोनों पृथक् भाषाएँ खड़ी वाली की ज़मीन पर संस्कृत और फारसी के खाद्य-बीज से उत्पन्न दो पौधों के समान हैं, अतः दो भिन्न संस्कृतियों हिन्दू और मुस्लिम की प्रतीक हैं।”

ये मान्यताएँ नई नहीं हैं। हिन्दू और मुस्लिम सम्प्रदायवादी यही बातें कहते रहे हैं। लेकिन यह श्री शिवदानसिंह चौहान का ही वृत्त था कि वह हिन्दू राष्ट्रवादियों की निन्दा करते हुए उन्हीं की स्थापनाओं को अपने जनवाद के नाम पर दोहराते चले।

उनका जनवाद धन्य है क्योंकि “हम जनवाद के उन सिद्धान्तों के आधार पर इस प्रश्न का समाधान करना चाहते हैं जिनका आधार अखंड हिन्दुस्तान अथवा विभाजित हिन्दुस्तान की केन्द्रीय सरकारों को भी लेना पड़ेगा।”

श्री चौहान ने जनवाद पर इतनी गहराई से विचार किया था कि उन्होंने अखंड और खंडित दोनों तरह के देश के लिए अपना अचूक समाधान प्रस्तुत किया था—

“इस समय देश में ‘पाकिस्तान’ और ‘अखंड हिन्दुस्तान’ का विवाद छिड़ा हुआ है। हमने अपने विवेचन में अखंड अथवा विभाजित भारत को लक्ष्य में रखकर कोई समाधान निकालने की चेष्टा नहीं की, क्योंकि हमारी दृष्टि में अखंड हिन्दुस्तान हो अथवा पाकिस्तान और हिन्दुस्तान अलग-अलग हो, दोनों दशाओं में राष्ट्रभाषा का वही समाधान होगा जिस पर हम अभी विचार करेंगे।”

असली चीज है जनवादी दृष्टि प्राप्त करना। गुरु-कृपा से जिसे यह दृष्टि प्राप्त हो जाती है, उसके लिए जैसे पाकिस्तान, वैसे अखंड भारत। गुरु श्री सज्जाद ज़हीर की कृपा से यह दृष्टि मुरीद श्री चौहान को प्राप्त हो गई।

“इस जनवादी उदार दृष्टि को प्राप्त करने पर राष्ट्रभाषा के प्रश्न का समाधान स्वतः स्पष्ट हो जाता है।”

अब देखिए इस उदार दृष्टि के प्राप्त होने से भूत, भविष्यत् और वर्तमान तीनों कालों में सत्य कैसा स्पष्ट दिखाई देने लगता है।

पहले अतीत के दृश्य देखिए। भारत में मुसलमान आए। जब ताजे थे, तब तो हिन्दू-मुस्लिम संस्कृतियों का मेल हो गया, जब यहाँ रहते-रहते यही के हो गये, तब उनकी संस्कृतियों में भेद हो गया। और यह भेद करनेवाले थे ब्रज और अवधी के दो कवि—मूरदास और तुलसीदास !

मुनिएँ हिन्दी साहित्य के विकास का यह अभिनव जनवादी विश्लेषण।

“इसमें सन्देह नहीं कि भारत में मुसलमानों के आगमन के पश्चात् हिन्दू-मुस्लिम संस्कृतियों में एक लम्बी अवधि तक मुक्त आदान-प्रदान और मिश्रण होता रहा।”

ईरानियों की संस्कृति, अरबों, पठानों, उजबकों की संस्कृति—सब एक-सी, सब इस्लामी संस्कृति !

निर्गुणपंथियों और प्रेम-मार्गियों ने हिन्दू और मुस्लिम संस्कृतियों को मिलाया। “इस संयुक्त विचार-परम्परा की कविताएँ यद्यपि सत्रहवीं शताब्दी तक होती रहीं परन्तु

स्वामी रामानुजाचार्य के अनुयायी रामानन्द और श्री बल्लभाचार्य ने राम और कृष्ण को समुणोपासना की जो परिपाटी चलाई उसने तुलसी और मूर जैसे महाकवियों को जन्म दिया जिन्होंने अवधी और ब्रज की वाक्यधारा को कबीर और जायसी की हिन्दू-मुस्लिम सस्कृतियों की सम्मिलित परम्परा में एकदम अलग कर दिया। अवधी और ब्रज की काव्य-परम्परा हिन्दू सस्कृति की प्राचीन काव्य परम्पराओं की उत्तराधिकारिणी बन गई। यह हिन्दू जातीयता की नवचेतना का परिणाम था।"

मुसलमानों के आने पर पहले तो सम्मिलित सस्कृति की धारा चली, फिर उसे मूरदास और तुलसीदास ने तोड़ दिया। यह भी अच्छा हुआ क्योंकि सत्रहवीं सदी से हिन्दू जातीयता का अस्तित्व आरम्भ हो गया था। इन महाकवियों ने उसे पहचाना और उसे अपने साहित्य में अभिव्यक्त किया।

रोनि और भक्ति की काव्यधाराओं में भले ही बहुत से मुसलमानों ने योग दिया हो, श्री चौहान के अनुसार "ये काव्यधाराएँ हिन्दू जातीयता के नवोन्मेष की प्रतीक हैं।" इनके भाव विचार ही नहीं, "सौन्दर्य मूल्य, छन्द-रचना, ध्वनि-योजना, अलंकार विधान" भी "सम्बद्ध साहित्य और हिन्दू-आर्य सस्कृति से प्रभावित और निरूपित हैं।" चौहान ने यह नहीं बताया कि जिन कवियों ने हिन्दू-मुस्लिम सस्कृतियों का मेल किया था, उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम छंदों का मेल कैसे किया था।

आधुनिक हिन्दी के युग में आइए। हिन्दू सस्कृति की वह परम्परा आगे भी कायम रही। लिखा है— "मूरदास और तुलसीदास के समय से मारतेन्दु काल तक ब्रज और अवधी की काव्य-परम्परा में वह विचारधारा ही सर्वप्रधान बनी रही।"

आधुनिक खड़ी बोली ने अपने से पहले की साहित्यिक परम्पराओं से सम्बन्ध जोड़ जोड़ा। "खड़ी बोली हिन्दी ने सस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंशों से अपना सीधा सम्बन्ध जोड़ कर धीरसेनी, मागधी आदि अपभ्रंशों की अन्य भाषाओं के प्राचीन साहित्य को अपना प्राचीन साहित्य घोषित करके अपने को आय-हिन्दू परम्परा का उत्तराधिकारी सिद्ध किया। इस प्रकार हिन्दू जातीयता और तदनन्तर हिन्दू राष्ट्रीयता ने अपनी जाति, सगठन और विकास के लिए खड़ी बोली हिन्दी के द्वारा अपना मार्ग प्रगस्त किया अथवा कहें कि इस पुनरुत्थान और राष्ट्रीय चेतना में हिन्दुओं के लिए खड़ी बोली हिन्दी माध्यम और वाहक बनी। हिन्दी साहित्य के इतिहासकारों ने इस तथ्य को मुक्त कंठ से स्वीकार किया है।"

शिवदानसिंहजी ने उदात्तावस्था हिन्दी-साहित्य के इतिहासकारों का उल्लेख कर दिया है। वरना पहले हिन्दू जातीयता, तदनन्तर हिन्दू राष्ट्रीयता के विकास का मूलम भेद किसने किया है? साधारण पाठक इस भेद का समझ भी नहीं सकते। हिन्दू जातीयता हिन्दी-भाषी क्षेत्र तक सीमित थी, इसके प्रचारक प्रसारक मूरदास और तुलसीदास थे। खड़ी बोली सारे भारत में फैल गई, वह हिन्दुओं की नयी भारतव्यापी राष्ट्रीयता का चेतक हुई। इसलिए लिखा कि पहले हिन्दू जातीयता, तदनन्तर हिन्दू राष्ट्रीयता

का विकास हुआ। यदि यह व्याख्या गलत हो तो भाई शिवदानसिंह उसे दुरुस्त करके अपनी व्याख्या प्रस्तुत कर दें।

लेकिन 'अपभ्रंशों की अन्य भाषाओं' से उनका क्या तात्पर्य है, यह मैं बहुत कोशिश करने पर भी नहीं समझ पाया। खैर, अर्थ जो कुछ भी हो, "अपभ्रंशों की अन्य भाषाओं के प्राचीन साहित्य को अपना प्राचीन साहित्य"—यह टुकड़ा अपनी 'ध्वनि-योजना' में निश्चय ही हिन्दू राष्ट्रवादी है!

हिन्दी-साहित्य के इतिहासकारों ने ज्यादातर भारतीय साहित्य, भारतीय संस्कृति की बात की है। चौहान ने भारतीय शब्द की व्याख्या करके उसका तात्त्विक अर्थ स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने लिखा है—"आधुनिक हिन्दी के साहित्य के यदि सभी अंग-उपांगों का निरीक्षण करें (कितना धैर्य चाहिए इस कार्य के लिए! सराहिये उस मर्मभेदी दृष्टि को जो अंगों ही नहीं, उपांगों तक का निरीक्षण कर लेती है!) तो उससे निर्विवाद सिद्ध हो जायगा कि हिन्दी साहित्य में भारतीय साहित्य, संस्कृति, विचारधारा तथा राष्ट्रीयता आदि जिन शब्दों के आगे 'भारतीय' विशेषण निर्वाध प्रयोग होता है वह वास्तव में मुसलमानों के योग से विकसित एक संयुक्त अखिल भारतीय संस्कृति अथवा विचार-धारा का द्योतन नहीं करता। इन प्रयोगों में 'भारतीय' केवल हिन्दू-आर्य संस्कृति और हिन्दू राष्ट्रीयता का अर्थवाची है।"

भाषाविज्ञान और समाजशास्त्र दोनों ही की दृष्टि से श्री चौहान की यह खोज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है कि हिन्दी लेखक भारतीय शब्द का प्रयोग उसी अर्थ में करते हैं जिसमें भारतीय जनसंघ के नेता करते हैं।

जिन निर्गुणपंथी सन्तों के बारे में चौहानजी की राय है कि उन्होंने [हिन्दू-मुस्लिम संस्कृतियों का मेल किया था, उनके लिए हजारीप्रसाद द्विवेदीजी ने लिखा है कि उनके काव्य की बाहरी रूपरेखा 'सम्पूर्णतः भारतीय' है ('हिन्दी साहित्य की भूमिका', पृ० ३१)। गायद उनका मतलब है कि बाहर से पूरे हिन्दू हैं, भीतर से आधे मुसलमान। लेकिन उसी वाक्य में बौद्धों को भी लाकर 'भारतीय' के विशुद्ध अर्थ को खंडित कर दिया है—बौद्ध धर्म के अन्तिम सिद्धों और नाथपंथी योगियों के पदादि से उसका सीधा सम्बन्ध है।"

'काव्य में प्राकृतिक दृश्य' नाम के अपने निबन्ध में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा था, "आजकल के पाकों में हम भारतीय आदर्श की छाया देखते हैं।" अर्थात् ये पाक हिन्दू हैं, मुस्लिम नहीं।

श्री हरिशंकर शर्मा ने उर्दू-साहित्य के इतिहास में जीण मलीहाबादी की राष्ट्रीय कविताओं का उल्लेख किया है; श्री गोपीनाथ अमन ने 'उर्दू और उसका साहित्य' में चकवस्त की राष्ट्रीय कविताओं की चर्चा की है। चकवस्त तो हिन्दू थे ही, जोश भी कुछ समय के लिए हिन्दू राष्ट्रीयता के गीत गाने लगे, वरना आर्यसमाजी विद्वान् श्री हरिशंकर शर्मा उनकी राष्ट्रीयता की प्रशंसा कैसे करते।

फिराक साहब ने उर्दू की प्रगतिशील कविताओं के संग्रह 'जंजीरें टूटती हैं' की

भूमिका में इनके रचयिताओं के लिए दावा किया है कि "आदिकाल से अब तक की भारतीय सस्कृति उनकी जागीर है।" चूंकि यह जागीर हिन्दुओं की है, इसलिए फिराक गारखपुरी का तो उसमें यादा-बहुत हिस्सा हो भी सकता है, लेकिन मलदम मुह्रीउद्दीन, गही मायूम रजा बाभिक जौनपुरी, अली सरदार जाफरी बगैरह भी हिस्सेदार हो जायें, यह बात वर्जित नहीं की जा सकती।

बगानिया ने शांदा का जर्ज जवाब भ्रष्ट कर दिया है। प्राचीन सस्कृति के मयमें बड़े जागीरदार श्री रवी इनाथ ठाकुर ने बबीर, नानक, दादू आदि का पहले तो भारतीय राष्ट्रकृता, फिर उनका सम्बन्ध राममोहन राय में जाड़ा, राममोहन राय का सम्बन्ध आधुनिक साहित्य में जोड़कर हिन्दू-मुस्लिम विकास के नाम पर इतिहास का ही सत्यानाश कर दिया। (दखिए दादू बन्यावसी की भूमिका)

भारत के आधुनिक विकास की विशेषता क्या है? श्री चौहान कहते हैं, "बस्तुतः हमारा देश के ऐतिहासिक विकास का ही यह विशिष्टता है कि राष्ट्रीय चेतना ने हिन्दू राष्ट्रीयता और मुस्लिम राष्ट्रवादिता का रूप ग्रहण किया।"

जिसे राष्ट्रवादी लोग साम्प्रदायिकता कहते थे, वही मजबूती राष्ट्रीयता है, जिसे वह राष्ट्रीयता कहते थे, वह 'पाँच-सान मौ वय के ऐतिहासिक जीवन की स्मृतियाँ तक की उमूलन करने की अममभव चेष्टा' है।

हिन्दुओं और मुसलमानों की एक राष्ट्रीयता? अममभव! यह साम्प्रदायवाद है, जननत्र की हत्या है। उदार जनवादी दृष्टि से विचार कीजिए तो पता चल जाएगा कि इस 'वैत का स्थापित प्रदान करने में जंगेजी शासन का भी हाथ भले गहा हो, "राष्ट्रीय जागरण ने इस भेद चेतन्य को और भी निखारा है।" चेतन्य महाप्रभु के बाद गौरांग महाप्रभु की कृपा से ये नये भेद चेतन्यजी प्रकट हुए।

इन भेद चेतन्यजी के प्रकट होने का फल यह हुआ कि एक ओर हिन्दू सस्कृति का प्रतिबिम्बित करनेवाला हिन्दी साहित्य विकसित हुआ, उसी तरह मुस्लिम सस्कृति को प्रतिबिम्बित करनेवाला उर्दू-साहित्य भी सर्वाङ्गित हुआ।

"हिन्दी (सम्पूतनिष्ठ साहित्यिक बोली) के समानांतर (अरबी-फारसीनिष्ठ साहित्यिक खड़ी बोली) का विकास मुस्लिम सस्कृति के प्रभाव में हुआ।"

सस्कृति के शब्द आर्य हिन्दू है, फारसी के शब्द मुसलमान हैं, इसलिये जहाँ सस्कृति के शब्द ज्यादा हा वहाँ हिन्दू सस्कृति जीनी, जहाँ अरबी फारसी के शब्द ज्यादा हों वहाँ इस्लाम जीता।

"राष्ट्रीय जाग्रति के साथ-साथ हिन्दी और उर्दू का भेद और भी बढ़ गया।" पहले प्रगतिशील लेखक यह भेद दखन परेसान होते थे, उसे दूर करने की कोशिश करने थे। चौहान ने बताया कि परेगानी की कोई बात नहीं है, "दोनों भाषाओं ने अपनी प्रकृति के अनुकूल पर्याप्त विकास किया" और "राष्ट्रीय जाग्रति के बिना इन दोनों भाषाओं का ऐसा अपूर्व विकास अममभव होना।"

इस राष्ट्रीय जाग्रति से शायद गांधीजी का भी कुछ सम्बन्ध था। उन्होंने जीवन-भर प्रयत्न किया कि यह भेद मिटे और हिन्दी-उर्दू एक-दूसरे के नजदीक आएँ। वे हिन्दू-मुसलमानों तथा हिन्दी-उर्दू के भेदभाव से क्षुब्ध थे। इसका कारण यह था कि उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आधुनिक इतिहास को समझा न था, उसका निर्माण भले ही किया हो। श्री चौहान के शब्दों में “हिन्दी और उर्दू के स्वतन्त्र विकास से केवल ऐसे ही लोग विशुद्ध हैं जो अपने अनैतिहासिक दृष्टिकोण और इस बद्धमूल धारणा के कारण कि हिन्दू-मुस्लिम एकता अथवा समस्त भारत की अखंडता के लिए एक ही राष्ट्रभाषा का होना अनिवार्य है, भारत की विविष्ट वस्तुस्थिति को समझ नहीं पाते।”

यह हुई विशुद्ध समाजशास्त्र की बात। आप पूछ सकते हैं, किसी भाषा के शब्द-भण्डार या व्याकरण-व्यवस्था ने धर्म का क्या सम्बन्ध है। आप न जानते होंगे कि मराठी के तमाम ईसाइयों की भाषाओं का व्याकरण एक-सा है, तनाम मुसलमानों की भाषाओं का व्याकरण एक-सा है। जब इस्लाम भारत में आया तो उसने न केवल यहाँ की भाषाओं के शब्द-भण्डार में भारी उथल-पुथल की, उसने इन भाषाओं के व्याकरण में भी राष्ट्रीय और जनवादी क्रान्ति कर दी।

चौहान ने लिखा—“हिन्दी और उर्दू की भिन्नता केवल शब्दों के संस्कृत या फारसी प्रयोग तक ही सीमित नहीं है। उनके व्याकरण, पिगल वाक्य-विन्यास आदि में भी मौलिक भेद उत्पन्न हो गया है।” विलुप्त शब्द तो दोनों में होते ही हैं, “परन्तु इससे भी अधिक खड़ी बोली के व्याकरण का शुद्ध पालन न हिन्दी में किया जाता है, न उर्दू में। हिन्दी व्याकरण पर संस्कृत व्याकरण का प्रभाव स्पष्ट लक्षित है और उर्दू व्याकरण पर फारसी और अरबी व्याकरण की गहरी छाप पड़ गई है।”

सम्भवतः अरबी और फारसी—दो भिन्न कुलों की भाषाओं—का व्याकरण एक-सा है क्योंकि दोनों का प्रभाव मुसलमानों की खड़ी बोली पर पड़ा है। आश्चर्य की बात है कि मराठी, हिन्दी और बँगला—तीनों के व्याकरण पर संस्कृत का प्रभाव पड़ा लेकिन मराठी में तीन लिंग हैं, हिन्दी में दो, बँगला में एक भी नहीं। गम्भीरता से विचार कीजिए तो आपको ज्ञान हो जायगा कि मराठी पर संस्कृत का प्रभाव सबसे ज्यादा है, इसलिए उसके बोलनेवाले सब हिन्दू हैं या हिन्दू राष्ट्रवादी हैं; हिन्दी में दो ही लिंग हैं, इसलिए यहाँ हिन्दुत्व कमजोर रहा, मुसलमान हिन्दू राष्ट्रवादी न हुए, उल्टा अपना राष्ट्रवाद विकसित करते रहे। बँगला में एक भी लिंग नहीं, संस्कृत का प्रभाव सबसे कम, इसलिए बंगाल के दो टुकड़े हो गए !

यहाँ तक तो हुई भूत और वर्तमान की बात।

अब लीजिए भविष्य की बात। चौहानजी ने गुरुजी को समझाया कि आप यह भ्रम त्याग दीजिए कि भविष्य में कभी हिन्दी-उर्दू मिलकर एक हो जाएँगी। “यह कहना कि राष्ट्रीय भावना ज्यों-ज्यों व्यापक होती जाएगी त्यों-त्यों हिन्दी-उर्दू का भेद कम होता जाएगा, केवल भ्रान्त धारणा है। यथार्थ सत्य तो यह है कि ज्यों-ज्यों राष्ट्रीय भावना व्यापक



होनी गई है, दोनों भाषाओं के पृथक् विकास की गति भी उतनी ही तीव्र होनी गई है।"

अन्त में समाधान यह रहा कि "मुस्लिम प्रधान प्रांतों में राजकीय कार्यों में उर्दू भाषा का प्रयोग होगा," उसी प्रकार "मध्यदेश (हिन्दू-प्रधान प्रान्तों) में राजकीय कार्यों में हिन्दी भाषा का प्रयोग होगा।" दोनों दलों को वे अल्पसंख्यक अपनी-अपनी भाषा का व्यवहार भी कर सकेंगे। चौहानजी यह मानकर चले थे कि पूर्वी बंगाल के मुसलमान उर्दू का व्यवहार करने की बहुत उन्मुख हैं। हिन्दू भारत में एक द्रविड़ प्रदेश है। उसके बारे में वह अधिक सतर्क थे। उन्होंने जबरन राष्ट्रभाषा लागू का विरोध करते हुए सुझाया—“सम्भव है कि वे अपनी ही किसी भाषा को अपने प्रान्तों की राष्ट्रभाषा बना लें।” इस तरह भाषा-समस्या का जनवादी समाधान यह हुआ कि द्रविड़ प्रान्तों की अपनी राष्ट्रभाषा, मुस्लिम प्रान्तों की राष्ट्रभाषा उर्दू द्रविड़ों में भिन्न आर्य-हिन्दू भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी। तीन राष्ट्र और राष्ट्रभाषाएँ।

यह तो राष्ट्रभाषा की समस्या का समाधान हुआ। हिन्दी प्रान्तों की एक विशेष समस्या को और भी उन्होंने ध्यान आकृष्ट किया। हिन्दी प्रान्तों में “लगभग बीस भाषाएँ और बड़ी बोलियाँ बोली जाती हैं।” इनके आधार पर “हिन्दी प्रान्तों का भी पुनर्विभाजन करना होगा।” इस तरह हिन्दीभाषी प्रदेश को मिलाने के बख्ते चौहानजी ने बीस नये प्रान्त बनाने की सलाह दी।

‘जनपदीय भाषाओं का प्रान’ नाम के लम्बे निबन्ध में उन्होंने राहुलजी की राष्ट्रभाषा सम्बन्धी मान्यताओं को और भी संवारकर पेश किया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने अंग्रेजी को अनिवार्य राजभाषा बनाकर यहाँ की भाषाओं का दमन किस तरह किया, इसका विवेचन न करके, साम्राज्यवाद की भूमिका को भुलाकर श्री शिवदानमिह ने खड़ी बोली हिन्दी के साम्राज्यवाद पर आक्रमण किया। यह साम्राज्यवाद हिन्दी क्षेत्र की बोलियों का दमन कर रहा था।

उन्होंने लिखा, “अकेली खड़ी (हिन्दी उर्दू) ने लगभग पंद्रह करोड़ बयामी लाख व्यक्तियों को अपनी मातृभाषाओं में शिक्षा पाने से वंचित कर रखा है। इससे सिद्ध है कि भारत भी ‘भाषाओं का विनाश कारागार’ है।”

भारत कारागार ब्रिटिश साम्राज्य के कारण नहीं है, यहाँ की भाषाएँ अंग्रेजी के कारण कारागार में बन्दी नहीं हैं, उन्हें कारागार में डाँसा है खड़ी बोली ने।

भारत को उपनिवेश ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने नहीं बनाया, यहाँ उपनिवेश कायम किये हैं हिन्दी साम्राज्य ने।

चौहान अपने अद्भुत भाषाशास्त्र की दृष्टि “हिन्दी-साम्राज्य के विभिन्न भाषा-उपनिवेशों को आन्तरिक परिस्थिति पर” डालते हैं। वह इन ननोज पर पहुँचने हैं, ‘हिन्दी का वर्तमान साम्राज्य ‘ताश के घर’ से अधिक मजबूत नहीं है।’ बोलियों के उपनिवेश टूट जाएँगे, फिर खड़ी बोली को अपने साम्राज्य का परिवर्ती हिन्दी के क्षेत्र में भी विघटन करके अपने जनपद से ही संतुष्ट करना पड़ेगा।”

चौहान का विचार था कि अंग्रेजों और अंग्रेजी का साम्राज्य चाहे वाद में खत्म हो, हिन्दी का साम्राज्य पराधीन भारत में ही खत्म हो जाना चाहिए। “यदि वर्तमान आधार को हटाकर न्याय, समानता और स्वतन्त्रता का नया आधार न प्रदान किया गया तो भारत के स्वतन्त्र होने पर हिन्दी के साम्राज्य को दहते देर न लगेगी।”

भारत स्वतन्त्र हो गया; हिन्दी का ‘साम्राज्य’ न उठा। बोलियों के उपनिवेश न दूटे। हिन्दी प्रान्तों में नये बीस प्रान्त न बने। इसलिए अठारह साल तक हिन्दी-साम्राज्य के टूटने की राह देखने के बाद चौहानजी ने स्वयं शस्त्र उठाये और आलोचना न० ३४ (जुलाई, '६५; सितम्बर में प्रकाशित) में भारत की एकता के नाम पर इस साम्राज्य पर हल्ला बोल दिया।

चौहान के पहले के लेखों में जैसे अंग्रेजी का प्रभुत्व खत्म करने पर जोर नहीं है, वैसे ही इन लेख में अंग्रेजी को अनिवार्य राजभाषा के पद से हटाने का आग्रह नहीं है। श्री नज्माद जहीर ने आत्मनिर्णय के मिद्धान्त को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध, सारे देश की स्वाधीनता के लिए न लागू करके, उसे राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध, जनतन्त्र के नाम पर, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हित में लागू किया था। इस समय उन्हें उर्दू के संरक्षण की जितनी चिन्ता है, उतनी अंग्रेजी हटाने की नहीं। उन्हीं की तरह श्री चौहान ने उर्दू की रक्षा का नारा लगाया है लेकिन वह दूसरों की स्थापनाओं को दोहराते-भर नहीं हैं। वह योग्य शिष्य हैं, इस नाते उन्होंने आत्मनिर्णय का अधिकार हिन्दी के उपनिवेशों पर लागू किया है !

अब, दुन्देलखण्ड, ब्रज, भोजपुरी क्षेत्रों के जो लेखक हिन्दी को अपनी मातृभाषा कहते हैं, उनकी निन्दा करते हुए श्री चौहान ने प्रश्न किया है कि जब अंग्रेजी में साहित्य रचनेवाले मुल्कराज आनन्द, भवानी भट्टाचार्य, और के० नारायणन अंग्रेजी को अपनी मातृभाषा नहीं कहते, तब प्रेमचन्द, प्रसाद, निराला, वृन्दावनलाल वर्मा, रामचन्द्र शुक्ल ही हिन्दी को अपनी मातृभाषा क्यों कहें ? हिन्दी साहित्य का सारा इतिहास चौहानजी को विवृत दिखाई देता है; इसके रचनेवालों की मातृभाषा हिन्दी थी ही नहीं, जैसे मुल्कराज आनन्द और भवानी भट्टाचार्य की मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है। यशपालजी की मातृभाषा हिन्दी नहीं है। “इस दृष्टि से उनकी और डा० मुल्कराज आनन्द की स्थिति में विशेष फर्क नहीं है। यह बात भारतेन्दु से लेकर मोहन राकेश तक की नई पीढ़ी के निन्यानवे फी सदी हिन्दी लेखकों और हिन्दी-आन्दोलन के मुभट योद्धाओं के बारे में भी सच है।”

मुल्कराज और यशपाल की स्थिति में विशेष फर्क न हो, थोड़ा बहुत फर्क तो है ही। चौहान हिन्दी के निन्यानवे फी सदी लेखकों को मातृभाषा कहते हैं क्योंकि उनकी समझ में इन लेखकों की मातृभाषा हिन्दी नहीं है। लेकिन अंग्रेजी में उपन्यास-कहानियाँ लिखनेवाले मुल्कराज आनन्द को मातृभाषा कहने का साहस उनमें नहीं है। कारण, इससे विश्वभाषा अंग्रेजी के प्रति संकीर्णता प्रकट होती है और ‘एफ्रो-एशियन-सौलिडैरिटी’ को घक्का लगता है। भारत में इस सौलिडैरिटी के तीन स्तम्भ हैं—मुल्कराज आनन्द,

सदस सम्झाद जगैर आर निवदानमिह खोजन ।

भारतेश्वर से लेकर मोहन रावेंग तक हिन्दी के निजानने की गदीसंगव अपनी मानुभाषाएँ छोड़कर हिन्दी की सेवा क्यों करने रहे हैं ? अर्थ और मंगल-मार्ग के लिए । देशभक्त बनने का गुन धर्म में । इत मानुभाषानिया में मानुभाषाओं की रक्षा करने के लिए लड़न लवर उठ गये हुए हैं, श्री निवदानमिह खोजन ।

जनानिवाना की हाड में सभी भाषनीय संलका को पछानने हुए उन्होंने लिखा है "जात्र की हिन्दी" हम मुबन अपनी मानुभाषाओं का रसामकर स्त्रनों में लिखाश में हो सीसी-मही है, जिस तरह अचेडी रकून में लिताबो में सीसी-मही है । इसे आप क्या पहन, मानुषात या बुद्ध और, मैं यह तो नहीं जानता, बराबर अब हम बोपा ने निशावर में प्रवण किया उस समय हिन्दी या उद के जगावा अपनी मानुभाषाओं में पढ़ने का कोई विवरण ही नहीं था । जात्र भी नहीं है । लेकिन यह सब है कि एक समय जो विवगता यो वह बालिग हाथ पर अब और दशानन और देशभक्ति के रूप में प्रगति प्राप्त का नम्र्या साबित हुई, हमारा अपनी मानुभाषाओं के प्रति अपना बतबर मुता देना ही हम सबके आगे सबके मुदिपावनक नाम था ।"

मुबन का भूग गाम को घर मोट आए तो उस भूना हुआ नहीं रहने । चांगन अब गमनक गए हैं कि अब और मंग के लिए हिन्दी-मंग्य करना अनुचित है । उन्होंने स्वयं जाड़ी मंग अजिन कर लिया है, अब भी 'आमोचना' में ऐसा क्या मिलना होता ? उन्हें चाहिए कि वह हिन्दी के मानुषानी लमका के गामन अपने रपाग से एक मिमान काम करें । अब उन्हें जिन्ने दिलना बाद कर देना चाहिए और बिन्दी के बाकी दिन मानुभाषा की सेवा में लगाने चाहिए । मममवन उनकी मानुभाषा बज है, उमकी सेवा करें । जमी तक उनका कोई नैन, कोई पुस्तक बजभाषा म लिपी हूँ देखने को नहीं मिली । बज-भाषा में अपनी गतिधिव प्रतिभा का परिचय देकर वह बज और हिन्दी दोनों का उपहार करेंगे । मानुभाषा बज न हो तो जो भी मानुभाषा हा, उसकी सेवा करें । उनके पिताजी न एक बार आरा में दान दिए थे । पुनिम के आदनी म । उन्होंने अरुत पुत्रा की खर्चा करने हुए बहुत मुहारदेदार मडी बोली का व्यवहार किया था । उनके पारप्रवाह बाक्य मुझे अभी तक याद हैं मरुति उन्हें निगवर प्रकाशित करने का गहन मुन्में नहीं है । यह हाल मवान मानुभाषा का है, पितृभाषा का नहीं ।

प्रायद ने ईडीएम काम्प्लेक्स ईजाद करके सभी किशोरा और पितृभाषा को सम्भाव्य पित्राणी गिद कर दिया था । निवदानमिहजी ने पितृभाषा की घान पुरानी पढ जाने से उसे दशपवर अधिक वतानिह इस मानुषानी काम्प्लेक्स का आविष्कार किया है । अब देखिए, इसने कैसे अटिस ग्रथिया लोका के मन में पढ जाती हैं ।

कहते हैं, 'अपनी मानुभाषाओं के प्रति अपनी उमेधा की हम मानुषात कह या नहीं, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि हिन्दी के संलक और आन्दोलन-कारी नेताओं के अलमन में कही कोई अपराध-भावना की ग्रन्थि जहर पढ गई है, जिसके

कारण वे अपने अपराध पर परदा डालने के लिए इतिहास को तोड़-मरोड़कर यह मिट्ट करने की कोशिश करते रहते हैं कि मैथिली, राजस्थानी, अवधी, ब्रज आदि वस्तुतः स्वतन्त्र भाषाएँ नहीं हैं, 'हिन्दी' (नरतुनिष्ठ साहित्यिक गड़ी बोली) की ही स्थानीय बोनियाँ हैं और जनगणना आदि के मौकों पर हिन्दी-प्रचारक और जनसंघ के अन्व-हिन्दू राष्ट्रवाद से प्रभावित नरनारी अमना इन भाषाओं को बोलनेवाली जनता पर दबाव डालते हैं कि वे मातृभाषा के गाने में राजस्थानी या मैथिली न लिखवाकर 'हिन्दी' लिखवाएँ, यानी वे उत्तर भारत की समूची जनता को अपने 'अपराध' में साक्षीदार बना लेना चाहते हैं।"

इस अपराध-भावना से वे नरक मुक्त हैं जिन्होंने गड़ी बोली के उर्दू रूप को अपनाया है। खड़ी बोली यदि मातृभाषा है तो उर्दू-रूप में, हिन्दी-रूप में नहीं ! यह नयी मान्यता है जो श्रीचौहान के पुराने निबन्धों की मान्यता से बहुत आगे बढ़ गई है। अब उन्होंने सीधे-सीधे उर्दू को मुस्लिम राष्ट्रवाद की भाषा कहना छोड़ दिया है; अब वे हिन्दी का ही सम्बन्ध हिन्दू राष्ट्रवाद से जोड़ते हैं। उर्दू हिन्दुओं और मुसलमानों की मुक्तकाँ उवान है !

लिखा है, "माँ के घुटनों पर बैठकर हम में ने किसी ने 'हिन्दी' नहीं सीखी जिस तरह कि अधिक पुरानी 'मैली' (!) उर्दू को दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद अनेक सांस्कृतिक क्षेत्रों के बच्चे हजारों हिन्दू और मुसलमान परिवारों में पुस्त-दर-पुस्त से अपनी माताओं की गोद में ही सीखते आए हैं।

क्या कारण है कि दिल्ली, लखनऊ और हैदराबाद के हिन्दू-मुसलमान तो पुस्त-दर-पुस्त अपनी माताओं की गोद में ही उर्दू सीखते आए हैं लेकिन इलाहाबाद, बनारस और पटना के हिन्दू-मुसलमान अपनी माँ की गोद में हिन्दी नहीं सीख पाए ? कारण यह है कि चौहान की ममक में उर्दू मुख्यतः मुसलमानों की भाषा है; दिल्ली, लखनऊ और हैदराबाद में मुसलमान काफ़ी बड़ी संख्या में हैं; बनारस, पटना और इलाहाबाद में वे इतनी बड़ी संख्या में नहीं हैं, इसलिए खड़ी बोली के प्रसार का एक नियम लागू होता है मुस्लिम-प्रधान शहरों में, दूसरा नियम लागू होता है हिन्दू-प्रधान शहरों में। इस कारण खड़ी बोली का उर्दू-रूप तो मातृभाषा है, उसका हिन्दी-रूप नहीं है ! शिवदानसिंह चौहान ने भाषाओं का विभाजन फिर उसी पुराने साम्प्रदायिक आधार पर किया है। उनके जनताधिक आडम्बर के नीचे वही साम्प्रदायिकता का चोर छिपा हुआ है।

यदि यह मान भी लें कि दिल्ली, लखनऊ और हैदराबाद के हिन्दुओं और मुसलमानों की मातृभाषा उर्दू है, तो भी यह बात साफ़ नहीं होती कि चौहान उर्दू के उन तमाम लेखकों को मातृभाषी क्यों नहीं कहते जो इन शहरों से दूर ब्रज, अवध, पंजाब या भोजपुरी क्षेत्रों के रहनेवाले थे। उर्दू के दो सबसे बड़े शायर ग़ालिब और मीर आगरा में पैदा हुए थे। सौदा के वाप ईरानी थे। इक़बाल पंजाबी थे। साहिर लुधियानवी, हफीज जालन्धरी, जोश मलसियानी, जगन्नाथ आज़ाद, अहमद नदीम कासिमी, फैज़, राजेन्द्र-

निहृ देवी, दुःख भाङ्ग आदि नवावी है। य सब मानुषार्थी है या भरी ? जोंग मरीहवादी, निम्न भाग्यवर्ती, मज्जन्त मुग्धवर्ती, कानि बडावर्ती इतद अनीमावादी, अद्वय इमाहावादी वगैर मानुषार्थी क्या नहीं है ?

दरअंगत बीजान अग्रही और उरवाता के मानन गर्भो निपोरने हैं, अर्ध और  
मनवाय व निष्ठ नहा, निष्ठुद जननन की रणा व निष्ठ, निष्ठुवायो परदुरनि है वराणि  
निष्ठ पजन म माना, उनी म एत वरणा उरकी ग्यावनिमता का मरने बदा प्रमाण होता।  
ग्यानि मानननु म मकर मानन गद्या लक के निष्ठु-मगरों व। बीजने म उरु वरा  
नी निष्ठु नहा। हानी, मेविन उरु बीजान और ग्यानि व निष्ठु वर निष्ठु-वायो दुमद  
करा मरु हैं।

उह यह नहीं मानूँ कि उहूँ के बहुत से मेमबर आज भी अजब परों में अकली ज़ा नज़रों बोलते हैं। उह नहीं मानूँ कि उहूँ के बहुत से कविता की भाषा पर कदाभी बोलिया का प्रभाव पड़ा है। उह प्रभाव तबीर की कविताओं में सबसे बड़ा स्पष्ट है। उहें यह ना बकर मानव हाथा कि उहूँ के पदावी मेमबर आजग में पदावी बोलते हैं। पदाव, अकल और बज ब उहूँ मेमबर का निहाय दीनार, तीन बीदाई उहूँ-माहिद का मन्दा हा जगगा। बीदा का यह नहीं मानूँ कि हैरावार में हिदुओं और मुसलमानों की ज़ा बोलबाल की भाषा है, बहूँ पुगगी मही बाली का यह नर है जिन उतर मानव क मांग दाई में अजब माय व माय में और जिन पर मराठी-नेतु माहि भाषा का प्रभाव पड़ा है।

बापवान की दृष्टि में 'ब्रह्मना तदा', 'तामई च नरो मेने', 'साइ नो ब्रह्मने' आदि जैसे प्रयोग होते हैं। (इति) योगमार्गों का मतभेद 'इति' शब्दों का अर्थ और पद, पृ० ४४६)। हैदराबादी बापु ने 'क' की जगह 'ग' की बोलनी है, इनके बीच में लगी लकीरें लगाए हैं। बोलाने की इन सब बातों में अंतर है। 'उल्टा चार बोलवान की लकीरें' की मूल्य परीक्षा करने हुए पता चलता है, 'इक कोई व्यक्ति, वह या समुदाय जीवों की सामूहिक परिस्थिति का मुनी अंगों में रहने में असमर्थ हो जाता है और इन तरह की असमर्थ स्थिति परिकल्पना गृह्यते उनमें से जीवन-सामर्थ्य का देखने लगता है, तब उसमें भक्ति, विवेक और जोश की अभाव नहीं की जा सकती।'

वास्तविक परिस्थिति क्या है ? हैदराबाद में लोगों की मानचान की इज्जत शिन्नी की उर्दू है या उग्रे भित्त दक्की ? उर्दू के पत्राबी सभकों की घर की भाषा उर्दू है ? मलीहाबाद अजमाबाद, गारगपुर, इलाहाबाद के भाषा की दीनमान की भाषा माहिियत उर्दू है ? तथ्या में कीन भास चराना है ?

वास्तविक स्थिति यह है कि हर भाषा की अपनी शानियाँ होती हैं। जपेजी, फ्रांसीसी, रूसी की तरह बंगला, मराठी, हिन्दी, तमिल आदि भाषाओं की भी अपनी शानियाँ हैं। इस सार में कहा हो सकती है कि कोई बोली स्वतन्त्र भाषा है या धोनी, लेकिन किसी भाषा की शानियाँ हो न हो, ऐसा नहीं होता। पंजीबाद के विचार के साथ

हिन्दी-भाषी जाति के विकास और गठन में दिल्ली, आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद और पटना मुख्य सांस्कृतिक केन्द्र बने। यहाँ खड़ी बोली का प्रसार हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों ने किया। इनकी बोलचाल की भाषा में धार्मिक आधार पर कोई फर्क नहीं है। साथ ही इन शहरों के बहुत से हिन्दू और मुसलमान अपने घरों में खड़ी बोली से भिन्न अपनी पुरानी बोली का भी व्यवहार करते रहे हैं। इसलिए यह कहना कि उर्दू तो मातृ-भाषा है, हिन्दी नहीं है, ग़लत है। दिल्ली, आगरा, लखनऊ आदि शहरों में हज़ारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने माँ की गोद में खड़ी बोली सीखी है और हज़ारों ऐसे हैं जिन्होंने मोहल्ले के दोस्तों से खड़ी बोली सीखी है। कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत कोशिश करने पर भी खड़ी बोली नहीं सीख पाए, न उसका हिन्दी रूप, न उर्दू रूप।

अहिन्दी प्रदेशों में जो लोग हिन्दी के विरोधी हैं, वे यह तर्क देते हैं कि हिन्दी कृत्रिम भाषा है। उसकी कृत्रिमता सिद्ध करने के लिए वे हिन्दी की बोलियों का हवाला देते हैं, उन्हें स्वतन्त्र भाषाएँ कहकर हिन्दी को साम्राज्यवादी उत्पीड़क भाषा मानते हैं। यदि कोई हिन्दी-प्रेमी मराठी, बँगला या तमिल के लिए कहे कि वे हिन्दी की बोलियाँ हैं, या यह कि भारत में एक राष्ट्रभाषा रहेगी, और सब भाषाएँ मिटा दी जाएँगी, तो यह जरूर साम्राज्यवादी उत्पीड़न की बात होगी। लेकिन लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली में जो लोग मेहनत-मजदूरी करने आते हैं, वे खड़ीबोली का व्यवहार न करें ताँ वे मौत मरें। दिल्ली और कानपुर के सूती मिल-मजदूर खड़ी बोली का व्यवहार न करे तो

उनका टूट धूलिघन आदोलन ठप हो जाय। मजदूर वर्ग को अपने संगठन के लिए जातीय भाषा की जरूरत होती है जो असंग्रसंग बोलियाँ बोलनेवाले मजदूरों को एकजुट करे। चौहान के भावमवाद में मजदूर वर्ग को स्थान नहीं है। यदि हो तो एक भी भिन्न, एक भी कारखाने, एक भी उद्योग का नाम बतान की कृपा करें जहाँ सिर्फ़ मैथिली, सिर्फ़ भाजपुरी, सिर्फ़ अवधी या अन्य कोई जनपदीय बोली बोलनेवाले ही काम करने हो।

चौहान ने कुण्ठित समाजशास्त्र की काफी निंदा की है। लेकिन उनके कुम्हारोंन विमुक्त समाजशास्त्र में कहीं धूँजीवासी विकास के अन्तर्गत नये विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जनपदा में एकत्र होनवाले मध्यम और धार्मिक वर्गों का उल्लेख नहीं है।

जातीय भाषा का प्रसार सामाजिक विकास का परिणाम है, इसलिए उमरा विभाजन धर्म के आधार पर नहीं होना। भारतीय बुद्धिजीवियों पर अंग्रेज़ी का प्रभाव है, वे 'मिथिक' परिवर्तनवादी की बात करते हैं, अंग्रेज़ी शब्दों और मुहावरों का गहन अनुवाद करते अपनी हिन्दी को मजाते हैं (जैसे 'कौन्सिली' के लिए 'कीमती' शब्द का व्यवहार—“कीमती किन्तु अनुपयोगी प्रयोग”, “यह प्रयोग शायद बहुत कीमती भी मानिन हो।”) तो इसका अर्थ यह नहीं होना कि वे ईसाई हो गए हैं या उन पर ईसाइयन का प्रभाव है। बानबान की लड़ी बोली में हिन्दू और मुसलमान साधारणजन अरबी-फारसी या मरुहल के कटिन शब्दों का व्यवहार नहीं करते। यह है बुनियादी बात। यहाँ धर्म के आधार पर कोई विभाजन नहीं है। लोग फारसी या मरुहल के शब्दों का स्वयंसा प्रयोग करते हैं तो इसका प्रधान कारण सांस्कृतिक है, धार्मिक नहीं।

उस विनाश क्षेत्र में, जिसके नगरी के हिन्दू और मुसलमान, विभिन्न जनपदा से आये हुए मजदूर और नौकरीपेसा लोग, शिष्ट भाषा के रूप में लड़ी बोली का व्यवहार करने हैं, सभी की जाति, वर्ग या नेशन एक है, वहाँ दम या पट्टे प्रान्त बनाने की बात करना हिन्दीभाषी जनता को जातीय एकता का तोड़ने का प्रयास करना है। इस क्षेत्र की बोलचाल की भाषा में हिन्दी-उर्दू का भेद नहीं है, इसलिए उन्हें क्षेत्रीय भाषा कहना गलत है। यदि बोलचाल को उर्दू और हिन्दी में एक ही बन-कारखाने में काम करने-वाले मजदूर भेद करने तो उर्दू को क्षेत्रीय भाषा मानना उचित होना। लेकिन आम जनता बोलचाल में ऐसा कोई भेद नहीं करती। यह भेद शिष्ट भाषा के रूप और निधि को लेकर है। अधिकांश जनता देवनागरी लिपि का व्यवहार करती है और शिष्ट भाषा के लिए अधिकतर शब्द मरुहल से लेती है। एक अल्पमध्यम समुदाय ऐसा है जो फारसी लिपि का व्यवहार करता है और अपनी शिष्ट भाषा में अरबी-फारसी से शब्द लेता है। इस समुदाय में मुसलमानों के साथ हिन्दू भी हैं, इसलिए उसे सांस्कृतिक अल्पमत कहना चाहिए। इन सांस्कृतिक अल्पमध्यमों की भावनाओं का आदर करते हुए उनकी लिपि और शिष्ट भाषा की रक्षा करना चाहिए लेकिन हमका यह अर्थ नहीं है कि हम दो कौमा के मिश्रण के आधार पर दो भाषाएँ स्वीकार कर लें। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ साहित्यिक उर्दू बोलचाल की भाषा हो या जहाँ उर्दू की बोलचाल का रूप वहीं की हिन्दी के

बोलचाल के रूप से भिन्न हो। बोलचाल की खड़ी बोली के दो साहित्यिक रूप हैं—हिन्दी और उर्दू। उर्दू को हिन्दी की शैली कहने से बुरा लगता हो तो उसे खड़ी बोली की शैली कहिए, हिन्दी को भी खड़ी बोली की एक शैली कहिए। लेकिन सांस्कृतिक बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों का भेद याद रखिए। यह जान लीजिए कि बहुत से उर्दू लेखक और लेखिकाएँ—जिनमें श्रीमती रजिया सज्जाद जहीर भी हैं—अपनी रचनाएँ, उर्दू की इबारत में कोई फेर-बदल किये बिना, देवनागरी में छपवाती हैं। यह रिवाज बढ़ता जा रहा है कि प्रसिद्ध उर्दू लेखकों की रचनाएँ देवनागरी लिपि में पहले छपें, फारसी लिपि में बाद को। इससे हिन्दी-उर्दू साहित्य को देवनागरी के माध्यम से पढ़नेवालों की एक मिली-जुली जमात बनती है। यह जमात अपनी एकता, अपनी रूचि का असर लेखकों पर, उनकी हिन्दी-उर्दू शैली पर डालकर एक ही शैली के विकास में सहायक होती है। जो लोग दो कौमों के सिद्धान्त में विश्वास नहीं करते, वे इस एकता के नये सिलसिले से नृश होंगे।

राजपाल एण्ड सन्ज ने लोकप्रिय उर्दू गायरों की सिरिज निकालकर लाखों हिन्दी-भाषियों तक इनकी रचनाएँ पहुँचाई, उन्हें दरअसल लोकप्रिय गायर बनाया। इससे उर्दू का नाश नहीं हो गया। देवनागरी लिपि में 'उर्दू साहित्य', 'डगर' जैसे पत्र निकलते हैं जिनमें उर्दू की रचनाएँ देवनागरी लिपि में छपती हैं। ख्वाजा अहमद अब्बास और उनके साथियों ने 'सरगम' निकाला था जिसमें देवनागरी लिपि में सरल उर्दू रचनाएँ छपती थीं। हिन्दी 'ब्लिट्ज़' की भाषा, 'जनयुग' और 'आलोचना' से भिन्न आसान उर्दू होती है जिसमें बहुत थोड़े पारिभाषिक शब्द संस्कृत के होते हैं। इस तरह हिन्दी-भाषियों ने उर्दू को अपनाया है, उसका दमन नहीं किया। देवनागरी के माध्यम से उन लोगों तक उर्दू-साहित्य पहुँचा है जो पहले उससे कोसों दूर थे। जो लोग अपने को मार्क्सवादी कहते हैं, बोलचाल की भाषा और उसके साहित्यिक रूप में बुनियादी भेद नहीं मानते, उन्हें सांस्कृतिक विकास के इस सिलसिले से खुश होना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा मुहरंमी मूरतें वही लोग बनाये हुए हैं जो अपने को मार्क्सवादी लेखकों का रहनुमा समझते हैं। कोई भूख-हड़ताल की धमकी देता है तो कोई नक्शे देखकर वह इलाका तय करने में लगा है जहाँ हिन्दी से अलग लोगों की मातृभाषा उर्दू है। कुछ अन्य मित्र सांस्कृतिक बहुसंख्यक-अल्पसंख्यक का भेद न समझकर दिल्ली में या अन्य राज्यों में हिन्दी के बराबर उर्दू को राजभाषा बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। और इन सबमें कोई भी यह माँग नहीं करता कि भारत की सभी भाषाओं का दमन करनेवाली विदेशी भाषा अंग्रेजी का प्रभुत्व खत्म हो!

जहाँ तक राजस्थानी और पंजाबी का सम्बन्ध है, उनके लिखने-बोलनेवाले तय करें कि वे हिन्दी अपनाएँगे या पंजाबी-राजस्थानी का स्वतन्त्र विकास करेंगे। यदि उत्तर प्रदेश की सरकार या दिल्ली सरकार उन पर किसी तरह का दबाव डालेगी कि वे हिन्दी का ही व्यवहार करें, तो मैं इसका विरोध करूँगा। साथ ही उपेन्द्रनाथ अशक और यशपाल हिन्दी लिखते हैं तो मैं इसे मातृघात न कहूँगा।



हिन्दी भाषा जातीय विकास के परिणामस्वरूप विज्ञान हिन्दी क्षेत्र की भाषा बनी है। इस विकास को न समझने से आने-रू से लेकर मोहन रायस मर हिन्दी के मकड़ों लेकर साम्राज्यवादी या अवसरवादी दिखाई देने हैं। इस विज्ञान क्षेत्र में अंधविश्वास व दमन की बातें बहने हैं जो भारत में अंग्रेजों की राष्ट्रभाषा बनाये रखना चाहते हैं। अंग्रेजों की रक्षा उन 'जनता' की यह वृत्ति पहचान नहीं की जा सकती।

जैसे जने अंग्रेजों का हटाने का समय उबदीक आया वैसे-वैसे उद् के सरण की मांग भी जार पकड़नी गई। वेद की बात है कि कुछ गुप्तकालीन भाषावादी नेता हिन्दी पर उद् व दमन का अवगणन लगाकर 'सिंह' अंग्रेजों कायम रखन की नीति का प्रचार कर रहे हैं। उद् व सरण और उद् साहित्य के प्रेमी पाठक उनकी रक्षा हिन्दी क्षेत्रों और हिन्दीभाषी जनता के सम्मान से ही कर सकते हैं। उन्हें इस हिन्दीभाषी जनता के साथ मिलकर अंग्रेजों का हटान और सभी भारतीय भाषाओं का अंग्रेजों की दागता से मुक्त करान के लिए संघर्ष करना चाहिए। सम्मुखिनी की पदवानने हुए वे सामुदायिक अल्पसंख्यकों के रूप में अपने अधिकारों के लिए लड़ें, हिन्दी भाषी जनता उनका साथ दायें। उनका जनभाव का रवैया सम्प्रदायवाद की उपज है और उन्हीं के विरुद्ध लड़ना है।

चाहान ने फातिम और हिटलर की उच्चतर आर्थिक-सामर्थ्य की परिकल्पना की निद्रा की है। यह कृपा करने अपने पुराने राष्ट्रभाषावादी विचारों में देस जाते, उन्होंने जिनकी बार आप हिन्दुओं और हिन्दू राष्ट्रवाद की चर्चा की है और उसके आधार पर हिन्दी व विकास का विस्तार किया है। उन्होंने अब हिन्दू राष्ट्रवाद का नाम लेना बन्द कर दिया लेकिन हिन्दू-मुस्लिम सम्बन्धों और सरकार है। उन्होंने लिखा है कि 'सिद्धि कोमा की जनता (विशेषकर उत्तर भारत की जनता) ने हिन्दू और मुस्लिम सम्बन्धों का योगदान में दिल्ली के आग-वाय बोलों जानेवासी सभी बोलों की भूमि पर एक अंग्रेजी ही सम्पूर्ण भाषा उद् का विकास किया।'

चाहान ने यह नहीं बताया कि बंगाल, बरमौर, मिल्म आदि में हिन्दू मुस्लिम सम्बन्धों के योगदान से जिनो नयी सम्पूर्ण भाषा का विचार क्यों नहीं हुआ। वह यह नहीं जानते कि ईरानी, अरब, पठान, उज्बक मुसलमानों की सभ्यताएँ एक नहीं हैं, न समझना, बंगाल और गुजरात की सभ्यताएँ एक हैं। और मारे हिन्दुओं की एक सभ्यता ही भी तो उनकी एक भाषा कैसे हो जायगी? भारत में आनेवाले मुक्त, पठान और ईरानी मुसलमानों की भाषा कैसे एक हो जायगी?

गुल्मी वही पुरानी है। वह समझते हैं कि सभ्यता के समूह हिन्दू हैं और फारसी के समूह मुसलमान। दोनों के मिलने से उद् का विकास हुआ।

और हिन्दी का विकास कैसे हुआ?

"हिन्दू समाज में उद् मुधार-आन्दोलन और कई दूसरी ऐतिहासिक परिस्थितियों का प्रभाव से उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सदी बोलों की ही जमीन पर उद् के मुकाबले में उसके एक सभ्यताविष्ठ साहित्यिक रूप हिन्दी का विकास हुआ।"

वही बात है जो श्री सज्जाद जहीर ने अपने निबन्ध में लिखी थी और जिसे चौहानजी ने अपने पुराने निबन्ध में पल्लवित किया था। हिन्दी का विकास हिन्दू-समाज में उठे सुधार-आन्दोलनों के कारण हुआ। वह हिन्दुओं की भाषा है। उर्दू मुख्यतः मुसलमानों की भाषा है जिनके साथ कुछ गरीब हिन्दू भी हैं।

चौहान को यह नहीं मालूम कि जितनी संस्कृतनिष्ठ हिन्दी (उन्हें छोड़कर) हिन्दी के औसत लेखक लिखते हैं, उससे ज्यादा संस्कृतनिष्ठ बंगला पूर्वी पाकिस्तान के दक्का रेडियो से बोली जाती है, वंसी ही संस्कृतनिष्ठ मलयालम केरल के ईसाई लिखते और बोलते हैं। भाषा से धर्म का अटूट सम्बन्ध होता तो हर प्रदेश में नयी-नयी सम्पर्क भाषाएँ बन गई होतीं।

चौहान के विचार से "संस्कृतनिष्ठ होने के कारण" हिन्दी ने उर्दू के मुकाबले में "राष्ट्रीय आन्दोलन को एकजुट करने में अधिक व्यापक योग दिया।" होना यह चाहिए या कि जो सहज सम्पर्क भाषा बनी थी, वही राष्ट्रीय आन्दोलन को एकजुट करती। लेकिन यह काम किया संस्कृतनिष्ठ—हिन्दू समाज की भाषा—हिन्दी ने। यह भी उसी पुरानी स्थापना का नया रूप है; गांधीजी ने जो राष्ट्रीय आन्दोलन चलाया वह मूलतः हिन्दू राष्ट्रवाद का आन्दोलन था।

अब बच गए मुसलमान। वे अलग राष्ट्र की माँग तो कर चुके। अब उर्दू की क्षेत्रीय भाषा बनाने के अलावा और किस चीज की माँग करें?

इस प्रकार चौहान का यह नया लेख भी उनकी पुरानी हिन्दू-मुस्लिम संस्कृति की सम्प्रदायवादी—मावसवाद-विरोधी—समझ के आधार पर लिखा गया है। वह वस्तुगत रूप से अंग्रेजी का समर्पन करता है, अंग्रेजी को राजभाषा बनाये रखनेवालों के तर्क दोहराता है। उनकी एक भी स्थापना हिन्दी के लेखक और पाठक न मानें तो यह स्वाभाविक है; इस पर उन्हें खफा न होना चाहिए।

परिशिष्ट—१

## भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और उन्नीसवीं सदी में आन्दोलन

“हिन्दी नई चाल में ढली, सन् १८७३ ई० ।”

इस नई चाल की हिन्दी ने एक ऐतिहासिक आवश्यकता की पूर्ति की। उसने हिन्द प्रदेस की जनता के राजनीतिक और सांस्कृतिक जागरण को वाणी दी।

गिलफ्राइस्ट और ग्रियर्सन आदि अंग्रेज विद्वानों की फैलाई हुई एक भ्रान्त धारणा अब भी लोगों में मिल जाती है कि उर्दू ने अरबी-फारसी के शब्द निकालकर और उनकी जगह संस्कृत शब्द डालकर उन भाषा का निर्माण हुआ। भारतेन्दु का गद्य देखने से यह धारणा निर्मूल सिद्ध होती है। उनके निबन्धों में हुज्जत, जमाना, बयान, सफ़र, मुर्दे, कलम, रिवाज, तलाश, दरख्त, सबूत, गरज आदि जैसे शब्द निहायत बेतकलुफी से इस्तेमाल किये गए हैं। यही हाल बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुन्द गुप्त, राधाचरण गोस्वामी आदि लेखकों का भी है। कुछ लेखक ऐसे ज़रूर थे जो प्रचलित अरबी-फारसी के शब्द निकालकर उनकी जगह संस्कृत-शब्दावली रखकर शुद्ध हिन्दी लिखने के पक्षपाती थे। लेकिन भाषा की समस्या प्रचलित शब्दों की न थी।

समस्या यह थी कि जहाँ अप्रचलित शब्दों की ज़रूरत पड़े, यानी साधारण बोलचाल से अलग जहाँ गैर-बुनियादी शब्द-भण्डार की ज़रूरत पड़े, वहाँ अरबी-फारसी से शब्द लिये जाएँ या संस्कृत से। बोलचाल की भाषा के आधार पर जिस साहित्यिक उर्दू का विकास हुआ, उसका रूझान गैर-बुनियादी शब्द-भण्डार के लिए संस्कृत के बदले अरबी-फारसी की तरफ जाने का था। उर्दू की भी दो शैलियाँ थीं, एक वह जिसमें बोलचाल की हिन्दी के शब्द निकालकर उनकी जगह भी अरबी-फारसी के शब्द डाले जाते थे, गैर-बुनियादी हिस्से में तो उनकी भरमार रहती ही थी। दूसरी शैली वह थी जिसमें बोलचाल की हिन्दी के शब्दों का बायकाट न किया जाता था और गैर-बुनियादी हिस्से में भी अरबी-फारसी की ब्रेजा भरमार न की जाती थी।

बोलचाल की भाषा एक ही थी, हिन्दी-उर्दू का बुनियादी शब्द-भण्डार एक ही था। लेकिन साहित्यिक शैली का निर्माण उन लोगों के हाथों हुआ जो अरबी-फारसी के विद्वान् थे या संस्कृत के विद्वान् थे। इन लोगों ने गैर-बुनियादी शब्द-भण्डार के लिए अरबी-फारसी या संस्कृत का सहारा लिया।

यदि गैर-बुनियादी शब्द-भण्डार के लिए अरबी-फारसी का सहारा लेने की नीति हमारे जातीय विकास की ऐतिहासिक आवश्यकताएँ पूरी कर सकती तो 'नई हिन्दी' के चलन का मवाल न उठना, मवाल उठने पर भी उसमें मजबूती न मिलती। कचहरियों, पुनिम विभाग आदि में उद्गम्य थी। जनता का समर्थन मिलने पर उसका प्रचार इतना व्यापक हो जाया कि कई भाषा-प्रेमी उससे होठ करने की जुरत न करती। लेकिन गैर-बुनियादी शब्द भण्डार के लिए सिर्फ अरबी-फारसी का सहारा लेने की नीति भारत की किसी भाषा में न अपनायी थी। कारण यह था कि यहाँ की भाषाओं का जो, सम्बन्ध मस्कृत से था, वह अरबी-फारसी में न था। हिन्दी की क्रियाएँ—चलना, गिरना, हँसना, रोना, खाना, पीना, भरना, जीना, आदि-आदि—मस्कृत की क्रियाएँ भी हैं। इस तरह अरबी फारसी की क्रियाएँ बोलचाल की हिन्दी में बहुत कम हैं। इसलिए इस तरह की क्रियाओं में बोलनेवाले शब्द भी अरबी-फारसी की क्रियाओं से बोलनेवाले शब्दों की अपेक्षा बोलचाल की हिन्दी में कहीं ज्यादा हैं। बोलचाल की हिन्दी में तदभव की भरमार है। उसने तदभव अरबी-फारसी से नहीं बने, यद्यपि बोलचाल की भाषा में आये हुए अरबी-फारसी के शब्दों का रूप और कभी-कभी अर्थ भी एक हद तक बदला है।

बोलचाल की हिन्दी की तरह भारत की अन्य भाषाओं में भी अरबी-फारसी के सैकड़ों शब्द घुल-मिल गए। इसका सबब यह नहीं था कि मुसलमानों की भाषा अरबी-फारसी थी और हिन्दुओं की भाषा संस्कृत, प्राकृत या अपभ्रंश थी। बाबर काँवरु की जवान दरबख्त, तुर्की थी। कुछ ईरानियों के अलावा उच्च वर्ग के मुसलमानों के घरों में भी फारसी न बाली जाती थी। लेकिन सैकड़ों साल तक फारसी उत्तर भारत की राजभाषा रही थी। सैकड़ों अरबी के शब्द फारसी के जरिये यहाँ आए। इसके अलावा सिन्धु मुसलमानों के लिए धर्मग्रन्थ की भाषा अरबी थी। बोलचाल की हिन्दी में फारसी शब्दों के घुलने मिलने का मुख्य कारण फारसी का राजभाषा होना था।

फिर भी हिन्दी भाषी प्रदेश की-नी समस्या कश्मीरी, बँगला, मराठी आदि भाषाओं में नहीं पैदा हुई। इसके कई कारण थे। राजभाषा फारसी के केन्द्र हिन्द प्रदेश ही में थे। आगरा और दिल्ली मुगल की राजधानी रह चुके थे। यहाँ के शिक्षित वर्ग में फारसी का प्रचार भारत के दूसरे नगरों और प्रांतों के मुजावले में ज्यादा था। १८३६ ई० तक यहाँ राजभाषा फारसी रही और उसके बाद कचहरियों, पुनिम विभाग आदि में जो भाषा बली, वह अरबी-फारसी शब्दों से सरी हुई थी।

अंग्रेजों ने यहाँ की सामन्तशाही को अपना मित्र और चाकर बनाया। नवाबों के दरबार जन-समृद्धि के केन्द्र न थे। जनता से उनका अलगाव उनके सरक्षण में चलने-वाली भाषा-नीति पर भी पड़ा। समनऊ, रामपुर, हैदराबाद के दरबार एक खास तरह की शैली और कविता के केन्द्र बन गये। अंग्रेजों ने दो नियमों और दो शर्तियों के चलन को प्रोत्साहन दिया और भाषा-सम्बन्धी विवाद उनकी 'फूट शाली और राज करो' नीति का जहरी हिस्सा बन गया। लेकिन यह समझना बहुत बड़ी भूल होगी कि समुचा उर्दू

साहित्य सामन्ती संस्कृति से प्रभावित है। उर्दू का एक बहुत बड़ा हिस्सा सामन्त-विरोधी और राष्ट्रीय है। उसने हिन्दी के लैराक बहुत कुछ सीखा सकते हैं और पिछले हिन्दी लेखकों ने बहुत कुछ सीखा है। उसमें बोलचाल की हिन्दी का बहुत ही सुन्दर और सँवारा हुआ रूप मिलता है।

भारतेन्दु के समय तक—और एक हद तक अब भी—शिक्षा पर पंडितों और भौतवियों का इजारा था। इसका एक फल यह हुआ कि हिन्दी-उर्दू की दो लिपियों का चलन हुआ। इससे साहित्य के पाठक दो हिस्सों में बँट गये और अक्सर उन्हें पता न रहता था कि दूसरी लिपि में क्या लिखा जा रहा है। जननाधारण की भाषागत एकता साहित्य की रंगीनी पर अपना अनर न डाल पाई। फिर भी लिपि-भेद से ही हिन्दी-उर्दू का भेद इस हद तक नहीं बढ़ा। जायसी के 'पद्मावत' के फारसी लिपि में लिखे जाने से वह उर्दू का ग्रन्थ नहीं हो गया। मृग प्रदन और बुनियादी शब्द-भण्डार का था। उन्नीसवीं सदी के अनेक उर्दू-लेखक अपनी भाषा को सरल करने का प्रयत्न कर रहे थे और उसमें अरबी-फारसी की अनावश्यक भरमार कम कर रहे थे। फिर भी जरूरत पड़ने पर बोलचाल की शब्दावली में बाहर से अरबी-फारसी का ही सहारा लेते थे।

भारतेन्दु ने कोई नयी भाषा नहीं बनाई। उन्होंने प्रचलित खड़ी बोली को साहित्यिक रूप दिया। उनके पक्ष में तीन बातें महत्वपूर्ण थीं। उनकी भाषा-सम्बन्धी नीति वही थी जो अवधी और ब्रज के पुराने हिन्दू-मुसलमान कवियों की थी। उर्दू के कवि—कुछ अपवाद छोड़कर—तुलसी, मीरा, रहीम, रसखान, आलम शेख, पजनेस, जायसी, पद्माकर, भूपण आदि की परम्परा से अपरिचित थे। इस परम्परा और उसकी भाषा-नीति को भारतेन्दु ने अपनाया। यह भाषा-नीति यह थी कि तत्सम संस्कृत के मुक्तावले में तद्भव शब्दों का प्रयोग करना, बोलचाल के अरबी-फारसी शब्दों का वहिष्कार न करना, और बुनियादी शब्द-भण्डार के लिए संस्कृत का सहारा लेना। दूसरी बात उनके पक्ष में यह थी कि उन्होंने ग्रामीण या जनपदीय बोलियों का स्वभाव पहचाना और अपनी हिन्दी को गाँव के साधारण पढ़े-लिखे लोगों के लिए सुलभ बनाने की कोशिश की। तीसरी बात उनके पक्ष में नागरी लिपि थी। सैकड़ों साल तक फारसी के राजभाषा बने रहने पर भी नागरी का लोप न हुआ। गाँव के लोग ज्यादातर नागरी ही काम में लाते थे। इस लिपि के जरिये भारतेन्दु जनता के उस तमाम हिस्से को बटोर सके जो उर्दू न जानता था या जिसकी जातीय आवश्यकताएँ उर्दू से पूरी न होती थीं।

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में भाषा-सम्बन्धी वहस में हिस्सा लेनेवालों ने यह सब विकास-क्रम न समझा था। उर्दू के समर्थकों को हिन्दी प्रतिद्वन्दी के रूप में दिखाई दी। कुछ मुसलमान लेखकों को यह अपनी संस्कृति पर ही हमला दिखाई दिया। अंग्रेजों ने अपनी भाषा-नीति से वहस को बढ़ावा दिया और उसमें दोनों तरफ से ऐसी बातें कही गईं जो उचित न थीं। इसी वहस की गर्मी में भारतेन्दु ने 'उर्दू का स्थापा' लिखा था :

“है है उर्दू हाय हाय ! कहाँ सिधारी हाय हाय ॥”

और आगे चलकर बालमुहम्मद गुल ने 'उर्दू को उत्तर' लिखा था

"न बीबी बहुत जी मे पवराइये,  
मम्हलिय जरा होय मे आइय ।"

लेकिन उर्दू मिथारी नहीं। इसका कारण उका बुनियादी शब्द-भण्डार या जोबोले चान की हिंदी का ही था। वह दूसरी त्रिपि के माध्यम से—दरबारा और दरदारी साहित्य के अन्तर्गत—साधारण जनता के एक हिस्से की सेवा करती रही। इसलिए प्रेमचंद, पद्मसिंह शर्मा आदि लेखकों का मन था कि क्रमशः साहित्य में एक मिली जुती शैली का विकास होगा और वह उर्दू की हटाकर या दबाकर न होगा बल्कि उसमें बहुत कुछ लेकर होगा।

भारतेन्दु ने बहुत के दौरान कुछ तड़बाने ज़रूर लियीं लेकिन बहुत उर्दू से नज़र न रखते थे, न उर्दू के प्रचलित गुज़रा का बहिष्कार करने थे। यही नहीं, वह उर्दू में एक पद्य श्रुति भी लिखते थे। भारतेन्दु का जब ध्यानाग्रह देने के लिए बतिया बुलाया गया था, तब विज्ञापन में उन्हें 'शायर-मास्टर बुनबुने हिन्दुस्तान' कहा गया था। वाजिद अली शाह के शायर मिर्जा आबिद ने 'बागे आनम में मोतज़िब है हवा' आदि उन पर कमीदा लिख कर भेजा था। श्री रामगकर ध्यान ने लिखा था कि उन्हें बज़ौर और अनीस का काव्य विशेष प्रिय था। १७ मितम्बर, १८७० की 'कबिचचन-मुषा' में एक दिनचर्या विज्ञापन छपा था। यह विज्ञापन उर्दू के साप्ताहिक पत्र 'कानिद' के बारे में था जिसे भारतेन्दु निकालनेवाले थे।

"कानिद ।

सातहूँ दिन आर्वात ।।

नये हितकारी और विविध समाचार कहैगा ।।।

यह एक साप्ताहिक उर्दू पत्र निकलैगा इसमें अनेक हित की, नये उद्गार की, सामान्य जनमानुसार लोक-वृद्धि की और अनेक शुभ समाचार की बातें रहैगी—यह पत्र बहुत उत्तम बड़े-बड़े पृष्ठों में स्वच्छ अक्षरों में छपैगा मूल्य—(१०) बापिक।

हरिचन्द्र

उद्यमकर्त्ता ।"

भारतेन्दु से उर्दू के प्रति द्वेषभाव होता तो वह 'कानिद' निकालने की बात क्या न सोचते।

भारतेन्दु ने हिन्दी के माध्यम से जिस जानीब साठन में योग दिया, उसमें अवध, प्रज, बुन्देलखण्ड, भोजपुर आदि जनपदों की जनता शामिल थी। यदि महापंडित रहन साहसनाथन की यह स्थापना सब मानी जाय कि अवधी, प्रज, बुन्देलखण्ड, भोजपुरी बोलनेवाले अला-अलग जातियों के लोग हैं, तो भारतेन्दु का यह काम इतिहास-विरोधी ठहरेगा। भारतेन्दु भोजपुरी क्षेत्र के निवासी थे। भोजपुरी जानते

भी अच्छी तरह थे । लेकिन उन्होंने भोजपुरी में न लिखकर हिन्दी को अपना साहित्यिक माध्यम बनाया जैसे कि आगे प्रेमचन्द और प्रसाद ने किया । इतिहास-विरोधी राम भारतेन्दु का नहीं था; इतिहास-विरोधी स्थापना महापंडित राहुल और उन जैसे विचारकों की है । यद्यपि राहुलजी स्वयं हिन्दी के लेखक हैं—और अपना जीवनचरित उन्होंने भोजपुरी में लिखना उचित नहीं समझा—फिर भी वह हिन्दीभाषी जनता का एक प्रान्त बनाने की मांग करने के बदले बोलियों के आधार पर हिन्द प्रदेश के तेरह टुकड़े करने का मुझाव पेश करते हैं । सन् १९५३ की 'आलोचना' (दिल्ली) में इस आशय का उनका एक लेख छपा था । सोलहवीं सदी के आस-पास ही व्यापार के प्रसार के साथ भोजपुरी आदि के क्षेत्रों में खड़ी बोली फैलने लगी थी । व्यापार के केन्द्रों में एक ही बोली बोलनेवाले लोग एकट्ठा हों, ऐसा नहीं होता । उद्योग-धन्धे और व्यापार शहरो में विभिन्न बोलियाँ बोलनेवाले लोगों को बटोरते हैं और उनमें किसी एक बोली का व्यवहार 'शिष्ट' लोग करते हैं । बनारस आदि पूर्वी नगरों में खड़ी बोली व्यापारी कामों के साथ आई । २ अक्टूबर, १८७२ की 'कविवचन-मुद्रा' में भारतेन्दु का हिन्दी भाषा नाम का निबन्ध छपा था । यह निबन्ध ऐतिहासिक महत्त्व का है । इसमें भारतेन्दु ने बनारस की बोलियों का अध्ययन किया है और यह दिखाया है कि शिष्ट जनों की भाषा हिन्दी है ।

बनारस के लोगों की बोली के बारे में वह कहते हैं, "इसी बनारस में जो बनारस के पुराने रहवासी हैं उनके घर में विचित्र-विचित्र बोलियाँ बोली जाती हैं जैसा पुरवियों की बोली तो आइला जाइला प्रसिद्ध ही है परन्तु यहाँ के पुराने निवासी कसेरे लोग 'वाट' गन्द का बहुत प्रयोग करते हैं जैसा 'आवत हुई' के स्थान पर 'आवत बाटी', 'का करत होव' वा 'का करल' के स्थान पर 'का करत बाटय' वा 'बाटो' वा 'वाटः' ।"

बनारस में इन बोलियों के एकत्र होने और उन सबके ऊपर हिन्दी के चलन का कारण क्या है ? इसका कारण व्यापार का प्रसार, औद्योगिक और व्यापारी केन्द्रों का निर्माण, सामन्ती सम्बन्धों के भीतर पूँजीवादी सम्बन्धों का पनपना और विभिन्न बोलियाँ बोलनेवालों का जातीय गठन है । 'प्रेमजोगिनी' में भूपटिया 'मिसरो नहीं आए' कहता है लेकिन जलधरिया 'सुत्तल थोड़े रहली' और 'कंधा छिला जाला' कहता है । और शिष्ट लोग खड़ी बोली का व्यवहार करते हैं ।

बनारस की विभिन्न बोलियों का उल्लेख करने के बाद भारतेन्दु 'हिन्दी भाषा' वाले निबन्ध में कहते हैं, "जो हो यह तो सिद्धान्त है कि जो यहाँ के शिष्ट लोग बोलते हैं वह परदेसी भाषा है और यहाँ पश्चिम से आई है ।"

पछाँह से यह बोली किसके साथ आई, इस प्रश्न का उत्तर भारतेन्दु के इस वाक्य से मिलता है : "अब पश्चिमोत्तर देश में घर में बोलने की भाषा कौन है यह निश्चय नहीं होता क्योंकि दिल्ली प्रान्त के वा अन्य नगरों में भी खत्रियों वा पछाँही अगरवालों वा और पछाँही जातियों के अतिरिक्त घर में हिन्दी कोई नहीं बोलते वरंच यहाँ तो कोस-कोस पर भाषा बदलती है ।" दिल्ली के अलावा अन्य नगरों में भी खड़ी बोली खत्रियों, पछाँहीं



अधिकांशों आदि के जस्ये फंती जिनका मुख्य पक्ष व्यापार था। आचार्य मुकेश ने लिखा है कि मुगल-साम्राज्य के ध्वस्त के बाद "दिल्ली के आग-प्याम के प्रदेशों की हिन्दू व्यापारी जातियाँ (अगरवाले, खत्री आदि) जीविका के लिए लखनऊ फैलावारा, प्रयाग, काशी, पटना आदि पूर्वी शहरों में फैलने लगी। उनके माप-माप उनकी बोलचाल की भाषा सड़ी बोली भी लगी चलनी थी।"<sup>१</sup>

वास्तव में यह कम मुगल-साम्राज्य के ध्वस्त से पहले ही शुरू हो चुका था। मुकेशजी ने व्यापारियों द्वारा सड़ी बोली का प्रसार का तथ्य बहुत मही दिखा है। इन व्यापारियों ने मुमयमान भी थे। इनके सिवाय मालहूँ तो उम्मीमवीं तक एक बोली बोलनेवाला का हमरी बानी के क्षेत्र में जाकर बनने का काम बराबर चलता रहा। अवध के औद्योगिक मान मिथिला में जाकर बन गए और वहाँ एक नये दंग की हिन्दुस्तानी का व्यवहार करने लगे, वह कार्य भी इसी काम के अन्तर्गत हुआ।

जो लोग समझते हैं कि सड़ी बोली केवल राज्य व्यवहार या साहित्य की भाषा है, उन्हें इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए कि दिल्ली के अकाबा अन्य नगरों में वह बहुत से लोगों की मातृभाषा थी और है। इस विस्तार में भारतेन्दु ने लिखा था, "ऐसे ही पश्चिमोत्तर देश में अनेक भाषा हैं पर उनमें ऐसे नगर होते हैं जिनमें आबान-बूढ़-जतिना सब सड़ी भाषा बोलते हैं अनएव यद्यपि काशी ऐसे पूर्वी प्रदेशों की मातृभाषा या घर के बोलचाल की भाषा हिन्दी है पर तो हम नहीं कह सकते पर हाँ यह कह सकते हैं कि इसी पश्चिमोत्तर देश में कई नगर ऐसे हैं जहाँ यही सड़ी बोली मातृभाषा है।"

इन बोलचाल की भाषा में हिन्दी-उर्दू का भेद न था। यह विभिन्न बोलियों बोलनेवाली जनता की नई जानीय भाषा थी जो उसे एक सूत्र में बाँध रही थी। गिल-फ्राइस्ट ने ही इस बात का सूत्रपाद हो चुका था कि मुसलमानों की निष्ट बोली और होगी और हिन्दुओं की और। लेकिन भारतेन्दु बोलचाल की भाषा में भेद न मानते थे। हिन्दी-उर्दू का भेद अरबी-फारसी या संस्कृत से प्राप्त लेने के कारण था। = सितम्बर, १८७३ की 'कविवचन-मुद्रा' में हिन्दी-उर्दू के बारे में एक लेख छपा है जिसका अंग्रेजी में शीर्षक है, "Hindi Versus Urdu, Philologically हिन्दी और उर्दू।" इसमें हिन्दी-उर्दू के भेद के बारे में यह स्थापना है "हिन्दी और उर्दू में अंतर क्या है हम बिना संकोच के उत्तर देने हैं कि भाषाओं में कुछ अंतर नहीं है क्योंकि व्याकरण की विभिन्नता और नियम दोनों का एक है पर इतना ही अंतर है कि हिन्दी में जिसके लिए हिन्दी शब्द नहीं मिलता वहाँ संस्कृत शब्द काम में आते हैं और उर्दू में संस्कृत हिन्दी शब्द होने पर भी वहाँ जहाँ शब्द नहीं मिलते हैं वहाँ तो अवश्य ही अरबी और फारसी के शब्द लिखे जाने हैं, यही दोनों में अंतर है।"

भारतेन्दु ने हिन्दी के नई चाल में बनने का वर्ष १८७३ लिखा था। वास्तव में

१८६० में ही 'विद्यासुन्दर' के प्रकाशन और 'कविवचन-मुषा' के निकलने से हरिश्चन्द्री हिन्दी का चमकन शुरू हो गया था। लेकिन हरिश्चन्द्र ने न तो कोई नई भाषा बनाई थी, न व्याकरण आदि में ही कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन किया था। उनकी हिन्दी की विशेषता उनकी मीठी थी। 'विद्यासुन्दर' में 'ममाचार नेने के हेतु', 'यह पीन हमारी प्राणप्यारी विभूवनमोहनो का अंग लपटी करके आता है', 'पुरस्कार के हेतु', 'बन अब बहुत भई', 'नव काम सिद्ध भया', 'बिना कुछ भए', 'मिमी दगा मय की होय', 'और जो वह संन्यासी हनी होय', 'जो ननु यात सचच होय' आदि प्रयोग मिलते हैं। 'कर्पूरमंजरी' में: "महाराज, कहिये और क्या होय?" 'मुद्राराक्षस' में: "जो कोई मुननेवाला और समझनेवाला होय।" 'वैदिकी हिमा' में: "बड़ा आनन्द भया"। 'नृत्य हरिश्चन्द्र' में: "बेटा, तौंक भई", "ठीक है, नैव मोना"। 'विपश्य विषयीषयम्' में: "तो क्या हुआ है, होय।" 'वैष्णवता और भारतवर्ष' में: "स्नान आदि भी यहीं तक रहै", 'भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है' में: "छरासी जो बीच में भई है।"

भाषा के परिष्कार की दृष्टि से भारतेन्दु का काम युगान्तरकारी नहीं कहा जा सकता। उनके पहले—उर्दू गद्य को छोड़ भी दें तो—रामप्रसाद निरंजनी, नवासुखलाल, राजा लक्ष्मणसिंह आदि रामयं हिन्दी-लेखक हो चुके थे। लल्लूलाल की भाषा की तुलना में भारतेन्दु की भाषा युगान्तरकारी मालूम हो सकती है लेकिन हिन्दी गद्य के विकास में लल्लूलाल का जो महत्त्व ग्रियर्सन ने घोषित किया है, वह इतिहास से सिद्ध नहीं होता।

भारतेन्दु अनेक शब्दों में पूर्वी बोलचाल के अनुकूल 'ह' का इकारान्त प्रयोग भी करते हैं। 'पहिवानना', 'पहिले' ('विद्यासुन्दर') ही नहीं, 'गहिना पहिनाओ', 'पहिरने नये' ('कर्पूरमंजरी'), 'कवच पहिराया' ('मुद्राराक्षस') आदि प्रयोग भी उनके यहाँ हैं। कदमाया का भी काफ़ी असर उनके गद्य पर है। आछत, बेर, तँ, कै आदि शब्द नाटकों के गद्य में मिलते हैं। विराम चिह्न आदि के मामले में उन्होंने पूरी स्वच्छन्दता बरती है। शब्दों के हिज्जे में भी जहाँ-तहाँ स्वतन्त्र प्रयोग मिलते हैं।

भारतेन्दु का युगान्तरकारी महत्त्व इस बात में है कि उन्होंने हिन्दी भाषा की गरिमा पहचानी, अपने गद्य में उन्होंने अमल से दिखा दिया कि यह भाषा कितनी मीठी है, उनके हाथ में गद्य एक कला बन गया, वह सभी तरह के भावों और विचारों के लिए गद्य की लचीले माध्यम की तरह काम में लाने लगे। 'विद्यासुन्दर' ही में उन्होंने कुशल धिस्वी की प्रतिभा दिखा दी। "हाय हाय, ऐसा सुन्दर रूप तो न कभी आँखों देखा, न कानों सुना, इसकी दोनों हाथ से बलैया लेने की जी चाहता है। लोग सब कहते हैं कि चन्द्रमा को सिंगार न चाहिए। हमको जान पड़ता है कि चन्द्रमा ही पृथ्वी पर उतर के बैठा है। क्या कामदेव इस रूप की बराबरी कर सकता है? ऐसी कौन स्त्री है जो इसकी देख के धीरज धरेगी।" इस स्वर पर हम मुग्ध हो जाते हैं, उसे बार-बार सुनना चाहते हैं। वह स्वर उनके नाटकों में बार-बार सुनाई देता है और हिन्दी-नाटकों में वह स्वर तो क्या, उसके कहीं नजदीक पहुँचनेवाला स्वर भी अब तक नहीं सुनाई दिया।

इस गद्य की सरमता का कारण तद्भव शब्दों और बोलचाल के साधारण शब्दों का चतुर्धाई से प्रयोग है। चन्द्रमा को शृंगार नहीं, सिंगार। रूप की समानता नहीं, बराबरी। धैर्य धारण करेगी नहीं, धीरज धरेगी। और बलैया लेन की बात पर तो मुड़ हिन्दीवादिना का हाट फेंक हो जाएगा।

‘विद्यामुन्दर’ के गद्य का लेखक कृतावली और मुहावरों का धनी है। ‘देखकर भी बहाली दिए जाती है’—छेठ बनारसी मुहावरा इस्तेमाल किया है। कृतावली विशेष रूप से ब्रजभाषा से ली गई हैं।

कप्रमजरी’ में एक दोहा है

“कठिन मस्कृत, अनिमघूर, भाषा सरस सुनाय।

धुरूप नारि अन्तर मरित, इनमें बीच लघाय ॥”

मस्कृत और भाषा का यह भेद भारतेन्दु की गद्य-रचना में सही साबित होता है। यदि उन्होंने मस्कृत-शब्दावली का अपनी शैली का मुख्य आधार बनाया होता, तो उनमें वैसी सरमता न पैदा होती। उनके समय तक ब्रजभाषा के प्रति निरादर भावना न पैदा हुई थी। आगे चलकर कुछ हिन्दी साहित्यकारों ने ब्रजभाषा के तद्भव शब्दों को छोड़कर उनका तत्सम रूप अपनाया जो शैली अपनायी, उससे हिन्दी की अपनी विशेषता का काफी धक्का लगा। इस अवैतानिक धारणा को सही ठहराने के लिए यह सिद्धान्त गढ़ा गया कि ब्रजभाषा तुलनाती भी और खड़ी बोली स्पष्ट बोलने लगी है। दूसरा सिद्धान्त यह गढ़ा गया कि मस्कृत शब्दों की बहुतायत होने से हिन्दी भारत के हमारे हिस्सों में ज्यादा समझी जाएगी। ये दोनों ही तर्कावयिन सिद्धान्त हिन्दी की प्राप्तिता के आगे आते थे।

‘हिन्दी भाषा’ नाम के निबन्ध में भारतेन्दु ने लिखने की भाषा की विभिन्न शैलियों के उदाहरण दिए हैं। इनमें एक शैली यह है जिसमें ‘मस्कृत के शब्द बहुत हैं, दूसरी यह है जिसमें ‘मस्कृत के शब्द थोड़े हैं, तीसरी यह है जो ‘गुड़ हिन्दी है’। गुड़ हिन्दी किससे गुड़ है? यह हिन्दी फारसी शब्दों से गुड़ नहीं है, वह मस्कृत से भी बहुत कुछ गुड़ है। इसीलिए जिस शैली में ‘मस्कृत के शब्द थोड़े हैं’, उसमें भी उगे अनेक श्रेणी में रखा गया। चौथी शैली यह है जिसमें ‘किसी भाषा के शब्द मिलने का नेम नहीं है, पाँचवी यह है जिसमें ‘फारसी शब्द विदेश हैं इत्यादि। इन शैलियों पर अपना मत देते हुए भारतेन्दु ने लिखा है कि “नम्बर २ और ३ लिखने के योग्य हैं।” भारतेन्दु ने उन शैलियों को पसन्द किया है जिनमें मस्कृत के शब्द थोड़े हैं या नहीं के बराबर हैं। उनके विशद भारतेन्दु के नामलेवा और पानीदवा बहुत से गुड़ हिन्दीवादियों ने अच्छी शैली उसे समझा है जिसमें भरमस्कृत मस्कृत के शब्द हो (और जिनका ही निरर्थक हो, शैली जतना ही साधक समझी जाए।)

भारतेन्दु की ‘गुड़ हिन्दी’ का मसूदा यह है—

“पर मेरे प्रीतम अब तक घर न आया क्या उस देश में बरमान नहीं होता या किसी सोन के फेर में पड़ गये कि इनकी की मुण ही भूल गये। वहाँ तो वह प्यार की

वातें कहाँ एक संग ऐसा भूल जाना कि चिट्ठी भी न भिजवाना । हा ! मैं कहाँ जाऊँ कैसी कहीं मेरी तो ऐसी कोई मुंहवोली सहेली नहीं कि उससे दुखड़ा रो मुनाऊँ कुछ इधर-उधर की बातों ही से जी बहलाऊँ ।”

ब्रजभापा से इस गद्यशैली का कितना नज़दीकी सम्बन्ध है, यह सहज ही देखा जा सकता है । खास तौर से अपने नाटकों की भाषा में भारतेन्दु ब्रजभापा की तद्भव प्रधान शैली का ब्यादा प्रयोग करते हैं । ‘कर्पूरमंजरी’ में उनकी सरस शैली गद्यकाव्य की तरह प्रभावशाली हो गई है । यथा—“इसकी चितवन कलेजे में से चित्त को जोराजोरी निकाले लेती है । इसकी सहज शोभा इस समय कैसी भली मालूम पड़ती है । अहा ! इस कपड़े से जो पानी की बूँदें टपकती हैं वे ऐसी मालूम होती हैं मानो भावी वियोग के भय से वस्त्र रोते हैं । काजल आँखों से धो जाने से नेत्र कैसे सुहाने हो रहे हैं, और बहुत देर तक पानी में रहने से कुछ लाल भी हो गए हैं ।”

भारतेन्दु ने गद्य के लिए तो खड़ी बोली को माध्यम बनाया लेकिन पद्य के लिए उनका विचार था कि ब्रजभापा को ही माध्यम बना रहना चाहिए । इस तरह गद्य और पद्य में एक असंगति रही और भारतेन्दु के बाद पद्य में खड़ी बोली को माध्यम बनाने के लिए एक लम्बा संघर्ष चला । ‘हिन्दी भाषा’ वाले निबन्ध में उन्होंने अपना यह मत प्रकट किया है कि “पश्चिमोत्तर देश की कविता की भाषा ब्रजभाषा है यह निर्णय हो चुकी है ।” अपने अनुभव के बारे में लिखा है : “मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि सड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊँ पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं बनी, इससे यह निश्चय होता है कि ब्रजभाषा में ही कविता करना उत्तम होता है और इसी से सब कविता ब्रजभाषा में ही उत्तम होती है ।” खड़ी बोली में कविता मीठी क्यों नहीं होती, इसका “यवसे बड़ा कारण यह जान पड़ा कि इसमें क्रिया इत्यादि में प्रायः दीर्घ मात्रा होती है इससे कविता अच्छी नहीं बनती ।”

वास्तव में खड़ी बोली की कविता में मिठास के अभाव के लिए कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है । कारण कवियों में अभ्यास की कमी ही हो सकता है । ब्रजभाषा में पद्य का एक बना-बनाया रास्ता था; कविता की अपनी शब्दावली थी । खड़ी बोली में यह सब गहना था ।

खड़ी बोली बनारस और दूसरे पूर्वी जिलों में शिष्ट लोगों की बोलचाल की भाषा के रूप में फैल रही थी । इसलिए भारतेन्दु जैसे कवि का उससे प्रभावित न होना असम्भव था । उनकी एक तरह की शैली वह है जिसमें ब्रजभाषा खड़ी बोली के साथ घुलती-मिलती दिखाई देती है । जैसे ‘प्रेमतरंग’ के इस गीत में—

किन वे रुठाया मेरा यार ।

कहाँ गया, क्यों छोड़ गया मोहि, तोड़ गया क्यों प्यार ।

या

नमीली आँखोंवाली सोए रहो अभी है बड़ी रात ।

मगरी रैन मेरे सग जागत रहे करत रंगीली बात ॥

दूसरी तरह की बोली उनकी लावणियों की है जिसमें प्रचलित फारसी के शब्द भी आते हैं और जिसकी भाषा आमनीर से कुछ गड़ी बोली होती है। मुफ्ती कवियों के रस में भारतेन्दु खड़ी बोली की कितनी मरस कविता कर सकते थे, इसका सपूत इन पंक्तियाँ म मिलेगा—

श्री राधा-माधव जुगन चरन रम का अपने को मस्त बना ।

पी प्रेम पिपाता भर भर कर कुछ इस में का भी देल मजा ॥

यह वह मैं है जिसने पीने से और ध्यान छूट जाना है ।

अपने मे ओ' दिगंबर में फिर कुछ भेद नहीं दिखाना है ॥

इसके मुरूर से मस्त हूँक अपने को नजर बस आता है ।

फिर और ह्वम रहती न जरा कुछ ऐसा मजा दिखाता है ॥

दुव मान मेरा कहना दिल को इन मँछाने की तर्फ भुका ।

पी प्रेम पिपाता भर भर कर कुछ इस में का भी देल मजा ॥

लावनीवाजी ने खड़ी बोली कविता की एक सजीव परम्परा कायम की थी। उनके लिए दीर्घ ह्रस्व मात्राओं में खड़ी बोली के मीठे, कड़े बताने का सवाल न था। उनके यहाँ खड़ी बोली एक बहुत ही लचीला माध्यम बन गई थी और भारतेन्दु ने जब उस परम्परा का सहारा लिया, तब उन्होंने खड़ी बोली में बहुत ही सरस कविता की। यह सही है कि यह कविता पा प्रसाद की 'गैली' से बहुत दूर है लेकिन वह जन-जीवन की परम्परा के बहुत निकट है।

जनसाधारण ने कवियों ने पद्य में खड़ी बोली की परम्परा बहुत दिन से चला रखी थी। उन्हें यह विश्वास दिलाने की जरूरत न थी कि ब्रजभाषा छोड़कर खड़ी बोली में लिखने में साहित्य और जल्दी उन्नति करेगा। कवियों के सामने प्रश्न यह था कि वे इस सजीव परम्परा में नाला जोड़ेंगे या नहीं। भारतेन्दु के नाटकों में खड़ी बोली के गीतों आदि का जाना यह साबित करता है कि जनता में खड़ी बोली के पद्य प्रचलित थे। 'बदिकी हिमा' में राजा गाता है 'पील अवधू के मतवाले प्यारा प्रेम हरी रम का रे' 'मय हरिदचन्द्र' में यम कहता है—

हम चौधरी डाम सरदार ! जमल हमारा दोनों पार ।

और पिशाच-डाकिनियों का भीत—

हम सज्जे वस्त्रों धजके चलें यमकमें, यम यम यम ।

'भारत-मुद्रा' में आलम्प का गीत है—

दुनिया में हाथ-पैर हिलाना नहीं अच्छा ।

'अधर-नगरी' में घामीराम का 'चने जोर गरम' खड़ी बोली की जपनी चना-जोर गैली

में है। ऐसे ही चूरनवाले का लटका है—

चूरन अमलवेद का भारी। जिसको खाते कृष्णमुरारी।

मेरा पाचक है पचलोना। जिसको खाता श्यामसलोना ॥

आम जनता में खड़ी बोली के पद्यों के चलन का मतलब यह था कि कविता में भी खड़ी बोली को माध्यम बनाने की ऐतिहासिक आवश्यकता पैदा हो गई थी।

भारतेन्दु की उपर्युक्त शैलियों के अलावा उनकी उर्दू शैली की रचनाएँ हैं।

‘रसा’ नाम से वह शायरी करते थे और आमतौर से उनकी भाषा सरल उर्दू होती है। यथा—

दिल मेरा ले गया दगा करके।

बेवफा हो गया वफा करके ॥

○

○

दोस्तो कौन मेरी तुवंत पर,

रो रहा है ‘रसा रसा’ करके।

भारतेन्दु की समूची खड़ी बोली की कविता परिमाण में कम नहीं है। उन्होंने खड़ी बोली की सरल लोकप्रिय कविता में सफलता पाई थी। लेकिन ब्रजभाषा में जिस पुरानी शैली पर वह शृंगार-रस के पद्य बनाते थे, उस शैली पर उन्होंने खड़ी बोली में पद्य नहीं बनाये। खड़ी बोली बनाम ब्रजभाषा विवाद में भारतेन्दु के अपने प्रयोग यह साबित नहीं करते कि खड़ी बोली में सरस कविता न लिखी जा सकती थी।

भारतेन्दु ने खड़ी बोली को—उसके हिन्दी रूप में—नाटक, निबन्ध, पत्रकारिता, उपन्यास और एक हद तक कविता का भी माध्यम बनाया। उनके सामने हिन्दी में वैज्ञानिक साहित्य रचने की समस्या भी थी। उनका यह स्वप्न था कि एक हिन्दी विश्व-विद्यालय खोला जाय। शिल्प की उन्नति के लिए वह बराबर जोर देते रहे थे। इसलिए विज्ञान के लिए पारिभाषिक शब्दावली की समस्या का उठ खड़ा होना स्वाभाविक था। उस समय भी ऐसे लोग थे जो हिन्दी में वैज्ञानिक पुस्तकों का अभाव दिखाकर हिन्दी माध्यम से विज्ञान की शिक्षा देने का विरोध करते थे। भारतेन्दु के समय में ही हिन्दी-प्रेमी विद्वान् वैज्ञानिक पुस्तकें तैयार करने की तरफ ध्यान देने लगे थे। उन्हें भारतेन्दु से इस काम में प्रोत्साहन मिला।

२३ अगस्त, १८७३ की ‘कविवचन-सुधा’ में भारतेन्दु ने ‘हिन्दी की उन्नति’ नाम के निबन्ध में उन लोगों को जवाब दिया था जो कहते थे कि हिन्दी में वैज्ञानिक पुस्तकें लिखी ही नहीं जा सकतीं। ऐसे ‘विद्वानों’ का मजाक उड़ाते हुए उन्होंने लिखा था, “बहुत से लोग बिना समझे-बूझे दाढ़ी हिला-हिलाकर कहा करते थे कि हिन्दी में वैज्ञानिक ग्रन्थ (Scientific Works) नहीं लिखे जा सकते और भाषा में इतने शब्द नहीं कि वैज्ञानिक भावना प्रकाश की जाय पर हम लोग यह जल्पने वाले लोगों को सचेत करते हैं कि वे इस निद्रा से जागें और टुक आंख खोलकर देखें कि अब हिन्दी भाषा की उन्नति

चाहनेवाले लोग जो कहते थे सो कर दिखाने हैं। काश्मिरी राजकीय पाठशाला के गणित विद्या के मुख्य अध्यापक पंडित लक्ष्मीनारायण मिश्र एम० ए० ने हिन्दी भाषा में गणित विद्या की पूरी श्रृंखला (Mathematical Series) बनाने का संकल्प किया है तथाच उनके महाशय ने सरल त्रिकोणमिति (Plane Trigonometry) हिन्दी भाषा में प्रस्तुत कर ली।'

१६ जनवरी, १८७३ की 'विविध-सुधा' में इस विषय की खर्चा करते हुए उन्होंने फिर लिखा था, "बहुन लोग मान बजाकर कहते हैं कि हिन्दी हो जाने से विज्ञान के पढ़न पढ़ान में विघ्न हो जायगा क्योंकि हिन्दी भाषा में इनके थोड़े शब्द हैं कि वैज्ञानी भाषना उनके द्वारा प्रकाश नहीं हो सकती है पर हम उम्मा यही उत्तर देते हैं कि कोई बात बिना युक्ति के प्रामाणिक नहीं हो सकती है हिन्दी में शायद बरबस यह भी कह सकत है कि इस संसार में ऐसे भी गनुष्य होते हैं जिनके चार सींग होते हैं पर इसको कोई बुद्धिमान न मानेगा क्योंकि इसका कुछ प्रमाण नहीं है पर उनके इस कहने पर भी हिन्दी में वैज्ञानी शिक्षा नहीं हो सकती है कोई नहीं मानेगा जब तक कि अपने माध्य के लिए प्रबल प्रमाण न देंगे सो तो अपनी कलम है और अपना कागज।"

ऐसे लोगों की आज भी कमी नहीं है जो समझते हैं कि हिन्दी (या अथ किसी दूसरी भाषा) के माध्यम से विज्ञान की शिक्षा नहीं दी जा सकती। यही नहीं, कहनेवाले यहाँ तक कहते हैं कि हिन्दी में शिक्षा देने से शिक्षा का स्तर गिर जाएगा, देश का सांस्कृतिक पतन हो जाएगा। ऐसे लोग शिक्षा और विज्ञान को थोड़े-से अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों की जागीर समझते हैं। हिन्दी के माध्यम से लोग विज्ञान पढ़ने लगे तो हाकी जागीरदारी खत्म हो जाएगी। भारमदु अंग्रेजी पढ़ने और अंग्रेजी द्वारा आधुनिक विज्ञान की शिक्षा पाने के विरुद्ध न थे। लेकिन उनके सामने समस्या यह थी कि इस शिक्षा और ज्ञान को तमाम देशवासियों के लिए सुलभ कैसे बनाया जाय। वह शिक्षा को जनवादी और लोक-प्रिय रूप देना चाहते थे, उसे बाड़े के अंग्रेजी-भक्त विद्वानों की जागीर न बना देना चाहते थे। इसीलिए 'हिन्दी की उन्नति' में उन्होंने कहा था—

विविध कला शिक्षा अमिन, ज्ञान अनेक प्रकार।

सब देशन से लै करहु, भाषा माहि प्रचार॥

भारतेन्दु की यह नीति देश में शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति की उन्नति के लिए एकमात्र सही नीति है। हिन्दी को चुन्छ समझना उसे विज्ञान की शिक्षा के अयोग्य समझना वास्तव में अपनी अशिक्षा और विज्ञान में अपनी अयोग्यता का परिचय देना है। दोष भाषा का नहीं है शिक्षा के कर्णधारों का है। जिस दिन शिक्षा का उद्देश्य जनता की वास्तविक उन्नति करना होगा, उस दिन अंग्रेजी के माध्यम का मोह छोड़ना ही होगा और हिन्दी में विज्ञान की शिक्षा के लिए भरपूर कोशिश करनी ही होगी।

रामप्रसाद बिरजनी, महासुखलाल, राजा लक्ष्मणसिंह के युग के बाद भारतेन्दु ने हिन्दी नई काल में दाखी। उन्होंने बीजबाल की भाषा का यह साहित्यिक रूप अरबी-

फारसी के प्रचलित शब्दों को निकालकर नहीं सँवारा। उन्होंने बोलचाल की शब्दावली के अलावा शैर-बुनियादी शब्द-भण्डार के लिए संस्कृत का सहारा लिया। उनकी भाषा यहाँ की ग्रामीण बोलियों के निकट थी, वह ब्रज-अवधी की पुरानी साहित्यिक परम्परा की भाषा-नीति के अनुकूल थी। नागरी लिपि के सहारे वह जनता में लोकप्रिय हुई।

हिन्दी का विकास हिन्द प्रदेश की जनता के जातीय विकास के साथ जुड़ा हुआ था। साहित्यिक हिन्दी का विकास हमारे जातीय विकास की जरूरत पूरा करता था। हिन्द प्रदेश के पूर्वी जिलों में भी व्यापारी लोगों के जरिये खड़ी बोली का प्रसार हुआ था। भोजपुर, अवध, ब्रज आदि जनपदों का अलग-अलग बहुत पहले कम होना शुरू हो गया था। भारतेन्दु के समय में वह और कम हो रहा था। शहरों में विभिन्न बोलियों का एकत्र होना देखा जा सकता था, उन सबके ऊपर जातीय भाषा के रूप में हिन्दी का प्रसार हो रहा था। इस बोलचाल की हिन्दी में साहित्यिक हिन्दी-उर्दू वाला भेद न था। हिन्दी जाति की भाषा एक थी। उसके साहित्यिक रूप दो हुए।

भाषा के परिष्कार की दृष्टि से भारतेन्दु के गद्य में बहुत-सी खामियाँ थीं, लेकिन उनका युगान्तरकारी काम यह था कि उन्होंने बोलचाल की भाषा की प्रकृति पहचानी, उसकी मिठास को साहित्य में जगह दी, उस भाषा को सभी तरह के साहित्य का समर्थ माध्यम बनाया। वह समझते थे कि पद्य के लिए ब्रजभाषा ही उपयुक्त है, फिर भी उन्होंने स्वयं खड़ी बोली में कम पद्य नहीं रचा जो उनके ब्रजभाषा में लिखे हुए पद्य से बढ़कर है। जनता में खड़ी बोली कविता की अपनी एक परम्परा कायम हो चुकी थी। भारतेन्दु ने इसे पहचाना और उसके अनुकूल पद्य भी रचे। वास्तव में खड़ी बोली (हिन्दी) में पद्य-रचना के लिए ऐतिहासिक आवश्यकता कभी की पैदा हो चुकी थी।

भारतेन्दु ने उन लोगों का विरोध किया जो यह दावा करते थे कि हिन्दी में विज्ञान की किताबें लिखी ही नहीं जा सकतीं या हिन्दी में विज्ञान की शिक्षा न देना चाहिए। उनके सामने शिक्षा और विज्ञान का उद्देश्य समूचे देश की उन्नति करना था और यह काम देशी भाषाओं द्वारा ही हो सकता था।

इस तरह भारतेन्दु ने हिन्दी को नई चाल में ही नहीं ढाला बल्कि उसके चामुखी विकास के लिए संघर्ष भी किया।

(१८५३)



## गांधीजी और भाषा-समस्या

— अपने राजनीतिक जीवन के आरम्भ से ही गांधीजी ने भाषा-समस्या पर मोबना जोर लिखना आरम्भ कर दिया था। मत्स्य, अहिंसा, स्वराज्य, सर्वोदय—किसी भी अन्य विषय पर उनके विचार आज के लिए इतने उपादेय नहीं हैं, जितने भाषा-समस्या पर। अंग्रेजी, भारतीय भाषाओं, राष्ट्रभाषा हिन्दी और हिन्दी-उर्दू की समस्या पर उन्होंने जितनी बातें कही हैं, वे बहुत ही मूल्यवान हैं। किसी राजनीतिक नेता ने इन समस्याओं पर इतनी गहराई से नहीं सोचा, किसी पार्टी और उसके नेताओं ने भाषा-समस्या के नैदानात्मक समाधान को अपनी नित्यप्रति की कामवाही में दृढ़ तरह अमली जामा नहीं पहनाया, जैसे गांधीजी ने। उनकी नीति के मूल सूत्र छोड़ देने से यह समस्या दिन-पर-दिन उलझनी जा रही है। जो लोग उसे उलझा रहे हैं, वे गांधीजी की जय बोलते हुए, गांधीवाद की दुहाई देने हुए ऐसा कर रहे हैं।—

गांधीजी का भाषा-नीति का पहला सूत्र है, भाषा-समस्या का समाधान जनता के हित में हो।

नता अंग्रेजी में भाषण दें, जनता समझे नहीं। ऐसे नेता न तो देश में कोई बड़ा परिवर्तन कर सकते थे, न उनकी राजनीति जनता की राजनीति बन सकती थी। जो नेता अंग्रेजी में ही बोलने की छिद करते थे और हिन्दी सीखने में इन्कार करते थे, उनके लिए गांधीजी ने सन् '२७ में लिखा था, “वास्तव में वे अंग्रेजी में बोलनेवाले नेता हैं जो आम जनता में हमारा काम जल्दी आगे बढ़ने नहीं देते। वे हिन्दी सीखने से इन्कार करते हैं जबकि हिन्दी ब्रिटिश प्रदेश में भी तीन महीने के अन्दर सीखी जा सकती है, अगर सीखने-वाने इसके लिए तीन घंटे हर रोज दें।” (वाल्म जीन नगनल लैंग्वेज, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद, पृ० २३)।

गांधीजी ने नेताओं का अंग्रेजी बोलना छुड़ाया। उनके सपनों के फलस्वरूप कम-से-कम अब अपने प्रदेशों में वे जनता के सामने अंग्रेजी में भाषण नहीं करत। लेकिन उनका राजनीतिक-नामकृतिक कार्य अब भी बहुत कुछ अंग्रेजी में होता है। अब राज्यसत्ता कांग्रेसी नेताओं के हाथ में है। यह राज्यसत्ता, उसे चलावेवाला नीकरसाही क्या किस्म का है? स्वराज्य किसके लिए है? सन् '३१ में गांधीजी ने लिखा था, “यदि स्वराज्य

अंग्रेजी-पढ़े भारतवासियों का है और केवल उनके लिए है, तो सम्पर्क भाषा अवश्य अंग्रेजी होगी। यदि वह करोड़ों भूखे लोगों, करोड़ों निरक्षर लोगों, निरक्षर स्त्रियों, सताये हुए वछूतों के लिए है तो सम्पर्क भाषा केवल हिन्दी हो सकती है।” (उप०, पृ० ३१)

इसलिए यदि जनतन्त्र जनता का है और जनता के लिए है तो उसमें अंग्रेजी के लिए जगह न होनी चाहिए। अंग्रेजी को अपनानेवाले वे लोग हैं जो भाषा-समस्या पर जनता के हितों को ध्यान में रखकर विचार नहीं करते। उन्होंने लिखा था, “कुछ लोग जो अपने दिमाग से जनता की बात एकदम निकाल देते हैं, वे यही नहीं कहते कि अंग्रेजी भी सम्पर्क भाषा हो सकती है, वे कहते हैं कि अंग्रेजी ही एकमात्र सम्पर्क भाषा हो सकती है।” (उप०, पृ० ३०)

जो राजनीतिज्ञ जनता-जनता सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं, वे अपनी राजनीतिक कार्यवाही में इसी जनता की उपेक्षा करते हैं। गांधीजी मार्क्सवादी-लेनिनवादी नहीं थे लेकिन लेनिन की भाषा-सम्बन्धी नीति का सारतत्त्व उन्होंने ग्रहण कर लिया था। उन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा अंग्रेजी के व्यवहार की आलोचना करते हुए तन् ३७ में लिखा था, “उनके लेख अंग्रेजी न जाननेवालों के लिए गुप्त खजाना (सील्ड बुक) हैं। लेकिन रूस का हाल देखिए। वहाँ क्रान्ति से पहले ही तमाम पाठ्य पुस्तकें (वैज्ञानिक पुस्तकों समेत) रूसी में छपती थी। दरअसल इसी बात ने लेनिन की क्रान्ति के लिए मार्ग तैयार किया। हम आम जनता से सच्चा सम्पर्क तब तक कायम नहीं कर सकते, जब तक कांग्रेस यह फैसला नहीं करती कि उसका सारा विचार-विमर्श हिन्दी में होगा और उसके प्रान्तीय संगठनों का काम प्रान्तीय भाषाओं में होगा।” (उप०, पृ० ५३)

विभिन्न प्रदेशों के बीच विदेशी भाषा को अपनी सम्पर्क-भाषा बनाकर कोई भी देश जन-क्रान्ति नहीं कर सकता। क्रान्ति का अर्थ मुट्ठी-भर आदमियों द्वारा खूनखराबी करना नहीं होता। क्रान्ति का अर्थ है, समाज-व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन लाना। इस तरह के परिवर्तन आम जनता के सहयोग के बिना कभी नहीं लाये जा सकते। जो देश पराधीन हैं, वे आम जनता के संघर्ष के बिना स्वाधीन नहीं हो सकते; और जो देश स्वाधीन हैं, वे आम जनता की दृढ़ एकता और समर्थ राजनीतिक कार्यवाही के बिना अपनी स्वाधीनता की रक्षा नहीं कर सकते।

कुछ लोग समझते हैं कि सम्पर्क भाषा तो मन्त्रियों, नेताओं, बड़े-बड़े अफसरों वगैरह के लिए ही जरूरी है। आम जनता अपनी प्रादेशिक भाषाएँ बोलती ही है; उसे सम्पर्क भाषा से क्या लेना-देना है? ऐसा सोचनेवाले अपने को शासक और जनता को शासित समझते हैं। उनके लिए नौकरशाह जनता के नौकर नहीं हैं, वे उसके बादशाह हैं। जिन पार्टियों के हाथ में राज्यसत्ता नहीं है, जिनके नेता निकट भविष्य में मन्त्री बनने के उम्मीदवार हैं, वे भी अज्ञाने अपने को जनता का सेवक नहीं हुक्मरान समझने लगे हैं। इसलिए वे अंग्रेजी को सम्पर्क भाषा बनाकर चैन से अपनी गद्दियों पर बैठे हुए हैं।

इन सबसे भिन्न गांधीजी का मत था कि सम्पर्क नेताओं में ही नहीं, विभिन्न प्रदेशों

की जाम जाता में होना चाहिए। उन्होंने लिखा था, "आप और हम चाहते हैं कि करोड़ा आदमी अनप्राप्तीय सम्पर्क बाधित करें। स्पष्ट है कि अंग्रेजी के द्वारा, कई पीढ़ियों गुजर जान पर भी, वे परस्पर सम्पर्क स्थापित न कर सकेंगे।" (१९०७, उप०, पृ० ४८)। यदि हमारे देश के जनवादी, समाजवादी, मार्क्सवादी-लेनिनवादी राजनीतिज्ञ गांधीजी की इस बात का मानें कि करोड़ा जनता को आपस में राष्ट्रीय स्तर पर सम्पर्क बाधित करना है, तो वे गहन आगे बढ़कर हिन्दी प्रचार के काम में हिम्मा बँटाएँ, वे अंग्रेजी की छतरी के नीचे बैठकर दूर से हिन्दी की मुताधीनी न करने रहें।

देगव्यापी सम्पर्क जनता का, स्वराज्य करोड़ा अक्षिगण और निधन लोगों के लिए, नेता और जनता के बीच सबसे बड़ी दीवार अंग्रेजी—यह हुआ गांधीजी की भाषा-नीति का पहला सूत्र।

गांधीजी के लिए भाषा समस्या कोई शुद्ध भाषा विज्ञान की समस्या नहीं थी। उन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन के सदर्भ में ही उस पर विचार किया था। अंग्रेजों ने भारतीय जनता को गुलाम बनाने के साथ उसकी भाषाओं का दमन किया, उस पर अंग्रेजी लादी। अंग्रेजी का बनन राजनीतिक-सांस्कृतिक पराधीनता का अंग था, उसे सम्पर्क भाषा के पद से हटाता राजनीतिक-सांस्कृतिक स्वाधीनता के लिए आवश्यक था। अंग्रेजी की जगह भारतीय भाषाओं का व्यवहार राष्ट्रीय आत्मसम्मान की रक्षा का प्रदत्त था।

उनकी भाषा-नीति का दूसरा सूत्र है राष्ट्रीय आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अंग्रेजी का प्रभुत्व खत्म करो।

१९०६ में गांधीजी ने लिखा था, "क्या वे लोग जो अपनी मानुभाषा का अपमान करते हैं, कभी देश का भला कर सकत हैं? मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता कि गुजरात के लोग अपनी मानुभाषा छोड़कर अन्य कोई भाषा अपना लें। ऐसा हो तो यह कहने में जरा भी जतिशयोक्ति न होगी कि जो लोग अपनी भाषा छोड़ देते हैं, वे देशद्रोही हैं और जनता के प्रति विश्वासघात करने हैं।" (उप०, पृ० १८६)

जो लोग अंग्रेजी में उपन्यास और कहानियाँ लिखकर अल्लरॉन्डूनि हयानि अजिन करते रहे हैं, वे गांधीजी के इन वाक्यों पर गंभीरता से विचार करें।

गांधीजी ने गुजराती भाषी शिक्षित जनो में मानुभाषा का प्रेम जगाया अंग्रेजी बोलने पर उनकी लानत-मनामत की। गुजरात के नवीन साहित्यिक अभ्युत्थान में उनका योगदान अनुपम है। दिसम्बर, १९१५ में सग्राधपुर, मूरत के जैन विद्यार्थियों ने गांधीजी की अपने पुस्तकालय का उद्घाटन करने के लिए बुलाया। गांधीजी के बोलने की बात सुनकर वहाँ बड़ा जल-समुदाय एकत्र हो गया। एक विद्यार्थी ने अंग्रेजी में भाषण किया। दूसरा खड़ा हुआ, उसने अंग्रेजी में निबन्ध पढ़ा। गांधीजी ने इन अंग्रेजी बोलनेवाला को लपट करके कहा, "यदि अंग्रेजी जाननेवाले मुठ्ठीभर लोगो को हम देश मान लें तो कहना होगा कि हमने देश शब्द का अर्थ नहीं समझा।" उन्होंने उन लोगों को फटकारा जो कहते थे कि वे मानुभाषा में अपने विचार अच्छी तरह प्रकट नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, "जो

युवक यह कहते हैं कि हम अपने विचार मातृभाषा द्वारा नहीं प्रकट कर सकते, उनसे मैं यही निवेदन करूँगा कि आप मातृभाषा के लिए भार-रूप हैं। मातृभाषा की अपूर्णता दूर करने के बदले उसका अनादर करना—उससे हाथ ही धो बैठना—किसी सच्चे सपूत को शोभादायक नहीं।”

यह फैशन अभी तक बना हुआ है कि जिनके पास कहने को कुछ नहीं है वे भी कण्ठ से क्षमा-याचना करते हुए जनता से कहते हैं, हम हिन्दी में अपने विचार ‘फ्लुएंटली’ प्रकट नहीं कर सकते ! मातृभाषा की अपूर्णता दूर करना इनके वश की बात नहीं ; वे अंग्रेजी के भारवाही बनकर मातृभाषा और मातृभूमि के लिए केवल भार-रूप हैं !

गांधीजी गुजराती के, समस्त भारतीय भाषाओं के सम्मान के लिए लड़े। उनके इस संघर्ष का आदर करनेवालों में आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी भी थे। उन्होंने गांधीजी का उपर्युक्त भाषण मार्च, १९१६ की ‘सरस्वती’ में छापा था। भाषण को हिन्दी में अनुवादित करके भेजा था गुजराती सज्जन श्री मणिभाई व्यास ने।

दिसम्बर, १९१६ में गांधीजी ने देवनागरी लिपि और हिन्दी भाषा के प्रचारपर लखनऊ में भाषण दिया। आठ-दस हजार श्रोताओं के बीच उन्होंने यह भाषण हिन्दी में दिया। अपने हिन्दी सीखने और हिन्दी के लिए अपमानित होने के बारे में उन्होंने ये मर्मस्पर्शी शब्द कहे थे—

“जिन प्रान्तों में हिन्दी का प्रचार कम है वहाँ हिन्दी पढ़नेवालों की बड़ी कमी है। मैं स्वयं हिन्दी सीखना चाहता था। पर अहमदाबाद में कोई हिन्दी-ज्ञाता शिक्षक न मिला। मिला वेचारा एक गुजराती-भाषाभाषी, जिसने पन्द्रह-बीस वर्ष काशी में रहकर टूटी-फूटी हिन्दी सीखी थी। उसी से मैंने हिन्दी सीखी। सम्मेलन यदि अन्य भाषा-भाषी प्रान्तों में आदमी भेजे तो बहुत से लोग हिन्दी सीख जाएँ।”

हिन्दी की दरिद्रता के गीत गाते अंग्रेजी-प्रेमी भारतवासी थकते नहीं हैं। पता नहीं इनकी संख्या पहले ज्यादा थी, या अब है। गांधीजी ने इन लोगों को लक्ष्य करके कहा था, “लोग कहते हैं कि हिन्दी में कुछ नहीं है—हिन्दी साहित्य खोखला है—अतएव अंग्रेजी के बिना काम नहीं चल सकता। कभी-कभी तो अंग्रेजी न जानने के कारण लोगों को वृथा ही बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। यह मैं भी मानता हूँ। यहाँ तक कि मुझ-जैसे लोगों को, हिन्दी का व्यवहार करने के कारण—हिन्दी बोलने के कारण—रेलवे इत्यादि में धक्के भी खाने पड़ते हैं। अंग्रेजी से हिन्दी कितना ही पीछे क्यों न हो, हमें उसका गौरव बढ़ाना ही पड़ेगा।”

राष्ट्र के जो नेता आज हवाई जहाजों और ‘एयर कंडीशण्ड’ गाड़ियों में सफ़र करते हुए अंग्रेजी को सम्पर्क भाषा का गौरव प्रदत्त करते हैं, क्या वे कभी धाद करते हैं कि अंग्रेजी-रेलो के यात्री मोहनदास कर्मचन्द गांधी को हिन्दी बोलने के कारण धक्के खाने पड़े थे ? वे राष्ट्रपिता की जय बोलते हैं, राष्ट्रपिता के नाम पर जनता को अध्यात्मवाद के उपदेश देते हैं, राष्ट्र के नाम पर सन्देश प्रसारित करते हैं, उस भाषा में

त्रिमका व्यवहार गांधीजी राष्ट्र सम्मान के प्रतिकूल समझते थे।

गांधीजी ने अंग्रेजों के सामने, उच्चतम अंग्रेज पदाधिकारियों के सामने, महा-प्रतापी ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतिनिधि वाइसराय के सामने भारतीय भाषाओं के गौरव की रक्षा की। उगी भाषण में उन्होंने कहा था, "नरकारी बोलियों में अंग्रेजी की प्रशंसा है—उसी का विनाश आदर है। जोग बहन हैं कि वाइसराय इत्यादि अंग्रेजी के अतिरिक्त और कोई भाषा नहीं समझते। अतएव अंग्रेजी का ही उपयोग करना आवश्यक है। पर मैं कहना चाहता हूँ कि यदि मैं बातें जानता हूँ और मेरे कंधन में कोई बात ऐसी है जिसमें वाइसराय लाभ उठा सकें तो अवश्य मैंने बाने, हिन्दी में हाने पर भी, मुनेंगे। आपकी जगह दुःख और झलावा में काम लेना चाहिए। आमावलम्ब किए बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता।"

नव अंग्रेज वाइसराय नहीं हैं। लेकिन मनोवृत्ति बड़ी है। अंग्रेजी बोलने में लोग गारव का अनुभव करने हैं। हमने राष्ट्रीय आत्मसम्मान की भावना क्षीण होनी है। अंग्रेज वाइसराय एक बार किसी का हिन्दी में बोलने की अनुमति भी दे दें लेकिन यदि स्वाधीन भारत की लोकमता में कोई भी हिन्दी में बोलें तो महाक्रान्तिकारी कामरेड गोपालन 'बाक आउट कर देते हैं'। गांधीजी ने केवल दूगरा को वाइसराय के सामने हिन्दी बोलने का उपदेश न दिया था, उन्होंने माहम से अपने उपदेश के अनुसार आचरण भी किया था।

१९३१ में संयुक्त भारत के चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अधिवेशन कराची में हुआ। उसमें विभिन्न प्रान्तों के मेठ और व्यापारी मौजूद थे। अंग्रेज भी थे। किन्तु गांधीजी ने अपना भाषण हिन्दी में दिया। इस भाषण में उन्होंने बताया कि सन् '१९ में वाइसराय के सामने वह हिन्दी में बोलें थे। तब '१९ में अंग्रेज वाइसराय अंग्रेज और अंग्रेजियत का वह आनक। उस घातावरण में वाइसराय के सामने हिन्दी बोलने खड़े हुए कमंडोर गांधी।

—कराचीवाले भाषण में उन्होंने कहा था, "मेरे अंग्रेज मित्र मुझे समझा करेंगे कि जो कुछ मुझे कहना है, वह मैं राष्ट्रभाषा में कहूँगा। इस अवसर पर मुझे उस सभा की याद आती है जो यहाँ १९१९ में बुलाई गई थी। बहुत बहस सुनाहने के बाद जब मैं इस सभा में आने को तैयार हुआ तो मैंने उसमें प्रार्थना की कि मुझे हिन्दी या हिंदुस्तानी में बोलने की अनुमति दी जाय। मैं जानता हूँ कि इसके लिए प्रार्थना करना जरूरी नहीं था, फिर भी सम्मता का लक्ष्य था, करना वाइसराय को बुरा लगता। उन्होंने तुरंत मुझे अनुमति दे दी और तब से इस मामले में मेरी हिम्मत और खुल गई है। और आज फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका यह कर्तव्य है कि अपना सारा काम राष्ट्रभाषा में करें। इस संगठन में आपको अपनी जनता में ही वास्ता पड़ता है। देश का वातावरण भी इस समय ऐसा है कि उसका प्रभाव आप पर भी जरूर पड़ेगा।" (उप०, पृ० २४) —

आज किसी अविन भारतीय संगठन में लोग से कहा जाय कि अपना काम

राष्ट्रभापा में कीजिए तो बहुत से देशभक्त कह उठेंगे—हम पर हिन्दी लादी जा रही है ! उन पर अंग्रेजी पहले से लदी हुई है, यह वे भूल जाते हैं। अंग्रेजी के लिए स्वेच्छा, हिन्दी के लिए अनिच्छा—यह है उनकी देशभक्ति !

५ जुलाई, १९२८ के 'यंग इंडिया' में गांधीजी ने अंग्रेजी के प्रभुत्व से होनेवाली देश की हानि के बारे में लिखा था, हजारों नवयुवक अपना कीमती समय इस विदेशी भाषा को सीखने में नष्ट करते हैं जब कि उनके दैनिक जीवन में उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, अंग्रेजी सीखने में समय लगाते हुए वे मातृभाषा की उपेक्षा करते हैं, वे इस अन्ध-विश्वास के शिकार होते हैं कि ऊँचे दर्जे के विचार अंग्रेजी ही में प्रकट किए जा सकते हैं, अंग्रेजी के लादे जाने से राष्ट्र की शक्ति मूल गई है, विद्यार्थियों की आयु क्षीण हो गई है, आम जनता से वे दूर जा पड़े हैं, शिक्षा पाना बड़े खर्च का काम हो गया है। "यदि यही सिलसिला जारी रहा तो बहुत सम्भव है कि राष्ट्र की आत्मा का नाश हो जाय।"

और सब तरह की हानि तो होती ही है, खर्च ज्यादा होता, उम्र कम होती है, मातृभाषा की उपेक्षा होती है; गांधीजी के लिए सबसे बड़ा खतरा यह था कि अंग्रेजी का प्रभुत्व राष्ट्र की आत्मा का नाश कर देगा। वह ऐसा क्यों सोचते थे ? इसलिए सोचते थे कि वह स्वाधीनता-आन्दोलन के सन्दर्भ में भाषा-समस्या पर विचार करते थे। उनके लिए प्रश्न यह नहीं था कि अंग्रेजी विश्व-भाषा है और हिन्दी दरिद्र है; प्रश्न यह था कि विदेशी भाषा के व्यवहार से राष्ट्रीय चरित्र पर असर क्या पड़ता है। इसलिए वह तुरन्त अंग्रेजी को विदा करने के पक्ष में थे। लेकिन जिसे गांधीजी राष्ट्र की आत्मा कहते थे, उसे अंग्रेजी-प्रेमी नेता मानसिक संकीर्णता कहते हैं !

गांधीजी अंग्रेजी पढ़ने के विरुद्ध नहीं थे। वह उसे वाणिज्य और कूटनीति की भाषा मानते थे। किन्तु वह यह सहन न कर सकते थे कि वह किसी भारतीय भाषा के हक मारे। वह बहुत अच्छी तरह जानते थे कि अंग्रेजी का विश्व-महत्त्व ब्रिटिश साम्राज्य के कारण है। उन्होंने १९१८ में ही घोषित किया था, "हमें ऐसी हालत पैदा कर देनी चाहिए कि हमारे राजनीतिक या सामाजिक सम्मेलनों में, कांग्रेस तथा प्रांतीय सभाओं आदि में अंग्रेजी का एक शब्द भी न सुना जाय। अंग्रेजी का व्यवहार हमें पूरी तरह बन्द कर देना चाहिए। अंग्रेजी ने विश्वभाषा की जगह पा ली है लेकिन यह इसलिए कि अंग्रेज सारी दुनिया में फैल गए हैं और हर जगह अपने पैर उन्होंने जमा लिये हैं। जब उनकी यह स्थिति नहीं रहेगी, तब अंग्रेजी का प्रसार भी संकुचित हो जाएगा।" (उप०, पृ० ६)

साम्राज्यवाद के पतन के साथ अंग्रेजी के प्रसार का दायरा कम हो गया है। अन्य भाषाएँ विश्व-स्तर पर अंग्रेजी से स्पर्धा करती हैं। बोलनेवालों की संख्या की दृष्टि से संसार की तीसरी भाषा हिन्दी भी विश्वभाषा के रूप में अंग्रेजी का महत्त्व कम कर सकती है, विश्वभाषा के रूप में उससे स्पर्धा कर सकती है यदि अंग्रेजी-प्रेमी भारतवासी अपने देश को अंग्रेजी की गुलामी से आजाद कर दें।

सन् '४५ से पहले हर देशभक्त मानता था कि अंग्रेजी का व्यवहार; शिक्षा-संस्थाओं,

राजनीतिज्ञ सगठों आदि में अंग्रेजी का चयन मानसिक पराधीनता का लक्षण है। राजा राममोहन राय जैसे समाज-सुधारक समझते थे कि भारत की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी हो जाएगी। ६ जून, १८६४ के "यू एन" (साप्ताहिक) में डी० सी० होय नाम के सम्पादन में लिखा है कि उत्तरीमहदी सदी के मध्य में जब भारत में नया औद्योगिक युग शुरू हो रहा था, तब भारत के प्रमुख नागरिकों ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए गुरु-छात्रद्वारा आन्दोलन किया। राजा राममोहन राय ने इनका नेतृत्व किया।

दिनचरम बात है कि जो भी अंग्रेजी को भारत की अमली राष्ट्रभाषा मानता है वह किसी-न किसी रूप में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की प्रगतिशील भूमिका भी मानता है। डी० सी० होय के अनुसार "प्लानी के मतानुसार यह बाद, यानी जब ब्रिटिश साम्राज्यवाद की वस्तुगत रूप में प्रगतिशील भूमिका का एक चक्कर पूरा हो गया था, तब क्या हमने यह पता नहीं चलता कि समाज में नया काय पूरा करने की उम्मीदना पैदा हो गई थी?"

जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हर देश में समाजवाद अपने-दगमें आता है और उसका अपना रूप होता है वैसे ही क्या अजब कि हर देश में पूँजीवाद भी अपने-दग में आए और उसका अपना रूप हो। भारतीय पूँजीवाद की विशेषताएँ क्या हैं? इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह आरम्भ में ही अंग्रेजी बोलना रहा है। आखिर देश की एकता तो कायम रखनी ही थी, यहाँ मस्तूत राष्ट्रभाषा बन न सकती थी। प्रादेशिक भाषाएँ बोलियाँ थीं नहीं कि वे किसी एक राष्ट्रभाषा के नीचे दब जायें। द्रविड और मस्तूत भाषा-परिवारों का नेद अलग! अंग्रेजी के सिवाय भारतीय पूँजीवाद कौन-सी भाषा बोलता? इसलिए जिन लोगों ने साइ-सैकान के लिए गम्भीर साफ़ किया, जिन्होंने मैकाने की भाषा-नीति का समर्थन किया, वे सब प्रगतिशील थे। जितनी अंग्रेजी का विराय विषा, वे सब दक्षिणानुमी और प्रतिक्रियावादी थे।

मस्तूत और द्रविड परिवारों में ऐसी भयानक शत्रुता है ही मनमाना, वेतु आदि भाषाओं में मस्तूत के इनने शब्द कैसे पहुँच गए? द्रविड देश के इन-राजाय में मस्तूत में अपने विचार क्यों प्रकट किए? क्या उस समय तक कोई द्रविड भाषा उगल ही न हुई थी? वह समिल कहाँ थी जो प्राचीनता में समकक्ष कही जाती है?

वास्तव में यहाँ तमिल भी थी, जनेक द्रविड और गैर-द्रविड भाषाएँ भी थीं। फिर भी शिक्षितजन मस्तूत का व्यवहार करते थे क्योंकि सामन्ती व्यवस्था ने वायबूद, डी० सी० होय सम्प्रदाय की अपथा, उनमें राष्ट्रीयता का बोध पैदा था।

जनता के दृष्टिकोण से न सीधे पर आज के मुमराह प्रगतिशील विचारकों की पूँजीवाद और समाजवाद दाना के विकास के लिए अंग्रेजी आवश्यक दिखाई देती है।

श्री मोहनकुमार भगलम ने 'भारत का भाषा-संकट' नामक पुस्तक में लिखा है, "हम यह याद किये बिना नहीं रह सकते कि महान् राजा राममोहन राय उस दिन का स्वप्न देखते थे, जब भारत की भाषाएँ समकक्ष से हो-जायेंगी और अंग्रेजी यहाँ की करोड़ों जनता की सामान्य भाषा हो जाएगी।" (पृ० ४)

लार्ड मैकाले और इन महान् समाज-सुधारकों का सम्बन्ध इस प्रकार है, “इस तरह इन प्रारम्भिक समाज-सुधारकों ने भी अंग्रेजी को उठाने और भारतीय भाषाओं का विकास रोकने में लार्ड मैकाले के प्रयत्न में मदद दी।” (पृ० ५)

भारत की भाषाओं और संस्कृति की हालत उस समय क्या थी ? “भारत और पूर्व की संस्कृति अधिक प्राचीन थी परन्तु इस समय वह ठहराव की हालत में (स्टैगनेन्ट) थी। वह पश्चिम के शक्तिशाली सांस्कृतिक उभार के सम्पर्क में आई।”

भले ही शेली, मैथ्यू आर्नल्ड, येट्स आदि लेखक भारतीय संस्कृति से प्रभावित रहे हों, श्री मोहनकुमार मंगलम के लिए यहाँ की संस्कृतिगतिरुद्ध ही थी। इसीलिए आज राजभाषा के पद के लिए तमिल को योग्य बनाना उन्हें हिमालय पहाड़ उठाने जैसा लगता है। (उप०, पृ० ६८)

होम और मोहनकुमार मंगलम दोनों का मत है कि भारत में संस्कृत के बाद कोई भी सम्पर्क भाषा न थी। इसलिए अंग्रेजी सम्पर्क भाषा के रूप में स्वाधीनता-प्राप्ति के पहले भी जरूरी थी और आज भी जरूरी है। भारतीय इतिहास के ये विशेषज्ञ भूल जाते हैं कि अंग्रेजों का राज कायम होने से पहले यहाँ सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी का प्रचार और प्रसार सर्वत्र था। इसीलिए अंग्रेजों ने अपने अफसरों के लिए हिन्दुस्तानी का ज्ञान अनिवार्य कर दिया था।

दिल्ली के असिस्टेंट रेजिडेंट मेटकाफ ने २६ अगस्त, १८०६ को हिन्दुस्तानी के अपने शिक्षक गिलक्रिस्ट के नाम एक पत्र में लिखा था, “भारत के जिस भाग में भी मुझे काम करना पड़ा है, कलकत्ता से लेकर लाहौर तक, कुमाऊँ के पहाड़ों से नर्मदा तक, अफगानों, मराठों, राजपूतों, जाटों, सिखों और उन प्रदेशों के सभी कबीलों में जहाँ मैंने यात्रा की है, मैंने उस भाषा का आम व्यवहार देखा है जिसकी शिक्षा आपने मुझे दी थी। अपने अनुभव से और दूसरों से सुनी हुई बातों के बल पर मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक या आवा से सिंधु के मुहाने तक इस विश्वास से यात्रा करने की हिम्मत कर सकता हूँ कि मुझे हर जगह ऐसे लोग मिल जाएँगे जो हिन्दुस्तानी बोल लेते होंगे।” (जे० बी० गिलक्रिस्ट, ‘ए वार्कबुलरी, हिन्दुस्तानी एण्ड इंग्लिश, इंग्लिश एण्ड हिन्दुस्तानी, एडिनबरा में उद्धृत)

राजा राममोहन राय ने अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए मेमोरैंडम पेश किया, होम-सम्प्रदाय को यह तो दिखाई देता है लेकिन जिस भाषा को कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की करोड़ों जनता अपनी सम्पर्क भाषा बना रही थी, वह उन्हें बहुत आँखें गड़ाकर देखने पर भी नहीं दिखाई देती।

गांधीजी न लार्ड मैकाले के रोव में थे, न राजा राममोहन राय के। उन्होंने सन् २० में लिखा था, “हम अपने विचार से अपने राष्ट्रीय जीवन में प्रादेशिक भाषाओं (वनविथुलर्स) को उनका उचित स्थान दे रहे हैं। भाग्य राजा राममोहन राय की इस भविष्यवाणी का साथ नहीं दे रहा कि भारत एक दिन अंग्रेजी-भाषी देश हो जाएगा।



नेकिन उस महान् समाज-सुधारक का भूत अब भी कुछ लोगो पर मवार है। कुछ प्रसिद्ध आदमी बहुत जल्दी यह फमला दे देते हैं कि राष्ट्र की सम्पत्ति भाषा अंग्रेजी होगी।" (घॉटस ऑन नेशनल नेक्विजि, पृ० १७)

गांधीजी का भी सम्बन्ध भारतीय पूजावाद के विकास में रहा है। उनके स्वदेशी आन्दोलन से भारतीय पूजापनियारो अपने उद्योग धर्मों में विकसित करने में सहायता मिली। बिड़ला जैसे उद्योगपति गांधीजी के मजदूरी की लोगो में थे। होम मन्त्रालय का मन्त्री बीस के बाद का पूजावादी विकास नहीं दिखाई देता क्योंकि तब अंग्रेजी का विरोध और भारतीय भाषाओं का समर्थन जाना गया था।

गांधीजी को उल्टा मैकाले यहाँ से बराबर सावका पड़ा होगा। ये लोग सीधे मैकाले का नाम न लेकर राजा राममोहन राय की दुहाई देते रहे होंगे। इसीलिए राममोहन राय का नाम अकसर उनके लेखों में जाता है। सन् '२१ में उन्होंने इस बात पर दुःख प्रकट किया था कि अंग्रेजी ने प्रान्तीय भाषाओं की जगह ले ली है। उन्होंने कहा था कि राजा राममोहन राय और भी बड़े समाज-सुधारक होते यदि वह अंग्रेजी में सोचने और उसी में अपने विचार प्रकट करने की अस्वाभाविक क्रिया न करनी पड़ती। (उप०, पृ० २०१)

अंग्रेजी के आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका आदि में भ्रमक वहाँ की भाषाओं का नाश किया। लाला लोप्रोजन अपनी भाषाएँ छोड़कर—गुनाम बनाए जाकर—अंग्रेजी-भाषी हो गए। भारतीय जनता ने १८५७ में अंग्रेजों को उस जा घानी, भाषा-घाती नीति पर चमने का मजा चखा दिया। सन् १८५७ में पहले भी महाराष्ट्र के शिक्षा शास्त्रिया ने जमकर मैकाले की भाषा-नीति का विरोध किया। वहाँ के समाज-सुधारक डी० सी० होम एण्ड कम्पनी को नहीं दिखाई देना। "दिया लोम चममा चन्नि लघू पुनि बडो दिवाय।" अंग्रेजियत के चरमे से अंग्रेजी-परमा तो बहुत बड़े समाज सुधारक मालूम होते हैं, अंग्रेजी का विरोधी इतने छोट हो जाने हैं कि उनके अस्तित्व का उतना भी आवश्यक नहीं होता।

गांधीजी ने राजा राममोहन राय के साथ लोकमान्य तिलक का नाम भी लिया था और कहा था कि यदि उनकी शिक्षा दीक्षा कम अस्वाभाविक व्यवस्था में हुई होती तो जनता पर उनका प्रभाव और भी गहरा पड़ा होता।

लोकमान्य तिलक मराठी के समर्थ लेखक थे। वह भारतीय भाषाओं का ध्यान अंग्रेजी का देने के पक्ष में नहीं थे। इसके अलावा राजा राममोहन राय के विपरीत वह हिन्दी को राष्ट्रभाषा मानते थे। कानपुर में जनता ने उनका स्वागत किया तो उन्होंने इस बात पर शेर प्रकट किया कि वह हिन्दी में भाषण नहीं कर सकते। "यद्यपि मैं उन लोगो में से हूँ जो चाहते हैं और जिसका विचार है कि हिन्दी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है। मैं हिन्दी समर्थक हूँ और टूटी-फूटी बोली भी सकता हूँ, व्याख्यान नहीं दे सकता।" ('सरस्वती', फरवरी, १९१७)

इस विचार को अमली रूप देने के लिए उन्होंने 'केसरी' का एक हिस्सा हिन्दी में प्रकाशित करना शुरू कर दिया था।

लोकमान्य तिलक जैसे समाज-सुधारक होम-जैसे अंग्रेजी-प्रेमियों की दृष्टि से ओझल रहते हैं।

स्वाधीनता-प्राप्ति से साल-भर पहले गांधीजी ने उस दिमागी गुलामी की निन्दा की थी जो अंग्रेजी को अपनी राजाभाषा बनाने के लिए नेताओं को मजबूर करती है। सोवियत संघ की मिसाल देते हुए उन्होंने लिखा था, "रूस ने अपनी सारी वैज्ञानिक प्रगति अंग्रेजी के बिना ही की है। यह हमारी दिमागी गुलामी है जो हम कहते हैं कि अंग्रेजी के बिना काम नहीं चल सकता। मैं इस पराजवादी मत को कभी स्वीकार नहीं कर सकता।" (उप०, पृ० २०१)

स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद गांधीजी ने २१ सितम्बर, १९४७ के 'हरिजन' में 'दिमागी क्राहिली' की निन्दा की जिससे प्रेरित होकर अफसर और नेता कहते थे कि शिक्षा और शासन में अंग्रेजी ही चलेगी।

गांधीजी ने अपने राजनीतिक जीवन के आरम्भ से लेकर भारत के स्वाधीन होने के बाद तक, अपने जीवन की आखिरी घड़ियों तक अंग्रेजी का विरोध किया, अंग्रेजी के ऊपर निर्भर रहने की आदत को राष्ट्र के लिए हानिकार बताया, अंग्रेजी की हिमायत को राष्ट्रीय चरित्र के लिए घातक बताया। जो लोग अंग्रेजी कायम रखकर भाषा-समस्या का समाधान खोजते रहे हैं, उनमें राष्ट्रीय आत्मसम्मान की कमी है। —

— राष्ट्रभाषा की समस्या राष्ट्रीय चेतना के आधार पर ही हल हो सकती है। जो लोग भाषा-समस्या को साम्राज्य-विरोधी संघर्ष के सन्दर्भ से अलग हटाकर हल करना चाहते हैं, वे समस्या को बराबर उलझाते जाएंगे, उसे सुलझाना उनके लिए सम्भव न होगा। यह गांधीजी का दूसरा सूत्र हुआ। —

— गांधीजी का तीसरा सूत्र है—भारतीय जनता की अमली राष्ट्रभाषा हिन्दी है। यदि राजनीतिज्ञ जनता के व्यवहार को देखें, इस बात को समझें कि अंग्रेजी न जाननेवाले साधारण जनों को भी परस्पर सम्पर्क के लिए एक सामान्य भाषा की जरूरत होती है, तो उन्हें यह दिखाई देने लगे कि जनता के अन्तर्प्रदेशिक सम्पर्क की भाषा कौन-सी है। महाराष्ट्र-गुजरात-पंजाब के लोग आपस में हिन्दी को सम्पर्क भाषा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इसे बहुत-से लोग मानते हैं। सवाल है दक्षिण भारत का। क्या वहाँ के साधारण लोग भी हिन्दी को सम्पर्क भाषा के रूप में अपनाते हैं?

गांधीजी ने दक्षिण अफ्रीका के अपने इस अनुभव का उल्लेख किया था कि वहाँ तमिल और तेलुगु बोलनेवाले लोग परस्पर सम्पर्क के लिए हिन्दी काम में लाते हैं। जो कार्य वे दक्षिण अफ्रीका में करते थे, उसे वे दक्षिण भारत में भी अवश्य करते रहे होंगे। वास्तव में तमिल-तेलुगु-भाषियों को उत्तर भारत से सम्पर्क कायम करने के लिए ही हिन्दी की जरूरत नहीं होती, उन्हें आपस में सम्पर्क-भाषा के लिए भी जरूरत हिन्दी की होती है।

एक मिन ने जर्मन में मुझे वही की भाषा स्थिति के बारे में यह लिखा है, "अधिकतर यहाँ बेंगला, उमिन, तेलुगु, कन्नड और मलयालम बोली जाती हैं। आप में व्यवहार की भाषा हिन्दी है जो 'हम' बोलता है, आप करना माँगा है' पद्धति में बोली जाती है। हिन्दी ही गण्डभाषा है यहाँ स्वयं मित्र हो जाता है। समित तेलुगु ने हिन्दी में ही बोल कर पाना है। इसी प्रकार अन्य भाषा-भाषी।" —

दक्षिण भारत में गांधीजी का अनुभव ऐसा ही था, "यह कहना सही नहीं है कि मद्रास में जेजेजी व बिना काम नहीं चलना। मैंने अपने सारे कामों के लिए यहाँ सफ़ाया-पूर्वक हिन्दी का व्यवहार किया है। मैंने रेल में मद्रासी मुसाफ़ियों को दूंगों से हिन्दी में बोलें बतल सुना है।" (उप०, पृ० ६)

सौ० एफ० एण्ड्रूज का अनुभव भी यही था। उनकी मातृभाषा अंग्रेज़ी थी लेकिन उन्हें हिन्दी बोलने में उतना कष्ट न होता था जितना राजगणभाषा या सांक्रमभाषा के कुछ भारतीय सदस्यों का। 'द टू इंडिया' (१९३६) पुस्तक में उन्होंने लिखा था, "बन एक व्यक्ति मुझसे मिलने आया था, उससे जब मैंने अंग्रेज़ी में बातचीत करने की काशिष की तो उसने कहा, 'उपा करके हिन्दुस्तानी में बातचीत कीजिए।' और जब मैं उस भाषा में बोला तो वह मेरी बात आगानी में समझ गया।"

राजनीतिशा को उत्तर-दक्षिण में सम्पर्क के लिए नई भाषा गढ़ना नहीं है, वह भाषा जनता में पहले से प्रचलित है, उसे केवल सरकारी स्तर पर सम्पर्क-भाषा के रूप में स्वीकार करना है। जहाँ तक बंगाल का सम्बन्ध है, वहाँ की भाषा हिन्दी के बहुत ही नजदीक है। इस मजदीरीपन के जलावा कसबता की लगभग भाषी आबादी हिन्दुस्तानी है। इस आबादी में उपादातर लोग मेहनत-मजूरी करके गुज़र करनेवाले हैं। उनके मालिकों को उनसे हिन्दी ही में बात करनी होती है। गांधीजी ने लिखा था कि "उत्तर भारत का जो भैया बम्बई के सेठ के यहाँ दरबानगोरी करता है, वह गुज़राती नहीं बोलता, उसका मालिक सेठ ही मजदूर हाकर उससे टूटी फूटी हिन्दी में बातचीत करता है" (उप०, पृ० ६)। यही स्थिति बंगाल की है। वहाँ न जाने कितने 'हिन्दुस्तानी' दरबान का काम करते रहते हैं। उनके मालिक उनसे टूटी-फूटी हिन्दी में ही बातें करने को बाध्य हुए हैं।

डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी ने पहले हिन्दी इसी तरह के लोगों से सीखी थी। 'कलकत्ता में क्षयों वचन में ही लेखक ने हाट-बाज़ारों में तथा घर के बिहारी नौकरों से बंगाल में प्रयुक्त बाज़ार हिन्दी' कहना में योग्य भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लिया था।" (भारतीय जाय भाषा और हिन्दी, पृ० २६५) यद्यपि डॉ० सुनीतिकुमार भाषा को घर्मे से और घर्मे की सन्धिति में जाइकर यह नतीजा निकालते हैं कि 'हिन्दी के सङ्ग उपादान को क्रमशः कम करने की प्रवृत्ति भारतीय परम्परा एक भारतीय सङ्घति पर प्रत्यक्ष आधार-सा है' (उप०, पृ० २३८) फिर भी वह मानते हैं कि 'हिन्दी (हिन्दुस्तानी) के सङ्गे चीबीस करोड़ धायने या समझनेवाला में से लगभग बीस करोड़ हिन्दुस्तानी का

यही सहज रूप बोलते हैं" (उप०, पृ० २०६) ; मौलवी, मुंशी और मुल्ला लोग "फारसी-भरी उर्दू का निर्माण एवं वर्द्धन करते रहे। उसी प्रकार पंडित लोग तथा अन्य लेखक लोग संस्कृत-भरी हिन्दी का निर्माण करते रहे। परन्तु साधारण जनों का हिन्दुस्थानी के विषय में एक ही रुख रहा; इनमें पश्चिमी पंजाब से लगाकर पूर्वी बंगाल तक के हिन्दू-मुसलमान सभी थे। वे अब भी, साधारण जीवन में अपने से भिन्न भाषावालों से बात-चीत करना चाहते हैं तो प्रचलित हिन्दुस्थानी का ही व्यवहार करते हैं।" (उप०, पृ० २०६)

पश्चिमी पंजाब से पूर्वी बंगाल तक, जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जन-सम्पर्क की भाषा बोलचाल की हिन्दी है। व्याकरण के अनुसार शुद्ध रूप में, संस्कृत शब्दों से सजाकर जनता इसे नहीं बोलती। उसके स्थानीय भेद हैं जैसे ब्रिटेन, अमरीका और आस्ट्रेलिया की अंग्रेजी में भेद हैं। बोलचाल की हिन्दी बंगाल में भी समझी जाती है और जनता के व्यवहार में आती है। फिर भी बंगाल में हिन्दी का तीव्र विरोध है, सभी लोगों में नहीं किन्तु मध्यवर्ग और पढ़े-लिखे लोगों में है, इसमें कोई सन्देह नहीं।

गांधीजी ने सन् २१ में 'यंग इंडिया' में लिखा था कि बंगाल के लोग अपने पूर्वाग्रह के कारण भारत की और कोई भाषा सीखना नहीं चाहते (थाॅट्स ऑन नेशनल लेन्वेज, पृ० १६)। हिन्दी-प्रचार के काम में बंगाली विद्वानों ने महत्त्वपूर्ण योग दिया है। हिन्दी के समर्थकों में डॉ० मुनीतिकुमार चटर्जी जैसे भाषाविद् रहे हैं। उन्होंने भारतीय भाषाओं के लिए—विशेषकर बंगला और हिन्दी के लिए—बहुत काम किया है। आज वह हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के विरुद्ध अंग्रेजी का समर्थन करते हैं, इससे उनका पहले किया हुआ काम निरर्थक नहीं हो जाता। उसके लिए कृतज्ञता प्रकट करना धर्म है। उनसे पहले वंकिमचन्द्र चटर्जी के समय में 'बंगदर्शन' पत्र ने लिखा था, "हिन्दी भाषा साहाय्ये भारतवर्षे विभिन्न प्रदेशेषु मध्ये जांहारा ऐक्यबन्धन सस्थापन करिते पारिवेन तांहाराई-प्रकृत भारतवन्धु नामे अभिहित हइवार योग्य।" (बालमुकुन्द गुप्त द्वारा उद्धृत, बालमुकुन्द गुप्त निबन्धावली, कलकत्ता, पृ० १५६)

फिर भी बंगाल में ऐसे बुद्धिजीवी बहुतायत से हैं जो किसी भी भारतीय भाषा को सीखना अपने लिए हेठी की बात समझते हैं। डॉ० मुनीतिकुमार चटर्जी ने ही लिखा है, "कोई भी महाराष्ट्रीय या बंगाली व्यक्ति इस बात का अनुभव नहीं करता कि अपनी मातृभाषा की अपेक्षा नागरी-हिन्दी या उर्दू के माध्यम द्वारा उच्चतर संस्कृति की प्राप्ति हो सकती है; वाजारू हिन्दी का तो प्रश्न ही दूर है।" (भारतीयआर्यभाषा और हिन्दी, पृ० २१५)

इसी तरह तमिलनाडु के श्री मोहनकुमार मंगलम ने यह राय जाहिर की है कि "स्वाधीनता-प्राप्ति के समय हिन्दी शायद सबसे कम विकसित भाषा थी।" (भारत का भाषा-संकट, पृ० ३१)। वाक्य में 'शायद' उन्होंने शालीनतावश लगा दिया है, वरना हिन्दी को पिछड़ी हुई भाषा कहना प्रत्येक भारतवासी का वैधानिक अधिकार है।

तमिलनाडु और बंगाल के अंग्रेजी प्रेमी बुद्धिजीवियों को विगैर एनिहामिक परिस्थिति ध्यान में रखना चाहिए। किसी समय अमम, उड़ीसा, बिहार आदि प्रदेश समुक्त बंगाल के अन्तर्गत थे। इसी प्रकार केरल और आंध्र तमिलनाडु के साथ जुड़े हुए थे। इन बड़े-बड़े प्रांतों में तमिल और बंगाली बुद्धिजीवी अंग्रेजी के कारण सरकारी नौकरियों पाने थे, अफसर बनकर दूसरों पर हुकूमत करते थे, बकील, डाक्टर, इंजीनियर आदि के पेशे थे इन्हीं का बोलबाला था। मद्रास प्रेसीडेन्सी टूट गई, रह गया तमिलनाडु। उडुपट्टी, अमम और बिहार जलग हो गए, रह गया विभाजित बंगाल। अमम में बंगालिया और असमियों के बीच दंगे हुए। फौरी कारणों के अलावा दंगा के पीछे दोनों जातियों के बीच पुराना तनाव भी काम कर रहा था। तमिलनाडु और आंध्र के गिरिजन दोनों में उम्मीद मिलना-जुलना तनाव है। तमिलनाडु में भाषावार प्रान्त बनाने का आन्दोलन नहीं चला। यह आन्दोलन चलाया उन्होंने जो तमिल पूजापनिया या तमिल बुद्धिजीवियों के संग में परेशान हो चुके थे। बंगाल जैसे ही कटा छँटा था, वहाँ भाषावार प्रान्त बनाने के आन्दोलन का मवाल नहीं था। इन दो प्रदेशों में हिन्दी विरोध सबसे ज्यादा है। तमिलनाडु में इस विरोध ने हिमात्मक रूप लिया।

यह विरोध मध्यम के कुछ लोगों और पूजापनिया तक सीमित है। ये लोग आम जनता को यह भय दिखलाकर कि उनकी भाषा खत्म कर दी जाएगी उसे भड़काने हैं। लेकिन तमिलनाडु में तमिल राजभाषा बन गई हो, विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम हो, ऐसा नहीं है। सरकारी नौकरियों पाने के लिए लोग वहाँ अपने बच्चा का अंग्रेजी के माध्यम से ही शिक्षा देना पसन्द करते हैं। श्री मोहनकुमार मंगलम के अनुसार मद्रास सरकार के अम-विभाग का कार्य भी अंग्रेजी में होता है, अधिक मध्य और कारखानों के इन्स्पेक्टरों के बीच पत्र-व्यवहार अंग्रेजी में होता है, राज्य सेक्रेटेरियट का सारा काम केवल अंग्रेजी में होता है, छोटे-मोटे व्यापार और धन्धों तक में अंग्रेजी चलती है, "इसमें अनिश्चयबोध नहीं है कि मद्रास में तमिल का एक दाद सीधे जितना भी आदमी वर्षों तक रह सकता है, नौकरों के मामले में घोड़ी परशानी उबर हागी।" (भारत का भाषा-संकट, पृ० ६६-७०)

हिन्दी-विरोध का कारण मानुभाषा प्रेम नहीं है, अंग्रेजी प्रेम है।

बंगाल की तरह तमिलनाडु में अनेक विद्वान् और वैना हिन्दी-प्रचार में योग देने रहे हैं। इनमें श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी मुख्य हैं। डॉ० सुनीतिकुमार जटर्जी की तरह वह भी अब अंग्रेजी के प्रदत्त समर्थक बन गए हैं। मरटी० विजयराघवाचारी ने सन् '२५ में हिन्दी को भारतीय शिक्षा-व्यवस्था में अनिवार्य बना देने पर जोर दिया था। श्री राजगोपालाचारी ने दस साल बाद उसी मुद्दा पर अमल किया था। दिसम्बर, १९१६ में सत्यनरु की एक सभा में गांधीजी के निर्देश से हिन्दी और देवनागरी को लेकर जो प्रस्ताव पाम हुआ, उसके समर्थकों में श्री रामस्वामी ऐयर और श्री रामस्वामी आर्यमर थे। ('मरस्वनी', फरवरी, १९१७)

भारत की राष्ट्रभाषा देवनागरी लिपि में लिखी जानेवाली हिन्दी होगी—यह प्रस्ताव संविधान सभा में श्री गोपालस्वामी आयरंगर ने पेश किया था।

तमिलनाडु के हिन्दी-प्रचारकों ने राष्ट्रीय एकता और हिन्दी-प्रचार के लिए जो काम किया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाय थोड़ी है। परिस्थितियाँ अक्सर उनके प्रतिकूल रही हैं। यह न समझना चाहिए कि आज से तीस साल पहले हिन्दी-प्रचार के लिए परिस्थितियाँ ज्यादा अनुकूल थीं।

दिसम्बर, १९१६ में कांग्रेस का इकत्तीसवाँ अधिवेशन लखनऊ में हुआ। भारतीय कुलियों का विदेश भेजना बन्द करने के विषय में गांधीजी ने एक प्रस्ताव कांग्रेस में उपस्थित किया। आपकी हार्दिक इच्छा थी कि आप हिन्दी में भाषण करें। आपने हिन्दी में भाषण आरम्भ भी कर दिया था। इतने में मद्रासी प्रतिनिधियों की ओर से आवाज आई—‘English, please’ अर्थात् अंग्रेजी में बोलिए। उत्तर में गांधीजी बोले—“आपकी आज्ञा मुझे स्वीकार है, पर एक शर्त है—अगले साल की कांग्रेस तक आपको यह Lingua Franca (अर्थात् राष्ट्रभाषा हिन्दी) अवश्य सीख लेना चाहिए। देखिए, इसमें गलती या लापरवाही न हो !” उस समय जान पड़ता था मानो कोई “देवदूत—ईश्वर का कोई प्रतिनिधि—आकर हमें ईश्वरीय आज्ञा सुना रहा है।” (‘सरस्वती’; फरवरी, १९१७)। गांधीजी ने हिन्दी और राष्ट्रीय एकता के लिए कितना भगीरथ प्रयत्न किया, उनके इस प्रयत्न का कैसा प्रभाव हिन्दी-भाषियों पर पड़ा, यह द्विवेदीजी के उपर्युक्त विवरण से मालूम हो जाता है।

गांधीजी चाहते थे, साल-भर में लोग हिन्दी सीख लें और कांग्रेस के अधिवेशनों में अंग्रेजी के बदले हिन्दी बोलें। अब भारत को स्वाधीन हुए अठारह साल हो गए; फिर भी नेता कहते हैं, हिन्दी के मामले में जल्दी न करना चाहिए। ध्यान देने की बात है कि पराधीन भारत में हिन्दी के प्रचार-कार्य से ही कुछ लोग यह शोर करने लगे थे कि उनकी भाषाओं का दमन किया जा रहा है ! उस समय गांधीजी मौजूद थे; हिन्दी-प्रचार कार्य उन्हीं की देख-रेख में चल रहा था। केन्द्र में सत्ता कांग्रेस के हाथ में न थी; मद्रास में राजाजी का मंत्रिमण्डल भी कायम न हुआ था। फिर भी आवाज यह उठी कि हिन्दी-प्रचारक दक्षिण की भाषाओं का नाश कर देना चाहते हैं !

गांधीजी ने सन् ३५ में इन्दौर साहित्य-सम्मेलन के सभापति-पद से भाषण देते हुए कहा था, “अपनी यात्रा (दक्षिण-यात्रा) के दौरान काका साहब (काका कालेलकर) ने देखा कि कुछ लोग समझते हैं कि हम उनकी प्रादेशिक भाषाओं का नाश कर देना चाहते हैं और सारे देश में एक ही भाषा चलाना चाहते हैं। कहीं-कहीं हमारा उद्देश्य न समझकर लोगों ने हमारे हिन्दी-प्रचार कार्य का विरोध किया है।” (थाट्स, पृ० ३८)

आश्चर्य की बात है कि कांग्रेसी मंत्रिमंडल बनने से पहले ही, केन्द्र में सत्ता-परिवर्तन से बहुत पहले, जो लोग हिन्दी से अहिन्दी भाषाओं के लिए खतरा पैदा होने की बात कहते थे, वे अंग्रेजी के बारे में चुप रहते थे, अंग्रेजी उन्हें लादी हुई भाषा न

मान्य होती थी उसमें उन्हें अपनी भाषाओं के लिए रास्ता न दिखाई देता था ।

सरकारी नीतिशास्त्र के उम्मीदगारों के लिए राजभाषा अंग्रेजी, आम जनता की सम्भव भाषा हिन्दी—देश की भाषा-सम्बन्धी स्थिति तब भी यह थी, आज भी है । गान्धी का मत यह था कि भारत की अपनी राष्ट्रभाषा हिन्दी है, सरकारी तौर पर उसी की राजभाषा बनाना चाहिए ।—

गान्धी जी भाषा-नीति का चौथा सूत्र है—कांग्रेस की अपनी राजनीतिक कार्यवाही की भाषा हिन्दी होनी चाहिए ।

यह बात दरल में बहुत मायारण मालूम होती है लेकिन वास्तव में है सबसे महत्वपूर्ण । भारत की राजनीतिक पार्टियाँ भाषा-समस्या पर प्रत्यक्ष बरकत डूंगों की निष्कर्षा रही है कि उन्हें क्या करना चाहिए । वे स्वयं ज़र्रे की हड्डाने के लिए क्या करन ली रही हैं इसकी सूचना व डूंगों को कम ली हैं । आप बचपना कीजिए यदि कांग्रेस का राग राजभाषा हिन्दी में हुआ करता तो क्या हुकूमत की बाइडोर गैरालने ही अंग्रेजी हड्डान में कांग्रेसी नेता-रा को माल भर म दयादा देर लगती ? य कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट नेता आ पहले कांग्रेस के ही सदस्य थे, स्वाधीनता प्राप्ति के दो साल पहले तक जो कांग्रेस में थे क्या उसमें जतन होने पर अलग नहीं भी हिन्दी का व्यवहार न करते ? यदि वे विभिन्न पार्टियाँ न बना ज़र्रे की के बिना अपना काम चलाने के आशी हों, तो क्या विविधान सभा में हिन्दी अंग्रेजी का लेकर इनकी बहस होगी ? क्या सर्वविधान सभा हिन्दी का राष्ट्रभाषा स्वीकार करने के बाद पन्द्रह साल तक अंग्रेजी को बालू रगने का नियम बनानी ? क्या पन्द्रह साल बीतने में पहले अंग्रेजी का आगे भी मह राष्ट्रभाषा—असल में एकमात्र बन्द्रीय राजभाषा—बनाए रखन का कानून पास होना ? क्या पन्द्रह साल बीतने पर अंग्रेजी की अनिवार्यता मान तक कायम रखन की नीयत आती ?

इससे आप समझ लीजिए कि कांग्रेस के अन्दर से अंग्रेजी हटाने का मध्यम दिवना महत्वपूर्ण था और यह मध्यम चलाकर गान्धीजी ने कितनी बड़ी कीरता और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया था । उन्हें अपने मर्म में सफ़लता नहीं मिली, इसमें यह भी समझ लीजिए कि अंग्रेजी के हिमायती इस देश में कितने घुसियाती हैं । गान्धीजी को हिन्दू मुस्लिम सम्प्रदायवाद छुट करने में सफ़लता नहीं मिली, उन्हें देश का विभाजन होकने में सफलता नहीं मिली, उन्हें सरकार और कांग्रेस के अन्दर में अंग्रेजी हटाने में सफ़लता नहीं मिली । इन तन्नाम असफलताओं का लिए हुए वह भारतीय प्रतिनिधिमण्डल की मोनी सावरमसार में चले गए । लेकिन रास्ता बड़ी है बिल पर बह चले थे और उध रास्ते पर घनकर भारत एक दिन अवश्य विजयी होगा ।

दिसम्बर, १९१६ । उसनक़ में कांग्रेस का इक्कीनवाँ अधिवेशन । गान्धीजी हिन्दी में बोलता शुरू करते हैं । 'इग्लिंग प्लेज' की आवाज़ें आती हैं । वह मदस्यो से कहत है—  
सात भर में हिन्दी अवश्य सीम लीजिए । अगले साल की कांग्रेस में अंग्रेजी न बननी चाहिए ।

१९१८ : वह कहते हैं, “हमारी राष्ट्रीय सस्थाओं में हिन्दी का ही व्यवहार होना चाहिए। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इस दिशा में बहुत-कुछ कर सकते हैं और उन्हें करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि यह सम्मेलन (हिन्दी साहित्य-सम्मेलन) कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के समय उसके सामने इस आग्रह का प्रस्ताव रखे।” (थाँटन, पृ० १२)

१९२१ : वह बंगाल और दक्षिण के लोगो से खास तौर से कहते हैं, “मैं आशा करता हूँ कि बंगाली और द्रविड़ लोग दूसरी कांग्रेस में (यानी कांग्रेस के अगले अधिवेशन में) काम लायक हिन्दी सीखकर आएँगे। हमारी यह महान् सभा जनता की शिक्षक तब तक नहीं बन सकती जब तक वह ऐसी भाषा में न बोले, जिसे ज्यादा-से-ज्यादा जनता समझती हो।” (उप०, पृ० १६)

१९२५ : कांग्रेस का नया विधान, धारा ३३—“जहाँ तक सम्भव होगा कांग्रेस की कार्यवाही हिन्दुस्तानी में होगी। यदि कोई हिन्दुस्तानी न बोल सके या जरूरत पड़े तो अंग्रेजी तथा प्रान्तीय भाषा का व्यवहार भी किया जा सकेगा।” इस प्रस्ताव में अंग्रेजी-प्रेमियों पर तगड़ी पाबन्दी न लगाई गई थी, फिर भी जो लोग हिन्दी-हिन्दुस्तानी का व्यवहार करना चाहे, उनके लिए छूट थी।

१९२८ : गांधीजी ने श्री विजयराघवाचारी के इस कथन का उल्लेख किया कि “हम लोग उत्सुकता से उस दिन की राह देख रहे हैं जब हम हिन्दुस्तानी पहले होंगे, मद्रासी या बंगाली बाद को। वह दिन जल्दी आएगा यदि मद्रासी, जो इस मामले में सबसे ज्यादा ग्राफिल हैं, बड़ी तादाद में हिन्दी सीखने लगें।” इसके बाद गांधीजी ने ‘यंग इंडिया’ में लिखा, “दक्षिण के लोगों को हिन्दी-प्रचार सभा के कारण हिन्दी सीखने के लिए हर तरह की सुविधा है। यदि भारत के लिए हमारे हृदय में वैसे ही सच्चा प्यार है जैसे अपने प्रान्तों के लिए है तो हम अवश्य ही जल्दी सीख लेंगे और हमें यह अपमान-जनक दृश्य न देखना पड़ेगा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यवाही—पूरी-की-पूरी नहीं तो अधिकांश—अंग्रेजी में हो रही है।” (उप०, पृ० २६)

१९३१ : “दक्षिण के लोग वायदा कर चुके हैं कि अगले साल की कांग्रेस के लिए वे ऐसे प्रतिनिधि भेजेंगे जो हिन्दी में बोलेंगे और हिन्दी समझेंगे। हम अस्वाभाविक परिस्थितियों में न रहते होते तो दक्षिण के लोगों को हिन्दी सीखना बिल्कुल न मालूम होता, व्यर्थ की बात तो और भी नहीं।” (उप०, पृ० ३०)

१९३७ : मद्रास में हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के मंच से उन्होंने यह प्रस्ताव पेश किया कि सम्मेलन कांग्रेस से हिन्दी का व्यवहार करने की प्रार्थना करता है। उन्होंने प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा, “हम राष्ट्रभाषा हिन्दी के समर्थन में प्रस्ताव पास करते रहें और कांग्रेस पुरानी लीक पर चलती रहे तो हमारे काम की रफ़्तार बहुत धीमी होगी। इस प्रस्ताव में कांग्रेस से अपील की गई है कि वह अन्तर्प्रान्तीय भाषा के रूप में अंग्रेजी का बहिष्कार करे। इसके अनुसार अंग्रेजी को न तो प्रान्तीय भाषा, न हिन्दी की जगह देनी चाहिए।” (उप०, पृ० ५२)



अन्त में अपने और अन्य सहयोगियों के मुदीर्ष प्रयत्न का विहंगावलोकन करते हुए उन्होंने अपने जीवन के अन्तिम चरण में लिखा, "१९२५ में कांग्रेस ने अपने कानपुर अधिवेशन के प्रसिद्ध प्रस्ताव में इस अखिल भारतीय भाषा की हिंदुस्तानी कहा। तब से कम-से-कम बड़त-भरको हिंदुस्तानी राष्ट्रभाषा हो गई है। कहने-भर को इसलिए कि कांग्रेस ने भी उस प्रस्ताव पर उस तरह जमन नहीं किया जैसे उन्हें करना चाहिए था, १९२० में जबकि यह कोशिश शुरू हुई कि आम जनता की राजनीतिक शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं का महत्त्व पहचाना जाय, साथ ही एक अखिल भारतीय सामान्य भाषा का महत्त्व पहचाना जाय, जिसे राजनीति में प्रबुद्ध भाग आसानी में चोल सके और विभिन्न प्रांतों के मध्य कांग्रेस के अखिल भारतीय अधिवेशन में सम्मिलित सके। मुझे यह कहने का दुःख होना है कि बहुत से कांग्रेसी जनता उस प्रस्ताव पर जमन नहीं किया। और इसलिए यह दुःख उपस्थित होना है जो मेरी समझ में सामना है कि कांग्रेसमें अंग्रेजी बोलने की छिड़ करते हैं और दूसरों को भी अपनी छानिद अंग्रेजी बोलने पर मजबूर करने हैं। अंग्रेजी का जादू अभी खत्म नहीं हुआ। उस जादू के अमर में हम देश का अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में रोकने हैं। जनता के लिए हमारा प्रेम एकदम सचही है यदि हम हिंदुस्तानी सीखने के लिए उतने महीने भी नहीं देना चाहते जितने सात हम अंग्रेजी सीखने में लगाने हैं।" (उप०, पृ० ६०)

भारत स्वतंत्र हुआ। गांधीजी ने चेतावनी दी कि "सरकार और मेकेंटेरियट सावधान रहें ता सम्भव है कि अंग्रेजी हिंदुस्तानी की जगह ले ले। इससे भारत की करोड़ जनता का बेहद नुकसान होगा जो अंग्रेजी समझ न पाएंगी।" (उप०, पृ० १६८)। उन्होंने प्रांतीय भाषाओं की पुनर्जीवन करने की सलाह दी, साथ ही यह सुझाव रखा कि प्रांतीय सरकारें ऐम बर्गचारी रखें जो प्रांतीय भाषा के साथ अन्तर्प्रांतीय भाषा हिंदुस्तानी भी जानने हों।

यह सब न हुआ क्योंकि जिन लोगों के हाथ में शासन की बागडोर थी, वे अपने राजनीतिक संगठन में अंग्रेजी का व्यवहार करते थे। जो विरोधी दल समझ में भारतीय लोकतंत्र के संचालन में शामिल हुए, वे भी अखिल भारतीय सम्पर्क के लिए अंग्रेजी का ही व्यवहार करने लगे।

इसलिए वे तब चाहते हैं कि स्वाधीन भारत में अंग्रेजी का प्रभुत्व खत्म हो, उन्हें पहला कदम यह उठाना चाहिए कि भारत के राजनीतिक दलों के केन्द्रीय दलों से अंग्रेजी निकालें, एक अखिल भारतीय अधिवेशन में अंग्रेजी का व्यवहार बन्द कराएँ, उनका अखिल भारतीय प्रचार-वाद्य अंग्रेजी के माध्यम से बन्द कराएँ। सबसे मुश्किल यह पहला कदम ही है। यदि एक बार भारतीय जनता यह कदम उठाने के लिए पाठियों के नेताओं को बाध्य करे तो दूसरे कदम उठाना बहुत आसान हो जाएगा।

पूरा परिणाम के अन्दर में अंग्रेजी की जड़ काटिए।

फिर लोकतन्त्र में अपने प्रतिनिधियों का भारतीय भाषाओं में बोलने—और

अंग्रेजी छोड़ने—पर मजबूर कीजिए।

इसके बाद नौकरशाहों पर दवाव डालिए कि वे दफ्तरों से अंग्रेजी निकालें। जब नेता लोग अंग्रेजी का बहिष्कार कर देंगे तब मन्त्रीजी के सामने कोई फ़ाइल अंग्रेजी में न आएगी। अफसर लोग लोकतन्त्र का अनुसरण करेंगे। इस समय विश्वविद्यालय अखिल भारतीय सेवाओं से नतीही है। शिक्षा का एक उद्देश्य और मुख्य उद्देश्य अफसर तैयार करना है। जब आइ० ए० एस० में अंग्रेजी का चलन न होगा, तब विश्वविद्यालयों में भी अंग्रेजी का प्रभुत्व न रहेगा।

पार्टी—लोकतन्त्र—नौकरशाही—युनिवर्सिटियाँ, इस क्रम से अंग्रेजी के किलों पर हमला करना चाहिए।

गांधीजी की भाषा-नीति का पाँचवाँ सूत्र है—भारत का विकास और राष्ट्रीय एकता की रक्षा प्रादेशिक भाषाओं को दबाकर नहीं, उनके पूर्ण विकास से ही सम्भव है।

गांधीजी ने अपने राजनीतिक जीवन के आरम्भ से ही अंग्रेजी का विरोध किया और प्रान्तीय भाषाओं की हिमायत की। १९०६ में ही उन्होंने प्रान्तीय भाषाओं और राष्ट्र-भाषा का सम्बन्ध अच्छी तरह समझ लिया था। उन्होंने लिखा था, “हिन्दुस्तान में आज-कल हिन्दू, मुसलमान, पारसी वगैरह ‘अपने देश’ की बात करने लगे हैं। इस समय मैं इस बात पर राजनीतिक दृष्टि से विचार नहीं कर रहा हूँ। भाषा की दृष्टि से यह जरूरी है कि इसके पहले कि हम अपने देश को अपना कहें, हमारे दिलों में अपनी भाषाओं के लिए प्रेम और आदर पैदा होना चाहिए। ऐसा मालूम होता है कि सारे भारत में लोग अपनी भाषाओं की ओर ध्यान देने लगे हैं। यह प्रसन्नता की बात है।” (उप०, पृ० १८८)

इस लेख में गुजरातियों को अंग्रेजी बोलने पर उन्होंने फटकारा। उन्होंने इस बात पर हर्ष प्रकट किया कि लोग गुजराती, मराठी, बँगला, उर्दू आदि की प्रगति के लिए संस्थाएँ बना रहे हैं।

सन् '१५ में संग्रामपुर के विद्यार्थियों के सामने भाषण (जिसका उल्लेख पहले हो चुका है) करते हुए उन्होंने मातृभाषा की अवज्ञा करनेवालों की निन्दा की।

सन् '२७ में जब हिन्दी-प्रचार आन्दोलन शक्तिशाली होने लगा था, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि “हिन्दी या हिन्दुस्तानी का उद्देश्य यह नहीं है कि वह प्रान्तीय भाषाओं की जगह ले ले। वह अतिरिक्त भाषा होगी और अन्तर्प्रान्तीय सम्पर्क के काम आएगी।” (उप०, पृ० २६)

१९३५ में जब काका कालेलकर ने गांधीजी को बताया कि लोग यह कहते हैं कि हिन्दी-प्रचार का उद्देश्य प्रान्तीय भाषाओं का दमन है, तब गांधीजी ने साहित्य-सम्मेलन के मंच से घोषित किया, “मेरा कहना बराबर यही रहा है कि प्रान्तीय भाषाओं का जरा भी अहित हम नहीं करना चाहते, उनका दमन या नाश करना तो दूर की बात है।” (उप०, पृ० ३८)

गांधीजी स्वयं गुजराती के श्रेष्ठ लेखक थे। उनकी प्रेरणा से गुजराती बुद्धि-

जीविया ने अंग्रेजी का मोह छोड़ा और मानुभाषा की सेवा की। गुजराती भाषा के मेजर अंग्रेजी की गुलामी से मुक्त होने के कारण हिन्दी के समर्थक हुए। हिन्दी-भाषी प्रदेशों के नेता, विशेषकर उत्तर प्रदेश (भूतपूर्व संयुक्त प्रान्त) के अधिकांश कांग्रेसी और कम्युनिस्ट नेता गांधीजी की तरह मानुभाषा के मेवक नहीं थे। अंग्रेजी का प्रभुत्व कायम रखने में उनका बहुत हाथ रहा है। गांधीजी स्वयं गुजराती के भक्त थे, इसलिए वह प्रान्तीय भाषाओं और हिन्दी का सम्बन्ध अच्छी तरह समझते थे।

सन् ३६ में उन्होंने बंगलौर में कहा था, “लोगों ने एक हीवा खड़ा कर रखा है जिसे मैं आप लोग के दिमाग में निकाल देना चाहता हूँ। क्या हिन्दी की शिक्षा बमरु को हटाकर दी जाएगी? क्या यह सम्भावना है कि वह बमरु की जगह दे दे? इसके विपरीत मरा कहना है कि हम जितना ही हिन्दी प्रचार करेंगे, उतना ही अपनी मानुभाषाओं के अध्ययन का जोर मशक बनाना, इन भाषाओं की शक्ति और सामर्थ्य को भी नीचा कर देंगे। मैं विभिन्न प्रान्तों में अपने अनुभव के आधार पर यह कहना हूँ।” (उप०, पृ० ५०)

गांधीजी खूब जानते थे कि प्रादेशिक भाषाओं का मुख्य अन्तर्विरोध अंग्रेजी से है, न कि हिन्दी से। उन्होंने मद्रास में कहा था, “अगर अंग्रेजी ने जनता की भाषाओं की जगह न ले ली होती तो आज वे अत्यन्त समृद्ध अवस्था में होती।” (१९३७, पृ० ५०)

गांधीजी की नानि स्पष्ट थी किन्तु कांग्रेस के कुछ नेता, विशेषकर उत्तर प्रान्त के नेता, यह कहते थे कि उच्च शिक्षा और शासन-व्यवस्था में अंग्रेजी की तरह हिन्दी भी प्रादेशिक भाषाओं की जगह लेगी। इससे अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं का मुख्य अन्तर्विरोध गौण हो जाता था, और हिन्दी-अहिन्दी भाषाओं का नया अन्तर्विरोध सामने आ जाता था। हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के जो हिमायती प्रादेशिक भाषाओं के हक मारकर उसे अंग्रेजी की जगह देने की बात कह रहे हैं, वे हिन्दी के माग में कानि विचार नहीं हैं और इसमें लाभ हुआ है अंग्रेजी को।

गांधीजी जानते थे कि भारत ऐसा राष्ट्र है जिसमें अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं। वह ब्रिटिश या फ्रांस की तरह एक भाषावाला राष्ट्र नहीं है। इसलिए वह इस पक्ष में थे कि भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो जिससे प्रदेशों का राजधानी वहाँ की भाषाओं में हो सके। गांधीजी के बहने में जातीय दत्तकों के आधार पर कांग्रेस कमेटीयों का माटन किया गया था। स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद गांधीजी ने लिखा, “प्रान्तीय भाषाओं को अपना पूर्ण विकास करना है तो भाषा के आधार पर प्रान्तों का पुनर्गठन आवश्यक है। हिन्दुस्तानी राष्ट्रभाषा होगी लेकिन वह प्रान्तीय भाषाओं की जगह न लेगी। वह प्रान्तों में शिक्षा का माध्यम न होगी—अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम ही, इसका मान नहीं है। हिन्दुस्तानी का उद्देश्य यह होना कि वह लोगों को महसूस कराए कि वे भारत के अन्तिम अंग हैं। बाहर के लोग हमें गुजराती, महाराष्ट्री, तमिल आदि कहकर नहीं जानते हैं। उनके लिए हम सब हिन्दुस्तानी हैं। इसलिए हमें सभी विघटनकारी प्रवृत्तियों को

दृढ़ता से रोकना चाहिए। इस मुख्य बात को ध्यान में रखते हुए हम मानेंगे कि भापावार प्रान्त बनाने से शिक्षा और व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा। (१९४८; उप०, पृ० २०२)

केन्द्रीय सरकार ने भापावार प्रान्त बनाने का प्रबल विरोध किया। तमिलनाडु और गुजरात के बड़े पूंजीपति यह नहीं चाहते थे कि उनके विशाल प्रान्त खण्डित हों। इनके अंग्रेजी अव्वारों ने भापावार प्रान्त-निर्माण का जोरों से विरोध किया। गांधीजी ने कहा था कि भापावार प्रान्त बनाने से शिक्षा और व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा। गांधीजी की निगाह छोटे व्यापारियों और पूंजीपतियों पर थी जो बड़े प्रान्तों में उदीयमान इजारेदारों से पीड़ित थे। लेकिन दिल्ली की सरकार इन इजारेदारों की बात ज्यादा नुनती थी, गांधीजी और मध्यम पूंजीपतियों की कम। यही कारण है कि उसने प्राणपण से महाराष्ट्र और आंध्र के नये प्रान्त बनाने के आन्दोलन का विरोध किया।

गांधीजी के नाम पर जनता से वोट लेनेवाला, गांधीवाद-विरोधी दिल्ली का सरकारी कांग्रेस-नेतृत्व भापावार प्रान्त-निर्माण का विरोध करके हिन्दी का अहित और अंग्रेजी का हित कर रहा था। कुछ अहिन्दी-भाषियों में यह भय उत्पन्न हुआ कि उनकी भाषाओं का दमन किया जाएगा और उन पर हिन्दी लादी जाएगी। इधर दिल्ली सरकार के नेता जानते थे कि अंग्रेजी न आज जानेवाली है, न कल। फिर भी वे बराबर हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का दावा करते जाते थे क्योंकि इसके बिना विशाल हिन्दी-भाषी क्षेत्र से उन्हें वोट न मिल सकते थे।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि भापावार प्रान्त-निर्माण का विरोध करने में दिल्ली सरकार ने बड़े पूंजीपतियों के दबाव में आकर अपनी नीति निर्धारित की। इन बड़े पूंजीपतियों की साँठ-गाँठ ब्रिटेन के इजारेदारों से भी थी। दिल्ली सरकार भारत के बड़े पूंजीपतियों के अलावा जब-तब ब्रिटेन के इजारेदारों का रुख देखकर भी काम करती थी। ब्रिटिश पूंजीपति चाहते थे कि भारत में अंग्रेजी रहे। इससे एक तो भारत सांस्कृतिक रूप से ब्रिटेन के साथ नट्थी रहता है, दूसरे अंग्रेजी किताबों की बिक्री के लिए इतना बड़ा बाजार ब्रिटिश प्रकाशकों के हाथ में बना रहता है! इसीलिए जो लोग भापावार प्रान्त बनाने के विरोधी थे, वे अंग्रेजी के बहुत बड़े समर्थक थे। दिल्ली सरकार तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की दलाल थी, न वह केवल भारत के बड़े पूंजीपतियों की प्रतिनिधि थी। उसने भारत के औद्योगीकरण में, विशेषकर सरकारी उद्योग-धन्धों के निर्माण में, भारत की स्वतन्त्र विदेश-नीति निर्धारित करने में और समाजवादी देशों से मैत्री-सम्बन्ध कायम करने में बहुत बड़ा योग दिया। फिर भी उसने भारत और ब्रिटेन के बड़े पूंजीपतियों के हित में कुछ गलत कदम उठाए।

कुछ प्रगतिशील विचारक भापावार प्रान्त-निर्माण के पक्ष में गांधीजी के विचार बड़े गर्व से उद्धृत करते हैं किन्तु गांधीजी ने अंग्रेजी हटाने के बारे में जो कुछ कहा था, उसे वे बड़े प्रेम से नजरन्दाज कर देते हैं। ये विचारक उन मध्यमवर्गी बुद्धिजीवियों के प्रतिनिधि हैं जो केन्द्र में अंग्रेजी चालू रखकर अखिल भारतीय नौकरियों के उम्मीदवार हैं।

गांधीजी के नाम की दुहाई देकर केन्द्र में 'विप्लव' अंग्रेजी चलाते रहते की बात करना ह्याम्यारपद है।

प्रांतीय भाषाओं के सम्बन्ध में गांधीजी का यह उदार दृष्टिकोण ध्यान देने योग्य है कि अंग्रेजी की जगह जहाँ अन्तर्प्रान्तीय सम्पर्क के लिए सोम हिन्दी न बोल सकें, वहाँ वे प्रांतीय भाषा का ही व्यवहार करें।

१९४४ में बनारस विश्वविद्यालय में गांधीजी ने हिन्दी में भाषण करते हुए कहा था, 'यही मंत्र पर एक के बाद दूसरा सत्ता भाषा और मैं अधीनता से राह दसता रहा कि कोई हिन्दी या उर्दू या हिन्दुस्तानी में, या संस्कृत में ही भाषण करे, यह न सही तो पराधीन मया और किसी भारतीय भाषा में बोले। लेकिन मुझे यह भीमाग्न प्राप्त न हुआ। क्या? इसलिए कि हम गुलाम हैं और उन्हीं की भाषा को छानी में बिपनाये हुए हैं जिन्होंने हमें गुलाम बना रखा है।'

विद्यार्थियों का नड्ड करके उन्होंने कहा, 'ये उरा-उरा-सी बात पर हड़ताल कर देने हैं, भूत-हड़ताल कर देन हैं। ये राष्ट्रभाषा में शिक्षा पाने के लिए क्यों नहीं लड़ते?' मुझे बताया गया है कि आंध्र प्रदेश के दाईं भी विद्यार्थी हैं। उन्हें सर राधाकृष्णन् के पास जाना चाहिए और कहना चाहिए कि विश्वविद्यालय में एक आंध्र विभाग खोना जाम। वे राष्ट्रभाषा नहीं सीखना चाहते तो तेलुगु के माध्यम से शिक्षा पान की मांग करें।'

(उप०, पृ० ६२-६३)

'राष्ट्रभाषा नहीं सीखना चाहते तो तेलुगु के माध्यम में शिक्षा पाने की मांग करें', इस मंत्र को आज की परिस्थिति में लागू करें तो हम नेताओं से कहेंगे कि आप हिन्दी नहीं बोल सकते तो अपनी मातृभाषा में भाषण कीजिए। श्री कामराज नाडार इसी नीति का पालन करते हैं और तमिल में बोलते हैं। अनुवाद की व्यवस्था करके उन लोगों की कठिनाई दूर की जा सकती है जो हिन्दी का व्यवहार नहीं कर सकते या जान-बूझकर नहीं करना चाहते।

गांधीजी भरिया गए। सभा में हड़ारो मउदूर थे। गांधीजी का अभिनन्दन अंग्रेजी में किया गया। इस पर उन्होंने 'यंग इंडिया' में लिखा, "अधिकार छोटा आसानी में हिन्दा समझ लेते और बाकी लोग बंगला समझ लेते। उस सभ के पदाधिकारी बंगाली थे। अगर उन्होंने अंग्रेजी का व्यवहार मेरे लिए किया तो बिलकुल अनावश्यक था। वे अभिनन्दन (या भाषण) बंगला में लिख सकते थे और मुझे उसका हिन्दी-अनुवाद दे देन। अंग्रेजी में भी अनुवाद करके दे सकते थे। लेकिन उनकी बड़ी सभा पर अंग्रेजी घोषणा उसका अपमान करना था।"

इसके आगे दक्षिण भारत को लक्ष्य करके उन्होंने लिखा, "यह घटना समाप्त कर देनेवालों के लिए हर जगह चेतावनी का काम करे, खास तौर से आंध्र, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के सभा-संयोजकों को भावधान कर दे, यह मैं चाहता हूँ। मैं उनकी कठिनाई समझता हूँ। लेकिन छह साल से उनके बीच हिन्दी-प्रचार सभा

जोरों से काम कर रही हैं। उनके भाषण प्रान्तीय भाषाओं में होने चाहिए और मेरी सुविधा के लिए उनके हिन्दी-अनुवाद दे देने चाहिए।” (उप०, पृ० २२-२३)

गांधीजी ने यह सब सन् '२७ में लिखा। तब से अब तक हिन्दी-प्रचार सभा लाखों आदमियों को हिन्दी सिखा चुकी है। फिर भी वे या अन्य अहिन्दी-भाषी राष्ट्रभाषा का व्यवहार न कर सकें या न करना चाहे तो उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलना चाहिए और उनके भाषण के अनुवाद की व्यवस्था होनी चाहिए।

२७-२८ जून को इस साल वरेली में साहित्य-सम्मेलन का जो अधिवेशन हुआ, उसके प्रस्ताव में कहा गया है, “केन्द्रीय सरकार और हिन्दी-भाषी राज्य-सरकारों से उत्तर प्रदेश सरकार केवल हिन्दी में सम्पूर्ण पत्र-व्यवहार करे तथा इतर भाषी राज्य-सरकारों से पत्र-व्यवहार मूल रूप से हिन्दी में करे और साथ में तत्क्षेत्रीय भाषा में रूपान्तर संलग्न कर दिया करे।” (राष्ट्रभाषा सन्देश, इलाहाबाद; ८ जुलाई, १९६५)

गांधीजी की नीति को वर्तमान परिस्थिति में कैसे अमली रूप दिया जाय, सम्मेलन का सुझाव इसकी बहुत अच्छी मिसाल है। प्रस्ताव में यह नहीं कहा गया कि उत्तर प्रदेश की सरकार अन्य प्रदेशों की सरकार से केवल हिन्दी में पत्र-व्यवहार करे, या हिन्दी के साथ अंग्रेजी में अनुवाद भेजे, प्रस्ताव में अंग्रेजी के मुकाबले प्रान्तीय भाषाओं को ऊंचा आसन दिया गया है। इस प्रकार अनुवाद की व्यवस्था करके अन्य प्रदेशों की सुविधा का ध्यान रखते हुए अंग्रेजी को हटाया जा सकता है।

गांधीजी ने कहा था कि आंध्र के विद्यार्थी राष्ट्रभाषा के माध्यम से शिक्षा पाना नहीं चाहते तो वे तेलुगु में शिक्षा पाने की मांग करें। वे उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक केन्द्र काशी में प्रादेशिक भाषा तेलुगु और हिन्दी को समान अधिकार देने के लिए तैयार थे। पाठक विचार करें, संयुक्त राष्ट्र संघ का काम कैसे चलता है। वह विश्व-संस्था है। उसके सेक्रेटेरियट में न जाने कितनी भाषाओं में बोलनेवालों की बातों का हिसाब-किताब रखना पड़ता है। सेक्रेटेरियट में दुनिया की सभी भाषाओं में कार्रवाई नहीं दर्ज की जाती; न संयुक्त राष्ट्रसंघ ने अंग्रेजी को विश्व-भाषा मानकर केवल उसी में दफ्तर चलाने का नियम बनाया है। उसने अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, चीनी और स्पेनी को बराबर अधिकार देकर उन्हें अपने काम-काज की भाषा बनाया है। हर भाषण का अनुवाद इन भाषाओं में एक साथ किया जाता है।

भारत में जब तक अहिन्दी प्रदेशों के नेता स्वेच्छा से हिन्दी स्वीकार नहीं करते, तब तक यदि हिन्दी, बंगला, तमिल, तेलुगु और मराठी को समान रूप से केन्द्रीय भाषा मान लिया जाय, तो क्या यह समाधान हिन्दी-अहिन्दी नेताओं को मान्य न होना चाहिए?

यदि विश्व-संस्था का दफ्तर एक से अधिक भाषाओं में चल सकता है तो क्या हम लोकसभा में एक से अधिक भाषाओं में बोलने और पाँच स्वीकृत भाषाओं में भाषण के अनुवाद की व्यवस्था नहीं कर सकते? इसी तरह केन्द्रीय सरकारी दफ्तरों का काम एक से अधिक भाषाओं में हो सकता है।

गांधीजी ने लिखा था, “दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में अंग्रेजी और उर्दू भाषाओं की टक्कर थी। अन्त में फैमला यट हुआ कि दोनों भाषाओं को बराबरी का दर्जा देना चाहिए।” (गॉटन, पृ० ७४)

दूसी तरह कनाडा में अंग्रेजी, फ्रांसीसी, बेल्जियम में फ्रांसीसी पेरुगिया, पाकिस्तान में उर्दू-बंगला, लका में मिहली-नामिल भाषाओं की टक्कर है। इन देशों में भाषा-समस्या का एक ही समाधान है कि दा भाषाओं को बराबर अधिकार देकर उन्हें केन्द्रीय भाषण माना जाय।

जो लोग यह समझते हैं कि अंग्रेजी हटाने की माँग दूसरी भाषाओं पर उर्दू की हिन्दी लादने की माँग है, उनके विचार और चिन्तन के लिए भरा उर्दू का प्रभाव है। हममें न तो केन्द्रीय सेवाओं के लिए सभी ने एक भाषा सीखन का आग्रह है, न भारत की सभी भाषाओं को केन्द्रीय भाषा देना देने की माँग है। यह मध्यमार्गी प्रभाव है और अमल में लाया जा सकता है बगैरे कि पढ़ने कायम, कम्युनिस्ट पार्टी तथा अन्य दल अपने केन्द्रीय दफ्तरों से अंग्रेजी निकाल दें।

गांधीजी की भाषा-नीति का अन्तिम सूत्र है—हिन्दी-उर्दू बुनियादी तौर पर एक ही भाषा है और आगे चलकर उनका एक ही सम्मिलित साहित्यिक रूप होगा।

हिन्दी-उर्दू की बुनियादी एकता के बारे में उन्होंने लिखा था, “हिन्दी और उर्दू या हिन्दुस्तानी में कोई भी फर्क नहीं है। दोनों का व्याकरण एक है। फर्क केवल लिपि का है। विचार कोजिएना मालूम होगा कि हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी—इन तीनों शब्दों में एक ही भाषा का बोध होता है। इनके सम्बन्धों देखें तो पता चलेगा कि अधिकांश शब्द एक-से हैं।” (उप० पृ० १०)

गांधीजी ने जो कुछ लिखा था, वह बोलचाल की भाषा की दृष्टि से सही था। हिन्दी-उर्दू मूलतः एक ही भाषा हैं और आम जनता उनके व्यवहार में कोई भेद नहीं करती।

गांधीजी ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि उर्दू भाषा और लिपि केवल मुसलमानों की सम्पत्ति नहीं है। “ऐसे काफी हिन्दू और अन्य धर्मों के लोग भी हैं जिनकी मातृभाषा उर्दू है और जो केवल उर्दू लिपि जानते हैं।” (उप०, पृ० १७१)

इसमें भी गंभीरता निकलती है, वह यह कि उर्दू धार्मिक अल्पसंख्यकों की भाषा न होकर सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की भाषा है। वह स्वतन्त्र भाषा नहीं, इसलिए उसकी रक्षा रक्षा करनी चाहिए जब तक एक ही बोलचाल की भाषा के दोनों गिष्ठ रूप धुन-मिलकर एक न हो जाएं।

देश में हिन्दू मुस्लिम समस्या अंग्रेजों के हाथ में बहुत बड़ा हथियार थी जिसे वे राष्ट्रीय आंदोलन को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे। उर्दू का सम्बन्ध मुसलमानों के विशेषाधिकारों से जुड़ा गया। उर्दू की रक्षा का प्रश्न—विशेष रूप से उनकी लिपि की रक्षा का प्रश्न—धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा का प्रश्न बन गया। गांधीजी ने हिन्दी-

हिन्दुस्तानी का नारा देकर हिन्दुओं और मुसलमानों को मिलाने का भगीरथ प्रयत्न किया। किन्तु भाषा केवल बहाना थी; अलगव के कारण दूसरे थे। बंगाल में उर्दू लिपि की रक्षा का प्रश्न न था; फिर भी उसका विभाजन हुआ। सिन्धी भाषा के लिए फारसी लिपि का ही संशोधित रूप काम में आता था। फिर भी सिन्ध पाकिस्तान में गया। जिनकी भाषा उर्दू थी, वे यही रहे। उर्दू के दमन का नारा लगाकर मुस्लिम जनता को भड़काया गया; साम्राज्यवादियों और उनके साम्प्रदायिक सहायकों ने भाषा-समस्या से लाभ उठाकर राष्ट्रीय आन्दोलन को कमजोर किया।

इस परिस्थिति को बदलने का एक ही तरीका था, साम्राज्यवाद के खिलाफ आम जनता का संगठन किया जाय। उत्तर भारत में किसान-सभाओं और मजदूर-संघों में एक ही भाषा का व्यवहार किया जाय, इन जन-संगठनों में फारसी, संस्कृत शब्दों के व्यवहार पर रोक न लगाकर एक ही लिपि देवनागरी के व्यवहार पर जोर दिया जाय। एक लिपि के माध्यम से जो किसान-मजदूर अपना राजनीतिक-सांस्कृतिक काम करते, वे अरबी-संस्कृत के शब्दों की छँटाई खुद कर लेते। वे लेखक जो मार्क्सवाद से प्रभावित थे, हिन्दी-उर्दू साहित्य का प्रकाशन एक ही लिपि देवनागरी में करके दोनों के बीच का फासला काम करने में मदद दे सकते थे। गांधीजी गुजराती थे। वह आधुनिक हिन्दी साहित्य से बहुत कम परिचित थे, उर्दू-साहित्य के विकास से और भी कम परिचित थे। उत्तर प्रदेश के प्रगतिशील लेखक गांधीजी की बहुत बड़ी मदद कर सकते थे। लेकिन इन लेखकों की भाषा-नीति में स्वामियाँ थी जिनकी चर्चा अगले निबन्ध में होगी।

हिन्दी-उर्दू का भेद नगण्य नहीं था। पंडिताऊ हिन्दी और मौलवियाना उर्दू की निन्दा करके यह भेद समाप्त न किया जा सकता था। कोशों से शब्द चुनकर साल-दो साल में एक सामान्य शिष्ट भाषा गढ़ी न जा सकती थी। गांधीजी भारत की तमाम भाषाओं के लिए एक लिपि के व्यवहार पर जोर देते थे। किन्तु राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी के लिए वह दोनों लिपियों का व्यवहार आवश्यक बतलाते थे। वह जानते थे और कहते थे कि देवनागरी लिपि अधिक वैज्ञानिक है और आगे चलकर वही रहेगी। उर्दू लिपि और उर्दू-साहित्य को सुरक्षित रखने की बात सही थी। किन्तु यदि एक ही किसान-सभा में पचास आदमी हिन्दी में अपना काम करते हैं और दस आदमी उर्दू में, तो इससे किसानों का वर्ग-संगठन कमजोर होता है। सारे देश में राष्ट्रभाषा की दो लिपियाँ हों, तो इससे सारे देश का काम कठिन हो जाता है। सारे देश के शिक्षित लोग दोनों लिपियाँ सीखें, राष्ट्रभाषा दोनों ही लिपियों में लिखी जाय, यह बात अव्यावहारिक थी।

व्यावहारिक बात यह थी कि हिन्दी-उर्दू की लिपियों को बराबरी का दर्जा न देकर एक को प्रधान और अन्य प्रादेशिक व्यवहार के लिए स्वीकार किया जाय और दूसरी को अल्पसंख्यकों के लिए आवश्यक मानकर संरक्षण प्रदान किया जाय। यदि उर्दू को मुसलमानों की लिपि मान ही लिया जाय तो भी वह अल्पसंख्यकों की लिपि होगी; उसे देवनागरी का दर्जा देना गलत था।



हिन्दू और मुस्लिम सम्प्रदायवादियों ने भिन्न भाषीजों हिन्दी-उर्दू की युनियादी एकाता में विश्वास करते थे और समझते थे कि जयसाम्प्रदायिक तनाव कम हो जाएगा, तब दोनों सैलियाँ घुल मिलकर एक हो जाएँगी। उन्होंने मनु' २७ में लिखा था, 'जब तब हिन्दू मुस्लिम तनाव समाप्त हुआ है, तब तब वह कभी फारसी-अरबी शब्दों से नहीं हुई फारसी लिपि में लिखी जानेवाली उर्दू का रूप लेता है, कभी समूह शब्दों से नहीं हुई देवनागरी लिपि में लिखी जानेवाली हिन्दी का रूप लेता है। जब दोनों के दिल मिलेंगे तब एक ही भाषा व यदा रूप घुल मिलकर एक हो जाएँगे और इस भाषा में समूह, फारसी, अरबी या अन्य भाषाओं के उनसे ही शब्द होंगे जितने उसके पूर्ण विकास और पूर्ण व्यक्तता शक्ति व लक्षण दर्शाते होंगे।" (उप, पृ० २६-२७)

इन वाक्यांशों में जो भाषा की मूल प्रवृत्ति पर है। किन्तु शब्द कि भाषा से मिले जायेंगे यह भाषा के अपने विकास पर, उसके बोलनेवालों के विकास पर निर्भर है, इसका फैसला कोणका नहीं कर सकते। लेकिन दोनों मिलेंगी जरूर, गांधीजी का यह दृढ़ विश्वास था। उनका यह विश्वास बिल्कुल सही था। बंगाल के विभाजन से बंगला के दो रूप नहीं हो गए, पंजाब के बँटवारे से दो पंजाबी भाषाएँ नहीं बन गई। भाषाओं के विकास के नियम साम्राज्यवादी योजनाओं से ज्यादा शक्तिशाली हैं। उर्दू पाकिस्तान की नहीं हिन्दुस्तान की भाषा है। हम उसका संरक्षण करेंगे, साथ ही हिन्दी-उर्दू का भेद मिटान का प्रयत्न भी करेंगे। हिन्दी-उर्दू लिखने-बोलनेवालों का प्रदेश एक, जाति एक आर्थिक सम्बन्ध एक। बोलचाल की भाषा के दोनो साहित्यिक रूपों को एक दिन मिलना ही होगा।

गांधीजी की भाषा नीति के ये छह महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिन्हें आज की परिस्थितियों में विवेक से लागू करके हम भाषा-समस्या के सही समाधान की ओर बढ़ सकते हैं।

(१९६५)

परिशिष्ट—२

## प्रेमचन्द और भाषा-समस्या

प्रेमचन्द ने भाषा के सम्बन्ध में काफ़ी विचार किया था और उसके सम्बन्ध में लिखा भी काफ़ी है। जब उन्होंने उन्होंने उर्दू छोड़कर हिन्दी में लिखना शुरू किया था तब भी उनके सामने भाषा का प्रश्न महत्त्वपूर्ण होकर आता था। इसीलिए 'सेवासदन' में भी हम उन्हें इस विषय पर सोचते-विचारते देखते हैं। डॉ० श्यामाचरण मोटर से उतरकर अंग्रेजी में अपने देर होने की क्षमा चाहते हैं, तब कुंवर साहब उन्हें याद दिलाते हैं, "डॉक्टर साहब, आप भूलते हैं, यह काले आदमियों का समाज है।" डॉक्टर साहब अंग्रेजी को देश की लिंगुआ फ्रांका मानते हैं, परन्तु कुंवर साहब इसका कारण देश के कुछ अंग्रेजी-भक्तों को बताते हैं। अंग्रेजी से कुंवर साहब को 'ऐसी ही घृणा होती है जैसी किसी अंग्रेज के उतारे कपड़े पहनने से।"

उर्दू और हिन्दी का प्रश्न प्रेमचन्द के सामने ताज़ा था। उसके बारे में कुंवर साहब कहते हैं—“फारस और काबुल के सूखे सिपाहियों और हिन्दू व्यापारियों के समागम से उर्दू जैसी भाषा का प्रादुर्भाव हो गया। अगर हमारे देश के भिन्न-भिन्न प्रान्तों के विद्वज्जन अपनी ही भाषा में सम्भाषण करते तो अब तक कभी एक सार्वदेशिक भाषा बन गई होती।” दिसम्बर, १९३१ के 'हंस' में एक पुस्तक की आलोचना करते हुए प्रेमचन्द ने लिखा था, “साहित्य-मंडल ने उर्दू के केन्द्र दिल्ली में हिन्दी-प्रकाशन का भार उठाया है, यह उद्योग प्रशंसनीय है।” प्रेमचन्द हिन्दी-उर्दू का भेद मिटाने के पक्ष में थे क्योंकि वास्तव में भाषाएँ दोनों एक हैं। इसके लिए वह काफ़ी उदारता से काम लेना चाहते थे, भाषा शुद्ध ही हो, इसके वह कायल न थे। परन्तु राष्ट्रभाषा को कुछ गिने-चुने आदमियों की न होकर देश के समूह की समझ में आनीवाली होना चाहिए। जैसा उन्होंने 'हंस' में लिखा था, “राष्ट्रभाषा केवल रईसों और अमीरों की भाषा नहीं हो सकती। उसे किसानों और मजदूरों की भाषा बनना पड़ेगा।” कौन-सी भाषा किसानों और मजदूरों की भाषा बन सकती है, यह उनकी कहानियों और उपन्यासों के ही किसान-मजदूरों की भाषा देखकर बताया जा सकता है।

अन्य भाषा-भाषियों की मुगमता के लिए वह हिन्दी का शब्दकोश बढ़ाना चाहते थे परन्तु वह ऐसे शब्द लेने के पक्ष में न थे जिनसे हिन्दी हिन्दी न रहे। नवम्बर,

'३५' के 'हम' में उन्होंने लिखा था, "इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि अपना कोप बढ़ाने की धुन में वह अपना रूप ही न खो बैठे हिन्दी की एक मर्यादा है, और उसका चाहे जितना भी विस्तार हो, उसकी इस मर्यादा की रखा होनी आवश्यक है।" इन शब्दों में उन्होंने अपने जीवन-पर्यन्त के अनुभव और चिन्तन का सार रख दिया है।

मरल भाषा निखन के पक्षपाती होने हुए भी प्रेमचन्द साहित्यिक की कठिनाइयाँ को जानते थे। उन्होंने स्वीकार किया है, दर्शन, विज्ञान आदि में और कथा-साहित्य में भी जहाँ वह विवेचनात्मक हो जाता है, जन-साधारण की भाषा में जहाँ कठिन शब्द अपनाने पड़ते हैं। भाषा-काठिन्य के विरुद्ध कुछ लोगों की तरह आवाज उठाकर प्रेमचन्द ने जन-साधारण में ही अधिकाधिक भाषा और साहित्य के प्रचार पर जोर दिया है। जो लोग उच्चकोटि का गम्भीर साहित्य रचनेवाला की भाषा-सम्बन्धी कठिनाइयों को न समझकर उस पर तुरन्त ही दुःखता, जम्वाभाविकता आदि का आरोप कर बैठते हैं, उन्हें प्रेमचन्द ने इन शब्दों की ध्यान में रखना चाहिए—“जब तक जनता में शिक्षा का अच्छा प्रचार नहीं हो जाता, उसकी व्यावहारिक गणनावसी बट नहीं जाती, हम उनके समझने योग्य भाषा में साहित्यिक विवेचनाएँ नहीं लिख सकते।” शिक्षा का प्रचार होने पर वही कठिन शब्द “जिन्हें देखकर आज हम भयभीत हो जाते हैं, जब अभ्यास में आ जायेंगे तो उनका होवापन जाता रहेगा।” ('हम', जनवरी, १९३५)

राष्ट्रभाषा के राजनीतिक महत्त्व को वह पूरी तरह स्वीकार करते थे और इसके लिए उन्होंने नानाओं पर यह दोष भी लगाया है कि वे इस सम्बन्ध में अधिक सचेष्ट नहीं रहे। “जब हमारे नेता हिन्दी साहित्य से बेखबर-से हैं, जब हम लोग थोड़ी-सी अंग्रेजी लिखने की सामर्थ्य होते ही हिन्दी को तुच्छ और घामीणा की भाषा समझने लगते हैं, तब यह कैसे आशा की जा सकती है कि हिन्दी में ऊँचे दर्जे के साहित्य का निर्माण हो।” ('हम', जनवरी, १९३६)

फिर भी उनका विचार था देश का साहित्य यदि उन्नति कर सकता है तो राष्ट्र-भाषा के द्वारा ही, अन्य उपभाषाओं से नहीं, राष्ट्रभाषा का साहित्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिद्वन्द्विता में टहर सकता होगा। “यह स्वप्न देखना कि भारत की सभी प्रांतीय-भाषाएँ ससार की समुन्नत भाषाओं के बराबर हो सकती हैं, भ्रम है। एक राष्ट्र एक ही भाषा को लेकर अन्तर्राष्ट्रीय मनों के सामन खड़ा हो सकता है।” ('हम', नवम्बर, १९३५)

इसमें मायूम होता है राष्ट्रभाषा ने प्रदत्त को प्रेमचन्द विजिता महत्त्वपूर्ण समझते थे और उसके साहित्य की उन्नति के लिए उनमें किसी उत्कट अभिलाषा थी। उसी लगन से साहित्य रचकर उन्होंने राष्ट्रभाषा का मस्तक भी ऊँचा किया है।

लिपि के सम्बन्ध में उन्होंने विशेष कुछ विवेचनात्मक नहीं लिखा, परन्तु जय भाषा के सम्बन्ध में उनकी पहली कसौटी बोधगम्यता की है, उसी प्रकार लिपि के लिए उन्होंने पहले-पहल उसका मरत वार सुबोध होना आवश्यक समझा है। इसलिए उन्होंने देवनागरी लिपि का ही समर्थन किया था। “हिन्दुस्तानी भाषा के लिए हिन्दी लिपि रखना

ही सुविधा की बात है।" ('हंस', नवम्बर, १९३५)

(१९४०)

२

प्रेमचन्द ने साहित्यकारों के लिए लिखा था कि उन्होंने कौम की तारीख बनाई है, उसकी संस्कृति बनाई है। प्रेमचन्द किस कौम की तारीख बनानेवाले साहित्यकार थे ? वैसे तो उनके साहित्य का आदर सारे हिन्दुस्तान में हुआ है लेकिन वह खास तौर से हिन्दीभाषी जाति के लेखक थे। वह हिन्दुस्तानी कौम की तारीख बनानेवाले साहित्यकार थे। उन्होंने हिन्दी और उर्दू दोनों ही में रचनाएँ की। हिन्दी और उर्दू के लेखकों की नजदीक लाने में, हिन्दी और उर्दू के सामन्ती साहित्य का मुकाबला करने में, हिन्दी और उर्दू के नये साहित्य में आजादी और जनतन्त्र के भाव और विचार भरने में प्रेमचन्द ने हमारी जाति की अद्वितीय सेवा की है। तुलसीदास के बाद हिन्दी के वह सबसे बड़े साहित्यकार थे जिन्हें हमारी किमान-जनता ने अपनाया। जहाँ-जहाँ हिन्दी-उर्दू पढ़नेवालों ने प्रेमचन्द की रचनाओं में रस लिया, वहाँ-वहाँ जातीय एकता का भाव और मजबूत हुआ।

हिन्दुस्तानी कौम की एकता में हिन्दी-उर्दू का विवाद एक बहुत बड़ी बाधा बना हुआ था। प्रेमचन्द इसके लिखनेवालों को दो कौमों का लेखक न मानते थे। वह उन्हें नजदीक लाना चाहते थे जिससे कि एक मिली-जुली साहित्यिक भाषा का चलन हो सके। दिल्ली में हिन्दुस्तानी सभा के स्थापित होने पर उन्होंने उसका स्वागत किया था क्योंकि उसमें हिन्दी और उर्दू के लेखक एक साथ बैठते और बहस करते थे। हिन्दी-उर्दू के लेखकों का परस्पर मिलना-जुलना और एक माय भाषा और साहित्य की समस्याओं पर विचार करना उनकी नजर में कितना जरूरी था यह 'हिन्दुस्तानी सभा' पर उनकी टिप्पणी से जाहिर होता है। इसमें उन्होंने लिखा था, "जब उर्दू का अदीब अपनी कोई रचना ऐसे समाज के सामने पढ़ेगा, जिसमें हिन्दी के लेखक भी शरीक है, तो वह ऐसी भाषा लिखने की कोशिश करेगा, जो हिन्दीवालों की समझ में आए। इसी तरह हिन्दी का लेखक उर्दू के अदीबों की मण्डली में अपनी भाषा को सुबाध रखने पर मजबूर होगा।" इस तरह के परस्पर प्रभाव और आदान-प्रदान से वह एक मिली-जुली साहित्यिक शैली के विकास की आशा करते थे।

इस तरह के प्रयोग की सफलता एक दूसरी बात पर भी निर्भर है और वह यह कि इस तरह की सभाओं में शामिल होनेवाले लेखक किस हद तक जनता के लिए लिखते हैं और किस हद तक अपने जीवन में जनता के नजदीक हैं। जनता के लिए न लिखने पर साहित्यकार उसी पुरानी लफ्फाजी और उन्ही पुराने अलंकारों की दुनिया में चक्कर लगाता रहता है और तब हिन्दी और उर्दू के लेखक एक-दूसरे से सीखने के बदले एक-दूसरे के कठिन शब्दों को ढूँढने में लग जाते हैं। एक मिली-जुली साहित्यिक भाषा के जरिये कौम की सेवा करने और उसको संगठित करने का सवाल पीछे पड़ जाता है। जहाँ पर हिन्दी-उर्दू लेखकों के मिलकर काम करने और सभाएँ चलाने के काम पूरी तरह

मफन नहीं हुए। यहाँ असफलता का मुख्य कारण जनता में लेखकों के अपनाव को गमभना चाहिए।

एक साहित्यिक शैली गढ़ने में पत्र में होते हुए भी प्रेमचन्द उमे गढ़ने की कठिनाइयाँ का जानते थे। "भारतीय साहित्य परिषद्" में हिन्दुस्तानी को जगह देने पर मौताना अनुन हक की आलोचना का जवाब देने हुए उन्होंने जून, मन्, '३६ के 'हम' लिखा था, "और जा हिन्दुस्तानी अभी व्यवहार में नहीं आई, उसके और ज्यादा हिमायनी नहीं निकले ता कोई मायबूब नहीं। जो लोग हिन्दुस्तानी का बकासततामा निते हुए हैं, और उनमें एक इन पतियों का नेग्रक भी है, वे भी अभी तक हिन्दुस्तानी का कोई रूप पडा नहीं कर सके। केवत उसी बन्पता-मान कर सके हैं, यानी वह ऐसी भाषा हो जो उर्दू और हिन्दी दोनों ही के गमय की मूरत में हो, जो सुबोध हो और आम बानचाल की हो।"

इससे नतीजा गही निकलता था कि एक मिली-जुली साहित्यिक शैली के लिए वक्त की जरूरत थी। हिन्दी को बहुत जगदा सस्त्रुतमय और उर्दू को फारसी-अरबीमय बनान का विरोध करना गही था लेकिन हिन्दी और उर्दू की जो दो शैलियाँ बन रही थीं, उन्हें एकाएक छोडा नहीं जा सकता था। प्रेमचन्द हिन्दी और उर्दू दोनों में लिखने थे और उनकी हिन्दी उर्दू में भेद भी रहता था। इस पर कुछ लोगो ने उन पर यह तोहमन लगाई कि वह भूँह में तो हिन्दुस्तानी की हिमायन करते हैं, असन से हिन्दी का प्रचार करने हैं।

'हम' के 'प्रेमचन्द-स्मृति अंक' में श्री अशाफाज हुसेन ने एक दिलचस्प घटना का जिक्र किया है। "अलीगढ से 'मुहैन' नाम का एक उर्दू अगधार निकलता है। उसमें छापने के लिए प्रेमचन्दजी ने अपनी दो रचनाएँ भेजी थी, जिनमें एक तो हिन्दी में थी और दूसरी उर्दू में। इसके लिए एक माहय ने प्रेमचन्द के बारे में बहुत-सी उल्टी-सीधी बातें लिख डाली थी। उनकी हिन्दीवाली रचना में तो सस्त्रुत के कई शब्द थे और उर्दू-वाली रचना में उसमें भी अधिक फारसी के शब्द थे। इसकी आलोचना जिस तरह के लोगो का करनी चाहिए थी, उनी तरह के लोगो ने की थी और कहा था कि 'प्रेमचन्दजी दोहरी चालें चलत हैं, दोनों तरफ मिने रहता चाहते हैं और दोनों तरफ से अच्छे बने रहता चाहते हैं।'"

अगर प्रेमचन्द का यह दावा होता कि हिन्दी-उर्दू का बायकाट करके, तुरन्त हिन्दुस्तानी रायज की जा सकती है, तो शायद इन आलोचना में कुछ तथ्य होता। लेकिन जैसा कि हम देख चुके हैं, प्रेमचन्द हवाई सिद्धांतकार नहीं थे, वह असल में तुरन्त एक मिली-जुली भाषा गौली ईजाद करने की कठिनाइयों को जानते थे। इसलिए हिन्दी और उर्दू दोनों में कुछ हेर-फेर के साथ लिखने की उनकी नीति सही थी, चीनचाल की कौमी जवान हिन्दुस्तानी का समर्थन करना भी ठीक था।

'प्रेमचन्द-स्मृति अंक' में श्री मोहम्मद आकिन ने इस तरह की दूसरी घटना का जिक्र किया है। "इस मिलसिले में देहली के रिसाले माकी' ने जो तनक़ीद की थी कि

प्रेमचन्दजी उर्दू के लिए मरहूम हो चुके हैं, उसके बारे में हँसकर कहने लगे कि 'साक्की' के एडिटर को मैंने लिखा है कि मैं उर्दू के लिए न सिर्फ़ जिन्दा हूँ बल्कि ज्यादा जोरों से जी रहा हूँ।" प्रेमचन्द उन थोड़े से लेखकों में थे जिनमें हिन्दी-उर्दू को लेकर बड़ा-चढ़ी का भाव नहीं था। यह भाव तब पैदा होता है जब लेखक के दिमाग में हिन्दी-उर्दू के पीछे हिन्दुस्तानी कौम नहीं होती बल्कि हिन्दू धर्म और इस्लाम होता है। प्रेमचन्द ने अपने अमल से दिखलाया कि साहित्य का जातीय रूप समृद्ध करने से, उसमें जनवादी विचारों का समावेश करने से भापा की समस्या हल करने में मदद मिलती है। प्रेमचन्द के जल्दवाज़ आलोचक, जो तुरन्त हिन्दुस्तानी रायज करना चाहते थे, इस दिशा में ऐसा कोई बड़ा काम नहीं कर पाए।

प्रेमचन्द ने राष्ट्रभाषा और हिन्दुस्तानी के सम्बन्ध में जो भाषण दिए थे, उनमें एक तरफ़ तो साम्राज्यवादियों की गुलामी के हर रूप से बेहद नफरत जाहिर होती है, दूसरी तरफ़ हर जगह उनका यह दृढ़ विश्वास भी जाहिर होता है कि हिन्दी और उर्दू एक ही कौम की जवान हैं और इनका एक होना लाजमी है।

प्रेमचन्द को देश के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में अंग्रेज़ी भाषा की प्रभुता खलती थी। यह उनकी साम्राज्य-विरोधी राष्ट्रीय चेतना, उनके आत्मसम्मान की भावना का जबर्दस्त सबूत था। किसी ने साम्राज्यवादियों की अंग्रेज़ी लादने की नीति के खिलाफ़, बुद्धिजीवियों में इस नीति के सामने सिर झुकाने की नीति के खिलाफ़ इतने रोप और तर्क के साथ वसावत न की थी जैसे प्रेमचन्द ने। सन् ३४ में बम्बई के राष्ट्रभाषा-सम्मेलन में उन्होंने पशुओं और मनुष्यों में यह भेद बतलाया कि मनुष्य भाषा इस्तेमाल करते हैं, पशु नहीं करते। "समाज की बुनियाद भाषा है।" इस महत्व की जगह से अंग्रेज़ी यहाँ की भाषाओं को हटाने की कोशिश करती रही थी। सारे देश के लोग आपस में किस भाषा का व्यवहार करें, इस बारे में नेताओं वगैरह की उदासीनता का जिक्र करते हुए उन्होंने इस सम्मेलन में कहा था—“इस लापरवाही का ख़ास सबब है—अंग्रेज़ी ज़बान का बढ़ता हुआ प्रचार और हममें आत्म-सम्मान की वह कमी, जो गुलामी की शर्म को नहीं सहस्र करती।”

किसी भी देश और जाति की उन्नति में यह आत्म-सम्मान की भावना जनता में ज़ोर्ग भर देती है, उसे संगठित होकर नए-नए मोर्चे फतह करने में बेहद मदद देती है। प्रेमचन्द का स्वाभिमान यह देखकर तिलमिला उठता था कि गुलाम देश के बुद्धिजीवी अपने मालिकों की भाषा पर अभिमान करते हैं। अंग्रेज़ी भाषा के प्रभुत्व को उन्होंने साम्राज्यवादी प्रभुत्व का ही अटूट हिस्सा बतलाते हुए कहा था—“अंग्रेज़ी राजनीति का, व्यापार का, साम्राज्यवाद का हमारे ऊपर जैसा आतंक है, उससे कहीं ज्यादा अंग्रेज़ी भाषा का है। अंग्रेज़ी राजनीति से, व्यापार से, साम्राज्यवाद से तो आप वसावत करते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी भाषा को आप गुलामी के तौक की तरह गर्दन में डाले हुए हैं।”

प्रेमचन्द के इन उचित क्रोध से भरे हुए वाक्यों के सामने कोई दलील कारगर

नहीं हो सकती। सवाल है राष्ट्रीय आत्म सम्मान का। चीन-भा देश, जो स्वाधीन है या स्वाधीनता के लिए लड़ रहा है, हमारी तरह दूसरों की ख़्वाब को अपने राजस्व की ख़्वाब बनाए हुए है? प्रेमचन्द ने उन लोगों को बड़ी फटकार बनाई जो हम मुलामी पर नाज़ करने थे। उन्होंने तमाम अंग्रेज़ी-भक्ता पर घरा पानी उड़ेलते हुए कहा था— 'अंग्रेज़ी राज्य की जगह आप स्वराज्य चाहते हैं। उनके व्यापार की जगह अपना व्यापार चाहते हैं लेकिन अंग्रेज़ी भाषा का मिक्का हमारे दिलों पर बँठ गया है, उसके बिना हमारा पड़ा लिखा समान अनाथ हो जाएगा। पुराने समय में आय और अनाथ का भेद था आज अंग्रेज़ी और और अंग्रेज़ी का भेद है। अंग्रेज़ी आय है। उसके हाथ में, अपने स्वामिनी की कृपा-दृष्टि की बदौलत कुछ अक्षितयार है, रोव है, सम्मान है, गर-अंग्रेज़ी ही अनाथ है और उसका काम केवल आयों की सेवा टहल करना है और उनके लोग विकास और भोजन के लिए सामग्री जुटाना है।' प्रेमचन्द ने भारत के अंग्रेज़ी प्रेमी आयों के लिए य शब्द अठारह साल पहले कहे थे। उनका महत्त्व आज भी कम नहीं हुआ।

प्रेमचन्द हिन्दी-उर्दू की एक ख़्वाब मानते थे। राष्ट्रभाषा सम्मेलन वाले भाषा में उन्होंने हिन्दी उर्दू का भेद मस्ठुत और फारसी शब्दों के प्रयोग पर निर्भर बनलाया था। इस भाषण में उन्होंने हिन्दी की बोलियों के स्वभाव की तरफ ध्यान दिनाया था, जिस तरह वे मस्ठुत शब्दों को ज्या-का त्या नहीं लेती। उन्होंने दग कुनक का जोरो से लपटन किया कि हिन्दी में मस्ठुत शब्दों की भरमार करने से वह सभी प्रान्ता के लोगों के लिए आमान हो जाएगी।

हिन्दी-उर्दू की बुनियादी एकता के बारे में प्रेमचन्द कहते हैं—“हमारे सूबे के देहात में रहनेवाले मुसलमान प्रायः देहातिया की भाषा ही बोलते हैं। जा बहुत से मुसलमान देहात से जाकर शहरों में आबाद हो गए हैं, वे भी अपने घरों में देहाती ख़्वाब ही बोलते हैं। बालबाल की हिन्दी समझने में न तो साधारण मुसलमानों को ही कोई कठिनाई होती है और न बालबाल की उर्दू समझने में साधारण हिन्दुओं को ही। दोनों बात की हिन्दी और उर्दू प्रायः एक-सी हैं।”

यहाँ पर प्रेमचन्द न दग अवैतानिक सिद्धान्त का खण्डन किया है कि भाषा का आधार धर्म है और इसलिए हिन्दुओं की भाषा हिन्दी है और मुसलमानों की भाषा उर्दू है। उन्होंने धर्म के नाम पर भाषा और कौम का बँटवारा करने वाले साम्राज्यवादी और सामन्ती भाषा-वैतानिकों का खण्डन किया और हिन्दुस्तानी जाति की भाषा और मस्ठुति के विकास में बहुत बड़ी मदद की। इस जाति की भाषा की लिपि के लिए वह देवनागरी लिपि के पक्षपाती थे। राष्ट्रभाषा-सम्मेलन में उन्होंने कहा था—“प्रान्तीय भाषाओं की हम प्रान्तीय लिपियों में लिखते आएँ, कोई ऐतराज नहीं, लेकिन हिन्दुस्तानी भाषा के लिए हिन्दी लिपि ख़्वाब ही सुविधा की ख़ास है, इसलिए नहीं कि हम हिन्दी लिपि में ख़ास मोह हैं, बल्कि हिन्दी लिपि का प्रचार बहुत ज्यादा है और उसके सीखने



में भी किसी को दिक्कत नहीं हो सकती। और जो लोग उर्दू लिपि के आदी हैं, उन्हें हिन्दी लिपि का व्यवहार करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर जवान एक हो जाय, तो लिपि का भेद कोई महत्त्व नहीं रखता।”

हिन्दी-उर्दू को एक करने, कौमी भाषा और संस्कृति का नया विकास करने की जिम्मेदारी प्रेमचन्द अगली पीढ़ी पर छोड़ गए थे। उनके बताये हुए रास्ते पर चलकर ही हम उस जिम्मेदारी को पूरा कर सकते हैं।

(१९५२)

## उत्तर प्रदेश की सरकार और हिन्दी

१५ अगस्त, १९६४ की 'उत्तर प्रदेश पचायती राज्य' नामक पत्रिका में श्रीमती मुचंता कृपानानी का एक लेख छपा है 'उत्तर प्रदेश और राष्ट्रभाषा'। इसमें उन्होंने हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के सिलसिले में जो बातें कही हैं, उनका सम्बन्ध राजनीतिज्ञों में अधिक साहित्यकारों से है। आशा है, हिन्दी लेखक उन पर उचित ध्यान देंगे।

पहले तो उन्होंने यह बताया कि हिन्दी का प्रचार शतक ढंग से किया गया और वह शतक बग छोड़ देना चाहिए। फिर उन्होंने बताया कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का सही तरीका क्या है।

जिम तरीके से हिन्दी का प्रचार हुआ, उससे अहिन्दी जनता के मन में यह प्रतिक्रिया पैदा हुई—“हम क्यों हिन्दी सीखें?”

“भाषा का प्रचार तलवार से नहीं होता।”

बिलकुल सही बात है। राज्यमन्त्री कांप्रेस के हाथ में है। तलवार का किसी ने प्रयोग किया होगा तो वह कांग्रेसी नेता ही होगा। उत्तर भारत में तमिल के विरोध में या अंग्रेजी के विरोध में स्टेशनो, डाकखानों वगैरह पर हमला नहीं हुआ। इस तरह की कारवाही तमिलनाडु में हुई। इसे तलवार का प्रयोग कहा जाय या प्रेम प्रदर्शन, यह कांग्रेस नेता तय करें। एक बात निश्चित है कि तलवार का प्रयोग हिन्दी जनता या हिन्दी प्रचारकों ने नहीं किया।

हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का सही तरीका उन्होंने यह बताया—

“हिन्दी भाषा को प्रगति पर लाएँ। हिन्दी को उस स्तर पर लाएँ कि हरेक हिन्दी को मुँगी से सीखे।”

“अगर भाषा उन्नत हो, भाषा मधुर हो, भाषा सुन्दर हो, भाषा में इतने शब्द हों या भाषा इस स्तर में पहुँची हो कि हमारी हरेक ज़रूरतों को पूरी कर सके तब लोग आप-से-आप भाषा को लेते हैं।”

“हिन्दी को अगर भारत की भाषा बनाना है, भारत की राष्ट्रभाषा बनाना है, तो हिन्दी-श्रेणी बैठकर सोच करें, अनुसंधान करें, किताबें लिखें, लोगों को बैठकर हिन्दी सिखाएँ। ऐसी सुन्दर किताबें लिखी जाएँ, ऐसी भाषा में किताबें लिखी जाएँ कि लोग उसे

ग्रहण करने के लिए आग्रह करें।”

“हिन्दी को लोगों द्वारा ग्राह्य बनाने के लिए तलवार से नहीं बल्कि साहित्य के महत्त्व से, साहित्य की उच्चता और सुन्दरता से और प्रचार और प्रसार करने के सुन्दर तरीके से यह होगी।”

जहाँ तक भाषा के सुन्दर और मधुर होने का सम्बन्ध है, हिन्दी जैसी है, वैसी है। हर व्यक्ति को अपनी भाषा सबसे ज्यादा मीठी लगती है। यदि वह कहे कि दूसरे की भाषा ज्यादा मीठी है तो समझना चाहिए कि उसके संस्कारों में कहीं कोई दोष है। मिठास के कारण कोई अपनी भाषा के मुकाबले दूसरी भाषा को महत्त्व नहीं देता।

जहाँ तक भाषा में ‘हरेक जरूरियात’ के शब्द होने का सवाल है, दस साल तक कांग्रेसी सरकार का शिक्षा-मंत्रालय और उसके विशेषज्ञ यह काम करते रहे हैं। यदि हिन्दी अभी तक आवश्यक शब्द इकट्ठे नहीं कर पाई, तो इसमें दोष सुचेताजी की पार्टी के नेताओं का है। लेकिन राजकाज के लिए उन तमाम शब्दों की जरूरत नहीं होती जिन्हें गढ़ने या इकट्ठा करने में दस साल से विशेषज्ञ लग रहे हैं। राजकाज की जरूरियात-भर को तो हिन्दी में शब्द हैं, भले ही हरेक जरूरियात के लिए न हों।

जहाँ तक साहित्य की उच्चता का सम्बन्ध है, अंग्रेजी काफ़ी उच्च भाषा है। लेकिन आगरा विश्वविद्यालय की बी० एस-सी० परीक्षाओं में जब से अंग्रेजी ऐन्ड्रिक विषय हो गई है, तब से अंग्रेजी लेनेवाले छात्रों की संख्या लगभग अस्सी फी सदी कम हो गई है। जो बी० ए० में अंग्रेजी पढ़ते हैं, उनका हाल मत पूछिये। किताबें पढ़े बिना ही बाज़ार से या प्रोफ़ेसर के लिखाये हुए नोट पढ़कर पास होता चाहते हैं। जो छात्र एम० ए० में अंग्रेजी पढ़ते हैं, उनमें नित्यानवै फी सदी ऐसे होते हैं जो किसी तरह पास होना चाहते हैं या डिग्रीजन बनाना चाहते हैं। साहित्य-प्रेम से उन्हें कोई वास्ता नहीं है।

अंग्रेजी के अलावा भारत की जो दूसरी मधुर भाषाएँ हैं उनके साहित्य को वे फूटी आँखों भी नहीं देखते। आगरा और लखनऊ में ऐसे हिन्दी-भाषी छात्र कम मिलेंगे जिन्होंने रवीन्द्रनाथ की रचनाएँ बँगला में पढ़ी हों। कलकत्ता के बँगलाभाषी युवक सुब्रह्मण्य भारती या बल्लत्तोल की रचनाएँ बड़े चाव से पढ़ते हों, ऐसा भी मेरे देखने में नहीं आया।

भारत की शिक्षा-व्यवस्था नौकरियों से जुड़ी है और नौकरियों की भाषा है अंग्रेजी। इसके लिए सुचेताजी की पार्टी के नेता जिम्मेदार हैं, हिन्दी साहित्यकार नहीं।

मान लिया कि हिन्दी भाषा सुन्दर नहीं है और उसका साहित्य घटिया किस्म का है। भारत की किन भाषाओं का साहित्य—अनुवादित हुए बिना—अन्य प्रदेशों में बहुतायत से पढ़ा जाता है? अंग्रेजी को भारतीय जीवन में जो महत्त्व दिया गया है, उससे समस्त भारतीय भाषाओं के पठन-पाठन में बाधा पड़ती है, हिन्दी के प्रचार-प्रसार में ही नहीं।

मान लिया, हिन्दी-प्रचारकों के गलत उत्साह के कारण लोग अहिन्दी प्रान्तों में हिन्दी से नाखुश हो गए। बंगाल में बँगला राजभाषा क्यों नहीं है? वहाँ बँगला के व्यवहार

पर किन लोगों ने प्रतिवध लगाया है ? तमिलनाडु में तमिल के व्यवहार पर किमन रोक लगाई है ?

हिन्दी प्रचारकों को दोष देना एक बहाना है जिससे केन्द्र और प्रान्तों में अंग्रेजी का चलन बना रहे ।

मुद्र उत्तर प्रदेश में राष्ट्रभाषा हिन्दी का क्या हाल है ?

राष्ट्रभाषा मन्त्र (प्रधान) ने २ मितम्बर, १९६४ के अक म लिखा है, वास्तविक स्थिति कम-से-कम उत्तर प्रदेश में यह है कि यहाँ नियानवे प्रतिशत से अधिक सरकारी काम अंग्रेजी में किया जाता है ।”

उत्तर प्रदेश मान्यता का मसले बड़ा हिन्दीभाषी राज्य है । मारे देश में हिन्दी की स्थिति क्या हाली है, यह बहुत कुछ उत्तर प्रदेश में हिन्दी की स्थिति पर निर्भर है ।

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी ने हिन्दी भाषा में उच्च साहित्य की आवश्यकता पर जो विचार प्रकट किये हैं, वैसे विचार मन् ३६-४० में कांग्रेसी नेता पटेल भी प्रकट किया करने थे । लेकिन वे हिन्दी लिख-पढ़ लेने थे । सुचेताजी ने अपने उनसे कन लख म बनाया है कि उन्होंने “मर-मरकर रोज सुबह एक घंटा साहित्य” रामचरितमानस पढ़ा । उसमें उन्हें कोई चीज मिली । लेकिन मालूम होता है, लिखने में उन्हें अब भी कठिनाई होती है ।

“मैं हिन्दी तब नहीं समझती — श्रीमती सुचेता कृपलानी का यह वाक्य पढ़कर किसे दुःख न होगा ? आगा है अगले चुनाव तक वह अपनी यह कठिनाई भी दूर कर देंगी । मय मान्य हिन्दी साहित्यकारों को वह जो उपदेश देंगी, वे और भी मधुर और शानप्रद होंगे ।

(१९५५)

## भारत का भाषा-संकट

श्री मोहनकुमार मंगलम ने अंग्रेजी में एक बहुत सुन्दर पुस्तक लिखी है जिनका नाम है—'भारत का भाषा-संकट'। जो लोग चाहते हैं कि भारत में अंग्रेजी का प्रभुत्व सतम हो, उन्हें यह पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। उत्तर भारत में लाखों आदमी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हिन्दी राष्ट्रभाषा हो। वे चाहते हैं कि विभिन्न प्रदेशों में वहाँ की भाषाएँ राजभाषा के गौरवमय आसन पर प्रतिष्ठित हों। प्रश्न यह है कि वे राजभाषा क्यों नहीं बन पातीं? कौन-सी शक्ति उन्हें अपने उचित आसन पर बैठने से रोकती है?

श्री मोहनकुमार मंगलम की पुस्तक के छठे अध्याय में इस विषय का विवेचन किया गया है कि तमिलनाडु में तमिल अभी तक क्यों राजभाषा नहीं बन पाई। तमिल को सरकारी तौर पर सन् '५७-५८ में राजभाषा बना दिया गया था किन्तु इसके बाद मद्रास में अंग्रेजी का रुतवा बढ़ा है, कम नहीं हुआ। अधिकांश विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। कुछ साल पहले अंग्रेजी की शिक्षा छठे दर्जे से शुरू होती थी, अब वह तीसरे दर्जे से शुरू होती है। शिक्षा-केन्द्रों में अंग्रेजी का प्रभुत्व अटल है। "माता-पिता सोचते हैं कि बेटे को तरक्की करनी है तो बढ़िया अंग्रेजी सीखकर ही वह आगे बढ़ सकता है। इसलिए जिन स्कूलों में शिक्षा का माध्यम तमिल थी, उनमें छात्रों की संख्या लगातार कम होती गई और वे अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा पाने लगे।"

तमिलनाडु की जनता अपने मातृभाषा-प्रेम के लिए प्रसिद्ध है। उसे अपनी भाषा की प्राचीनता और साहित्य की समृद्धि पर उचित गर्व है। फिर क्या कारण है कि स्कूलों और कॉलेजों में तमिल शिक्षा का माध्यम नहीं हो पाती?

इस प्रश्न का उत्तर श्री मोहनकुमार मंगलम ने बहुत स्पष्ट शब्दों में दिया है। उन्होंने लिखा है: "ऐसा इसलिए होता है कि सरकार और यूनिवर्सिटी-अधिकारियों ने छात्रों के सामने लक्ष्य यह रखा है—'अंग्रेजी खूब अच्छी तरह सीखो जिससे अखिल भारतीय स्तर पर ऊँची नौकरियों के लिए होड़ कर सको और यूनिवर्सिटी में भी कारगर ढंग से शिक्षा प्राप्त कर सको।'" (शब्दों पर जोर मूल पुस्तक में है।)

१. इंडियाज लैंग्वेज काउंसिल : मोहनकुमार मंगलम, प्रकाशक : न्यू सेंचुरी बुक हाउस मद्रास, पृ० १२२, मू० ५ रु०।

हमारे देश में शिक्षा-मस्याएँ नौकरियों में जुड़ी हुई हैं। अंग्रेजों ने शासन-तंत्र चलाने के लिए वर्क के लेकर कमिशनर तक के लिए अंग्रेजी की शिक्षा अनिवार्य कर दी थी। वही स्थिति आज भी है।

श्री मोहनकुमार मंगलम ने दो साल पहले दिया हुआ श्री भक्तवत्सलम का भाषण उद्धृत किया है। इसमें उन्होंने कहा था, “माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे सरकारी नौकरियाँ पाएँ। राज्य की नौकरियों के मुकाबले में केन्द्रीय नौकरियाँ ज्यादा आकर्षक होती हैं। इसलिए माता-पिता और छात्रों की भी पहली तमन्ना यह होती है कि वे आई० ए० एस० और आई० पी० एम० जैसी केन्द्रीय सेवाओं की परीक्षा में बैठें।” यही कारण है कि तमिलनाडु में तमिल राजभाषा नहीं बन पायी। उसे कागजी तौर पर राजभाषा बना दिया जाता है लेकिन वास्तविक प्रभुमत्ता रहती है अंग्रेजी के हाथ में। श्री मोहनकुमार मंगलम के शब्दों में—‘अंग्रेजी की शिक्षा पाये बिना किसी भी तमिलभाषी के लिए केन्द्रीय नौकरी पाने का सवाल नहीं उठता।’

कांग्रेसी नेताओं ने केन्द्र में अंग्रेजी का प्रभुत्व कायम रखकर राज्या में वहाँ की भाषाओं को पददलित कर रखा है। तमिल-जैसी प्राचीन और सम्पन्न भाषा अंग्रेजी की दासी बनी हुई है। मद्रास में तमिल राजभाषा नहीं बन पाई, इसका कारण यह नहीं है कि हिन्दी उसका दमन और पतन कर रही है, इसका कारण यह है कि कांग्रेसी नेताओं ने साम्राज्यवादियों की चलाई हुई—शासन-तन्त्र और शिक्षा के बारे में अंग्रेजी व्यवहार की—नीति को बरकरार रखा है। इस नीति के लिए केवल हिन्दी-क्षेत्र के नेता जिम्मेदार नहीं हैं—यद्यपि उन्हें ज्यादा धम आनी चाहिए क्योंकि वे हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का दावा भी करते हैं।—अहिन्दी क्षेत्रों के नेता भी उनके ही जिम्मेदार हैं।

भारतीय भाषाओं में मुख्य अन्तर्विरोध हिन्दी अहिन्दी का नहीं है, मुख्य अन्तर्विरोध अंग्रेजी और समस्त भारतीय भाषाओं का है। राज्यों में अंग्रेजी के प्रभुत्व का कारण है—केन्द्रीय सेवाओं में उसका व्यवहार।

ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जब तक केन्द्रीय सेवाओं में अंग्रेजी में हटेगी, तब तक तमिल भी मद्रास में व्यावहारिक रूप में राजभाषा न बनेगी। इसलिए समाधान ऐसा होना चाहिए जिससे केन्द्रीय सेवाओं में अंग्रेजी का चलन खत्म हो।

श्री मोहनकुमार मंगलम ने कांग्रेस के पुराने प्रस्ताव का हवाला देते हुए सभी भारतीय भाषाओं को अस्थित भारतीय परीक्षाओं का माध्यम बनाने की बात कही है। उनका सुझाव सही है। कभी इतनी है कि उन्होंने केन्द्रीय सेवाओं में केवल परीक्षाओं के लिए भारतीय भाषाओं के ऐच्छिक माध्यम होने का सवाल उठाया है। जब मद्रास के छात्र तमिल में परीक्षा देकर अफसर बनेंगे, तब वे अंग्रेजी का व्यवहार करेंगे, या भारतीय भाषाओं का—इस प्रश्न पर उन्होंने विचार नहीं किया। अस्थित भारतीय सेवाओं का माध्यम अंग्रेजी ही रहेगी—इसलिए सबक ज्यों-का-रखा बना रहता है। परीक्षा आप चाहे जिसमें दे लें, काम अंग्रेजी में ही करना पड़ेगा।

श्री मोहनकुमार मंगलम ने तीन भाषाओंवाले फार्मूले का समर्थन किया है। इस फार्मूले में अंग्रेजी का स्थान सुरक्षित है। अंग्रेजी का स्थान सुरक्षित रखकर अंग्रेजी का प्रभुत्व नहीं खत्म किया जा सकता। फलतः तमिलनाडु में भी तमिल को राजभाषा और उच्च शिक्षा का माध्यम भी नहीं बनाया जा सकता।

अंग्रेजी की शिक्षा वैकल्पिक हो—यह मांग करनी चाहिए। किसी भी स्वाधीन देश के विद्यालयों में किसी विशेष विदेशी भाषा का अध्ययन सभी छात्रों के लिए अनिवार्य नहीं होता। केन्द्र में अंग्रेजी का प्रभुत्व खत्म करना चाहिए। उसकी जगह हिन्दी चले या अनेक भारतीय भाषाओं का व्यवहार हो—श्री मोहनकुमार मंगलम जो फैसला करेंगे, मैं उसका समर्थन करूँगा। लेकिन केन्द्र में अंग्रेजी चलाते रहने से भारत का भाषा-संकट हल न होगा, उल्टे वह और गहरा होगा और इससे तमिल को उतनी ही हानि होगी जितनी हिन्दी को।

भारतीय भाषाओं को प्रदेशों में राजभाषा का पद न दिया जाय—इसके लिए अंग्रेजी-प्रेमी विद्वान तर्क देते हैं कि वे भाषाएँ पिछड़ी हुई हैं। यद्यपि किसी ने भारतीय भाषाओं में एक भाषा लेकर वैज्ञानिक परीक्षा करके यह नहीं दिखाया कि पिछड़ापन किस बात में है—फिर भी यह सर्वमान्य सत्य बन गया है कि अंग्रेजी के मुकाबले में भारतीय भाषाएँ बाम तौर से—और हिन्दी खास तौर से—पिछड़ी हुई हैं।

तमिल विकसित भाषा है या नहीं? उसमें मद्रास राज्य का सरकारी काम हो सकता है या नहीं? उसमें उच्च शिक्षा दी जा सकती है या नहीं?

श्री मोहनकुमार मंगलम ने इन प्रश्नों के परस्पर-विरोधी उत्तर दिये हैं। उनकी समझ में भारत के भाषा-संकट का मुख्य कारण यह है कि सरकारी परवरिश के कारण हिन्दी को विकसित होने का मौका मिला लेकिन अहिन्दी भाषाएँ अविकसित रह गईं। इसलिए समस्या का समाधान यह है कि पहले इन भाषाओं को राजभाषा बना दिया जाय, उन्हें विकसित होने दिया जाय, इसके बाद ही केन्द्र से अंग्रेजी हटाने का सवाल उठेगा।

उन्होंने लिखा है, “हमें यह न भूलना चाहिए कि अपनी प्राचीनता, अपनी देन, अपने उत्कृष्ट साहित्य आदि गुणों के बावजूद वे किसी भी समय, बहुत से बहुत, एक संकुचित गुट के विचारों का बाहन ही रही है।”

इसका अर्थ है कि वे वर्तमान सभ्य समाज की शिक्षा-संस्कृति-राजनीति का माध्यम बनने के योग्य नहीं हैं।

उनके विचार से अंग्रेजों के आने से पहले भारत की संस्कृति प्राचीन होते हुए भी गतिरुद्ध (स्टैगनेन्ट कल्चर ऑफ़ इंडिया) हो चुकी थी। अंग्रेजी के प्रभुत्व से भारतीय भाषाओं की प्रगति रुक गई थी, “अर्थात् आधुनिक भाषाओं के रूप में, आधुनिक विचारों को प्रकट करनेवाले माध्यम के रूप में विकसित होने से रोका गया।”

मैं नहीं जानता कि वे आधुनिक विचार कौन से हैं जो तमिल या हिन्दी के माध्यम से प्रकट नहीं किए जा सकते। इतना जरूर कह सकता हूँ कि आदरणीय बन्धु मोहनकुमार

मगलम ने जो विचार इस पुस्तक में प्रकट किये हैं, वे किसी भी भारतीय भाषा में बसूबा प्रकट किए जा सकते हैं।

कुमार मंगलमजी ने यह मत भी बड़ी स्पष्टता से प्रकट किया है कि भारतीय भाषाएँ सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप पूर्णतः विकसित हैं। उन्होंने पुस्तक के पृष्ठ ४० पर लिखा है—

‘हकीकत यह है कि (बाइबी अनुसूची में उल्लिखित) सभी भाषाएँ विकसित भाषाएँ हैं। इन्हें बराबरी आदमी बोलते हैं और मानते हैं कि उच्च शिक्षा का माध्यम बनने के लिए वे पूरी तरह विकसित हैं।’

यदि भारतीय भाषाएँ विकसित हैं तो भाषा-सकट टगलिंग नहीं पैदा हो गया कि सरकार ने हिन्दी को ऐसादा विकसित कर दिया है और तमिल पीछे रह गई है। भाषाएँ अविकसित हैं—यह एक बहाना है जो हिन्दी और तमिल, सभी भारतीय भाषाओं के खिलाफ दमनमात्र किया जाता है। सकट का बगमनी कारण है केन्द्र में अंग्रेजी का प्रभुत्व। इसी प्रभुत्व के कारण तमिल अपने प्रदेश में राजभाषा नहीं बनो, इसी कारण वह शिक्षा का माध्यम नहीं बनो। जहाँ भी केन्द्र में अंग्रेजी कायम रखकर राज्यों से अंग्रेजी हटाने का अपना देखा है वह अपने का और दूसरों को धोखा देता है। जब तक केन्द्रीय सरकार में अंग्रेजी का चलन रहता, तब तक मद्रास का विद्यार्थी कभी अंग्रेजी छोड़ने की राखी न लगा।

श्री माजिनकुमार मंगलम कम्युनिस्ट पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। श्रमिक जनता का आंदोलन से उनका गहरा सम्बन्ध रहा है। उनसे हम आशा कर सकते हैं कि वे मजदूर का की एकता और भाषा-समस्या पर भा बुद्ध कहेंगे। लेकिन उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा।

अखिल भारतीय स्तर पर मजदूरों के माछा की भाषा अंग्रेजी क्यों है? अखिल भारतीय किसान-सभा के कन्दाय दफ्तर की कार्यवाही अंग्रेजी में क्या होती है (या होती थी)? कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सम्पूर्ण भाषा के रूप में अंग्रेजी का व्यवहार क्यों करते हैं? कम्युनिस्ट पार्टी के कन्दाय दफ्तर में अंग्रेजी का व्यवहार क्यों होता है? पार्टी और जन-संगठना में अंग्रेजी का इस प्रभुत्व से हानि होती है या लाभ? श्री माजिनकुमार मंगलम ने ऐसा एक भी सवाल अपनी पुस्तक में नहीं उठाया। यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है।

इस दंग में जब अंग्रेज जाए, तब यहाँ के राजा और नवाब, मिलकर उनसे लड़ने के बजाय, आपस में मरते रहे। भारत में गहने के लिए वे बारी-बारी ने अंग्रेजों की मदद लेते रहे और अंग्रेज बारी-बारी से उन्हें खाम करके उनका राज्य हड़पते रहे।

वर्तमान बारी मजदूरों के विद्रोह से बड़ा है। गोआ को लेकर मैसूर के मुद्रमन्त्री ने जिनगी सराफों महाराष्ट्र के विद्रोह दिखाई है उसकी मरगमी पुनर्गल के खिलाफ न दिखाई थी। भाषा की समस्या जातीय समस्या का अंग है। भारतीय भाषाओं के हिमायती आपस में लड़ते हैं और अंग्रेजी की जग खोलते हैं। जातीय विद्रोह का एक रूप भाषागत



विद्वेष है। इस तरह का द्वेष पूंजीपतियों के लिए स्वाभाविक है; पूंजीवादी विचारधारा से प्रभावित मध्यवर्ग श्रेणी के बुद्धिजीवियों के लिए यह विद्वेष बहुत कुछ सुखकर और जीवन की मुख्य प्रेरणा है। केवल मजदूर वर्ग में यह क्षमता है कि वह इस विद्वेष से ऊपर उठकर अन्तर्जातीय भाईचारे के आधार पर राष्ट्रीय एकता दृढ़ करे। इसीलिए अंग्रेजी और मजदूर वर्ग की अखिल भारतीय एकता का प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

भाषा-संकट क्यों पैदा हुआ, मद्रास में अंग्रेजी क्यों कायम रहती है, संविधान के निर्माताओं की किन गलतियों से प्रादेशिक भाषाओं का चलन न हुआ यह समस्त सूक्ष्म विश्लेषण, कम्युनिस्ट पार्टी के अन्दर अंग्रेजी के व्यवहार पर नजर डालते ही, वकीलों की जिरह की तरह कानूनी तौर पर सही परन्तु न्याय के प्रतिकूल मालूम होने लगता है। भला भाषाओं के विकास में 'इम्ब्रैलेन्स' पैदा हो जाने से कम्युनिस्ट पार्टी में अंग्रेजी का चलन क्यों हो ?

भारतीय जनतंत्र को चलाने के लिए आसमान से फरिश्ते नहीं आते। वर्तमान युग में जनतंत्र को चलाती हैं पार्टियाँ और पार्टियों के नेता। जब तक देश की राजनीतिक पार्टियाँ अपना अखिल भारतीय काम अंग्रेजी में करती हैं, तब तक न तो वे देश की भाषा-समस्या हल कर सकती हैं, न दरअसल उन्हें इस समस्या पर बोलने का नैतिक अधिकार है।

✓ श्री मोहनकुमार मंगलम ने लिखा है कि हर नागरिक को यह अधिकार होना चाहिए कि वह लोकसभा में अपनी मातृभाषा में बोल सके। ✓

मैं इस माँग का समर्थन करता हूँ। हमारे साथी बोलें तो भारतीय भाषाओं में। फिर देखें, हिन्दी और अहिन्दी-भाषियों का कैसा जबरदस्त अंग्रेजी-विरोधी मोर्चा बनता है। लेकिन वे खुद बोलेंगे अंग्रेजी में; दूसरों के लिए मातृभाषा में बोलने का अधिकार माँगेंगे ! इस तरह सात जन्म में अंग्रेजी का प्रभुत्व दूर न होगा।

लोकसभा में भारतीय भाषाओं का व्यवहार कीजिए। जन-संगठनों का अखिल भारतीय काम देशी भाषाओं में कीजिए। अपने केन्द्रीय दफ्तर से अंग्रेजी निकालिए। भारत का भाषा-संकट हल करने का यही कारगर तरीका है।

